भारतीय रिज़र्व बैंक

बुलेटिन

अप्रैल 2023

खंड 77 अंक 4

अध्यक्ष
माइकल देवब्रत पात्र

संपादन समिति
अजित आर. जोशी
देब प्रसाद रथ
मुनिश कपूर
रेखा मिश्र
इन्द्रनील भट्टाचार्य
स्नेहल हेरवाडकर
पंकज कुमार
तुषार बरन दास
वी. धन्या
श्वेता कुमारी
सुजाता कुंडू

संपादक
जी. वी. नथनएल

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन संपादकीय समिति के निर्देशन में आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग द्वारा मासिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है।
इसमें व्यक्त व्याख्याओं और विचारों के लिए बैंक का केंद्रीय निदेशक मंडल उत्तरदायी नहीं है।
हस्ताक्षरित आलेखों में व्यक्त विचारों के लिए लेखक स्वयं उत्तरदायी हैं।

© भारतीय रिज़र्व बैंक 2023

सर्वाधिकार सुरक्षित।
सामग्री के पुनः प्रयोग की अनुमति है,
बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया जाए।

बुलेटिन के सदस्यता शुल्क के लिए कृपया “भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के महत्त्वपूर्ण प्रकाशन” खंड देखें।

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन को इंटरनेट के माध्यम से
https://bulletin.rbi.org.in पर भी देखा जा सकता है।

विषय-वस्तु

गवर्नर का वक्तव्य

गवर्नर का वक्तव्य 1

मौद्रिक नीति वक्तव्य 2023-24

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प, 3-6 अप्रैल 2023 7

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य 11

मौद्रिक नीति रिपोर्ट

मौद्रिक नीति रिपोर्ट - अप्रैल 2023 13

भाषण

विकसित भारत के लिए एक सहायक के रूप में वित्तीय क्षेत्र

एम. राजेश्वर राव 103

आलेख

अर्थव्यवस्था की स्थिति 109

हालिया प्रतिगामी मुद्रास्फीति – भारतीय अनुभव 153

भारतीय राज्यों का पूंजी परिव्यय: इसकी भूमिका और निर्धारकों का एक तथ्यात्मक मूल्यांकन 163

औद्योगिक संबंध संहिता और श्रम उत्पादकता: एक अंतर-देशीय अधि-विश्लेषण 173

भारत में रियल्टी क्षेत्र की गतिविधि का एक समग्र संकेतक 183

वर्तमान सांख्यिकी **195**

हाल के प्रकाशन **248**

गवर्नर का वक्तव्य

गवर्नर का वक्तव्य

*गवर्नर का वक्तव्य**

शक्तिकान्त दास

वर्ष 2023 की शुरुआत एक नई आशा के साथ हुई क्योंकि आपूर्ति की स्थिति में सुधार हो रहा था, आर्थिक गतिविधि आघात-सह बनी हुई थी, वित्तीय बाज़ारों ने अधिक आशावाद का संचार किया और केंद्रीय बैंक अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आसान उतराई (सॉफ्ट लैंडिंग) की ओर ले जा रहे थे। मार्च के दौरान कुछ ही सप्ताह में, इस स्थिति में नाटकीय परिवर्तन आया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था अब कतिपय उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में बैंकिंग क्षेत्र की उथल-पुथल से नई विपरीत परिस्थितियों के साथ अशांति के एक नए चरण का सामना कर रही है। बैंक विफलताओं और संक्रामक जोखिम ने वित्तीय स्थिरता के मुद्दों को सबसे आगे ला दिया है। मुद्रास्फीति में दृढ़ता को देखते हुए, केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति में सख्ती को जारी रख रहे हैं, यद्यपि धीमी गति से। हाल के महीनों में विश्व स्तर पर मुद्रास्फीति में कमी आई है, लेकिन लक्ष्य तक इसका पहुंचाना दीर्घकालिक और कठिन प्रतीत हो रहा है।

अमेरिकी फेडरल रिज़र्व के पूर्व अध्यक्ष एलन ग्रीनस्पैन ने कहा था: "अनिश्चितता मौद्रिक नीति परिदृश्य की परिभाषित विशेषता है।"[1] उन्होंने आज की स्थिति की तुलना में बहुत अधिक संतुलन के युग में और अधिक सामान्य समय में यह बात कही थी। आज हम जो देख रहे हैं वह भू-राजनीति, आर्थिक गतिविधियों, मूल्य दबावों और वित्तीय बाज़ारों में अभूतपूर्व अनिश्चितता है जो पहले कभी नहीं देखी गई। आज के विश्व में केंद्रीय बैंकों और अन्य नीति निर्माताओं के सामने आने वाली चुनौतियों के परिमाण की कल्पना की जा सकती है।

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के निर्णय और विचार-विमर्श

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक 3, 5 और 6 अप्रैल 2023 को हुई और इसमें समष्टि आर्थिक स्थिति और इसकी संभावना का मूल्यांकन किया गया। इस बैठक में आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई हेतु तैयार रहने के साथ नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया गया। परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 6.25 प्रतिशत तथा सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 6.75 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहेंगी। एमपीसी ने 6 में से 5 सदस्यों के बहुमत से निभाव को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित रखने का भी निर्णय लिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति संवृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए उत्तरोत्तर लक्ष्य के साथ संरेखित हो। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि रेपो दर पर विराम लगाने का निर्णय केवल इसी बैठक के लिए है।

अब मैं नीतिगत दर और रुख पर इन निर्णयों के लिए एमपीसी के तर्क के बारे में बताना चाहूंगा। जबकि हाल के उच्च आवृत्ति संकेतक वैश्विक आर्थिक गतिविधि में कुछ सुधार की ओर इशारा करते हैं, संभावना अब वित्तीय स्थिरता चिंताओं के अतिरिक्त अधोगामी जोखिम के कारण कम हो गई है। हेडलाइन मुद्रास्फीति कम हो रही है लेकिन केंद्रीय बैंकों के लक्ष्यों से काफी ऊपर है। इन घटनाक्रमों ने वैश्विक वित्तीय बाज़ारों में अस्थिरता को बढ़ा दिया है, जो बॉण्ड प्रतिफल में बड़े पैमाने पर दोतरफा उतार-चढ़ाव, इक्विटी बाज़ारों में गिरावट और अमेरिकी डॉलर के सितंबर 2022 के अपने चरम स्तर से गिरावट के रूप में परिलक्षित होता है।

इस अस्थिरता के बीच, भारत में बैंकिंग और गैर-बैंकिंग वित्तीय सेवा क्षेत्र मजबूत बने हुए हैं तथा वित्तीय बाज़ार एक व्यवस्थित तरीके से विकसित हुए हैं। आर्थिक गतिविधि आघात-सह बनी हुई है और 2022-23 में वास्तविक जीडीपी संवृद्धि दर 7.0 प्रतिशत रहने की आशा है। तथापि, उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति दिसंबर 2022 से बढ़ी है, जो अनाज, दूध और फलों में कीमतों के दबाव से प्रेरित है। मूल मुद्रास्फीति उच्च बनी हुई है।

आगे देखते हुए, 2023-24 में हेडलाइन मुद्रास्फीति के कम होने का अनुमान है। मई 2022 से की गई मौद्रिक नीति कार्रवाइयों का प्रभाव अभी भी प्रणाली के माध्यम से हो रहा है। तदनुसार, एमपीसी ने उभरती मुद्रास्फीति संभावना की बारीकी से निगरानी करते हुए अब तक हुई प्रगति का आकलन करने के लिए नीतिगत दर को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया। एमपीसी अपनी

* गवर्नर का वक्तव्य - 6 अप्रैल 2023

[1] "मोनेटरी पॉलिसी अंडर अनसर्टेनिटी", जैक्सन हॉल सिम्पोजियम, व्योमिंग, 29 अगस्त 2003।

भविष्य की बैठकों में आवश्यक कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेगी।

अब तक की गई कार्रवाइयों को संक्षेप में बताने हेतु, हमने मई 2022 से पिछले 11 महीनों में नीतिगत रेपो दर को संचयी रूप से 250 बीपीएस बढ़ा दिया है। इससे पहले स्थिर दर प्रतिवर्ती रेपो की तुलना में 40 बीपीएस अधिक दर पर स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) की शुरुआत की गई थी। इस प्रकार, पिछले वर्ष अप्रैल से प्रभावी दर वृद्धि 290 बीपीएस रही है। ये वृद्धि पूरी तरह से एक दिवसीय भारित औसत मांग मुद्रा दर (डब्ल्यूएसीआर) में अंतरित हो गई है, जो मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य है, जो मार्च 2022 में दैनिक औसत 3.32 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2023 में 6.52 प्रतिशत हो गया है। अब इन दरों में वृद्धि के संचयी प्रभाव का मूल्यांकन करना आवश्यक है। इन परिस्थितियों में हमें अपने कार्यों में अत्यंत विवेकपूर्ण होना होगा। हम सदैव अत्यधिक सतर्क रहते हैं और हमने एक सुविचारित और संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है तथा आगे भी ऐसा करना जारी रखेंगे।

जब हमने संवृद्धि को समर्थन प्रदान करने के लिए फरवरी 2019 में दर में कटौती का चक्र शुरू किया था, तब सीपीआई मुद्रास्फीति लगभग 2 प्रतिशत थी[2] और नीतिगत रेपो दर 6.50 प्रतिशत थी। अब, नीतिगत दर 6.50 प्रतिशत है लेकिन मुद्रास्फीति 6.4 प्रतिशत (फरवरी 2023) है। कुल मिलाकर, मुद्रास्फीति लक्ष्य से ऊपर है और इसके मौजूदा स्तर को देखते हुए, वर्तमान नीतिगत दर को अभी भी निभावकारी माना जा सकता है। अतः, एमपीसी ने निभाव को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया।

संवृद्धि और मुद्रास्फीति का आकलन

संवृद्धि

जैसा कि पहले कहा है, भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 2022-23 में 7.0 प्रतिशत की संवृद्धि दर्ज करने की आशा है। अतः, आर्थिक गतिविधि आघात-सह बनी हुई है।

आपूर्ति पक्ष पर, 2022-23 में रबी खाद्यान्न उत्पादन में 6.2 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। पीएमआई विनिर्माण मार्च में 56.4 पर मजबूत रहा, जिसमें अनुकूल घरेलू मांग के कारण लगातार 21वें महीने विस्तार दर्ज किया गया। सेवा क्षेत्र की गतिविधि ने भारी वृद्धि हुई। पीएमआई सेवाएं मार्च में 57.8 पर विस्तार क्षेत्र में रहीं, जो अनुकूल मांग की स्थिति और नए व्यावसायिक लाभ से प्रेरित था।

2022-23 की चौथी तिमाही में समग्र मांग की स्थिति आघात-सह थी, यद्यपि निजी खपत में गिरावट के कुछ संकेत प्रतीत हुए। यात्री वाहनों की बिक्री और क्रेडिट कार्ड व्यय जैसे शहरी मांग संकेतकों ने फरवरी में मजबूत संवृद्धि दर्ज की, जबकि उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं में जनवरी में कमी आई। गैर-टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं, ट्रैक्टर और दुपहिया वाहनों की बिक्री जैसे ग्रामीण मांग संकेतकों ने मजबूत संवृद्धि दर्ज की। बुनियादी ढांचे पर व्यय पर सरकार के जोर, उच्च क्षमता उपयोग और कतिपय महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कॉर्पोरेट निवेश में बहाली के कारण निवेश गतिविधि में भारी वृद्धि दर्ज की गई।[3] 24 मार्च 2023 तक खाद्येतर बैंक ऋण में 15.4 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई। वाणिज्यिक क्षेत्र में संसाधनों का कुल प्रवाह 2022-23 के दौरान एक वर्ष पहले के 19.0 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 26.0 लाख करोड़ रुपये बढ़ गया है। फरवरी में पण्य निर्यात और गैर-तेल गैर-स्वर्ण आयात में कमी आई। सेवा निर्यात में मजबूत संवृद्धि जारी रही। वैश्विक स्तर पर और साथ ही घरेलू स्तर पर आपूर्ति श्रृंखलाएं सामान्य स्थिति की ओर वापस आ रही हैं।

आगे देखते हुए, उच्च रबी उत्पादन ने कृषि क्षेत्र और ग्रामीण मांग की संभावनाओं को आशान्वित किया है। संपर्क-गहन सेवाओं में स्थिर संवृद्धि, शहरी मांग के लिए सकारात्मक होनी चाहिए। पूंजीगत व्यय पर सरकार का ज़ोर, दीर्घावधि औसत से अधिक क्षमता उपयोग और कमोडिटी की कीमतों में नरमी से विनिर्माण और निवेश गतिविधि को बढ़ावा मिलना चाहिए। बढ़ी हुई वैश्विक विपरीत परिस्थितियों के कारण निवल बाह्य मांग में कमी जारी रह सकती है। दीर्घकालिक भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक वित्तीय बाज़ार में उतार-चढ़ाव संभावना के लिए अधोगामी जोखिम

[2] सीपीआई मुद्रास्फीति दिसंबर 2018 में 2.1 प्रतिशत और जनवरी 2019 में 2.0 प्रतिशत थी।

[3] फरवरी 2023 में इस्पात की खपत और सीमेंट उत्पादन में क्रमशः 12.5 प्रतिशत और 7.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2022-23 की तीसरी तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र में क्षमता उपयोग 74.3 प्रतिशत (74.1 प्रतिशत, मौसमी रूप से समायोजित) था, जो दीर्घावधि औसत 73.7 प्रतिशत से ऊपर था।

गवर्नर का वक्तव्य

उत्पन्न कर रहे हैं। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, 2023-24 के लिए वास्तविक जीडीपी संवृद्धि दर पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत; दूसरी तिमाही में 6.2 प्रतिशत; तीसरी तिमाही में 6.1 प्रतिशत; और चौथी तिमाही में 5.9 प्रतिशत के साथ 6.5 प्रतिशत अनुमानित है। जोखिम समान रूप से संतुलित हैं।

मुद्रास्फीति

नवंबर-दिसंबर 2022 के दौरान मुद्रास्फीति में नरमी सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति के जनवरी-फरवरी 2023 के दौरान उच्च सहन-सीमा को पार करने के साथ अस्थायी हो गई।[4] खाद्य मुद्रास्फीति में तीव्र बदलाव से हेडलाइन मुद्रास्फीति में तेजी आई क्योंकि कई वस्तुओं और सेवाओं में मूल मुद्रास्फीति उच्चतर बनी रही।

आगे देखते हुए, रिकॉर्ड रबी फसल की आशा, खाद्य कीमतों के दबाव के कम होने के मजबूत संकेत देती है। सरकार द्वारा आपूर्ति पक्ष में मध्यक्षेप के कारण मार्च में गेहूं की कीमतों में सुधार के पहले से ही प्रमाण हैं। तथापि, देश के कतिपय हिस्सों में हाल की बेमौसम बारिश के प्रभाव पर नजर रखने की आवश्यकता है। वैश्विक कमोडिटी की कीमतें एक वर्ष पहले अपने उच्च स्तर से उल्लेखनीय रूप से कम हुई हैं। जैसा कि हमारे सर्वेक्षण बताते हैं, लागत की स्थिति कुछ हद तक बेहतर हो गई है। परिवारों की मुद्रास्फीति प्रत्याशा भी कम हो गई है। ऊपर की ओर, प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियां भविष्य में मुद्रास्फीति के प्रक्षेपवक्र के लिए जोखिम हैं। मांग-आपूर्ति संतुलन और चारा लागत के दबाव के कारण दूध की कीमतें भी गर्मी के मौसम में स्थिर रहने की संभावना है। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में बढ़ती अनिश्चितता और आयातित मुद्रास्फीति के दबावों पर बारीकी से नजर रखने की आवश्यकता है। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए तथा 85 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल की वार्षिक औसत कच्चे तेल की कीमत (भारतीय समूह) और एक सामान्य मानसून की कल्पना करते हुए, सीपीआई मुद्रास्फीति पहली तिमाही में 5.1 प्रतिशत; दूसरी तिमाही में 5.4 प्रतिशत; तीसरी तिमाही में 5.4 प्रतिशत; और चौथी तिमाही में 5.2 प्रतिशत के साथ 2023-24 के लिए 5.2 प्रतिशत तक कम होने का अनुमान है। जोखिम समान रूप से संतुलित हैं।

[4] दिसंबर 2022 में 5.7 प्रतिशत के हाल के निचले स्तर से, हेडलाइन मुद्रास्फीति 80 बीपीएस बढ़कर जनवरी में 6.5 प्रतिशत और फरवरी 2023 में 6.4 प्रतिशत हो गई।

अब तक मैंने जो कुछ कहा है, उसे संक्षेप में कहता हूं। हम बहुत ही अस्थिर समय में रह रहे हैं। कुछ दिनों पहले ओपेक+ द्वारा अचानक उत्पादन में कटौती की घोषणा और इसके परिणामस्वरूप कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि इस अस्थिरता का एक और प्रमाण है। इस प्रकार समग्र संभावना गतिशील है और तेजी से विकसित हो रही है। हाल की अवधि में हमारी मौद्रिक नीति ने महामारी काल के प्रोत्साहन उपायों से गैर-विघटनकारी सामान्यीकरण का लक्ष्य रखा है। जब तक मौद्रिक नीति निर्णायक रूप से निभाव को वापस लेने की ओर बढ़ी, वित्तीय स्थितियां अर्थव्यवस्था की उत्पादक अपेक्षाओं के अनुरूप विकसित हुईं। संवृद्धि तब से व्यापक-आधारित हो गई है। एक वर्ष पहले के उच्च स्तर से महंगाई में कमी आई है; तथापि, यह अभी भी उच्च सहन स्तर से ऊपर है। 2023-24 के अनुमान मुद्रास्फीति में नरमी की ओर इशारा करते हैं, तथापि मूल या अंतर्निहित मुद्रास्फीति दबावों में दृढ़ता को देखते हुए अवस्फीति धीरे-धीरे और लंबी होने की संभावना है। इस समय, हम उभरती संभावनाओं और पिछले एक वर्ष के दौरान की गई हमारी कार्रवाइयों का व्यापक वास्तविक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पर नजर रख रहे हैं। जबकि हमने नीतिगत दर को अपरिवर्तित रखा है, यह ध्यातव्य है कि यह निर्णय आज तक उपलब्ध जानकारी के संदर्भ में समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थितियों के हमारे मूल्यांकन के आधार पर लिया गया है। हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है और मुद्रास्फीति के विरुद्ध कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक हम लक्ष्य के करीब मुद्रास्फीति में टिकाऊ गिरावट नहीं देखते हैं। हम उचित और समय पर कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। हमें विश्वास है कि हम मध्यम अवधि में मुद्रास्फीति को लक्षित दर पर लाने के लिए सही मार्ग पर हैं। जैसे-जैसे हम इस उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं, मुझे दो हज़ार वर्ष से भी पहले की कौटिल्य की बुद्धिमान सलाह याद आती है: "संपूर्ण कार्य पूर्ण होने से पूर्व आलस्य न करें।"[5]

वित्तीय स्थिरता

हालांकि मुद्रास्फीति के विरुद्ध लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, वैश्विक अर्थव्यवस्था, अब कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में बैंकिंग क्षेत्र की गतिविधियों से गंभीर वित्तीय स्थिरता चुनौतियों

[5] चाणक्य नीति, बी.के. चतुर्वेदी।

का सामना कर रही है। यह विश्व भर में नियामकों और विनियमित संस्थाओं की जिम्मेदारियों और वित्तीय प्रणाली की स्थिरता की सुरक्षा में उनकी सामूहिक भूमिका के पुनर्मूल्यांकन की मांग करता है। जबकि नियामकों को संभावित कमजोरियों की पहचान करने और सक्रिय विनियामक और पर्यवेक्षी उपाय करने की आवश्यकता है, यह विनियमित संस्थानों पर निर्भर है कि वे अपने जोखिम प्रबंधन और कॉर्पोरेट सुशासन प्रणालियों में उचित परिश्रम करें। पर्याप्त पूंजी बफर तैयार करते समय और समय-समय पर तनाव परीक्षण करते समय उन्हें परिसंपत्ति-देयता बेमेल और उनके जमा आधार के प्रोफाइल पर बारीकी से ध्यान देने की आवश्यकता है।

इसी संदर्भ में हमने, रिज़र्व बैंक में, हाल के वर्षों में समष्टि- और व्यष्टि विवेकपूर्ण उपायों पर ध्यान केंद्रित किया है ताकि वित्तीय कमजोरियों के निर्माण को रोका जा सके। हमने विनियमन और पर्यवेक्षण के प्रति विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया है और हाल के वर्षों में इन क्षेत्रों में कई कदम उठाए हैं।[6] इनमें से कुछ विनियामक उपायों को इस वक्तव्य के फुटनोट में सूचीबद्ध किया गया है।

हमारी पर्यवेक्षी प्रणाली भी हाल के वर्षों में काफी मजबूत हुई है। हमने वाणिज्यिक बैंकों, एनबीएफसी और शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए एक एकीकृत और सुसंगत पर्यवेक्षी दृष्टिकोण अपनाया है।[7] अकेले लक्षणों से निपटने के बजाय अब कमजोरियों के मूल कारण की पहचान करने पर अधिक ध्यान दिया जाता है। परिणामस्वरूप, भारतीय बैंकिंग प्रणाली, मजबूत पूंजी और तरलता की स्थिति, संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार, बेहतर लाभप्रदता के साथ बेहतर प्रावधान कवरेज के साथ मजबूत और स्वस्थ बनी हुई है।[8]

फिर भी, हम कुछ विकसित देशों में बैंकिंग क्षेत्र की उथल-पुथल पर कड़ी नजर रख रहे हैं। इस संदर्भ में, मैं एक बार फिर कौटिल्य के ज्ञान को याद करता हूं, जो आज की दुनिया के लिए भी प्रासंगिक है: “देश की समृद्धि के हित में, ….. [हमें] आपदाओं की संभावना का पूर्वाभास करने में सतर्क रहना चाहिए, टालने का प्रयास करना चाहिए इससे पहले कि वे उत्पन्न हों, जो हो रहा है उसे दूर करें, आर्थिक गतिविधियों में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करें….”।[9]

चलनिधि और वित्तीय बाजार की स्थिति

रिज़र्व बैंक चलनिधि प्रबंधन के लिए सूक्ष्म और चुस्त दृष्टिकोण अपनाना जारी रखेगा। अधिशेष चलनिधि में बड़े संतुलन के बीच, रिज़र्व बैंक ने 10 फरवरी और 10 मार्च को 14-दिवसीय परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामी (मुख्य परिचालन) और 24 मार्च 2023 को 5-दिवसीय वीआरआर नीलामी का आयोजन किया। आने वाले समय में, रिज़र्व बैंक,जब आवश्यक हो, दोतरफा परिचालनों के माध्यम से अर्थव्यवस्था की उत्पादक आवश्यकताओं को पूरा करने में लचीला बना रहेगा। हम 2023-24 के दौरान बाजार की स्थितियों को सुव्यवस्थित बनाए रखते हुए सरकार के उधार कार्यक्रम को गैर-विघटनकारी तरीके से पूरा करना भी सुनिश्चित करेंगे।

भारतीय रुपया, कैलेंडर वर्ष 2022 में एक व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ा है और 2023 में भी ऐसा ही बना रहेगा। यह घरेलू समष्टि आर्थिक आधार की ताकत और वैश्विक स्पिलओवर के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के आघात-सह को दर्शाता है। हम भारतीय रुपये की स्थिरता बनाए रखने पर सतर्क और केंद्रित हैं।

[6] इन उपायों में अन्य के अलावा लीवरेज अनुपात, चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर), निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर), बृहद एक्सपोजर फ्रेमवर्क (एलईएफ), वाणिज्यिक बैंकों में सुशासन पर दिशानिर्देश, एनबीएफसी के लिए स्केल-आधारित नियामक (एसबीआर) ढांचे का कार्यान्वयन शामिल है। प्रतिकूल प्रतिफल से बैंकों को बचाने हेतु एक बफर बनाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने बैंकों सूचित किया है कि वे निवेश उतार-चढ़ाव वाले आरक्षित निधि (आईएफआर) को व्यापार के लिए धारित (एचटीएफ़) और बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफ़एस) पोर्टफोलियो के 2 प्रतिशत के आईएफआर की वांछनीय फ्लोर के साथ निर्मित करें। इसके अलावा, पूंजी और चलनिधि की अपेक्षाएँ सभी बैंकों पर समान रूप से लागू होती हैं, भले ही उनकी संपत्ति का आकार और जोखिम कुछ भी हो।

[7] दास, शक्तिकान्त (2023), “भारत की अध्यक्षता के दौरान एक बेहतर वैश्विक आर्थिक व्यवस्था के लिए जी20”, 17वां केपी होर्मिस स्मारक व्याख्यान, 17 मार्च, t https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_SpeechesView.aspx?Id=1356 पर उपलब्ध

[8] दिसंबर 2022 के अंत तक बैंकिंग प्रणाली के लिए जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) 16.0 प्रतिशत पर आवश्यक न्यूनतम 9.0 प्रतिशत से काफी ऊपर रहा। एससीबी का चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) फरवरी 2023 में 145 प्रतिशत पर रहा, जबकि एससीबी का निवल स्थिर निधीयन अनुपात, चलनिधि के लिए दीर्घकालिक उपाय, 100 प्रतिशत की न्यूनतम नियामक आवश्यकता से काफी ऊपर है। दिसंबर 2022 में बैंकिंग प्रणाली का निवल एनपीए 1.2 प्रतिशत था।

[9] स्त्रोत: एल.एन. रंगराजन द्वारा संपादित अर्थशास्त्र, कौटिल्य,

बाहरी क्षेत्र

2022-23 की पहली तीन तिमाहियों के लिए चालू खाता घाटा (सीएडी) सकल घरेलू उत्पाद का 2.7 प्रतिशत रहा। तीसरी तिमाही में, सीएडी दूसरी तिमाही में 3.7 प्रतिशत से काफी कम होकर 2.2 प्रतिशत हो गया, जिसका कारण पण्य व्यापार घाटा कम होना और सेवा निर्यात में मजबूत वृद्धि है। वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) में वृद्धि द्वारा समर्थित आईटी सेवाओं, कारोबार प्रणाली प्रबंधन (बीपीएम), और इंजीनियरिंग अनुसंधान और डिजाइन (ईआर एंड डी) जैसे प्रमुख कार्यक्षेत्रों में मजबूत सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में वृद्धि देखी गई।

आयात में निरंतर गिरावट के कारण, पण्य व्यापार घाटा, 2022-23 की तीसरी तिमाही के स्तर से जनवरी और फरवरी 2023 के दौरान और कम हो गया। इसके अलावा, 2023 के पहले दो महीनों में भारत का सेवा निर्यात स्वस्थ गति से बढ़ता रहा। खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) देशों की बेहतर संवृद्धि संभावनाओं से विप्रेषण के मजबूत रहने की उम्मीद है। वास्तव में, आवक सकल विप्रेषण, कैलेंडर वर्ष 2022 के दौरान 107.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर को छू गया। चालू खाता घाटा(सीएडी) 2022-23 की चौथी तिमाही और वर्ष 2023-24 में एक ऐसे स्तर पर मध्यम रहने की उम्मीद है जो व्यवहार्य और प्रबंधनीय दोनों है।

कुल मिलाकर, हमारे बाहरी क्षेत्र के संकेतकों में काफी सुधार हुआ है। 21 अक्तूबर 2022 को विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि का 524.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से पलटाव हुआ है और अब हमारी अग्रिम परिसंपत्तियों को ध्यान में रखते हुए 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है।

अतिरिक्त उपाय

अब मैं कुछ अतिरिक्त उपायों की घोषणा करूंगा।

एक तटीय (ऑनशोर) गैर- प्रदेय (नॉन-डिलीवरेबल) व्युत्पन्नी बाज़ार विकसित करना

भारत में आईएफ़एससी बैंकिंग इकाइयों (आईबीयू) वाले बैंकों को पहले अनिवासियों और आईबीयू वाले अन्य पात्र बैंकों के साथ भारतीय रुपया (आईएनआर) गैर- प्रदेय विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदा (एनडीडीसी) में लेनदेन करने की अनुमति थी। अब आईबीयू वाले बैंकों को तटीय बाज़ार में निवासी उपयोगकर्ताओं को आईएनआर से जुड़े एनडीडीसी प्रदान करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है। यह उपाय भारत में विदेशी मुद्रा बाज़ार को और गहरा करेगा और निवासियों को उनकी हेजिंग आवश्यकताओं को पूरा करने में अधिक लचीलापन प्रदान करेगा।

विनियामक प्रक्रियाओं की दक्षता बढ़ाना

वर्तमान में, संस्थाओं के लिए विभिन्न कानूनों/विनियमों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक से लाइसेंस/प्राधिकरण या विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से होती है। ऐसी प्रक्रियाओं को सरल और सुव्यवस्थित करने के लिए और केंद्रीय बजट 2023-24 की घोषणा के अनुरूप, ऐसी प्रक्रियाओं के लिए 'PRAVAAH' (विनियामक आवेदन, सत्यापन और प्राधिकरण के लिए मंच) नामक एक सुरक्षित वेब आधारित केंद्रीकृत पोर्टल बनाने का निर्णय लिया गया है। पोर्टल मांगे गए आवेदनों/अनुमोदनों पर निर्णय लेने की समय-सीमा दिखाएगा। यह उपाय विनियामक प्रक्रियाओं में अधिक दक्षता लाएगा और रिज़र्व बैंक की विनियमित संस्थाओं के लिए व्यापार करने में आसानी की सुविधा प्रदान करेगा।

दावारहित जमाराशियों को खोजने हेतु जनता के लिए केंद्रीकृत वेब पोर्टल विकसित करना

वर्तमान में, जमाकर्ताओं या लाभार्थियों को 10 वर्ष या उससे अधिक की दावारहित बैंक जमाराशियों का पता लगाने के लिए कई बैंकों की वेबसाइटों के माध्यम से जाना पड़ता है। अब, ऐसी अदावी जमाराशियों के बारे में सूचना तक जमाकर्ताओं/लाभार्थियों की पहुंच में सुधार लाने और उनका विस्तार करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि एक वेब पोर्टल विकसित किया जाए ताकि संभावित अदावी जमाराशियों के लिए कई बैंकों में खोज की जा सके। इससे जमाकर्ताओं/लाभार्थियों को अदावी जमाराशि वापस पाने में मदद मिलेगी।

साख संस्थाओं द्वारा साख सूचना रिपोर्टिंग तथा साख सूचना कंपनियों द्वारा प्रदान की गई साख जानकारी से संबंधित शिकायत निवारण तंत्र

हाल ही में, साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) को रिज़र्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना (आरबी-आईओएस) के दायरे में

गवर्नर का वक्तव्य

लाया गया था। अब निम्नलिखित उपायों को लागू करने का प्रस्ताव है: (i) साख सूचना रिपोर्ट के अद्यतन/सुधार में विलंब के लिए एक मुआवजा तंत्र; (ii) ग्राहकों को एसएमएस/ईमेल अलर्ट का प्रावधान जब भी उनकी साख सूचना रिपोर्ट को एक्सैस किया जाते हैं; (iii) साख संस्थाओं से सीआईसी द्वारा प्राप्त आंकड़ों को शामिल करने की समय-सीमा; और (iv) सीआईसी द्वारा प्राप्त ग्राहक शिकायतों पर प्रकटीकरण। ये उपाय उपभोक्ता संरक्षण को और बढ़ाएंगे।

यूपीआई के माध्यम से बैंकों में पूर्व-स्वीकृत ऋण व्यवस्था का परिचालन

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) ने भारत में खुदरा भुगतान को बदल दिया है। समय-समय पर नए उत्पादों और सुविधाओं को विकसित करने के लिए यूपीआई की सुदृढ़ता का उपयोग किया गया है। हाल ही में रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करने की अनुमति दी गई थी। यह जमा खातों के साथ यूपीआई को जोड़ने की मौजूदा सुविधा के अतिरिक्त था। अब यूपीआई के माध्यम से बैंकों में पूर्व-स्वीकृत ऋण व्यवस्थाओं के परिचालन की अनुमति देकर यूपीआई के दायरे का विस्तार करने का प्रस्ताव है। इस पहल से नवाचार को और बढ़ावा मिलेगा।

निष्कर्ष

2020 की शुरुआत से ही विश्व अत्यधिक अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में, भारत का वित्तीय क्षेत्र आघात-सहनीय और स्थिर बना हुआ है। कुल मिलाकर, आर्थिक गतिविधियों का विस्तार; मुद्रास्फीति में अपेक्षित कमी; पूंजीगत व्यय पर ध्यान देते हुए राजकोषीय समेकन; चालू खाते के घाटे को अधिक टिकाऊ स्तरों तक काफी हद तक कम करना; और विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि का सहज स्तर एक प्रशंसनीय घटनाक्रम हैं, जो भारत की समष्टि-आर्थिक स्थिरता को और मजबूत करेगा। यह मौद्रिक नीति को मुद्रास्फीति पर दृढ़तापूर्वक केंद्रित रहने की अनुमति देता है। अडिग मूल मुद्रास्फीति के साथ, हम मूल्य स्थिरता को बनाए रखने में दृढ़ और अटल बने हुए हैं जो सतत संवृद्धि के लिए सर्वोत्तम गारंटी है। पिछले 12 महीनों में हमारी कार्रवाइयों का असर अब भी दिख रहा है और यह भावी मुद्रास्फीति प्रक्षेपवक्र को अत्यधिक प्रभावित करेगा। जैसा कि मैंने पिछले वर्ष अप्रैल में अपने नीतिगत वक्तव्य में उल्लेख किया था, मूल्य स्थिरता, सतत संवृद्धि और वित्तीय स्थिरता के हमारे लक्ष्य पारस्परिक रूप से सुदृढ़ बने हुए हैं और हम इस दृष्टिकोण से निर्देशित होते रहेंगे। हम मूल्य और वित्तीय स्थिरता के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ चुनौतियों का सामना करने के लिए सतर्क और तैयार रहते हैं। महात्मा गांधी ने जो कहा था, उससे हम प्रेरित हैं: "... अटूट दृढ़ता और धैर्य से... कोई हार नहीं सकता।"[10]

धन्यवाद। नमस्कार।

[10] महात्मा, वॉल्यूम। 4., डी. जी. तेंदुलकर द्वारा

मौद्रिक नीति वक्तव्य 2023-24

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 3-6 अप्रैल 2023

*मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2023-24 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प**

वर्तमान और उभरती समष्टि-आर्थिक परिस्थिति का आकलन करने के आधार पर मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (6 अप्रैल 2023) अपनी बैठक में यह निर्णय लिया है कि:

- चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए।

स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 6.25 प्रतिशत तथा सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 6.75 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बनी हुई है।

- एमपीसी ने निभाव को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित रखने का भी निर्णय लिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति उतरोत्तर संवृद्धि को समर्थन प्रदान करते हुए लक्ष्य के साथ संरेखित हो।

ये निर्णय, संवृद्धि को समर्थन प्रदान करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति को +/- 2 प्रतिशत के दायरे में रखते हुए 4 प्रतिशत का मध्यावधि लक्ष्य हासिल करने के अनुरूप है।

इस निर्णय में अंतर्निहित मुख्य विचार नीचे दिए गए विवरण में व्यक्त किए गए हैं।

आकलन

वैश्विक अर्थव्यवस्था

2. उच्च स्तर पर मुद्रास्फीति के बने रहने, कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) की बैंकिंग प्रणाली में उथल-पुथल, तंग वित्तीय स्थितियों और दीर्घकालिक भू-राजनीतिक युद्ध स्थिति के बीच वैश्विक आर्थिक गतिविधि आघात-सहनीय बनी हुई है। हाल की वित्तीय स्थिरता संबंधी चिंताओं ने जोखिम से बचने, सुरक्षित बने रहने को प्रेरित किया है और वित्तीय बाजार में अस्थिरता को बढ़ा दिया है। आक्रामक मौद्रिक रुख और संचार पर फरवरी में तेज वृद्धि को उलटते हुए, सुरक्षित आश्रय की मांग पर सॉवरेन बांड प्रतिफल में मार्च में तेज गिरावट आई। एमपीसी की पिछली बैठक के बाद से इक्विटी बाजारों में गिरावट आई है और अमेरिकी डॉलर ने अपने लाभ को कम कर दिया है। कमजोर बाहरी मांग, कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में बैंकिंग संकट से स्पिलओवर, अस्थिर पूंजी प्रवाह और कुछ कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में ऋण संकट, संवृद्धि की संभावनाओं पर दबाव डालते हैं।

घरेलू अर्थव्यवस्था

3. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा 28 फरवरी 2023 को जारी दूसरे अग्रिम अनुमान (एसएई) में 2022-23 में भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर को 7.0 प्रतिशत रखा गया है। निजी खपत और सार्वजनिक निवेश, संवृद्धि के प्रमुख चालक थे।

4. चौथी तिमाही में आर्थिक गतिविधि आघात-सहनीय बनी रही। रबी खाद्यान्न उत्पादन 2022-23 में 6.2 प्रतिशत तक बढ़ सकती है। जनवरी में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में 5.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि आठ प्रमुख उद्योगों का उत्पादन जनवरी में 8.9 प्रतिशत और फरवरी में 6.0 प्रतिशत की तेजी से बढ़ा, जो औद्योगिक गतिविधि की क्षमता का संकेत देती है। सेवा क्षेत्र में, घरेलू हवाई यात्री यातायात, बंदरगाह माल-भाड़ा यातायात, ई-वे बिल और टोल संग्रह ने चौथी तिमाही में बेहतर वृद्धि दर्ज की, जबकि रेलवे माल-भाड़ा यातायात में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। क्रय प्रबंधकों के सूचकांक (पीएमआई) ने मार्च में विनिर्माण और सेवाओं दोनों में सतत वृद्धि का संकेत दिया।

5. शहरी मांग संकेतकों में, यात्री वाहनों की बिक्री में फरवरी में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई, जबकि जनवरी में टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री में कमी आई। ग्रामीण मांग संकेतकों में, फरवरी में ट्रैक्टर और दोपहिया वाहनों की बिक्री मजबूत रही। जहां तक निवेश गतिविधि का संबंध है, फरवरी में इस्पात की खपत और सीमेंट उत्पादन की वृद्धि में तेजी आई। पण्य निर्यात और तेल से इतर स्वर्ण से इतर आयात फरवरी में संकुचित हुए जबकि सेवा निर्यात में मजबूत वृद्धि जारी रही।

* 6 अप्रैल 2023 को जारी।

6. अनाज, दूध और फलों में उच्च मुद्रास्फीति और सब्जियों की कीमतों में धीमी अवस्फीति के कारण सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति दिसंबर 2022 में 5.7 प्रतिशत से बढ़कर फरवरी 2023 में 6.4 प्रतिशत हो गई। ईंधन मुद्रास्फीति उच्च बनी रही, हालांकि मिट्टी के तेल (पीडीएस) की कीमतों में गिरावट और अनुकूल आधार प्रभावों के कारण फरवरी में कुछ नरमी देखी गई थी। मूल मुद्रास्फीति (अर्थात्, खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई) उच्च बनी रही और यह जनवरी-फरवरी में 6 प्रतिशत से ऊपर थी। कपड़े और जूते, तथा परिवहन और संचार की मुद्रास्फीति में देखी गई कमी, व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव तथा आवास में मुद्रास्फीति में तेजी से काफी हद तक ऑफसेट हुई।

7. एलएएफ के अंतर्गत औसत दैनिक अवशोषण दिसंबर-जनवरी में औसतन ₹1.6 लाख करोड़ से घटकर फरवरी-मार्च के दौरान ₹1.4 लाख करोड़ हो गया। 2022-23 के दौरान, मुद्रा आपूर्ति (एम3) में 9.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई और खाद्य से इतर बैंक ऋण में 15.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 31 मार्च 2023 तक भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि 578.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

संभावना

8. 2023-24 में मुद्रास्फीति की गति को घरेलू और वैश्विक दोनों कारकों द्वारा आकार दिया जाएगा। रिकॉर्ड रबी खाद्यान्न उत्पादन की उम्मीद, खाद्य कीमतों की संभावना के लिए अच्छा संकेत है। हालांकि, हाल की बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के प्रभाव पर नजर रखने की जरूरत है। उच्च लागत और मौसमी कारकों के कारण दूध की कीमतें स्थिर रह सकती हैं। कच्चे तेल की कीमतों की संभावना उच्च अनिश्चित बनी हुई है। आयातित मुद्रास्फीति जोखिमों की संभावित बढ़ोत्तरी के कारण वैश्विक वित्तीय बाजार में अस्थिरता बढ़ी है। रिज़र्व बैंक के उद्यम सर्वेक्षणों के अनुसार, लागत में कमी की स्थिति, विनिर्माण और सेवाओं के उत्पादन मूल्य वृद्धि की गति में कुछ कमी ला रही है। तथापि, इनपुट लागतों का विलंबित प्रभाव अंतरण मूल मुद्रास्फीति को बढ़ाए रख सकता है। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए तथा 85 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल की वार्षिक औसत कच्चे तेल की कीमत (भारतीय टोकरी) और सामान्य मानसून की आशा करते हुए, सीपीआई मुद्रास्फीति 2023-24 के लिए 5.2 प्रतिशत पर अनुमानित है, जोकि पहली तिमाही में 5.1 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 5.4 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 5.4 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 5.2 प्रतिशत और जोखिम समान रूप से संतुलित रहना अनुमानित है (चार्ट 1)।

9. एक अच्छी रबी फसल से ग्रामीण मांग मजबूत होनी चाहिए, जबकि संपर्क-गहन सेवाओं में निरंतर उछाल से शहरी मांग को समर्थन मिलना चाहिए। विनिर्माण में क्षमता उपयोग की प्रवृत्ति से ऊपर पूंजीगत व्यय पर सरकार का जोर, दोहरे अंकों की ऋण वृद्धि और कमोडिटी की कीमतों में कमी से विनिर्माण और निवेश गतिविधि को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। भारतीय रिज़र्व बैंक के सर्वेक्षणों के अनुसार, व्यवसाय और उपभोक्ता भविष्य की संभावना को लेकर आशान्वित हैं। धीमे वैश्विक व्यापार और उत्पादन को देखते हुए, विलंबित बाह्य मांग में वृद्धि हो सकती है। दीर्घकालिक भू-राजनीतिक तनाव, तंग वैश्विक वित्तीय स्थिति और वैश्विक वित्तीय बाजार में अस्थिरता से संभावना के लिए जोखिम उत्पन्न हो सकता है। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, 2023-24 के लिए वास्तविक जीडीपी संवृद्धि 6.5 प्रतिशत अनुमानित है; जोकि जोखिम में समान रूप से संतुलन के साथ पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 6.2 प्रतिशत; तीसरी तिमाही में 6.1 प्रतिशत; और चौथी तिमाही में 5.9 प्रतिशत रहना अनुमानित है (चार्ट 2)।

10. सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति के लगातार सहन-सीमा बैंड के ऊपर रहने के कारण, एमपीसी ने लक्ष्य के साथ मुद्रास्फीति को संरेखित करने पर दृढ़ता से ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। मूल्य दबावों के सामान्यीकरण को नियंत्रित करना और मुद्रास्फीति की उम्मीदों को स्थिर करना आवश्यक है। घरेलू आर्थिक गतिविधि में आघात-सहनीयता को बनाए रखने के लिए न्यून एवं स्थिर कीमतों का वातावरण आवश्यक है। हालांकि, मई 2022 से नीति दर में संचयी रूप से 250 आधार अंकों की वृद्धि की गई है, जो अभी भी सिस्टम के माध्यम से काम कर रही है, लेकिन फिर भी मूल्य स्थिरता पर अपनी तैयारी में किसी भी प्रकार की ढिलाइ नहीं बरत सकते हैं। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, एमपीसी ने इस बैठक में नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया, साथ ही, यदि आवश्यक हो तो कार्रवाई करने के लिए तैयार है। एमपीसी उभरती मुद्रास्फीति और संवृद्धि की संभावना पर कड़ी निगरानी रखना जारी रखेगी और भावी बैठकों में आवश्यक कार्रवाई करने में

चार्ट 1 : सीपीआई मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष) का तिमाही पूर्वानुमान

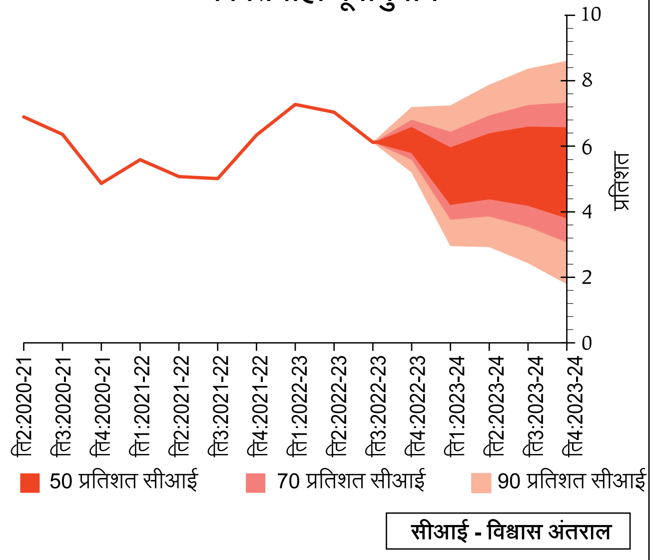

चार्ट 2 : वास्तविक जीडीपी संवृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) का तिमाही पूर्वानुमान

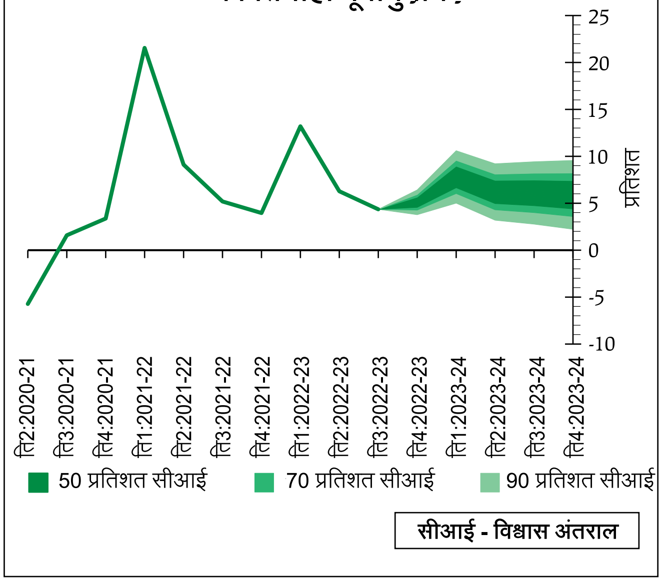

संकोच नहीं करेगी। एमपीसी ने निभाव को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित रखने का भी निर्णय लिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति उतरोत्तर संवृद्धि को समर्थन प्रदान करते हुए लक्ष्य के साथ संरेखित हो।

11. एमपीसी के सभी सदस्य - डॉ. शशांक भिड़े, डॉ. आशिमा गोयल, प्रो. जयंत आर. वर्मा, डॉ. राजीव रंजन, डॉ. माइकल देवब्रत पात्र और श्री शक्तिकान्त दास ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने के लिए वोट किया।

12. डॉ. शशांक भिड़े, डॉ. आशिमा गोयल, डॉ. राजीव रंजन, डॉ. माइकल देवब्रत पात्र और श्री शक्तिकान्त दास ने निभाव को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित रखने के लिए वोट किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति उतरोत्तर संवृद्धि को समर्थन प्रदान करते हुए लक्ष्य के साथ संरेखित हो। प्रो. जयंत आर. वर्मा ने संकल्प के इस हिस्से पर आपत्ति जताई।

13. एमपीसी की बैठक का कार्यवृत्त 20 अप्रैल 2023 को प्रकाशित किया जाएगा।

14. एमपीसी की अगली बैठक 6-8 जून 2023 के दौरान निर्धारित है।

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

यह वक्तव्य (i) वित्तीय बाजारों; (ii) विनियमन और पर्यवेक्षण; और (iii) भुगतान और निपटान प्रणाली से संबंधित विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीतिगत उपायों को निर्धारित करता है।

I. वित्तीय बाजार

1. एक तटीय (ऑनशोर) गैर- प्रदेय (नॉन-डिलीवरेबल) व्युत्पन्नी बाज़ार विकसित करना

भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफ़एससी) बैंकिंग इकाइयों (आईबीयू) का परिचालन करने वाले बैंकों को 1 जून 2020 से अनिवासियों और एक दूसरे के साथ भारतीय रुपया (आईएनआर) गैर- प्रदेय विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदा (एनडीडीसी) में लेनदेन करने की अनुमति दी गई थी। तटीय आईएनआर एनडीडीसी को विकसित करने और निवासियों को उनके हेजिंग कार्यक्रमों को कुशलतापूर्वक डिज़ाइन करने की सुविधा प्रदान करने हेतु, यह निर्णय लिया गया है कि आईबीयू वाले बैंकों को तटीय बाज़ार में निवासी उपयोगकर्ताओं को आईएनआर एनडीडीसी प्रदान करने की अनुमति दी जाए। इन बैंकों के पास अपने एनडीडीसी लेनदेन को अनिवासियों के साथ और एक दूसरे के साथ विदेशी मुद्रा या आईएनआर में निपटान की सुविधा होगी, जबकि निवासियों के साथ लेनदेन का निपटान अनिवार्य रूप से आईएनआर में होगा। संबंधित दिशा-निर्देश अलग से जारी किए जा रहे हैं।

II. विनियमन और पर्यवेक्षण

2. विनियामक प्रक्रियाओं की दक्षता बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित गतिविधियों को करने के लिए विभिन्न संस्थाओं को लाइसेंस/ प्राधिकरण प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, विनियमित संस्थाओं को समय-समय पर विभिन्न संविधियों/ विनियमों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक से कतिपय विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। वर्तमान में, इसके लिए आवेदन और अनुमोदन की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से होती है। 2023-24 के केंद्रीय बजट में विभिन्न विनियमों के अंतर्गत आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए निर्धारित समय- सीमा के भीतर वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों द्वारा अनुपालन की लागत को सरल, आसान और कम करने की अपेक्षा की घोषणा की गई है। अतः, यह निर्णय लिया गया है कि ‘PRAVAAH’ (विनियामक आवेदन, सत्यापन और प्राधिकरण के लिए मंच) नामक एक सुरक्षित वेब आधारित केंद्रीकृत पोर्टल विकसित किया जाए, जो उत्तरोत्तर सभी कार्यों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को आवेदन प्रस्तुत किए जाने हेतु लागू होगा।

3. अदावी जमाराशियों को खोजने के लिए जनता के लिए केंद्रीकृत वेब पोर्टल विकसित करना

किसी बैंक में 10 वर्षों तक अदावी जमाराशि को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुरक्षित “जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता” (डीईए) निधि में अंतरित कर दिया जाता है। चूंकि जमाकर्ताओं का संरक्षण एक व्यापक उद्देश्य है, भारतीय रिज़र्व बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय कर रहा है कि नई जमाराशियाँ अदावी न हों और उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद वर्तमान अदावी जमाराशि सही मालिक या लाभार्थियों को वापस कर दी जाएं। दूसरे पहलू पर, बैंक अदावी जमाराशियों की सूची अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करते हैं। ऐसे आंकड़ों तक जमाकर्ताओं/ लाभार्थियों की पहुंच में सुधार और विस्तार करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक वेब पोर्टल विकसित करने का निर्णय लिया है ताकि उपयोगकर्ता इनपुट के आधार पर संभावित अदावी जमाराशि के लिए कई बैंकों में खोज की जा सके। कुछ एआई उपकरणों के उपयोग से खोज परिणामों में सुधार आएगा।

4. साख संस्थाओं द्वारा साख सूचना रिपोर्टिंग तथा साख सूचना कंपनियों द्वारा प्रदान की गई साख सूचना से संबंधित शिकायत निवारण तंत्र

साख सूचना रिपोर्टिंग और साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) के कामकाज के संबंध में ग्राहकों की शिकायतों में वृद्धि के कारण, यह निर्णय लिया गया है कि साख संस्थानों (सीआई) और सीआईसी द्वारा प्रदान की जाने वाली शिकायत निवारण तंत्र और ग्राहक सेवा की प्रभावकारिता को मजबूत करने और सुधारने के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार किया जाए। इस प्रयोजन के लिए, सीआईसी को रिज़र्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना (आरबी-आईओएस) के तत्वावधान में लाया गया है। इसके अलावा, निम्नलिखित उपायों को लागू करने का भी प्रस्ताव है: साख सूचना के अद्यतन/सुधार में विलंब के लिए एक मुआवजा तंत्र; ग्राहकों को एसएमएस/ईमेल अलर्ट का प्रावधान जब भी

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

उनकी साख सूचना को सीआईसी से एक्सेस किए जाते हैं; साख संस्थाओं से सीआईसी द्वारा प्राप्त आंकड़ों को शामिल करने की समय-सीमा; और सीआईसी की वेबसाइट पर प्राप्त ग्राहक शिकायतों की संख्या और प्रकृति से संबंधित प्रकटीकरण। इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश शीघ्र ही जारी किए जाएंगे।

III. भुगतान और निपटान प्रणाली

5. यूपीआई के माध्यम से बैंकों में पूर्व-स्वीकृत ऋण व्यवस्था का संचालन

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) एक सुदृढ़ भुगतान प्लेटफॉर्म है जिसमें कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। वर्तमान में भारत में डिजिटल भुगतान का 75% भुगतान इसके माध्यम से किया जाता है। भारत के भुगतान डिजिटलीकरण लक्ष्यों के अनुरूप उत्पादों और सुविधाओं को विकसित करने के लिए यूपीआई प्रणाली का उपयोग किया गया है। हाल ही में, रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करने की अनुमति दी गई थी। वर्तमान में, यूपीआई लेनदेन बैंकों में जमा खातों के बीच किए जाते हैं, कभी-कभी वॉलेट सहित प्री-पेड उपकरणों द्वारा मध्यस्थता की जाती है। अब जमा खातों के अलावा, बैंकों में पूर्व-स्वीकृत ऋण व्यवस्थाओं को/से अंतरण को सक्षम करके यूपीआई के दायरे का विस्तार करने का प्रस्ताव है। दूसरे शब्दों में, यूपीआई नेटवर्क बैंकों से ऋण द्वारा वित्तपोषित भुगतान की सुविधा प्रदान करेगा। यह इस तरह की व्यवस्थाओं की लागत को कम कर सकता है और भारतीय बाजारों के लिए विशिष्ट उत्पादों के विकास में मदद कर सकता है।

इस संबंध में विस्तृत अनुदेश अलग से जारी किए जाएंगे।

मौद्रिक नीति रिपोर्ट 2023-24

मौद्रिक नीति रिपोर्ट - अप्रैल 2023

I. समष्टि-आर्थिक दृष्टिकोण

धीमी होती वैश्विक अर्थव्यवस्था में घरेलू आर्थिक गतिविधि लचीली बनी हुई है। मुद्रास्फीति पूरे विश्व में और भारत में ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति को प्रगतिशील रूप से लक्ष्य के अनुरूप बनाने पर केंद्रित रहती है। भू-राजनीतिक शत्रुता, अस्थिर वैश्विक वित्तीय बाजार और जलवायु झटके संवृद्धि और मुद्रास्फीति दृष्टिकोण के लिए प्रमुख जोखिम हैं।

I.1 सितंबर 2022 एमपीआर से अब तक के प्रमुख घटनाक्रम

सितंबर 2022 की मौद्रिक नीति रिपोर्ट (एमपीआर) जारी होने के बाद से, भिन्न-भिन्न अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति ऊंचे स्तर पर कायम रहने, भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं निरंतर बने रहने और वित्तीय स्थितियां सख्त होने की वजह से वैश्विक आर्थिक गतिविधियों पर उनका असर पड़ रहा है। अधिकांश केंद्रीय बैंकों ने सख्ती बरतना जारी रखा है। वित्तीय बाजार अस्थिर और आने वाली जानकारी के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो गए हैं। मौद्रिक नीति में ब्याज दरों में अल्प वृद्धि की आशा में नवंबर-दिसंबर के दौरान सरकारी बॉण्ड प्रतिफल में कमी आई, लेकिन फरवरी के दौरान उम्मीद से अधिक जोरदार आर्थिक गतिविधियों और कीमतों का लगातार दबाव पड़ने की वजह से इसमें तेजी आई। अमेरिकी अल्पावधि बॉण्ड प्रतिफल मार्च की शुरुआत में डेढ़ दशक में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। इक्विटी बाजारों ने कुछ हद तक वापसी की। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतें युद्ध पूर्व के स्तर पर आ गई हैं, लेकिन धातु की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। वैश्विक स्तर पर, हाल के महीनों में आपूर्ति की स्थिति में सुधार हुआ है। यूएस और यूरोप में बैंकिंग संकट और उसके साथ वित्तीय स्थिरता की चिंताओं ने मार्च में वैश्विक वित्तीय बाजारों को परेशान किया। जोखिम से बचने की प्रवृत्ति बढ़ने से महफ़ूज़ रहने की होड़ शुरू हो गई और मौद्रिक सख्ती का सिलसिला जल्द उलटने की उम्मीदों की वजह से भिन्न-भिन्न परिपक्वता अवधि में सरकारी बॉण्ड प्रतिफल में तेज गिरावट आई, इक्विटी कीमतों में सुधार हुआ और बाजार में उतार-चढ़ाव संकेतकों में उछाल आया। यूएस डॉलर सितंबर 2022 के अपने उच्च स्तर से असमान रूप से पीछे हट गया है।

घरेलू आर्थिक गतिविधियों ने 2022-23 की दूसरी छमाही में सुदृढ़ता प्रदर्शित की। राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) के दूसरे अग्रिम अनुमान में 2022-23 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 7.0 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है, जिसकी मुख्य वजह निजी खपत और निवेश है। तीसरी तिमाही में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 4.4 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष, व-द-व) थी, जो निवेश मांग की बदौलत बढ़ी जबकि निजी खपत में कमी आई। आपूर्ति पक्ष को देखें तो, कृषि और सेवा क्षेत्रों द्वारा गतिविधि को समर्थन दिया गया, जबकि उच्च इनपुट लागत के दबाव में विनिर्माण को रोक दिया गया।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति 2022-23 के दौरान उच्च स्तर पर बनी रही, जो कई विपरीत आपूर्ति संबंधी झटकों और उच्च इनपुट लागतों का निरंतर असर पड़ने से प्रभावित थी। खाद्य पदार्थों की कीमतों में सामान्य से अधिक मजबूत मौसमी सुधार के साथ नवंबर-दिसंबर के दौरान सहनशीलता बैंड में कुछ समय के लिए प्रवेश करते हुए, खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ने के कारण फरवरी में यह फिर से बढ़कर 6.4 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) हो गई। मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने मई 2022-फरवरी 2023 के दौरान नीतिगत रेपो दर में 250 आधार अंकों (बीपीएस) की वृद्धि की और मौद्रिक नीति विकास का समर्थन करते हुए मुद्रास्फीति को प्रगतिशील रूप से लक्ष्य के अनुरूप करने पर केंद्रित रही।

मौद्रिक नीति समिति : सितंबर 2022-मार्च 2023

सितंबर 2022 में आयोजित एमपीसी की बैठक के समय अगस्त में सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति 7.0 प्रतिशत थी। 2022-23 की पहली तिमाही में दो अंकों की जीडीपी वृद्धि के साथ त्योहार के मौसम से पहले घरेलू आर्थिक गतिविधि जोर पकड़ रही थी। सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति 2022-23[1] की पहली तीन तिमाहियों के दौरान 6 प्रतिशत के ऊपरी सहनशीलता स्तर से ऊपर बने रहने का अनुमान लगाया गया था। एमपीसी ने महसूस किया कि मुद्रास्फीति संबंधी प्रत्याशाओं को दृढ़पूर्वक बनाए रखने, मूल्य दबाव के विस्तार को रोकने

[1] जीडीपी वृद्धि के अनुमान को 20 बीपीएस घटाकर 7.0 प्रतिशत (अगस्त 2022 के अनुमानों के सापेक्ष) कर दिया गया जबकि मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान को 2022-23 के लिए 6.7 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया। एमपीसी की दिसंबर 2022 की बैठक में जीडीपी वृद्धि के अनुमान को संशोधित कर 6.8 प्रतिशत और फरवरी 2023 की बैठक में मुद्रास्फीति के अनुमान को संशोधित कर 6.5 प्रतिशत कर दिया गया।

और दूसरे दौर के प्रभावों को पहले ही काबू में करने के लिए आगे सुविचारित मौद्रिक नीतिगत कार्रवाई आवश्यक थी। तदनुसार, एमपीसी ने 5-1 वोट के साथ नीतिगत रेपो दर को 50 बीपीएस बढ़ाकर 5.9 प्रतिशत कर दिया। एक सदस्य ने 35 बीपीएस की अल्प वृद्धि के पक्ष में मतदान किया। एमपीसी ने 5-1 के बहुमत से यह भी तय किया कि निभावकारी रुख को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित किया जाए ताकि विकास का समर्थन करते हुए यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति आगे चलकर लक्ष्य के भीतर बनी रहे।

दिसंबर 2022 की बैठक[2] के समय, एमपीसी ने ध्यान दिया कि अक्टूबर में सीपीआई मुद्रास्फीति का आंकड़ा सहनशीलता बैंड से ऊपर बना हुआ था। वास्तविक जीडीपी ने 2022-23 की दूसरी तिमाही में 6.3 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि दर्ज की। एमपीसी ने कहा कि 2023-24 की पहली छमाही में हेडलाइन मुद्रास्फीति में नरमी आने की संभावना है, फिर भी यह लक्ष्य से काफी ऊपर रहेगी। आर्थिक गतिविधियां अच्छी रही थीं और सुदृढ़ बने रहने की उम्मीद है। किए गए मौद्रिक नीतिगत उपायों के प्रभाव की सावधानीपूर्वक निगरानी किए जाने की आवश्यकता है। इस पृष्ठभूमि में, एमपीसी ने 5-1 वोट के साथ नीतिगत रेपो दर को 35 बीपीएस बढ़ाकर 6.25 प्रतिशत कर दिया और 4-2 के बहुमत से निभावकारी रुख को वापस लेने के अपने रुख को जारी रखा।

फरवरी 2023 की बैठक से पहले, सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति दिसंबर 2022 में घटकर 5.7 प्रतिशत हो गई थी, जो सब्जियों की कीमतों में मजबूत अपस्फीति की बदौलत थी, भले ही स्फीतिकारी दबाव अन्य खाद्य वस्तुओं और मुख्य श्रेणी में बढ़ गया हो। केंद्रीय बजट 2023-24 में पूंजी और इन्फ्रास्ट्रक्चर संबंधी खर्च पर ध्यान केंद्रित करने से घरेलू आर्थिक गतिविधि के बने रहने की उम्मीद है। सब्जियों की कीमतों में गिरावट के कारण मुद्रास्फीति में अस्थायी राहत से परे, एमपीसी ने मुद्रास्फीति को दृष्टिकोण के लिए एक प्रमुख जोखिम के रूप में माना और पाया कि मुद्रास्फीति की उम्मीदों को दृढ़पूर्वक बनाए रखने, मुख्य मुद्रास्फीति की दृढ़ता को तोड़ने और इस तरह मध्यम अवधि की विकास संभावनाओं को मजबूत करने के लिए आगे सुविचारित मौद्रिक नीतिगत कार्रवाई की आवश्यकता है। तदनुसार, एमपीसी ने नीतिगत रेपो दर को 25 बीपीएस बढ़ाकर 6.50 प्रतिशत कर दिया और वह दर कार्रवाई तथा रुख संबंधी निर्णय दोनों के लिए 4-2 वोट के साथ निभावकारी रुख को वापस लेना जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध थी।

सारणी I.1 मौद्रिक नीति समिति की बैठकें और नीति दर मतदान पैटर्न

देश	नीति की बैठकें : अक्टूबर 2022 – मार्च 2023			
	कुल बैठकें	पूर्ण सहमति वाली बैठकें	पूर्ण असहमति वाली बैठकें	नीति दर में परिवर्तन (आधार अंक)
ब्राजील	4	4	0	0
चिली	3	3	0	50
कोलंबिया	4	2	2	300
चेक गणराज्य	4	0	4	0
हंगरी	5	5	0	0
भारत*	3	0	3	110
जापान	4	4	0	0
दक्षिण अफ्रीका	3	0	3	150
स्वीडन	2	2	0	125
थाईलैंड	3	3	0	75
यूके	4	0	4	200
यूएस	4	4	0	175

*: 30 सितंबर 2022 को आयोजित बैठक समेत।
स्रोत: केंद्रीय बैंक के वेबसाइट।

एमपीसी का मतदान पैटर्न व्यक्तिगत सदस्यों के आकलन, अपेक्षाओं और नीतिगत प्राथमिकताओं में विविधता को दर्शाता है, यह एक ऐसी विशेषता है जो अन्य केंद्रीय बैंकों के मतदान पैटर्न में भी परिलक्षित होती है (सारणी I.1).

समष्टि-आर्थिक दृष्टिकोण

अध्याय II और III 2022-23 की दूसरी छमाही (अक्टूबर 2022 - मार्च 2023) के दौरान मुद्रास्फीति और आर्थिक गतिविधि से संबंधित समष्टि-आर्थिक घटनाक्रमों का विश्लेषण करते हैं। पिछले छह महीनों में प्रमुख समष्टि-आर्थिक और वित्तीय चरों के विकास के मद्देनजर आधारभूत मान्यताओं में संशोधन आवश्यक है (सारणी I.2).

[2] मुद्रास्फीति लगातार तीन तिमाहियों - ति4: 2021-22 (6.3 प्रतिशत), ति1: 2022-23 (7.3 प्रतिशत) और ति2 (7.0 प्रतिशत) के लिए लक्ष्य के आसपास 6 प्रतिशत की ऊपरी सहनशील सीमा से अधिक होने के परिणामस्वरूप 3 नवंबर 2022 को एमपीसी की एक अलग बैठक आयोजित की गई, ताकि आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45 जेडएन और आरबीआई एमपीसी के विनियमन 7 और मौद्रिक नीति प्रक्रिया विनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा सरकार को भेजी जाने वाली रिपोर्ट पर चर्चा और मसौदा तैयार किया जा सके।

सारणी I.2 : पूर्वानुमान हेतु आधारभूत मान्यताएं

	एमपीआर सितंबर 2022	एमपीआर अप्रैल 2023
कच्चा तेल (भारतीय बास्केट)	2022-23 की दूसरी छमाही के दौरान प्रति बैरल यूएस$ 105	2023-24 के दौरान प्रति बैरल यूएस$ 85
विनिमय दर	2022-23 की दूसरी छमाही के दौरान ₹80/यूएस$	2023-24 के दौरान ₹82/यूएस$
मानसून	2022-23 के लिए सामान्य से 6 प्रतिशत ऊपर	2023-24 के लिए सामान्य
वैश्विक संवृद्धि	2022 में 3.2 प्रतिशत 2023 में 2.9 प्रतिशत	2023 में 2.9 प्रतिशत 2024 में 3.1 प्रतिशत
राजकोषीय घाटा (जीडीपी का प्रतिशत)	बीई 2022-23 के भीतर रहेगी केंद्र : 6.4 संयुक्त : 9.3	बीई 2023-24 के भीतर रहेगी केंद्र : 5.9 संयुक्त : 8.5
पूर्वानुमान अवधि के दौरान घरेलू समष्टि-आर्थिक / संरचनात्मक नीतियां	कोई बड़ा परिवर्तन नहीं	कोई बड़ा परिवर्तन नहीं

टिप्पणियां : 1. कच्चे तेल का भारतीय बास्केट एक व्युत्पन्न मूल्यमान का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें खट्टा ग्रेड (ओमान और दुबई औसत) और मीठा ग्रेड (ब्रेंट) कच्चा तेल शामिल है।
2. यहां माना गया विनिमय दर पथ आधारभूत अनुमानों को उत्पन्न करने के उद्देश्य से है और विनिमय दर के स्तर पर किसी 'राय' को इंगित नहीं करता है। रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में अत्यधिक अस्थिरता को नियंत्रित करने के उद्देश्य से निर्देशित होता है, न कि विनिमय दर के किसी विशिष्ट स्तर और/या बैंड द्वारा।
3. बीई : बजट अनुमान।
4. संयुक्त राजकोषीय घाटे में केंद्र और राज्यों के घाटों को एक साथ लिया गया है।

स्रोत : आरबीआई अनुमान; बजट दस्तावेज; और आईएमएफ।

सबसे पहले, वैश्विक संवृद्धि धीमा होने और यूरोप में उम्मीद से कम सर्दियों के कारण दूसरी छमाही में अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में कमी आई। भू-राजनीतिक तनाव और पेट्रोलियम निर्यातक प्लस देशों के संगठन (ओपेक प्लस) की वजह से दृष्टिकोण को लेकर काफी अनिश्चितता है (चार्ट I.1.ए और चार्ट I.1.बी)। वैश्विक पेट्रोल और डीजल की कीमतें, जो घरेलू उत्पाद की कीमतों का प्रमुख निर्धारक हैं, मांग-आपूर्ति रिफाइनरी असंतुलन के मद्देनजर बढ़ी हैं (चार्ट I.1.सी). इन घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए, सितंबर एमपीआर बेसलाइन में 105 अमेरिकी डॉलर की तुलना में बेसलाइन में कच्चे तेल की कीमतें (भारतीय बास्केट) 85 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल मानी जाती हैं।

दूसरा, भारतीय रुपये या आईएनआर की सांकेतिक विनिमय दर दूसरी छमाही में 81-83 रुपया प्रति अमेरिकी डॉलर (यूएसडी) के दायरे में चली गई। अमेरिकी डॉलर में गिरावट से रुपये को समर्थन मिला, जबकि उभरती बाजार वाली अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) की परिसंपत्तियों को लेकर जोखिम दूर होने के मनोभाव और बढ़ते चालू खाता घाटे के दबाव के कारण मुद्रा का मूल्य गिरने लगा। इन घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए, विनिमय दर बेसलाइन में सितंबर 2022 एमपीआर के 80 रुपये की तुलना में 82 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर मानी जाती है।

चार्ट I.1: कच्चे तेल की कीमतें

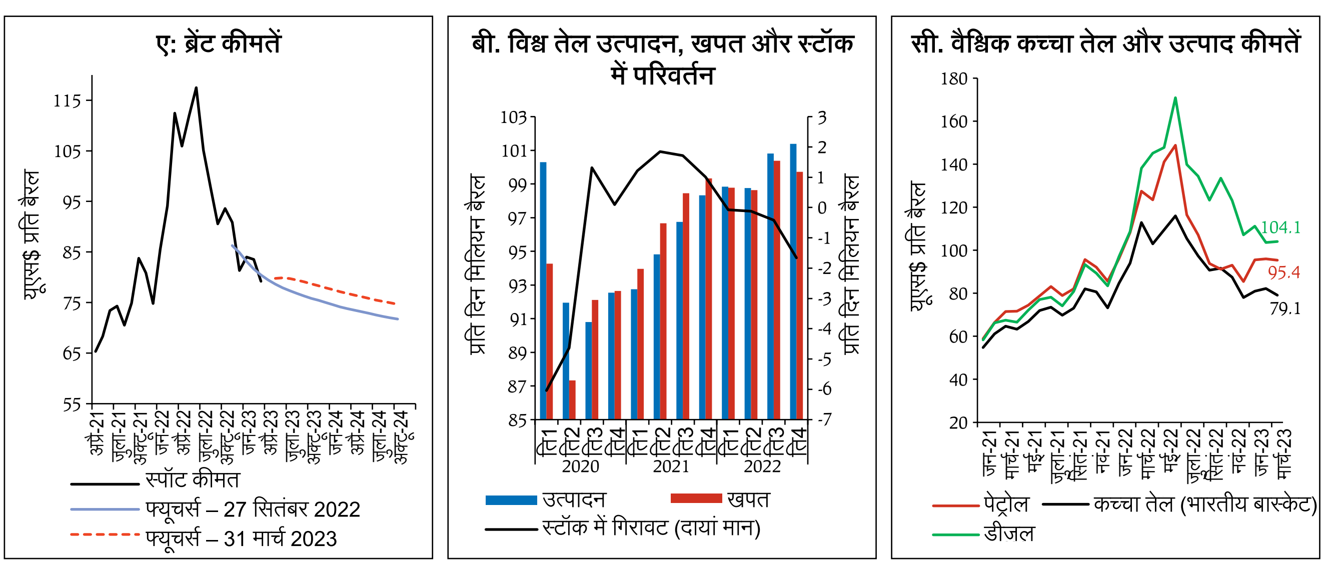

स्रोत : ब्लूमबर्ग; अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन (ईआईए); और पेट्रोलियम आयोजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ

चार्ट I.2: वैश्विक जीडीपी वृद्धि और मुद्रास्फीति

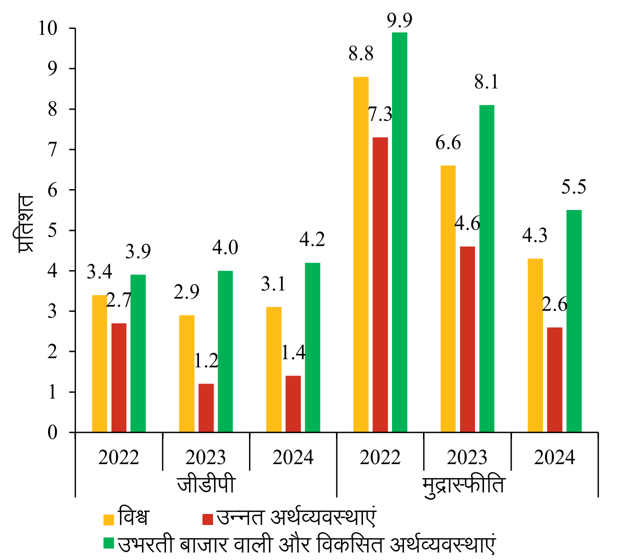

स्रोत : आईएमएफ।

चार्ट I.3: परिवारों की मुद्रास्फीति प्रत्याशाएं

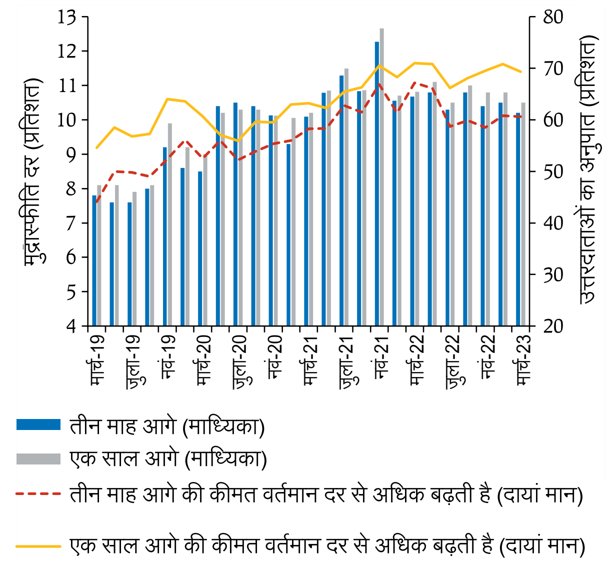

स्रोत : परिवारों का मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण, आरबीआई।

तीसरा, जबकि वैश्विक आर्थिक संभावनाओं में कुछ महीने पहले की तुलना में मामूली सुधार हुआ है, दृष्टिकोण अत्यधिक अनिश्चित है। वैश्विक समग्र खरीद प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) जुलाई 2022-जनवरी 2023 के दौरान लगातार छह महीनों तक संकुचन क्षेत्र में रहने के बाद फरवरी में विस्तार पाया। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के *विश्व आर्थिक परिदृश्य* (डब्ल्यूईओ) के जनवरी 2023 के अपडेट के अनुसार, वैश्विक विकास 2022 में 3.4 प्रतिशत से घटकर 2023 में 2.9 प्रतिशत और 2024 में 3.1 प्रतिशत होने की उम्मीद है, जिसमें उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) के सापेक्ष उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) के लिए तेज मंदी का अनुमान है (चार्ट 1.2)। साथ ही, 2023 में वैश्विक व्यापार में गिरावट की उम्मीद है।

I.2 मुद्रास्फीति दृष्टिकोण

प्रतिकूल आपूर्ति झटके और उत्पादन कीमतों पर इनपुट लागतों के प्रभाव ने दूसरी छमाही में सीपीआई मुद्रास्फीति पर निरंतर ऊपर की ओर दबाव डाला (अध्याय II)। आगे देखते हुए, रिज़र्व बैंक के सर्वेक्षण[3] के मार्च 2023 के दौर में शहरी परिवारों की तीन महीने आगे और एक साल आगे की औसत मुद्रास्फीति की उम्मीदों, प्रत्येक में 30 बीपीएस की गिरावट आई है। पिछले दौर की तुलना में दोनों क्षितिजों के लिए सामान्य मूल्य स्तर में मौजूदा दर से अधिक की वृद्धि की उम्मीद करने वाले उत्तरदाताओं का अनुपात घटा (चार्ट I.3)।

रिज़र्व बैंक के औद्योगिक दृष्टिकोण सर्वेक्षण के जनवरी-मार्च 2023 दौर के सर्वेक्षण में शामिल विनिर्माण कंपनियों ने 2023-24 की पहली तिमाही में कच्चे माल की लागत बढ़ने की गति स्थिर रहने जबकि बिक्री कीमतों में कमी की उम्मीद की (चार्ट 1.4ए)।[4] सेवा क्षेत्र और इन्फ्रास्ट्रक्चर फर्मों ने 2023-24 की पहली तिमाही में इनपुट की लागत और बिक्री कीमतों की वृद्धि में मामूली गिरावट की उम्मीद की (चार्ट I.4बी और I.4सी)।[5] पीएमआई सर्वेक्षणों में, विनिर्माण और सेवा फर्मों ने फरवरी 2023 की तुलना में मार्च में कम इनपुट लागत मुद्रास्फीति लेकिन उच्च उत्पादन मूल्य मुद्रास्फीति की सूचना दी।

[3] रिज़र्व बैंक का मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण मार्च 2021 से 19 शहरों (पिछले दौर में 18 शहरों) में किया जा रहा है और मार्च 2023 दौर के परिणाम 6,075 परिवारों की प्रतिक्रियाओं पर आधारित हैं।

[4] औद्योगिक दृष्टिकोण सर्वेक्षण के जनवरी-मार्च 2023 दौर के नतीजे 1066 कंपनियों की प्रतिक्रियाओं पर आधारित हैं।

[5] सेवा और इन्फ्रास्ट्रक्चर दृष्टिकोण सर्वेक्षण के जनवरी-मार्च 2023 दौर के मतदान में शामिल 522 सेवा कंपनियों और 116 इन्फ्रास्ट्रक्चर फर्मों पर आधारित।

चार्ट I.4: कच्चे माल/इनपुट की लागत और बिक्री कीमत संबंधी प्रत्याशाएं

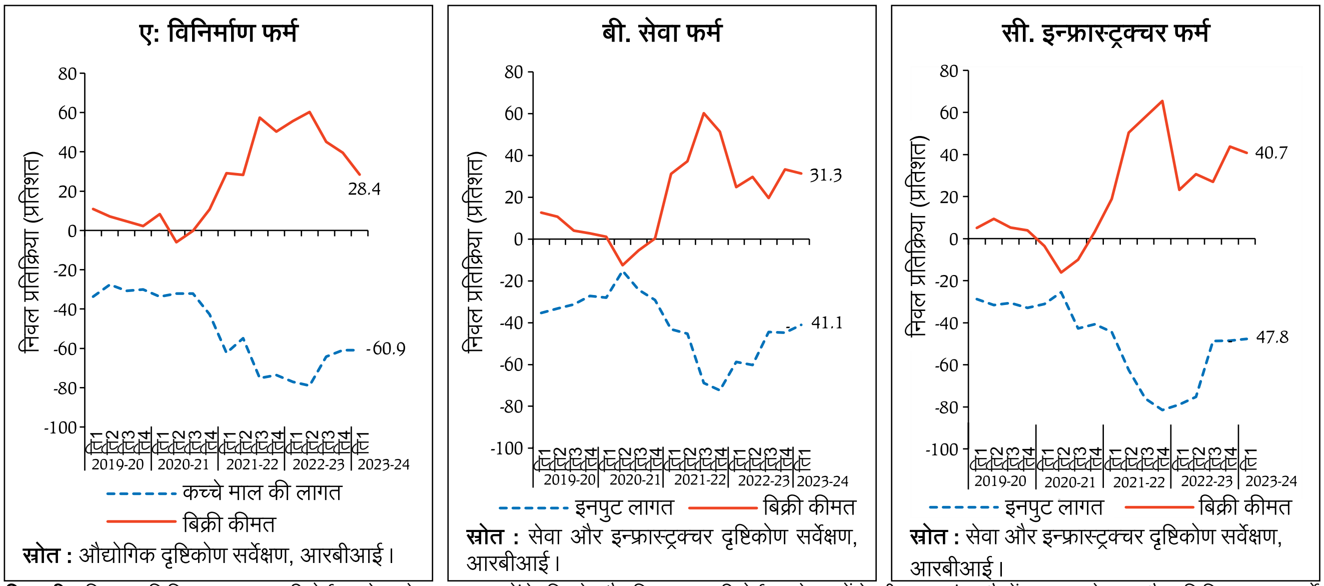

टिप्पणी : निवल प्रतिक्रिया आशावाद रिपोर्ट करने वाले उत्तरदाताओं के हिस्से और निराशावाद रिपोर्ट करने वालों के बीच का अंतर है। रेंज -100 से 100 है। प्रतिक्रियादाता फर्मों के नजरिए से निवल प्रतिक्रिया के धनात्मक / ऋणात्मक मान को आशावादी / निराशावादी माना जाता है। इसलिए, बिक्री कीमतों के उच्च धनात्मक मान उत्पादन कीमतों में वृद्धि का संकेत देते हैं जबकि कच्चे माल की लागत/ इनपुट लागत के लिए कम मान उच्च इनपुट कीमत दबाव को इंगित करते हैं और *इसके विपरीत*।

मार्च 2023 में रिज़र्व बैंक द्वारा सर्वेक्षण किए गए पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं ने सीपीआई मुद्रास्फीति 2022-23 की चौथी तिमाही में 6.2 प्रतिशत से घटकर 2023-24 की पहली तिमाही में 5.0 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 5.3 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 5.5 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 5.2 प्रतिशत (चार्ट I.5ए और सारणी I.3) होने की उम्मीद की।[6] उत्तरदाताओं ने खाद्य एवं पेय पदार्थ, पान, तंबाकू और नशीले पदार्थों तथा ईंधन एवं प्रकाश को छोड़कर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति 2022-23 की चौथी तिमाही में 6.2 प्रतिशत से 2023-24 के दौरान 5.4-5.6 प्रतिशत होने की उम्मीद की। उनकी 5 और 10

चार्ट I.5: पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं की मुद्रास्फीति प्रत्याशाएं

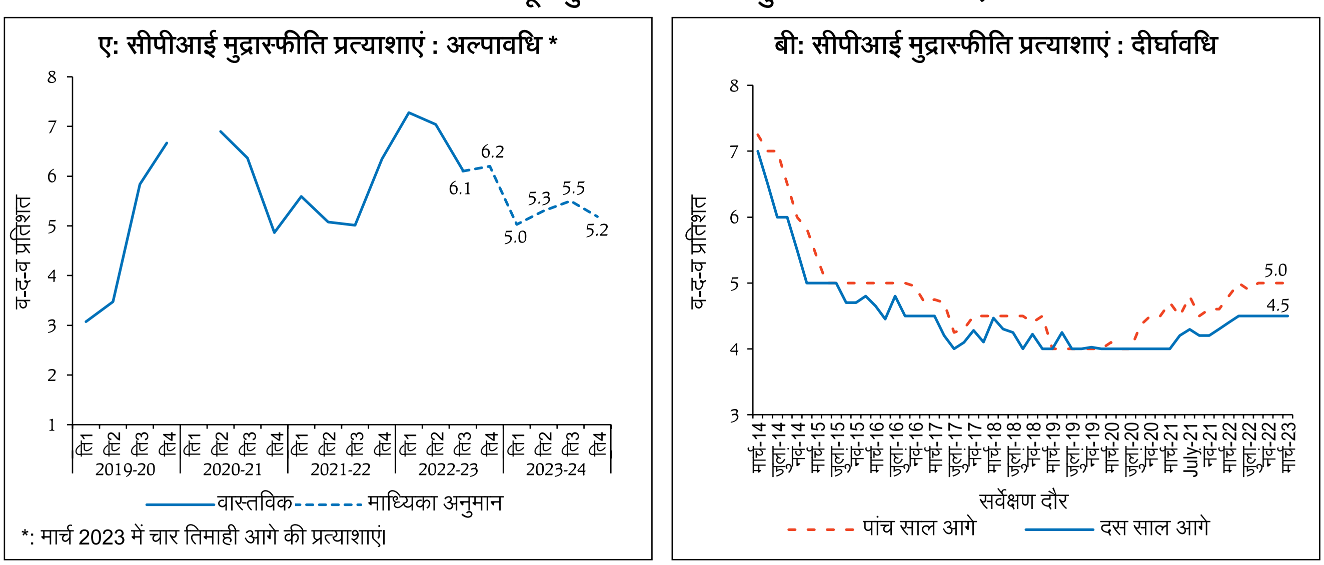

स्रोत : पेशेवर पूर्वानुमानकर्ता सर्वेक्षण, आरबीआई; और एनएसओ।

6 रिज़र्व बैंक के पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं के सर्वेक्षण के मार्च 2023 दौर में 41 पैनलिस्टों ने भाग लिया।

सारणी I.3: अनुमान - रिज़र्व बैंक और पेशेवर पूर्वानुमानकर्ता

(प्रतिशत)

	2022-23	2023-24	2024-25
रिज़र्व बैंक का आधारभूत अनुमान			
मुद्रास्फीति, ति4 (व-द-व)	5.7	5.2	4.4
वास्तविक जीडीपी वृद्धि	7.0@	6.5	6.5
पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं का औसत अनुमान			
मुद्रास्फीति, ति4 (व-द-व)	6.2	5.2	
वास्तविक जीडीपी वृद्धि	7.0	6.0	
सकल घरेलू बचत (जीएनडीआई का प्रतिशत)	29.2	29.7	
सकल पूंजी निर्माण (जीडीपी का प्रतिशत)	31.1	30.8	
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण वृद्धि	15.0	12.0	
संयुक्त सकल राजकोषीय घाटा (जीडीपी का प्रतिशत)	9.5	8.9	
केंद्र सरकार सकल राजकोषीय घाटा (जीडीपी का प्रतिशत)	6.4	5.9	
रेपो दर (समाप्त-अवधि)	6.50	6.75	
91-दिनों के ट्रेजरी बिलों पर प्रतिफल (समाप्त-अवधि)	6.7	6.5	
10-साल की केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों पर प्रतिफल (समाप्त-अवधि)	7.4	7.2	
समग्र भुगतान शेष (बिलियन यूएस$)	-20.0	4.2	
पण्य निर्यात वृद्धि	4.1	-2.3	
पण्य आयात वृद्धि	16.0	-3.8	
चालू खाता शेष (जीडीपी का प्रतिशत)	-2.6	-2.0	

टिप्पणी : जीएनडीआई: सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय।
@: एनएसओ अग्रिम अनुमान
स्रोत : एनएसओ, आरबीआई स्टाफ अनुमान; और पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं का सर्वेक्षण (मार्च 2023)

साल आगे की मुद्रास्फीति संबंधी उम्मीदें मार्च दौर में क्रमशः 5.0 प्रतिशत और 4.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहीं (चार्ट I.5बी)।

आगे देखते हुए, मुद्रास्फीति दृष्टिकोण वैश्विक और घरेलू दोनों तरह के कई कारकों से प्रभावित होगा। हालांकि हाल के महीनों में कच्चे तेल और पण्य की कीमतों में गिरावट आई है, लेकिन उनके भविष्य के अनुमान अनिश्चित बने हुए हैं, क्योंकि भू-राजनीतिक शत्रुता और महामारी-संबंधी लॉकडाउन से फिर से खुलने वाले देशों से मांग में तेजी आने की संभावना है। वैश्विक वित्तीय बाजारों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। घरेलू स्तर पर, *रबी* की बंपर फसल की उम्मीद खाद्य मुद्रास्फीति की भावी राह के लिए अच्छा संकेत है। दूसरी ओर, प्रतिकूल मौसम के झटके लगातार हो रहे हैं और दक्षिण-पश्चिम मानसून की बारिश को लेकर अत्यधिक अनिश्चितता है। प्रारंभिक स्थितियों,

चार्ट I.6: सीपीआई मुद्रास्फीति संबंधी अनुमान (व-द-व)

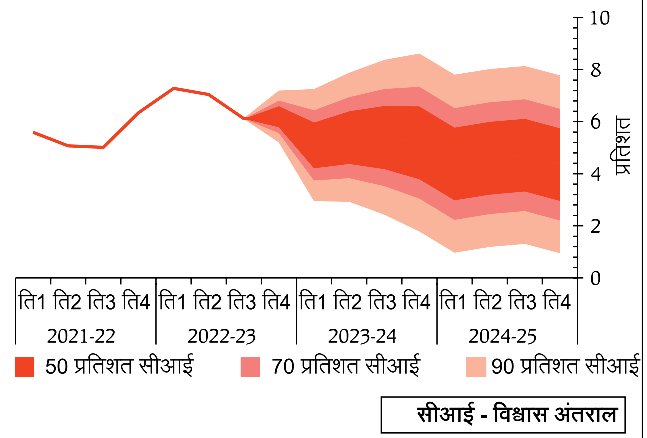

टिप्पणी : फैन चार्ट आधारभूत अनुमान पथ के आसपास अनिश्चितता को दर्शाता है। आधारभूत अनुमान सारणी I.2 में निर्धारित मान्यताओं पर आधारित हैं। गहरा लाल छायांकित क्षेत्र 50 प्रतिशत विश्वास अंतराल का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका अर्थ है कि 50 प्रतिशत संभावना है कि वास्तविक परिणाम गहरे लाल छायांकित क्षेत्र द्वारा दर्शाई गई सीमा के भीतर होगा। इसी तरह, 70 प्रतिशत और 90 प्रतिशत विश्वास अंतराल के लिए, क्रमशः 70 प्रतिशत और 90 प्रतिशत संभावना है कि वास्तविक परिणाम संबंधित छायांकित क्षेत्रों द्वारा प्रतिनिधित्व की गई सीमा में होंगे।
स्रोत : आरबीआई स्टाफ अनुमान।

दूरंदेशी सर्वेक्षणों के संकेतों और संरचनात्मक और अन्य समय-श्रृंखला मॉडलों[7] के अनुमानों को ध्यान में रखते हुए, सीपीआई मुद्रास्फीति का औसत 2023-24 में 5.2 प्रतिशत – जो 2023-24 की पहली तिमाही में 5.1 प्रतिशत, दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही में 5.4 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 5.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जिसमें जोखिम को लेकर समान रूप से संतुलन बना हुआ है (चार्ट 1.6)। 2023-24 की चौथी तिमाही में हेडलाइन मुद्रास्फीति के लिए 50 प्रतिशत और 70 प्रतिशत विश्वास अंतराल क्रमशः 3.8-6.6 प्रतिशत और 3.1-7.3 प्रतिशत हैं। 2024-25 के लिए, सामान्य मानसून, आपूर्ति श्रृंखलाओं के प्रगतिशील रूप से सामान्य होने और आगे कोई बाह्य या नीतिगत झटके नहीं होने को मानते हुए, संरचनात्मक मॉडल अनुमानों से संकेत मिलता है कि मुद्रास्फीति औसतन 4.5 प्रतिशत रहेगी। 2024-25 की चौथी तिमाही में सीपीआई मुद्रास्फीति 4.4 प्रतिशत रहने के साथ 50 प्रतिशत और 70 प्रतिशत विश्वास अंतराल क्रमशः 3.0-5.8 प्रतिशत और 2.2-6.5 प्रतिशत होने का अनुमान है।

[7] जॉन, जोइस, दीपक कुमार, आशीष थॉमस जॉर्ज, प्रतीक मित्रा, मनीष कपूर और माइकल देबब्रत पात्र (2023), "भारत के लिए एक रीकैलिब्रेटेड क्वार्टरली प्रोजेक्शन मॉडल (क्यूपीएम 2.0)", *भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन*, फरवरी, वॉल्यूम LXXVII (2), पीपी.59-77

अस्थिर वैश्विक वातावरण और मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान में बड़े विचलन को लेकर पारदेशीय अनुभव को देखते हुए आधारभूत पूर्वानुमान कई अपसाइड और डाउनसाइड जोखिमों के अधीन हैं (बॉक्स I.1)। भू-राजनीतिक संघर्षों में संभावित वृद्धि, उच्च वैश्विक कच्चा तेल और पण्य कीमतों, उच्च मुद्रास्फीति और वित्तीय स्थिरता चिंताओं के बीच वैश्विक वित्तीय बाजार की

बॉक्स I.1: उच्च अस्थिरता की अवस्था में मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान की सटीकता: पारदेशीय साक्ष्य

महामारी के बाद से, आपूर्ति और मांग संबंधी झटके परस्पर व्याप्त होने के कारण मुद्रास्फीति अत्यधिक अस्थिरता के साथ 1970 और 1980 के दशक के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है (चार्ट I.1.1)। इससे केंद्रीय बैंकों और बाजार पूर्वानुमानकर्ताओं दोनों द्वारा मुद्रास्फीति को लेकर किए गए पूर्वानुमान में बड़ी त्रुटियां हुई हैं (चाहड़ एवं अन्य, 2022; रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, 2022)। फिलिप कर्व फ्रेमवर्क – मुद्रास्फीति पूर्वानुमान हेतु वर्कहॉर्स मॉडल – बड़े झटकों और गैर-क्रमिकताओं के सामने बेअसर साबित हुए हैं।

आठ केंद्रीय बैंकों[8] के नमूने के बीच मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान के विश्लेषण से महामारी की अवधि के दौरान पूर्वानुमान प्रदर्शन में गिरावट का पता चलता है। पूर्वानुमान त्रुटियां लंबी अवधि और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के लिए अधिक थीं। इस पारदेशीय तुलना में भारत में पूर्वानुमान त्रुटियां सबसे कम थीं (चार्ट I.1.2)।

चार्ट I.1.1: सीपीआई मुद्रास्फीति का मानक विचलन

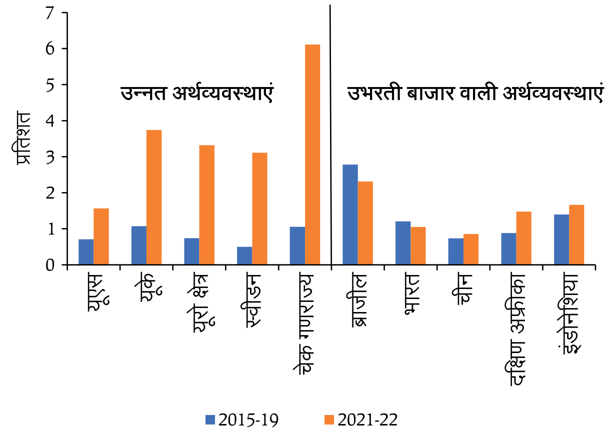

टिप्पणी : मुद्रास्फीति को व-द-व प्रतिशत परिवर्तन के रूप में दर्शाया गया है। यूएस के आंकड़े व्यक्तिगत उपभोग व्यय (पीसीई) मुद्रास्फीति से संबंधित हैं।
स्रोत : ब्लूमबर्ग; आरबीआई स्टाफ अनुमान।

महामारी से पहले, पूर्वानुमान त्रुटियां सांख्यिकीय रूप से शून्य से अलग नहीं थीं (जैसा कि सांख्यिकीय रूप से मामूली कान्स्टन्ट द्वारा सुझाया गया है) और इसलिए उन्हें निष्पक्ष माना जा सकता है। हाल के पूर्वानुमान पक्षपातपूर्ण रहे हैं, जिसमें वास्तविक परिणाम

चार्ट I.1.2: रूट मीन वर्ग पूर्वानुमान त्रुटि

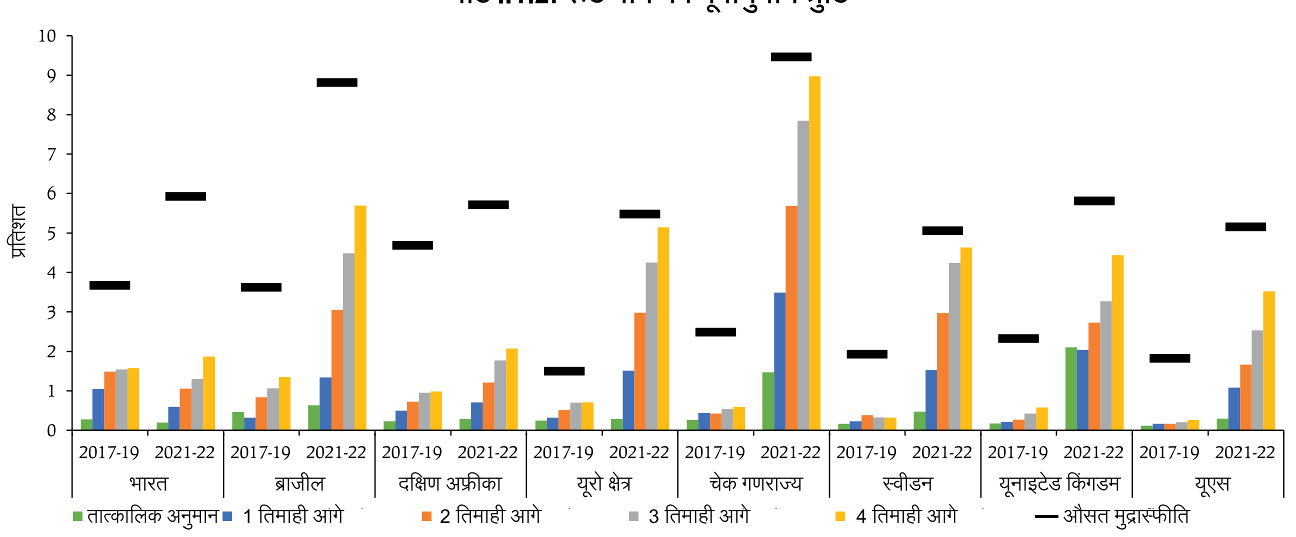

स्रोत : आरबीआई स्टाफ अनुमान।

(जारी)

8 ये केंद्रीय बैंक हैं - भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंको सेंट्रल डी ब्रासिल, दक्षिण अफ्रीकी रिजर्व बैंक, यूरोपीय सेंट्रल बैंक, चेक नेशनल बैंक, स्वेरिजेस रिक्सबैंक स्वीडन, बैंक ऑफ इंग्लैंड और अमेरिकी फेडरल रिजर्व।

सारणी I.1.1: पूर्वानुमान त्रुटियों की निष्पक्षता

	1 तिमाही आगे	2 तिमाही आगे	3 तिमाही आगे	4 तिमाही आगे
महामारी डमी	0.602***	1.850***	3.280***	4.117***
(ति1:2021-ति4:2022)	(0.001)	(0.000)	(0.000)	(0.000)
कान्स्टन्ट	-0.044	-0.115	-0.226	-0.265
	(0.667)	(0.435)	(0.197)	(0.214)
टिप्पणियां	165	162	161	153
देश के निश्चित प्रभाव	हां	हां	हां	हां

टिप्पणी : ***, **, * क्रमशः 1%, 5% और 10% पर सार्थकता के स्तर को दर्शाता है। पी-मान कोष्ठक में हैं। नमूना अवधि ति1:2017-ति4:2022 है।
स्रोत : आरबीआई स्टाफ अनुमान।

निरंतर पूर्वानुमानों का काफी हद तक अतिक्रमण करते हैं और अवधि बढ़ने[9] के साथ अधिक होते जाते हैं (सारणी I.1.1)।

जेनरलाइज़्ड मेथड ऑफ मोमेन्ट्स (जीएमएम) (अरेलानो और बॉण्ड, 1991) द्वारा ति1:2017 – ति4:2022 की अवधि को कवर करने वाले सात देशों के नमूने के लिए अनुमानित एक गतिशील पैनल डेटा मॉडल पूर्वानुमान त्रुटियों में उच्च दृढ़ता दिखाता है (सारणी I.1.2)। मुद्रा मूल्यह्रास को मिलाकर अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा और खाद्य कीमतों में पर्याप्त वृद्धि, पूर्वानुमान त्रुटियों के प्रमुख चालक प्रतीत होते हैं।

कुल मिलाकर, वैश्विक अनुभव से पता चलता है कि बड़े आपूर्ति झटकों के सामने पूर्वानुमान त्रुटियां बड़ी हो सकती हैं और दूरंदेशी मौद्रिक नीति के तौर-तरीकों को जटिल बना सकती हैं। ऐसे गतिशील और अनिश्चित वातावरण में, अधिक सटीकता के लिए वैकल्पिक परिदृश्यों और मॉडलिंग दृष्टिकोण के साथ आधारभूत पूर्वानुमान को सहारा देने की आवश्यकता है।

सारणी I.1.2: पूर्वानुमान त्रुटियों के मूल कारक – जीएमएम अनुमान

	1 तिमाही आगे	1 तिमाही आगे	4 तिमाही आगे	4 तिमाही आगे
आश्रित चर, अंतराल	0.789** (0.040)	0.748** (0.048)	1.080*** (0.000)	0.935*** (0.000)
ऊर्जा कीमत मुद्रास्फीति		0.009 (0.253)		0.007* (0.051)
खाद्य कीमत मुद्रास्फीति		0.061* (0.053)		0.037** (0.011)
मुद्रा मूल्यवृद्धि (+)/ मूल्यह्रास (-)		-0.041** (0.037)		-0.038** (0.013)
कान्स्टन्ट	0.005 (0.945)	-0.142 (0.247)	0.191** (0.040)	-0.219 (0.118)
टिप्पणियां	156	156	140	140
देशों की संख्या	7	7	7	7
एआर1 (पी-वैल्यू)	0.0418	0.0481	0.301	0.151
एआर2 (पी-वैल्यू)	0.273	0.238	0.0892	0.117
हैनसेन-जे (पी-वैल्यू)	0.398	0.989	0.338	0.643

टिप्पणी : ***, **, * क्रमशः 1%, 5% और 10% पर सार्थकता के स्तर को दर्शाता है। पी-मान कोष्ठक में हैं। n-तिमाही आगे पूर्वानुमान त्रुटि के लिए, वर्तमान तिमाही t हेतु बाह्य रिग्रेसरों अर्थात, ऊर्जा कीमतों, खाद्य कीमतों और मुद्रा में वृद्धि की गणना {(Qt-Qt-n)/Qt-n} *100 के रूप में की जाती है। नमूना अवधि ति1:2017-ति4:2022 है।
स्रोत : आरबीआई स्टाफ अनुमान।

संदर्भ :

अरेलानो, एम., और एस. बॉण्ड (1991), "पैनल डेटा के लिए विशिष्टता के कुछ परीक्षण: मोंटे कार्लो साक्ष्य और रोजगार समीकरणों पर प्रयोग", *आर्थिक अध्ययन की समीक्षा*, खंड 58, सं. 2, अप्रैल।

चाहड़ एम., ए. होफमैन-ड्रेहोन्स्की, बी. म्यूनियर, ए. पेज और एम. तिरपक (2022), "यूरोसिस्टम और ईसीबी स्टाफ के मुद्रास्फीति अनुमानों में हालिया त्रुटियों की व्याख्या क्या है?", *ईसीबी आर्थिक बुलेटिन*, अंक 3/2022.

रिज़र्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया (2022), "हालिया मुद्रास्फीति पूर्वानुमान त्रुटियों की व्याख्या क्या है?", *मौद्रिक नीति पर वक्तव्य* - नवंबर 2022.

अस्थिरता में वृद्धि, नए सिरे से आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान उत्पन्न होने, कठोर मौसम स्थितियों और कमजोर मानसून, एवं मांग मजबूत होने के साथ उत्पादन कीमतों पर इनपुट लागत का व्यापक दबाव पड़ने से अपसाइड जोखिम उत्पन्न होता है। भू-राजनीतिक तनाव के जल्द समाधान, वैश्विक मांग में धीमेपन के कारण वैश्विक कच्चा तेल और पण्य कीमतों में गिरावट तथा आपूर्ति की स्थिति में और सुधार से डाउनसाइड जोखिम पैदा हो सकता है।

[9] पूर्वानुमानों की निष्पक्षता का मूल्यांकन निम्नलिखित समीकरण का अनुमान लगाकर किया जाता है: $FE_{it}=\alpha_i+\beta * PandemicDummy+\varepsilon_{it}$, जहां, FE_{it} केंद्रीय बैंकों द्वारा किए गए विभिन्न अवधियों पर मुद्रास्फीति पूर्वानुमान त्रुटि है और *PandemicDummy* पूर्वानुमान त्रुटि पर महामारी के प्रभाव को दर्शाता है।

I.3 संवृद्धि दृष्टिकोण

सतत रूप से सालों के जोरदार कृषि उत्पादन, महामारी के बाद संपर्क-गहन सेवाओं में तेजी आने, बैंक ऋण में अत्यधिक वृद्धि, एक सुदृढ़ बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली[10] और सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने की बदौलत घरेलू आर्थिक गतिविधि लचीली बनी हुई है। हालांकि, वैश्विक संवृद्धि में नरमी, भू-राजनीतिक तनाव, वित्तीय बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ने और वैश्विक वित्तीय स्थितियों में सख्ती का दृष्टिकोण पर भारी असर पड़ता है।

दूरंदेशी सर्वेक्षणों के प्रमुख संदेशों की ओर देखें तो, उपभोक्ता विश्वास (वर्तमान स्थिति सूचकांक) में सामान्य आर्थिक स्थिति, रोजगार और घरेलू आय पर बेहतर धारणाओं की वजह से मार्च 2023 के सर्वेक्षण दौर में पिछले दौर की तुलना में सुधार हुआ, हालांकि यह निराशावादी क्षेत्र में बना हुआ है। आगामी वर्ष के लिए उपभोक्ताओं की उम्मीदें आशावादी क्षेत्र में जारी रहीं, हालांकि कुछ नरमी के साथ (चार्ट I.7)।[11]

चार्ट I.7: उपभोक्ता विश्वास

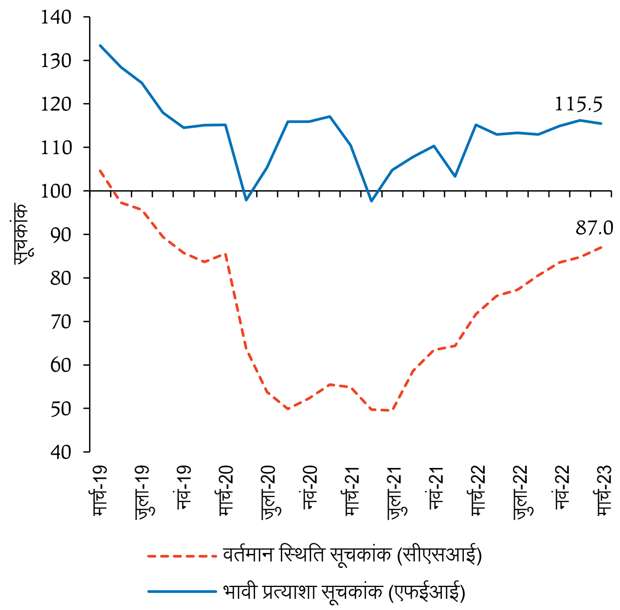

स्रोत : उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण, आरबीआई।

विनिर्माण क्षेत्र की फर्मों की आशावाद रिज़र्व बैंक के औद्योगिक दृष्टिकोण सर्वेक्षण में पिछले दौर की तुलना में आगे की तिमाही के लिए कम हो गई (चार्ट I.8ए)। दूसरी ओर, सेवाओं और इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की कंपनियों की अपेक्षाओं में समग्र कारोबार स्थिति के संदर्भ में सुधार हुआ (चार्ट I.8बी और I.8सी)।

चार्ट I.8: कारोबार मूल्यांकन और प्रत्याशाएं

ए: विनिर्माण फर्म

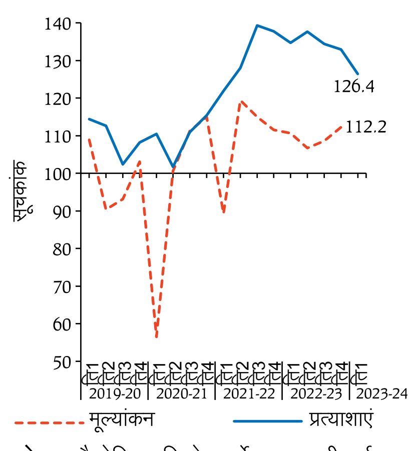

स्रोत : औद्योगिक दृष्टिकोण सर्वेक्षण, आरबीआई।

बी. सेवा फर्म

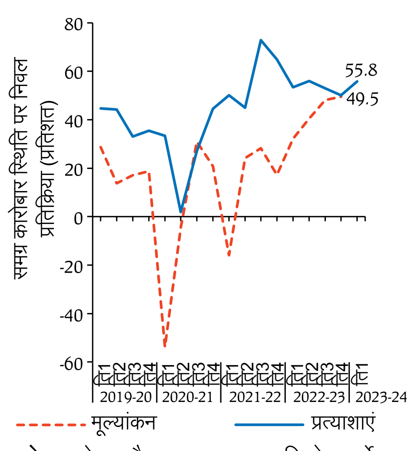

स्रोत : सेवा और इन्फ्रास्ट्रक्चर दृष्टिकोण सर्वेक्षण, आरबीआई।

सी. इन्फ्रास्ट्रक्चर फर्म

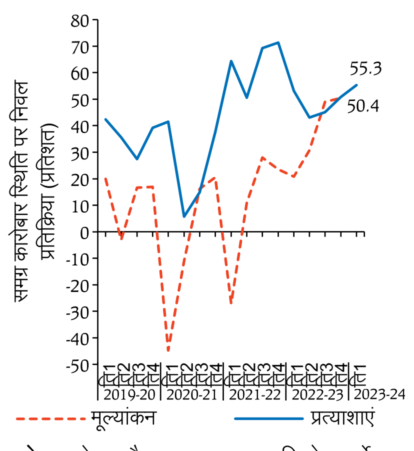

स्रोत : सेवा और इन्फ्रास्ट्रक्चर दृष्टिकोण सर्वेक्षण, आरबीआई।

[10] दास, शक्तिकान्त (2023), "भारत की अध्यक्षता के दौरान बेहतर वैश्विक आर्थिक व्यवस्था के लिए जी 20", 17वां के पी होर्मिस स्मारक व्याख्यान, 17 मार्च, जो https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_SpeechesView.aspx?Id=1356 पर उपलब्ध है।

[11] रिज़र्व बैंक का उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण मार्च 2021 से 19 शहरों (पिछले दौर में 13 शहरों) में किया जा रहा है और मार्च 2023 दौर के परिणाम 6,075 उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं पर आधारित हैं।

सारणी I.4: कारोबार प्रत्याशा सर्वेक्षण

मद	एनसीएईआर कारोबार विश्वास सूचकांक (जनवरी 2023)	फिक्की समग्र कारोबार विश्वास सूचकांक (जनवरी 2023)	डन और ब्रैडस्ट्रीट मिश्रित कारोबार आशावाद सूचकांक (जनवरी 2023)	सीआईआई कारोबार विश्वास सूचकांक (दिसंबर 2022)
सूचकांक का वर्तमान स्तर	126.6	61.0	77.3	67.6
पिछले सर्वेक्षण के अनुसार सूचकांक	132.5	59.9	83.1	62.2
% परिवर्तन (ति-द-ति) आनुक्रमिक	-4.5	1.8	-7.0	8.7
% परिवर्तन (व-द-व)	1.8	-4.5	-14.0	1.2

टिप्पणियां :

1. एनसीएईआर : राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद
2. फिक्की : भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल परिसंघ
3. सीआईआई : भारतीय उद्योग महापरिसंघ
4. डन और ब्रैडस्ट्रीट मिश्रित कारोबार आशावाद सूचकांक ति4:2022-23 के लिए है और शेष के लिए डेटा ति3:2022-23 से संबंधित है।

स्रोत : एनसीईआर; फिक्की; सीआईआई; एवं भारतीय डन और ब्रैडस्ट्रीट सूचना सेवा प्रा. लि.

अन्य एजेंसियों द्वारा हाल के सर्वेक्षण पिछले दौर के सापेक्ष कारोबार संबंधी अपेक्षाओं पर मिश्रित तस्वीर का संकेत देते हैं (सारणी I.4)। विनिर्माण और सेवा फर्मों ने मार्च 2023 के पीएमआई सर्वेक्षणों में आगामी वर्ष के लिए आशावाद प्रदर्शित किया।

रिज़र्व बैंक के सर्वेक्षण के मार्च 2023 दौर में शामिल पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं ने वास्तविक जीडीपी वृद्धि 2022-23 की चौथी तिमाही में 4.6 प्रतिशत, 2023-24 की पहली छमाही में 6.7-6.0 प्रतिशत और दूसरी छमाही में 5.8-5.5 प्रतिशत रहने की उम्मीद जताई है (चार्ट I.9 और सारणी I.3)।

आधारभूत अनुमानों, सर्वेक्षण संकेतकों और मॉडल पूर्वानुमानों को ध्यान में रखते हुए, वास्तविक जीडीपी वृद्धि 2023-24 में 6.5 प्रतिशत - पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत; दूसरी तिमाही में 6.2 प्रतिशत; तीसरी तिमाही में 6.1 प्रतिशत; और चौथी तिमाही में 5.9 प्रतिशत होने की उम्मीद है – और इस आधारभूत पथ के आसपास जोखिम को लेकर समान रूप से संतुलन बना हुआ है (चार्ट I.10 और सारणी I.3)। 2024-25 के लिए, सामान्य मानसून और कोई बड़ा बाह्य या नीतिगत झटका नहीं होने को मानते हुए, संरचनात्मक मॉडल अनुमानों में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.5 प्रतिशत होने का संकेत दिया गया है, जिसमें तिमाही वृद्धि दर 5.5-7.0 प्रतिशत के बीच है।

चार्ट I.9: पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं द्वारा वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान

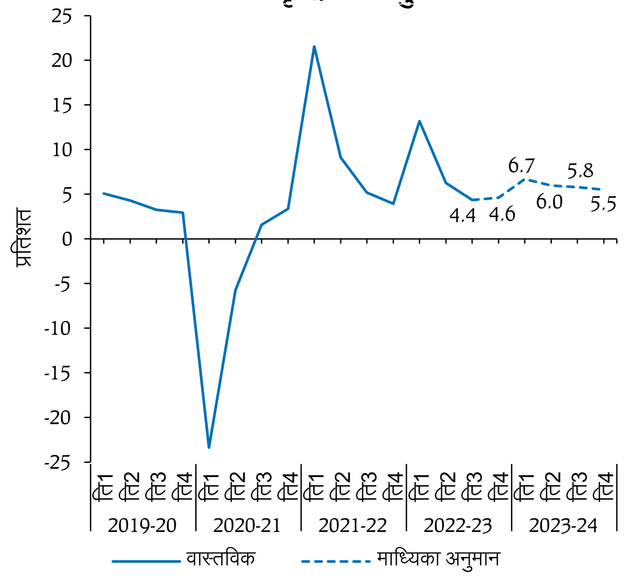

स्रोत : पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं का सर्वेक्षण, आरबीआई; और एनएसओ।

इस आधारभूत वृद्धि पथ के लिए अपसाइड और डाउनसाइड जोखिम हैं। अपसाइड जोखिम संपर्क-गहन सेवाओं में उम्मीद से अधिक जोरदार वापसी, क्योंकि वे महामारी से पूरे जोर से उभरते

चार्ट I.10: वास्तविक जीडीपी में वृद्धि का अनुमान (व-द-व)

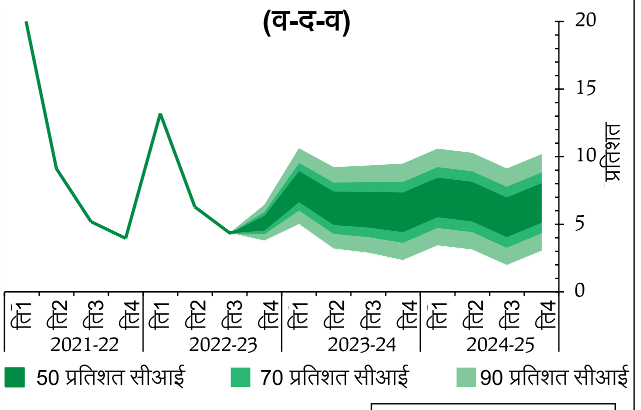

टिप्पणी : फैन चार्ट आधारभूत अनुमान पथ के आसपास अनिश्चितता को दर्शाता है। आधारभूत अनुमान सारणी I.2 में निर्धारित मान्यताओं पर आधारित हैं। गहरा हरा छायांकित क्षेत्र 50 प्रतिशत विश्वास अंतराल का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका अर्थ है कि 50 प्रतिशत संभावना है कि वास्तविक परिणाम गहरे हरे छायांकित क्षेत्र द्वारा दर्शाई गई सीमा के भीतर होगा। इसी तरह, 70 प्रतिशत और 90 प्रतिशत विश्वास अंतराल के लिए, क्रमशः 70 प्रतिशत और 90 प्रतिशत संभावना है कि वास्तविक परिणाम संबंधित छायांकित क्षेत्रों द्वारा प्रतिनिधित्व की गई सीमा में होंगे।
स्रोत : आरबीआई स्टाफ अनुमान।

हैं; स्वस्थ कॉर्पोरेट तुलन पत्र को देखते हुए सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने की वजह से निजी निवेश संबंधी गतिविधि फिर से शुरू होने; कच्चा तेल और पण्य कीमतों में उम्मीद से तेज सुधार के मामले में अनुकूल व्यापार शर्त संबंधी झटके; उम्मीद से बेहतर वैश्विक संवृद्धि की संभावनाओं; और भू-राजनीतिक संघर्ष के जल्द समाधान से उत्पन्न होता है। इसके विपरीत, भू-राजनीतिक तनाव का बढ़ना, अंतरराष्ट्रीय कच्चा तेल और अन्य पण्य कीमतों में और वृद्धि, आपूर्ति श्रृंखलाओं में निरंतर व्यवधान, वैश्विक वित्तीय बाजार में अस्थिरता का बने रहना, वैश्विक व्यापार और मांग की गति तेजी से कम होना और मौसम से संबंधित व्यवधान आधारभूत वृद्धि पथ के लिए डाउनसाइड जोखिम पैदा करते हैं।

I.4 जोखिम संतुलन

इस अध्याय में वृद्धि और मुद्रास्फीति के आधारभूत अनुमान अन्य बातों के साथ-साथ सारणी I.2 में निर्धारित प्रमुख घरेलू और अंतरराष्ट्रीय समष्टि-आर्थिक चरों की भावी राह की मान्यताओं पर निर्भर करते हैं। लंबे समय तक भू-राजनीतिक तनाव बने रहने, मुद्रास्फीति में वृद्धि का वैश्विक स्तर पर हैरान करने, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजार में अस्थिरता और बारंबार प्रतिकूल मौसम के आने के कारण इन मान्यताओं के आसपास की अनिश्चितताएं काफी बढ़ गई हैं। इस पृष्ठभूमि में, यह खंड आधारभूत अनुमानों के आसपास जोखिमों के संतुलन का आकलन करने के लिए संभाव्य वैकल्पिक परिदृश्यों की पड़ताल करता है।

(i) वैश्विक संवृद्धि संबंधी अनिश्चितताएं

आधारभूत दृष्टिकोण के लिए काफी डाउनसाइड जोखिमों के साथ वैश्विक संवृद्धि धीमी पड़ रही है। वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति प्रमुख चिंता का विषय बनी हुई है और इसे नियंत्रण में करने के लिए और अधिक मौद्रिक सख्ती की आवश्यकता हो सकती है। यह वैश्विक ब्याज दरों को वर्तमान अनुमान से अधिक समय तक बढ़ा सकता है। ऋण चुकौती लागत बढ़ सकती है और वित्तीय स्थिरता जोखिम को बढ़ा सकती है। इसके अलावा, भू-राजनीतिक तनाव और बढ़ सकता है। ऐसे परिदृश्य में, यदि वैश्विक संवृद्धि बेसलाइन से 100 बीपीएस कम है, तो घरेलू वृद्धि और मुद्रास्फीति आधारभूत पथ से क्रमशः लगभग 30 बीपीएस और 15 बीपीएस नीचे हो सकती है। इसके विपरीत, यदि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति तेजी से कम होती है और वैश्विक वित्तीय स्थिति में सुधार होता है, भू-राजनीतिक तनाव कम हो जाता है और वैश्विक संवृद्धि 50 बीपीएस तक अधिक हो जाता है, तो घरेलू वृद्धि और मुद्रास्फीति क्रमशः लगभग 15 बीपीएस और 7 बीपीएस तक बढ़ सकती है (चार्ट I.11ए और I.12ए)।

चार्ट I.11: आधारभूत मुद्रास्फीति पथ पर जोखिम परिदृश्यों का प्रभाव

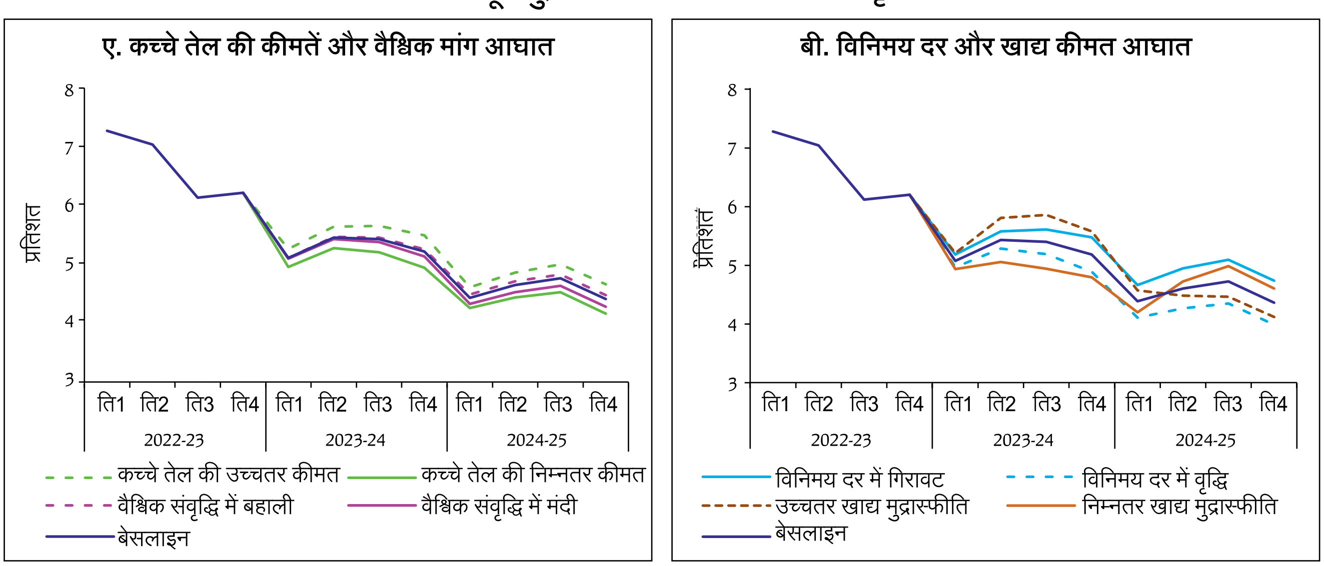

स्रोत : आरबीआई स्टाफ अनुमान।

(ii) कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतें

पिछले एमपीआर के बाद से कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में कमी आई है, लेकिन इसमें उतार-चढ़ाव बना हुआ है। वैश्विक मांग में जोरदार वापसी, ओपेक *प्लस* देशों द्वारा उत्पादन में कटौती और भू-राजनीतिक शत्रुता बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। वैश्विक मांग-आपूर्ति असंतुलन को देखते हुए दरार का फैलाव और बढ़ सकता है। कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतें बेसलाइन से 10 प्रतिशत ऊपर मान ली जाएं तो घरेलू मुद्रास्फीति और वृद्धि दर क्रमश: 30 बीपीएस अधिक और लगभग 15 बीपीएस कमजोर हो सकती है। इसके विपरीत, भू-राजनीतिक तनाव जल्द कम होने और आक्रामक मौद्रिक नीति कार्रवाई के कारण वैश्विक मांग में कमी से कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में बेसलाइन से नीचे कमी आ सकती है। यदि, परिणामस्वरूप, कच्चे तेल की कीमतों के भारतीय बास्केट में 10 प्रतिशत की गिरावट आती है और घरेलू उत्पाद की कीमतों पर पूर्ण प्रभाव पड़ता है, तो 15 बीपीएस की वृद्धि के साथ मुद्रास्फीति लगभग 30 बीपीएस तक कम हो सकती है (चार्ट I.11ए और I.12ए)।

(iii) विनिमय दर

सख्त वैश्विक वित्तीय स्थितियों, अनिश्चित वैश्विक वातावरण और पोर्टफोलियो बहिर्वाह के बीच 2022-23 की दूसरी छमाही में अमेरिकी डॉलर के सापेक्ष भारतीय रुपये में गिरावट आई। 'लंबे समय तक उच्च' ब्याज दर परिदृश्य और धीमी पड़ती वैश्विक संवृद्धि जोखिम से बचने की प्रवृत्ति को बढ़ा सकती है और ईएमई में पूंजी प्रवाह पर असर डाल सकती है। यदि ऐसे परिदृश्य में भारतीय रुपया बेसलाइन से 5 प्रतिशत नीचे गिरता है, तो मुद्रास्फीति लगभग 35 बीपीएस तक बढ़ सकती है, जबकि निर्यात को बढ़ावा मिलने के जरिए जीडीपी वृद्धि लगभग 25 बीपीएस तक अधिक हो सकती है। दूसरी ओर, चूंकि भारत का विकास प्रदर्शन और दृष्टिकोण अपेक्षाकृत रूप से प्रतिस्पर्धियों से बेहतर है, इसलिए यह विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षक बन सकता है। इसके अलावा, चालू खाता घाटा कम होने के साथ, भारतीय रुपया बेसलाइन के सापेक्ष बढ़ सकता है। पांच प्रतिशत की वृद्धि के साथ मुद्रास्फीति और जीडीपी वृद्धि क्रमश: लगभग 35 बीपीएस और 25 बीपीएस कम हो सकती है (चार्ट I.11बी और I.12बी)।

चार्ट I.12: आधारभूत संवृद्धि पथ पर जोखिम परिदृश्यों का प्रभाव

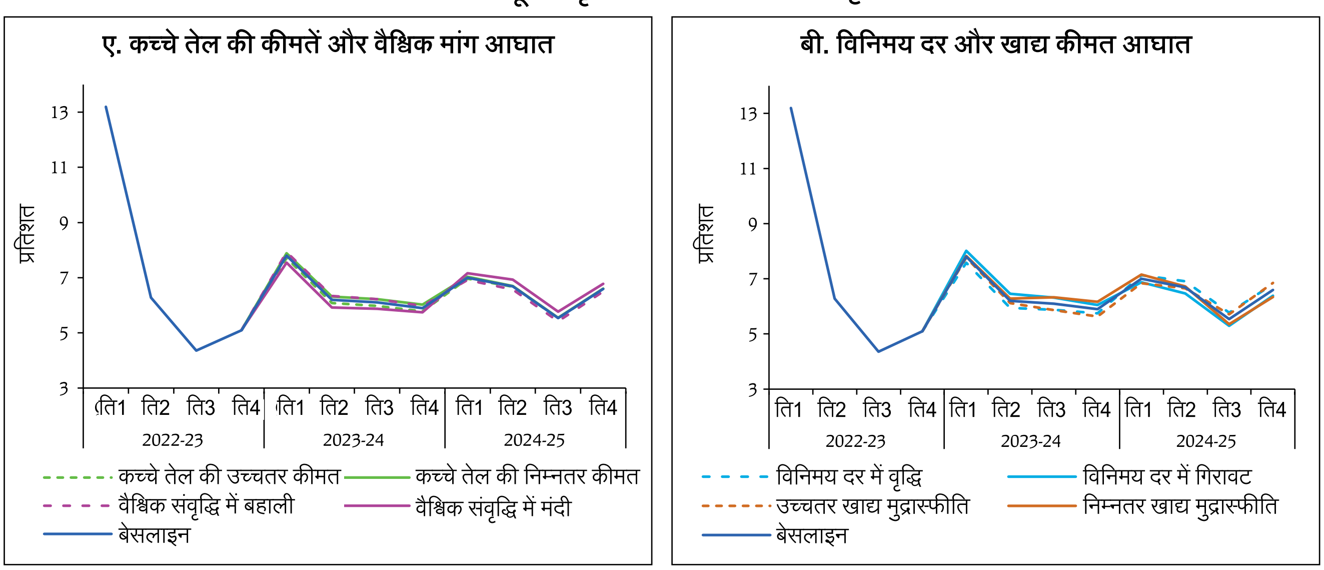

स्रोत : आरबीआई स्टाफ अनुमान।

(iv) खाद्य मुद्रास्फीति

गर्मी की लहरें, बड़ी बेमौसम बारिश, और मानसून का अपने सामान्य पैटर्न से विचलन – ज्यादा बारंबार और तीव्रता के साथ हो रही हैं। इस तरह की प्रतिकूल मौसम की घटनाओं से खाद्य कीमतों पर ऊपर की ओर दबाव बढ़ सकता है जिससे हेडलाइन मुद्रास्फीति लगभग 50 बीपीएस तक बढ़ सकती है (चार्ट I.11बी और I.12बी)। दूसरी ओर, रबी की जबर्दस्त फसल की संभावना, पर्याप्त बफर स्टॉक, सरकार द्वारा प्रभावी आपूर्ति प्रबंधन उपाय और वैश्विक खाद्य स्थिति में सुधार खाद्य मुद्रास्फीति पर नीचे की ओर दबाव डाल सकता है और हेडलाइन मुद्रास्फीति को बेसलाइन से 50 बीपीएस नीचे ला सकता है। आधारभूत हेडलाइन मुद्रास्फीति पथ और जोखिम संतुलन, पनपती मौसम की स्थिति और दक्षिण-पश्चिम मानसून की वर्षा के अस्थायी और स्थानिक प्रसार पर काफी निर्भर करते हैं।

I.5 निष्कर्ष

भारतीय अर्थव्यवस्था 2023-24 में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने की उम्मीद है, जो मजबूत घरेलू उत्प्रेरकों और सशक्त समष्टि-आर्थिक सिद्धांतों द्वारा समर्थित है। भारतीय वित्तीय क्षेत्र स्थिर बना हुआ है। हेडलाइन मुद्रास्फीति अपने मौजूदा उच्च स्तर से कम होने और 2023-24 के दौरान ऊपरी सहनशीलता बैंड से नीचे जाने की उम्मीद है। मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति को प्रगतिशील रूप से लक्ष्य के अनुरूप बनाने पर केंद्रित रहती है। भू-राजनीतिक शत्रुता, सख्त वैश्विक मुद्रास्फीति, अस्थिर वैश्विक वित्तीय बाजार और जलवायु झटके संवृद्धि और मुद्रास्फीति दृष्टिकोण के लिए प्रमुख जोखिम हैं।

II. मूल्य और लागत

वर्ष 2022-23 की दूसरी छमाही में मुद्रास्फीति का पथ एक के बाद एक घरेलू खाद्य आपूर्ति के आघातों से घिरे होने के कारण प्रभावित हुआ था, जिसने इसे नवंबर-दिसंबर 2022 में एक अस्थायी नरमी को छोड़कर, ऊपरी सहन-सीमा से ऊपर रखा था। पण्यों की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में नरमी से निविष्टि लागतों में कमी आने के बावजूद, कोर मुद्रास्फीति उच्चतर स्तर पर बनी रही।

सितंबर 2022 एमपीआर के बाद से, हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति[1] पथ मौसम संबंधी अनिश्चितताओं और दबी हुई निविष्टि लागतों का असर आने के बीच घरेलू खाद्य आपूर्ति के आघातों से प्रभावित हुआ था। नवंबर-दिसंबर 2022 के दौरान सब्जी की कीमतों में एक अस्थायी लेकिन अपेक्षा से अधिक मौसमी सुधार से कुछ राहत मिली लेकिन जनवरी-फरवरी 2023 में अनाज और मसालों की कीमतों के निरंतर दबाव और प्रोटीन आधारित खाद्य मुद्रास्फीति में तेजी के कारण यह स्थिति उलट गयी। घरेलू मांग की स्थिति में सुधार के साथ, निविष्टि लागतों को वस्तुओं और सेवाओं की खुदरा कीमतों पर लगातार अंतरित कर दिया गया, जिसने पहले से ही उच्च कोर (खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई) मुद्रास्फीति[2] को और भी सख्त बना दिया।

इन कई आघातों को दर्शाते हुए, हेडलाइन मुद्रास्फीति, दिसंबर तक बस थोड़े समय के लिए 5.7 प्रतिशत तक कम होने से पहले, सितंबर-अक्टूबर के दौरान औसतन 7.1 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) रही। जनवरी-फरवरी 2023 के दौरान खाद्य मूल्य दबावों के पुनः बढ़ जाने से हेडलाइन मुद्रास्फीति 6.5 प्रतिशत हो गई। कोर मुद्रास्फीति दूसरी छमाही के दौरान 6 प्रतिशत या उससे ऊपर ही बनी रही (चार्ट II.1)।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) अधिनियम, आरबीआई को अनुमानों से वास्तविक मुद्रास्फीति परिणामों के विचलन, यदि कोई हो, को निर्धारित करने और उसके अंतर्निहित कारणों की व्याख्या करने के लिए बाध्य करता है। सितंबर 2022 एमपीआर में 2022-23 की तीसरी तिमाही के लिए मुद्रास्फीति 6.5 प्रतिशत और चौथी तिमाही के लिए 5.8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था। तीसरी तिमाही में वास्तविक मुद्रास्फीति अनुमान से 40 आधार अंक कम ही रही, जिसका मुख्य कारण सब्जियों की कीमतों में अपेक्षा से तीव्रतर मौसमी सुधार था, जो सामान्य से पहले ही शुरू हो गया था। सब्जियों की सीपीआई कीमतों में माह-दर-माह गिरावट नवंबर 2022 में (-) 8.3 प्रतिशत थी जो नवंबर माह के लिए मौजूदा सीपीआई (2012=100) श्रृंखला में सबसे अधिक थी (चार्ट II.2)। इसके बाद दिसंबर में सब्जियों की कीमतों में और भी बड़ी गिरावट आई। वास्तव में, नवंबर-दिसंबर में लगभग 20 प्रतिशत की संचयी कीमत की गिरावट वर्तमान सीपीआई श्रृंखला में सबसे अधिक थी। चौथी तिमाही (जनवरी-फरवरी 2023) में स्थिति उलट गई क्योंकि अपेक्षा से उच्चतर अनाज

चार्ट II.1: सीपीआई मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष)

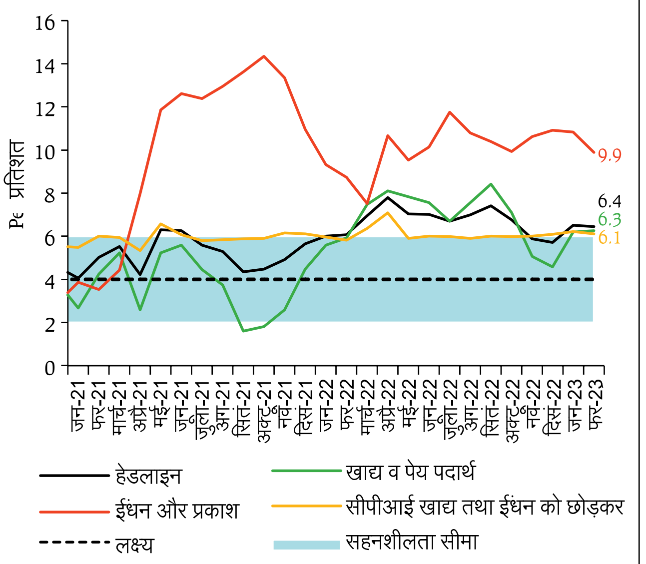

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ); और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

---

1 हेडलाइन मुद्रास्फीति को, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा सृजित अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में वर्ष-दर-वर्ष (वाई-ओ-वाई) परिवर्तनों द्वारा मापा जाता है। अप्रैल और मई 2021 के लिए वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति के आंकड़ों की गणना एनएसओ द्वारा अप्रैल और मई 2020 के लिए जारी किए गए अभ्यारोपित सूचकांक के आधार पर की गई है।

2 कोर सीपीआई, यानी, खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई को, हेडलाइन सीपीआई से 'खाद्य और पेय पदार्थ' और 'ईंधन और प्रकाश' समूहों को हटाकर आकलित किया जाता है।

चार्ट II 2: सीपीआई मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष): वास्तविक *बनाम* पूर्वानुमान

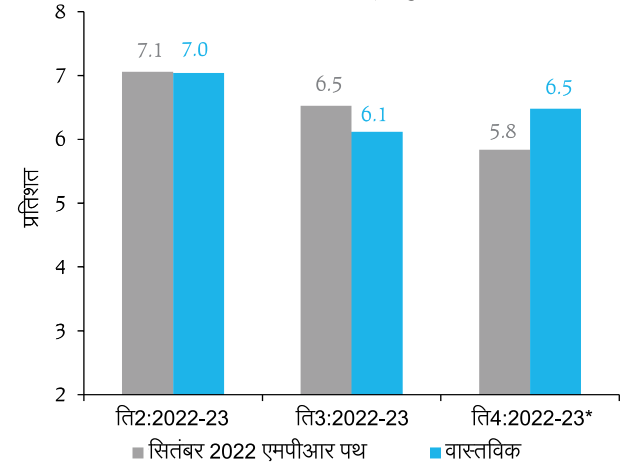

*: 2022-23 की संपूर्ण चौथी तिमाही के लिए पूर्वानुमानों की तुलना में जनवरी-फरवरी 2023 के दौरान वास्तविक औसत मुद्रास्फीति।
स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

मूल्य मुद्रास्फीति होने के कारण मुद्रास्फीति में अनुमान से 70 आधार अंकों की वृद्धि हो गई। बाजार में अनाज की ऊंची कीमतों[3] को देखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत मुफ्त में वितरित चावल और गेहूं को अलग करते हुए भारांकों के पुनर्वितरण के कारण सीपीआई एकत्रीकरण पद्धति, और सितंबर 2022 एमपीआर की बेसलाइन धारणा के सापेक्ष यूएसडी के मुक़ाबले रुपये में हुए मूल्यह्रास के कारण भी चौथी तिमाही में पूर्वानुमान त्रुटियां आईं।

II.1 उपभोक्ता मूल्य

दूसरी छमाही में हेडलाइन मुद्रास्फीति की गतिशीलता, खाद्य मूल्यों की अस्थिर गति और आधार प्रभावों के बीच परस्पर क्रिया को दर्शाती है[4]। सितंबर 2022 में हेडलाइन मुद्रास्फीति में 7.4 प्रतिशत की तेजी, जो अगस्त से लगभग 40 आधार अंकों की वृद्धि थी, व्यापक-आधारित सकारात्मक मूल्य गति से आई। अक्टूबर में, मूल्य गति में और तेजी के बावजूद खाद्य, ईंधन और कोर श्रेणियों में मजबूत अनुकूल आधार प्रभावों के कारण, हेडलाइन मुद्रास्फीति लगभग 60 आधार अंक घटकर 6.8 प्रतिशत हो गई। इसके बाद, हेडलाइन सीपीआई की गति में गिरावट दर्ज की गई, जो खाद्य कीमतों में गिरावट से प्रेरित थी। इसने, अनुकूल आधार प्रभावों के साथ, नवंबर में हेडलाइन मुद्रास्फीति को लगभग 90 आधार अंक कम किया। प्रतिकूल आधार के बावजूद दिसंबर में हेडलाइन गति में एक और तेज सुधार के कारण, हेडलाइन मुद्रास्फीति में लगातार दूसरे महीने नरमी आई। जनवरी 2023 में, खाद्य और मुख्य श्रेणियों में सकारात्मक मूल्य गति और प्रतिकूल आधार प्रभाव ने हेडलाइन मुद्रास्फीति को 80 आधार अंक ऊपर खींचकर 6.5 प्रतिशत कर दिया। फरवरी में, अनुकूल आधार प्रभाव के साथ खाद्य कीमतों में गिरावट के कारण, हेडलाइन मुद्रास्फीति में मामूली कमी आई और यह 6.4 प्रतिशत हो गई (चार्ट II.3)।

वर्ष 2022-23 के दौरान सीपीआई के वितरण ने पिछले वर्ष से अलग पैटर्न का खुलासा किया। वितरण का औसत 2022-23 (अप्रैल-फरवरी) में बढ़कर 6.8 प्रतिशत हो गया जो कि 2021-22 के दौरान 5.5 प्रतिशत था जबकि निम्नतर मानक विचलन और लघु धनात्मक झुकाव सीपीआई बास्केट में मुद्रास्फीति के दबाव के सामान्यीकरण की ओर इशारा करते हैं (चार्ट II.4 और II.5)।

कीमत दबावों का व्यापक आधार सीपीआई प्रसार सूचकांकों (डीआई)[5] में भी दिखाई दे रहा था, जो सीपीआई वस्तुओं द्वारा संचालित होने के कारण सितंबर 2022 से जनवरी

[3] पीडीएस में मुफ्त वितरण के कारण गेहूं और चावल के शून्य मूल्य के भारांक, अनाज समूह की अन्य वस्तुओं में अंतरित हुए। (दास, प्रज्ञा और आशीष थॉमस जॉर्ज (2023), "उपभोक्ता मूल्य सूचकांक: एकत्रीकरण विधि मायने रखता है", रिज़र्व बैंक बुलेटिन, मार्च)।

[4] किसी भी दो महीनों के बीच सीपीआई वर्ष-दर-वर्ष (वाई-ओ-वाई) मुद्रास्फीति में परिवर्तन, वर्तमान माह-दर-माह (एम-ओ-एम) मूल्य सूचकांक (गति) में परिवर्तन और 12 महीने पहले मूल्य सूचकांक में एम-ओ-एम परिवर्तन के बीच का अंतर है (आधार प्रभाव)। अधिक जानकारी के लिए, एमपीआर, सितंबर 2014 का बॉक्स I.1 देखें।

[5] सीपीआई प्रसार सूचकांक, जो कीमत परिवर्तनों के विकीर्णन को मापने का साधन है, सीपीआई बास्केट में वस्तुओं को वर्गीकृत करता है कि पिछले महीने की तुलना में क्या उनकी कीमतें बढ़ी हैं, स्थिर हैं या गिर गई हैं। प्रसार सूचकांक के लिए रीडिंग 50 से अधिक होने का अर्थ है, कीमत वृद्धि का विस्तार व्यापक रूप से या आम है; यदि 50 से नीचे है, तो सभी वस्तुओं की कीमतों में व्यापक गिरावट है।

चार्ट II.3 : सीपीआई मुद्रास्फीति – गति तथा आधार प्रभाव

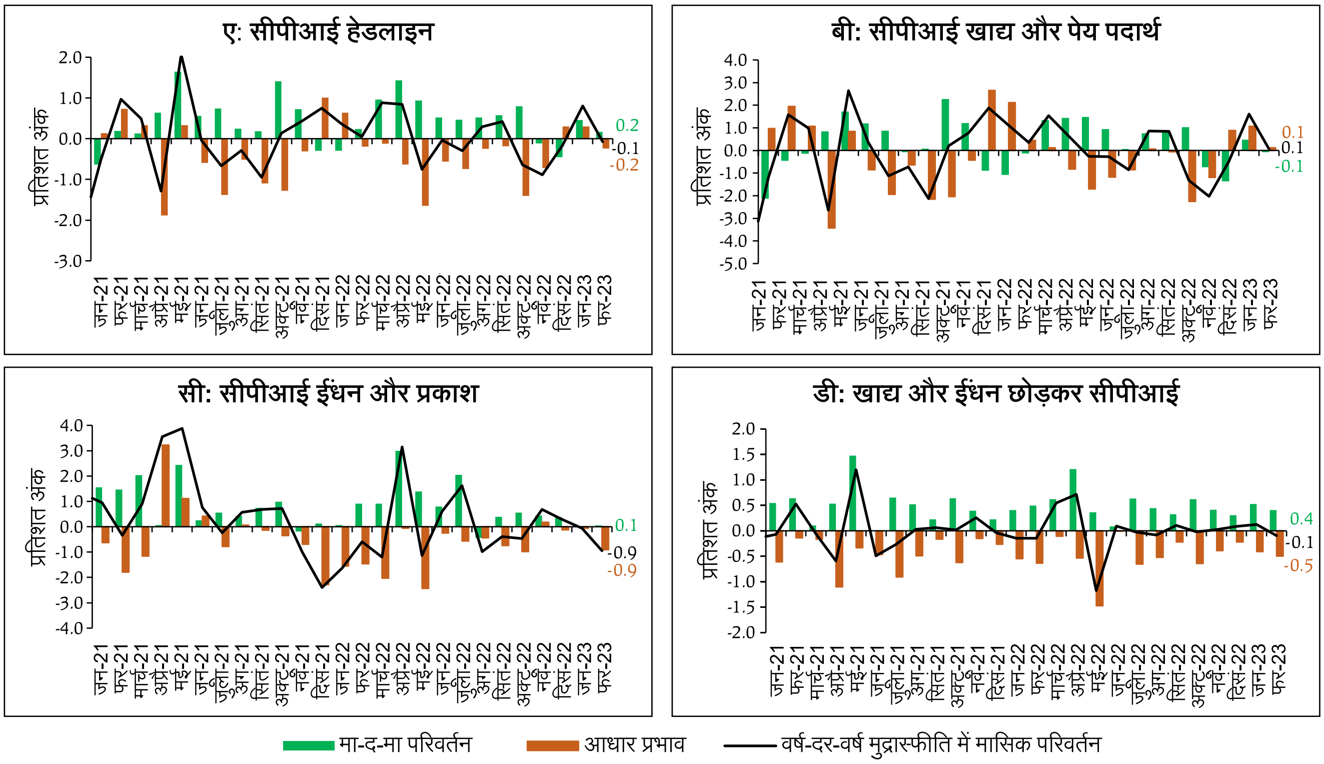

स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

2023 के दौरान बढ़ गया जो कि फरवरी में कुछ कम हुआ (चार्ट II.6ए)। पिछले छह महीनों के दौरान औसतन मौसमी रूप से समायोजित वार्षिक दर (सार) के आधार पर कीमत वृद्धि के लिए डीआई[6] सीमा 6 प्रतिशत से अधिक रही (चार्ट II.6बी)।

चार्ट II.4: औसत सीपीआई मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष) (केरनेल घनत्व अनुमान)

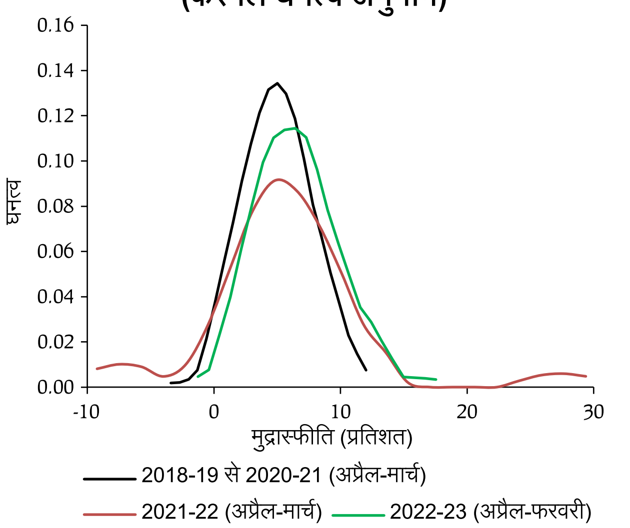

स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट II.5: सीपीआई उप समूह/समूह मुद्रास्फीति सीमा (वर्ष-दर-वर्ष)

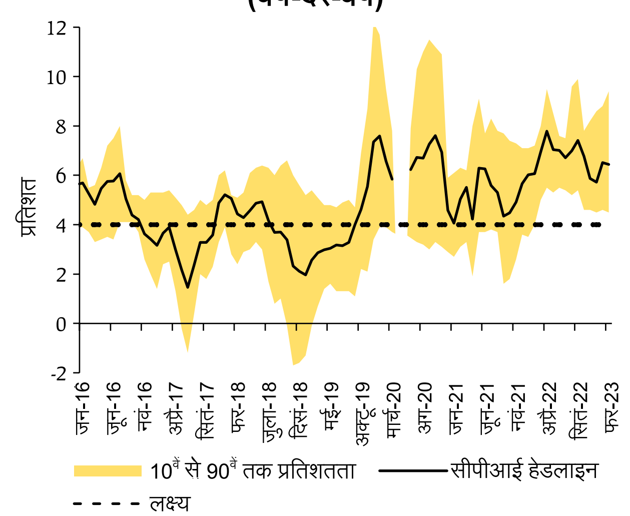

स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

6 सीमा प्रसार सूचकांक सीपीआई बास्केट में कीमत वृद्धि के फैलाव को 4 प्रतिशत और 6 प्रतिशत की निर्दिष्ट एसएएआर सीमा से ऊपर के कीमत को दर्शाता है।

चार्ट II.6: सीपीआई डिफ्यूज़न सूचकांक (माह-दर-माह मौसमी रूप से समायोजित)

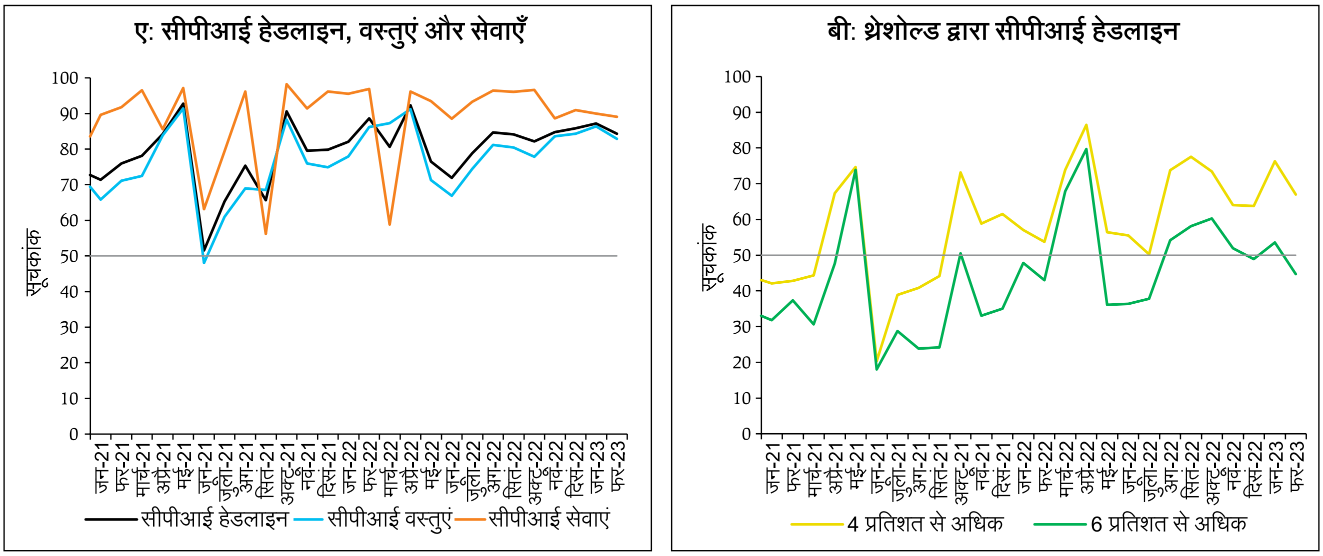

स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

II.2 मुद्रास्फीति के चालक

वेक्टर ऑटोरिग्रेशन (वीएआर)[7] मॉडल का उपयोग करते हुए मुद्रास्फीति का ऐतिहासिक विश्लेषण इंगित करता है कि दूसरी छमाही में आपूर्ति आघातों ने मुद्रास्फीति प्रक्षेपवक्र को गति प्रदान की, जबकि मौद्रिक कार्यों और कुल मांग की स्थितियों ने नीचे की ओर दबाव डाला (चार्ट II.7 ए)। आपूर्ति-पक्ष एवं लागत-प्रेरित आघातों के विश्लेषण से पता चलता है कि हेडलाइन सीपीआई पर उनके प्रभाव के संदर्भ में प्रत्यक्ष प्रभाव हावी हैं जबकि अप्रत्यक्ष प्रभाव भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं (बॉक्स II.1)।

बॉक्स II.1: घरेलू लागत-प्रेरित कीमत आघात और सीपीआई मुद्रास्फीति: इनपुट-आउटपुट सारणियों का उपयोग कर एक मूल्यांकन

बढ़ी हुई मुद्रास्फीति और इसकी निरंतरता आपूर्ति पक्ष के कई आघातों की एक श्रृंखला को दर्शाती है। यह देखा गया है कि जैसे ही आघातों का प्रत्यक्ष प्रभाव कम होता है, दूसरे दौर के प्रभाव जोर पकड़ लेते हैं, जिससे कीमत दबावों का सामान्यीकरण होता है। इसके अलावा, इस प्रसार तंत्र में कुछ क्षेत्र प्रणालीगत रूप से दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हैं (वेबर और अन्य., 2022)। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में घरेलू लागत-प्रेरित आघातों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव का विश्लेषण इनपुट-आउटपुट सारणी (आईओटी)[8] का उपयोग करके किया जा सकता है। प्रत्येक क्षेत्र में आघात लगने से सीपीआई बास्केट में कुल प्रभाव को समझने के लिए आईओटी को सीपीआई मदों/उप-समूहों में मैप किया जाता है। हेडलाइन मुद्रास्फीति पर क्षेत्रगत आघातों के प्रभाव का अनुमान *लियोन्टीफ इनवर्स मैट्रिक्स* (आरबीआई, 2022) का उपयोग करके लगाया जाता है, अर्थात,

$$L = (I - A)^{-1} \;;\; [e_{j,k}] = SHK.L \;;\; [C_j] = \sum_{k=1}^{K} e_{jk} \;;\; [I_k] = \sum_{j=1}^{J} e_{jk}$$

जहाँ L लियोन्टीफ इनवर्स है, I आयाम का पहचान मैट्रिक्स(J*KxJ*K) है, A आईओटी से प्राप्त तकनीकी गुणांक मैट्रिक्स है तथा J और K अर्थव्यवस्थाओं और उद्योगों की कुल संख्या है।

(जारी)

7 वेक्टर ऑटोरिग्रेशन (वीएआर) पर आधारित ऐतिहासिक विश्लेषणों का प्रयोग किसी प्रतिदर्श अवधि (2010-11 की चौथी तिमाही से 2022-23 की दूसरी तिमाही तक) के दौरान मुद्रास्फीति में उतार-चढ़ाव पर प्रत्येक आघात के प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है जिसके चर (वेक्टर Y_t के रूप में दर्शाया गया) इस प्रकार हैं - कच्चे तेल की कीमतें (प्रति बैरल यूएस डॉलर); विनिमय दर (रुपया प्रति अमरिकी डॉलर), परिसपंत्ति मूल्य (बीएसई सेंसेक्स), सीपीआई; उत्पादन अंतर; ग्रामीण मजदूरी; नीतिगत रेपो दर; और मुद्रा आपूर्ति(एम3)। नीतिगत रेपो दर को छोड़कर अन्य सभी चर वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर हैं। वीएआर को सक्षिप्त रूप में $Y_t = c + A\,Y_{t-1} + e_t$; के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर e_t आघातों के एक वेक्टर को दर्शाता है। वोल्ड विश्लेषण का प्रयोग करके, Y_t इसकी निर्धारक प्रवृत्ति के फलन और सभी आघातों के योग e_t के रूप में दर्शाए जा सकते हैं। इसका निरूपण मुद्रास्फीति की निर्धारक प्रवृत्ति का विभिन्न आघातों के योगदान के योग के रूप में विचलन के विश्लेषण की सुविधा प्रदान करता है।

8 आईओटी भारतीय संदर्भ में लागू किए गए अंतर-देश इनपुट-आउटपुट (आईसीआईओ) सारणी (ओईसीडी, 2021) पर आधारित हैं।

चार्ट II.1.1: सीपीआई मुद्रास्फीति पर 1 प्रतिशत अंक घरेलू क्षेत्रवार आघात का प्रभाव

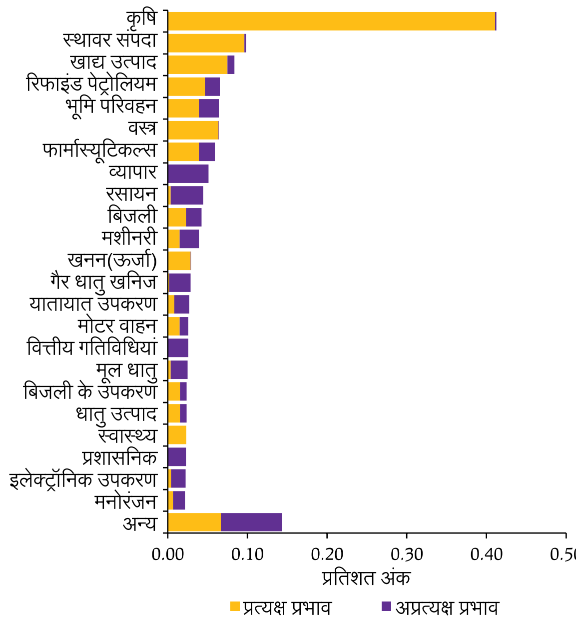

स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान।

अनुभवजन्य विश्लेषण से पता चलता है कि प्रत्येक क्षेत्र में 1 प्रतिशत अंक का आघात 46 आधार अंकों के अप्रत्यक्ष प्रभाव के साथ सीपीआई मुद्रास्फीति को 1.46 प्रतिशत अंक तक बढ़ा सकता है। क्षेत्र-वार, कृषि पर आघातों से हेडलाइन मुद्रास्फीति पर अधिकतम प्रभाव (41 बीपीएस) है, इसके बाद स्थावर सम्पदा(10 बीपीएस), खाद्य उत्पाद (8 बीपीएस) और रिफाइंड पेट्रोलियम (7 बीपीएस) का स्थान है (चार्ट II.1.1)। प्रत्यक्ष प्रभाव जो कि सीपीआई वस्तुओं के आघात और वजन के आकार पर निर्भर हैं, का वर्चस्व है। सीपीआई मुद्रास्फीति पर अप्रत्यक्ष प्रभाव व्यापार, रसायन, गैर-धातु खनिज और वित्तीय गतिविधियों जैसे क्षेत्रों के आघातों के मामले में अपेक्षाकृत बड़े हैं, हालांकि इन क्षेत्रों का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं है क्योंकि वे सीपीआई बास्केट का हिस्सा नहीं हैं। रिफाइंड पेट्रोलियम, भूमि परिवहन, फार्मास्यूटिकल्स और बिजली जैसे क्षेत्रों का सीपीआई मुद्रास्फीति पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह का प्रभाव पड़ता है। ये निष्कर्ष हाल के मुद्रास्फीति दबावों के लिए आपूर्ति प्रतिक्रियाओं की जानकारी दे सकते हैं।

संदर्भ:

ओईसीडी (2021), अंतर-देश इनपुट-आउटपुट सारणी।

आरबीआई (2022) "ग्लोबल कॉस्ट-पुश स्पिलओवर्स ऑन इन्फ्लेशन: इन्साइट्स फ्रॉम वर्ल्ड इनपुट-आउटपुट टेबल्स", बॉक्स I.2, *मौद्रिक नीति रिपोर्ट*, सितंबर।

वेबर, आई. एम., जौरेगुई, जे. एल., टेक्सेरा, एल., एंड नासिफ पिरेस, एल. (2022), "इन्फ्लेशन इन टाइम्स ऑफ ओवरलैपिंग ईमर्जेन्सीज: सिस्टेमिकली सिग्निफिकेंट प्राईसेस फ्रॉम एन इनपुट-आउटपुट पर्सपेक्टिव", यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स, इकोनॉमिक डिपार्टमेंट वर्किंग पेपर सिरीज़ 340.

हेडलाइन मुद्रास्फीति में माल का योगदान (समग्र सीपीआई में 76.6 प्रतिशत के भार के साथ) सितंबर 2022-फरवरी 2023 के दौरान 81 प्रतिशत रहा जबकि इसी अवधि में सेवाओं का योगदान (समग्र सीपीआई में 23.4 प्रतिशत के भार के साथ) 19 प्रतिशत रहा (चार्ट II.7बी)। वस्तुओं में, अर्ध-नाशवान वस्तुएं (30-दिन की वापसी वाले गैर-टिकाऊ वस्तुएं[9]) विशेष रूप से पेट्रोलियम उत्पाद (जैसे केरोसिन तेल, एलपीजी और जलाऊ लकड़ी और चिप्स) और अनाज, व्यक्तिगत देखभाल की वस्तुएं और दवाएं और साथ ही टिकाऊ वस्तुएं (365 दिन की वापसी वाली वस्तुएं) जैसे कपड़े और जूते के सामान, मोटर साइकिल/स्कूटर और सोना मुख्य चालक थे। समग्र मुद्रास्फीति में जल्दी खराब होने वाले वस्तुओं का योगदान फरवरी 2023 में घटकर 19 प्रतिशत रह गया, जो सितंबर 2022 में 38 प्रतिशत था।

यूक्रेन संघर्ष के बाद वैश्विक पण्य कीमतों में वृद्धि ने मार्च-जून 2022 के दौरान आयातित घटकों[10] के योगदान की वृद्धि में सहयोग दिया। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय पण्य की कीमतों में गिरावट

9 सीपीआई भार आरेख में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा किए गए 2011-12 उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के आधार पर आशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि (एमएमआरपी) के आंकड़ों का उपयोग किया जाता है। एमएमआरपी के अंतर्गत, पिछले सात दिनों के दौरान अक्सर खरीदी गई वस्तुओं पर किए गए खर्च के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं जैसे- खाद्य तेल, अंडे, मछली, मांस, सब्जियां, फल, मसाले, पेय पदार्थ, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, पान, तंबाकू और मादक पदार्थ- पिछले 365 दिनों के दौरान खरीदे गए कपड़े, बिस्तर, जूते, शिक्षा, चिकित्सा (संस्थागत), टिकाऊ वस्तुएं; और पिछले 30 दिनों में खरीदे गए अन्य सभी खाद्य, इंधन और प्रकाश, विविध वस्तुएं और सेवाएं जिनमें गैर-संस्थागत चिकित्सा सेवाएं, किराए और कर के आंकड़े शामिल हैं।

10 घरलू कीमतों को प्रभावित करने वाली वैश्विक वस्तुओं में पेट्रोलियम उत्पाद; कोयला; इलेक्ट्रॉनिक सामान; सोना; चांदी; रासायनिक उत्पाद; धातु उत्पाद; कपड़ा; अनाज; दुग्ध, उत्पाद और वनस्पति तेल शामिल हैं - इनका सीपीआई बास्केट में कुल भारांक 36.4 प्रतिशत है।

चार्ट II.7: सीपीआई मुद्रास्फीति के संचालक

ए: सीपीआई मुद्रास्फीति का वियोजन*

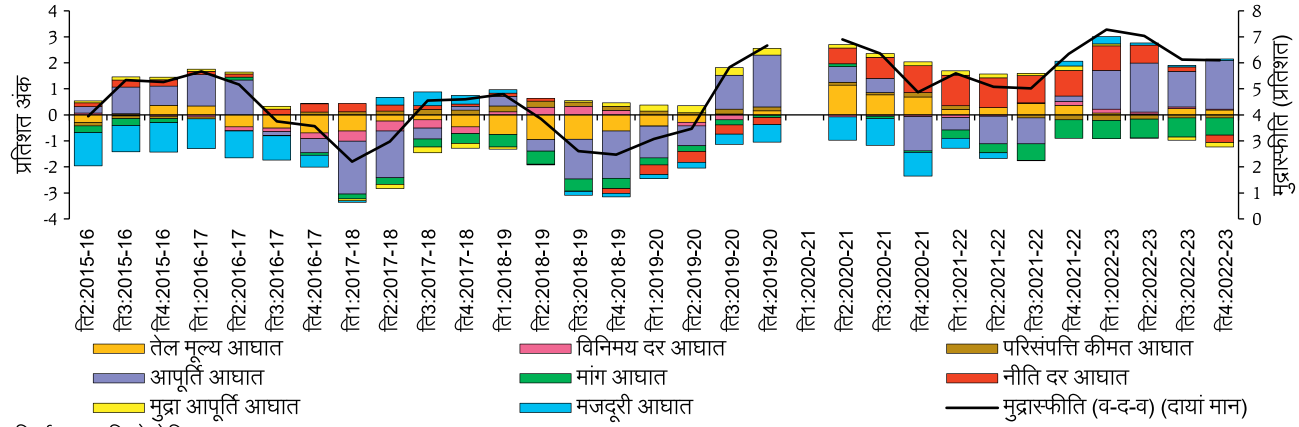

*निर्धारक प्रवृति से डेविएशन।

टिप्पणी: वेक्टर आटो रिग्रेशन का प्रयोग करते हुए अनुमानित (विस्तृत जानकारी के लिए फुटनोट 7 देखें)। ति4: 2022-23 जनवरी-फरवरी 2023 से संबंधित है।

स्रोत: एनएसओ; आरबीआई; पेट्रोलियम आयोजना और विश्लेषण कक्ष (पीपीएसी); बीएसई; श्रमिक ब्यूरो; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

बी: वस्तुओं तथा सेवाओं का योगदान

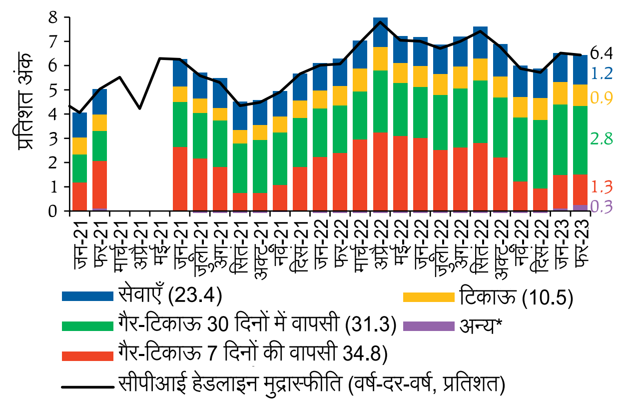

* भिन्न-भिन्न मदों और प्रकाशित उप-समूह/समूह/समग्र सीपीआई सूचकांक में वर्टिकली जोड़े गए सीपीआई मदों के सूचकांकों के बीच संतुलन की मद को दर्शाता है।

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिये गए आंकड़ें सीपीआई में भार को दर्शाते हैं।

सी: आयातित मुद्रास्फीति का योगदान

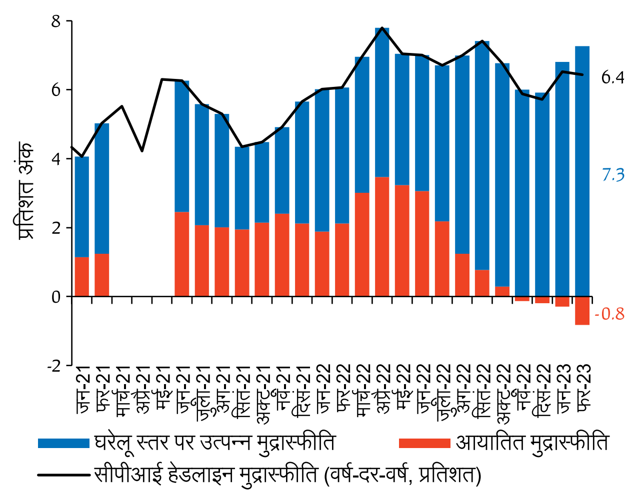

स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

के साथ आयातित मुद्रास्फीति का योगदान कम हो गया - यह नवंबर 2022-फरवरी 2023 के दौरान ऋणात्मक हो गया जो खाद्य तेलों, एलपीजी, इलेक्ट्रॉनिक सामानों के पुर्जों, पॉलिमर, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वर्ष-दर-वर्ष गिरावट से संचालित था (चार्ट II.7सी)।

सीपीआई खाद्य-समूह

सब्जियों की कीमतों में तेज सुधार के कारण, खाद्य और पेय पदार्थों की मुद्रास्फीति (सीपीआई बास्केट में भारांक 45.9 प्रतिशत) सितंबर 2022 में 8.4 प्रतिशत से घटकर दिसंबर में 4.6 प्रतिशत हो गई। हालांकि, फरवरी 2023 तक यह फिर से बढ़कर 6.3 प्रतिशत हो गई, क्योंकि अनाज और उत्पादों, दूध और मसालों की कीमतों में वृद्धि ने सब्जियों की कीमतों में आई मौसमी गिरावट को पीछे छोड़ दिया। गेहूँ और मसालों के कम रबी उत्पाद, चावल के कम खरीफ उत्पादन और गेहूं के बफर स्टॉक में गिरावट के कारण अनाज, उच्च निविष्टि लागत, और मसालों की कीमतों में वृद्धि हुई (चार्ट II.8)। सब्जियों को छोड़कर, सीपीआई खाद्य मुद्रास्फीति सितंबर-अक्टूबर 2022 के दौरान 7.0 प्रतिशत से बढ़कर फरवरी में 9.0 प्रतिशत हो गई।

चार्ट II.8: सीपीआई खाद्य मुद्रास्फीति

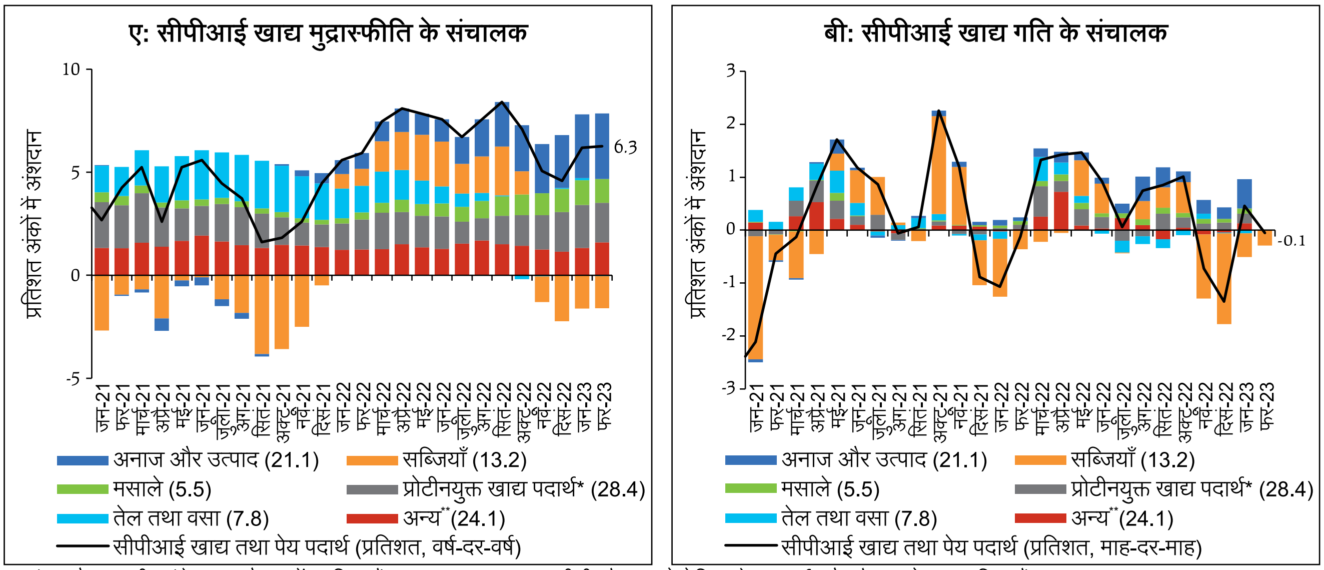

*: मांस और मछली, अंडे, दूध और दालें शामिल हैं। **: फल, चीनी, गैर-एल्कोहोलिक पेय पदार्थ और तैयार भोजन शामिल हैं |
टिप्पणी: कोष्ठकों में दिये गए आंकड़े सीपीआई खाद्य पदार्थ और पेय में भार को दर्शाते हैं।
स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

2022-23 में समग्र रूप से खाद्य मूल्य बने वे ऐतिहासिक अनुभवों से कम रहे, इसके बावजूद, बारह उप-समूहों में से पांच - अनाज; अंडे; मसाले; दूध; और तैयार भोजन - के संबंध में वृद्धि उनके दीर्घकालिक औसत से अधिक थी (चार्ट II.9)।

अनाज में मुद्रास्फीति (सीपीआई में 9.7 प्रतिशत और खाद्य और पेय समूह में 21.1 प्रतिशत का भार) अगस्त 2022 में 10 प्रतिशत से कम से बढ़कर फरवरी 2023 में 16.7 प्रतिशत हो गई, जो वर्तमान सीपीआई श्रृंखला में सबसे अधिक है(चार्ट II.10)। गेहूं और चावल ऐसे प्राथमिक चालक थे, जिन्होंने क्रमशः जून और अक्टूबर 2022 से दोहरे अंकों की मुद्रास्फीति दर्ज की। प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में गर्मी की लहर, स्टॉक में गिरावट और यूक्रेन में संघर्ष के चलते वैश्विक कीमतों में वृद्धि के कारण घरेलू उत्पादन

चार्ट II.9: वित्तीय वर्ष का कीमत बिल्ड अप (फरवरी की तुलना में मार्च)

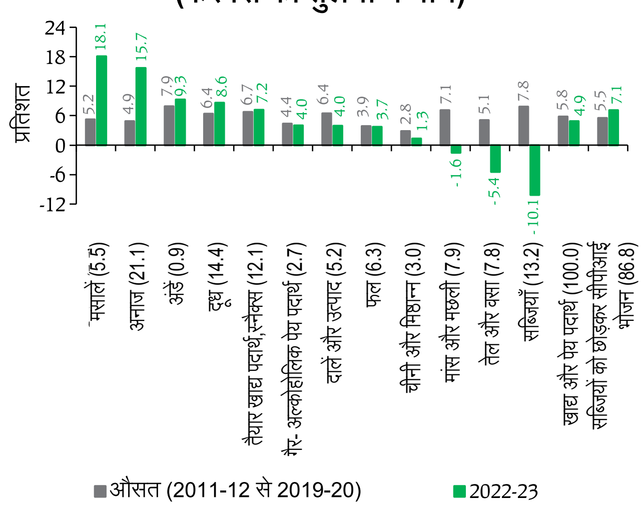

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिये गए आंकड़े सीपीआई-खाद्य और पेय पदार्थ में भार को दर्शाते हैं।
स्रोत: एनएसओ; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट II.10: सीपीआई अनाज और उत्पाद (संचयी वित्तीय वर्ष गति)

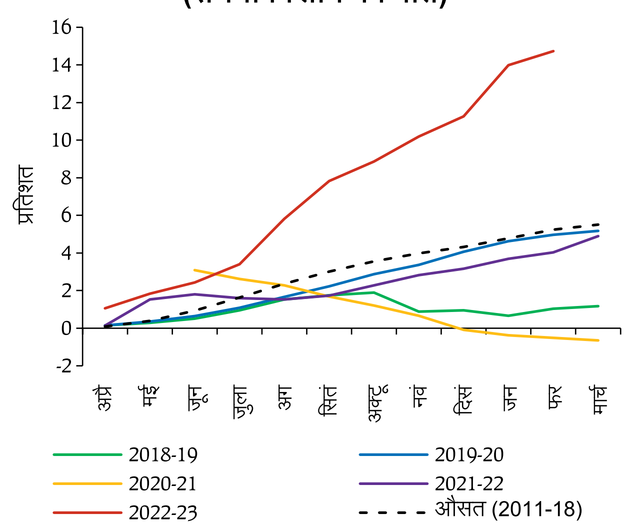

स्रोत: एनएसओ; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

[2021-22 में (-)1.7 प्रतिशत] कम होने की वजह से गेहूं की कीमतों में तेजी आई। खुले बाजार में कम आरक्षित मूल्य पर सरकार द्वारा संचयी 3.4 मिलियन टन गेहूं जारी करने के साथ-साथ 2022-23 में उच्च अनुमानित *रबी* उत्पादन (4.1 प्रतिशत की वृद्धि) ने मूल्य दबाव को धीरे-धीरे कम कर दिया है। घरेलू आपूर्ति में सुधार और मूल्य दबाव को कम करने के लिए मई 2022 से सरकार ने गेहूं के निर्यात पर और 25 अगस्त 2022 से गेहूं के आटे के निर्यात पर प्रतिबंध जारी रखा। 2022-23 में *खरीफ* उत्पादन ((-) 2.6 प्रतिशत) में आई गिरावट के कारण चावल में मुद्रास्फीति उच्च बनी रही। आगे, निर्यात की उच्च मात्रा (अप्रैल 2022 के दौरान वर्ष-दर-वर्ष 6.5 प्रतिशत) भी दर्ज की गई।

वर्ष 2022-23 के दौरान सब्जियों की कीमतों में मुद्रास्फीति (सीपीआई में 6.0 प्रतिशत और खाद्य और पेय समूह में 13.2 प्रतिशत का भारांक) अस्थिर रही। यह सितंबर 2022 में 18.2 प्रतिशत के उच्च स्तर से कम हुई और फरवरी 2023 में (-)11.6 प्रतिशत तक पहुंचकर मूल्य दबावों के मौसमी सहजता की शीघ्र शुरुआत के कारण नवंबर में अपस्फीति में प्रवेश कर गई। वर्ष 2021-22 में अधिक उत्पादन (17.4 प्रतिशत की वृद्धि), रिकॉर्ड खरीद (2022-23 में 2.5 लाख मीट्रिक टन का बफर स्टॉक) और *रबी* फसल की बेहतर संभावनाओं के कारण प्याज की कीमतें पूरे 2022-23 में अपस्फीति में बनी रहीं। हालांकि, वर्ष 2021-22 में कम उत्पादन ((-) 5.0 प्रतिशत) के कारण वर्ष के दौरान आलू की कीमत में मुद्रास्फीति उच्च बनी रही। कोल्ड स्टोरेज से स्टॉक का निर्गमन और *खरीफ* फसल की आवक के साथ, मौसमी पैटर्न के अनुसार नवंबर 2022 से कीमतों में गिरावट आई, जिससे फरवरी 2023 में मुद्रास्फीति नकारात्मक हो गई। जून 2023 तक भूटान से बिना किसी आयात लाइसेंस के आलू के आयात से भी कीमतों के दबाव पर लगाम लगी। प्रमुख उत्पादक राज्यों में उत्पादन पर लू के आघात, आंध्र प्रदेश में चक्रवात *'असानी'* और अतिरिक्त/बेमौसम बारिश के कारण टमाटर की कीमतों में उच्च अस्थिरता देखी गई। मौसमी पैटर्न के अनुसार और बुवाई क्षेत्र में वृद्धि के कारण अच्छे उत्पादन की प्रत्याशा के कारण नवंबर से कीमतें गिर गईं (चार्ट II.11)।

चार्ट II.11: सब्जी मुद्रास्फीति के संचालक (वर्ष-दर-वर्ष)

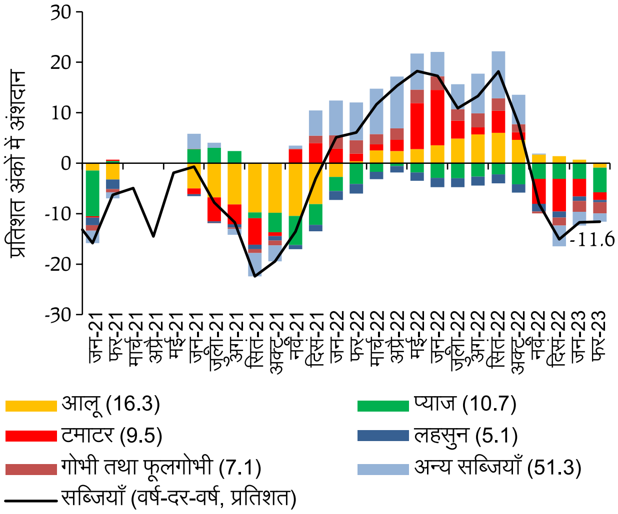

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिये गए आंकड़ें सीपीआई-सब्जियों में मदों के भार दर्शाते हैं। मार्च, अप्रैल और मई 2020 माह के लिए एनएसओ द्वारा मदवार आंकड़े जारी नहीं किए गए थे।

स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

वर्ष 2022-23 (अप्रैल-फरवरी) में औसतन 4.5 प्रतिशत के साथ फलों की कीमतों में मुद्रास्फीति (सीपीआई में 2.9 प्रतिशत और खाद्य और पेय समूह के भीतर 6.3 प्रतिशत का भार) अपेक्षाकृत कम थी। सेब और नारियल (फरवरी को छोड़कर) की कीमतों में अपस्फीति दर्ज की गई, जबकि केला, संतरा, पपीता और अन्य ताजे फलों की मुद्रास्फीति ऊंची बनी रही।

वर्ष 2022-23 में *अरहर* और *उड़द* के उत्पादन में कमी (क्रमशः 13.1 प्रतिशत और 1.0 प्रतिशत तक) के चलते *खरीफ* उत्पादन में गिरावट के कारण दालों, जो कि पादप-आधारित प्रोटीन का प्राथमिक स्रोत हैं, की कीमतों में मुद्रास्फीति (सीपीआई में 2.4 प्रतिशत और खाद्य और पेय समूह में 5.2 प्रतिशत का भारांक), अगस्त 2022 में 2.6 प्रतिशत से बढ़कर फरवरी में 4.1 प्रतिशत हो गई (चार्ट II.12)। आपूर्ति बढ़ाने और मूल्य दबाव को नियंत्रित करने के लिए, सरकार ने *तुअर* और *उड़द* के मुफ्त आयात की अवधि मार्च 2024 तक बढ़ा दी, *तुअर, उड़द* और *मसूर* के लिए मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत खरीद सीमा को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया और राज्यों को पीएसएस के तहत रियायती मूल्य पर *चना* के निपटान

चार्ट II.12: सीपीआई दालें और उत्पाद (संचयी वित्तीय वर्ष गति)

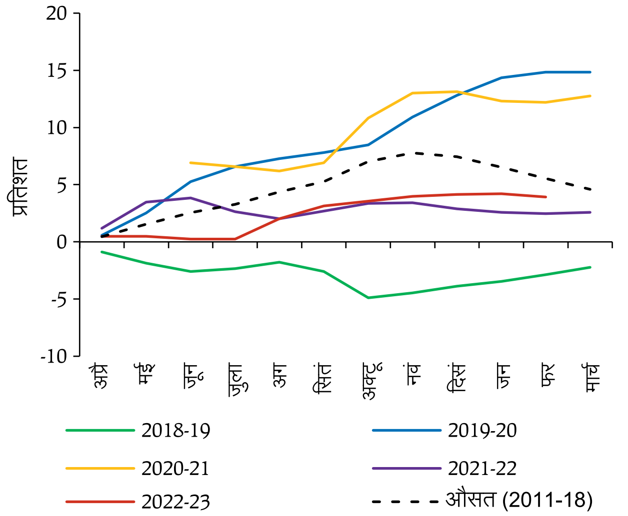

स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट II.13: दालें मुद्रास्फीति और स्टॉक-उपयोग अनुपात

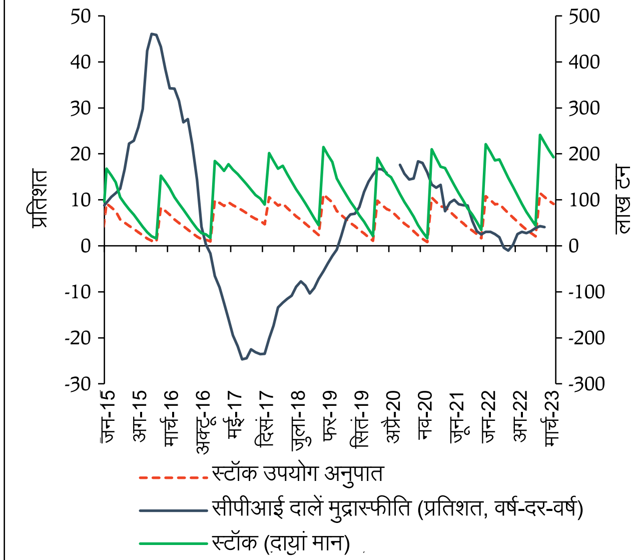

स्रोत: एमओएसपीआई; डीजीसीआईएस; सीएसीपी; कृषि मंत्रालय; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

की अनुमति दी। सरकार ने स्टॉक घोषणा की निगरानी को बढ़ा दिया है और *चना* के वायदा कारोबार पर रोक लगा दी है।

कुल मिलाकर, 2022-23 के दौरान 278 लाख टन का रिकॉर्ड दलहन उत्पादन और उच्च स्टॉक-टू-यूज (एसटीयू) अनुपात, घरेलू उपलब्धता और प्रभावी मूल्य प्रबंधन के लिए अच्छा संकेत है (चार्ट II.13)।

पशु आधारित प्रोटीन वस्तुओं में मुद्रास्फीति वर्ष 2022-23 (अक्टूबर-फरवरी) की दूसरी छमाही में तेजी से बढ़ी, जो मुख्य रूप से दूध और उत्पादों (सीपीआई में 6.6 प्रतिशत का भार और खाद्य और पेय समूह के भीतर 14.4 प्रतिशत) से प्रेरित थी (चार्ट II.14)। अमूल और मदर डेयरी जैसी प्रमुख दुग्ध सहकारी समितियों ने फीडस्टॉक लागत में वृद्धि का हवाला देते हुए सितंबर 2022 से दो से तीन चरणों में खुदरा कीमतों में 2-3 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की और इसके बाद अन्य राज्य सहकारी समितियों द्वारा भी कीमतों में वृद्धि की गई। फरवरी 2023 में 4.3 प्रतिशत तक कम होने के पूर्व, उच्च फ़ीड-लागत और मलेशिया को निर्यात में तेजी के कारण नवंबर 2022-जनवरी 2023 के दौरान अंडे की कीमतों में मुद्रास्फीति बढ़ी। फरवरी 2023 में कीमतों में सुधार के साथ-साथ अनुकूल आधार प्रभाव के कारण तेजी से कमी आने के पूर्व, जुलाई-नवंबर 2022 के दौरान मंद रहने के बाद मांस और मछली की मुद्रास्फीति (सीपीआई में 3.6 प्रतिशत और खाद्य और पेय समूह के भीतर 7.9 प्रतिशत का भार) जनवरी 2023 में बढ़कर 6.0 प्रतिशत हो गई।

चार्ट II.14: पशु प्रोटीन मुद्रास्फीति के संचालक (2022-23 की पहली छमाही की तुलना में 2022-23 की दूसरी छमाही)

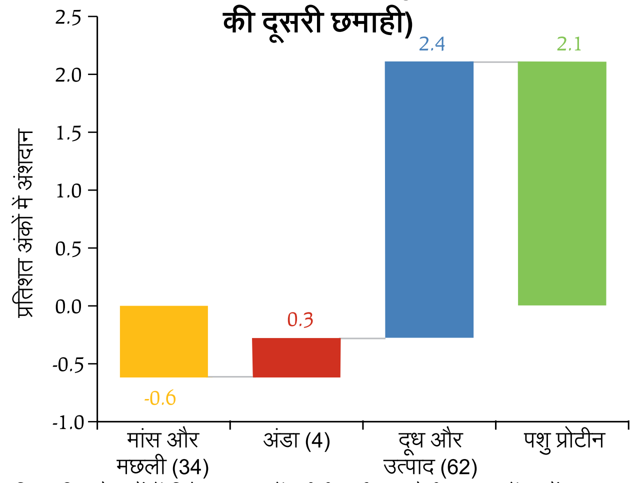

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिये गए आंकड़ें सीपीआई-पशु प्रोटीन समूह में 'मदों' का भार को दर्शाते हैं। 2022-23 की दूसरी छमाही अक्टूबर-फरवरी से संबंधित है।
स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट II.15: खाद्य तेल कीमतें: घरेलू और वैश्विक

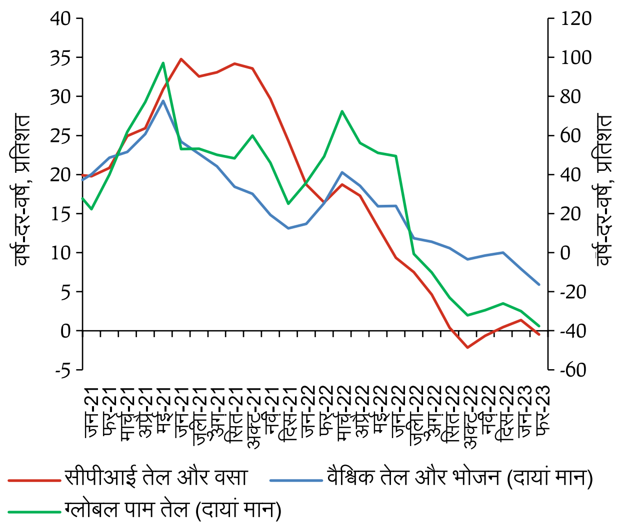

स्रोत: विश्व बैंक पिंक शीट; एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

तेल और वसा की कीमतों में मुद्रास्फीति (सीपीआई में 3.6 प्रतिशत और खाद्य और पेय समूह के भीतर 7.8 प्रतिशत का भार), जो 2022-23 के शुरुआती महीनों में यूक्रेन में संघर्ष और इंडोनेशिया द्वारा पाम तेल पर निर्यात प्रतिबंध के चलते वैश्विक कीमतों में वृद्धि के कारण बढ़ी थी, फरवरी 2023 में काफी कम होकर (-)0.5 प्रतिशत रह गई (चार्ट II.15)। इस नरमी को वैश्विक कीमतों में ढील, सरकार द्वारा आपूर्ति-पक्ष के उपायों (कच्चे और रिफाइंड तेलों पर मूल सीमा शुल्क में कमी और खाद्य तेल और तिलहन पर स्टॉक सीमा लागू करने) और 2022-23 में तिलहनों के उच्च अनुमानित घरेलू उत्पादन (5.4 प्रतिशत) से समर्थन मिला।

चीनी और मिष्ठान्न की कीमतों में मुद्रास्फीति (सीपीआई में 1.4 प्रतिशत तथा खाद्य और पेय समूह में 3.0 प्रतिशत भारांक) सितंबर 2022 में तेजी से कम हुई तथा उच्च घरेलू उत्पादन और 1 जून, 2022 से प्रभावी निर्यात प्रतिबंधों के कारण बाद के महीनों में भी कम बनी रही, इन प्रतिबंधों को पर्याप्त घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अक्टूबर 2023 तक बढ़ा दिया गया है।

अन्य खाद्य वस्तुओं में, मसालों की कीमतों में मुद्रास्फीति अप्रैल 2022 से फरवरी 2023 के दौरान औसतन 16.0 प्रतिशत रही, जो 2021-22 में प्रमुख मसालों, विशेष रूप से सूखी मिर्च, जीरा और धनिया के उत्पादन में कमी को दर्शाती है। खाद्य तेलों, एलपीजी और परिवहन लागतों से निविष्टि लागत में पिछली वृद्धि के धीरे-धीरे प्रभाव-अंतरण होने के कारण तैयार भोजन की कीमतों में वृद्धि हुई।

खुदरा मार्जिन

खुदरा मूल्य मार्जिन -- खुदरा और थोक कीमतों का अंतर[11] -- अनाज और दालों के लिए 2022-23 के दौरान लगातार ऊंचा बना रहा। खाद्य तेलों के लिए खुदरा मार्जिन में वृद्धि हुई क्योंकि खुदरा कीमतों (मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी और सरसों तेल) में गिरावट थोक कीमतों में गिरावट के अनुरूप कम थी। सब्जियों के मामले में सितंबर-नवंबर 2022 में मार्जिन में तेजी आई, जो सभी तीन घटकों, यानी आलू, टमाटर और प्याज से प्रेरित है। इसके बाद, कीमतों और मार्जिन में तीव्र मौसमी सुधार हुआ (चार्ट II.16)

सीपीआई ईंधन समूह

सितंबर 2022 से फरवरी 2023 के दौरान सीपीआई ईंधन मुद्रास्फीति उच्च थी और 9.9 प्रतिशत से 10.9 प्रतिशत के दायरे में रही। घरेलू एलपीजी की कीमतें फरवरी 2023 तक अपरिवर्तित रहीं, जबकि केरोसिन (पीडीएस) की कीमतें जुलाई 2022 के बाद अंतरराष्ट्रीय कीमतों के अनुरूप गिर गईं। केरोसीन की मुद्रास्फीति सितंबर 2022 में लगभग 60 प्रतिशत से घटकर फरवरी 2023 तक 30 प्रतिशत हो गई। दूसरी ओर, बिजली की कीमतें नवंबर 2022 में अपस्फीति की स्थिति से बाहर निकल गई और तब से काफी हद तक स्थिर बनी हुई हैं। फरवरी में नरम होने से पहले

[11] मद स्तर पर खुदरा और थोक मूल्यों का संकलन संबंधित उप-समूहों में मद स्तरीय सीपीआई भारांक का उपयोग करके किया जाता है। डीसीए द्वारा मूल्य संग्रह तंत्र और मद प्रकारों में बदलाव के कारण जनवरी-मार्च 2021 के आंकड़ों को बाहर रखा गया है।

चार्ट II.16: खुदरा और थोक मूल्य तथा मार्जिन

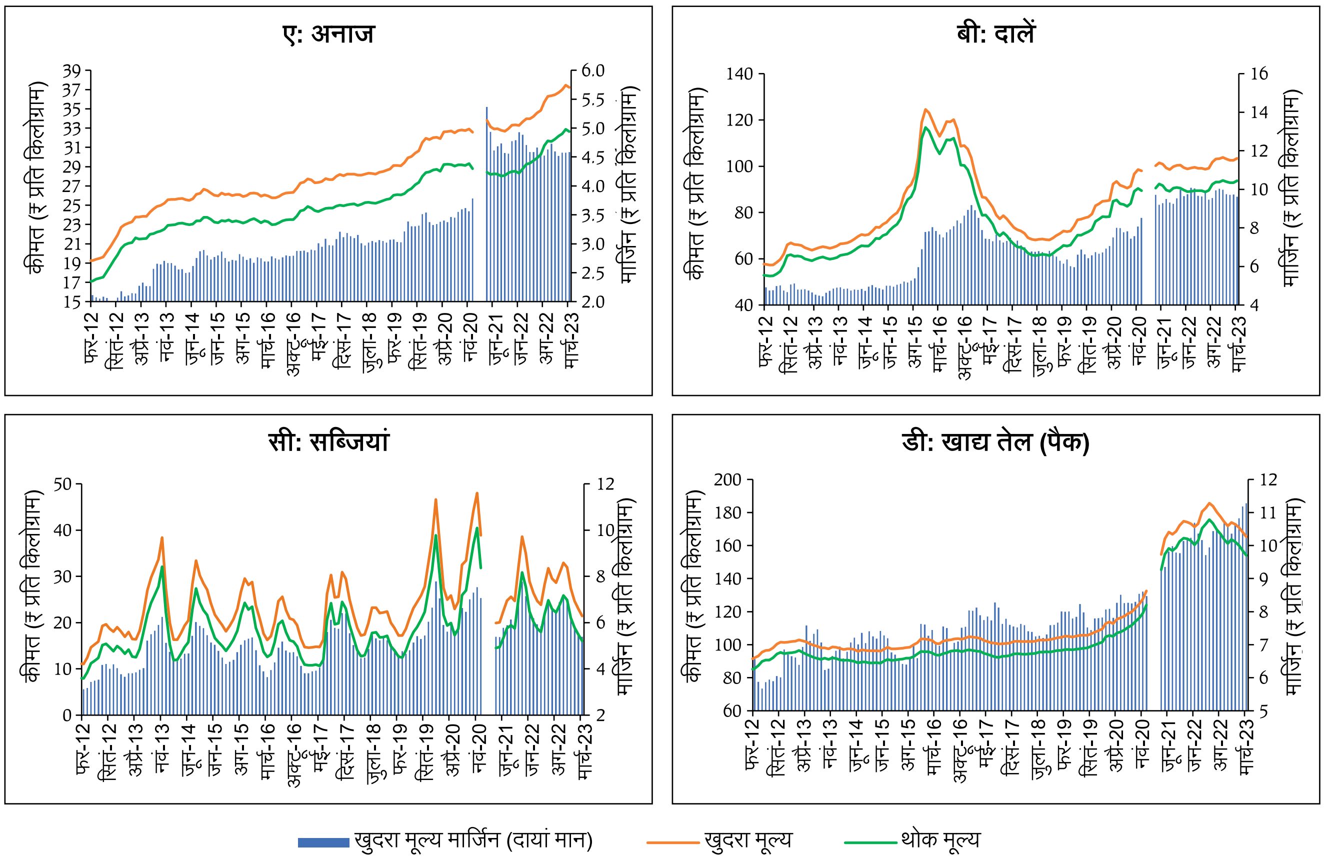

स्रोत: उपभोक्ता मामले विभाग; उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

तीसरी तिमाही के दौरान जलावन की लकड़ी और चिप्स संबंधी मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ गया (चार्ट II.17)।

मूल सीपीआई (खाद्य और ईंधन रहित सीपीआई)

मूल मुद्रास्फीति (खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई मुद्रास्फीति) ने दूसरी छमाही में 6 प्रतिशत और उससे ऊपर की स्थिरता का प्रदर्शन किया। उच्च मुद्रास्फीति दबाव मूल मुद्रास्फीति के सभी अपवर्जन-आधारित आंकड़ों में दिखाई दिया (सारणी II.1)।

वर्ष 2020-21 में, उच्च मूल मुद्रास्फीति परिवहन, संचार और व्यक्तिगत देखभाल और सामान जैसी चुनिंदा श्रेणियों में कीमतों के दबाव के कारण थी। हालांकि, 2021-22 के बाद से, यह तेजी से सामान्यीकृत और स्थायी हो गयी (चार्ट II.18)।

सारणी II.1: सीपीआई मुद्रास्फीति के अपवर्जित-आधारित आंकड़े (वर्ष-दर-वर्ष)

माह	खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई (47.3)	खाद्य, ईंधन, पेट्रोल और डीज़ल को छोड़कर सीपीआई (45.0)	खाद्य, ईंधन, पेट्रोल, डीज़ल, स्वर्ण और चांदी को छोड़कर सीपीआई (43.8)
मार्च-22	6.4	6.2	6.1
अप्रैल-22	7.1	6.5	6.4
मई-22	5.9	5.5	5.5
जून-22	6.0	6.1	6.1
जुलाई-22	6.0	6.3	6.4
अगस्त-22	5.9	6.2	6.2
सितं-22	6.0	6.3	6.4
अक्टू-22	6.0	6.5	6.5
नवं-22	6.0	6.3	6.4
दिसं-22	6.1	6.3	6.3
जन-23	6.2	6.5	6.3
फर-23	6.1	6.4	6.2

टिप्पणी: (1) कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े सीपीआई में भार को दर्शाते हैं।
(2) हेडलाइन सीपीआई से अवशिष्ट के रूप में व्युत्पन्न।

स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट II.17: सीपीआई ईंधन समूह मुद्रास्फीति

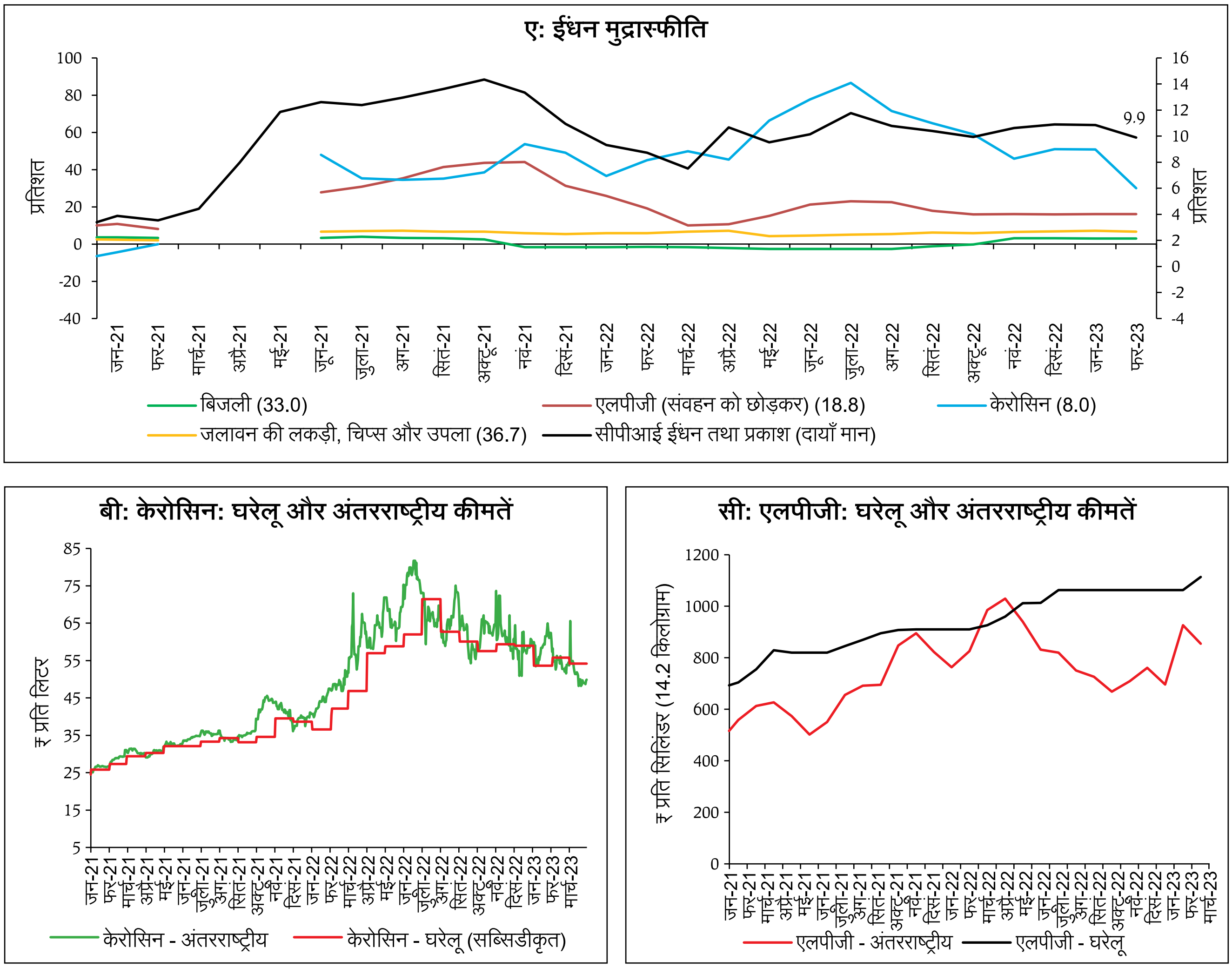

टिप्पणी: (1) एलपीजी के लिए अंतरराष्ट्रीय मूल्य सऊदी ब्यूटेन और प्रोपेन के लिए ब्लूमबर्ग स्पॉट मूल्य पर आधारित है, जो क्रमश: 60:40 के अनुपात में संयुक्त है। ये अंतरराष्ट्रीय उत्पाद मूल्य संकेतक आयात मूल्य हैं। अधिक जानकारी www.ppac.org.in पर उपलब्ध है।

(2) केरोसिन के लिए अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक मूल्य सिंगापुर जेट केरो स्पॉट मूल्य है।

(3) एलपीजी और केरोसिन की घरेलू कीमतें इंडियन ऑइल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के चार महानगरों की औसत कीमतों का प्रतिनिधित्व करती हैं।

(4) कोष्ठकों में दिये गए आंकड़ें सीपीआई-ईंधन समूह में मदों के भार को दर्शाते हैं।

स्रोत: एनएसओ; ब्लूमबर्ग; आईओसीएल; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

2022-23 (अप्रैल-फरवरी) के दौरान, मूल मुद्रास्फीति 2021-22 की समान अवधि के 6.0 प्रतिशत की तुलना में औसतन 6.1 प्रतिशत रही। 2021-22 और 2022-23 के बीच, समग्र कोर मुद्रास्फीति में परिवहन, संचार और स्वास्थ्य क्षेत्र के योगदान में गिरावट देखी गई, लेकिन घरेलू वस्तुओं और सेवाओं, व्यक्तिगत देखभाल और सामानों तथा शिक्षा के योगदान में वृद्धि के साथ कपड़े और फुटवेयर के योगदान में तेजी से वृद्धि हुई। 2022-23 के दौरान कोर सेवाओं का योगदान बढ़ा, जबकि कोर वस्तुओं का योगदान घटा (चार्ट II.19)।

सितंबर 2022 से फरवरी 2023 के दौरान पेट्रोल और डीजल के खुदरा बिक्री मूल्य अपरिवर्तित रहे (चार्ट II.20)।

अगस्त-नवंबर 2022 के दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमतें वर्ष-दर-वर्ष आधार पर अपस्फीति में चली गई और फरवरी

चार्ट II.18: खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई मुद्रास्फीति: सातत्य

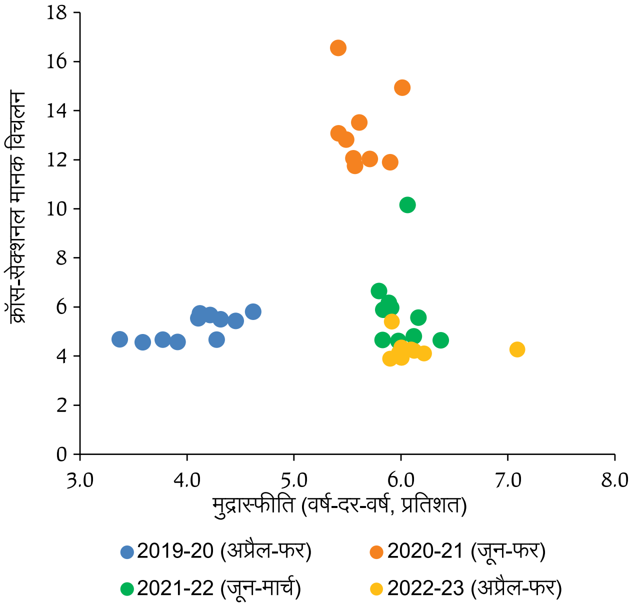

स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट II.19: खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई मुद्रास्फीति में योगदान (प्रतिशतता अंक)

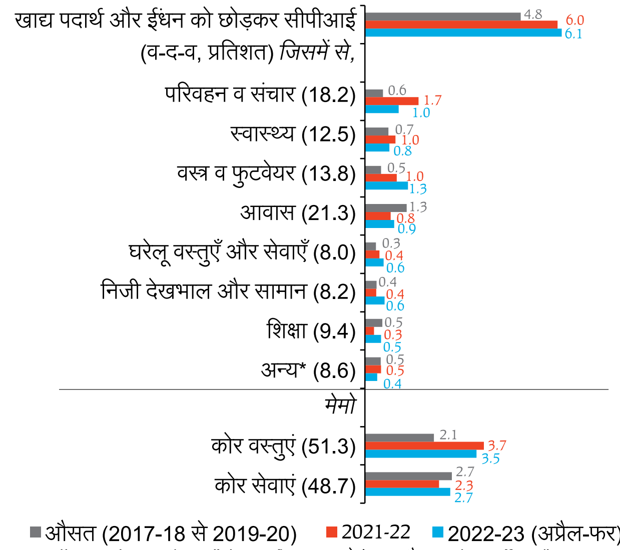

* अन्य में पान, तंबाकू और नशीले पदार्थ; तथा मनोरंजन और आमोद शामिल हैं।
टिप्पणी: कोष्ठकों में दिये गए आँकड़े खाद्य पदार्थ और ईंधन को छोड़कर सीपीआई में भार को दर्शाते हैं।
स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

में 0.9 प्रतिशत रहीं, जिसके परिणामस्वरूप परिवहन और संचार मुद्रास्फीति में और सीपीआई कोर मुद्रास्फीति में इसके योगदान में उल्लेखनीय गिरावट आई (चार्ट II.21)। दूसरी ओर, सोने की कीमतों में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप

चार्ट II.20: पेट्रोल और डीजल मूल्य बिल्ड-अप (आईओसीएल दिल्ली की कीमतें)

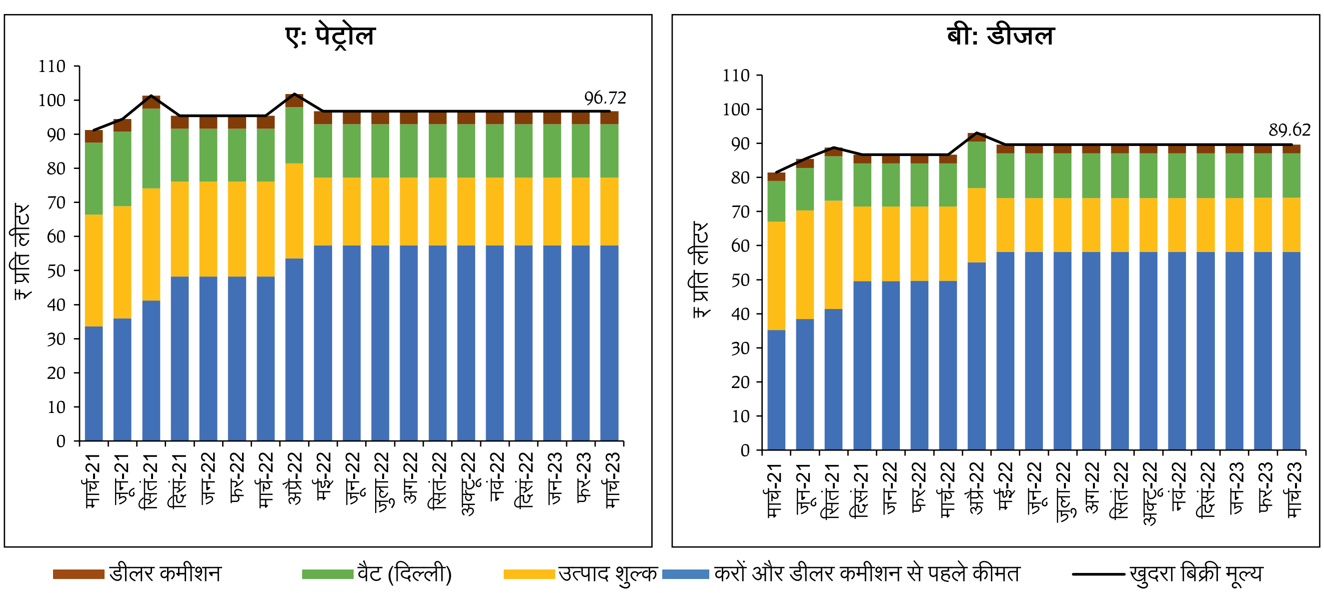

स्रोत: आइओसीएल और पीपीएसी।

चार्ट II.21: कोर मुद्रास्फीति के संचालक

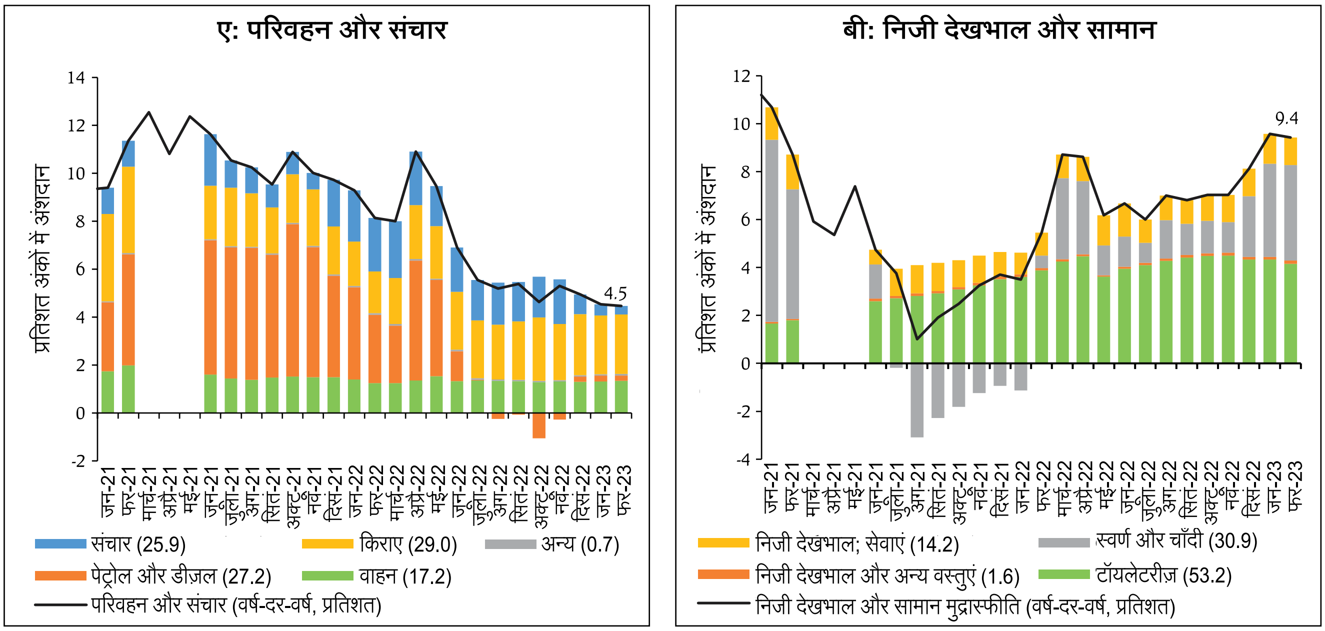

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिये गए आँकड़े संबन्धित उप-समूह में भार को दर्शाते हैं।
स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

निजी देखभाल की वस्तुओं से संबंधित मुद्रास्फीति में और उसके कोर मुद्रास्फीति में योगदान में वृद्धि हुई।

खाद्य, ईंधन, पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी को छोड़कर सीपीआई के लिए सीमाओं का व्याप्ति (थ्रेशोल्ड डिफ्यूज़न) सूचकांक सितंबर-अक्तूबर 2022 के दौरान 4 प्रतिशत से अधिक मूल्य वृद्धि दर्ज करने वाली वस्तुओं की उच्च संख्या को दर्शाता है। नवंबर 2022 से, 6 प्रतिशत से अधिक (एसएएआर) की मूल्य वृद्धि दर्ज करने वाली वस्तुओं के लिए व्याप्ति सूचकांक कमतर हो गया जो मूल्य वृद्धि की तीव्रता में कुछ नरमी को इंगित करता है (चार्ट II.22)।

खाद्य, ईंधन, पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी की मुद्रास्फीति को छोड़कर अपघटन अपने वस्तुओं (हेडलाइन सीपीआई में 20.7 प्रतिशत भार के साथ) और सेवाओं (23.0 प्रतिशत भार) के घटकों में सीपीआई का अपघटन यह दर्शाता है कि वस्तुगत मुद्रास्फीति सितंबर 2022 से फरवरी 2023 के दौरान औसतन 7.4 प्रतिशत रही, जो लगभग 5.4 प्रतिशत की सेवागत मुद्रास्फीति की तुलना में स्पष्ट रूप से अधिक है। वस्तुगत मुद्रास्फीति के मुख्य कारक – कपड़े और फुटवेयर, घरेलू सामान और सेवाएं और स्वास्थ्य रहे (चार्ट II.23ए)। सेवागत मुद्रास्फीति में, आवास

चार्ट II.22: खाद्य पदार्थ, ईंधन,पेट्रोल, डीजल,स्वर्ण और चांदी को छोड़कर सीपीआई: थ्रेशोल्ड द्वारा एसएएआर डिफ्यूजन इंडेक्स

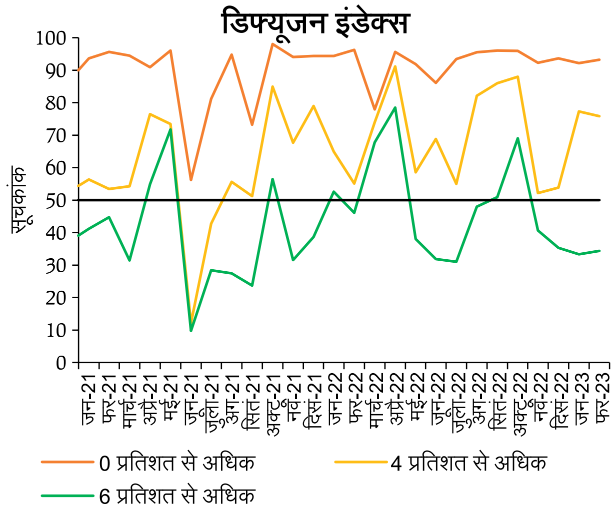

स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

(मुख्य रूप से आवास किराया शुल्क) का सबसे बड़ा योगदान रहा, इसके बाद परिवहन सेवाओं (बस/ट्राम/टैक्सी किराया, हवाई किराया) और शिक्षा (ट्यूशन और अन्य शुल्क) का स्थान रहा (चार्ट II.23बी)।

चार्ट II.23: खाद्य पदार्थ, ईंधन, पेट्रोल, डीजल, स्वर्ण और चांदी को छोड़कर सीपीआई मुद्रास्फीति में योगदान

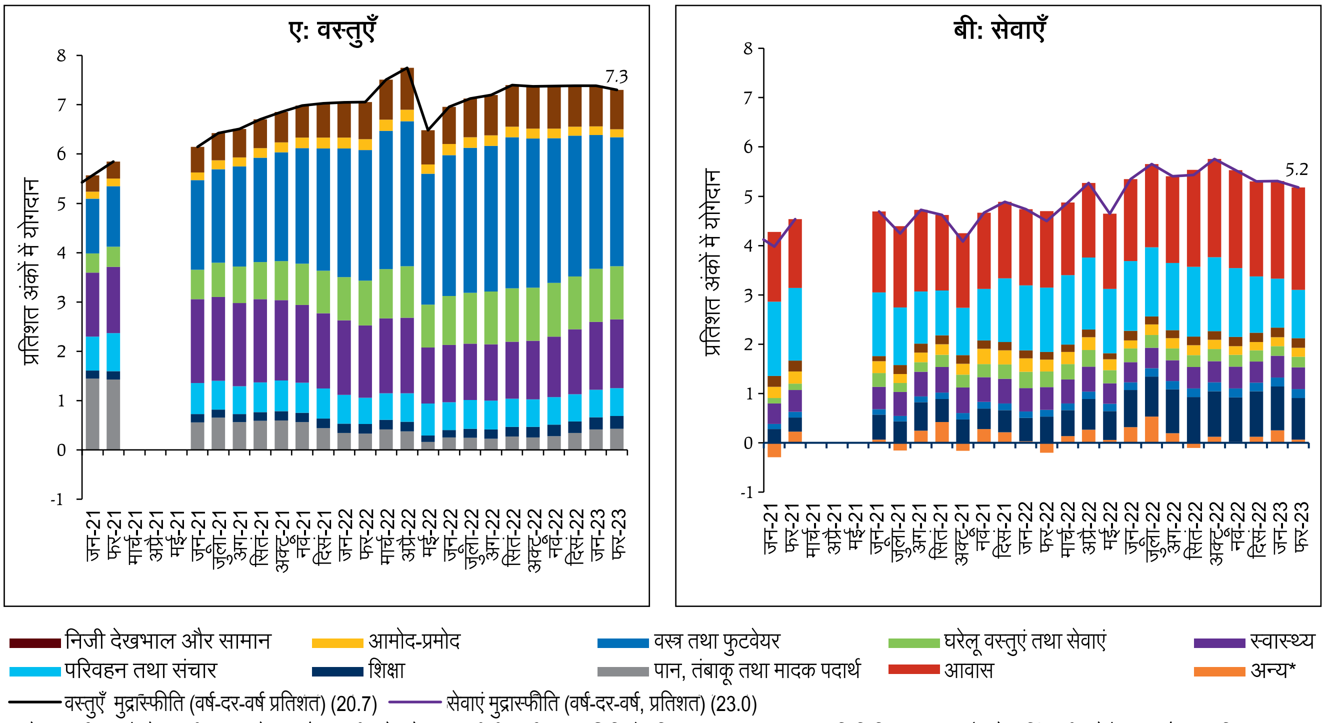

* भोजन, ईंधन, पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी को छोड़कर सीपीआई मुद्रास्फीति के लिए संतुलन शब्द का प्रतिनिधित्व करता है जो वर्टिकली जोड़े गए और अवशिष्ट आधारित गणना के बीच अंतर से आता है।

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिये गए आंकड़ें सीपीआई में भार को दर्शाते हैं।

स्रोत: एनएसओ तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

तराशे गए औसत मापकों[12] ने दिसंबर 2022-फरवरी 2023 (तालिका II.2) के दौरान 6.8 प्रतिशत पर भारित औसत मुद्रास्फीति दर के साथ बढ़े हुए अंतर्निहित मुद्रास्फीति दबावों को भी इंगित किया।

मुद्रास्फीति संबंधी अन्य मापक

कृषि श्रमिकों (सीपीआई-एएल) और ग्रामीण श्रमिकों (सीपीआई-आरएल) के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति, मुख्य रूप से सीपीआई-एएल और सीपीआई -आरएल में खाद्य मुद्रास्फीति अधिक होने के कारण सितंबर 2022 - फरवरी 2023 के दौरान सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति से ऊपर चली गई। दूसरी ओर, औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई (सीपीआई -आईडब्ल्यू) के संदर्भ में मुद्रास्फीति, हेडलाइन सीपीआई की तुलना में सीपीआई -आईडब्ल्यू में भोजन, कपड़े और फुटवेयर, आवास के साथ-साथ विविध श्रेणियों में कम होने के कारण इसी अवधि के दौरान हेडलाइन सीपीआई से नीचे रही।

सारणी II.2: सीपीआई मुद्रास्फीति के ट्रिम्ड मीन उपाय (वर्ष-दर-वर्ष)

माह	5% ट्रिम्ड	10% ट्रिम्ड	25% ट्रिम्ड	भारित माध्य
मार्च-22	6.6	6.3	6.1	6.1
अप्रैल-22	7.3	7.0	6.6	6.5
मई-22	6.4	6.1	5.5	5.7
जून-22	6.2	6.0	5.7	5.7
जुलाई-22	6.1	6.0	5.7	5.7
अगस्त-22	6.6	6.4	6.1	6.5
सितं-22	6.9	6.6	6.5	6.7
अक्टू-22	6.8	6.6	6.6	6.6
नवं-22	6.5	6.5	6.5	6.6
दिसं-22	6.5	6.5	6.5	6.9
जन-23	6.6	6.6	6.6	6.8
फर-23	6.6	6.5	6.5	6.6

स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

[12] जबकि व्यतिरेक-आधारित उपाय प्रत्येक अवधि में अस्थिर वस्तुओं (उदाहरण के लिए, खाद्य और ईंधन) के एक निश्चित सेट को गणना में नहीं लेते हैं, तराशे गए उपायों में मुद्रास्फीति वितरण के अंतिम छोर पर स्थित वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है अर्थात प्रत्येक महीने कीमतों में निर्दिष्ट सीमा से अधिक परिवर्तन प्रदर्शित करने वाली वस्तुओं को गणना में नहीं लिया जाता है और माह-दर-माह गणना में न ली जाने वाली वस्तुएं भिन्न-भिन्न होती हैं।

चार्ट II.24: मुद्रास्फीति के वैकल्पिक मापन

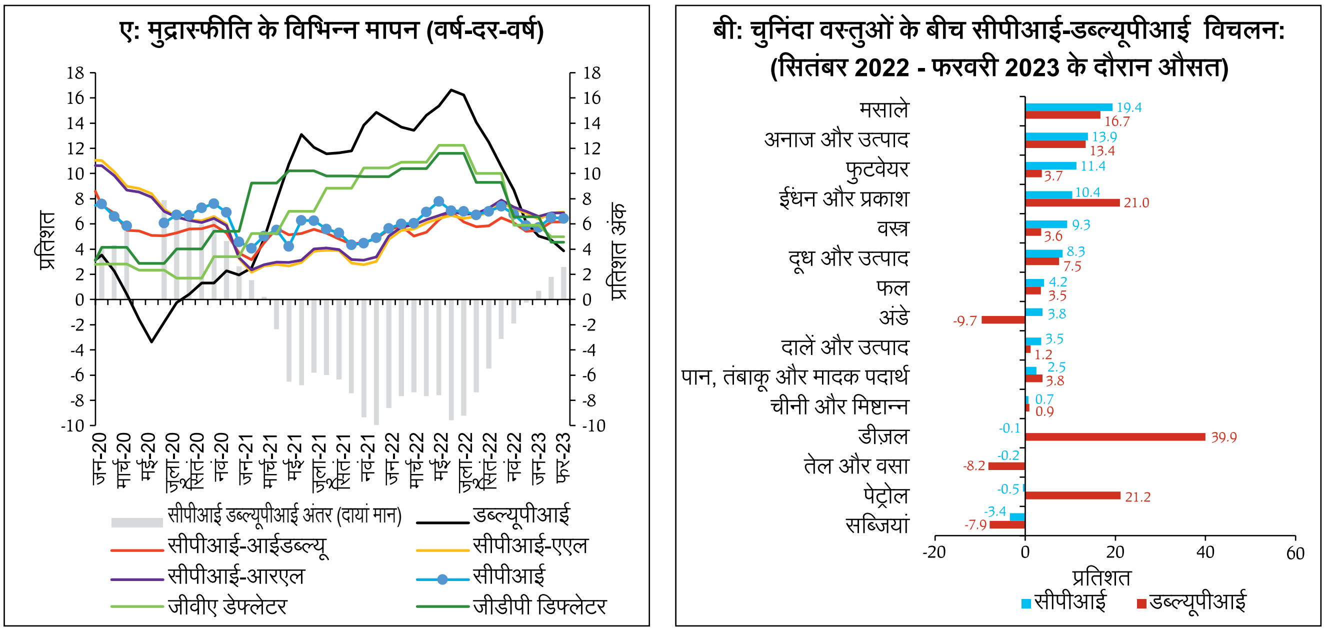

टिप्पणी: ति4:2022-23 के लिए, अंतर्निहित जीडीपी और जीवीए डिफ्लेटर का उपयोग किया जाता है।

स्रोत: एनएसओ; श्रमिक कार्यालय; वाणिज्य और औद्योगिक मंत्रालय; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) मुद्रास्फीति अप्रैल 2021 और सितंबर 2022 के बीच दोहरे अंकों में उच्च बनी रहने के पश्चात, अंतरराष्ट्रीय पण्य कीमतों में गिरावट और अनुकूल आधार प्रभावों के कारण फरवरी 2023 में 3.9 प्रतिशत पर आ गई। 2022-23 की तीसरी तिमाही में थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति में तीव्र नरमी ने योजित सकल मूल्य (जीवीए) और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) संबंधी अपस्फीतिकारकों द्वारा मापित मुद्रास्फीति को नीचे ला दिया (चार्ट II.24ए)।

जबकि कोविड-19 महामारी और यूक्रेन में संघर्ष के बाद डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति सीपीआई मुद्रास्फीति से आगे बढ़ गई, यह दिसंबर 2022 से सीपीआई मुद्रास्फीति से कम होने लगी।

सितंबर 2022-फरवरी 2023 के दौरान सीपीआई मुद्रास्फीति मसालों, फलों, प्रोटीन आधारित वस्तुओं (दालें, अंडा और दूध), कपड़ों और फुटवेयर के संबंध में संबंधित डब्ल्यूपीआई समूहों/उपसमूहों से ऊपर रही। खाद्य तेल और सब्जियों की कीमतों में अपस्फीति सीपीआई की तुलना में डब्ल्यूपीआई में अधिक थी। दूसरी ओर, ईंधन, पेट्रोल और डीजल में मुद्रास्फीति सीपीआई की तुलना में डब्ल्यूपीआई में अधिक थी (चार्ट II.24बी)[13]।

II.3 लागत

औद्योगिक कच्चे माल और कृषि आदानों की कीमतों से संबंधित डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति द्वारा मापी गई लागत, 2022-23 की दूसरी छमाही के दौरान धीरे-धीरे कम हो गई (चार्ट II.25)। औद्योगिक निविष्टियों - जैसे कि हाई-स्पीड डीजल (एचएसडी); नाफ्था; विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ); बिटुमेन; और फर्नेस ऑयल - की कीमतों में मुद्रास्फीति कम हो गई, जो अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में कमी को दर्शाती है। गैर-खाद्य प्राथमिक वस्तुओं, विशेष रूप से कच्चे कपास और तिलहन की कीमतों में अंतरराष्ट्रीय कीमतों और उच्च घरेलू उत्पादन की उम्मीदों के कारण गिरावट आई है। नवंबर 2022 से खनिज मूल्य मुद्रास्फीति

[13] थोक मूल्य सूचकांक और खुदरा मूल्य सूचकांक पेट्रोल और डीजल मुद्रास्फीति में अंतर इस तथ्य से उत्पन्न हुआ कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती के कारण सीपीआई पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट आई (वर्ष-दर-वर्ष आधार पर), डब्ल्यूपीआई प्रभावित नहीं हुआ क्योंकि डब्ल्यूपीआई में कीमतों की गणना घरेलू उत्पाद शुल्क प्रभावों के आधार पर की जाती है।

चार्ट II.25: कृषि तथा गैर-कृषि कार्य इनपुट लागत मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष)

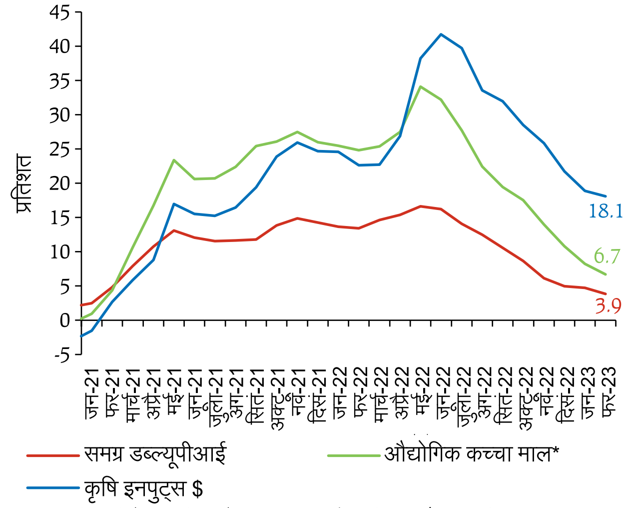

*: डब्ल्यूपीआई से प्राथमिक गैर-खाद्य वस्तुएँ, खनिज, कोयला, विमानन टरबाइन ईंधन, उच्च गति डीजल, नेफ्था, बिटुमेन, फर्नेस तेल, चिकनाई तेल, पेट्रोलियम कोक, बिजली, सूती धागे और कागज व लुगदी शामिल हैं।
$: डब्ल्यूपीआई से उच्च गति डीजल, चारा, बिजली, उर्वरक, कीटनाशक और कृषि एवं वानिकी मशीनरी शामिल हैं।
स्रोत: वाणिज्य और औद्योगिक मंत्रालय; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट II.26: ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी में वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) और मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष)

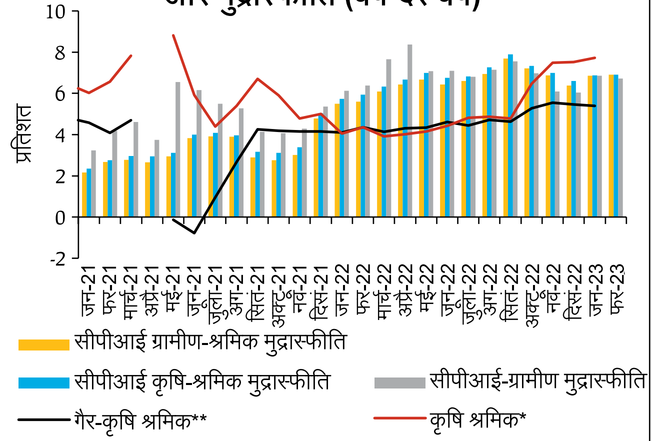

*: जुताई, बुवाई, कटाई, तुड़ाई, बागवानी मजदूर, मछुआरे, मछुआरे कोस्टल, लकड़हारे और लकड़ी काटने वाले, पशुपालन, पैकेजिंग, सामान्य कृषि मजदूर, पौध संरक्षण मजदूर शामिल हैं।
**: बढ़ई, लोहार, राज मिस्त्री, बुनकर, बीड़ी बनाने वाले, बांस-बेंत की टोकरी बुनकर, हस्तशिल्प कामगार, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, निर्माण मजदूर, एलएमवी और ट्रैक्टर चालक, झाड़-पोछ/सफाई कर्मचारी और अन्य गैर-कृषि मजदूर शामिल हैं।
टिप्पणी: अप्रैल-मई 2021 के लिए डेटा जारी नहीं किया गया।
स्रोत: एनएसओ; श्रम ब्यूरो; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

कम हो गई और अपस्फीति में बदल गई, जो लौह अयस्क की कीमतों में अपस्फीति और जनवरी 2023 से तांबा केंद्रित कीमतों में गिरावट से प्रभावित थी। एचएसडी की कीमतों में कमी के बावजूद चारा मूल्य में ऊंची मुद्रास्फीति के कारण कृषि निविष्टि मूल्य मुद्रास्फीति ऊंची बनी हुई है। डब्ल्यूपीआई बिजली की कीमत में मुद्रास्फीति - औद्योगिक और कृषि दोनों में एक महत्वपूर्ण इनपुट - उच्च स्तर पर बनी रही, जो वर्धित अंतरराष्ट्रीय कोयले की कीमतों और घरेलू मांग में वृद्धि के कारण उच्च इनपुट लागत को दर्शाती है।

अक्तूबर 2022 – जनवरी 2023 के दौरान कृषि और कृषि इतर मजदूरों दोनों के लिए सांकेतिक ग्रामीण मजदूरी संवृद्धि बढ़ी। जबकि कृषि मजदूरी संवृद्धि सभी व्यवसायों में व्यापक थी, गैर-कृषि मजदूरी में संवृद्धि मुख्य रूप से बीड़ी बनाने वाले, लोहार, राजमिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन और हल्के मोटर वाहन (एलएमवी)/ट्रैक्टर चालकों जैसी श्रेणियों द्वारा संचालित थी (चार्ट II.26)।

संगठित क्षेत्र में, विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों के लिए 2022-23 की तीसरी तिमाही में समग्र कर्मचारी लागत (वर्ष-दर-वर्ष आधार) में वृद्धि हुई। विनिर्माण और सेवाओं दोनों के लिए उत्पादन के मूल्य में कर्मचारियों की लागत का हिस्सा 2022-23 की दूसरी तिमाही में संबंधित स्तर से 2022-23 की तीसरी तिमाही में व्यापक तौर पर अपरिवर्तित था (चार्ट II.27)।

रिजर्व बैंक के उद्यम सर्वेक्षणों[14] में जिन कंपनियों के बीच सर्वेक्षण किया गया है, उनके अनुसार विनिर्माण, बुनियादी ढांचा और सेवा क्षेत्रों के वेतन खर्च की गति 2023-24 की पहली तिमाही में स्थिति व्यापक तौर पर स्थिर रहने की उम्मीद है। सभी के लिए

[14] औद्योगिक दृष्टिकोण सर्वेक्षण और सेवाएं तथा अवसंरचना दृष्टिकोण सर्वेक्षण।

चार्ट II.27: विनिर्माण और सेवाओं में स्टाफ लागत

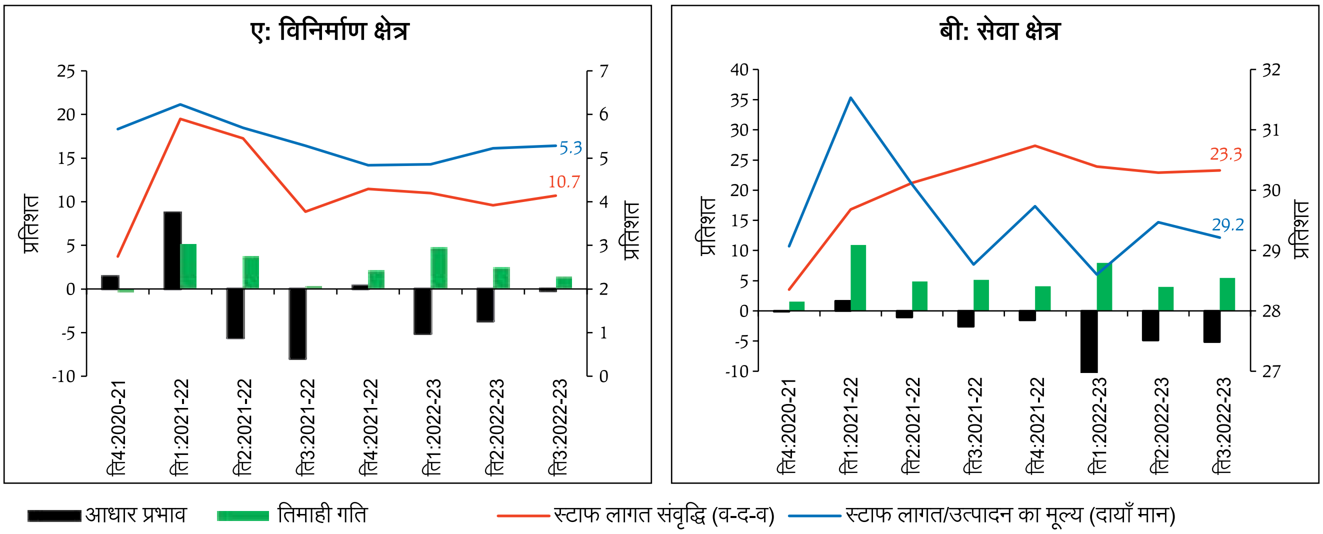

टिप्पणी: स्टाफ लागत वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) कंपनियों के सामान्य समूह पर आधारित है।
स्रोत: कैपिटलिन डेटाबेस; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

2023-24 की पहली तिमाही में इनपुट लागत दबाव कम होने की संभावना है। तीनों क्षेत्रों के लिए 2023-24 की पहली तिमाही में बिक्री कीमतों में कमी आने की उम्मीद है (चार्ट II.28)।

एक वर्ष आगे की व्यवसायिक मुद्रास्फिति प्रत्याशा[15], जो जनवरी 2023 में बढ़ गई थी, फरवरी 2023 में कम हो गई जो कीमत दबावों की कमी को दर्शाती है।

चार्ट II.28: लागत और मूल्य स्थितियों की अपेक्षाएं

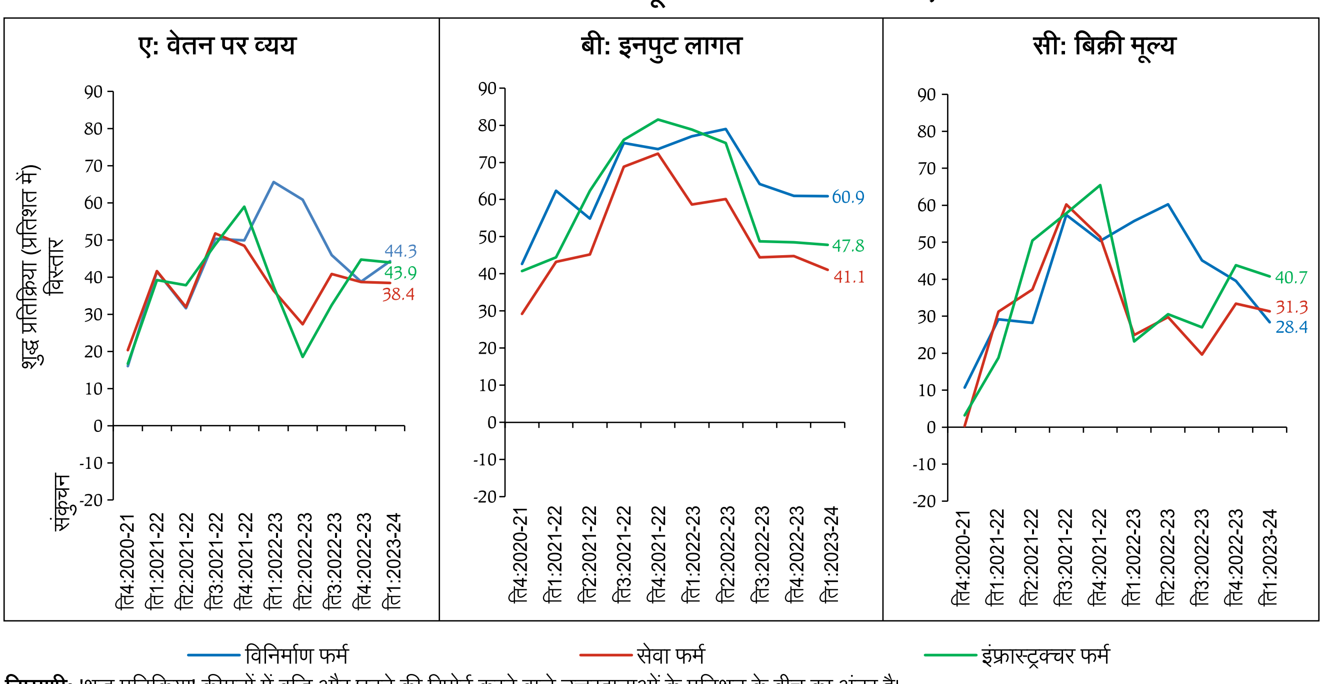

टिप्पणी: 'शुद्ध प्रतिक्रिया' कीमतों में वृद्धि और घटने की रिपोर्ट करने वाले उत्तरदाताओं के प्रतिशत के बीच का अंतर है।
स्रोत: रिज़र्व बैंक इंडस्ट्रियल आउटलूक सर्वे; सर्विसेस एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर आउटलूक सर्वे; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

[15] भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद के मासिक व्यापार मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण (बीआईईएस) पर आधारित। सर्वेक्षण में मुख्य रूप से विनिर्माण क्षेत्र के उद्योगपतियों का एक पैनल है, जिनसे लघु और मध्यम अवधि में मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं के बारे में मत लिया जाता है।

चार्ट II.29: पीएमआई इनपुट-आउटपुट मूल्य अंतर

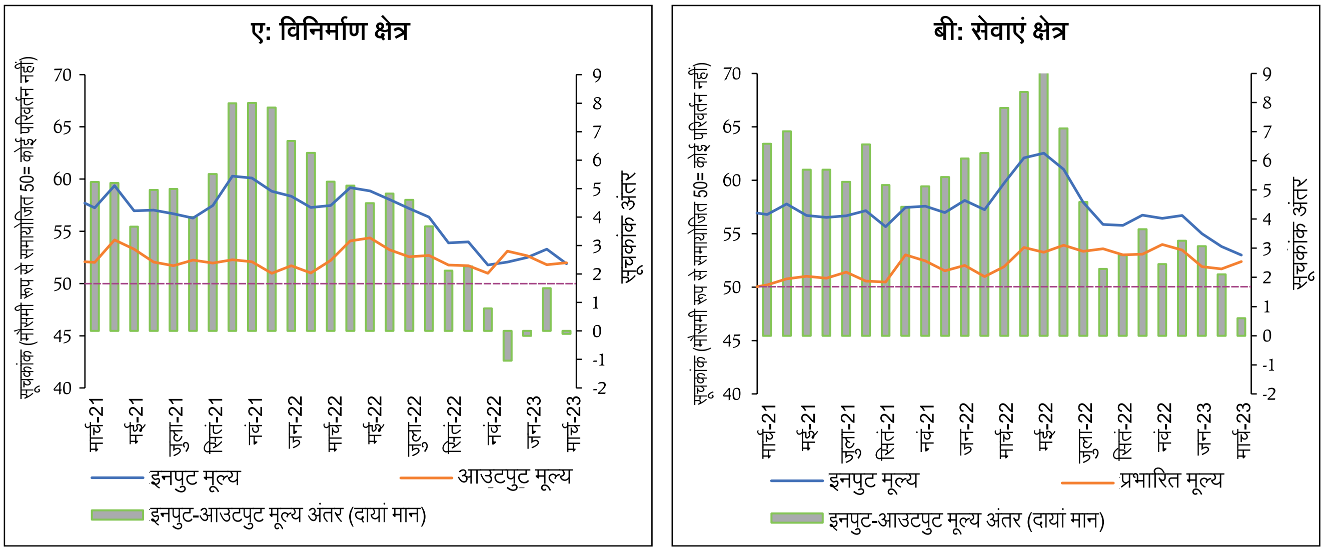

स्रोत: एसएण्डपी ग्लोबल; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) के लिए किए गए सर्वेक्षण में विनिर्माण कंपनियों के अनुसार, दिसंबर-फरवरी के दौरान इनपुट कीमतों में तेजी आई और फरवरी तक इनपुट-आउटपुट मूल्य अंतर के धनात्मक क्षेत्र में लौटने के साथ उत्पादन की कीमतें सामान्य रूप से कम हो गईं। इनपुट कीमतों में गिरावट के कारण इनपुट-आउटपुट कीमतों के बीच का अंतर पुनः ऋणात्मक हो गया जिससे मार्च महीने में यह प्रवृत्ति उलट गई (चार्ट II.29 ए)। पीएमआई सेवाओं में, इनपुट के साथ-साथ आउटपुट कीमतों की गति दिसंबर-फरवरी के दौरान कम हो गई और इनपुट-आउटपुट मूल्य अंतर अगस्त 2022 के बाद से काफी हद तक सीमा में रहा है (चार्ट II.29)। इनपुट कीमतों में कमी के साथ, मार्च महीने में प्रभारित कीमतों में वृद्धि हुई जिसके कारण इनपुट-आउटपुट कीमत का अंतर कम हुआ।

II.4 निष्कर्ष

प्रतिकूल आपूर्ति-पक्ष के झटकों और लंबित निविष्टि लागतों के प्रति उत्पादन की कीमतों के प्रभाव अंतरण के संयोजन ने 2022-23 के दौरान हेडलाइन मुद्रास्फीति पर निरंतर दबाव डाला। 2023-24 का परिदृश्य जलवायु से संबंधित बाधाओं, जैसे गर्मी की लहर और बेमौसम बारिश जोखिमों की अनिश्चितताओं से प्रभावित है। इसके अलावा, भू-राजनीतिक तनाव के पुनरुत्थान से आपूर्ति श्रृंखला अव्यवस्था और पण्य मूल्य पर दबाव हो सकता है; इसके विपरीत, भू-राजनीतिक शत्रुता का पूर्व समाधान मूल्य दबाव को कम कर सकता है। वित्तीय बाजार में बढ़ती अस्तव्यस्तता और वित्तीय स्थिरता की चिंताओं के बीच वैश्विक मांग की स्थिति अधिक अनिश्चित हो रही है, जिससे पण्य की कीमतों पर असर पड़ सकता है। इन बढ़ी हुई अनिश्चितताओं के बीच, मौद्रिक नीति लक्ष्य के साथ मुद्रास्फीति को उत्तरोत्तर संरेखित करने पर केंद्रित है। मुद्रास्फीति में अस्थिरता को कम करने और संवहनीय अवस्फीति को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बाधाओं और कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा सक्रिय आपूर्ति उपाय महत्वपूर्ण बने हुए हैं।

III. मांग और उत्पादन

वर्ष 2022-23 की दूसरी छमाही में घरेलू मांग लचीली बनी रही, निवेश गतिविधि ने जोर पकड़ा लेकिन निजी खपत में सुस्ती दिखाई दी। आपूर्ति पक्ष पर, संपर्क-गहन सेवाओं में सुधार ने विनिर्माण क्षेत्र जो उच्च इनपुट लागत दबाव से नीचे आ गया था के लिए भरपाई की। दीर्घ भू-राजनीतिक तनाव, कठोर वैश्विक वित्तीय स्थितियां, वैश्विक वित्तीय बाजार अस्थिरता और धीमी बाहरी मांग ने संभावनाओं के लिए जोखिम पैदा किया।

वर्ष 2022-23 की दूसरी छमाही में सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय पर लगातार जोर दिए जाने के कारण निवेश गतिविधियों में तेजी के साथ घरेलू मांग लचीली बनी रही। निजी खपत ने महामारी से बढ़ी मांग के सामान्य होने और मुद्रास्फीति के दबाव के प्रभाव के कम होने के साथ सुस्ती का प्रदर्शन किया। वैश्विक मांग में नरमी से वस्तुओं के निर्यात पर असर पड़ा; तथापि, आयात में गिरावट के साथ, कुल निर्यात में कमी हुई। कुल मिलाकर, 2022-23 की दूसरी छमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 4.8 प्रतिशत बढ़ा, जो अपने महामारी से पूर्व के स्तर से 12.3 प्रतिशत अधिक है। आपूर्ति पक्ष पर, संपर्क-गहन सेवाओं में सुधार जारी रहा। इनपुट लागत के दबाव में वृद्धि के कारण विनिर्माण क्षेत्र नीचे आ गया था। दीर्घ भू-राजनीतिक तनाव के प्रसार-प्रभाव, कठोर वैश्विक वित्तीय स्थितियों, वैश्विक वित्तीय बाजार में अस्थिरता और धीमी बाहरी मांग से संभावनाओं के प्रति जोखिम बना हुआ है।

III.1 समग्र मांग

वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही में वास्तविक जीडीपी द्वारा मापी गई कुल मांग 4.4 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़ी और चौथी तिमाही (चार्ट III.1 और सारणी III.1) में 5.1 प्रतिशत अनुमानित है। गति - तिमाही-दर-तिमाही मौसमी रूप से समायोजित वार्षिक वृद्धि दर (एसएएआर) – तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही में मजबूत बनी रही। 2022-23 के संपूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद पिछले वर्ष के 9.1

चार्ट III.1: जीडीपी संवृद्धि और उसके घटक

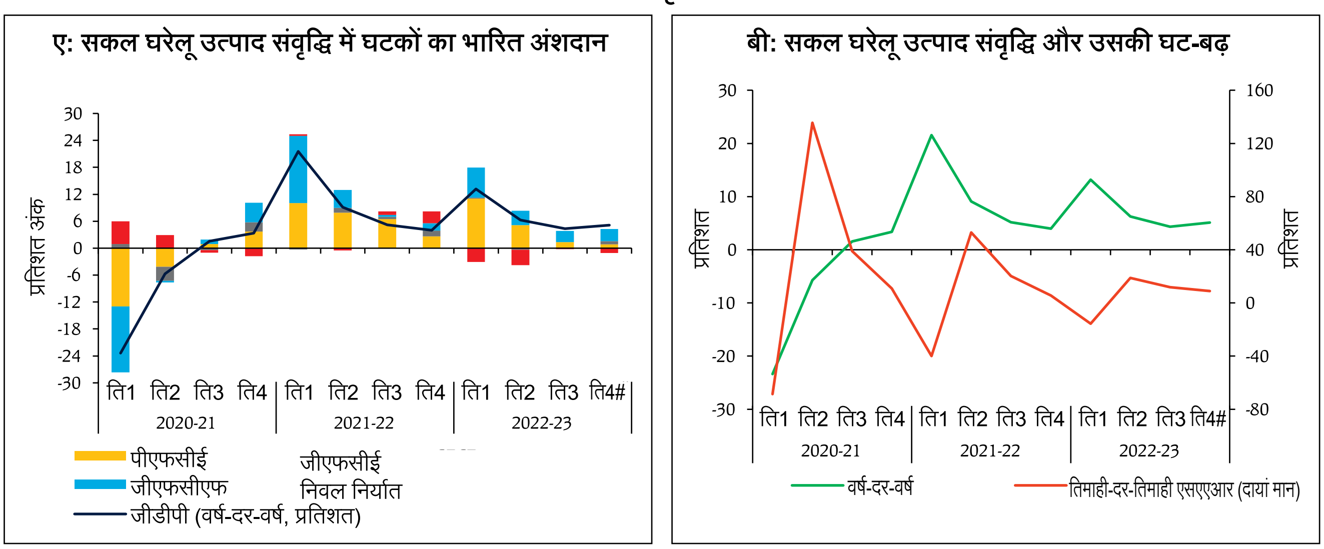

टिप्पणी: #: अंतर्निहित वृद्धि। एसएएआर - मौसमी समायोजित वार्षिकी दर।
स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ); भारत सरकार; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

सारणी III.1: वास्तविक जीडीपी संवृद्धि

(वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)

मद	2021-22	2022-23	भारित योगदान*		2021-22				2022-23			
	(एफआरई)	(एसएई)	2021-22	2022-23	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3	ति4#
निजी अंतिम उपभोग व्यय	11.2 (5.4)	7.3 (13.2)	6.4	4.3	17.6 (-9.3)	14.2 (5.9)	10.8 (12.6)	4.7 (11.8)	20.0 (8.9)	8.8 (15.2)	2.1 (14.9)	1.5 (13.4)
सरकारी अंतिम उपभोग व्यय	6.6 (5.6)	1.2 (6.9)	0.7	0.1	-2.1 (6.3)	11.7 (-17.6)	5.8 (0.9)	11.8 (38.0)	1.8 (8.3)	-4.1 (-20.9)	-0.8 (0.0)	6.1 (46.4)
कुल निश्चित पूंजी निर्माण	14.6 (6.2)	11.2 (18.1)	4.6	3.7	61.0 (-9.6)	12.4 (11.1)	1.2 (4.3)	4.9 (19.6)	20.6 (9.0)	9.7 (21.9)	8.3 (12.9)	7.8 (29.0)
निर्यात	29.3 (17.5)	11.5 (31.0)	5.5	2.5	46.1 (8.8)	25.1 (17.2)	27.8 (16.8)	22.4 (27.1)	19.7 (30.2)	12.3 (31.7)	11.3 (30.1)	3.9 (32.0)
आयात	21.8 (5.2)	18.8 (25.0)	4.6	4.4	44.8 (-14.6)	26.6 (4.2)	19.7 (13.6)	6.7 (19.5)	33.7 (14.1)	25.9 (31.2)	10.9 (25.9)	8.4 (29.5)
बाज़ार मूल्यों पर जीडीपी	9.1 **(2.7)**	7.0 (9.9)	9.1	7.0	21.6 (-6.9)	9.1 (2.9)	5.2 (6.9)	4.0 (7.5)	13.2 (5.4)	6.3 (9.3)	4.4 (11.5)	5.1 (13.0)

टिप्पणी: *: संवृद्धि के लिए घटक-वार योगदान को जीडीपी संवृद्धि के साथ नहीं जोड़ा है क्योंकि स्टाक, कीमती वस्तुओं में परिवर्तन और विसंगतियों को शामिल नहीं किया है। कोष्ठकों में दिये गए आंकड़े 2019-20 की संवृद्धि दरें हैं। एफआरई: पहला संशोधित अनुमान; एसएई: दूसरा अग्रिम अनुमान; #:अंतर्निहित।
स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ)।

प्रतिशत की तुलना में 7.0 प्रतिशत बढ़ा। 2022-23 में भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहा, जो यह दर्शाता है कि संवृद्धि प्रक्रिया में घरेलू संचालकों के रूप में इसकी प्रमुख भूमिका रही है (बॉक्स III.1)।

बॉक्स III.1: बाहरी आघात और भारत की जीडीपी वृद्धि

घरेलू आर्थिक गतिविधि पर वैश्विक स्पिलओवर(प्रसार-प्रभाव) की गतिशीलता का पता लगाने के लिए, एक संरचनात्मक वेक्टर ऑटो रिग्रेशन (एसवीएआर) का अनुमान बाहरी और घरेलू चर के साथ निम्नलिखित क्रम में लगाया जाता है - वैश्विक चर (जीडीपी संवृद्धि, सीपीआई मुद्रास्फीति और वित्तीय स्थितियां); घरेलू जीडीपी वृद्धि; घरेलू मुद्रास्फीति (जीडीपी डिफ्लेटर); और अल्पकालिक ब्याज दर

चार्ट III.1.1: आवेग प्रतिक्रिया कार्य

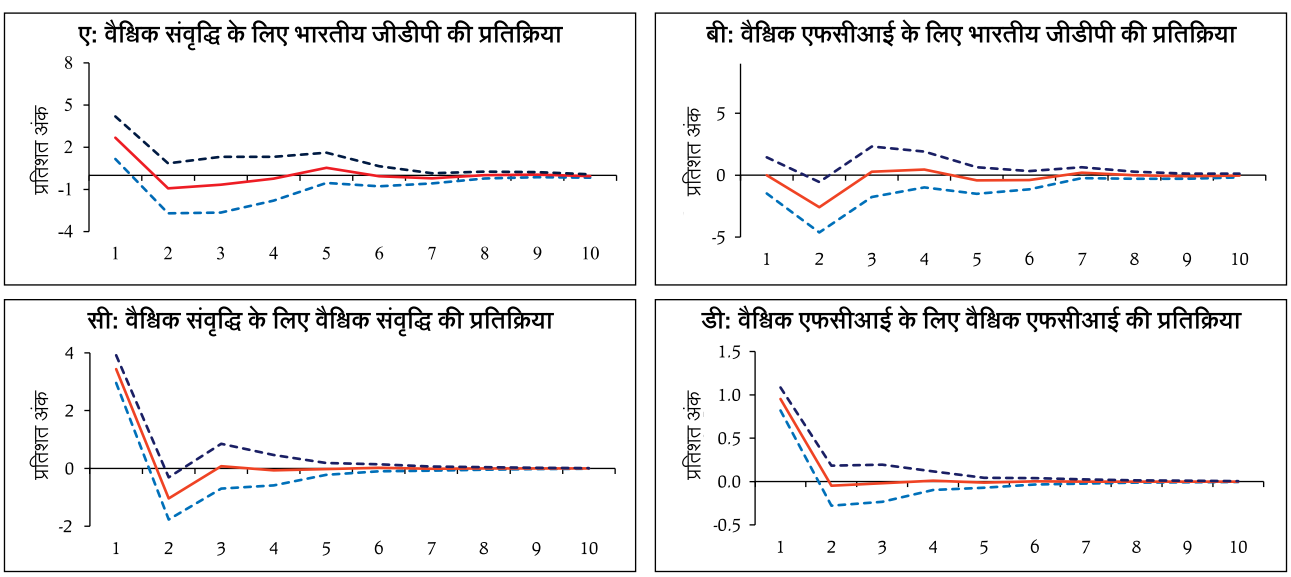

टिप्पणी: आवेग प्रतिक्रियाएं एक मानक विचलन कोलेस्की नवाचारों की प्रतिक्रियाओं को दर्शाती हैं; डॉटेड लाइनें +/- 2 मानक त्रुटि बैंड हैं। X-axes तिमाही का प्रतिनिधित्व करते हैं।
स्रोत: आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

(Contd.)

चार्ट III.1.2: घरेलू संवृद्धि के प्रसरण अपघटन

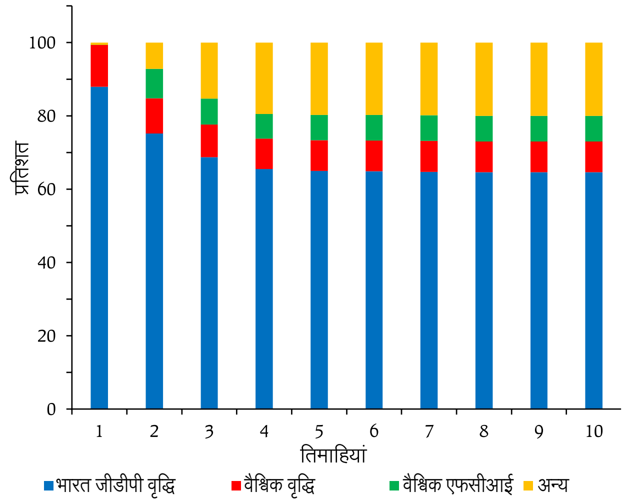

स्रोत: आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

(भारित औसत कॉल मनी दर (डब्ल्यूएसीएमआर) मुद्रास्फीति के लिए समायोजित है।[1] अनुमान में 1997-98 की पहली तिमाही से 2022-23 की तीसरी तिमाही तक के तिमाही आंकड़ों का उपयोग किया गया है। श्वार्ज़ सूचना मानदंड (एसआईसी) के आधार पर एसवीएआर में दो अंतराल शामिल हैं।

आवेग प्रतिक्रियाओं से संकेत मिलता है कि वैश्विक जीडीपी वृद्धि (लगभग 3.5 प्रतिशत अंक) के लिए एक मानक विचलन नकारात्मक आघात घरेलू संवृद्धि को एक तिमाही के अंतराल के साथ 2 प्रतिशत अंक से अधिक कम कर देता है (चार्ट III.1.1)। प्रसरण अपघटन से पता चलता है कि वैश्विक कारक भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में परिवर्तनशीलता का केवल 17-18 प्रतिशत ही बताते हैं, जो घरेलू संवृद्धि संचालकों के वर्चस्व को दर्शाता है (चार्ट III.1.2)।

संदर्भ

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, 2014, " आन द रिसीविंग एन्ड? वैश्विक वित्तीय संकट से पहले, दौरान और बाद में बाहरी परिस्थितियां और उभरते बाजार का विकास"। विश्व आर्थिक आउटलुक, अप्रैल।

विश्व बैंक समूह, 2015, " स्लोडाउन इन इमर्जिंग मार्केट्स: रफ पैच और प्रोलोंग्ड वीकनेस ?" पॉलिसी रिसर्च नोट, दिसंबर

जीडीपी अनुमान बनाम वास्तविक परिणाम

सितंबर 2022 की मौद्रिक नीति रिपोर्ट (एमपीआर) में 2022-23 की दूसरी तिमाही के लिए वास्तविक जीडीपी संवृद्धि दर 6.3 प्रतिशत तथा तीसरी और चौथी तिमाही के लिए प्रति 4.6 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था। दूसरी तिमाही में वास्तविक विकास दर 6.3 प्रतिशत रही जो अनुमान के अनुरूप थी (चार्ट III.2)। तीसरी तिमाही में निजी खपत और सरकारी व्यय में अपेक्षा से कम संवृद्धि के कारण यह अनुमान 20 आधार अंक कम रहा। एनएसओ द्वारा 31 मई, 2023 को 2022-23 की चौथी तिमाही के आंकड़े जारी किए जाने हैं।

चार्ट III.2: सकल घरेलू उत्पाद संवृद्धि: अनुमानित बनाम वास्तविक

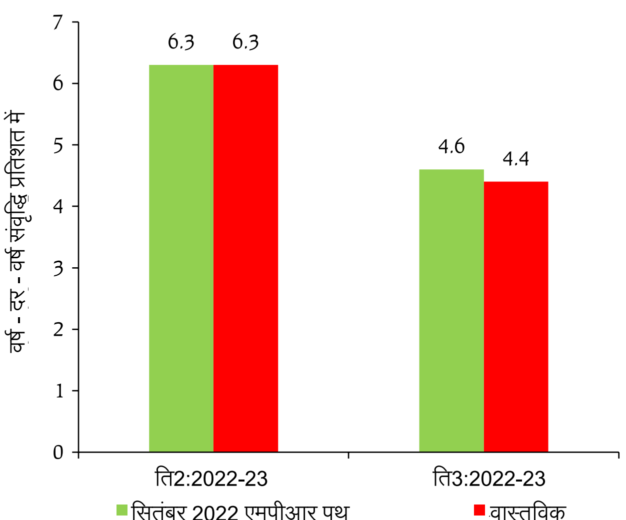

स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

[1] ओईसीडी देशों द्वारा वैश्विक जीडीपी वृद्धि और वैश्विक मुद्रास्फीति का और ब्लूमबर्ग द्वारा निर्मित वित्तीय स्थितियां सूचकांक द्वारा वैश्विक वित्तीय स्थितियों का प्रतिनिधित्व किया गया है। संवृद्धि और मुद्रास्फीति तिमाही दर तिमाही (एसएएआर) है, जबकि वैश्विक एफसीआई में पहले अंतर है।

III.1.1 निजी अंतिम खपत व्यय

निजी अंतिम खपत व्यय (पीएफसीई) में संवृद्धि - कुल मांग का मुख्य आधार - महामारी की वजह से दमित मांग कम हो जाने और उच्च मुद्रास्फीति के कारण 2022-23 की पहली तिमाही में 20.0 प्रतिशत की उपरोक्त प्रवृत्ति की गति से घटकर दूसरी तिमाही में 8.8 प्रतिशत और तीसरी तिमाही में 2.1 प्रतिशत हो गई।

शहरी मांग के उच्च आवृत्ति संकेतकों (एचएफआई) के बीच, घरेलू हवाई यात्री यातायात में अगस्त 2022 से धारणीय संवृद्धि देखी गई और दिसंबर 2022-फरवरी 2023 में अपने महामारी पूर्व स्तर को पार कर गयी (चार्ट III.3)। यात्री वाहनों की बिक्री और घरेलू ऋण में दूसरी छमाही में तेज संवृद्धि दर्ज की गई। तीसरी तिमाही और जनवरी 2023 में टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं में संकुचन हुआ जो कि परिवारों द्वारा वस्तुओं में खर्च न करते हुए घटती महामारी के साथ सेवाओं पर खर्च करने के झुकाव को दर्शाता है।

दूसरी छमाही में ग्रामीण मांग में सुधार के कुछ संकेत दिखाई दिए, हालांकि यह शहरी मांग से पिछड़ रहा है। एचएफआई में ट्रैक्टर की बिक्री दूसरी छमाही में तेजी से बढ़ी, जबकि दिसंबर 2022 में मामूली संकुचन के बाद जनवरी-फरवरी 2023 में मोटरसाइकिल की बिक्री में संवृद्धि धनात्मक क्षेत्र में लौट आई। जुलाई-अक्टूबर के दौरान गिरावट के बाद जनवरी 2023 में लगातार तीसरे महीने गैर-टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में संवृद्धि हुई। रबी की उच्च बुवाई और अनौपचारिक क्षेत्र के रोजगार में बहाली की वजह से ग्रामीण रोजगार बाजार में सुधार के कारण तीसरी और चौथी तिमाही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत काम की मांग में कमी आई (चार्ट III.4)।

भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र (सीएमआईई) के उपभोक्ता पिरामिड आंकड़ों के अनुसार चौथी तिमाही में श्रम शक्ति सहभागिता दर अपरिवर्तित रही और शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बेरोजगारी दर कम हुई (चार्ट III.5ए)। कर्मचारी

चार्ट III.3: शहरी मांग - उच्च आवृत्ति संकेतक

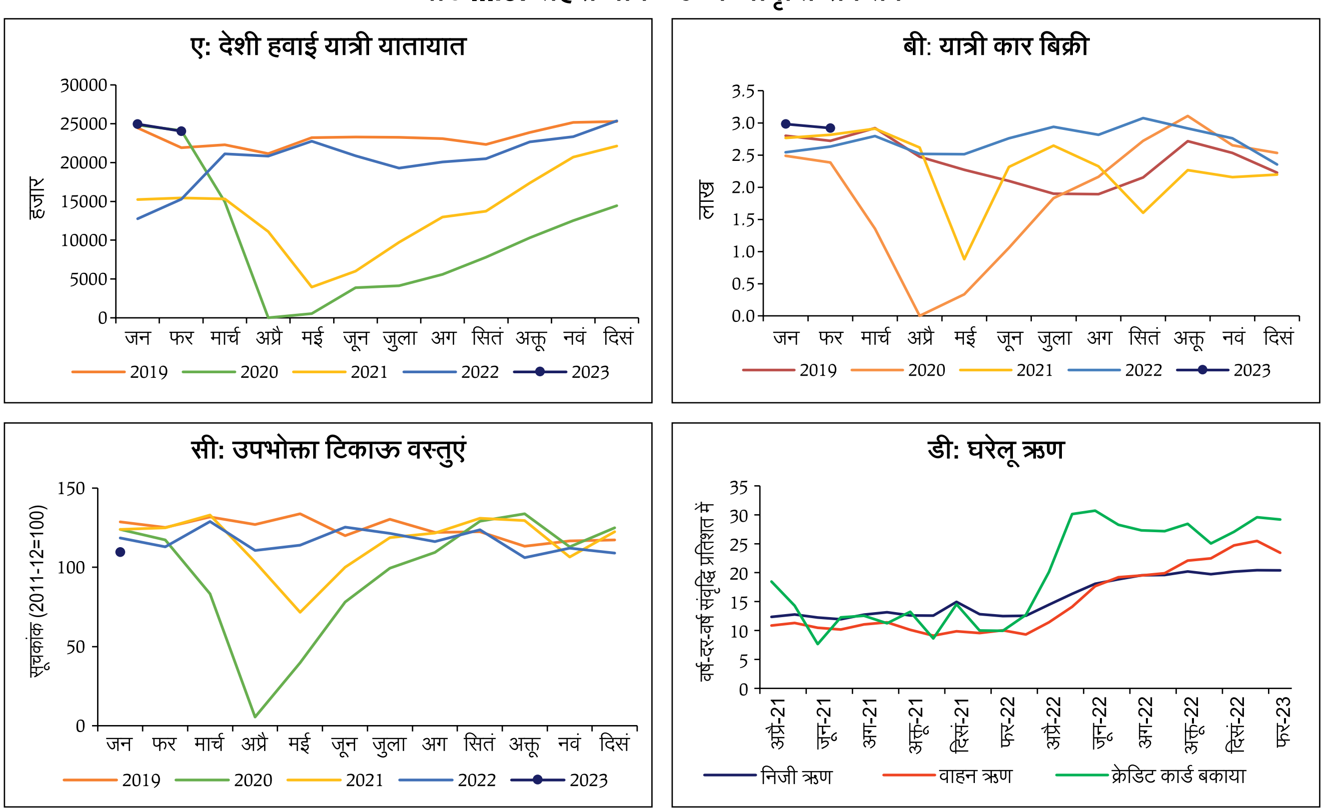

स्रोत: नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए); सोसाइटी ऑफ इंडियन आटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (एसआईएएम); एनएसओ; और आरबीआई।

चार्ट III.4: ग्रामीण मांग - उच्च आवृत्ति संकेतक

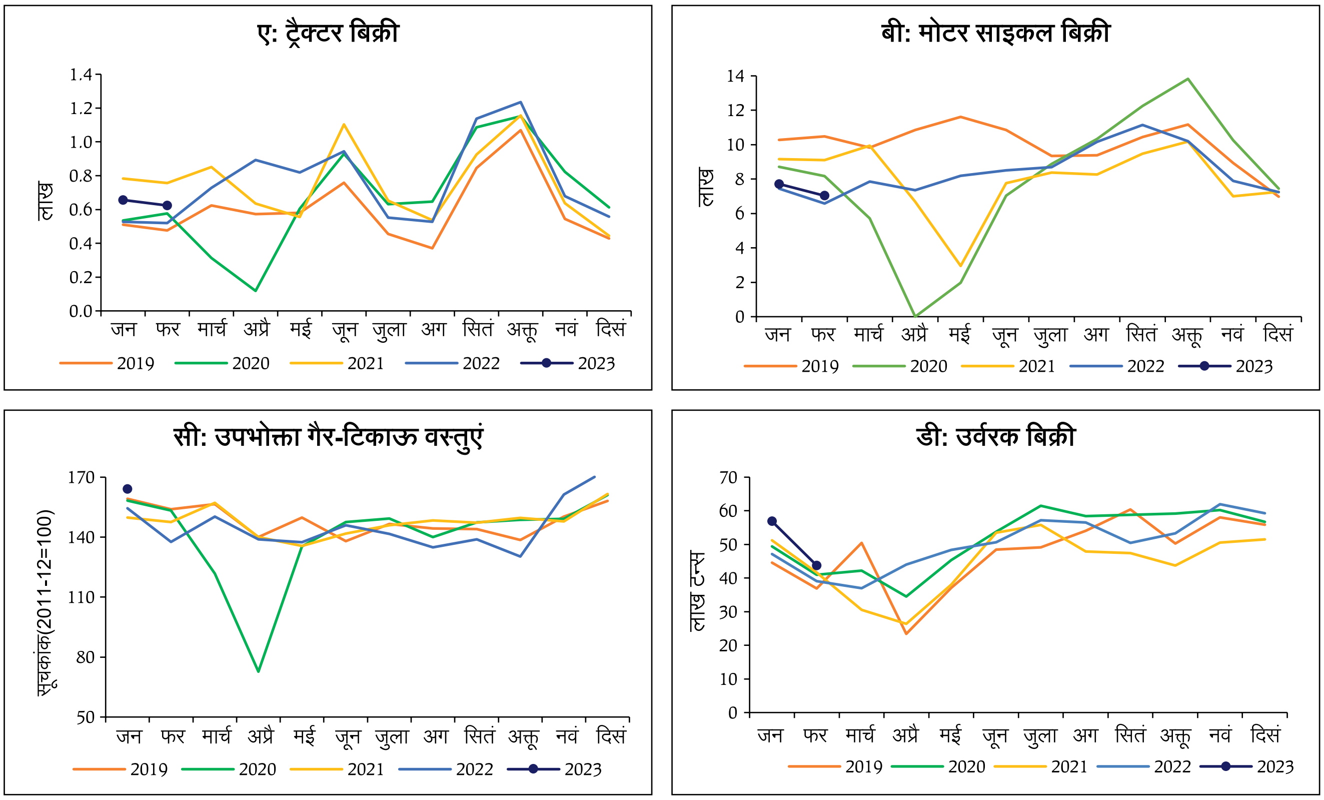

स्रोत: ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स असोसिएशन; एसआईएएम; एनएसओ; और रसायन और उर्वरक मंत्रालय।

भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के पेरोल आंकड़ों में दर्शाए अनुसार संगठित क्षेत्र का रोजगार पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में तीसरी तिमाही में और जनवरी 2023 में काफी सुदृढ़ हुआ है (चार्ट III.5बी)। नौकरी जॉबस्पीक के आंकड़ों के अनुसार बीमा, आतिथ्य, बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और स्थावर सम्पदा क्षेत्रों में नियुक्तियों में वृद्धि देखी गई।

चार्ट III.5: रोजगार की स्थिति

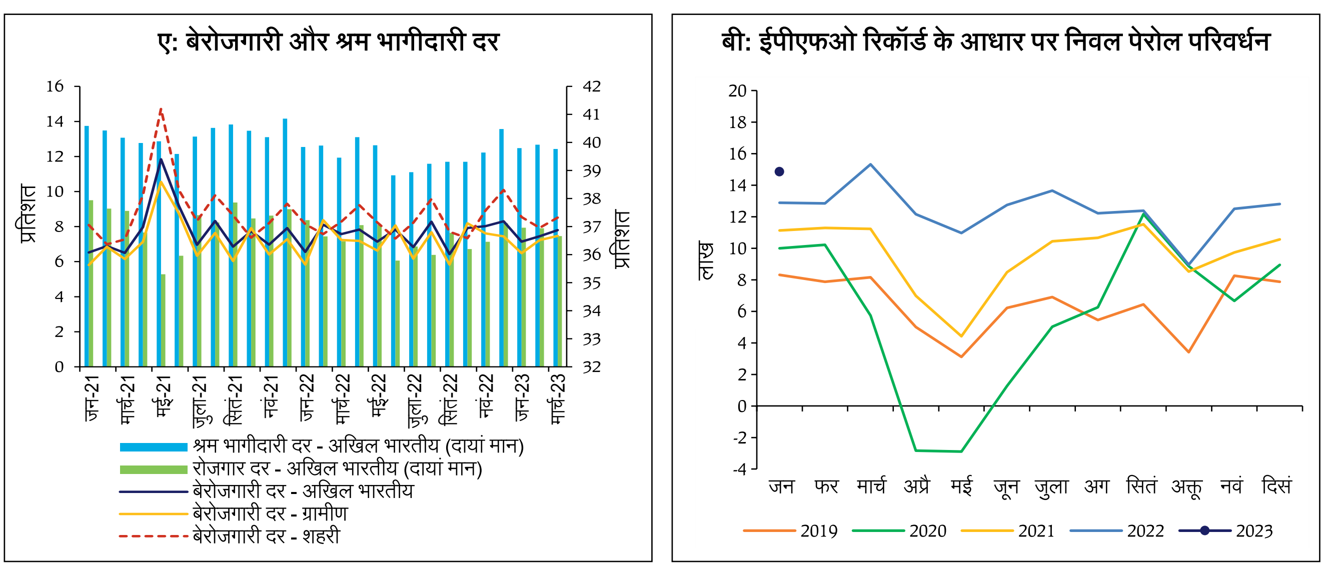

स्रोत: भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र (सीएमआईई); और कर्मचारी भविष्य - निधि संगठन (ईपीएफओ)।

चार्ट III.6: निवेश मांग के संकेतक

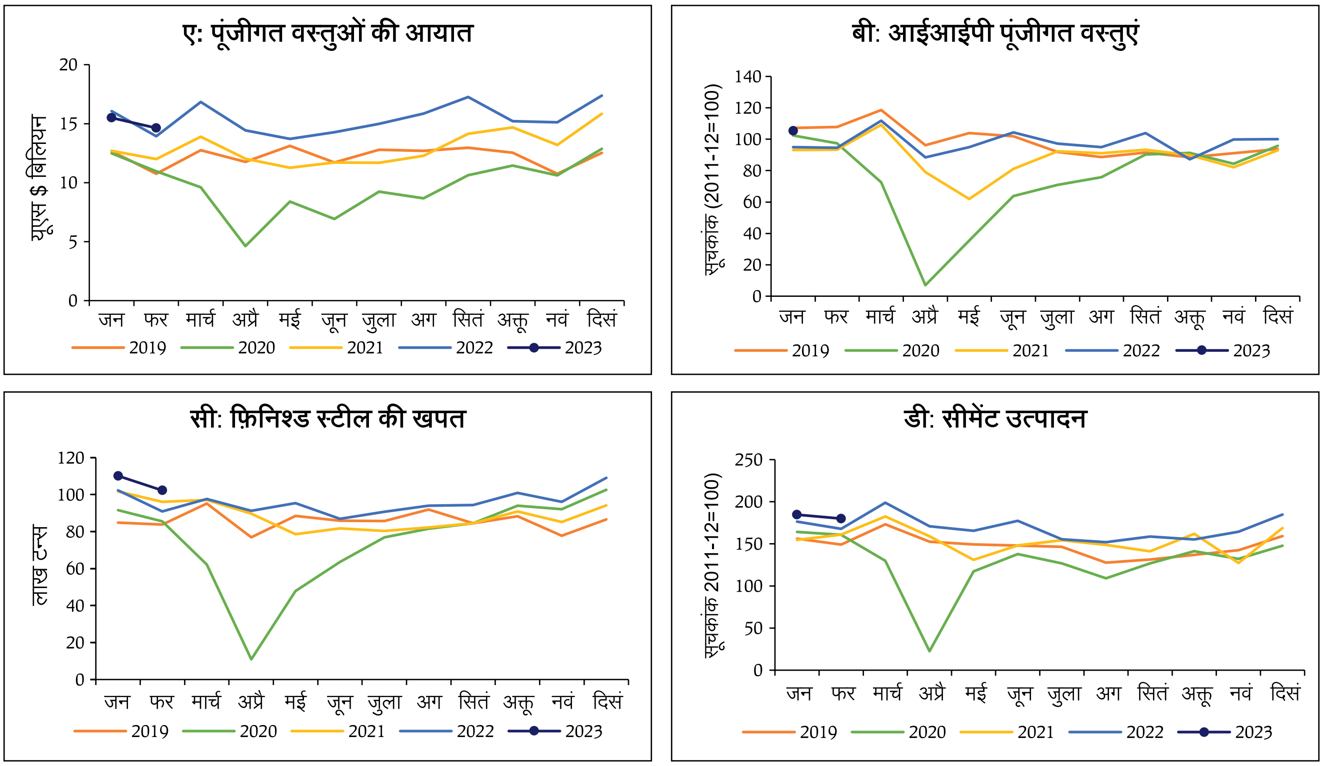

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस; एनएसओ; संयुक्त संयंत्र समिति; और आर्थिक सलाहकार का कार्यालय।

III.1.2 सकल स्थिर पूंजी निर्माण

सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) ने 2022-23 की पहली छमाही में 14.8 प्रतिशत की संवृद्धि से अधिक तीसरी तिमाही में 8.3 प्रतिशत की संवृद्धि दर्ज की। जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी एक साल पहले के 30.6 प्रतिशत से बढ़कर तीसरी तिमाही में 31.8 प्रतिशत हो गई। आवास की मांग और बुनियादी ढांचे के खर्च पर सरकार के जोर के कारण निर्माण गतिविधि में मॉनसून के बाद तेजी आई। तीसरी और चौथी तिमाही में सीमेंट उत्पादन और इस्पात की खपत जो कि नियत निवेश के संकेतक हैं, में तेजी से संवृद्धि हुई। तीसरी तिमाही और जनवरी 2023 में मशीनरी और उपकरणों में निवेश के मामले में पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन समुत्थानशील रहा तथा तीसरी तिमाही में पूंजीगत वस्तुओं का आयात उत्साहजनक रहा और जनवरी-फरवरी 2023 के दौरान विस्तार की गति में कमी आई (चार्ट III.6)।

आरबीआई के सर्वेक्षण[2] के अनुसार, विनिर्माण क्षेत्र में क्षमता उपयोग (सीयू) पिछली तिमाही के 74.0 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 की तीसरी तिमाही में 74.3 प्रतिशत हो गया। इस अवधि के दौरान हालांकि मौसमी रूप से समायोजित सीयू 74.5 प्रतिशत से गिरकर 74.1 प्रतिशत हो गया, हालांकि यह

चार्ट III.7: विनिर्माण क्षेत्र में क्षमता उपयोग

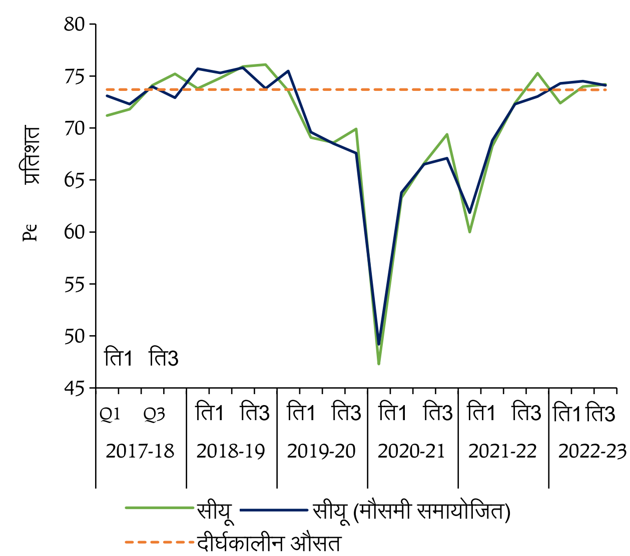

स्रोत: आरबीआई।

2 ऑर्डर-बुक, इंवेंट्रीज और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण।

अपने दीर्घावधि औसत (चार्ट III.7) से ऊपर रहा। केंद्रीय बजट 2023-24 ने 2022-23 के अपने संशोधित अनुमानों की तुलना में पूंजीगत व्यय में 37.4 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है और इससे निजी निवेश में अधिकता की उम्मीद है (बॉक्स III.2)।

विनिर्माण और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्रों में सूचीबद्ध गैर-वित्तीय निजी कंपनियों का ब्याज व्याप्ति अनुपात (आईसीआर)[3] 2022-23 की तीसरी तिमाही में सहज रहा, जो कि पर्याप्त ऋण-चुकौती-क्षमता (चार्ट III.8) का संकेत देता है। सेवा क्षेत्र (गैर-आईटी) के आईसीआर में तीसरी तिमाही में सुधार हुआ और, 2019-20 की पहली तिमाही के बाद, पहली बार यूनिटी के प्रारम्भिक स्तर को पार कर गया।

निवेश दर, अर्थात वर्तमान कीमतों पर सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) जीडीपी के प्रति का अनुपात, पिछले वर्ष के 27.9 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 31.4 प्रतिशत हो गया। घरेलू बचत में गिरावट को बराबर करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कमतर निर्बचत के साथ, इसी अवधि में सकल घरेलू बचत दर एक साल पहले के 28.8 प्रतिशत से बढ़कर जीडीपी का 30.2 प्रतिशत हो गई। शुद्ध घरेलू वित्तीय बचत – घाटे वाले क्षेत्रों के लिए निधियन का स्रोत – 2020-21 में 11.5 प्रतिशत से 2021-22 में

बॉक्स III.2: क्या सार्वजनिक निवेश से निजी निवेश बढ़ेगा ?

बुनियादी ढांचे में सुधार लाने, अतिरिक्त क्षमता बनाने, उत्पादकता बढ़ाने और निजी निवेश का अंतर्गमन करने के लिए गत वर्षों में सरकार ने पूंजीगत व्यय का विस्तार किया। सार्वजनिक पूंजी के कम प्रारंभिक स्टॉक के साथ ईएमई में सार्वजनिक निवेश गुणक अधिक हैं (इज़्क्वीएरदो, ए. और अन्य, 2019; सर्वन, 1999; बहल और अन्य, 2015; आरबीआई, 2019)। इस पृष्ठभूमि में, निजी निवेश पर सार्वजनिक निवेश के प्रभाव की जांच 1980-2019 के लिए एसवीएआर ढांचे में की गई है। बाह्य-मांग-आघातों को ध्यान में लेने के लिए वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को एक नियंत्रण चर के रूप में रखते हुए उक्त मॉडल में सार्वजनिक निवेश, निजी निवेश, और वास्तविक प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (विकास दर में सभी चर)

चार्ट III.2.1: सार्वजनिक निवेश पर निजी निवेश की संचित अनुक्रिया

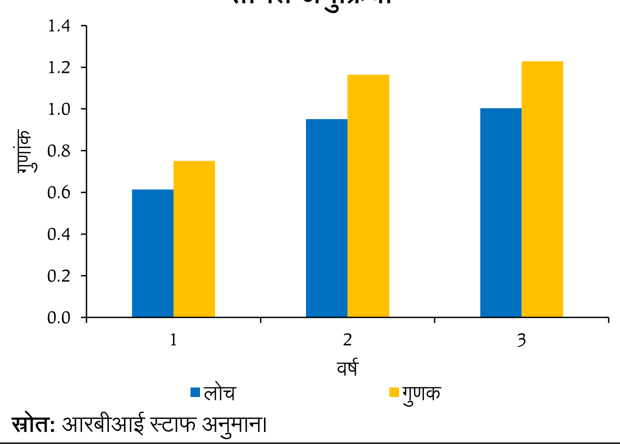

स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान।

शामिल हैं।आवेग अनुक्रियाओं से संकेत मिलता है कि सार्वजनिक निवेश में 1 प्रतिशत अंक की वृद्धि पहले वर्ष में निजी निवेश में 0.6 प्रतिशत अंक की वृद्धि करती है और 3 साल की अवधि में संचयी प्रभाव 1.0 प्रतिशत अंक (चार्ट III.2.1) है। निजी निवेश पर सार्वजनिक निवेश का गुणक 1.2 है और कुल जीडीपी पर तीन साल की अवधि में 1.7 है, जो कि यूनिटी से काफी अधिक है। इस प्रकार, अनुभवजन्य विश्लेषण इंगित करता है कि केंद्रीय बजट 2023-24 सहित हाल के बजटों में पूंजीगत व्यय पर सरकार का ध्यान, समय के साथ निजी निवेश और घरेलू मांग को, लाभकारी प्रभावों के साथ, प्रोत्साहित करने में प्रभावी हो सकता है।

संदर्भ:

बहल, जी., रायसी, एम., और तुलिन, वी. (2018), "क्राउडिंग-आउट ऑर क्राउडिंग-इन? पब्लिक एंड प्राइवेट इनवेस्टमेंट इन इंडिया", *वर्ल्ड डेवलपमेंट*, 109, 323-333।

इज़क्विएर्डो, एमए, लामा, एमआर, मदीना, जेपी, पुइग, जे, रिएरा-क्रिचटन, डी, वेग, सी, और वुलेटिन, जी जे (2019)। "इज़ द पब्लिक इनवेस्टमेंट मल्टीप्लायर हायर इन डेव्लपिंग कंट्रीज? एन एंपीरीकल एक्स्प्लोरेसन", आईएमएफ वर्किंग पेपर 289।

सर्वन, एल. (1996), "डज़ पब्लिक कैपिटल क्राउड आउट प्राइवेट कैपिटल? एविडेंस फ्रॉम इंडिया", वर्ल्ड बैंक पॉलिसी, रिसर्च वर्किंग पेपर 1613।

भारतीय रिज़र्व बैंक (2019), "मौद्रिक नीति रिपोर्ट", अप्रैल।

[3] ब्याज और करों से पहले की आय (ईबीआईटी) और ब्याज व्यय का अनुपात, ब्याज व्याप्ति अनुपात कहलाता है जो कि एक कंपनी की ,अपने कर्ज पर ब्याज भुगतान करने की, क्षमता को मापता है। व्यवहार्य आईसीआर का न्यूनतम मान 1 है।

चार्ट III.8: ब्याज कवरेज अनुपात

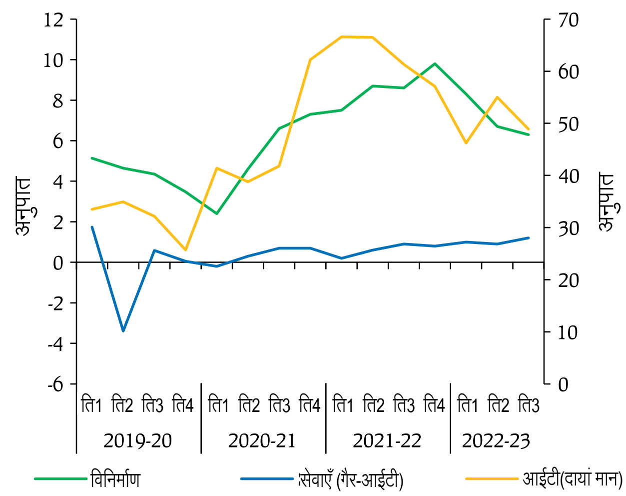

टिप्पणी: 2022-23 की तीसरी तिमाही के लिए डाटा 1,718 सूचीबद्ध निजी विनिर्माण कंपनियों और 740 सूचीबद्ध गैर-वित्तीय निजी सेवा कंपनियों के परिणामों पर आधारित है।
स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट III.9: बचत और निवेश

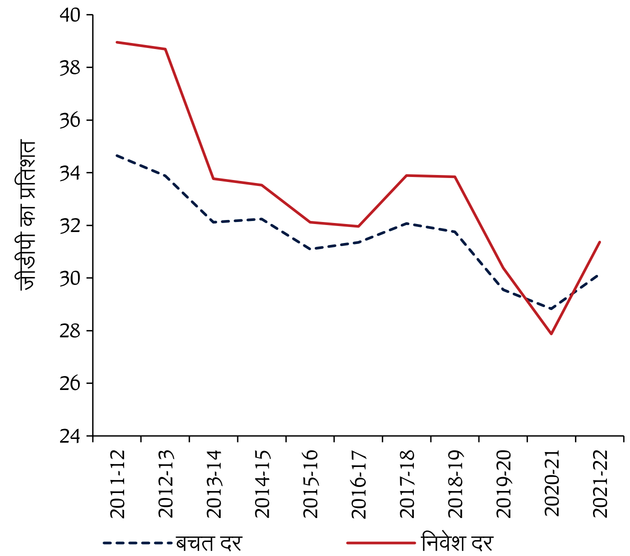

स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

सकल घरेलू उत्पाद का 7.6 प्रतिशत तक कम हो गया, जो खपत में वृद्धि और परिणामस्वरूप एहतियाती बचत में आहरण द्वारा कमी को दर्शाता है (चार्ट III.9)। अनंतिम अनुमानों के अनुसार, 2022-23 के दौरान शुद्ध घरेलू वित्तीय बचत का जीडीपी के 6.3-6.5 प्रतिशत तक कम होने का अनुमान है जो कि परिवारों की ऋण मांग में वृद्धि को दर्शाता है।

III.1.3 सरकारी खपत

सरकार के अंतिम बचत व्यय (जीएफसीई) ने पहली छमाही में संकुचन के बाद 2022-23 की दूसरी छमाही में सकल मांग को समर्थन दिया है (चार्ट III.10)। 2022-23 (आरई) में सब्सिडी खर्च में भारी वृद्धि के बावजूद, केंद्र सरकार का कुल व्यय जीडीपी के 15.4 प्रतिशत पर सीमित था, जो कि 2021-22 की तुलना में कम था (सारणी III.2)।

वर्ष 2023-24 के लिए, केंद्र सरकार ने सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) को सकल घरेलू उत्पाद का 5.9 प्रतिशत रहने का बजट अनुमान रखा है, जो 2022-23 (संशोधित अनुमान) के 6.4 प्रतिशत से कम है। राजस्व व्यय (विशेष रूप से सब्सिडी) को नियंत्रित करके राजकोषीय सुदृढ़ीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जबकि पूंजीगत व्यय को पिछले वर्ष के 2.7 प्रतिशत से बढ़ाकर 2023-24 में जीडीपी का 3.3 प्रतिशत किया जाएगा। ब्याज भुगतान और सब्सिडी को छोड़कर राजस्व व्यय का 2022-23 (आरई) के 7.3 प्रतिशत से घटकर, 2023-24 (बजट अनुमान) में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

2022-23 (फरवरी 2023 तक) के दौरान, उत्पाद शुल्क को छोड़कर सभी प्रमुख करों के तहत संग्रह में मजबूत वृद्धि के

चार्ट III.10: 2022-23 के दौरान केंद्र का राजस्व व्यय और पूँजीगत व्यय

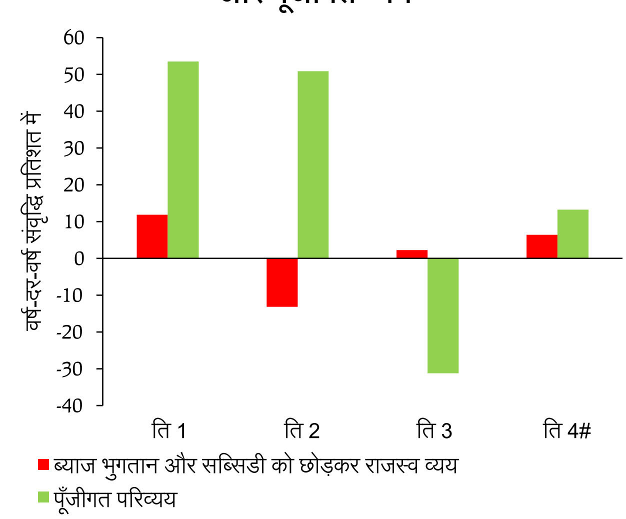

टिप्पणी: #: अंतर्निहित
स्रोत: महालेखा नियंत्रक और केंद्रीय बजट 2023-24।

सारणी III.2: केंद्र सरकार वित्त

संकेतक	जीडीपी का प्रतिशत			
	2020-21	2021-22	2022-23 (आरई)	2023-24 (बीई)
1. राजस्व प्राप्तियाँ	8.2	9.2	8.6	8.7
ए. कर राजस्व (निवल)	7.2	7.7	7.7	7.7
बी. गैर-कर राजस्व	1.0	1.6	1.0	1.0
2. गैर-कर्ज पूंजी प्राप्तियाँ	0.3	0.2	0.3	0.3
3. राजस्व व्यय	15.5	13.6	12.7	11.6
ए. ब्याज भुगतान	3.4	3.4	3.5	3.6
बी. प्रमुख सब्सिडीज़	3.6	1.9	1.9	1.2
4. ब्याज भुगतान और सब्सिडीज़ को छोड़कर राजस्व व्यय	8.6	8.3	7.3	6.8
5. पूंजी व्यय	2.1	2.5	2.7	3.3
6. पूँजी परिव्यय	1.6	2.3	2.3	2.8
7. कुल व्यय	17.7	16.2	15.4	14.9
8. सकल राजकोषीय घाटा	9.2	6.8	6.5	5.9
9. राजस्व घाटा	7.3	4.4	4.1	2.9
10. प्राथमिक घाटा	5.7	3.3	3.0	2.3

टिप्पणी: आरई: संशोधित अनुमान; बीई: बजट अनुमान।
जीडीपी में संशोधन के कारण केंद्रीय बजट में प्रकाशित आंकड़ों से भिन्न हो सकते हैं।
स्रोत: यूनियन बजट दस्तावेज़; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

साथ केंद्र सरकार के सकल कर राजस्व में साल-दर-साल 12.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में वार्षिक आधार पर क्रमश: 15.9 प्रतिशत और 8.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। अप्रत्यक्ष करों में, केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 18.6 प्रतिशत की गिरावट आई जो कि मुख्य रूप से मई 2022 में ईंधन पर उत्पाद शुल्क में कमी के कारण थी, जबकि आघातसह आर्थिक गतिविधि और बेहतर कर-अनुपालन[4] से लाभान्वित होकर जीएसटी संग्रहण (केंद्र *और* राज्यों) में अप्रैल-मार्च 2022-2023 में 21.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चार्ट III.11) । इस अवधि के दौरान ब्याज भुगतान और सब्सिडी को छोड़कर केंद्र सरकार के राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में क्रमशः 2.5 प्रतिशत और 21.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वर्ष 2022-23 में, पूंजीगत व्यय पर जोर देते हुए राज्य सरकारों के समेकित जीएफडी को जीडीपी के 3.4 प्रतिशत पर

चार्ट III.11: अप्रैल-फरवरी के दौरान केंद्र सरकार का कर संग्रहण

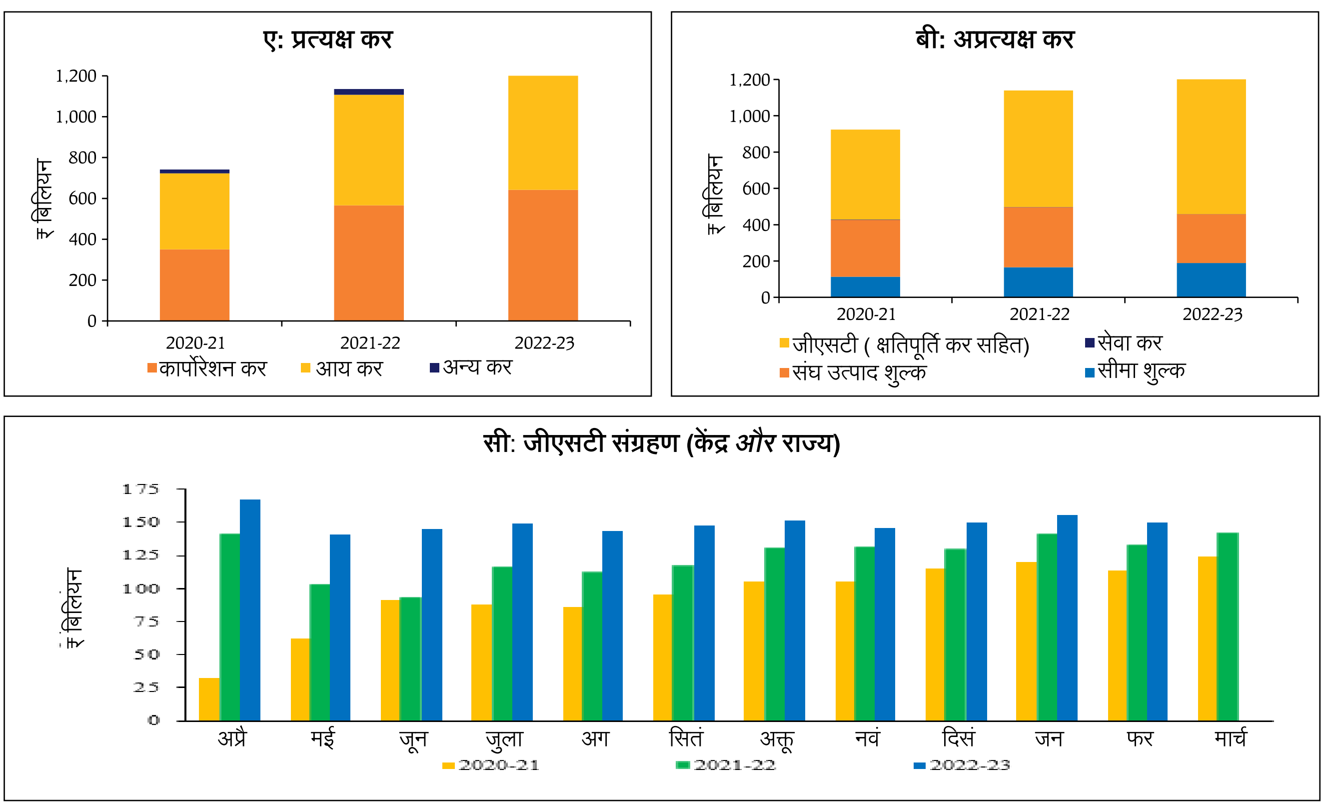

स्रोत: महालेखा नियंत्रक; वित्त मंत्रालय।

[4] अप्रैल-फरवरी 2022-23 के दौरान जीएसटी संग्रह औसतन 1.51 लाख करोड़ रुपये रहा, जो वर्ष 2021-22 के दौरान 1.24 लाख करोड़ रुपये था।

[5] अप्रैल-जनवरी अवधि के आंकड़े 24 राज्यों से संबंधित हैं।

सारणी III.3: राज्य सरकार वित्त – प्रमुख राजकोषीय संकेतक

मद	(जीडीपी का प्रतिशत)			
	2020-21 (ए)	2021-22 (बीई)	2021-22 (पीए)	2022-23 (बीई)
राजस्व घाटा	1.9	0.5	0.4	0.3
सकल राजकोषीय घाटा	4.1	3.5	2.8	3.4
प्राथमिक घाटा	2.1	1.6	1.1	1.6

टिप्पणी : डाटा 31 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश से संबंधित हैं।
ए: लेखा; बीई: बजट अनुमान; पीए: अनंतिम लेखा।
स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज; भारत के महालेखा महानियंत्रक (सीएजी)।

बजट किया गया था (सारणी III.3)। (अप्रैल-जनवरी) 2022-23[5] के उपलब्ध आंकड़ों से संकेत मिलता है कि राज्यों के राजकोषीय घाटे में पूर्ण रूप से गिरावट के साथ-साथ बजट अनुमानों (बीई) के अनुपात में भी गिरावट आई है (चार्ट III.12)।

सभी उप-घटकों में राज्यों की राजस्व प्राप्तियों में उछाल बना रहा (चार्ट III.13ए)। अप्रैल-जनवरी 2022-23 के दौरान पूंजीगत व्यय में 12.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि पहली तिमाही में इसमें गिरावट आई थी (चार्ट III.13बी)। राज्यों ने इस अवधि के दौरान पिछले रुझानों के अनुरूप अपने बजट किए गए पूंजीगत व्यय का लगभग 53 प्रतिशत खर्च किया है। केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में ₹0.7 लाख करोड़ के सामान्य मासिक अंतरण के सापेक्ष ₹1.4 लाख करोड़ की कर अंतरण राशि की चौदहवीं किस्त जारी की। केंद्र सरकार ने राज्यों द्वारा उच्च पूंजीगत व्यय को प्रोत्साहित करने के लिए 2023-24 में ₹1.3 लाख करोड़ के बढ़े हुए आबंटन के साथ पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता की योजना को जारी रखने का भी निर्णय लिया है। राजस्व और व्यय के रुझान को देखते हुए, 2022-23 में राज्यों का जीएफडी-जीडीपी अनुपात बजट अनुमान से कम रह सकता है।

वर्ष 2022-23 में केंद्र की सकल बाजार उधारी ₹14.21 लाख करोड़ रही, जबकि पहली और दूसरी छमाही के लिए सांकेतिक कैलेंडर में ₹14.37 लाख करोड़ की योजना बनाई गई थी। रिज़र्व बैंक ने ऋण समेकन के लिए केंद्र सरकार की ओर से ₹1.05 लाख करोड़ की ग्यारह स्विच नीलामी भी आयोजित की। 2022-23 के दौरान निर्गम की भारित औसत लागत पिछले वर्ष के 6.3 प्रतिशत से बढ़कर 7.3 प्रतिशत हो गई, साथ ही भारित औसत परिपक्वता 17.0 वर्ष से घटकर 16.05 वर्ष हो गई। राज्यों ने 2022-23 में 7.58 लाख करोड़ रुपये की सकल बाजार उधारी जुटाई, जबकि कुल संस्वीकृत राशि ₹8.81 लाख करोड़ थी।

चार्ट III.12: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रमुख राजकोषीय संकेतक: अप्रैल-जनवरी

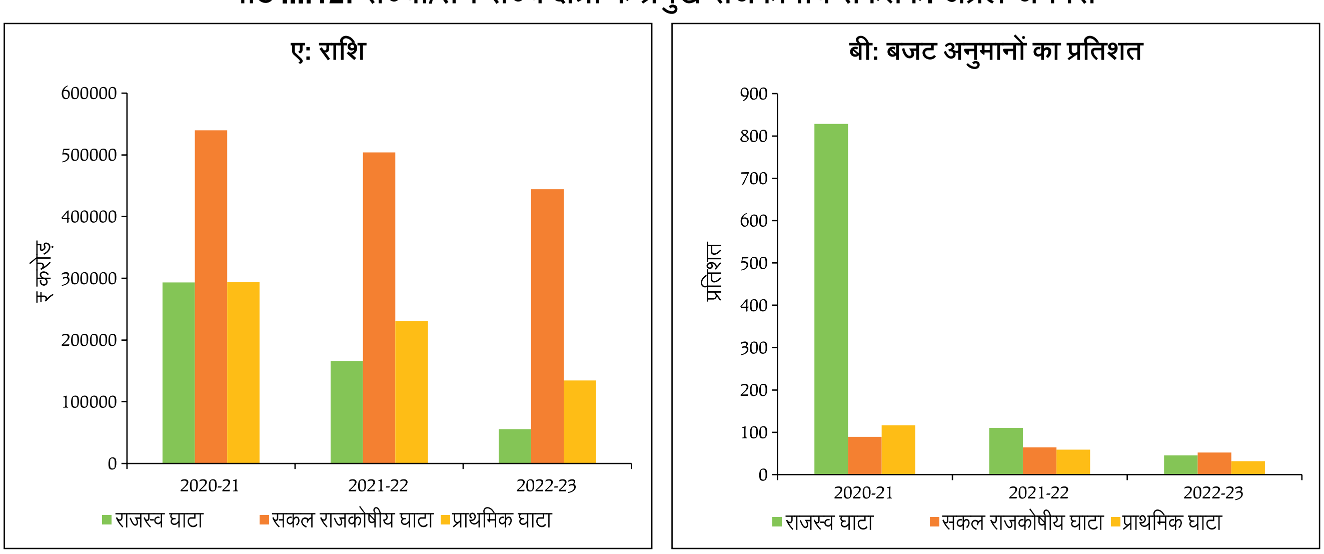

टिप्पणी: डेटा 24 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है।
स्रोत: सीएजी; और राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

चार्ट III.13: राज्यों के राजस्व और व्यय: अप्रैल – जनवरी

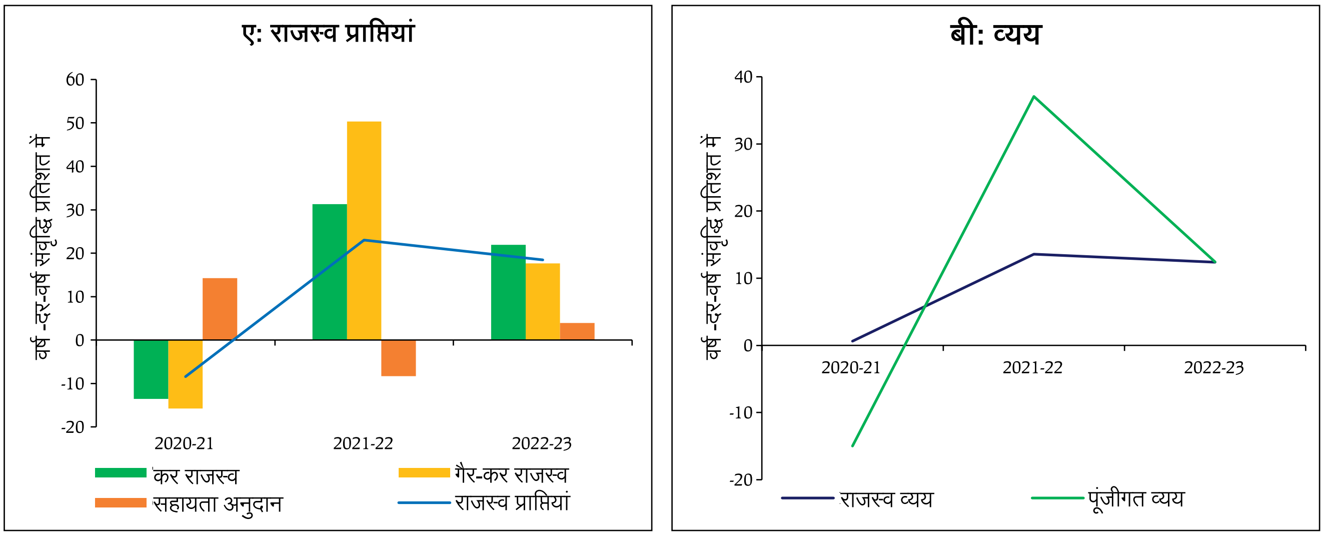

टिप्पणी: डेटा 24 राज्यों से संबंधित है।
स्रोत: सीएजी।

केंद्रीय बजट 2023-24 में सकल और निवल बाजार उधारी क्रमश: ₹15.43 लाख करोड़ और ₹11.81 लाख करोड़ निर्धारित की गई थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में क्रमश: 8.6 प्रतिशत और 6.6 प्रतिशत अधिक है (सारणी III.4)। वर्ष 2023-24 की पहली छमाही में, दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से केंद्र सरकार की सकल बाजार उधारी लगभग 8.9 लाख करोड़ रुपये रखने की योजना बनाई गई है, जो वर्ष के लिए कुल बजट की राशि का 57.6 प्रतिशत है। प्राप्तियों और भुगतानों के बीच अल्पकालिक अंतर को पूरा करने के लिए 2023-24 की पहली छमाही के लिए केंद्र सरकार के लिए अर्थोपाय अग्रिम सीमा 1.5 लाख करोड़ रुपये होगी। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, डब्ल्यूएमए सीमा राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिम पर सलाहकार समिति (अध्यक्ष: श्री सुधीर श्रीवास्तव) द्वारा सिफारिश के अनुसार 01 अप्रैल 2022 से ₹47,010 करोड़ तय की गई।

सारणी III.4: केंद्र के उधार

(₹ लाख करोड़)

मद		2020-21	2021-22	2022-23 (आरई)	2023-24 (बीई)
I	निवल उधार (जी-सेक)	10.4	7.4	7.8	11.8
	पुनर्भुगतान	2.3	2.6	3.1	3.6
	सकल उधार (जी-सेक)	12.6	10.0	10.9	15.4
II	टी-बिल/नकद प्रबंधन बिल (निवल)	2.0	0.8	1.0	0.5
III	निवल बाजार उधार (I+II)	12.4	8.1	8.8	12.3
IV	छोटी बचत के विरुद्ध प्रतिभूतियां	4.8	5.5	4.4	4.7
V	राज्य भविष्य निधि	0.2	0.1	0.2	0.2
VI	अन्य प्राप्तियां	0.1	1.7	0.8	0.5
VII	बाह्य ऋण	0.7	0.4	0.2	0.2
VIII	कुल ऋण (III से VII)	**18.3**	**15.8**	**14.4**	**18.0**
IX	नकद शेष पर ड्राडाउन	-0.1	0.0	0.0	-0.1
X	कुल निधीयन (VIII+IX)	18.2	15.8	17.6	17.9

स्रोत: जीओआई; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

III.1.4 बाह्य मांग

लंबे समय तक भू-राजनीतिक संघर्ष और धीमी वैश्विक मांग के बीच, 2022-23 की दूसरी छमाही के दौरान पण्य निर्यात में गिरावट आई। निर्यात से संबंधित मांग में मंदी के साथ-साथ पण्यों की कीमतों में कमी के कारण तीसरी तिमाही के दौरान पण्य आयात की वृद्धि में गिरावट दर्ज की गई और चौथी तिमाही (फरवरी तक) में संकुचित हुई (चार्ट III.14)। हालांकि, निवल निर्यात में गिरावट पिछली तिमाही की तुलना में तीसरी तिमाही में आई, जो सेवा निर्यात में निरंतर मजबूती को दर्शाता है।

चार्ट III.14: माल व्यापार

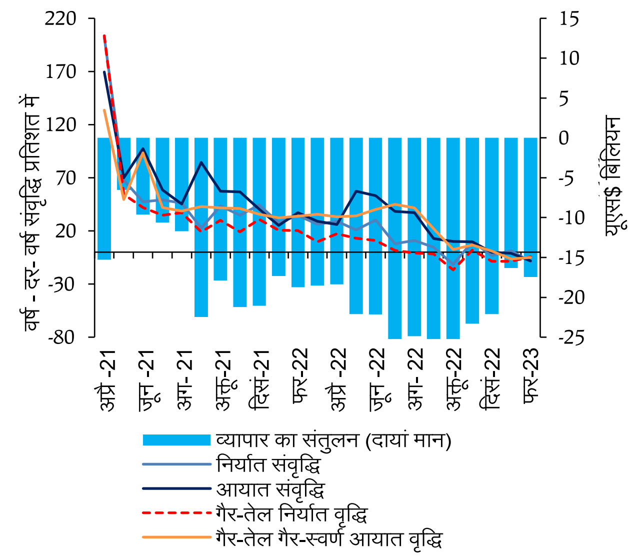

स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एण्ड एस)।

2022-23 की दूसरी छमाही (अक्तूबर-फरवरी) के दौरान, इंजीनियरिंग वस्तुओं, सूती धागे, रत्न और आभूषण, प्लास्टिक और लिनोलियम और रसायनों के निर्यात में गिरावट आई, जबकि पेट्रोलियम उत्पादों, इलेक्ट्रॉनिक्स, चावल, तेलीय खाद्य और लौह अयस्क ने समग्र व्यापारिक निर्यात वृद्धि में सकारात्मक योगदान दिया (चार्ट III.15)। वर्ष 2022-23 (अक्तूबर -फरवरी) की दूसरी छमाही के दौरान कुल पण्य निर्यात में पेट्रोलियम उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़कर 20.3 प्रतिशत हो गई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 16.2 प्रतिशत थी।

पण्य आयात वृद्धि 2022-23 की दूसरी छमाही (अक्टूबर-फरवरी) में 1.9 प्रतिशत तक कम होकर 280.7 बिलियन यूएसडी तक पहुंच गई। तेल के आयात में वृद्धि हुई जबकि स्वर्ण आयात में गिरावट आई क्योंकि ऊंची कीमतों के कारण खुदरा मांग सुस्त रही। गैर-तेल, गैर-स्वर्ण आयात में गिरावट इलेक्ट्रॉनिक्स सामान, मोती और कीमती पत्थरों, रसायनों और चांदी से प्रेरित थी (चार्ट III.16)। दूसरी छमाही में पण्य व्यापार घाटा पिछले वर्ष की इसी अवधि के 96.3 बिलियन यूएसडी से बढ़कर 106.6 बिलियन यूएसडी हो गया।

सेवा क्षेत्र व्यापार ने भारतीय सेवाओं के लिए मजबूत वैश्विक मांग को दर्शाते हुए महामारी के बाद की तेजी को बनाए रखा (चार्ट III.17)। सेवा निर्यात तीसरी तिमाही में 24.5 प्रतिशत और चौथी तिमाही (फरवरी तक) में 29.2 प्रतिशत बढ़ा, जो दूसरी तिमाही में 30.2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ शीर्ष पर था, यह सॉफ्टवेयर, व्यवसाय, वित्तीय और यात्रा सेवाओं से प्रेरित

चार्ट III.15: माल निर्यात

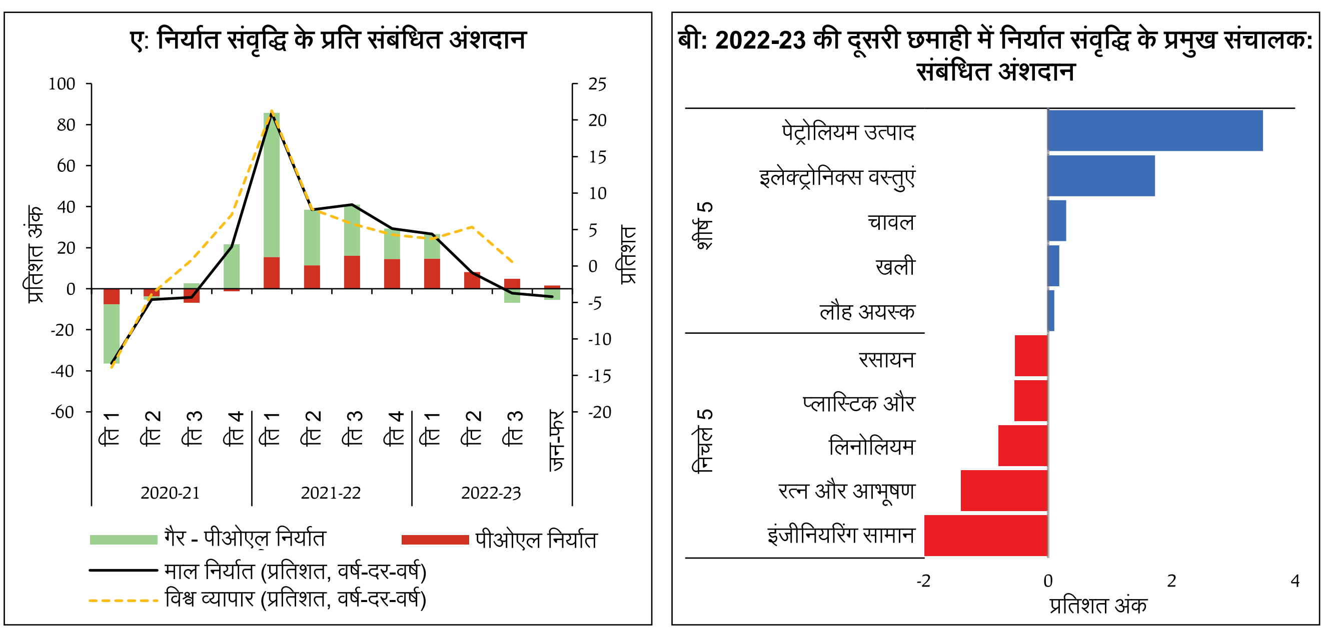

स्रोत: डीजीसीआई एण्ड एस; और सीपीबी, नेदरलैंड्स।

चार्ट III.16: माल आयात

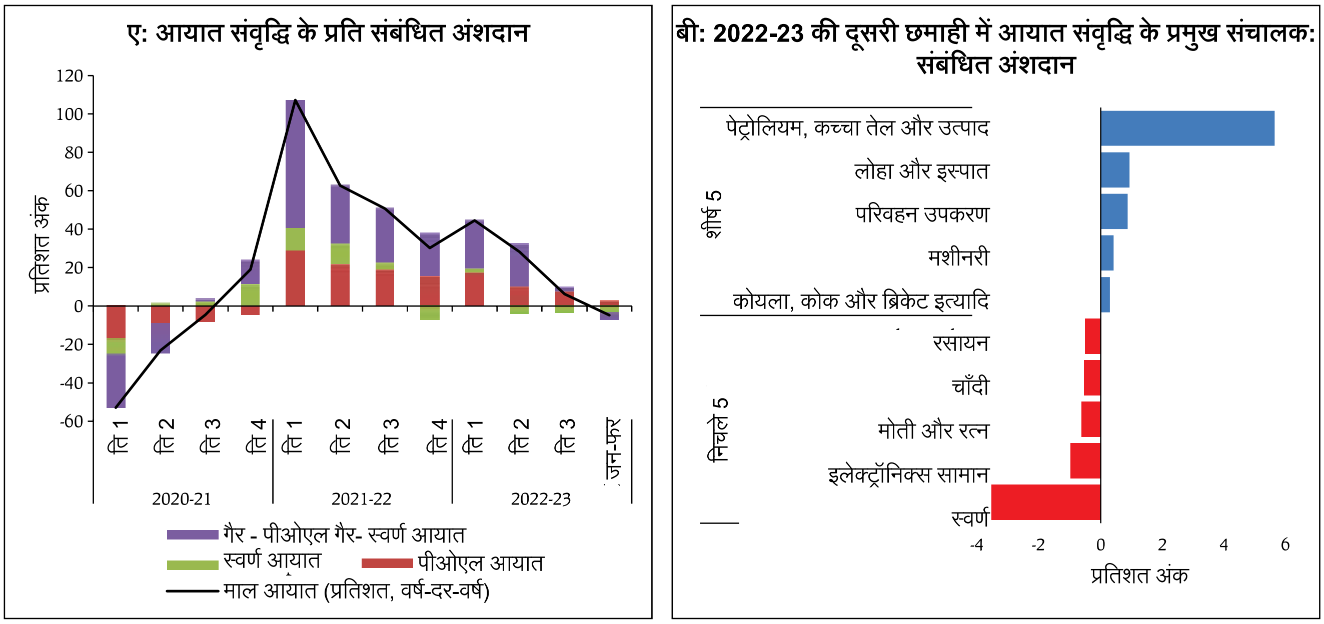

स्रोत: डीजीसीआई एण्ड एस।

था। आवक विप्रेषण ने दूसरी तिमाही में 30.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने के लिए 31.7 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ आघात-सहनीयता का प्रदर्शन किया। चालू खाता घाटा, दूसरी तिमाही के 3.7 प्रतिशत से कम होकर तीसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद का 2.2 प्रतिशत हो गया, जो पण्य व्यापार घाटे को दर्शाता है।

चार्ट III.17: सेवा व्यापार

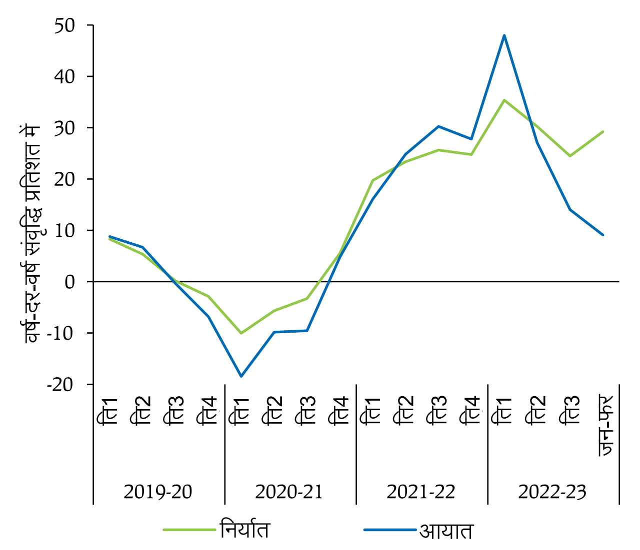

स्रोत: आरबीआई।

वित्तीय खाते की तरफ देखें, तो 2022-23 की दूसरी छमाही में पूंजी का प्रवाह कम हो गया। निवल एफडीआई एक वर्ष पहले के 4.6 बिलियन यूएसडी से घटकर तीसरी तिमाही में 2.1 बिलियन यूएसडी रह गया, जिसका कारण कम अंतर्वाह और उच्च जावक एफडीआई (चार्ट III.18) है। अप्रैल-जनवरी 2022-23 के दौरान, कुल एफडीआई अंतर्वाह में आधे से अधिक हिस्सा संयुक्त रूप में विनिर्माण, वित्तीय सेवाओं और कंप्यूटर सेवाओं का रहा। एफडीआई अंतर्वाह के मुख्य स्रोत सिंगापुर, यूएसए, मॉरीशस और यूएई रहे।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफ़पीआई) तीसरी तिमाही में 4.5 बिलियन यूएसडी की निवल खरीद के साथ आशावादी बने रहे। वे चौथी तिमाही के दौरान मुख्य रूप से इक्विटी सेगमेंट में मौद्रिक नीति प्रसार-प्रभाव और भू-राजनीतिक चिंताओं पर अनिश्चितता के कारण 2.2 बिलियन यूएसडी के निवल बहिर्वाह के साथ निवल विक्रेता थे।

बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) में 2022-23 (फरवरी 2023 तक) के दौरान 6.4 बिलियन यूएसडी का शुद्ध बहिर्वाह दर्ज किया गया, जो कम अंतर्वाह और उच्च मूलधन पुनर्भुगतान के कारण था। 22.8 बिलियन यूएसडी की ईसीबी को अन्य बातों के साथ-साथ ऑन-लेंडिंग/सब-लेंडिंग, नई परियोजनाओं, पूर्ववर्ती ईसीबी के पुनर्वित्त, पूंजीगत वस्तुओं (स्थानीय और

चार्ट III.18: निवल प्रत्यक्ष विदेशी और पोर्टफोलियो निवेश

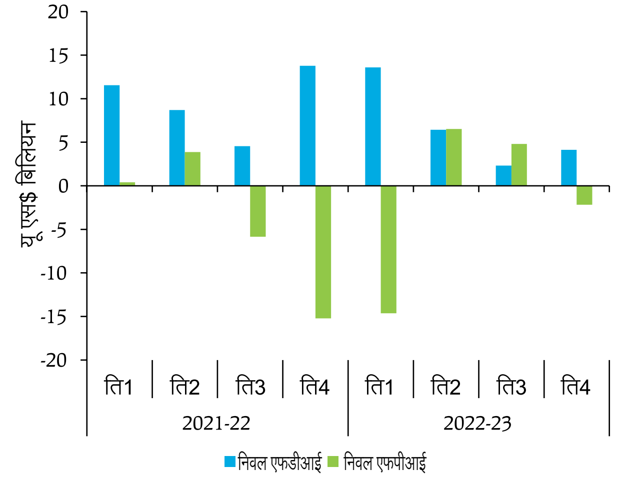

टिप्पणी: 2022-23 की चौथी तिमाही के लिए एफडीआई डेटा जनवरी से संबंधित हैं।
स्रोत: राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल); और आरबीआई।

आयात) की सोर्सिंग और कार्यशील पूंजी के लिए 2022-23 (अप्रैल-फरवरी) में अनुमोदित किया गया था। अप्रैल-2022-23 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान अनिवासी जमा खातों के तहत शुद्ध अंतर्वाह बढ़कर 6.0 बिलियन अमरिकी डॉलर हो गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान 2.7 बिलियन अमरिकी डॉलर था, इस प्रवाह को आकर्षित करने के लिए आरबीआई के जुलाई 2022 के उपायों से सहायता मिली। 31 मार्च 2023 तक, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 578.4 बिलियन अमरीकी डॉलर था, जो 2022-23 में 9.8 महीने के पण्य आयात के बराबर या दिसंबर 2022 के अंत में बकाया विदेशी ऋण का 94.4 प्रतिशत है।

III.2 समग्र आपूर्ति

आधार मूल्यों पर वास्तविक योजित सकल मूल्य (जीवीए) द्वारा मापी जाने वाली समग्र आपूर्ति में 2022-23 की तीसरी तिमाही में 4.6 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई (एक साल पहले यह 4.7 प्रतिशत थी), इसने महामारी-पूर्व में 2019-20 की तीसरी तिमाही के स्तर 12.6 प्रतिशत को पार कर लिया (सारणी III.5)। जहां कृषि और सेवा क्षेत्र आघात-सहनीय बना रहा, वहीं विनिर्माण क्षेत्र में निरंतर इनपुट लागत दबाव के कारण गिरावट आई। तिमाही-दर-तिमाही आधार पर समग्र जीवीए की प्रगति में तीसरी तिमाही में (चार्ट III.19) दोहरे अंकों में वृद्धि दर्ज की गयी।

सारणी III.5: वास्तविक जीवीए संवृद्धि

(वर्ष-दर-वर्ष प्रतिशत)

क्षेत्र	2021-22 (एफआरई)	2022-23 (एसएई)	भारित योगदान		2021-22				2022-23			
			2021-22	2022-23	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3	ति4#
कृषि,फोरेस्टरी और फिशिंग	**3.5 (7.8)**	**3.3 (11.4)**	**0.6**	**0.5**	**3.4 (7.4)**	**4.8 (9.4)**	**2.3 (7.2)**	**4.1 (7.6)**	**2.5 (10.1)**	**2.4 (12.0)**	**3.7 (11.1)**	**4.3 (12.3)**
उद्योग	**10.5** (11.5)	**1.7 (13.4)**	**2.4**	**0.4**	**42.1 (3.9)**	**7.3 (13.8)**	**2.2 (11.9)**	**1.3 (16.4)**	**7.6 (11.7)**	**-2.3 (11.1)**	**0.3 (12.2)**	**1.5 (18.2)**
खनन तथा उत्खनन	7.1 (-2.1)	3.4 (1.2)	0.2	0.1	12.2 (-7.5)	10.6 (1.7)	5.4 (-0.3)	2.3 (-1.5)	9.3 (1.1)	-0.4 (1.3)	3.7 (3.4)	0.9 (-0.6)
विनिर्माण	11.1 (14.3)	0.6 (14.9)	2.0	0.1	51.5 (6.3)	6.6 (16.2)	1.3 (14.3)	0.6 (20.2)	6.4 (13.1)	-3.6 (12.0)	-1.1 (13.0)	0.9 (21.3)
विद्युत,गैस, जल आपूर्ति तथा अन्य उपयोज्यता	9.9 (5.1)	9.2 (14.7)	0.2	0.2	16.3 (-1.6)	10.8 (6.4)	6.0 (6.7)	6.7 (9.4)	14.9 (13.1)	6.0 (12.8)	8.2 (15.5)	7.6 (17.8)
सेवाएँ	**9.6** (0.9)	**9.3 (10.3)**	**5.8**	**5.7**	**17.9 (-10.8)**	**11.0 (-0.5)**	**6.5 (6.3)**	**4.9 (9.1)**	**16.3 (3.8)**	**9.0 (8.4)**	**6.5 (13.2)**	**6.6 (16.3)**
निर्माण	14.8 (8.2)	9.1 (18.1)	1.1	0.7	77.0 (-8.7)	10.8 (5.3)	0.2 (8.6)	4.9 (26.0)	16.2 (6.2)	5.8 (11.5)	8.4 (17.7)	7.3 (35.2)
व्यापार, होटल, परिवहन, संचार	13.8 (-8.7)	14.2 (4.3)	2.3	2.5	41.4 (-28.6)	13.1 (-7.7)	9.2 (-1.2)	5.0 (1.8)	25.7 (-10.2)	15.6 (6.7)	9.7 (8.3)	9.7 (11.6)
वित्त, रियल एस्टेट एवं व्यावसायिक सेवाएँ	4.7 (6.9)	6.9 (14.2)	1.1	1.5	2.8 (1.9)	7.0 (1.6)	4.3 (14.4)	4.6 (13.2)	8.6 (10.7)	7.1 (8.9)	5.8 (21.0)	5.6 (19.5)
लोक प्रशासन , रक्षा तथा अन्य सेवाएँ	9.7 (1.3)	7.1 (8.5)	1.2	0.9	6.5 (-7.9)	16.8 (2.5)	10.6 (5.1)	5.2 (4.5)	21.3 (11.6)	5.6 (8.2)	2.0 (7.2)	2.9 (7.5)
मूल कीमतों पर जीवीए	**8.8 (4.2)**	**6.6 (11.2)**	**8.8**	**6.6**	**20.2 (-5.1)**	**9.3 (3.7)**	**4.7 (7.7)**	**3.9 (10.5)**	**12.1 (6.4)**	**5.5 (9.4)**	**4.6 (12.6)**	**5.1 (16.1)**

टिप्पणी: एफआरई: पहला संशोधित अनुमान; एसएई: दूसरा अग्रिम अनुमान; #:अंतर्निहित
कोष्ठकों में दिये गए आंकड़े 2019-20 की संवृद्धि दरें हैं |
स्रोत: एनएसओ।

चार्ट III.19: जीवीए संवृद्धि और गति

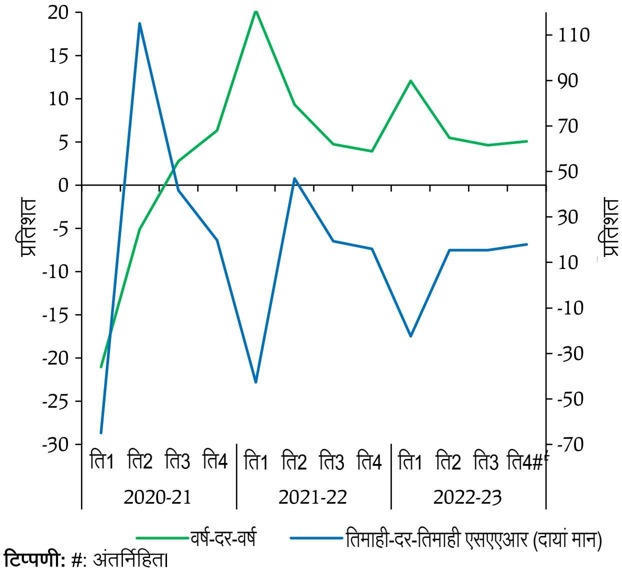

टिप्पणी: #: अंतर्निहित।
स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

III.2.1 कृषि

वर्ष 2022-23 की दूसरी छमाही में जीवीए ने कृषि, वानिकी और मत्स्यन में 4.0 प्रतिशत (एक साल पहले 3.1 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज की, यहां तक कि प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों में सामान्य से कम बारिश के कारण और कटाई के चरण के दौरान अधिक बारिश के कारण *खरीफ* उत्पादन में गिरावट देखी गई। 2022-23 में जलाशयों के स्तर और मिट्टी की नमी में सुधार से *रबी* में पिछले वर्ष की तुलना में 3.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वर्ष 2022-23 में खाद्यान्न उत्पादन ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। वर्ष 2022-23 में रबी की फसलों में मुख्यत: चना और अन्य दालों के उत्पादन कारण दालों का उत्पादन 1.9 प्रतिशत बढ़ गया था । व्यावसायिक फसलों में तिलहन और गन्ना ने 2022-23 में रिकॉर्ड उत्पादन स्तर हासिल किया (सारणी III.6)।

कृषि जीवीए में लगभग 45 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ पशुधन, वानिकी और मछली पकड़ने जैसी संबद्ध गतिविधियों ने 2021-22 में कृषि जीवीए वृद्धि में लगभग तीन-चौथाई योगदान दिया है (चार्ट III.20)।

सारणी III.6: 2022-23 में कृषि उत्पादन

(लाख टन)

फसल	2021-22		2022-23		2022-23 में परिवर्तन (प्रतिशत)		
	एसएई	अंतिम	लक्ष्य	एसएई	एसएई से अधिक 2021-22	अंतिम से अधिक 2021-22	लक्ष्य से अधिक
खाद्यान्न	3,160.6	3,156.2	3,280.0	3,235.5	2.4	2.5	-1.4
खरीफ़	1,535.4	1,553.6	1,631.5	1,534.3	-0.1	-1.2	-6.0
रबी	1,625.3	1,602.5	1,648.5	1,701.2	4.7	6.2	3.2
चावल	1,279.3	1,294.7	1,305.0	1,308.4	2.3	1.1	0.3
गेहूं	1,113.2	1,077.4	1,120.0	1,121.8	0.8	4.1	0.2
दालें	269.6	273.0	295.5	278.1	3.2	1.9	-5.9
तिलहन	371.5	379.6	413.5	400.0	7.7	5.4	-3.3
गन्ना	4,140.4	4,394.3	4,150.0	4,687.9	13.2	6.7	13.0
कपास #	340.6	311.2	370.0	337.2	-1.0	8.4	-8.9
जूट और मेस्ता ##	95.7	101.5	105.0	100.5	5.0	-1.0	-4.3

#: प्रत्येक 170 किलोग्राम की लाख गांठें। ##: प्रत्येक 180 किलो की लाख गांठें।
एसएई: दूसरा अग्रिम अनुमान।
स्रोत: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

वर्ष 2022-23 के दौरान 492.2 लाख टन चावल की कुल खरीद पिछले वर्ष की तुलना में 2.2 प्रतिशत कम थी। विस्तारित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के

चार्ट III.20: फसलों और सम्बद्ध गतिविधियों का योगदान

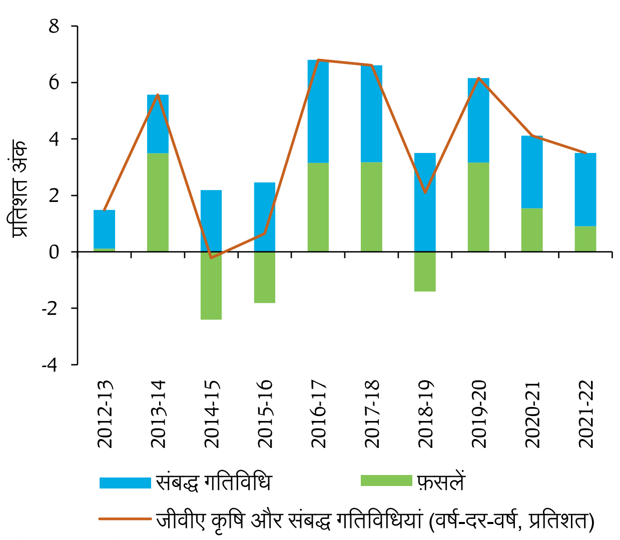

स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट III.21: स्टॉक, खरीद और उठाव

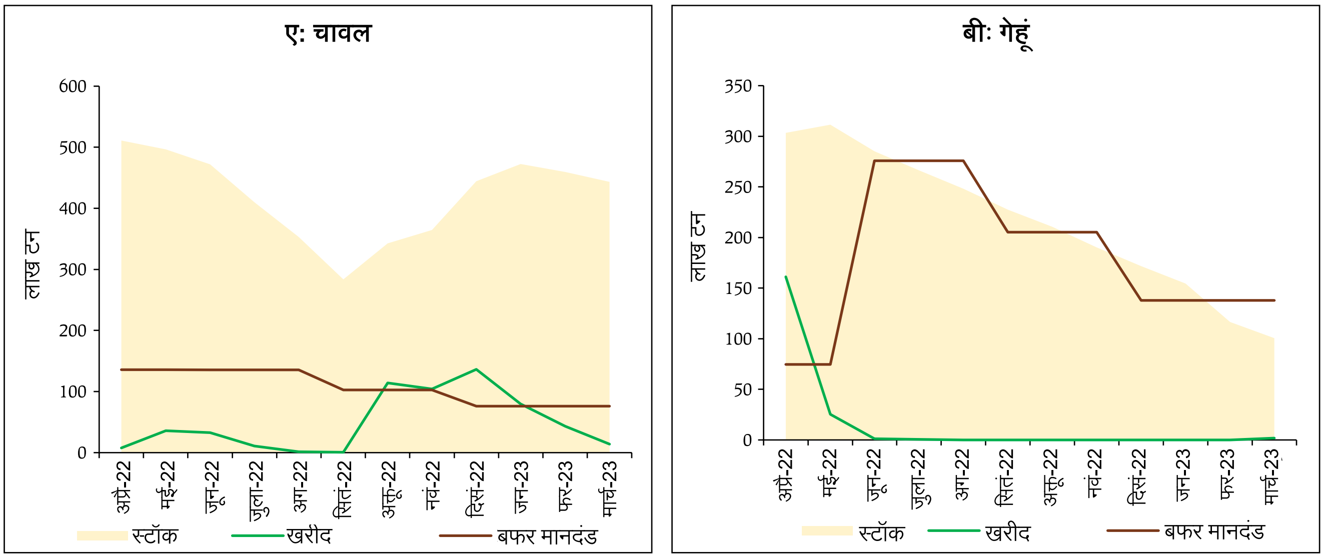

स्रोत: भारतीय खाद्य निगम, जीओआई।

तहत 16 मार्च 2023 में खाद्यान्न बफर स्टॉक - चावल के लिए 443.2 लाख टन (मानक से 5.8 गुना) और गेहूं के लिए 100.6 लाख टन (मानक से 0.7 गुना) - 82.6 लाख टन अनाज (अक्टूबर-दिसंबर 2022) की कुल खरीद के बावजूद मानदंड से ऊपर थे (चार्ट III.21)।

उच्च-आवृत्ति संकेतक जैसे ट्रैक्टर बिक्री, दोपहिया बिक्री, उर्वरक बिक्री, कृषि ऋण वृद्धि और मनरेगा नौकरियों की मांग दूसरी छमाही के दौरान ग्रामीण गतिविधि में सुधार दर्शाते हैं (सारणी III.7)।

सारणी III 7: ग्रामीण अर्थव्यवस्था - उच्च आवृत्ति संकेतक

मद	यूनिट	एच1 (अप्रैल-सितं)				एच2 (अक्टू-फर)			
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
ट्रैक्टर की बिक्री	संख्या (लाख में)	3.6	4.0	4.4	4.9	3.2	4.1	3.3	3.8
टू व्हीलर की बिक्री	संख्या (लाख में)	97.0	59.9	65.5	83.8	68.5	76.4	58.2	61.7
उर्वरक की बिक्री	लाख टन	272.6	312.4	269.1	307.2	254.6	268.9	232.0	275.2
रोजगार की मांग (मनरेगा)	करोड़ परिवार	11.8	17.6	16.7	16.7	10.7	15.5	13.6	12.0
कृषि और संबद्ध क्षेत्र का निर्यात*	अमरीकी डालर बिलियन	17.1	17.9	22.7	26.4	11.9	18.5	17.7	16.4
कृषि ऋण संवृद्धि	वर्ष-दर-वर्ष	6.5	10.9	10.6	13.4	9.8	8.8	10.3	14.9
बफर मानक के लिए चावल का स्टॉक#	अनुपात	2.9	2.4	3.4	2.8	6.6	6.7	7.8	6.0
बफर मानक के लिए गेहूँ का स्टॉक#	अनुपात	2.0	2.1	2.3	1.1	2.0	2.1	1.7	0.8

*जनवरी तक। #: दूसरी छमाही के दौरान 16 मार्च को।
स्रोत: ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन; एसआईएएम; रसायन और उर्वरक मंत्रालय; ग्रामीण विकास मंत्रालय; सीएमआईई; आरबीआई; और भारतीय खाद्य निगम।

III.2.2 उद्योग

लगातार दूसरी तिमाही के लिए विनिर्माण क्षेत्र जीवीए में संकुचन के कारण औद्योगिक गतिविधि, तीसरी तिमाही में सुस्त रही, *यद्यपि* इसकी गति धीमी रही (चार्ट III.22)। खनन गतिविधि को कोयला उत्पादन से बढ़ावा मिला, जो कि कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में गिरावट से अधिक था। चौथी तिमाही में औद्योगिक गतिविधि में सुधार हुआ। बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाओं ने दूसरी छमाही में वर्ष-दर-वर्ष 7.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) बिजली और खनन द्वारा समर्थित होकर दूसरी तिमाही में 1.6 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही में 2.6 प्रतिशत और जनवरी में 5.2 प्रतिशत बढ़ा। यह विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधि के कारण कम हुआ, जो तीसरी तिमाही में 1.1 प्रतिशत और जनवरी में 3.7 प्रतिशत तक विस्तारित हुआ। तीसरी तिमाही में कपड़ा, परिधान, चमड़ा और संबंधित उत्पादों और बिजली के उपकरणों जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों में कमी आई, जबकि बुनियादी धातु, मोटर वाहन, ट्रेलर और अर्ध-ट्रेलर, मशीनरी और उपकरण, और अन्य गैर-धात्विक खनिज उत्पादों में विस्तार दर्ज किया गया। (चार्ट III.23)। उपयोग-आधारित वर्गीकरण के संदर्भ में, तीसरी तिमाही और जनवरी के दौरान पूंजीगत वस्तुओं और बुनियादी ढांचे/ निर्माण वस्तुओं का विस्तार एक स्वस्थ गति से हुआ, जबकि टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन घटा (चार्ट III.23)। मूल आधारभूत संरचना प्रतिफल में वृद्धि तीसरी तिमाही के 4.5 प्रतिशत से बढ़कर चौथी तिमाही में 7.5 प्रतिशत हो गई (फरवरी तक) ।

वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही में बिजली उत्पादन 7.9 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़ा (महामारी पूर्व-स्तर से 18.2 प्रतिशत अधिक)। तीसरी तिमाही में ताप विद्युत (थर्मल पॉवर) उत्पादन में 7.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई और इसने कुल उत्पादन में लगभग 75.8 प्रतिशत का योगदान दिया। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (कुल उत्पादन में 11.5 प्रतिशत की हिस्सेदारी) में 22.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। चौथी तिमाही (फरवरी तक) में, बिजली उत्पादन की संवृद्धि 10.1 प्रतिशत तक बढ़ी (चार्ट III.24ए)। क्षेत्रवार, उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र बिजली मांग के चालक थे (चार्ट III.24बी)।

चार्ट III.22: उद्योग संवृद्धि

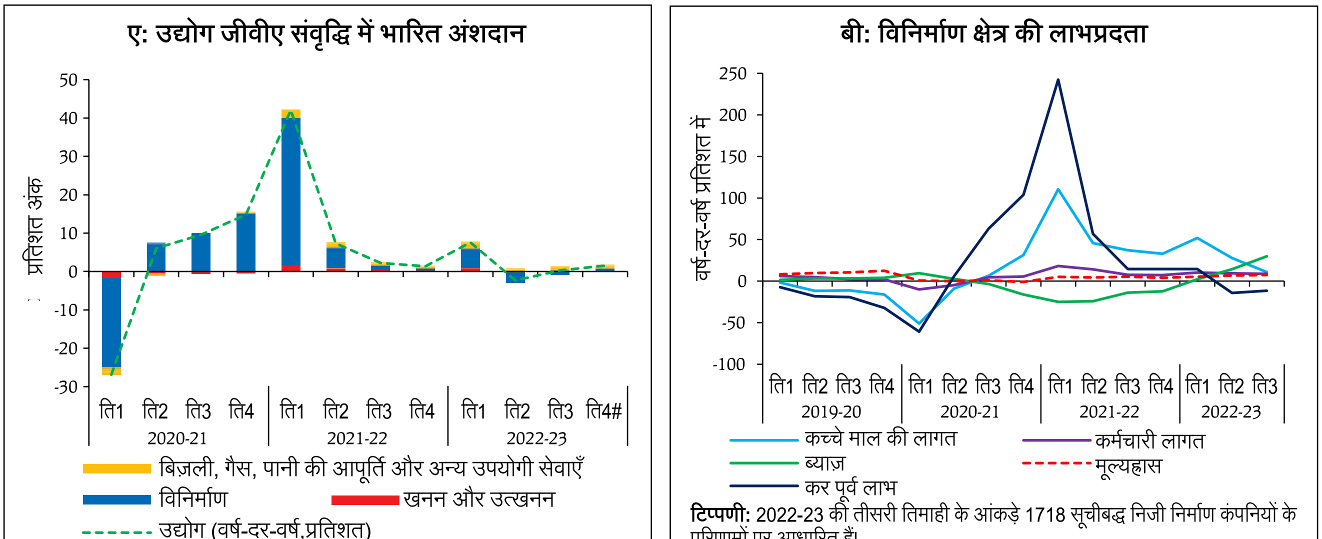

स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

टिप्पणी: 2022-23 की तीसरी तिमाही के आंकड़े 1718 सूचीबद्ध निजी निर्माण कंपनियों के परिणामों पर आधारित हैं।

स्रोत: सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट III.23: औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (आईआईपी)

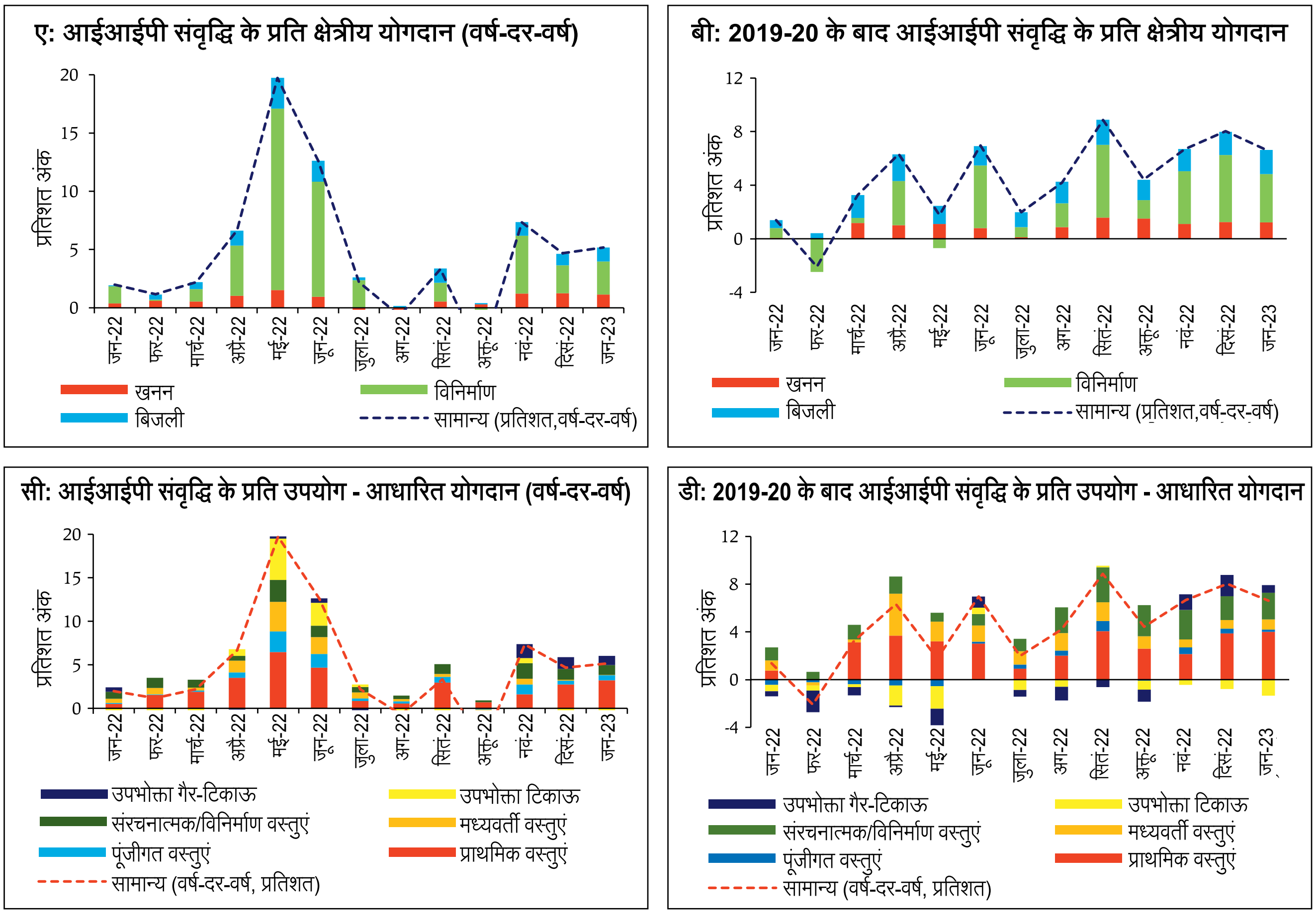

स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) में दूसरी छमाही में बढ़ोत्तरी हुई, हालांकि यह नए कार्यों और निर्यात ऑर्डर के कारण तीसरी तिमाही में 56.3 से घटकर चौथी तिमाही (फरवरी तक) में 55.7 हो गया (चार्ट III.2 5 ए)।

चार्ट III.24: बिजली उत्पादन और खपत

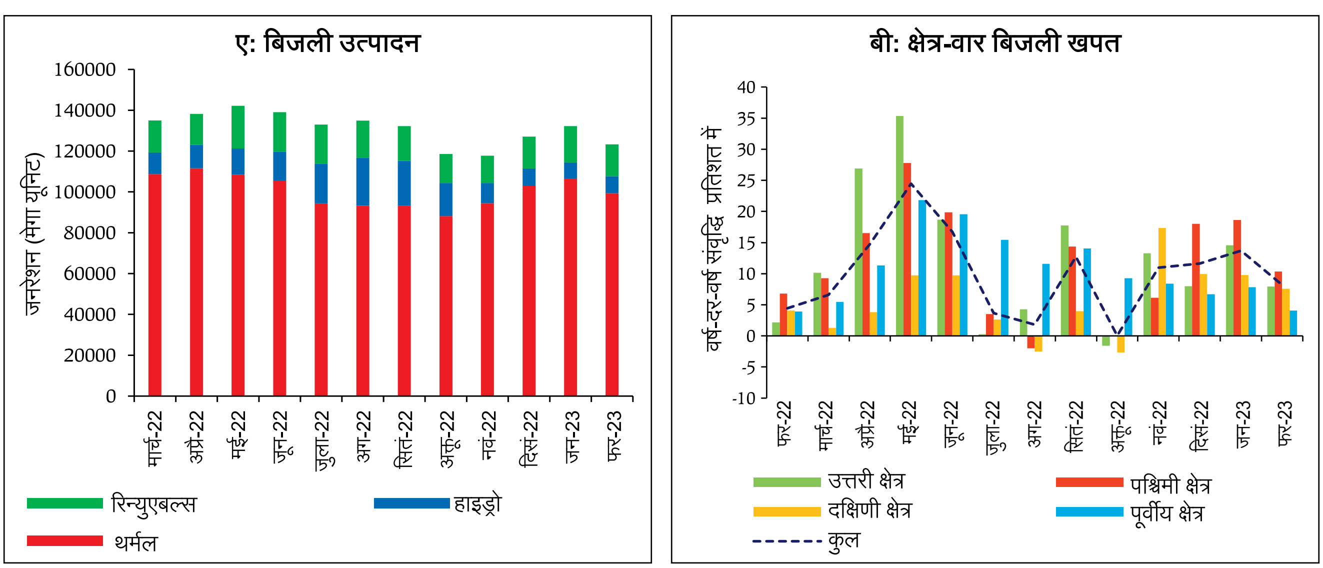

स्रोत: केंद्रीय बिजली प्राधिकरण और बिजली व्यवस्था संचालन निगम (पीओएसओसीओ)।

चार्ट III.25: पीएमआई विनिर्माण और सेवाएं

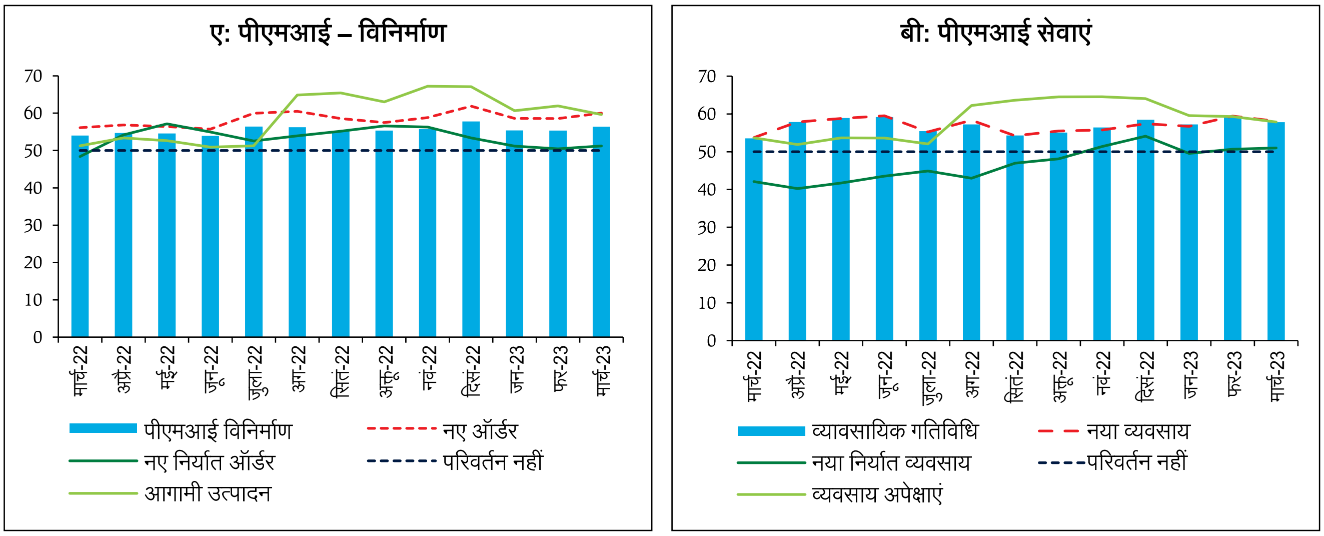

टिप्पणी: > 50: विस्तार, < 50: संकुचन|
स्रोत: एस एंड पी ग्लोबल।

विनिर्माण, प्राथमिक वस्तुएं, बुनियादी संरचना और निर्माण, और पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन महामारी पूर्व स्तर को पार कर गया, जबकि उपभोक्ता वस्तुएं पिछड़ रही हैं। प्रमुख उप-क्षेत्रों में, इस्पात उत्पादन, सीमेंट उत्पादन, बिजली उत्पादन और यात्री

सारणी III.8: औद्योगिकी क्षेत्र: सामान्यीकरण की दिशा में प्रगति
(2019-2020 के संबंधित माह/तिमाही के लिए अनुपात)

	संकेतक	2020-21				2021-22				2022-23					
		ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3	जन	फर	मार्च
I	**औद्योगिक उत्पादन**														
1	पीएमआई: विनिर्माण (>50 पिछले महीने की तुलना में वृद्धि दर्शाता है)	35.1	51.6	57.2	56.9	51.5	53.8	56.3	54.3	54.4	55.9	56.3	55.4	55.3	56.4
II	**औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक**	64	94	102	106	93	103	104	108	105	105	106	107		
2	आईआईपी: विनिर्माण	60	94	102	107	91	102	103	108	103	103	104	105		
3	आईआईपी: प्राथमिक वस्तुएं	80	92	99	101	96	103	103	105	110	107	109	112		
4	आईआईपी: पूंजीगत वस्तुएं	35	87	99	109	74	102	97	111	95	109	105	103		
5	आईआईपी: इन्फ्रास्ट्रक्चर और निर्माण वस्तुएं	53	98	105	110	98	110	109	117	108	116	118	117		
6	आईआईपी: उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	32	90	107	118	72	99	103	111	92	96	94	88		
7	आईआईपी: उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुएं	83	100	103	105	98	101	103	102	99	96	104	104		
III	**आठ कोर इंडस्ट्रीज इंडेक्स**	76	95	100	103	96	104	105	109	109	110	110	115	109	
8	ईसीआई: स्टील	51	100	103	113	97	108	105	118	104	115	114	124	115	
9	ईसीआई: सीमेंट	62	89	96	110	97	110	104	119	114	115	115	112	112	
10	बिजली की मांग	84	99	106	108	98	108	110	113	116	115	118	121	113	
III	**ऑटोमोबाइल का उत्पादन**														
11	यात्री वाहन	16	94	120	123	83	95	100	120	106	127	120	121	118	
12	टू व्हीलर्स	22	95	118	129	60	90	92	102	83	97	92	89	85	
13	थ्री व्हीलर्स	23	45	66	84	61	60	67	83	64	75	76	71	82	
14	ट्रैक्टर्स	60	123	162	153	133	143	118	99	152	140	125	133	120	

स्रोत: सीएमआईई; सीआईईसी; एनएसओ; एसआईएएम; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

← पूर्व-कोविड स्तर से नीचे गतिविधि का सामान्यीकरण/बहाली →

वाहनों का उत्पादन अपने 2019-20 के स्तर से ऊपर चल रहा है, जबकि दोपहिया और तिपहिया वाहनों का उत्पादन पिछड़ रहा है (सारणी III.8)।

III.2.3 सेवाएं

सेवा क्षेत्र ने 2022-23 की दूसरी छमाही में अच्छा प्रदर्शन किया, जो संपर्क-गहन सेवाओं और निर्माण गतिविधि (चार्ट III.26ए) की गति द्वारा समर्थित है। सेवा क्षेत्र का जीवीए तीसरी तिमाही में 6.5 प्रतिशत बढ़ा और यह सकल जीवीए (कुल जीवीए वृद्धि में लगभग 84 प्रतिशत योगदान के साथ) का मुख्य चालक था। संपर्क-गहन सेवाओं, जैसे व्यापार, होटल, परिवहन और संचार, दूसरी छमाही में 9.7 प्रतिशत (पहली छमाही में 20.1 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। फ़िनिश्ड स्टील की खपत और सीमेंट उत्पादन के रुझानों के अनुसार दूसरी छमाही में निर्माण गतिविधि मजबूत रही (चार्ट III.26बी)।

चौथी तिमाही में मजबूत जीएसटी संग्रह घरेलू व्यापारिक गतिविधियों के निरंतर पुनरुद्धार की ओर इशारा करता है (सारणी III.9)। अवकाश, कारोबारी यात्रा तथा संबंधित गतिविधियों के कारण घरेलू हवाई यात्री यातायात की संख्या 2022-23 की तीसरी तिमाही में बढ़ी और चौथी तिमाही में यह मजबूत बनी रही। परिवहन सेवाओं के संकेतकों के बीच, वाणिज्यिक वाहनों में तीसरी तिमाही में दोहरे अंकों की गति से वृद्धि हुई और तीसरी और चौथी तिमाही में टोल संग्रह मजबूत रहा। अक्टूबर-नवंबर के दौरान धीमी वृद्धि के बाद दिसंबर-फरवरी के दौरान पोर्ट कार्गो में तीव्र गति से वृद्धि हुई। तीसरी और चौथी तिमाही में रेलवे माल ढुलाई में मामूली वृद्धि हुई। सेवा पीएमआई तीसरी तिमाही में 56.6 से बढ़कर चौथी तिमाही में 58.1 हो गया। फरवरी में 59.4 पर पीएमआई सेवाओं ने नए व्यापार आदेशों के कारण 12 वर्षों में सबसे मजबूत वृद्धि का संकेत दिया (चार्ट III.25बी)। पीएमआई समग्र आउटपुट सूचकांक तीसरी तिमाही में 57.2 से सुधरकर चौथी तिमाही में 58.3 हो गया।

आईटी क्षेत्र ने 2022-23 की तीसरी तिमाही में अच्छा प्रदर्शन किया, यह निरंतर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मांग दोनों द्वारा समर्थित बिक्री में मजबूत वृद्धि से परिलक्षित होता है । वृद्धि में नरमी के बावजूद संपर्क-गहन सेवाओं में तेजी के साथ, आईटी से

चार्ट III.26: सेवा क्षेत्र

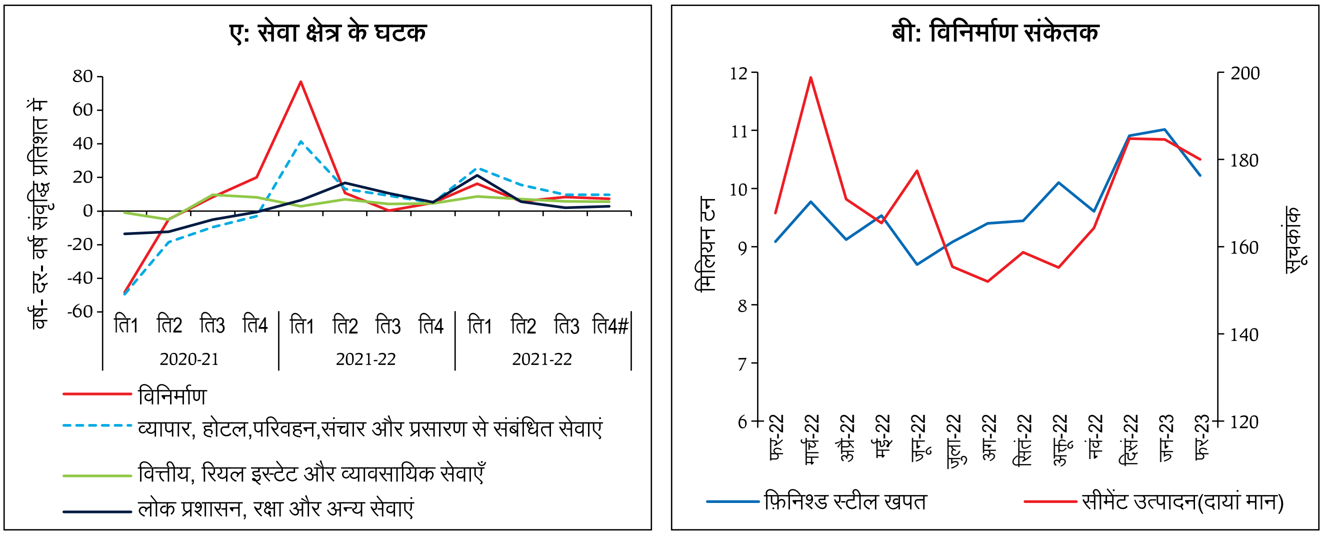

टिप्पणी: #: अंतर्निहिता।
स्रोत: आर्थिक सलाहकार कार्यालय; संयुक्त आयोजना समिति; औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग; वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।

सारणी III.9: सेवा क्षेत्र: सामान्यीकरण की दिशा में प्रगति
(2019-2020 के संबंधित माह/तिमाही के लिए अनुपात)

संकेतक	2020-21				2021-22				2022-23					
	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3	जन	फर	मार्च
1 पीएमआई: सेवाएं (>50 पिछले महीने की तुलना में वृद्धि दर्शाता है)	17.2	41.9	53.4	54.2	47.2	52.4	57.3	52.3	58.7	55.7	56.6	57.2	59.4	57.8
I **निर्माण**														
2 स्टील की खपत	49	93	114	123	99	94	107	122	109	107	121	120	120	
3 सीमेंट उत्पादन	62	89	96	110	97	110	104	119	114	115	115	112	112	
II **व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएं**														
4 वाणिज्यिक वाहन की बिक्री	15	80	99	143	51	99	100	170	108	139	117			
5 घरेलू हवाई यात्री यातायात	7	25	50	72	31	53	81	77	95	87	96	100	100	
6 घरेलू एयर कार्गो	26	68	90	105	78	86	92	101	103	95	90	87	95	
7 अंतर्राष्ट्रीय एयर कार्गो	43	77	87	101	94	96	100	103	92	92	89	86	88	
8 माल ढुलाई	79	105	111	113	110	118	119	121	123	128	123	122	116	
9 पोर्ट कार्गो	80	91	103	107	102	97	104	106	111	109	110	113	114	
10 टोल संग्रहण: मात्रा	184	349	295	174	548	699	513	259	1035	947	670	324	261	
11 पेट्रोलियम की खपत	74	88	101	100	85	93	98	105	100	103	104	100	102	
12 जीएसटी ई-वे बिल	50	100	115	128	98	127	128	140	143	153	150	145	143	
13 जीएसटी राजस्व	59	92	108	114	106	118	130	133	144	151	148	141	142	164
III **वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएँ**														
14 क्रेडिट बकाया वर्ष-दर-वर्ष संवृद्धि (प्रतिशत)	6.2	5.2	5.6	4.6	4.8	5.6	9.3	9.6	13.2	16.4	14.9	16.3	15.5	15.0
15 बैंक जमाराशि वर्ष-दर-वर्ष संवृद्धि (प्रतिशत)	11.0	10.5	11.5	11.4	10.3	9.4	10.3	8.9	8.3	9.2	9.2	10.5	10.1	9.6
16 जीवन बीमा प्रथम वर्ष का प्रीमियम	81	116	97	135	87	122	107	169	122	166	127	128	123	
17 गैर-जीवन बीमा प्रीमियम	95	105	104	115	107	118	113	127	133	130	132	147	144	

स्रोत: सीएमआईई; सीआईईसी;एनएसओ; एमओएसपीआई; आईआरडीएआई; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

← पूर्व-कोविड स्तर से नीचे गतिविधि का सामान्यीकरण/बहाली →

चार्ट III.27: औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में सांकेतिक बिक्री वृद्धि

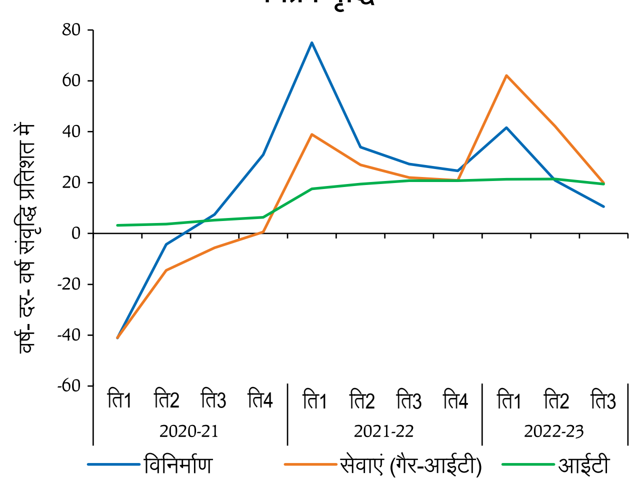

टिप्पणी: 2022-23 की तीसरी तिमाही का परिणाम 1,718 सूचीबद्ध निजी विनिर्माण कंपनियों और 740 सूचीबद्ध निजी गैर-वित्तीय सेवा कंपनियों पर आधारित है।
स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान।

इतर सेवाओं में भी बिक्री में मजबूत प्रदर्शन देखा गया (चार्ट III.27)।

वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही में स्थावर संपदा गतिविधि को उच्च नए लॉन्च और बढ़ी हुई अविक्रीत इन्वेंट्री (चार्ट III.28ए) द्वारा चिह्नित किया गया है। आवास की अखिल भारतीय कीमतों की वृद्धि में तीसरी तिमाही में गिरावट आई; शहर-वार, बेंगलुरु और चेन्नई में गति तेज हुई, जबकि दिल्ली और मुंबई में इस गति में कमी आई (चार्ट III.28बी)। लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं (पीएडीओ) में वृद्धि में दूसरी छमाही में कमी आई। ब्याज भुगतान और सब्सिडियों को छोड़कर केंद्र का राजस्व व्यय तीसरी तिमाही के दौरान 2.2 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) और जनवरी-फरवरी 2023 में 11.4 प्रतिशत बढ़ा। प्रतिकूल आधार के कारण तीसरी तिमाही में निजी सेवाओं में आंशिक रूप से कमी आई।

चार्ट III.28: आवास क्षेत्र – प्रारंभ, बिक्री और कीमतें

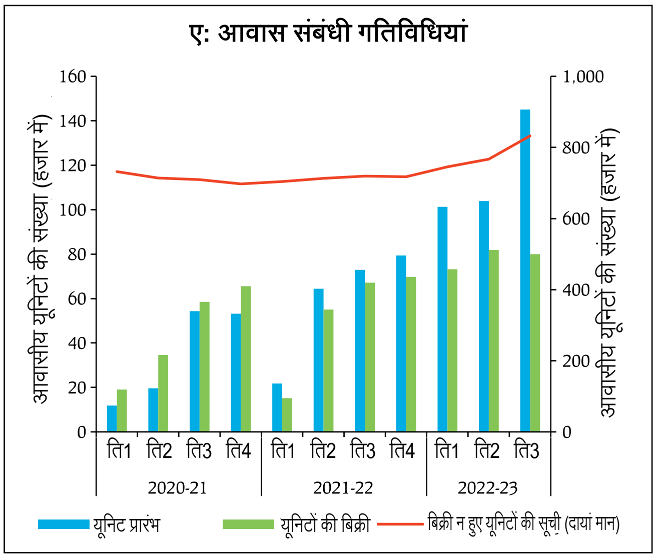

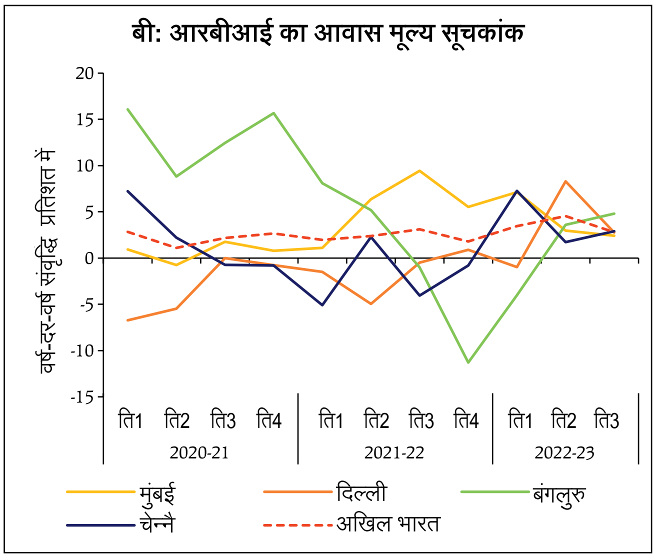

स्रोत: प्रोप टाईगर; और आरबीआई।

III.3 निष्कर्ष

बढ़ती हुए वैश्विक विपरीत परिस्थितियों के बीच वर्ष 2022-23 की दूसरी छमाही में घरेलू आर्थिक गतिविधियों में समुत्थानशीलता की स्थिति बनी रही। निवेश गतिविधियां मजबूत रहीं जबकि निजी उपभोग वृद्धि में कमी आई। आपूर्ति पक्ष में, जबकि उच्च सेवा क्षेत्र मुख्य चालक था,उच्च निविष्टि लागत दबाव विनिर्माण क्षेत्र को नीचे खींच रहा था। ग्रामीण मांग में सुधार, बुनियादी ढांचे के खर्च पर सरकार का जोर देना, कॉर्पोरेट निवेश में वृद्धि, स्वस्थ बैंक ऋण और पण्य की कीमतों में कमी आदि से आगे आर्थिक गतिविधि को समर्थन मिलेगा। लंबे समय तक भू-राजनीतिक तनाव, सख्त वैश्विक वित्तीय स्थितियाँ, वैश्विक वित्तीय बाजार में अस्थिरता और बाहरी मांग में गिरावट से निमित्त विपरीत परिस्थितियां इस दृष्टिकोण के लिए प्रमुख जोखिम हैं।

IV. वित्तीय बाज़ार एवं चलनिधि स्थितियां

वर्ष 2022-23 की दूसरी छमाही के दौरान नीतिगत रेपो दर में वृद्धि, चलनिधि में कमी और खासकर इक्विटी और विदेशी मुद्रा खंडों को बार-बार प्रभावित करने वाली वैश्विक अस्थिरता के दौर के बीच घरेलू वित्तीय बाजार व्यवस्थित तरीके से विकसित हुए। बैंक जमा और उधार दरों में उच्चतर वृद्धि हुई। इसे देखते हुए, आरबीआई को घरेलू वित्तीय बाजारों पर वैश्विक प्रभाव-विस्तार (स्पिलओवर)को कम करने के लिए सतर्क रहने की जरूरत होगी।

प्रस्तावना

सितंबर 2022 की मौद्रिक नीति रिपोर्ट के बाद से, वैश्विक वित्तीय बाजार लंबे भू-राजनीतिक तनावों, अर्थव्यवस्थाओं में लक्ष्य से काफी ऊपर मुद्रास्फीति और आक्रामक मौद्रिक सख्ती के बीच अस्थिर बने हुए हैं। मार्च में आ रहे आँकड़ों और उच्च तीव्रता वाली बैंकिंग उथल-पुथल की घटनाओं के चलते सॉवरेन बॉन्ड के प्रतिफल में व्यापक रूप से उतार-चढ़ाव हुआ। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) में इक्विटी बाजारों ने मौद्रिक नीति की अल्प प्रतिबंधात्मक रुख की प्रत्याशा में तेजी दिखाई है, साथ ही ईएमई शेयरों ने भी तब तक वैश्विक रुख को ही प्रतिबिंबित किया, जब तक अमेरिका में कुछ बैंकों के पतन ने सुरक्षित निवेश की और रुख मोड़ नहीं दिया। मुद्रा बाजारों में, अमेरिकी डॉलर दो दशक के शिखर पर रहने के बाद नीचे खिसका और अक्टूबर 2022-जनवरी 2023 के दौरान अधिकांश मुद्राओं के मुकाबले कमजोर हुआ, लेकिन मजबूत अमेरिकी आंकड़ों के कारण फरवरी में इसमें तेजी आई। अस्थिरता ने जोखिम से बचने, सुरक्षित निवेश की मांग और वैश्विक इक्विटी बाजारों में सुधार के माहौल में ईएमई मुद्राओं को प्रभावित किया।

IV.1 घरेलू वित्तीय बाजार

इसके विपरीत, घरेलू वित्तीय बाजार व्यवस्थित तरीके से विकसित हुए। वर्ष 2022-23 की दूसरी छमाही के दौरान मुद्रा बाजार की ब्याज दरें महंगी हो गईं, जबकि बॉन्ड प्रतिफल काफी हद तक एक दायरे में रहे। दूसरी छमाही में इक्विटी बाजारों ने दो-तरफा संचलन दर्शाया। भारतीय रुपये (आईएनआर) में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मूल्यह्रास हुआ। मौद्रिक नीति कार्रवाइयों के चलते बैंक जमा और उधार दरों में वृद्धि हुई। 2022-23 के पूरे वर्ष भर बैंक ऋण में वृद्धि दोहरे अंकों में रही, हालांकि दिसंबर 2022 से इसमें कमी के लक्षण दिखाई दिए।

IV.1.1 मुद्रा बाजार

वर्ष 2022-23 की दूसरी छमाही में मुद्रा बाजार दरों की सभी परिपक्वताओं में मजबूती आई, जो पॉलिसी रेपो दर में वृद्धि और अधिशेष चलनिधि में कमी को दर्शाता है। इन घटनाओं को प्रतिबिंबित करते हुए, भारित औसत मांग मुद्रा दर (डब्ल्यूएसीआर), मोटे तौर पर रेपों दर के आसपास रही- यह वर्ष 2022-23 की दूसरी छमाही में रेपो दर से 3 आधार अंक (बीपीएस) ऊपर थी जबकि यह पहली छमाही में 27 बीपीएस नीचे थी (चार्ट IV.1)।

ओवरनाइट मांग मुद्रा सेग्मेंट में, ट्रेड किए गए लेनदेनों (औसत) पर भारित औसत दर (डब्ल्यूएआर) नीति रेपो दर से 5 आधार अंक ऊपर थी, जबकि यह दूसरी छमाही में रिपोर्ट किए गए लेनदेनों[1] के 15 बीपीएस नीचे थी (चार्ट IV.2ए) । दूसरी

चार्ट IV.1: चलनिधि, पॉलिसी कॉरीडोर तथा डब्ल्युएसीआर

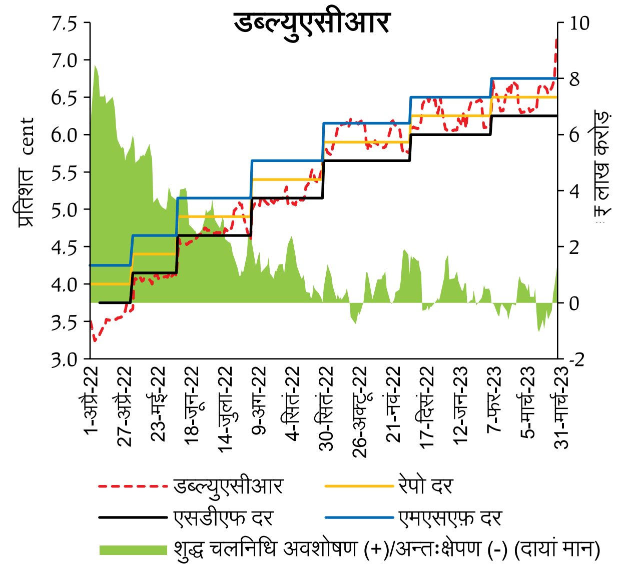

स्रोत: भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल); आरबीआई।

[1] 'ट्रेडेड डील' सीधे एनडीएस-कॉल प्लेटफॉर्म पर तय की जाती हैं, जबकि 'रिपोर्टेड डील' ओवर द काउंटर (ओटीसी) डील होती हैं, जो लेनदेनों की बातचीत पूरी होने के बाद एनडीएस-कॉल प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट की जाती हैं।

चार्ट IV.2: मांग मुद्रा बाजार में ट्रेडेड और रिपोर्टेड सौदे

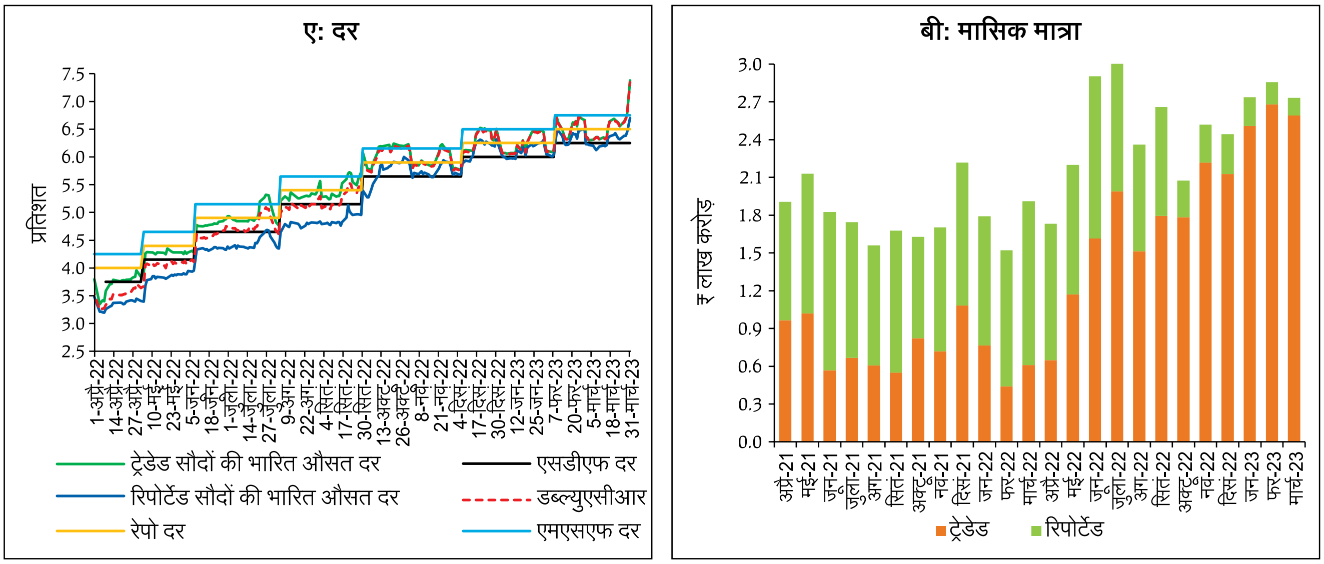

स्रोत: सीसीआईएल; आरबीआई।

छमाही में ट्रेड किए गए लेनदेनों की औसत मासिक मात्रा ₹2.32 लाख करोड़ थी, जो रिपोर्ट किए गए सेग्मेंट के ₹0.24 लाख करोड़ से उल्लेखनीय रूप से अधिक थी (चार्ट IV.2बी)। कुल मांग मुद्रा बाजार की मात्रा में रिपोर्ट किए गए लेनदेन की हिस्सेदारी सितंबर 2022 में 33 प्रतिशत से मार्च 2023 में घटकर 5 प्रतिशत हो गई, जो अन्य बातों के साथ-साथ एनडीएस- कॉल सदस्यता प्राप्त करने के लिए सभी पात्र मांग मुद्रा सहभागियों (सहकारी बैंकों सहित) को रिज़र्व बैंक के निर्देश नियमित बाजार घंटों की बहाली और चलनिधि की स्थितियों में सख्ती के कारण हुई थी।

मुद्रा बाजार के भीतर, संपार्श्विक खंड हावी रहे। दूसरी छमाही में कुल मुद्रा बाजार मात्रा में गैर-संपार्श्विक मांग मुद्रा बाजार की हिस्सेदारी 2 प्रतिशत थी। संपार्श्विकीकृत खंडों में, त्रिपक्षीय रेपो (टीआरईपीएस) की हिस्सेदारी एक साल पहले के 76 प्रतिशत से घटकर दूसरी छमाही में 71 प्रतिशत हो गई, जबकि बाजार रेपो 22 प्रतिशत से बढ़कर 27 प्रतिशत हो गई (चार्ट IV.3)। निवेशकों में, म्युचुअल फंड (एमएफ) - संपार्श्विक खंड में प्रमुख उधारदाताओं की हिस्सेदारी दूसरी छमाही में टीआरईपीएस खंड की पहली छमाही में 71 प्रतिशत से घटकर 67 प्रतिशत और बाजार रेपो में 45 प्रतिशत से 40 प्रतिशत हो गई और यह मुख्य रूप से डेट फंड के तहत कम प्रवाह के कारण हुआ। उधार लेने के पक्ष में, टीआरईपीएस और बाजार रेपो में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की हिस्सेदारी पहली छमाही में क्रमशः 65 प्रतिशत और 19 प्रतिशत से घटकर दूसरी छमाही में 61 प्रतिशत और 15 प्रतिशत हो गई।

लंबी अवधि के मुद्रा बाजार लिखतों - 3 महीने की टी-बिल (टीबी); जमा प्रमाणपत्र (सीडी); और वाणिज्यिक पत्र (सीपी) पर ब्याज दरें नीतिगत दर के अनुरूप बढ़ीं। दूसरी छमाही में टीबी का

चार्ट IV 3: ओवरनाईट मुद्रा बाज़ार मात्रा में शेयर

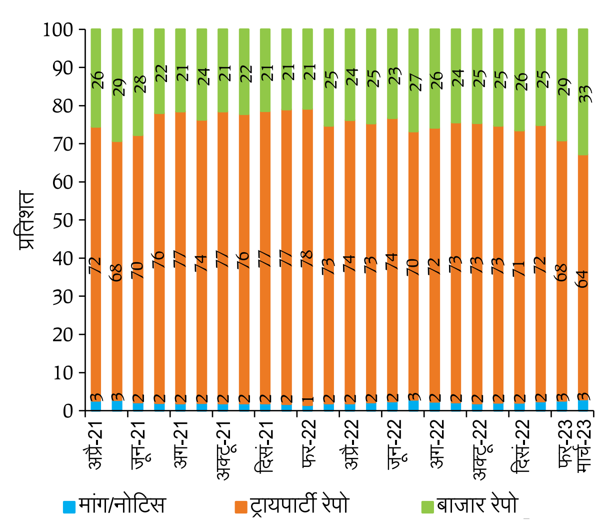

स्रोत: सीसीआईएल; आरबीआई।

चार्ट IV.4: मुद्रा बाज़ार दरें और जोखिम प्रीमियम

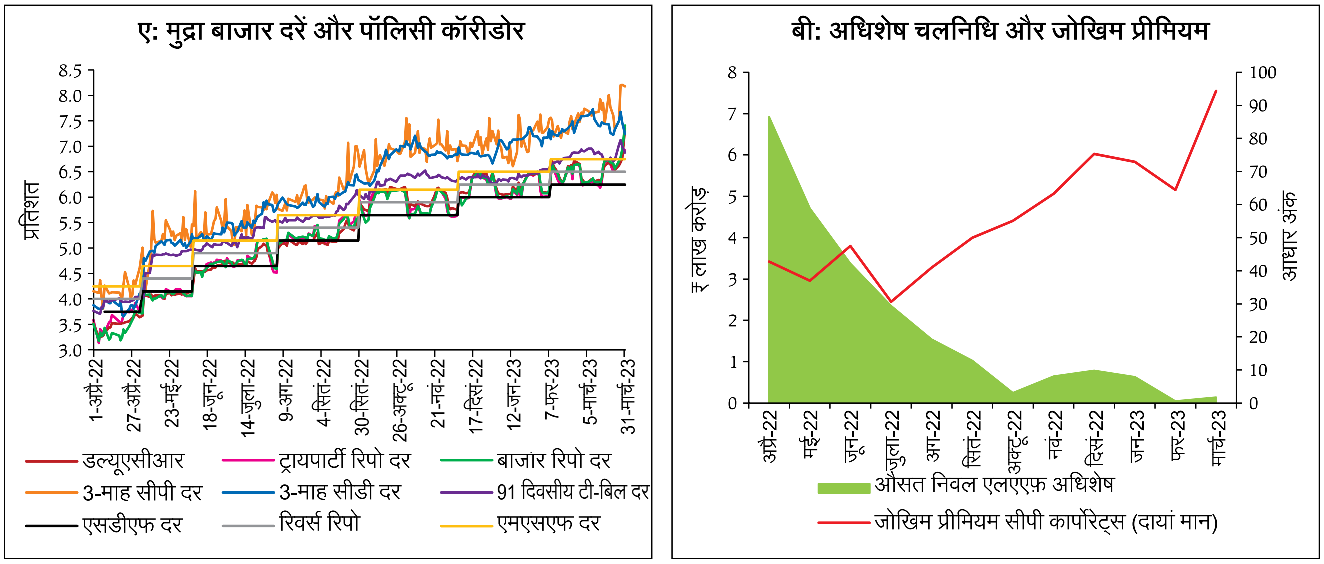

स्रोत: एफबीआईएल; आरबीआई; सीसीआईएल-एफ-ट्रैक; आरबीआई स्टाफ अनुमान।

स्प्रेड पॉलिसी रेपो दर से 30 आधार अंक अधिक रहा जो पहली छमाही में 25 आधार अंक से थोड़ी अधिक था जबकि सीडी और सीपी का स्प्रेड दूसरी छमाही में अधिशेष चलनिधि और बढ़ते जोखिम प्रीमियम[2] के घटने के कारण क्रमशः 46 आधार और 63 आधार अंक से बढ़कर क्रमशः 85 आधार अंक और 99 आधार अंक हो गया (चार्ट IV.4)।

दूसरी छमाही में ₹3.8 लाख करोड़ की सीडी (24 मार्च 2023 तक) जारी करने के साथ, पहली छमाही के ₹3.0 लाख करोड़ के के अलावा बैंकों ने वित्त पोषण के लिए सीडी पर आश्रित रहना जारी रखा। सीपी के माध्यम से जुटाया गया संसाधन पहली छमाही में ₹7.3 लाख करोड़ से घटकर दूसरी छमाही में ₹6.4 लाख करोड़ हो गया, जिससे बैंक क्रेडिट की प्राथमिकता का पता

चार्ट IV.5: वाणिज्यिक पत्र का प्राथमिक निर्गम

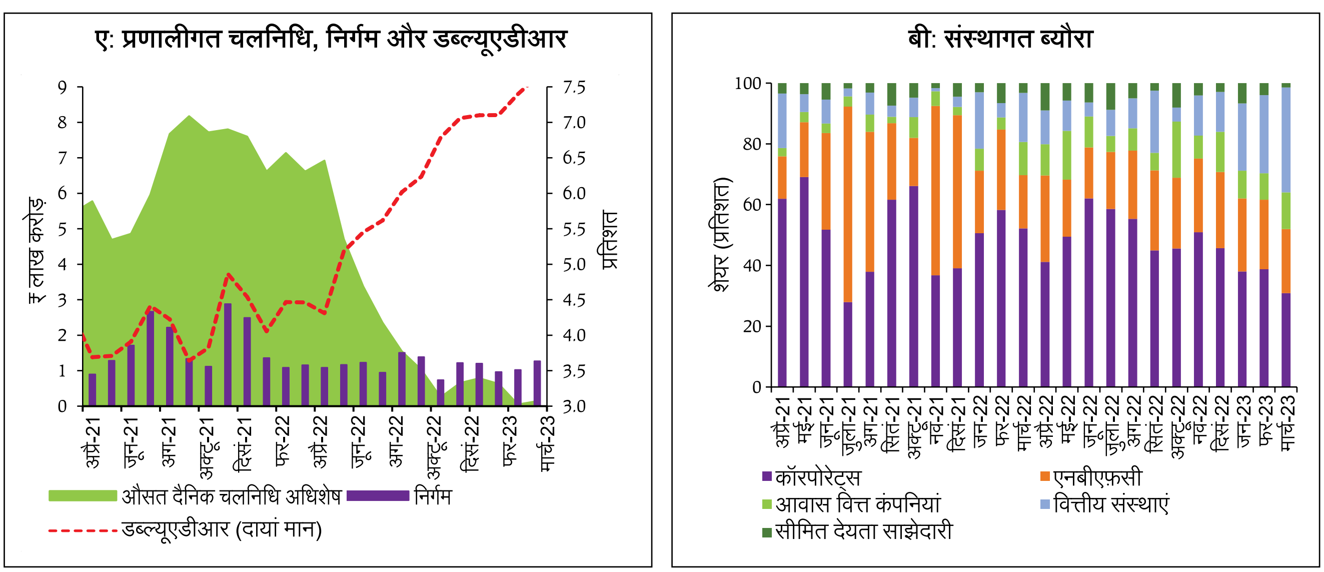

स्रोत: आरबीआई; सीसीआईएल; एफ-ट्रैक; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

2 91-दिवसीय टी-बिलों में 3एम सीपी-कॉरपोरेट का स्प्रेड।

सारणी IV.1: सीपी निर्गम की परिपक्वता प्रोफ़ाइल

(₹ लाख करोड़)

अवधि	छ2: 2021-22	छ1: 2022-23	छ2: 2022-23
7- 30 दिन	4.14	0.69	0.38
31-90 दिन	3.30	4.00	3.13
91-180 दिन	1.82	1.87	1.94
181-365 दिन	0.83	0.75	0.97
कुल	10.09	7.32	6.42
बकाया (अंत-अवधि के रूप में)	3.52	4.01	3.54

स्रोत: सीसीआईएल; एफ-ट्रैक; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चलता है। सीपी निर्गमन पर भारित औसत छूट दर (डब्ल्यूएडीआर) पहली छमाही में 5.53 प्रतिशत से दूसरी छमाही में 7.21 प्रतिशत तक पहुंच गई (चार्ट IV.5ए)। कॉरपोरेट्स सीपी के प्रमुख जारीकर्ता बने रहे, हालांकि उनकी हिस्सेदारी पहली छमाही में 52 प्रतिशत से घटकर दूसरी छमाही में 42 प्रतिशत हो गई (चार्ट IV.5बी)।

वर्ष 2022-23 की दूसरी छमाही में 49 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ 31-90 दिनों की परिपक्वता वाले खंड में सीपी निर्गमों का वर्चस्व बना रहा और यह एक साल पहले की तुलना में 33 प्रतिशत था (सारणी IV.1)।

IV.1.2 सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) बाजार

दूसरी छमाही के दौरान, जी-सेक प्रतिफल काफी हद तक एक दायरे में था (चार्ट IV.6)। सितंबर के लिए उम्मीद से अधिक घरेलू सीपीआई मुद्रास्फीति के अनुसरण में, अक्तूबर 2022 में प्रतिफल में वृद्धि हुई। उम्मीद से कम अमेरिकी सीपीआई प्रिंट और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के साथ अमेरिकी प्रतिफल में नरमी के लक्षण को देखते हुए नवंबर में प्रतिफलों में कमी हुई। समग्र रूप से, 10-वर्षीय बेंचमार्क प्रतिफल तीसरी तिमाही में 7 आधार अंक कम होकर 7.33 प्रतिशत रहा। चौथी तिमाही में 2023-24 के लिए केंद्र सरकार के प्रत्याशा से कम बाजार उधार कार्यक्रम के कारण फरवरी की शुरुआत में प्रतिफल में नरमी आई। बाद में उच्चतर घरेलू और अमेरिकी मुद्रास्फीति प्रिंट और मजबूत अमेरिकी आर्थिक डाटा के कारण प्रतिफल मजबूत हुए। मार्च में, प्रतिफल में नरमी आई और बैंक की विफलता के बाद अमेरिकी प्रतिफल के लक्षण को देखते हुए निवेशक सुरक्षित आस्तियों की ओर रुख कर गए। समग्र रूप से, मार्च 2023 के अंत तक 10 वर्ष का बेंचमार्क प्रतिफल 3 आधार अंक घटकर 7.31 प्रतिशत हो गया।

नीतिगत रेपो दर में वृद्धि और अधिशेष चलनिधि में कमी के साथ टी-बिल संबंधी प्रतिफल सभी अवधियों में बढ़ गए (चार्ट IV.7)।

वर्ष 2022-23 की दूसरी छमाही में जी-सेक ट्रेडिंग की मात्रा में वर्ष 2021-22 की उसी अवधि की तुलना में वृद्धि हुई जबकि समान अवधि के लिए टी-बिलों में गिरावट आई (चार्ट IV.8)। वर्ष 2021-22 की दूसरी छमाही में जी-सेक और टी-बिल्स के लिए ट्रेड की गई परिपक्वता पर भारित औसत प्रतिफल पिछले वर्ष की दूसरी छमाही में रहे स्तर से क्रमशः 107 आधार अंक और 293 आधार अंक बढ़ गए।

चार्ट IV.6: 10-वर्षीय सामान्य प्रतिफल रिपो दर और चलनिधि स्थितियाँ

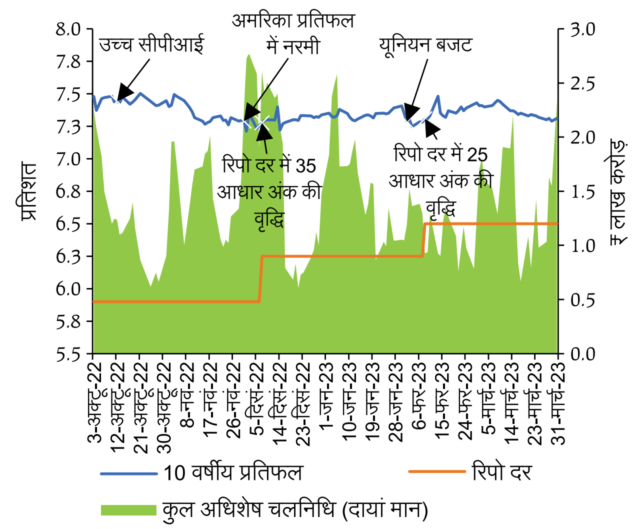

स्रोत: आरबीआई और एफबीआईएल।

चार्ट IV.7: एफबीआईएल: टी- बिल बेंचमार्क (परिपक्वता पर प्रतिफल)

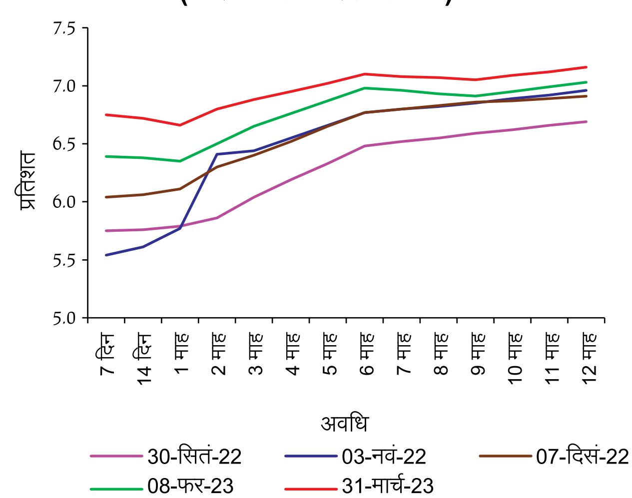

स्रोत: एफबीआईएल।

चार्ट IV.8: व्यापार मात्रा और प्रतिफल

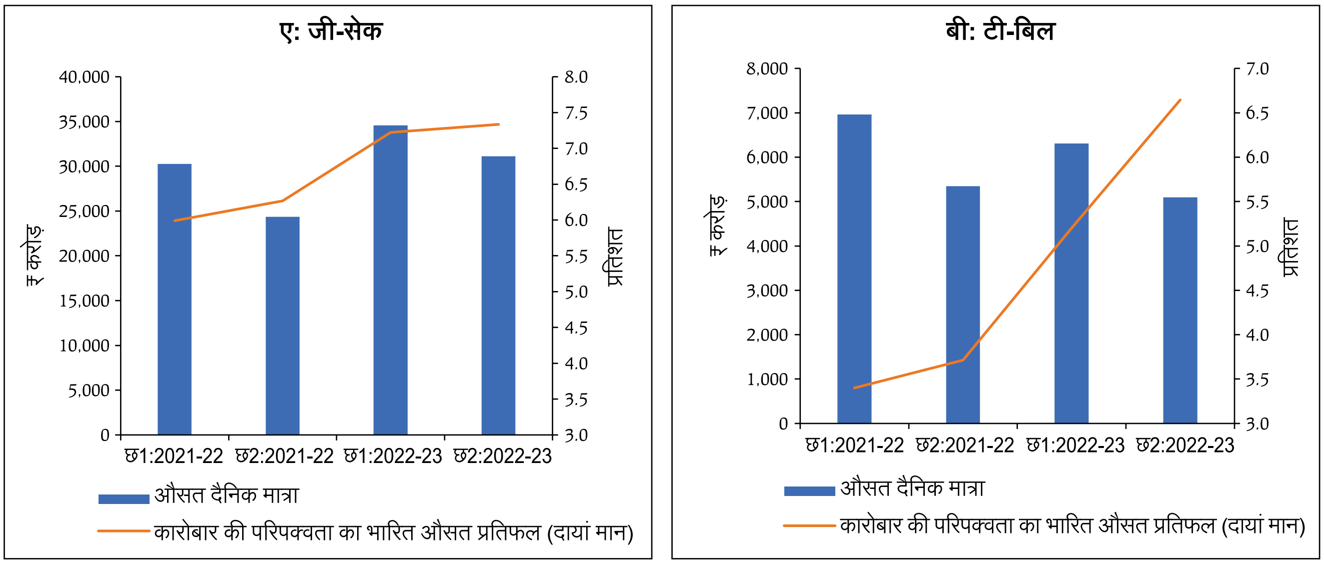

स्रोत: सीसीआईएल; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

प्रतिफल वक्र की समग्र गतिशीलता उसके लेवल, स्लोप और वक्रता द्वारा दर्ज की जाती है।[3] वर्ष 2022-23 की दूसरी छमाही में, प्रतिफल का औसत स्तर 11 आधार अंक तक नरम हो गया जबकि स्लोप 70 आधार अंक तक समतल हो गया, क्योंकि वैश्विक गतिविधियों को प्रतिबिंबित करते हुए, नीतिगत सख्ती के परिणामस्वरूप अल्पकालिक दरों में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हुई। लघु और दीर्घ खंडों की तुलना में वक्र के मध्य खंड में प्रतिफल कम मजबूत होने के कारण वक्रता में 66 आधार अंक की गिरावट हुई (चार्ट IV.9)। भारतीय संदर्भ में, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) के विपरीत, प्रतिफल वक्र की वक्रता और इसके स्तर में

चार्ट IV.9: जी-सेक प्रतिफल वक्र

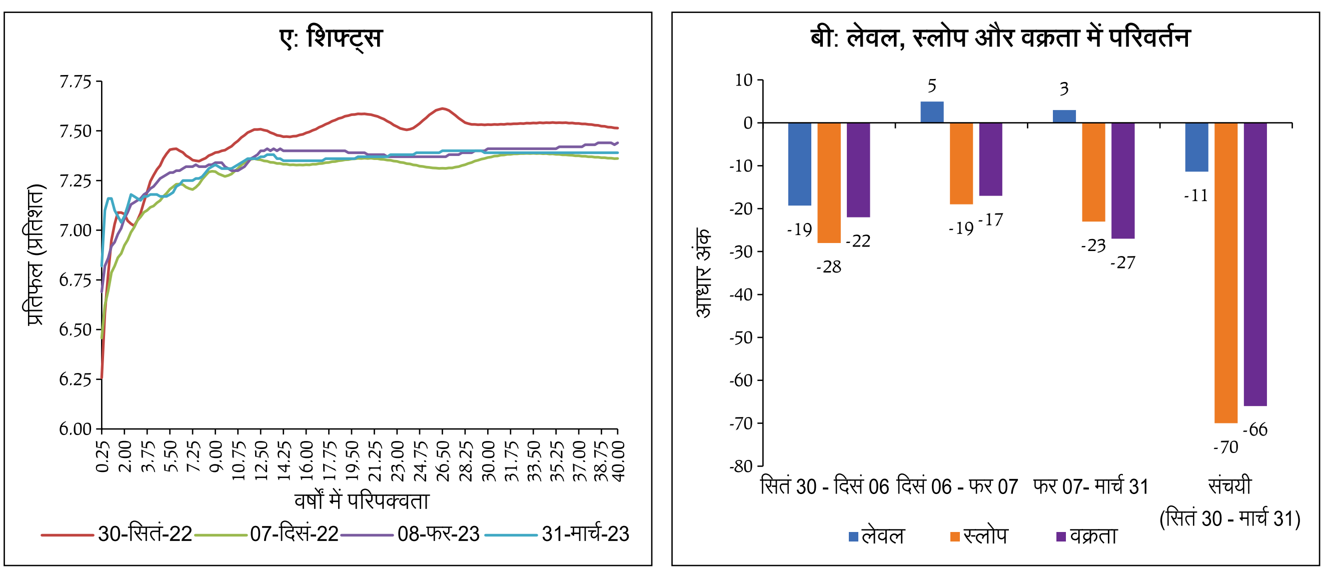

स्रोत: एफबीआईएल; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

[3] एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित 30-वर्ष तक की सभी अवधियों की सममूल्य प्रतिफल का औसत स्तर है और स्लोप (टर्म स्प्रेड) 3-महीने और 30-वर्ष की परिपक्वता अवधि के सममूल्य प्रतिफल में अंतर है। वक्रता की गणना 14-वर्षीय प्रतिफल के दूने में से 30 वर्ष और 03 महीने के कुल प्रतिफल को घटाकर की जाती है।

स्लोप की तुलना में भविष्य के समष्टि आर्थिक परिणामों में अधिक सूचना/जानकारी है।[4]

वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में घोषणा के अनुरूप, रिज़र्व बैंक ने 25 जनवरी और 9 फरवरी 2023 को ₹8,000 करोड़ की दो किश्तों में ₹16,000 करोड़ की राशि के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड (एस जीआरबीएस) जारी किए। इन लाभों का उपयोग पर्यावरण और/या जलवायु के अनुकूल नई और/या मौजूदा परियोजनाओं के वित्तपोषण या पुनर्वित्त के लिए किया जाएगा।

ऋण समेकन की सुविधा के लिए, रिज़र्व बैंक ने दूसरी छमाही में केंद्र सरकार की ओर से ₹49,387 करोड़ की पांच स्विच नीलामी की। दूसरी छमाही में 11.94 वर्षों पर जी-सेक के बकाया स्टॉक की भारित औसत परिपक्वता (डब्ल्यूएएम) सितंबर 2022 के अंत में 11.96 वर्षों के समान थी। मार्च 2023 के अंत में भारित औसत कूपन (डब्ल्यूएसी) 7.26 प्रतिशत रहा जो सितंबर 2022 के अंत के 7.15 प्रतिशत की तुलना में अधिक था।

तुलनीय परिपक्वता की जी-सेक प्रतिफल की तुलना में राज्य सरकार की प्रतिभूतियों (एसजीएस) पर कट-ऑफ प्रतिफल का भारित औसत स्प्रेड दूसरी छमाही में 30 आधार अंक था (चार्ट IV.10)। 10-वर्ष की अवधि (नए निर्गम) की प्रतिभूतियों पर औसत अंतर-राज्य स्प्रेड दूसरी छमाही में 4 आधार अंक था।

चार्ट IV.10: एसजीएस – जुटाई गई राशि और स्प्रेड

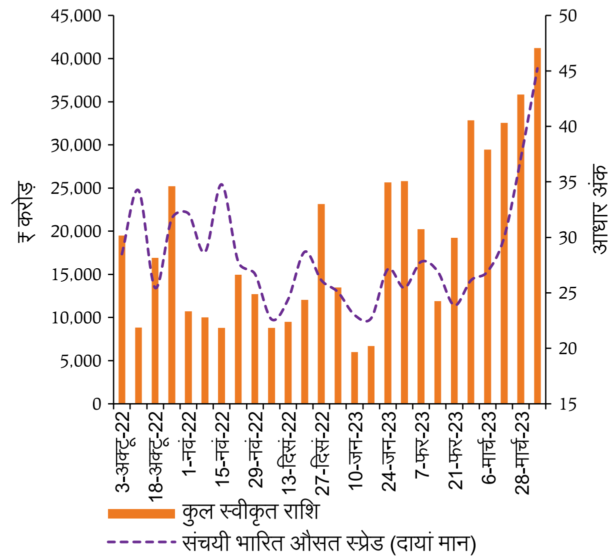

स्रोत: आरबीआई।

IV.3 कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट

जी-सेक प्रतिफल के साथ कॉर्पोरेट बॉन्ड प्रतिफल और स्प्रेड दूसरी छमाही में उच्चतर स्तर पर पहुंच गया। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और कॉरपोरेट्स द्वारा जारी एएए-रेटेड 3 - वर्षीय बॉन्ड पर औसत प्रतिफल मार्च 2023 में सितंबर 2022 की तुलना में क्रमशः 57 आधार अंक (8.12 प्रतिशत) और 49 आधार अंक (8.07 प्रतिशत) बढ़ गया। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू), वित्तीय संस्थानों (एफआई) और बैंकों के निर्गमों पर औसत प्रतिफल 46 आधार अंक से बढ़कर 7.75 प्रतिशत हो गया (चार्ट IV.11ए)। एनबीएफसी के लिए जोखिम प्रीमियम (3 वर्ष के जी-सेक प्रतिफल के स्प्रेड से मापा गया) 42 आधार अंक से बढ़कर 73 आधार अंक हो गया, कॉरपोरेट्स के लिए 45 आधार अंक से 68 आधार अंक और दूसरी छमाही में पीएसयू, एफआई और बैंकों के लिए 15 आधार अंक से 36 आधार अंक हो गया (चार्ट IV.11बी)।

सभी अवधियों (हालांकि छोटे खंडों में अधिक) के दौरान और रेटिंग स्पेक्ट्रम में जोखिम प्रीमिया में वृद्धि देखी गई (सारणी IV.2)। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के विदेशों में पेपर ट्रेडिंग के लिए 3 साल के औसत क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप (सीडीएस) स्प्रेड में तीन आधार अंकों की कमी आई है, जबकि आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों में पहली छमाही की तुलना में दूसरी छमाही में चार आधार अंकों की कमी आई है।

प्राथमिक बाजार में कॉर्पोरेट बॉन्ड निर्गम 2021-22 की इसी अवधि के दौरान 2.5 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर दूसरी छमाही (फरवरी 2023 तक) के दौरान 3.9 लाख करोड़ रुपये हो गए, जिससे विदेशी निर्गमों में 2021-22 की दूसरी छमाही में 0.5 लाख करोड़ रुपये से घटकर 2022-23 की दूसरी छमाही में 0.1 लाख करोड़ रुपये होने की कमी की भरपाई हुई(चार्ट IV.12ए)। ऋण मांग में वृद्धि से प्रेरित होकर बैंकों द्वारा अपनी तेजी से बढ़ती बैलेंस शीट के लिए पूंजी जुटाने के लिए बॉन्ड बाजार का उपयोग किया गया (चार्ट IV.12बी)। कॉरपोरेट बॉन्ड

[4] पात्रा, एम.डी., जॉइस, जे., कुशवाहा, के.एम., और आई. भट्टाचार्य (2022), "यील्ड कर्व हमें अर्थव्यवस्था के बारे में क्या बता रहा है?", भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन, जून।

चार्ट IV.11: एएए- मूल्यांकित 3-वर्षीय कॉर्पोरेट बॉन्ड प्रतिफल और स्प्रेड

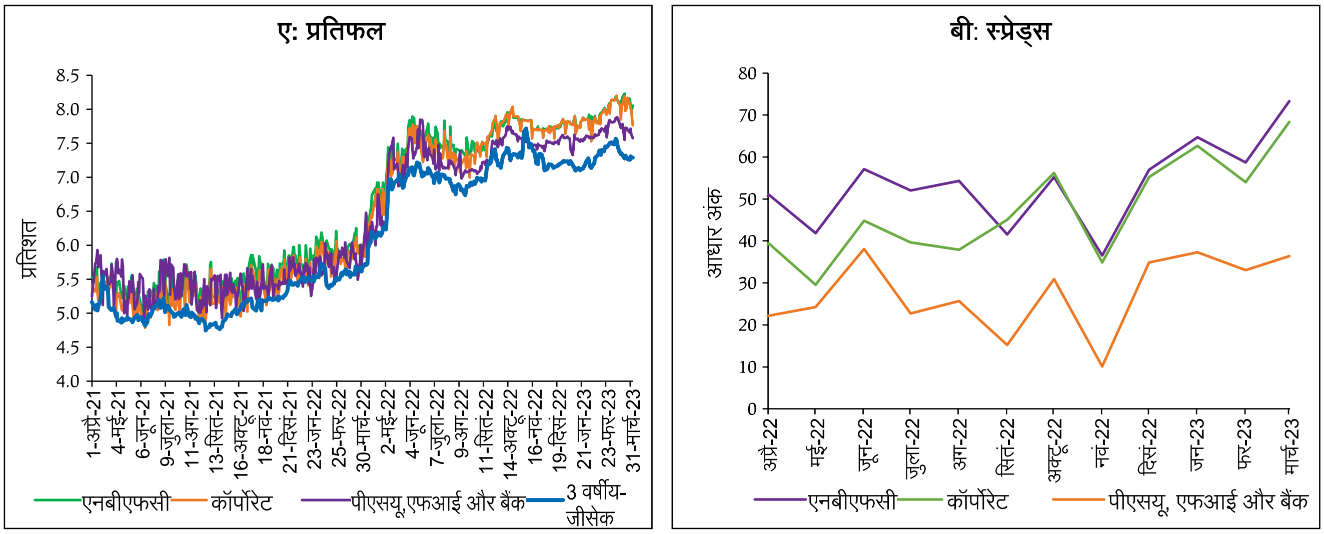

टिप्पणी: डेटा जी-सेक में स्प्रेड के लिए मासिक औसत हैं।
स्रोत: फिक्स इन्कम मनी मार्केट एण्ड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया (फिम्डा)।

बाजार (98.7 प्रतिशत) में लगभग संपूर्ण संसाधन निजी नियोजन के माध्यम से जुटाए गए। कॉरपोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा बकाया निवेश सितंबर 2022 के अंत में 1.14 लाख करोड़ रुपये से मामूली रूप से घटकर मार्च 2023 के अंत तक 1.04 लाख करोड़ रुपये रह गया, जिससे अनुमोदित सीमाओं का उपयोग 17.9 प्रतिशत से घटकर 15.5 प्रतिशत हो गया (चार्ट IV.12सी)। दूसरी छमाही (फरवरी 2023 तक) के दौरान

सारणी IV.2: वित्तीय बाज़ार - दरें और स्प्रेड

लिखत	ब्याज़ दरें (प्रतिशत)			बीपीएस में स्प्रेड (संबंधित जोखिम-रहित दर से अधिक)		
	मार्च 2022	सितंबर 2022	मार्च 2023	मार्च 2022	सितंबर 2022	मार्च 2023
1	2	3	4	5	6	7
कॉर्पोरेट बॉण्डस						
(i) एएए (1-वर्षीय)	5.03	6.87	8.08	28	12	66
(ii) एएए (3-वर्षीय)	5.86	7.58	8.07	25	45	68
(iii) एएए (5-वर्षीय)	6.43	7.54	8.00	-1	23	57
(iv) एए (3-वर्षीय)	6.57	8.33	8.77	96	120	139
(v) बीबीबी- माइनस (3-वर्षीय)	10.24	11.99	12.42	463	486	504

टिप्पणी: यील्ड और स्प्रेड मासिक औसत हैं।
स्रोत: एफआईएमएमडीए (फिम्डा)।

दैनिक द्वितीयक बाजार में औसत व्यापार की मात्रा ₹ 5,332 करोड़ थी, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 7.7 प्रतिशत अधिक थी (चार्ट IV.12डी)।

IV.4 इक्विटी बाजार

दूसरी छमाही में, घरेलू इक्विटि बाजारों की शुरुआत एफपीआई की मजबूत लिवाली और मजबूत कॉर्पोरेट आय, के बीच सकारात्मक रुख के साथ हुई। 01 दिसंबर 2022 को बेंचमार्क बीएसई सूचकांक 63,284 अंक के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। 2022-23 की चौथी तिमाही के आरंभ में श्रम बाजार की तंगी के बीच अमेरिकी फेडरल रिज़र्व के बढ़ते टर्मिनल दर अनुमानों से बाजार का रुख मंद हो गया। मार्च 2023 में अमेरिका और यूरोप में बैंकिंग उथल-पुथल के कारण घरेलू इक्विटी दबाव में रही। बीएसई बैंकिंग इंडेक्स (बैंकेक्स), हालांकि, मार्च 2023 में 0.9 प्रतिशत बढ़ा, जबकि यूएस और यूरोपीय बैंकिंग बेंचमार्क में क्रमशः 25.2 प्रतिशत और 13.8 प्रतिशत की गिरावट आई थी।[5] कुल मिलाकर, बीएसई सेंसेक्स दूसरी छमाही में 2.7 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च, 2023 को 58,992 पर बंद

[5] अमेरिका के लिए केबीडब्ल्यू सूचकांक और यूरो क्षेत्र के लिए यूरो स्टोक्स बैंकिंग इंडेक्स (एसएक्स 7 ई)।

चार्ट IV.12: कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार गतिविधि

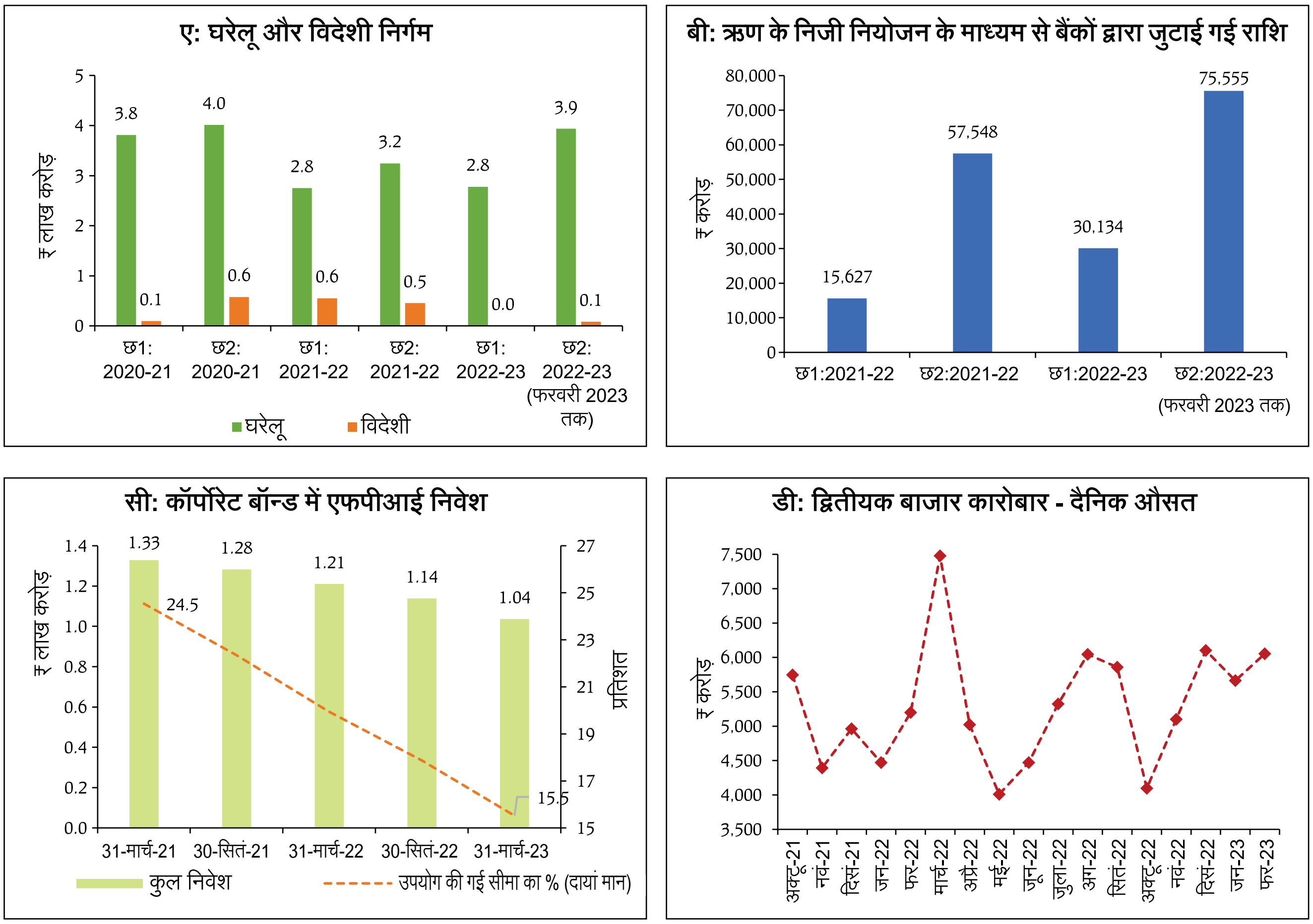

स्रोत: सेबी और प्राइम डेटाबेस।

हुआ। उथल-पुथल के संक्षिप्त चरणों को छोड़कर, इक्विटी बाजार में अस्थिरता नीचे की ओर बढ़ी, इंडिया वीआईएक्स - जो निफ्टी 50 की अल्पकालिक अपेक्षित अस्थिरता को कैप्चर करता है - सितंबर 2022 के अंत में 20 से घटकर मार्च 2023 के अंत में 12.9 हो गया (चार्ट IV.13ए)। अधिकांश ईएमई की तुलना में भारतीय इक्विटी बाजार 2022-23 में आघात-सहनीय बना हुआ है (चार्ट IV.13बी)।

उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में दूसरी छमाही के दौरान एफपीआई प्रवाह में उछाल आया(चार्ट IV.14ए) । भारत में, विदेशी निवेशक नवंबर 2022 में घरेलू इक्विटी बाजार में निवल खरीदार थे, जो मजबूत आय से आकर्षित हुए। हालांकि, अमेरिकी फेडरल रिज़र्व द्वारा मौद्रिक नीति में और सख्ती किए जाने की प्रत्याशा और एक बड़े भारतीय कारोबारी समूह के शेयरों में बिकवाली के कारण दिसंबर-फरवरी में विदेशी निवेशक निवल विक्रेता बन गए। विदेशी निवेशक मार्च में निवल खरीदार बन गए। दूसरी ओर, घरेलू संस्थागत निवेशक (डीआईआई) व्यवस्थित निवेश योजना (एसआईपी) के माध्यम से स्थिर खुदरा सहभागिता के बीच निवल खरीदार थे, जिससे बाजार आघात-सह बना रहा। एफपीआई और डीआईआई दूसरी छमाही में क्रमश: 25,027

चार्ट IV.13: शेयर बाजार का कार्यनिष्पादन

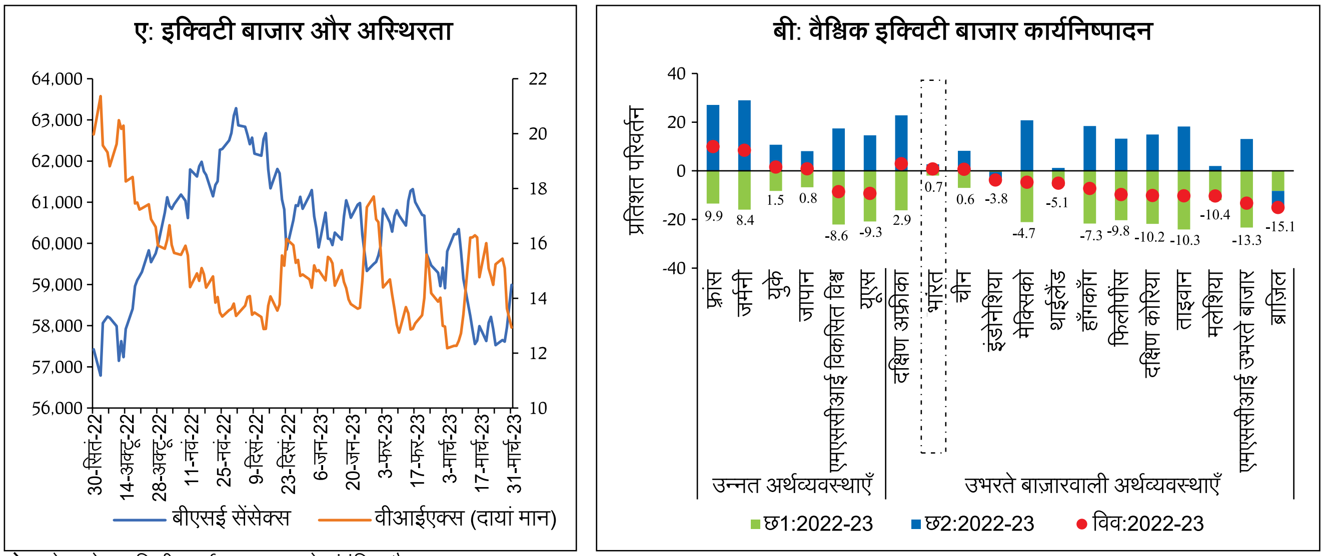

नोट: डेटा लेवल वित्तीय वर्ष 2022-23 से संबंधित है।

स्रोत: ब्लूमबर्ग।

करोड़ रुपये और 1.10 लाख करोड़ रुपये के शुद्ध खरीदार रहे (चार्ट IV.14 बी)। दूसरी छमाही में घरेलू प्राथमिक बाजार में गतिविधि कमजोर रही, जारीकर्ताओं ने अस्थिर बाजार स्थितियों के बीच अपने आईपीओ पर पुनर्विचार किया(चार्ट IV.14सी)।

चार्ट IV.14: भारत में ईएमई प्रवाह, संस्थागत निवेश और आईपीओ निर्गम

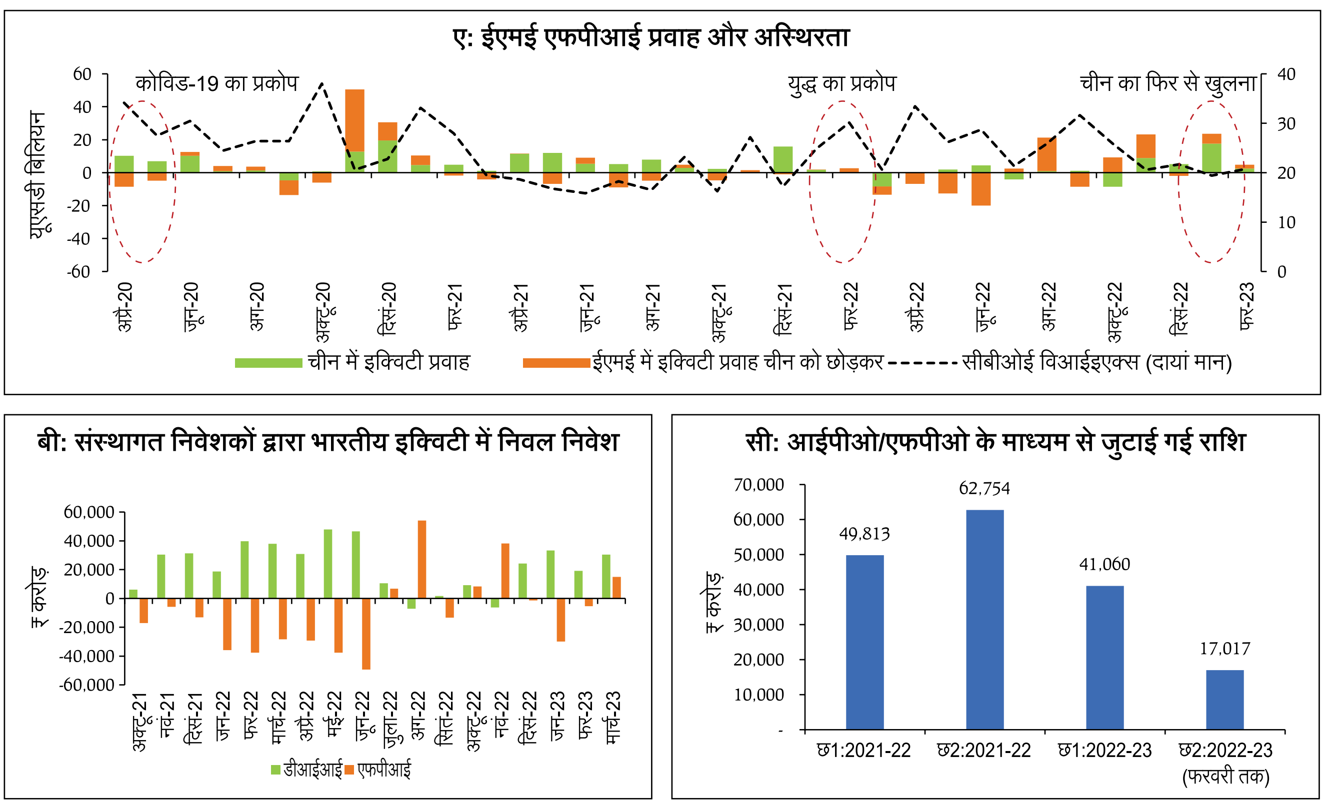

स्रोत: ब्लूमबर्ग; केपीटैलिन; एनएसडीएल; और सेबी।

चार्ट IV.15: भारतीय रुपया और अस्थिरता

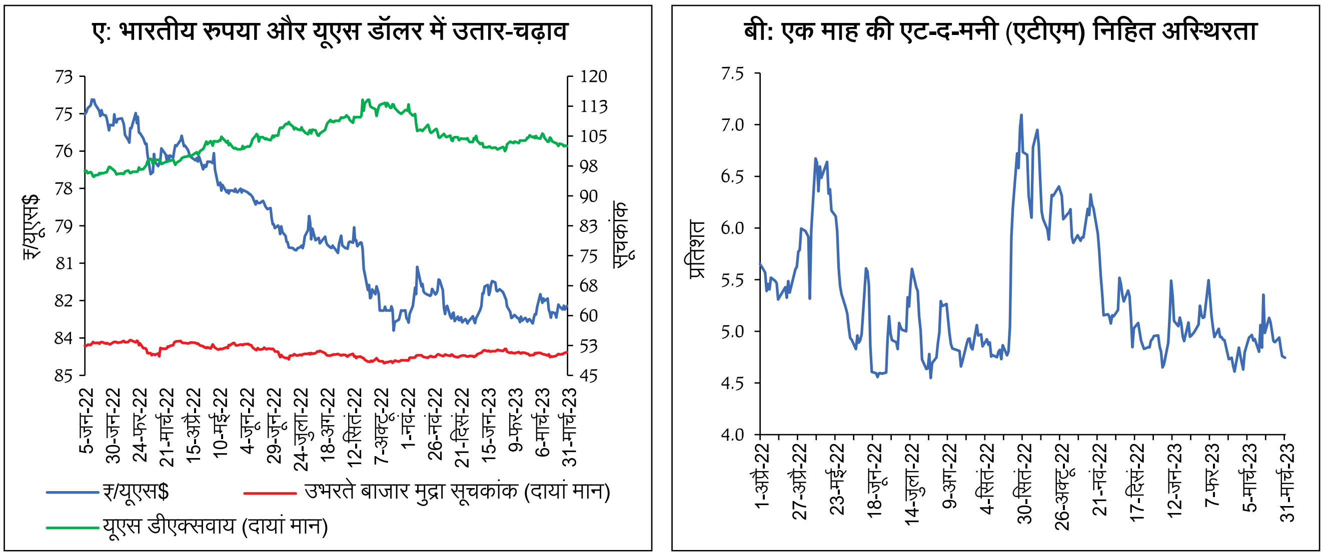

स्रोत: एफ़बीआईएल, रिफ़िनेटिव ईकोन और ब्लूमबर्ग।

IV.1.5. विदेशी मुद्रा बाजार

यूएस फेड द्वारा आक्रामक दर वृद्धि और उसके आक्रामक रुख के परिणामस्वरूप अमेरिकी डॉलर की मूल्यवृद्धि के कारण दूसरी छमाही में ईएमई मुद्राओं पर मूल्यह्रास का दबाव पड़ा (चार्ट IV.15ए)। इन वैश्विक प्रसार प्रभावों के कारण भारतीय रुपया 20 अक्टूबर 2022 को 83.2 प्रति अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गया। अमेरिकी डॉलर में गिरावट और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के माध्यम से निवल प्रवाह के कारण नवंबर 2022 में इसमें सुधार हुआ। तब से, यह काफी हद तक निर्धारित सीमा के भीतर बना हुआ है। भारतीय रुपए में अस्थिरता- जिसे एक-माह एट द मनी (एटीएम) विकल्प में निहित अस्थिरता से मापी जाती है- दूसरी छमाही के दौरान बढ़कर 5.33 प्रतिशत हो गई, जो पहली छमाही के दौरान 5.29 प्रतिशत थी (चार्ट IV.15बी)।

वित्तीय वर्ष के आधार पर, 2022-23 के दौरान भारतीय रुपए का प्रदर्शन अर्जेंटीन पेसो, दक्षिण अफ्रीकी रैंड और तुर्की लीरा सहित प्रमुख ईएमई मुद्राओं से बेहतर रहा (चार्ट IV.16)।

40-मुद्रा सांकेतिक और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर के संदर्भ में, सितंबर 2022 (औसत) और मार्च 2023 अंत तक के

चार्ट IV.16: मुद्रा का वैश्विक उतार- चढ़ाव

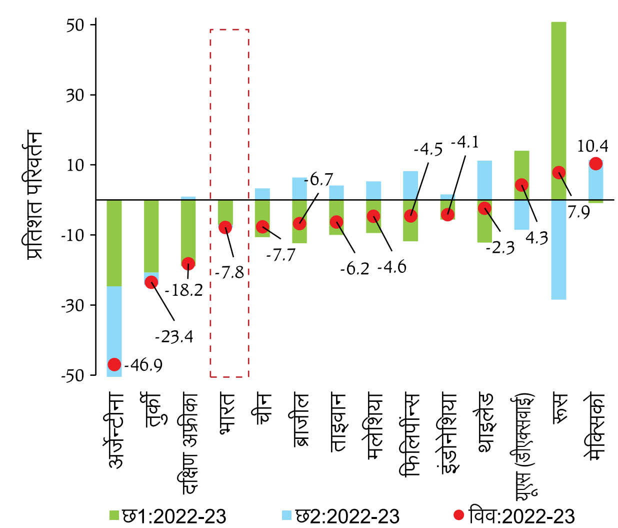

स्रोत: आईएमएफ; ब्लूमबर्ग; और रिफाइनिटिव ईकॉन।

सारणी IV.3: सांकेतिक तथा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक – (व्यापार भारित)
(आधार: 2015-16=100)

मद	सूचकांक : मार्च 31, 2023 (पी)	वृद्धि (+) / कमी (-) (प्रतिशत)
		सितंबर (औसत) 2022 की तुलना में मार्च 31, 2023
40-करेंसी आरईईआर	99.7	-5.0
40-करेंसी एनईईआर	89.0	-4.2
6- करेंसी आरईईआर	98.3	-6.4
6- करेंसी एनईईआर	82.8	-6.2
₹/यूएस $*	82.2	-2.4

पी: अनंतिम।
स्रोत: आरबीआई; और एफबीआईएल।

बीच रुपये में क्रमशः 4.2 प्रतिशत और 5.0 प्रतिशत की गिरावट आई (सारणी IV.3)।)

दूसरी छमाही के दौरान फॉरवर्ड प्रीमियम में गिरावट आई और 1 महीने का फॉरवर्ड प्रीमियम दूसरी छमाही के दौरान घटकर औसतन 2.39 प्रतिशत रह गया, जो पहली छमाही के दौरान 3.38 प्रतिशत था (चार्ट IV.17)।

IV.1.6 ऋण बाजार

आर्थिक गतिविधियों के साथ-साथ 2022-23 की दूसरी छमाही में बैंक ऋण संवृद्धि मजबूत रही। गैर-खाद्य बैंक ऋण में

चार्ट IV.17: फॉरवर्ड प्रीमियम में उतार-चढ़ाव

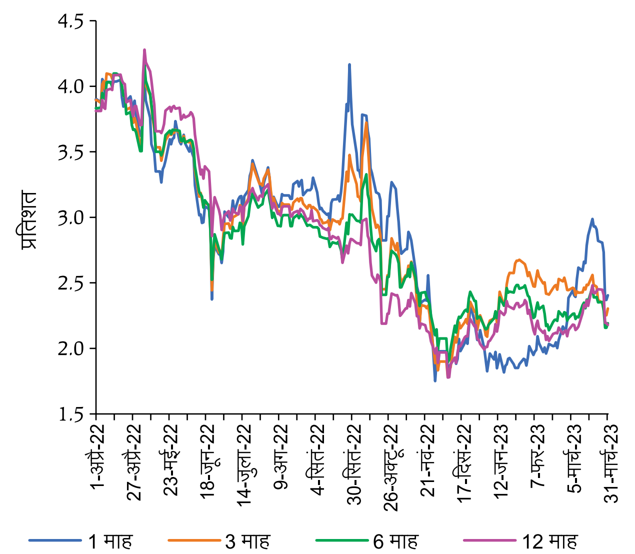

स्रोत: ब्लूमबर्ग।

वृद्धि मार्च 2023 के अंत तक बढ़कर 15.4 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) हो गई, जो मार्च 2022 में 9.7 प्रतिशत थी (चार्ट IV.18)। कुल जमाराशियों से अधिक ऋण वृद्धि होने के कारण वृद्धिशील ऋण जमा अनुपात 100 प्रतिशत से ऊपर था, जिससे उच्च ऋण वृद्धि की संवहनीयता पर सवाल उठे (बॉक्स IV.1)।

जहां समग्र रूप से ऋण वृद्धि में तेजी आई, लेकिन पीएसबी (13.7 प्रतिशत) की तुलना में निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) (18.4 प्रतिशत) के लिए यह अधिक रही (चार्ट IV.19ए)। हालांकि, 2022-23 में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा दिए गए वृद्धिशील ऋण के प्रमुख प्रेरक पीएसबी थे (चार्ट IV.19बी)।

ऋण उठाव में वैयक्तिक ऋण और सेवा क्षेत्र अग्रणी रहे[6]। वृद्धिशील ऋण उठाव में वैयक्तिक ऋण की हिस्सेदारी पिछले वर्ष

चार्ट IV.18: एससीबी की गैर-खाद्य ऋण संवृद्धि

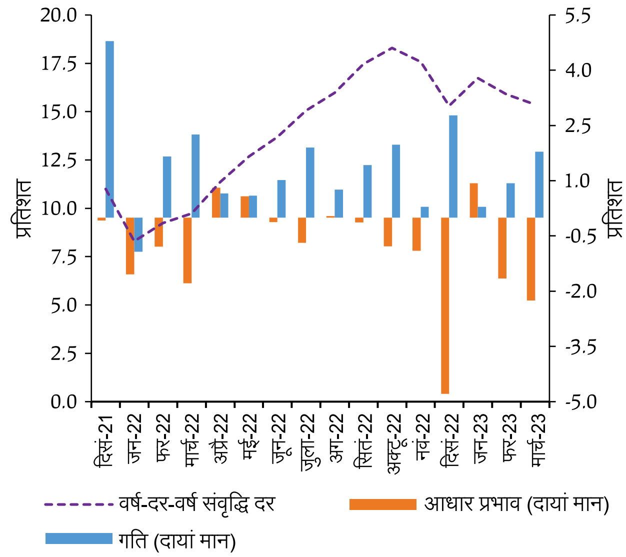

स्रोत: आरबीआई।

6 यद्यपि समग्र बैंक ऋण और गैर-खाद्य ऋण डेटा धारा -42 रिटर्न (जो सभी एससीबी को कवर करता है) पर आधारित हैं, क्षेत्रीय गैर-खाद्य ऋण डेटा क्षेत्र-वार और उद्योग-वार बैंक ऋण (एसआईबीसी) रिटर्न पर आधारित हैं, जो सभी एससीबी द्वारा दिए गए कुल गैर-खाद्य ऋण का लगभग 93 प्रतिशत हिस्सा रखने वाले चुनिंदा बैंकों को कवर करता है।

बॉक्स IV.1: क्या वर्तमान ऋण वृद्धि उच्च स्तर पर है?

बैंक ऋण में वृद्धि आर्थिक गतिविधियों में उतार-चढ़ाव, गैर-बैंक निधीयन की उपलब्धता और लागत, बैंक निधीयन की सापेक्ष लागत, बैंकिंग क्षेत्र की हालत और जोखिम लेने की उनकी क्षमता जैसे कारकों को दर्शाती है। 2022-23 के दौरान, बैंक ऋण में वृद्धि, महामारी-पूर्व वर्ष (2019-20) और महामारी चरण (2020-21 और 2021-22) के दौरान रही कमजोर प्रोफ़ाइल से बड़े पैमाने पर एक चक्रीय वापसी थी। यद्यपि, जमा वृद्धि 2022-23 में क्रेडिट वृद्धि से पीछे थी, तथापि पिछले दो वर्षों में यह स्थिति विपरीत थी, जो संपर्क-गहन सेवाओं पर कम खर्च के कारण उच्च बचत को दर्शाती है। हाल ही में, उच्चतर जमा दरों से आंशिक बल पाकर, जमा वृद्धि में तेजी आई है।

अप्रैल 2007-दिसंबर 2022 की अवधि के लिए सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के मासिक ऋण और जमाओं के आँकड़ों के अर्थमितीय विश्लेषण से पता चलता है कि बैंक जमाओं और ऋण को एकीकृत किया जाता है, यानी, वे समय के साथ-साथ चलते हैं[7]। जमाओं के संबंध में ऋण की दीर्घकालिक लोच 0.94 है, जो सह-गतिशीलता के इस उच्च स्तर को प्रमाणित करती है। त्रुटि सुधार गुणांक (-) 0.08 है (और -3.94 के जेड-सांख्यिकी के साथ अत्यधिक सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है), जो इंगित करता है कि ऋण और जमा वृद्धि के बीच किसी भी विचलन का लगभग 8 प्रतिशत हर महीने समाप्त हो जाता है। 2022-23 में बैंक ऋण में उछाल के बावजूद, ऋण-जीडीपी (क्रेडिट-टू-जीडीपी) अंतर ऋणात्मक बना हुआ है (चार्ट IV.1.1)। कुल मिलाकर, ऋण वृद्धि आर्थिक गतिविधियों में सुधार से प्रेरित है और जमा वृद्धि में सुधार द्वारा समर्थित है।

दीर्घकालिक समीकरण: $Log\ Credit = 0.819 + 0.94\ Log\ Deposit$
(29.1)

नोट: कोष्ठक में आंकड़े जेड-सांख्यिकी हैं।

चार्ट IV.1.1: जमा और ऋण गतिशीलता

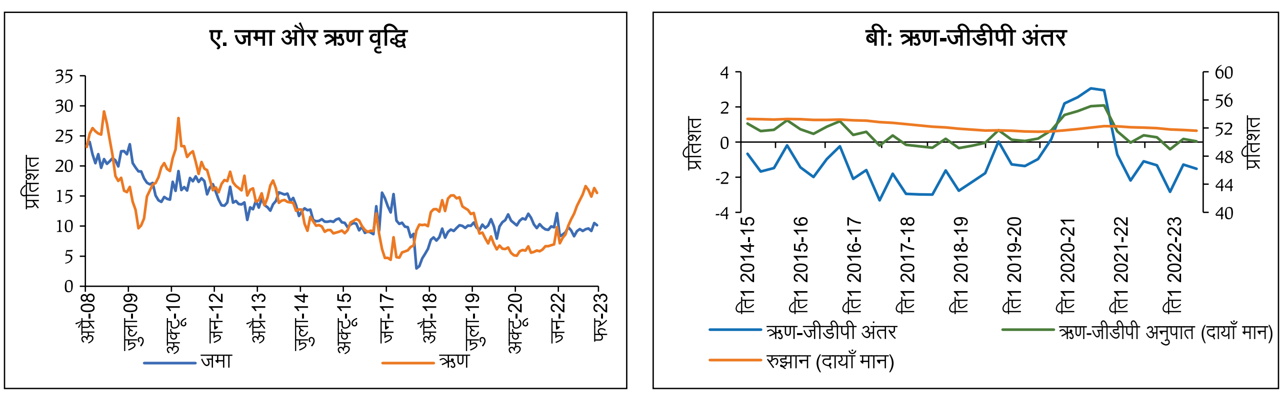

स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान

की तुलना में कम हो गई जबकि फरवरी 2023 में सेवा क्षेत्र का हिस्सा लगभग दोगुना हो गया (चार्ट IV.20)।

क्षेत्रवार देखा जाए तो फरवरी 2023 में कृषि ऋण की वृद्धि दर बढ़कर 14.9 प्रतिशत वर्ष-दर-वर्ष हो गई, जो एक साल पहले 10.3 प्रतिशत थी। फरवरी 2023 में उद्योगों को प्रदत्त बैंक ऋण में 7.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि एक साल पहले यह 6.7 प्रतिशत थी, जो बड़े उद्योगों, विशेष रूप से धातु, पेट्रोलियम और रासायनिक उद्योगों के कारण हुई। दूरसंचार क्षेत्र को प्रदत्त ऋण में गिरावट के कारण बुनियादी ढांचा क्षेत्र में ऋण वृद्धि में गिरावट आई है। मार्च 2023 तक बढ़ा दी गई आपातकालीन ऋण शृंखला गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) से बल पाकर, एमएसएमई की ऋण वृद्धि उत्साहजनक बनी रही। (चार्ट IV.21)।

[7] वेक्टर त्रुटि सुधार मॉडल में अकाइके सूचना मानदंड (एआईसी) के आधार पर आठ अंतराल शामिल हैं। जोहानसन का परीक्षण एक एकीकृत वेक्टर की उपस्थिति की पुष्टि करता है। रिग्रेशन डायग्नोस्टिक्स संतोषजनक है। अल्पकालिक समीकरण के लिए R2 0.70 है। अवशिष्ट में ऑटोकोरिलेशन के लिए लैग्रेंज गुणक (एलएम) परीक्षण लैग 12 तक कोई ऑटोकोरिलेशन की पुष्टि नहीं करता है।

चार्ट IV.19: बैंक समूहों में ऋण प्रवाह

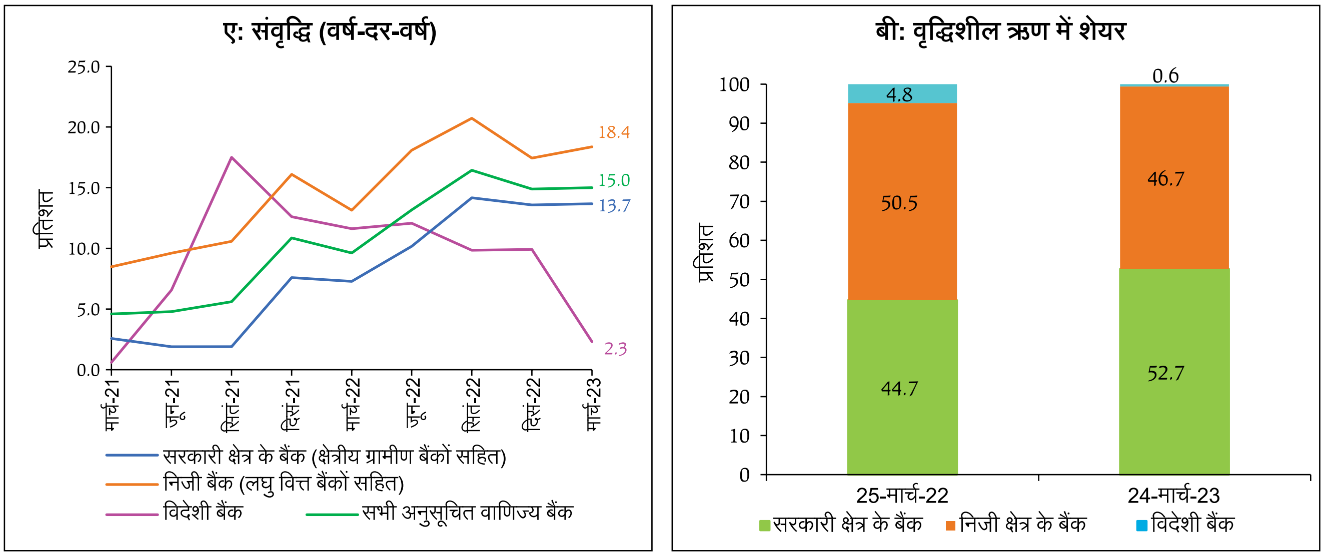

स्रोत: आरबीआई।

दूसरी छमाही में सेवा क्षेत्र के ऋण में और तेजी आई है, जो एनबीएफसी, आवास वित्त कंपनियों और अन्य एनबीएफसी दोनों में प्रवाह से प्रेरित है। थोक और खुदरा व्यापार को एमएसएमई श्रेणी के तहत शामिल करने और सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के तहत ऋण तक आसान पहुंच के साथ, दूसरी छमाही के दौरान व्यापार क्षेत्र के ऋण में तेजी से वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट IV.22)।

थोड़ी मंदी के बावजूद, 2022-23 में कुल ऋण वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) में खुदरा ऋण प्रमुख योगदानकर्ता बने रहे। आवास क्षेत्र

चार्ट IV.20: बैंक ऋण का क्षेत्रगत परिनियोजन

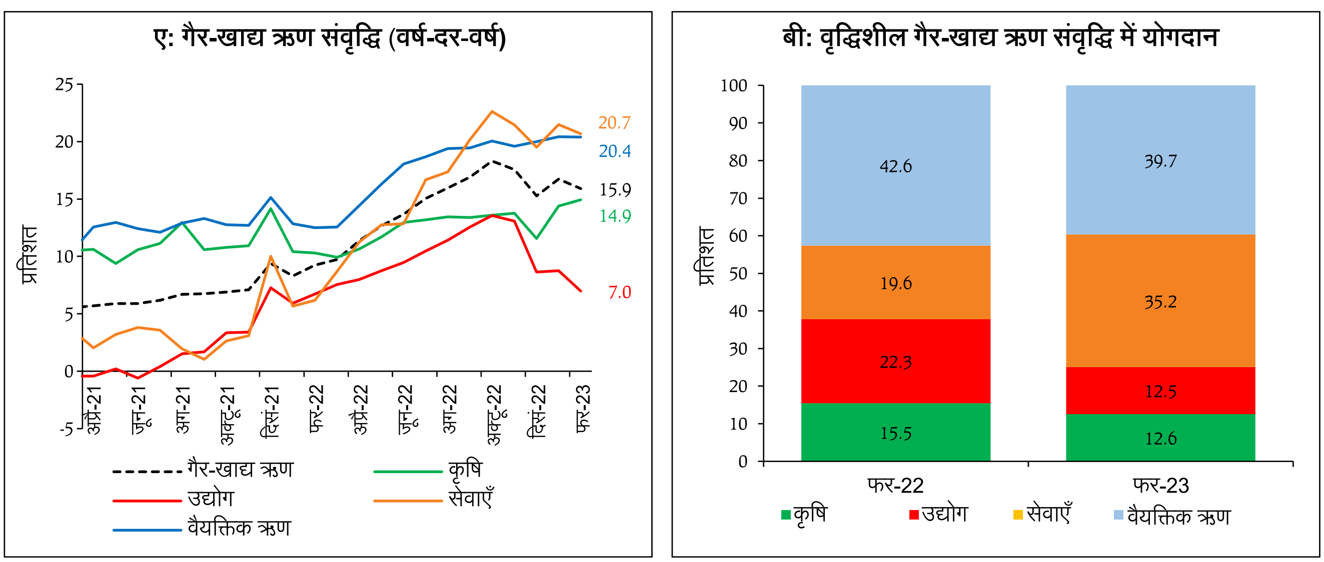

स्रोत: आरबीआई।

चार्ट IV.21: उद्योग क्षेत्र में बैंक ऋण-आकार-वार और प्रकार-वार

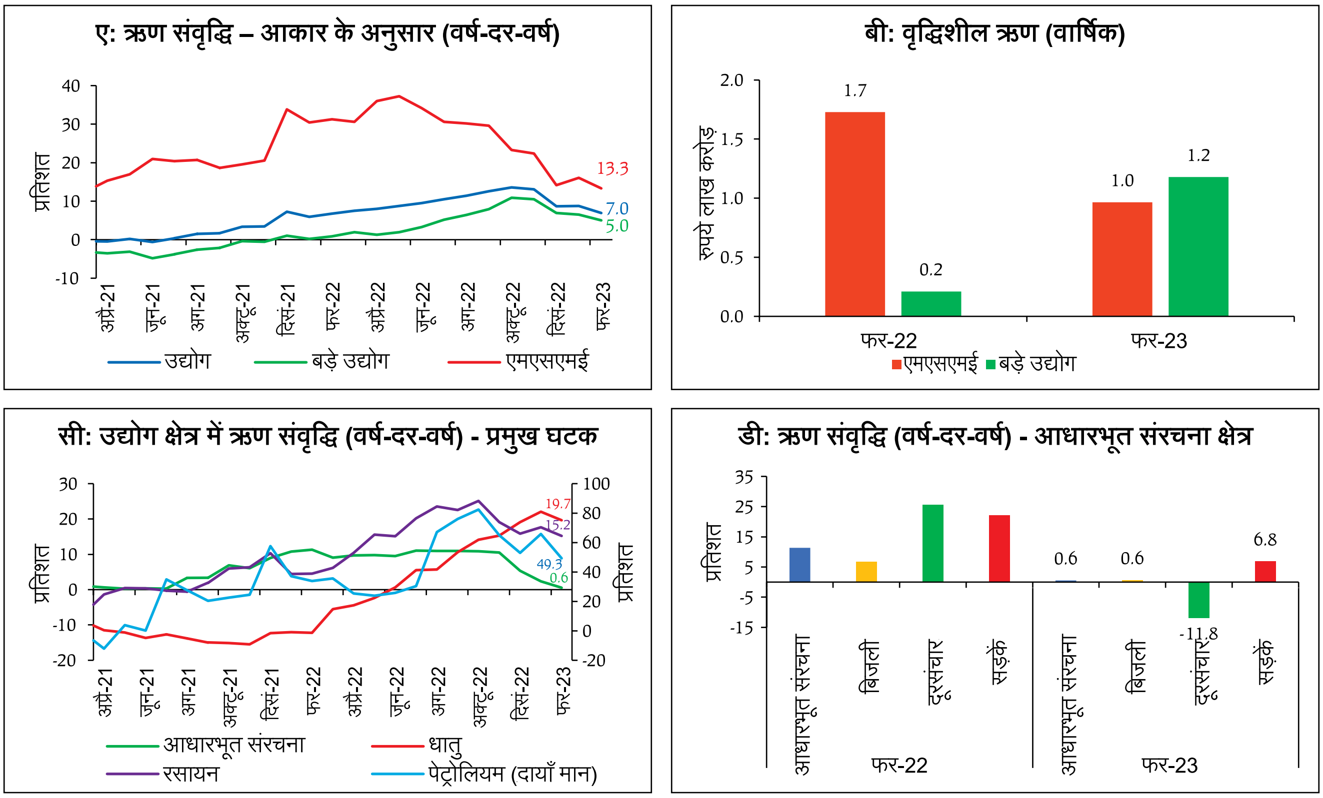

स्रोत: आरबीआई।

के ऋण में लगातार विस्तार दर्ज किया गया, जबकि वाहन ऋण वृद्धि और मजबूत हुई। पूरे 2022-23 में क्रेडिट कार्ड ऋण वृद्धि उच्च दोहरे अंकों में थी, जो खपत की दबी हुई मांग को दर्शाती है (चार्ट IV.23)।

चार्ट IV.22: सेवा क्षेत्र में ऋण संवृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष)

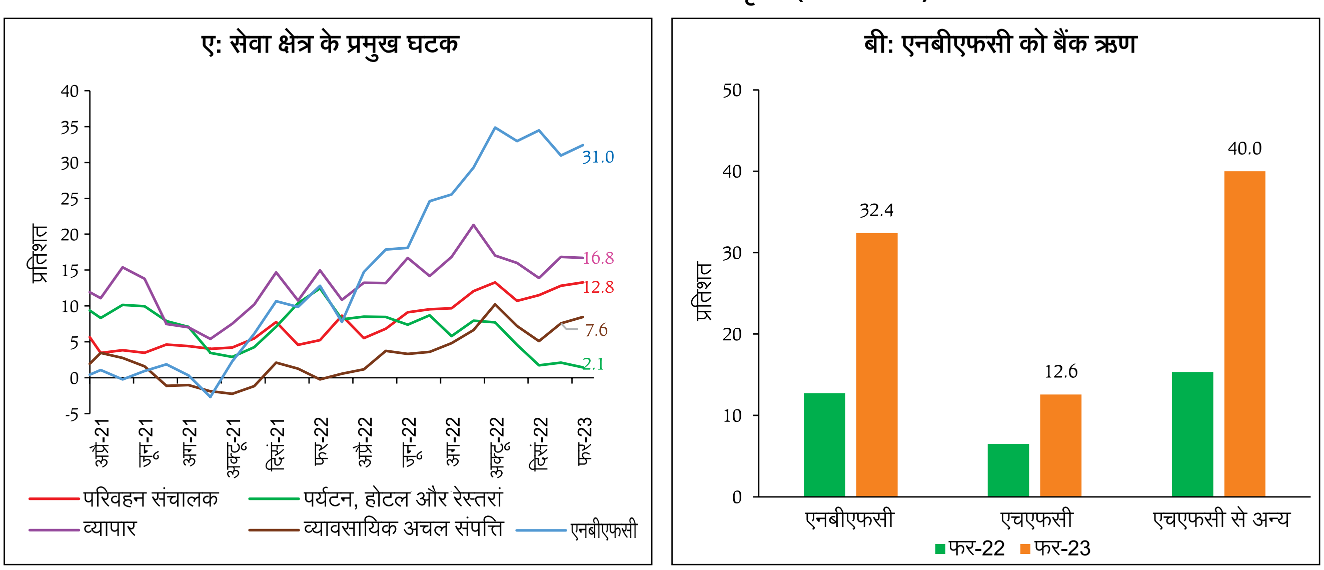

स्रोत: आरबीआई।

चार्ट IV.23: निजी ऋण में ऋण संवृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष)

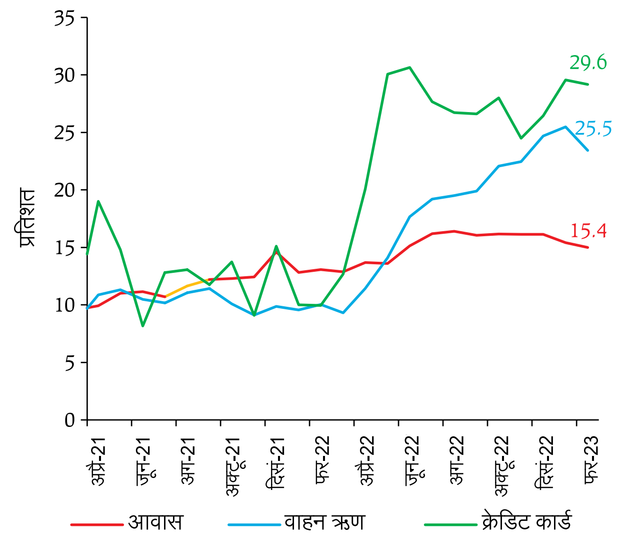

स्रोत: आरबीआई।

एससीबी की आस्ति गुणवत्ता में 2022-23 के दौरान सुधार हुआ, जिसमें समग्र गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) का अनुपात एक वर्ष पहले के 6.5 प्रतिशत से घटकर दिसंबर 2022 में 4.5 प्रतिशत रह गया (चार्ट IV.24ए)। इसी अवधि में सभी प्रमुख क्षेत्रों में आस्तियों की गुणवत्ता में सुधार हुआ (चार्ट IV.24बी)।

बैंकों के गैर-एसएलआर निवेश - यानी, सीपी, बॉन्ड, डिबेंचर और सार्वजनिक तथा निजी कंपनियों के शेयरों में निवेश - एक साल पहले की तुलना में दूसरी छमाही के दौरान कम थे, क्योंकि बैंकों ने ऋण और अग्रिम के माध्यम से वाणिज्यिक क्षेत्र का समर्थन करना पसंद किया (चार्ट IV.25ए)। समायोजित गैर-खाद्य ऋण (यानी, गैर-खाद्य बैंक ऋण और गैर-एसएलआर निवेश को मिलाकर) में वृद्धि, एक साल पहले के **9.1** प्रतिशत से बढ़कर, **मार्च 2023 में 13.9** प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) हो गई, जो थी, जो गैर-खाद्य ऋण से प्रेरित थी (चार्ट IV.25बी)।

बैंकों द्वारा सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) प्रतिभूतियों की अतिरिक्त होल्डिंग कम होकर 24 फरवरी, 2023 को रही उनकी निवल मांग और मियादी देनदारियों (एनडीटीएल) का 8.5 प्रतिशत रह गई, जो मार्च 2022 के अंत में 10.4 प्रतिशत थी क्योंकि बैंकों ने अतिरिक्त निवेश को कम करके ऋण मांग को वित्त पोषित किया (चार्ट IV.26)। अतिरिक्त एसएलआर होल्डिंग्स एलएएफ के तहत धन प्राप्त करने के लिए बैंकों को संपार्श्विक सुरक्षा प्रदान करती हैं और चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) का एक घटक भी हैं।

IV.2 मौद्रिक नीति संचरण

2022-23 की दूसरी छमाही में बैंकों की जमा और उधार दरों में नीतिगत रेपो दर के संचरण की गति बढ़ी है, जो ऋणों के

चार्ट IV.24: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की दबावग्रस्त आस्तियां और अनर्जक आस्तियां

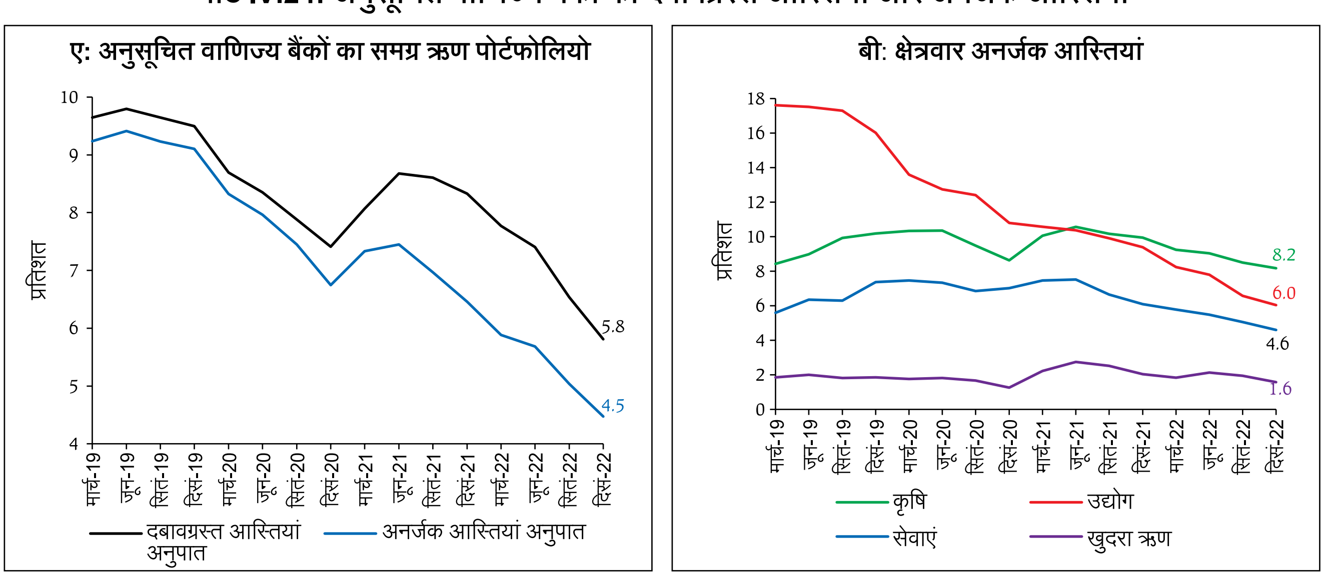

स्रोत: आरबीआई।

चार्ट IV.25: गैर- एसएलआर निवेश और समायोजित गैर–खाद्य ऋण

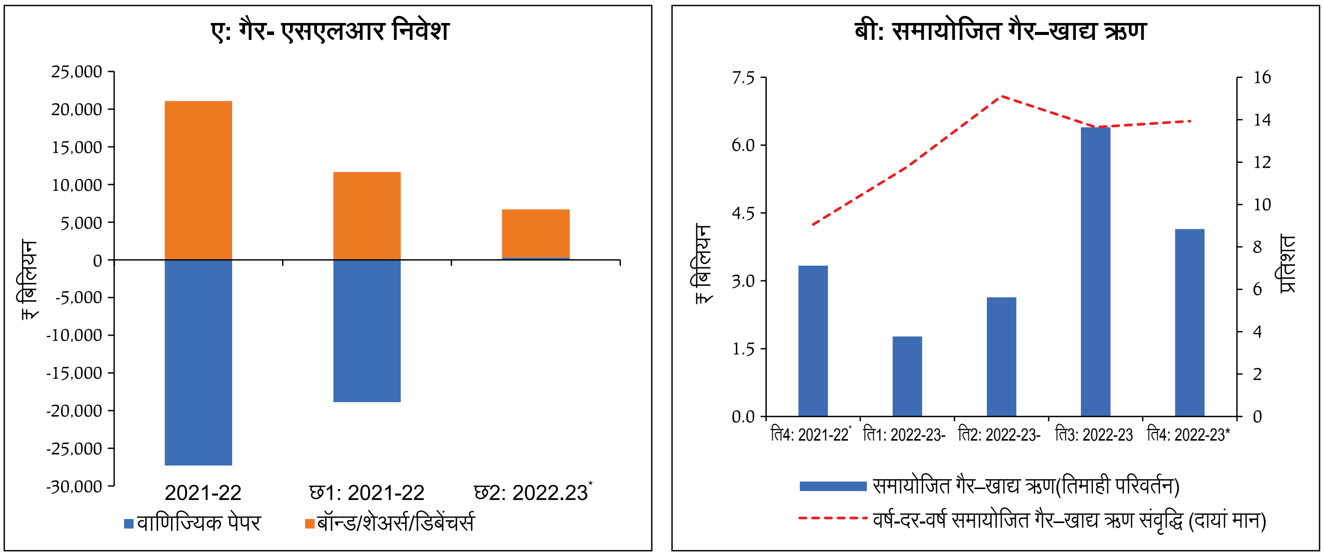

स्रोत: आरबीआई।

लिए बाहरी बेंचमार्क व्यवस्था, बैंकिंग प्रणाली में अधिशेष चलनिधि में कमी और जमा वृद्धि से ऊपर बनी हुई ऋण वृद्धि के संयुक्त प्रभाव को दर्शाती है। बैंकों ने मई 2022-मार्च 2023 के दौरान अपनी बाहरी बेंचमार्क-आधारित उधार दरों (ईबीएलआर) को 250 आधार अंकों तक संशोधित किया, जो नीतिगत रेपो दर में वृद्धि के अनुरूप है। इसी अवधि में निधि की सीमांत लागत आधारित उधार दरों (एमसीएलआर) में 140 आधार अंको की बढ़ोतरी हुई। मई 2022 से फरवरी 2023 के दौरान स्वीकृत नए रुपया ऋणों पर भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएएलआर) में 173 आधार अंकों की वृद्धि हुई और बकाया रुपया ऋणों पर 95 आधार अंकों की वृद्धि हुई (सारणी IV.4)।

चार्ट IV.26: बैंकों का अतिरिक्त सांविधिक चलनिधि अनुपात

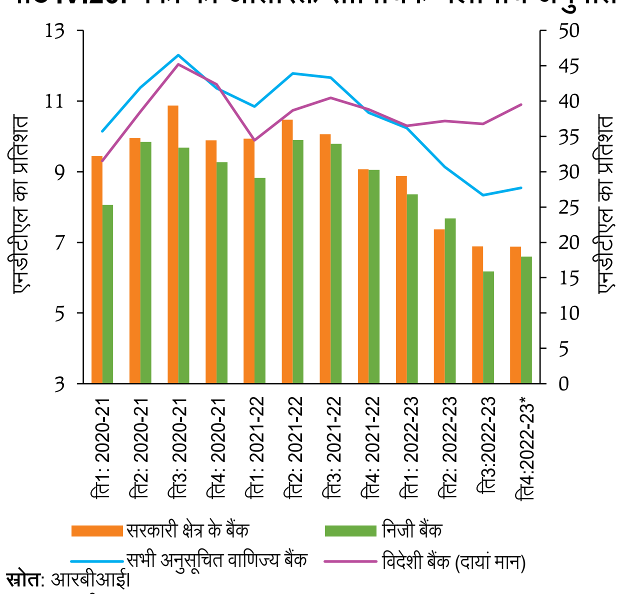

स्रोत: आरबीआई।
*: 24 फरवरी 2023 तक

बाह्य बेंचमार्क से जुड़े ऋण अब अस्थिर दर वाले बकाया ऋणों पर हावी हो गए हैं, जिसमें इसकी कुल हिस्सेदारी मार्च 2022 में 44.0 प्रतिशत से बढ़कर दिसंबर 2022 में 48.3 प्रतिशत हो गई है। तदनुसार, इस अवधि में, एमसीएलआर से जुड़े ऋणों का हिस्सा 48.6 प्रतिशत से घटकर 46.1 प्रतिशत हो गया है (सारणी IV.5)। ईबीएलआर ऋणों के भीतर, आरबीआई की रेपो दर प्राथमिक बेंचमार्क है, जिसमें दिसंबर 2022 के अंत में सभी ईबीएलआर से सम्बद्ध ऋणों का हिस्सा 81 प्रतिशत रहा। अल्पतर पुनःनिर्धारित अवधि के रेपो से जुड़े ऋणों के हिस्से में उल्लेखनीय वृद्धि ने बकाया ऋणों के डब्ल्यूएएलआर में संचरण की गति को समर्थन दिया।

समस्त घरेलू बैंकों में, मई 2022 से फरवरी 2023 के दौरान निजी बैंकों की तुलना में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामले

सारणी IV.4: रेपो दर से बैंकों की जमा और उधार दरों में संचरण

(आधार अंकों में परिवर्तन)

अवधि	रेपो दर	मियादी जमा दरें			उधार दरें			
		डब्ल्यूएडीटीडीआर (नयी जमाराशियां)	डब्ल्यूएडीटीडीआर (नयी जमाराशियां)	डब्ल्यूएडीटीडीआर (बकाया जमाराशियां)	ईबीएलआर	1-वर्षीय एमसी एलआर (माध्यिका)	डब्ल्यूएएलआर (नए रुपए ऋण)	डब्ल्यूएएलआर (बकाया रुपए ऋण)
		खुदरा जमा	खुदरा और थोक जमा					
फरवरी –2019 – मार्च 2022	-250	-209	-259	-188	-250	-155	-232	-150
मई 2022 से फरवरी/मार्च 2023*	250	170	222	99	250	140	173	95
मेमो:								
अप्रैल 2022	0	0	-9	0	0	0	-12	-2
मई-जून 2022	90	10	58	10	90	25	40	20
जुलाई-सितंबर 2022	100	38	70	26	50	36	68	30
अक्टूबर-दिसंबर 2022	35	105	85	39	85	45	29	30
जनवरी -मार्च 2023*	25	17	9	24	25	35	36	15

टिप्पणी: 1. डब्लूएएलआर: भारित औसत उधार दर; डब्लूएडीटीआर : भारित औसत घरेलू मियादी जमा दर; ईबीएलआर: बाहरी बेंचमार्क-आधारित उधार दर; एमसीएलआर: निधि-आधारित उधार दर की सीमांत लागत।
2. ईबीएलआर पर डेटा 31 घरेलू बैंकों से संबंधित हैं।
*: डब्लूएएलआर और डब्लूएडीटीआर पर अद्यतन डाटा फरवरी 2023 से संबंधित है।
स्रोत: आरबीआई।

में नए रुपया ऋणों पर डब्ल्यूएएलआर में वृद्धि अधिक हो गई थी (चार्ट IV.27ए)। पीवीबी की उधार दरें पीएसबी की तुलना में अधिक रहीं (चार्ट IV.27बी)। विदेशी बैंकों के मामले में उधार और जमा दरों में संचरण अधिकतम था, जो उनकी कुल देनदारियों में कम लागत और कम अवधि के थोक जमाओं के उच्च हिस्से को दर्शाता है, जिससे ब्याज दरों में तेजी से समायोजन करने की सुविधा मिलती है।

सारणी IV.5: ब्याज दर बेंचमार्क पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया फ्लोटिंग दर रुपया ऋण

(कुल का प्रतिशत)

	मार्च 2020	मार्च 2021	मार्च 2022	दिसंबर 2022
आधार दर व्यवस्था	10.3	6.4	4.9	3.4
एमसीएलआर व्यवस्था	78.3	62.3	48.6	46.1
बाहरी बेंचमार्क व्यवस्था	9.1	29.5	44.0	48.3
अन्य	2.3	1.8	2.5	2.2

टिप्पणी: डेटा 74 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित हैं।
स्रोत:आरबीआई।

चार्ट IV.27: उधार और जमा दरों के लिए बैंक समूह-वार संचरण

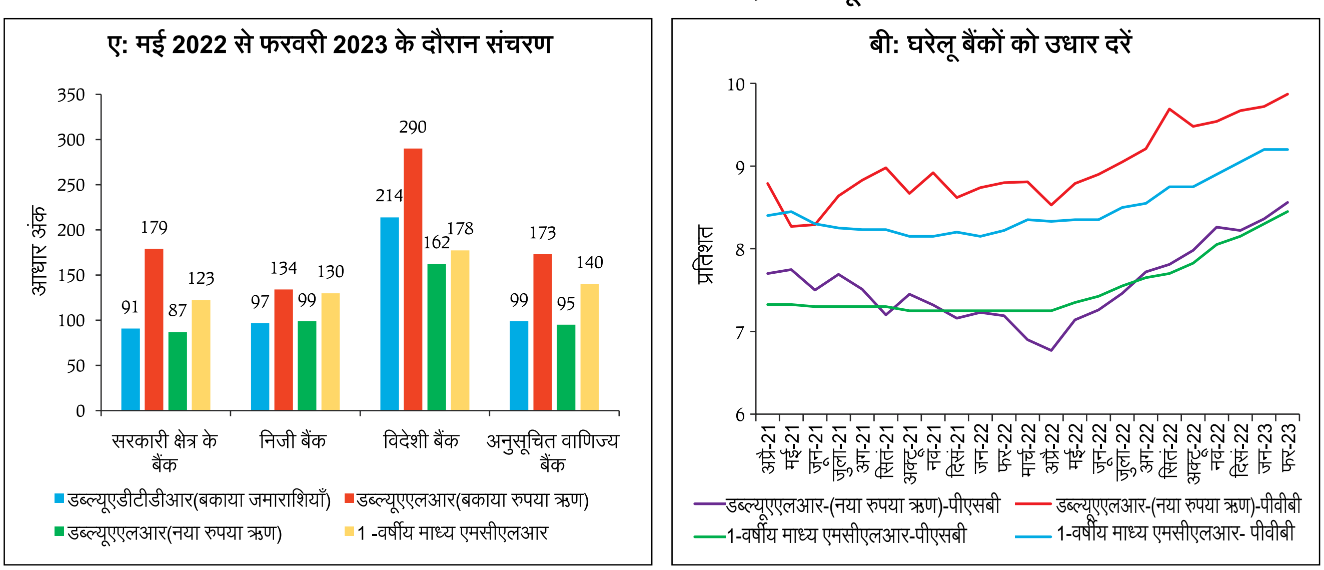

स्रोत: आरबीआई।

चार्ट IV.28: घरेलू बैंकों के डब्ल्यूएएलआर को क्षेत्रवार संचरण (मई 2022 से फरवरी 2023)

ए: ऋण (फिक्स्ड और फ्लोटिंग) पर डब्ल्यूएएलआर को संचरण

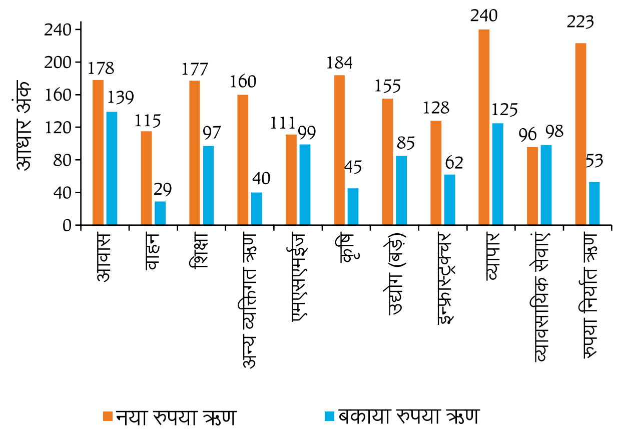

बी: अनिवार्य रूप से ईबीएलआर से जुड़े नए फ्लोटिंग दर रुपया ऋण पर डब्ल्यूएएलआर में संचरण

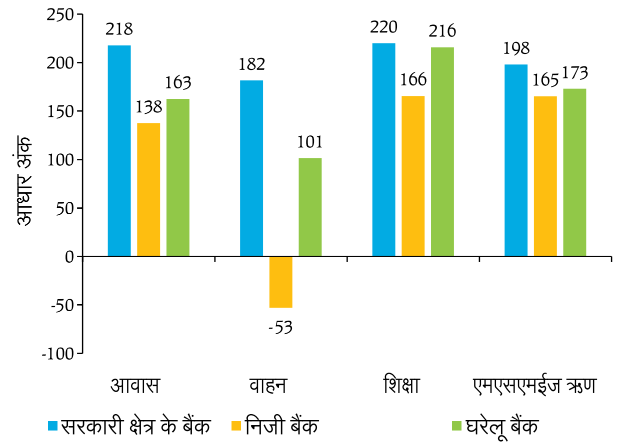

स्रोत: आरबीआई।

मई 2022-फरवरी 2023 के दौरान सभी क्षेत्रों में डब्ल्यूएएलआर में वृद्धि हुई (चार्ट IV.28ए)। ईबीएलआर से अनिवार्य रूप से जुड़े क्षेत्रों के मामले में संचरण अपेक्षाकृत अधिक था (चार्ट IV.28बी)।

2022-23 की दूसरी छमाही के दौरान व्यक्तिगत और एमएसएमई ऋणों के लिए नीतिगत रेपो दर (अस्थिर दर वाले नए रुपया ऋणों के मामले में, जहां रेपो दर बाहरी बेंचमार्क है) पर घरेलू बैंकों द्वारा प्रभारित स्प्रेड कम हुए (सारणी IV.6)।

सारणी IV.6: बाहरी बेंचमार्क से जुड़े ऋण – रेपो दर पर डब्लूएएलआर(नए ऋण) का स्प्रेड

(प्रतिशत)

क्षेत्र	सितंबर 2022			फरवरी 2023		
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	निजी बैंक	घरेलू बैंक	सरकारी क्षेत्र के बैंक	निजी बैंक	घरेलू बैंक
एमएसएमई ऋण	4.13	3.55	3.81	3.75	3.08	3.27
वैयक्तिक ऋण						
आवास	2.79	2.49	2.63	2.59	2.20	2.34
वाहन	3.09	3.48	3.13	2.69	1.36	2.06
शिक्षा	4.33	4.88	4.50	4.12	4.87	4.37
अन्य वैयक्तिक ऋण	4.03	6.38	4.21	3.43	3.35	3.42

स्रोत: आरबीआई।

पहली छमाही में मंद रहने के बाद, दूसरी छमाही में खुदरा जमा दरों में संचरण में तेजी आई क्योंकि बैंकों ने मजबूत ऋण वृद्धि के निधीयन के लिए खुदरा जमा जुटाने के अपने प्रयासों को तेज कर दिया (चार्ट IV. 29ए)। मई 2022 से फरवरी 2023 के दौरान नई जमाओं (खुदरा और थोक सहित) पर भारित औसत घरेलू मीयादी जमा दर (डब्ल्यूएडीटीडीआर) में 222 आधार अंक की वृद्धि हुई। पहली छमाही के दौरान बैंकों ने थोक जमा जुटाने पर ध्यान केंद्रित किया था। दूसरी छमाही में नई थोक जमा दरों **की वृद्धि** (77 आधार अंक) को पीछे छोड़ते हुए, नई खुदरा जमा दरों में वृद्धि (122 आधार अंक) के साथ यह स्थिति उलट गई (चार्ट IV.29बी)। बकाया जमाराशियों पर डब्ल्यूएडीटीडीआर में संचरण धीरे-धीरे ही सही, किन्तु बढ़ रहा है, जो नियत दरों पर मीयादी जमा राशियों की दीर्घकालिक परिपक्वता प्रोफाइल को दर्शाता है।

वर्तमान सख्ती चक्र में मीयादी जमा दरों में वृद्धि उधार दरों में वृद्धि से अधिक हो गई है (चार्ट IV.30ए)। बैंकों की बचत जमा दरें - जो कुल जमा का एक तिहाई हैं - हालांकि, मौजूदा सख्त अवधि में लगभग अपरिवर्तित रही हैं

चार्ट IV.29: अधिशेष चलनिधि, ऋण की स्थिति और सावधि जमा दरों में संचरण

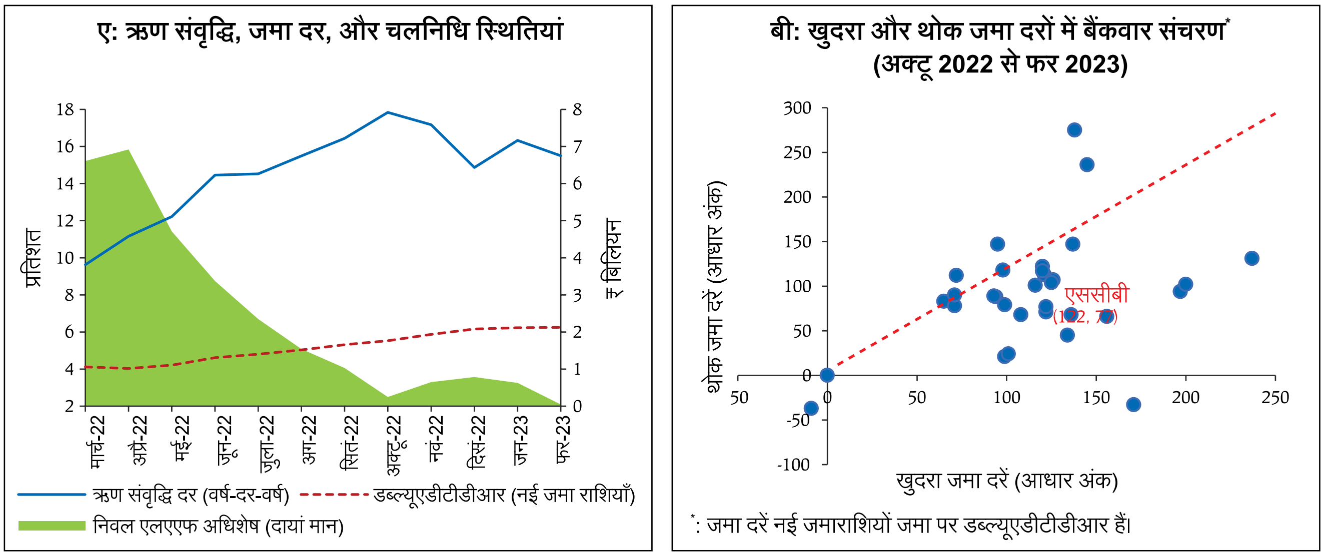

स्रोत: आरबीआई|

(चार्ट IV.30बी)[8]। इसने बैंकों की निधियों की समग्र लागत में वृद्धि को कम किया है और उनके निवल ब्याज मार्जिन में सुधार करने में मदद की है (चार्ट IV.30सी)।

चार्ट IV.30: बैंकों की जमा दरें और शुद्ध ब्याज मार्जिन

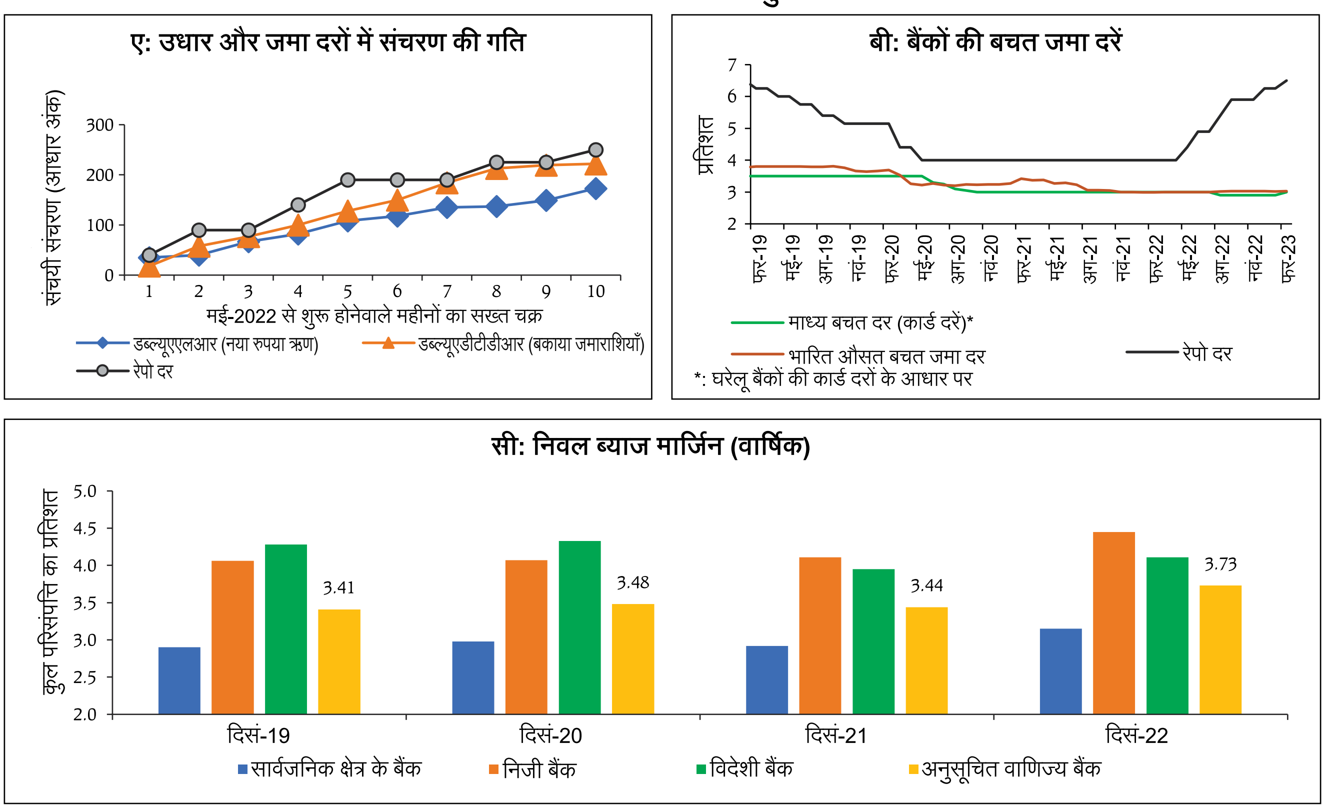

स्रोत: आरबीआई|

---

[8] दिसंबर 2022 में एसबीआई की कुल जमा राशि में मीयादी जमा की हिस्सेदारी 57.5 प्रतिशत थी, जबकि चालू खाता और बचत खाता जमा क्रमशः 9.5 प्रतिशत और 32.9 प्रतिशत थे।

सारणी IV.7: अल्प बचत लिखतों पर ब्याज दरें – ति1:2023-24

अल्प बचत योजना	परिपक्वता (वर्ष)	स्प्रेड (प्रतिशत अंक) $	संगत परिपक्वता का औसत जी-सेक यील्ड (%) (दिसंबर 2022 - फरवरी 2023)	फार्मूला- आधारित ब्याज दर (%) (ति1:2023-24 के लिए लागू)	ति1:2023-24 में सरकार द्वारा घोषित ब्याज दर (%)	अंतर (आधार अंक)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7) = (6) - (5)
जमा बचत	-	-	-	-	4.00	-
सार्वजनिक भविष्य निधि	15	0.25	7.51	7.76	7.10	-66
मियादी जमा						
1 वर्ष	1	0	6.80	6.80	6.80	0
2 वर्ष	2	0	6.91	6.91	6.90	-1
3 वर्ष	3	0	7.02	7.02	7.00	-2
5 वर्ष	5	0.25	7.25	7.50	7.50	0
आवर्ती जमा खाता	5	0	7.02	7.02	6.20	-82
मासिक आय योजना	5	0.25	7.21	7.46	7.40	-6
किसान विकास पत्र	115 माह#	0	7.51	7.51	7.50	-1
एनएससी VIII इश्यु	5	0.25	7.45	7.70	7.70	0
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना	5	1.00	7.25	8.25	8.20	-5
सुकन्या समृद्धि खाता योजना	21	0.75	7.51	8.26	8.00	-26

$: फरवरी 2016 की भारत सरकार की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अल्प बचत दरों के निर्धारण के लिए स्प्रेड्स।
#: वर्तमान परिपक्वता 115 महीने है।
टिप्पणी: कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी अलग-अलग लिखतों में भिन्न होती है।
स्रोत: भारत सरकार; एफबीआईएल; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

सरकार द्वारा प्रशासित और तुलनात्मक परिपक्वता वाले जी-सेक पर द्वितीयक बाजार प्रतिफल से जुड़ी लघु बचत योजनाओं (एसएसआई) पर ब्याज दरों को 2022-23 की तीसरी तिमाही के लिए 10-30 आधार अंक और चौथी तिमाही के लिए 20-110 आधार अंक तथा 2023-24 की पहली तिमाही के लिए 10-70 आधार अंको तक संशोधित किया गया, जबकि लगातार नौ तिमाहियों, *यानी* 2020-21 की दूसरी तिमाही से 2022-23 की दूसरी तिमाही तक इन्हें अपरिवर्तित रखा गया था। इन समायोजनों के साथ, अधिकांश एसएसआई दरें सूत्र-आधारित दरों के साथ निकटता से संरेखित हैं(सारणी IV.7)। बैंकों की मीयादी जमा दरें अब मीयादी डाकघर जमा दरों *की तुलना* में प्रतिस्पर्धी रूप से मूल्यांकित हैं (चार्ट IV.31)।

IV.3 चलनिधि संबंधी स्थितियां और परिचालन प्रक्रिया

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार रिज़र्व बैंक से यह अपेक्षित है कि वह मौद्रिक नीति के कार्यान्वयन से संबंधित प्रक्रियाओं और समय-समय पर उसमें होने वाले परिवर्तनों, यदि कोई हो, को सार्वजनिक पटल (पब्लिक डोमेन) पर रखे। मौद्रिक नीति के रुख के अनुरूप, निभावकारी, अधिशेष चलनिधि वापस लेने के लिए 2022-23 की छमाही में और कमी हो गई। 30 सितंबर, 2022 को, रिज़र्व बैंक ने 28-दिवसीय वीआरआरआर को पाक्षिक 14-दिवसीय मुख्य नीलामी के साथ विलय करने की घोषणा की। कम होती अधिशेष चलनिधि के बीच,

चार्ट IV.31: बैंक और डाक घर की सावधि जमा दरें

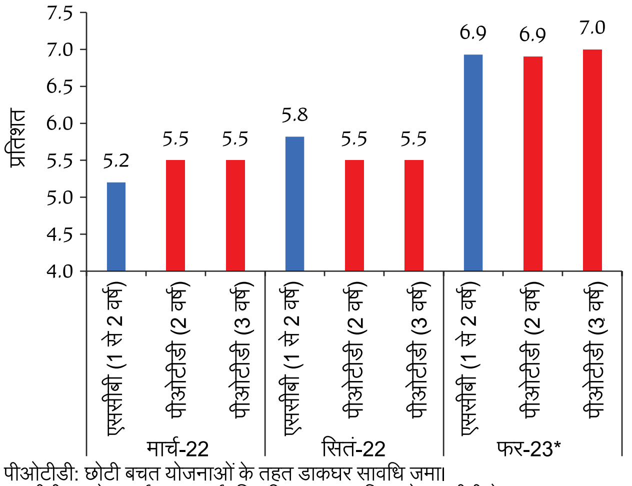

पीओटीडी: छोटी बचत योजनाओं के तहत डाकघर सावधि जमा।
एससीबी (1 से 2 वर्ष): 1-2 वर्ष की परिपक्वता अवधि वाले एससीबी के खुदरा जमा पर डब्ल्यूएडीटीडीआर।
* पीओटीडीके लिए डेटा ति:1:2023-24 से संबधित है।
स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान।

सारणी IV.8: चलनिधि - प्रमुख संचालक और प्रबंधन

(₹ करोड़)

संचालक	2021-22		2022-23*	
	छ1	छ2	छ1	छ2*
संचालक				
(i) सीआईसी [आहरण (-)/वापसी (+)]	-71,344	-2,08,609	-24,604	-2,22,099
(ii) शुद्ध विदेशी मुद्रा खरीद (+)/बिक्री(-)	3,04,980	-1,70,351	-2,73,554	49,278#
(iii) भारत सरकार नकद शेष [बिल्ड-अप (-)/ड्रॉडाउन (+)]	-1,75,933	3,73,153	-1,99,861	30,048#
(iv) अतिरिक्त रिजर्व [बिल्ड-अप (-)/ड्रॉडाउन (+)]	1,11,969	-1,55,698	95,719	38,005#
प्रबंधन				
(i) शुद्ध ओएमओ खरीद (+)/बिक्री(-)	2,36,926	-22,950	-21,080	-10,280
(ii) आवश्यक आरक्षित निधियां [एनडीटीएल और सीआरआर दोनों में परिवर्तन सहित]	-99,242	-28,913	-1,17,000	-39,082
मेमो आइटम				
(i) अवधि के दौरान औसत दैनिक अवशोषण	7,02,231	8,13,922	4,22,682	1,47,886

सीआईसी: संचालन में मुद्रा। जीओआई: भारत सरकार
टिप्पणी: (+)/(-) चिह्न बैंकिंग प्रणाली की चलनिधि में वृद्धि/कमी का संकेत देता है।
*:छ2 के लिए डेटा मार्च 24, 2023 तक का है। #: डेटा जनवरी, 2023 तक का है।
स्रोत: आरबीआई।

रिज़र्व बैंक ने फरवरी-मार्च में 14-दिवसीय परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामी और मार्च 2023 में एक वीआरआर परिष्करण (फाइन ट्यून) का आयोजन किया। रिज़र्व बैंक अर्थव्यवस्था की उत्पादक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहा, जिसमें चलनिधि की स्थिति के आधार पर एलएएफ के दोनों ओर संचालन करने में लचीलापन था। स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ), जो पिछले एक साल से एलएएफ कॉरिडोर के आधार के रूप में चालू है, ने आरबीआई को संपार्श्विक की उपलब्धता से बाधित हुए बिना, अधिशेष चलनिधि को निर्बाध रूप से अवशोषित करने की सहूलियत दी है।

चलनिधि के संचालक और प्रबंधन

संचलन में मुद्रा (सीआईसी) दूसरी छमाही के दौरान चलनिधि निकासी का प्रमुख चालक थी। त्योहारी मौसम की मांग के कारण दूसरी छमाही (24 मार्च, 2023 तक) के दौरान सीआईसी में 2.2 लाख करोड़ रुपये का विस्तार हुआ (सारणी IV.8)। इसका समंजन आंशिक रूप से निवल विदेशी मुद्रा खरीद (0.5 लाख करोड़ रुपये) और सरकारी खर्च में सामान्य तेजी (0.3 लाख करोड़ रुपये) से हुआ। बैंकों ने अपनी अतिरिक्त सीआरआर धारिता (0.4 लाख करोड़ रुपये) को कम कर दिया, जिससे चलनिधि में भी वृद्धि हुई। चलनिधि के प्रबंधन के संदर्भ में, ओएमओ बिक्री और नकद आरक्षित शेष राशि में वृद्धि (उच्च आरक्षित आधार के कारण) ने 2022-23 की दूसरी छमाही के दौरान अर्थव्यवस्था से चलनिधि को अवशोषित कर लिया।

एलएएफ के तहत निवल औसत दैनिक अवशोषण दूसरी छमाही के दौरान 0.4 लाख करोड़ रुपये तक कम हो गया, जो पहली छमाही के दौरान 3.3 लाख करोड़ रुपये था (चार्ट IV.32ए)। निवल एलएएफ दूसरी छमाही में कभी-कभार घाटे की स्थिति में आ गई; जो त्योहार-संबंधी मुद्रा मांग, माह के अंत में जीएसटी बहिर्वाह और तिमाही अग्रिम कर भुगतानों के घर्षणात्मक दबावों से प्रेरित थी। इस संबंध में, निवल एलएएफ़ इंजेक्शन 17 मार्च, 2023 को ₹1.05 लाख करोड़ तक बढ़ गया, जो 24 अप्रैल, 2019 के बाद उच्चतम (₹1.42 लाख करोड़) था। घटते चलनिधि अधिशेष के बीच, परिवर्तनीय रिवर्स रेपो दर (वीआरआरआर) नीलामियों के तहत अवशोषित राशियाँ दूसरी छमाही में घट गई; नीलामी का औसत प्रस्ताव-कवर अनुपात दूसरी छमाही में 0.26 था, जबकि पहली छमाही में यह 0.40 था। साथ ही, बैंकों ने सीमांत चलनिधि सुविधा (एमएसएफ़) का ज्यादा उपयोग किया और पहली छमाही के दौरान ₹3,448 करोड़ की तुलना में दूसरी छमाही के दौरान यह ₹8,438 करोड़ रहा (चार्ट IV.32बी)। एमएसएफ उधारी 24 अक्टूबर, 2022 को ₹65,646 करोड़ के उच्च स्तर को छू गई – जो 1 अप्रैल, 2019 के बाद सबसे अधिक (₹94,263 करोड़) थी। एमएसएफ विंडो तक बढ़ी हुई पहुंच, यहां तक कि बड़े अधिशेष फंडों को एसडीएफ के तहत रखा गया था,

चार्ट IV.32: चलनिधि स्थितियां और एमएसएफ उधार

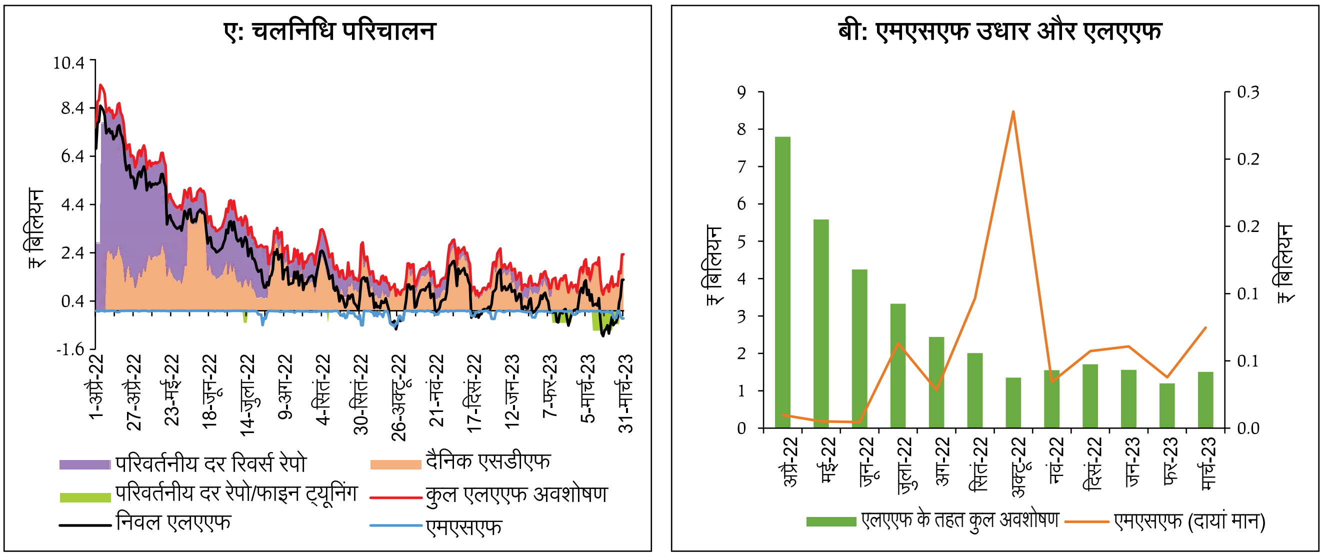

स्रोत: आरबीआई।

बैंकिंग प्रणाली के भीतर विषम चलनिधि वितरण को दर्शाता है। आरबीआई ने चलनिधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, 10 फरवरी और 10 मार्च, 2023 को दो 14-दिवसीय वीआरआर नीलामियाँ की और 24 मार्च को 5-दिवसीय परिष्करण (फाइन ट्यूनिंग) वीआरआर नीलामी आयोजित की। 31 मार्च, 2023 को स्थायी चलनिधि सुविधा (एसएलएफ) के तहत स्टैंडअलोन प्राथमिक डीलरों (एसपीडी) को मौजूदा रेपो दर पर ₹5,000 करोड़ की राशि भी उपलब्ध कराई गई थी और इस सुविधा के तहत प्राप्त निधि को 5 अप्रैल, 2023 को या उससे पहले चुकाया जाना था।

चार्ट IV.33: कुल एलएएफ अवशोषण और डब्ल्यूएसीआर स्प्रेड

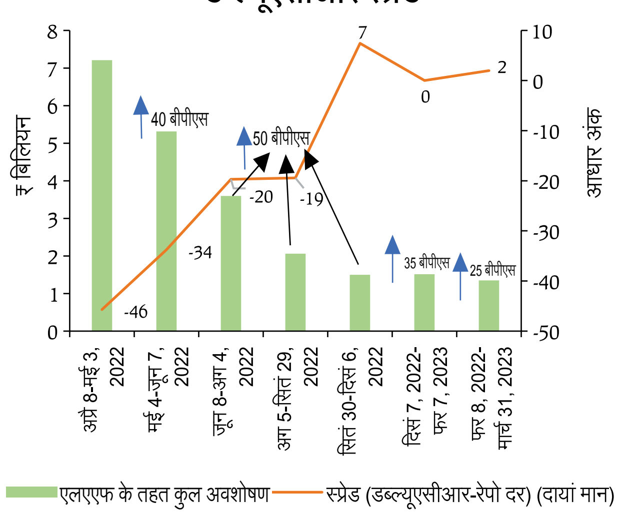

नोट : ↑ दर वृद्धि
स्रोत: आरबीआई।

अधिशेष चलनिधि के क्रमिक सामान्यीकरण के साथ-साथ आवधिक नीतिगत दरों में वृद्धि किए जाने से, डब्ल्यूएसीआर को पहली छमाही के विपरीत, दूसरी छमाही में रेपो दर के बिल्कुल अनुरूप रखा गया, जब अधिशेष चलनिधि स्थितियों ने डब्ल्यूएसीआर को रेपो दर से नीचे रखा था (चार्ट IV.33)।

आरक्षित धन (आरएम) में 24 मार्च, 2023 तक 10.0 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई, जबकि एक साल पहले यह

सारणी IV.9: बैंकिंग और मौद्रिक कुल राशियां
(वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि, प्रतिशत)

संकेतक	मार्च 2021	मार्च 2022	मार्च 2023
आरक्षित मुद्रा (सीआरआर परिवर्तनों के लिए समायोजित)	18.8 (15.1)	13.0 (10.3)	10.0 (7.6)
व्यापक मुद्रा(एम3)	12.2	8.8	9.0
जनता के पास मुद्रा	17.1	10.3	7.9
कुल जमाराशियां	11.4	8.9	9.6
मांग जमा	15.1	11.4	5.2
सावधि जमा	10.9	8.6	10.2
बैंक ऋण	5.6	9.6	15.0

टिप्पणी: जमा और ऋण वृद्धि के आंकड़े अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) से संबंधित हैं।
स्रोत: आरबीआई।

13.0 प्रतिशत थी (एक साल पहले 10.3 प्रतिशत की तुलना में सीआरआर में बदलाव के पहले दौर के प्रभाव के लिए समायोजन 7.6 प्रतिशत था)। मुद्रा आपूर्ति (एम3) में 24 मार्च, 2023 तक 9.0 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई, जबकि एक साल पहले यह 8.8 प्रतिशत थी (सारणी IV.9)।

अन्य नीतिगत उपाय

बैंकों को अपने निवेश पोर्टफोलियो का बेहतर प्रबंधन करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से, समाप्त कर दी गई 23 प्रतिशत की वर्धित धारित परिपक्वता सीमा (एचटीएम) की व्यवस्था को 31 मार्च, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। बैंकों को 1 सितंबर, 2020 और 31 मार्च, 2024 के बीच अधिग्रहीत प्रतिभूतियों को बढ़ी हुई एचटीएम सीमा में शामिल करने की भी अनुमति दी गई थी। एचटीएम सीमा जून 2024 से चरणबद्ध तरीके से 23 प्रतिशत से 19.5 प्रतिशत तक बहाल की जाएगी। सामान्य चलनिधि परिचालन की दिशा में सुविचारित कदम के तहत दिसंबर 2022 में कॉल/नोटिस/सावधि मुद्रा, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाणपत्र, मुद्रा बाजार के कॉर्पोरेट बॉन्ड खंडों में रेपो और रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव्स और फरवरी 2023 में सरकारी प्रतिभूति बाजार के लिए बाजार का समय सुबह 9.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक बहाल कर दिया गया था।

IV.4 निष्कर्ष

2022-23 की दूसरी छमाही में घरेलू वित्तीय बाजार की स्थितियों ने मौद्रिक सख्ती और चलनिधि में कमी के साथ समायोजन किया और वैश्विक नीतिगत स्पिलओवर (प्रभाव-प्रसार) के प्रति अघातसहनीयता प्रदर्शित की। सभी खंडों, लिखतों और परिपक्वता अवधियों में बाजार दरों में विभिन्न परिमाणों में मजबूती आई। आघातसह आर्थिक गतिविधियों के कारण बैंकों का ऋण उठाव उत्साहजनक बना रहा। मौद्रिक नीति कार्रवाइयों के अनुरूप बैंक ऋण और जमा दरों में वृद्धि हुई। भारतीय रुपये में गिरावट आई जो अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने और पोर्टफोलियो निकासी को दर्शाता है। आने वाले समय में, घरेलू वित्तीय बाजारों पर वैश्विक प्रभाव-प्रसार को कम करते हुए अर्थव्यवस्था की उत्पादक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, आरबीआई अपने चलनिधि प्रबंधन संचालन में सतर्क, चुस्त और दुरुस्त बना रहेगा।

V. बाह्य परिवेश

वैश्विक अर्थव्यवस्था सख्त वित्तीय परिस्थितियों, उच्च मुद्रास्फीति और यूक्रेन में लंबे समय से चल रहे संघर्ष से उत्पन्न प्रभाव के कारण धीमी पड़ रही है। वैश्विक वित्तीय बाजारों में मुद्रास्फीति और वित्तीय स्थिरता को लेकर उभरने वाले घटनाक्रम विशेष रूप से हाल के दिनों में बैंकिंग क्षेत्र में महसूस किए गए दबाव के फलस्वरूप बढ़ी हुई अस्थिरता देखी गई है। खाद्य और ऊर्जा संबंधी असुरक्षा, वित्तीय स्थिरता संबंधी चिंताएं एवं ऋण दबाव जनित जोखिमों, उभरते बाजारों तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के दृष्टिकोण के प्रति नकारात्मक जोखिम उत्पन्न करते हैं।

वैश्विक अर्थव्यवस्था कठिन वित्तीय परिस्थितियों, उच्च मुद्रास्फीति और यूक्रेन में लंबे समय से चल रहे संघर्ष से उत्पन्न प्रभाव के कारण धीमी हो रही है। उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति लक्ष्य से काफी ऊपर है और निरंतर ऊपर बने रहने के संकेत दे रही है। मार्च में, वैश्विक वित्तीय बाजार बैंकिंग क्षेत्र की विफलताओं/बेलआउट संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे, जिससे वे अत्यधिक जोखिम उठाने और आर्थिक स्थिति में गिरावट से बच रहे थे एवं सुरक्षित स्थानों पर निवेश का प्रयास कर रहे थे। सरकारी बॉन्ड प्रतिफल में पिछले छह महीनों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव देखा गया जिसमें नवंबर-जनवरी के दौरान नरम मुद्रास्फीति की स्थिति को देखते हुए कम आक्रामक मौद्रिक सख्ती की अपेक्षा के कारण नरमी आना; फरवरी 2023 में स्थिर मुद्रास्फीति और श्रम बाजार की मजबूत स्थितियों के कारण सख्त होना; बैंकिंग तथा वित्तीय स्थिरता संबंधी चिंताओं के कारण मार्च में सभी परिपक्वता अवधियों वाले बॉन्ड प्रतिफलों में गिरावट देखी गई। अल्पकालिक प्रतिफल ने मार्च में दशकों में सबसे तेज एकल-दिवसीय गिरावट दर्ज की। अमरीकी डॉलर जनवरी 2023 तक कमजोर रहा, लेकिन फरवरी 2023 में इसमें मजबूती आई। वैश्विक इक्विटी बाजार फरवरी तक ऊर्ध्वगामी झुकाव के साथ सजग रहे जिसमें मार्च में तेज गिरावट दर्ज की गई। आगे देखें तो, खाद्य और ऊर्जा संबंधी असुरक्षा, वित्तीय स्थिरता संबंधी चिंताएं एवं ऋण दबाव के जोखिम, उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के दृष्टिकोण के प्रति नकारात्मक जोखिम उत्पन्न करते हैं।

V.1 वैश्विक आर्थिक स्थिति

वर्ष 2022 की दूसरी छमाही में, वैश्विक वृद्धि अनुमान से अधिक मजबूत थी, जो दबी हुई मांग, संचित घरेलू बचत, श्रम बाजार लाभ, आपूर्ति बाधाओं में कमी और ऊर्जा की कीमतों में तेज गिरावट को दर्शाता है। वर्ष 2023 की पहली तिमाही के लिए उच्च आवृत्ति संकेतक, विनिर्माण से संबंधित मंदी में कमी और सेवा क्षेत्र गतिविधि में तेजी इंगित करते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने जनवरी 2023 के अपने *विश्व आर्थिक दृष्टिकोण* (डब्ल्यूईओ) की स्थिति को अद्यतन करते हुए 2022 और 2023 दोनों के लिए वैश्विक वृद्धि दर के अनुमान को 20 आधार अंक (बीपीएस) बढ़ाकर क्रमशः 3.4 प्रतिशत और 2.9 प्रतिशत कर दिया था[1]।

दो तिमाहियों तक लगातार संकुचन की स्थिति से उभरते हुए, अमरीकी अर्थव्यवस्था में 2022 की तीसरी तिमाही में 3.2 प्रतिशत (तिमाही-दर-तिमाही, मौसमी रूप से समायोजित वार्षिक दरें (तिमाही-दर-तिमाही, एसएएआर)) और चौथी तिमाही में 2.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी V.1)। यह सुधार निजी इन्वेंट्री में निवेश, उपभोक्ता खर्च, गैर-आवासीय सावधि निवेश, सरकारी खर्च और निर्यात द्वारा संचालित था। बेरोजगारी दर कई दशकों के निचले स्तर पर होने के कारण श्रम बाजार ने मजबूत वृद्धि दर्ज की। सांकेतिक वेतन में जबर्दस्त वृद्धि हुई थी, हालांकि हाल ही में वह कुछ धीमी हुई थी। यूएस कंपोजिट एसएंडपी ग्लोबल परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई[2]) का फरवरी 2023 में 50.1 का स्तर सात महीने तक लगातार गिरावट के समाप्त हो जाने का संकेत देता है।

तीसरी तिमाही में 1.5 प्रतिशत (तिमाही-दर-तिमाही, एसएएआर) की वृद्धि के बाद, यूरो क्षेत्र में वास्तविक जीडीपी चौथी तिमाही में निजी खपत और निवेश में गिरावट आने, उच्च मुद्रास्फीति की चपेट में आने, सख्त वित्तीय स्थिति तथा भू-राजनीतिक तनाव के कारण स्थिर बनी रही। यूरोजोन कंपोजिट पीएमआई अक्तूबर 2022 के लगभग दो साल के निचले स्तर से मार्च में लगातार तीसरे महीने बढ़कर 53.7 पर पहुंच गया जो कि सेवा क्षेत्र द्वारा संचालित था। बेरोजगारी दर दिसंबर 2022 में 6.7 प्रतिशत से गिरकर फरवरी 2023 में 6.6 प्रतिशत हो गई।

1 ओईसीडी ने अपने अंतरिम आर्थिक दृष्टिकोण (मार्च 2023) में, 2023 और 2024 के लिए वैश्विक वृद्धि पूर्वानुमानों के संबंध में नवंबर 2022 के 2.2 प्रतिशत और 2.7 प्रतिशत के अनुमानों को संशोधित कर क्रमशः 2.6 प्रतिशत और 2.9 प्रतिशत कर दिया है।

2 पीएमआई के सदंर्भ एस एडं पी ग्लोबल इंडेक्स के लिए हैं, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो।

सारणी V.1: वास्तविक जीडीपी संवृद्धि

(प्रतिशत)

देश	ति1-2022	ति2-2022	ति3-2022	ति4-2022	2021	2022 (ई)	2023 (पी)	2024 (पी)
तिमाही-दर-तिमाही मौसमी समायोजित वार्षिकीकृत दर (ति-दर-ति, एसएएआर)								
कनाडा	2.4	3.6	2.3	0.0				
यूरो क्षेत्र	2.5	3.6	1.5	-0.1				
जापान	-1.8	4.7	-1.1	0.1				
दक्षिण कोरिया	2.6	3.0	1.3	-1.6				
यूके	2.0	0.2	-0.4	0.5				
यूएस	-1.6	-0.6	3.2	2.6				
वर्ष-दर-वर्ष								
उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ								
कनाडा	3.1	4.7	3.8	2.1	5.0	3.5	1.5	1.5
यूरो क्षेत्र	5.5	4.4	2.4	1.8	5.3	3.5	0.7	1.6
जापान	0.5	1.7	1.5	0.4	2.1	1.0	1.8	0.9
दक्षिण कोरिया	3.0	2.9	3.1	1.3	4.1	2.6	1.7	2.6
यूके	10.6	3.8	2.0	0.6	7.6	4.1	-0.6	0.9
यूएस	3.7	1.8	1.9	0.9	5.9	2.1	1.4	1.0
उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएँ								
ब्राज़ील	2.4	3.7	3.6	1.9	5.0	2.9	1.2	1.5
चीन	4.8	0.4	3.9	2.9	8.1	3.0	5.2	4.5
भारत	4.0	13.2	6.3	4.4	9.1	7.0	6.1	6.8
इंडोनेशिया	5.0	5.5	5.7	5.0	3.7	5.3	4.8	5.1
फ़िलिपीन्स	8.2	7.5	7.6	7.2	5.7	7.6	5.0	6.0
रूस	3.5	-4.1	-3.7		5.6	-2.1	0.3	2.1
दक्षिण अफ्रीका	2.8	0.3	4.2	0.9	4.9	2.0	1.2	1.3
थाईलैंड	2.2	2.5	4.6	1.4	1.5	2.6	3.7	3.6

मेमो:

विश्व	2021	2022 (ई)	2023 (पी)	2024 (पी)
वर्ष-दर-वर्ष				
विश्व उत्पादन	6.2	3.4	2.9	3.1
विश्व व्यापार मात्रा	10.4	5.4	2.4	3.4

ई: अनुमान पी: पूर्वानुमान

टिप्पणी: भारत का डेटा वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) के अनुरूप है। उदा. अप्रैल 2022-मार्च 2023 वर्ष 2022 से संबंधित है।

स्रोत: आधिकारिक सांख्यिकीय एजेंसी; ब्लूमबर्ग; और आईएमएफ डब्ल्यूईओ अपडेट, जनवरी 2023।

यूके में, 2022 की तीसरी तिमाही में जीडीपी में 0.4 प्रतिशत (तिमाही-दर-तिमाही, एसएएआर) की गिरावट आई और चौथी तिमाही में 0.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई । ऊर्जा और वस्तुओं की ऊंची कीमतों के कारण वास्तविक घरेलू आय में गिरावट का प्रभाव उपभोक्ता खर्च पर पड़ा। मजबूत मजदूरी वृद्धि और कम बेरोजगारी दर के साथ श्रम बाजार मजबूत बना हुआ है। मार्च में यूके का कंपोजिट पीएमआई 52.2 पर था, जो लगातार दूसरे महीने विस्तार क्षेत्र में रहा, जो विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों में व्यावसायिक गतिविधि के उच्च स्तर को दर्शाता है।

जापान के सकल घरेलू उत्पाद में 2022 की तीसरी तिमाही में 1.1 प्रतिशत (तिमाही-दर-तिमाही, एसएएआर) की गिरावट आई और अर्थव्यवस्था चौथी तिमाही में 0.1 प्रतिशत की मामूली वृद्धि के साथ मंदी से बचकर निकाल सकी क्योंकि कमजोर येन और उच्च आयात लागत ने खपत और व्यवसायों को नुकसान पहुंचाया। नवम्बर में कंपोजिट पीएमआई (एयू जिबुन बैंक) वर्ष 2022 की दूसरी छमाही के सबसे कम पठनांक 48.9 से बढ़कर मार्च में 52.9 हो गया, इसने जून 2022 के बाद से सबसे तेज बढ़ोतरी दर्ज की जो कि विनिर्माण क्षेत्र के शिथिल होने के बावजूद भी सेवा क्षेत्र से संचालित रहा।

उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के बीच, चीन की जीडीपी वृद्धि 2022 की तीसरी तिमाही में 3.9 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) तक पहुंच गई, यह दूसरी तिमाही में 0.4 प्रतिशत थी, जो नीतिगत हस्तक्षेपों और कोविड-19 लॉकडाउन में ढील द्वारा समर्थित थी (सारणी V.1)। कोविड-19 संक्रमण के फिर से उभरने और लॉकडाउन के कारण चौथी तिमाही में वृद्धि दर घटकर 2.9 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) हो गई, जिससे 2022 के लिए वार्षिक वृद्धि 5.5 प्रतिशत के लक्ष्य से घटकर 3.0 प्रतिशत हो गई (सारणी V.2)। फरवरी में कंपोजिट पीएमआई (कैक्सिन) बढ़कर 54.2 पर पहुंच गया, जो विनिर्माण और सेवा दोनों गतिविधियों द्वारा समर्थित था। मार्च में, हालांकि, पीएमआई धीमा होकर 50 के स्तर के नजदीक आ गया जो 2023 की पहली तिमाही के अंत में कारोबारी परिस्थितियों के स्थिर होने का संकेत देता है। 2023 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि लक्ष्य लगभग 5 प्रतिशत तय किया गया है, जो तीन दशकों से भी अधिक समय में सबसे कम है।

अन्य बड़ी ईएमई के बीच, ब्राजील की जीडीपी वृद्धि 2022 की दूसरी तिमाही में 3.7 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) से घटकर तीसरी तिमाही में 3.6 प्रतिशत और चौथी तिमाही में पुनः घटकर 1.9 प्रतिशत हो गई। चौथी तिमाही में कृषि क्षेत्र में गिरावट (वर्ष-दर-वर्ष) दर्ज की गई। श्रम बाजार, जिसने पूरे 2022 में सकारात्मक रूप से प्रदर्शन किया, पेरोल में नेट एडमिशन की कमी से गिर रहा है। समग्र पीएमआई फरवरी 2023 में गिरकर 49.7 हो गया, जो सितंबर 2022 में 51.9 था, जिसमें सेवा और विनिर्माण दोनों गतिविधि कम हो गई। दक्षिण अफ्रीकी अर्थव्यवस्था 2022 की तीसरी तिमाही में 1.8 प्रतिशत (तिमाही-दर-तिमाही, एसएएआर) बढ़ी और चौथी तिमाही में 1.3 प्रतिशत की गिरावट आई। वर्ष दर वर्ष आधार पर, अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर तीसरी तिमाही में 4.2 प्रतिशत और

सारणी V.2: ब्रिक्स अर्थव्यवस्थों के लिए चुनिंदा समष्टिगत आर्थिक संकेतक

वास्तविक जीडीपी संवृद्धि दर (वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)	देश	2021	2022(ई)	2023(पी)
	ब्राज़ील	5.0	2.9	1.2
	रूस	5.6	-2.1	0.3
	भारत	9.1	7.0	6.1
	चीन	8.1	3.0	5.2
	दक्षिण अफ़्रीका	4.9	2.0	1.2

सामान्य सरकारी सकल ऋण (सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत)	देश	2021	2022(ई)	2023(पी)
	ब्राज़ील#	93.0	88.2	88.9
	रूस	17.0	16.2	16.9
	भारत	84.2	83.4	83.8
	चीन	71.5	76.9	84.1
	दक्षिण अफ़्रीका	69.0	68.0	70.7

सीपीआई मुद्रास्फीति दर (वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)	देश	2021	2022(ई)	2023(पी)
	ब्राज़ील	8.3	9.3	4.7
	रूस	6.7	13.8	5.0
	भारत	5.5	6.8	5.1
	चीन	0.9	2.0	2.2
	दक्षिण अफ़्रीका	4.6	6.9	5.1

चालू खाता शेष (सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत)	देश	2021	2022(ई)	2023(पी)
	ब्राज़ील	-1.7	-1.5	-1.6
	रूस	6.9	12.2	11.1
	भारत	-1.2	-3.5	-2.9
	चीन	1.8	1.8	1.5
	दक्षिण अफ़्रीका	3.7	1.2	-1.0

सामान्य सरकारी निवल उधार/ कर्ज (सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत)	देश	2021	2022(ई)	2023(पी)
	ब्राज़ील	-4.4	-5.8	-7.5
	रूस	0.8	-2.3	-2.1
	भारत	-10.0	-9.9	-9.0
	चीन	-6.1	-8.9	-7.2
	दक्षिण अफ़्रीका	-6.0	-4.9	-5.4

विदेशी मुद्रा भंडार * (बिलियन अमरीकी डॉलर)	देश	2021	2022(ई)	2023(पी)
	ब्राज़ील	362.2	324.7	328.1
	रूस	630.6	582.0	597.0
	भारत	633.6	562.7	562.7
	चीन	3426.9	3306.5	3372.5
	दक्षिण अफ़्रीका	57.8	60.6	61.9

ई: अनुमान पी: पूर्वानुमान|

*: 2023 के लिए विदेशी मुद्रा भंडार ब्राज़ील और भारत (फरवरी) को छोड़कर सभी के लिए जनवरी 2023 से संबंधित है।

#: सकल ऋण का तात्पर्य गैर-वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्र से है जिसमें एलेट्रोब्रास और पेट्रोब्रास को छोड़कर केंद्रीय बैंक के तुलन पत्र पर रखे गए खजाना बिल शामिल है।

टिप्पणी: विदेशी मुद्रा भंडार पर डेटा को छोड़कर भारत का डेटा वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) के अनुरूप है जो कैलेंडर वर्ष के अनुसार है। 2022 के लिए भारत की मुद्रास्फीति के आंकड़े अप्रैल 2022 से फरवरी 2023 तक हैं।

स्रोत: आधिकारिक सांख्यिकीय एजेंसियां; डब्ल्यूईओ अक्तूबर 2022 डाटाबेस और जनवरी 2023 अपडेट; आईएमएफ; राजकोषीय मॉनिटर अपडेट, अक्तूबर 2022, आईएमएफ; और इंटरनैशनल रिजर्व एंड फॉरेन करेंसी लिक्विडिटी (आईआरएफसीएल), आईएमएफ; और आरबीआई।

चौथी तिमाही में 0.9 प्रतिशत रही। 2023 की पहली तिमाही में, फरवरी में 50.5 पर समग्र पीएमआई ने उत्पादन में विस्तार की तरफ वापसी का संकेत दिया, जो जनवरी में 13 महीने के निचले स्तर 48.7 तक गिर गया था। रूसी अर्थव्यवस्था में 2022 की तीसरी तिमाही में 3.7 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की गिरावट आई। जहां बेरोजगारी अपने सार्वकालिक निचले स्तर के करीब रही है वहीं साथ-साथ श्रम बाजार सख्त बना हुआ है।

वर्ष 2022 की चौथी तिमाही में धीमी होने से पहले दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र ने खपत और पर्यटन में बहाली के कारण 2022 की तीसरी तिमाही में एक मजबूत वृद्धि दर्ज की। फरवरी के लिए एएसईएएन[3] विनिर्माण पीएमआई से विनिर्माण क्षेत्र में परिचालन स्थितियों में सुधार के संकेत मिले क्योंकि उत्पादन में विस्तार एवं नए आदेशों ने गति पकड़ी। इसके अतिरिक्त, अक्तूबर के बाद पहली बार रोजगार में वृद्धि हुई। परिचालन स्थितियों में मार्च में सुधार जारी रहा।

उच्च आवृत्ति संकेतकों के बीच, जनवरी-फरवरी 2023 के लिए आर्थिक सहयोग और विकास संगठन समग्र अग्रणी संकेतक (सीएलआई) अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं के लिए प्रवृत्ति स्तर से नीचे रहे (चार्ट V.1ए)। वैश्विक कंपोजिट पीएमआई लगातार छह महीने के संकुचन का सिलसिला समाप्त करते हुए फरवरी में 52.1 के विस्तारित स्तर पर वापस आया जिसमें सेवा क्षेत्र की अग्रणी भूमिका रही और यह जुलाई 2022 के बाद विनिर्माण उत्पादन में पहला विस्तार था (चार्ट V.1बी)। मार्च में विनिर्माण उत्पादन का विस्तार यद्यपि धीमी गति से जारी रहा।

[3] दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (एएसईएएन) में ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं।

चार्ट V.1: सर्वेक्षण संकेतक

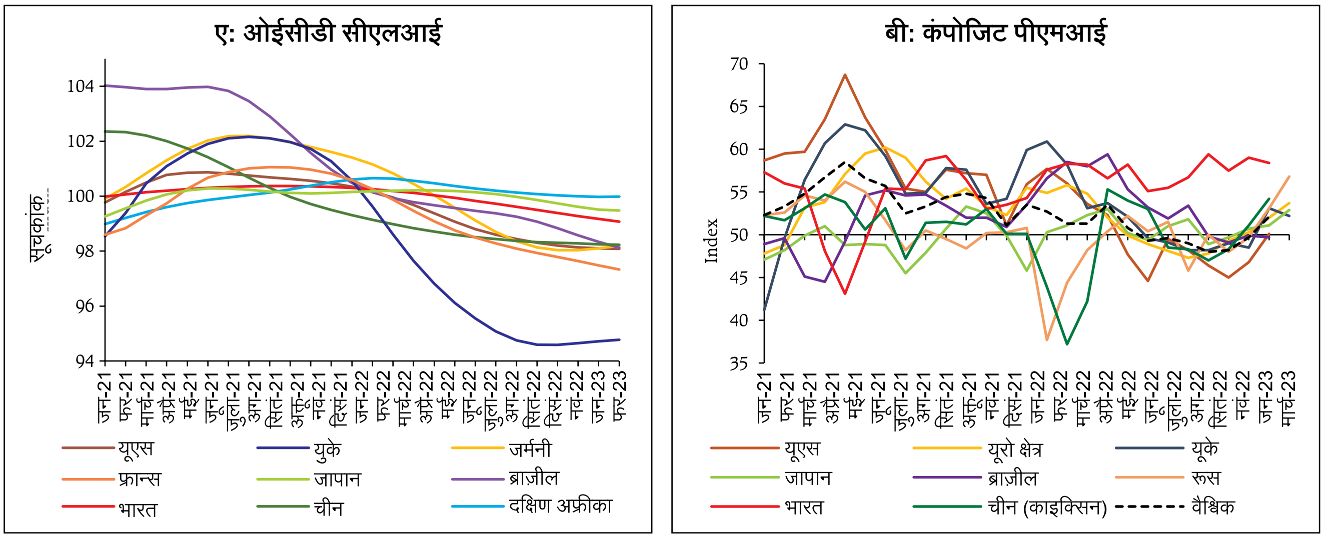

टिप्पणी: पीएमआई सूचकांकों के लिए 50 से ऊपर की रीडिंग पिछले महीने की तुलना में समग्र वृद्धि को दर्शाती है, और 50 से नीचे समग्र कमी को दर्शाती है। सूचकांक मौसमी रूप से समायोजित होते हैं।
स्रोत: ओईसीडी; और ब्लूमबर्ग।

आपूर्ति श्रृंखला के दबाव में कमी के बावजूद वैश्विक मांग में कमी के कारण व्यापार की मात्रा में कमी आई। पण्य व्यापार की मात्रा में 2022 की चौथी तिमाही में 0.3 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की गिरावट आई, और जनवरी 2023 में भी 1.5 प्रतिशत की गिरावट आई (चार्ट V.2ए)। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स, जो विविध प्रकार के थोक पण्यों जैसे कोयला और लौह अयस्क के लिए शिपिंग लागत का एक मापक है, मार्च 2023 में 2019-20 के पूर्व-कोविड औसत की तुलना में 9.3 प्रतिशत अधिक था (चार्ट V.2बी)। डब्ल्यूटीओ द्वारा संकलित वस्तु व्यापार बैरोमीटर दिसंबर 2022 में 92.2 (सितंबर में 96.2) तक गिर गया, जो 2023 की पहली तिमाही में व्यापार मात्रा में कमजोर वृद्धि का संकेत देता है। आईएमएफ ने अपने डब्ल्यूईओ की स्थिति को अद्यतन (जनवरी 2023) करते हुए विश्व व्यापार (वस्तु एवं सेवा) मात्रा की वृद्धि दर को 2022 के 5.4 प्रतिशत से घटकर 2023 में 2.4 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है।

चार्ट V.2: विश्व व्यापार मात्रा संवृद्धि

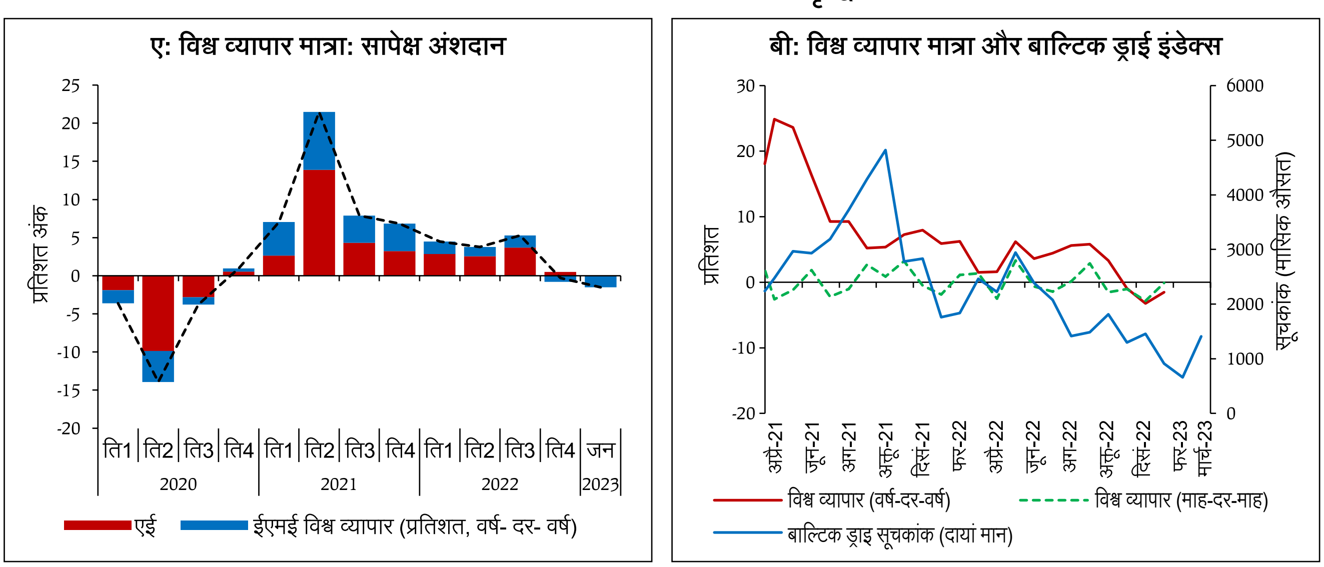

स्रोत: सीपीबी नेदरलैंड्स; और सीएआईसी।

V.2 पण्य कीमतें और मुद्रास्फीति

वैश्विक पण्य कीमतें 2022 की चौथी तिमाही और 2023 की पहली तिमाही में अस्थिर रहीं। वे शुरू में 2022 की चौथी तिमाही के पूर्वार्ध में 5.4 प्रतिशत (ब्लूमबर्ग कमोडिटी प्राइस इंडेक्स के संदर्भ में) बढ़ी, लेकिन फिर जनवरी 2022 (पूर्व-यूक्रेन युद्ध) स्तर के पास जाकर उनमें नरमी आ गई (चार्ट 3ए)। खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के अनुसार, मांस, वनस्पति तेल और डेयरी उत्पादों की कीमतों में गिरावट के कारण वैश्विक खाद्य कीमतों में 2022 की चौथी तिमाही में 3.1 प्रतिशत और 2023 की पहली तिमाही (फरवरी तक) में 1.5 प्रतिशत की कमी आई (चार्ट V.3बी)। अनाज की कीमतों में मामूली कमी आई जबकि चीनी के दामों में वृद्धि हुई।

कच्चे तेल की कीमतों में चौथी और पहली तिमाही के दौरान नरमी आई, लेकिन पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) द्वारा उत्पादन में कटौती की घोषणा के बाद निरंतर अस्थिरता के बीच अप्रैल की शुरुआत में इसमें वृद्धि हुई। हल्की सर्दी, यूरोप में कमजोर औद्योगिक गतिविधि, चीन में कोविड लॉकडाउन, और अमेरिका एवं कनाडा में सर्दियों के बर्फीले तूफान ने छुट्टियों में यात्रा को बाधित किया, जिससे 2022 की चौथी तिमाही में कच्चे तेल की मांग में गिरावट (वर्ष-दर-वर्ष) आई और कीमतें कम हुई (चार्ट V.3सी)। यूरोप में हल्की सर्दी और कमजोर आर्थिक गतिविधि के कारण प्राकृतिक गैस की कीमतें (विश्व बैंक के प्राकृतिक गैस सूचकांक के अनुसार) अगस्त 2022 और मार्च 2023 के बीच के अपने चरम स्तर से काफी हद तक नरम होकर 77 प्रतिशत रही (चार्ट V.3सी)।

पिछले छह महीनों में बेस मेटल की कीमतों में मामूली तेजी आई है, जो कमजोर अमरीकी डॉलर, इन्वेंट्री में गिरावट, चीनी अर्थव्यवस्था के फिर से खुलने और यूरोप में अनुमान से बेहतर

चार्ट V.3: पण्य कीमतें

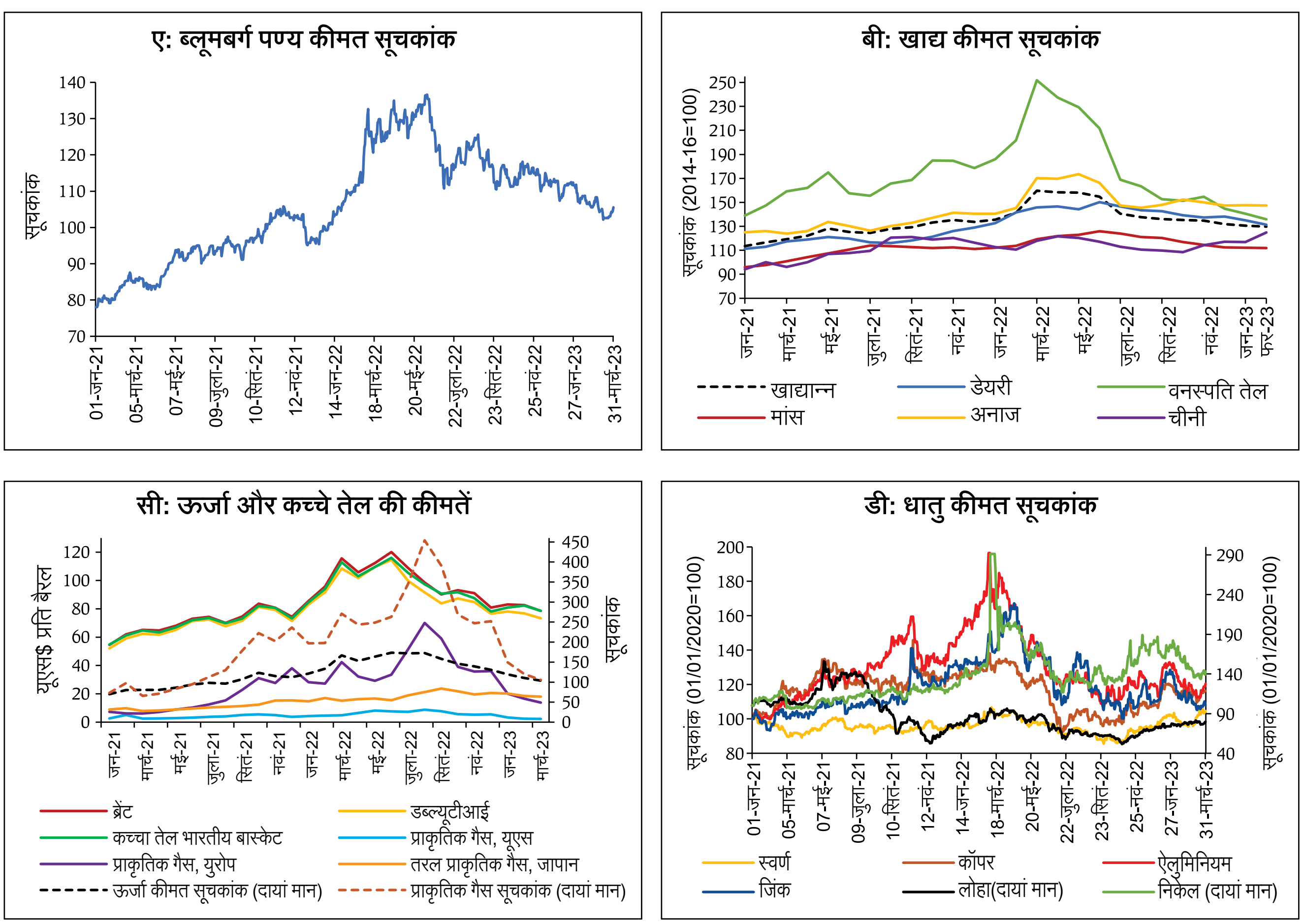

स्रोत: एफएओ; विश्व बैंक; ब्लूमबर्ग और पीपीएसी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार।

औद्योगिक वृद्धि को दर्शाती है। अमरीकी डॉलर के दो दशक के उच्च स्तर से नीचे आने और अमेरिका में बैंकों की विफलताओं के बीच सुरक्षित निवेश की मांग के कारण सोने की कीमतों में फिर से उछाल आया। अन्य धातुओं जैसे तांबा, एल्यूमीनियम, लोहा, निकिल, स्टील में भी 2022 की चौथी तिमाही और 2023 की पहली तिमाही के दौरान तेजी आई (चार्ट V.3डी)।

उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति

खाद्य और ऊर्जा की उच्च कीमतों से लागत में वृद्धि के दबाव और निरंतर कोर (प्रमुख) मुद्रास्फीति के दबाव के कारण अर्थव्यवस्थाओं में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति बढ़ी हुई है। हालांकि, ऊर्जा की कीमतों में नरमी, आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं में कमी, और मौद्रिक एवं राजकोषीय प्रोत्साहन में कमी के कारण यह अपने हाल के उच्चतम स्तर से नीचे आया है। हाल की नरमी के बावजूद, सभी एई और ईएमई में हेडलाइन मुद्रास्फीति लक्ष्य से काफी ऊपर बनी हुई है (सारणी V.3)। कोर मुद्रास्फीति की निरंतरता विशेष रूप से एई में सख्त श्रम बाजार और कम बेरोजगारी दर को दर्शाती है। आईएमएफ डब्ल्यूईओ (जनवरी 2023) के अनुसार, वैश्विक मुद्रास्फीति 2022 के 8.8 प्रतिशत से घटकर 2023 में 6.6 प्रतिशत और 2024 में 4.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो फिर भी महामारी पूर्व (2017-19) के 3.5 प्रतिशत के औसत से ऊपर है।

यूएस में, हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति जून 2022 के अपने 40 साल के उच्च स्तर 9.1 प्रतिशत से घटकर फरवरी 2023 में 6.0 प्रतिशत हो गई, जो ऊर्जा और खाद्य कीमतों की मुद्रास्फीति में गिरावट के कारण हुआ। इसी अवधि में, व्यक्तिगत उपभोग व्यय (पीसीई) मूल्य सूचकांक, जिसे फेडरल रिज़र्व (फेड) द्वारा मुद्रास्फीति मापने हेतु प्राथमिकता दी जाती है, के अनुसार मुद्रास्फीति 7.0 प्रतिशत से घटकर 5.0 प्रतिशत हो गया (चार्ट V.4ए), जबकि कोर पीसीई मुद्रास्फीति केवल मामूली रूप से घटकर 5.0 प्रतिशत से 4.6 प्रतिशत हुई (चार्ट V.4बी)।

यूरो क्षेत्र में, सीपीआई मुद्रास्फीति (उपभोक्ता कीमतों का सामंजस्यपूर्ण सूचकांक या एचआईसीपी) अक्तूबर 2022 में 10.6 प्रतिशत के अपने उच्चतम स्तर से घटकर मार्च 2023 में 6.9 प्रतिशत हो गई। हालांकि, इसी अवधि में अंतर्निहित उपाय सख्त हुए क्योंकि कोर मुद्रास्फीति (ऊर्जा, खाद्य, एल्कोहल और तंबाकू रहित मुद्रास्फीति) 5.0 प्रतिशत से बढ़कर 5.7 प्रतिशत हो गई और सेवा मुद्रास्फीति 4.3 प्रतिशत से बढ़कर 5.0 प्रतिशत हो गई। यूके में, परिवहन और रेस्तरां तथा होटलों में कम कीमत दबाव के कारण सीपीआई मुद्रास्फीति अक्तूबर 2022 के 11.1 प्रतिशत से घटकर फरवरी 2023 में 10.4 प्रतिशत हो गई। जापान में, ईंधन, बिजली और जल शुल्क के कारण सीपीआई मुद्रास्फीति जनवरी 2023 में 41 साल के उच्च स्तर 4.3 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो सितंबर 2022 में 3.0 प्रतिशत थी। यह फरवरी में घटकर 3.3 फीसदी हो गई।[4]

सारणी V.3: उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति

(वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)

देश	मुद्रास्फीति का लक्ष्य	ति1:2022	ति2:2022	ति3:2022	ति4:2022	ति1:2023
उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ						
कनाडा	2.0	5.8	7.5	7.2	6.7	5.6
यूरो क्षेत्र	2.0	6.1	8.0	9.3	10.0	8.0
जापान	2.0	0.9	2.5	2.9	3.8	3.8
दक्षिण कोरिया	2.0	3.8	5.4	5.9	5.2	5.0
यूके	2.0	6.2	9.2	10.0	10.8	10.3
यूएस	2.0	8.0 (6.4)	8.7 (6.6)	8.3 (6.3)	7.1 (5.7)	6.2 (5.2)
उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाएँ						
ब्राज़ील	3.25 ± 1.5	10.7	11.9	8.7	6.1	5.7
रूस	4.0	11.5	16.9	14.4	12.2	11.4
भारत	4.0 ± 2.0	6.3	7.3	7.0	6.1	6.5
चीन		1.1	2.2	2.7	1.8	1.6
दक्षिण अफ्रीका	3.0-6.0	5.8	6.6	7.6	7.4	7.0
मेक्सिको	3.0 ± 1.0	7.3	7.8	8.5	8.0	7.8
इंडोनेशिया	3.0 ± 1.0	2.3	3.8	5.2	5.5	5.4
फिलिपींन्स	3.0 ± 1.0	3.3	5.5	6.5	7.9	8.3
थाईलैंड	1.0-3.0	4.7	6.5	7.3	5.8	3.9
तुर्की	5.0 ± 2.0	54.8	74.0	81.1	78.1	54.5

मेमो:

	2021	2022(ई)	2023(पी)	2024(पी)
विश्व उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति	4.7	8.8	6.6	4.3

टिप्पणी : (1) अमरिका के कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े व्यक्तिगत उपभोग व्यय (पीसीई) मूल्य सूचकांक में वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन हैं।
(2) बैंक ऑफ कनाडा का लक्ष्य मुद्रास्फीति को 1:3 प्रतिशत की मुद्रास्फीति नियंत्रण लक्ष्य सीमा के 2 प्रतिशत मध्य-बिंदु पर रखना है।
(3) 2022 के लिए ब्राजील का मुद्रास्फीति लक्ष्य 3.50 ± 1.5 प्रतिशत था।
(4) ति1:2023 के लिए मुद्रास्फीति आकड़ें यूरो क्षेत्र को छोड़कर फरवरी 2023 तक है।

स्रोत: सेंट्रल बैंक वेबसाइट; और ब्लूमबर्ग।

[4] ताजा खाद्यों को छोड़कर सभी वस्तुओं में सीपीआई मुद्रास्फीति, जिससे बैंक ऑफ जापान द्वारा लक्ष्य मापा जाता है, जनवरी 2023 में बढ़कर 4.2 प्रतिशत हो गई, जो सितंबर 2022 में 3.0 प्रतिशत थी। यह फरवरी में घटकर 3.1 प्रतिशत हो गया।

चार्ट V:4: सीपीआई मुद्रास्फीति – चुनिन्दा अर्थव्यवस्थाएं

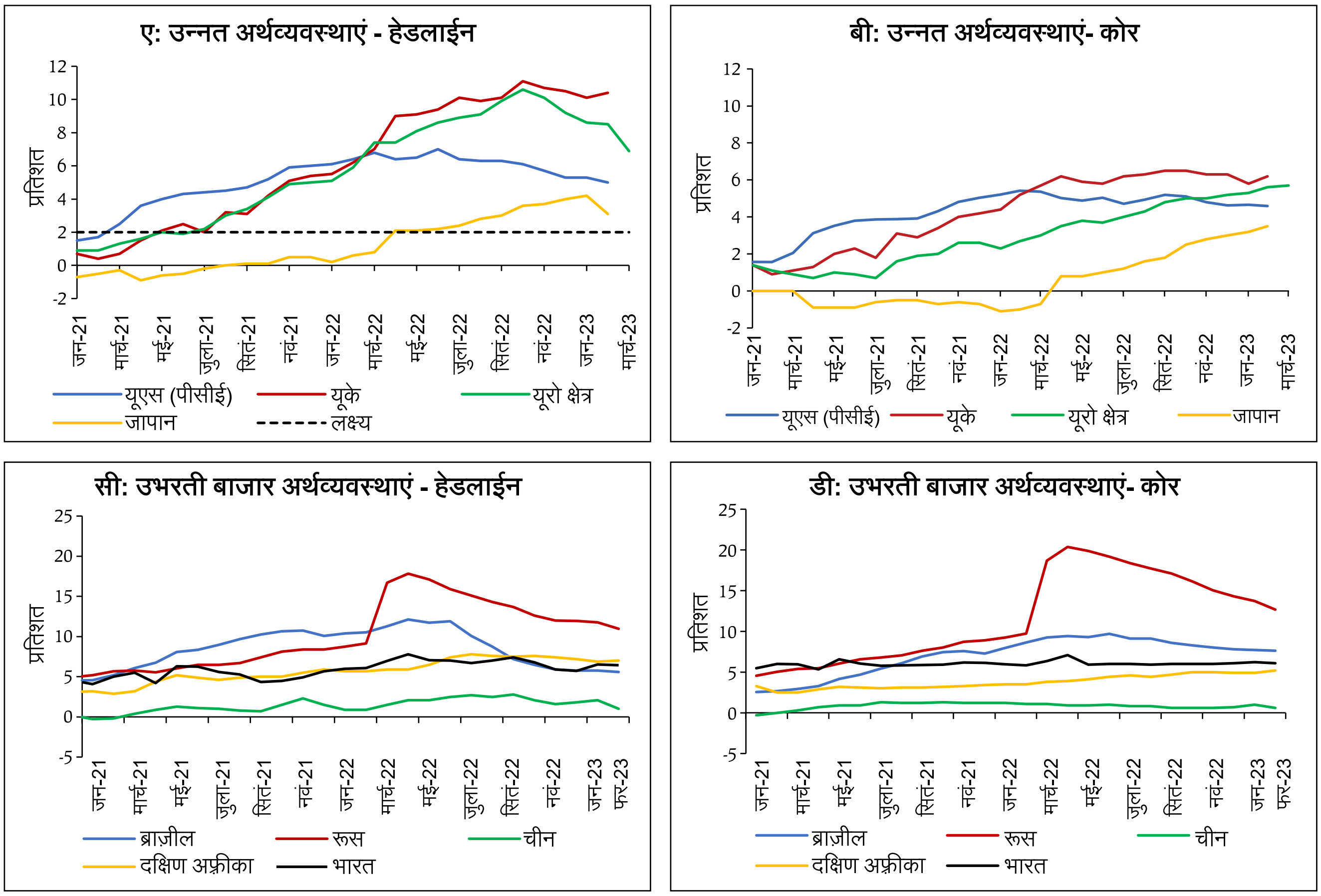

टिप्पणी: 1. भारत के लिए, कोर सीपीआई, यानी, भोजन और ईंधन को छोड़कर सीपीआई को हेडलाइन सीपीआई से 'खाद्य और पेय पदार्थ' और 'ईंधन और प्रकाश' समूहों को हटाकर काम किया जाता है।
2. चार्ट V.4ए में जापान का डेटा ताजा भोजन- बैंक ऑफ जापान का लक्ष्य उपाय छोडकर सभी वस्तुओं में सीपीआई मुद्रास्फीति को संदर्भित करता है , जबकि चार्ट V.4ब में डेटा ताजा भोजन और ऊर्जा को छोड़कर सीपीआई मुद्रास्फीति को संदर्भित करता है।

स्रोत: आधिकारिक सांख्यिकीय एजेंसियां; आरबीआई स्टाफ अनुमान; और ब्लूमबर्ग।

प्रमुख उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में देखें तो ब्राजील में सीपीआई मुद्रास्फीति सितंबर 2022 में दर्ज 7.2 प्रतिशत से नरम होकर फरवरी 2023 में 5.6 प्रतिशत पर आ गई (चार्ट V.4 सी)। रूस में, आंशिक रूप से मुद्रा की मजबूती के कारण यह सितंबर में दर्ज 13.7 प्रतिशत से घटकर फरवरी 2023 में 11.0 प्रतिशत हो गई। दक्षिण अफ्रीका में, सीपीआई मुद्रास्फीति सितंबर के 7.5 प्रतिशत से घटकर फरवरी 2023 में 7.0 प्रतिशत हो गई। चीन में, कमजोर मांग के कारण हेडलाइन मुद्रास्फीति सितंबर में दर्ज 2.8 प्रतिशत से गिरकर फरवरी 2023 में 1.0 प्रतिशत पर आ गई। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में कोर मुद्रास्फीति अपेक्षाकृत स्थिर रही (चार्ट V.4डी)।

V.3 मौद्रिक नीति रुख

यह देखते हुए कि हेडलाइन मुद्रास्फीति कम हो रही है, लेकिन धीमी गति से और अंतर्निहित मुद्रास्फीति दबाव लगातार उच्चतर बने हुए हैं, 2022 की चौथी तिमाही और 2023 की पहली तिमाही के दौरान केंद्रीय बैंकों ने 2022 की शुरुआती अवधि में दरों में कमतर वृद्धि या आक्रामक गति ने विराम की ओर रुख किया। हालांकि, बैंक की विफलताओं और बेल-आउट के बाद वित्तीय बाजार में उच्चतर अस्थिरता और वित्तीय स्थिरता संबंधी चिंताओं ने भविष्य की मौद्रिक नीति प्रक्षेपवक्र में अनिश्चितता जोड़ दी है।

मार्च 2022 से, यूएस फेड ने मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए अपनी बाद की सभी नीतिगत बैठकों में फेडरल फंड दर में वृद्धि की है। नवंबर 2022 में, यूएस फेड ने लक्ष्य सीमा में 75 बीपीएस की वृद्धि की, जो इसकी 75 बीपीएस की लगातार चौथी वृद्धि थी। इसने दिसंबर में 50 बीपीएस और फरवरी और मार्च 2023 - प्रत्येक में 25 बीपीएस की वृद्धि के साथ मौद्रिक सख्ती की गति को धीमा कर दिया। यूएस फेड ने मौद्रिक सख्ती के एक

वर्ष लंबे मौजूदा चरण में दरों में संचयी रूप से 475 बीपीएस की वृद्धि की है, जो 1980 के दशक के बाद से सबसे तेज गति रही। मार्च 2023 में जारी आर्थिक अनुमानों के सारांश के अनुसार, अधिकांश एफओएमसी प्रतिभागियों ने 2023 तक फेडरल फंड दर 5.0-5.25 प्रतिशत की सीमा में होने की उम्मीद की थी। बैंकिंग क्षेत्र में उथल-पुथल के मद्देनजर, मार्च में यूएस फेड ने बैंकों को उनके सभी जमाकर्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए चलनिधि प्रदान करने के लिए एक नई ऋण सुविधा- बैंक टर्म फंडिंग प्रोग्राम (बीटीएफपी) की घोषणा की। बीटीएफपी यूएस ट्रेजरी और अन्य योग्य आस्तियों सहित संपार्श्विक के बदले एक वर्ष तक का ऋण प्रदान करेगा, जिसका मूल्य समतुल्य होगा। इसके अतिरिक्त, बैंक ऑफ कनाडा, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान, यूरोपीय सेंट्रल बैंक और स्विस नेशनल बैंक के साथ फेडरल रिज़र्व ने 19 मार्च 2023 को स्टैंडिंग अमरीकी डॉलर चलनिधि स्वैप लाइन व्यवस्था के माध्यम से चलनिधि प्रावधान बढ़ाने के लिए एक समन्वित कार्रवाई की घोषणा की।

ईसीबी ने अक्तूबर 2022 में अपनी प्रमुख दर में 75 बीपीएस की वृद्धि की, जो लगातार दूसरी बार 75 बीपीएस की बढ़ोतरी है।[5] इसने दिसंबर 2022, फरवरी और मार्च 2023 - प्रत्येक में 50 बीपीएस बढ़ोतरी के साथ मौद्रिक सख्ती की गति को धीमा किया। ईसीबी ने दिसंबर 2022 की अपनी नीति में, मार्च 2023 की शुरुआत से अपने आस्ति खरीद कार्यक्रम (एपीपी) पोर्टफोलियो को 2023 की दूसरी तिमाही के अंत तक औसतन €15 बिलियन प्रति माह की गति से कम करने का भी निर्णय लिया, और कमी करने की अगली गति समय के साथ निर्धारित की जाएगी। हालाँकि, इसकी मंशा कम से कम 2024 के अंत तक अपने महामारी आपातकालीन खरीद कार्यक्रम (पीईपीपी) के तहत परिपक्व प्रतिभूतियों का पुनर्निवेश जारी रखने की है।

बैंक ऑफ इंग्लैंड (बीओई) ने नवंबर 2022 की बैठक में अपनी नीति दर में 75 बीपीएस की बढ़ोतरी की, इसके बाद दिसंबर और फरवरी 2023 - प्रत्येक में 50 बीपीएस और मार्च में 25 बीपीएस की बढ़ोतरी की। बीओई ने प्रारंभिक अक्तूबर 2022 की निर्धारित शुरुआत के बजाय 1 नवंबर को £80 बिलियन के स्टॉक कटौती कार्यक्रम के तहत अपनी गिल्ट बिक्री शुरू की। यह स्थगन सितंबर में यूके के वित्तीय बाजारों में उल्लेखनीय अस्थिरता के कारण किया गया था। बीओई ने व्यवस्थित बाजार स्थितियों को बहाल करने के लिए सितंबर 2022 में शुरू की गई £19 बिलियन की आपातकालीन बॉण्ड-खरीद योजना को भी समाप्त कर दिया।

अन्य प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में, बैंक ऑफ कनाडा ने अक्तूबर 2022 और दिसंबर की अपनी बैठकों में नीतिगत दर में 50-50 बीपीएस, जनवरी 2023 में 25 बीपीएस की बढ़ोतरी की और मार्च में यह बढ़ोतरी रोक दी। सितंबर में अपने नकद दर लक्ष्य को 50 बीपीएस तक बढ़ाने के बाद, ऑस्ट्रेलिया के रिज़र्व बैंक ने अक्तूबर, नवंबर, दिसंबर 2022, फरवरी और मार्च 2023 की अपनी बैठकों में हर बार 25 बीपीएस की कटौती करते हुए अपनी दर वृद्धि के आकार को सीमित कर दिया। नोर्गेस बैंक ने अपनी दर वृद्धि की गति को नवंबर 2022 से घटाकर 25 बीपीएस तक ला दिया जो उसकी पिछली बैठकों में 50 बीपीएस के स्तर पर था। बैंक ऑफ कोरिया ने मौद्रिक सख्ती के एक वर्ष के बाद, फरवरी 2023 में अपने दर वृद्धि चक्र को रोक दिया। चेक नेशनल बैंक ने 2022 में 325 बीपीएस की संचयी दर वृद्धि करने के बाद अगस्त 2022 से ठहराव बनाए रखा (चार्ट V.5ए)। बैंक ऑफ जापान ने अन्य उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से अलग हटते हुए, निभावकारी रुख बनाए रखा। इसने दिसंबर 2022 की अपनी नीतिगत बैठक में जापानी सरकार के 10-वर्षीय बॉण्ड प्रतिफल में उतार-चढ़ाव की सह्य-सीमा को विस्तारित करते हुए ± 0.25 प्रतिशत अंक से बढ़ाकर ± 0.5 प्रतिशत अंक कर दिया।

उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में, बैंको सेंट्रल डो ब्राजील ने सितंबर 2022 में ठहराव के बाद से अपनी नीतिगत दर को 13.75 प्रतिशत पर बनाए रखा। दक्षिण अफ्रीकी रिज़र्व बैंक ने नवंबर 2022 में अपनी नीतिगत दर में 75 बीपीएस, जनवरी 2023 में 25 बीपीएस और मार्च में 50 बीपीएस की वृद्धि की (चार्ट V.5बी)। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना (पीबीओसी) और बैंक ऑफ रूस (बीओआर) ने क्रमशः अगस्त और सितंबर में दरों में कटौती के बाद निभावकारी रुख बनाए रखा। पीबीओसी ने 27 मार्च

[5] नीतिगत दरों को बैंक उधार स्थितियों में समाहित करने और मूल्य स्थिरता बहाल करने के लिए, ईसीबी ने अपनी अक्तूबर की बैठक में ये निर्णय लिये: (ए) लक्षित दीर्घकालिक पुनर्वित्त संचालन (टीएलटीआरओ III) पर लागू ब्याज दर को समायोजित करना और उन्हें औसत लागू प्रमुख ईसीबी ब्याज दरों में अनुक्रमित करना और बैंकों को समय से पहले स्वैच्छिक पुनर्भुगतान तिथियों की पेशकश करना; (ख) न्यूनतम रिज़र्व पर लाभ, इसकी मुख्य पुनर्वित्त प्रचालन (एमआरओ) दर पर लाभ के स्थान पर, जमा सुविधा दर पर निर्धारित करना।

चार्ट V.5: नीति दर परिवर्तन - चुनिंदा अर्थव्यवस्थाएं

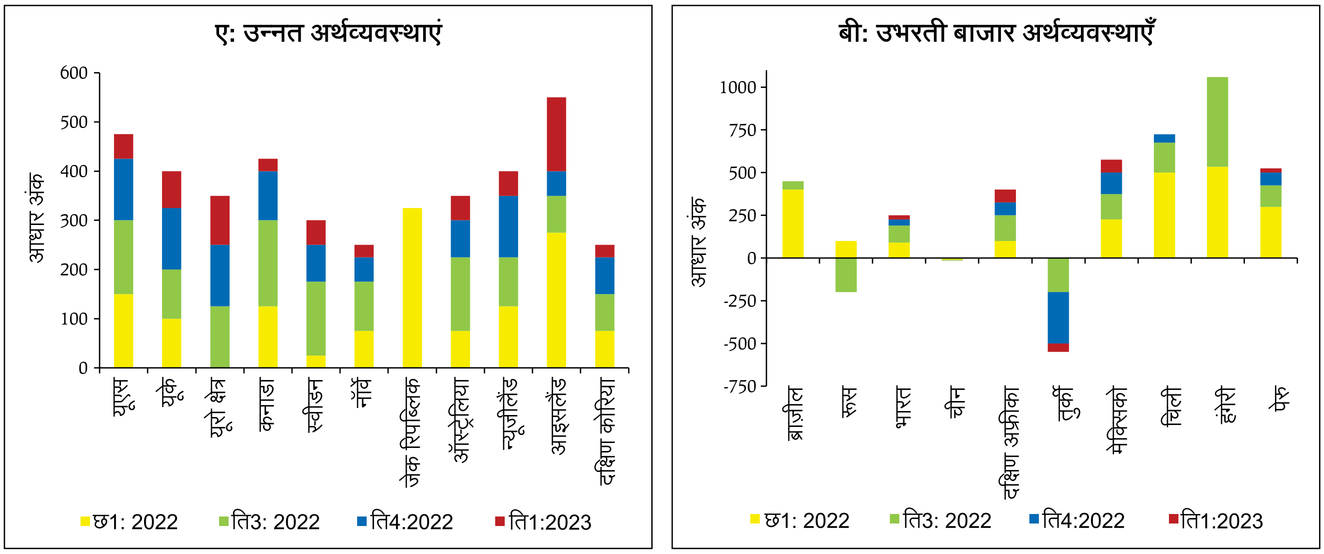

स्रोत: ब्लूमबर्ग।

2023 से वित्तीय संस्थानों के लिए अपेक्षित आरक्षित अनुपात (आरआरआर) को 25 बीपीएस घटा दिया।

एशिया की उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में, बैंक ऑफ थाईलैंड ने अगस्त 2022 में मौद्रिक सख्ती चक्र की शुरुआत की और इसके बाद की अपनी सभी बैठकों में 25 बीपीएस की दर-वृद्धि की। बैंक इंडोनेशिया ने अक्तूबर और नवंबर 2022- प्रत्येक में 50 बीपीएस और दिसंबर 2022 और जनवरी 2023- प्रत्येक से 25 बीपीएस की दर से वृद्धि की और फिर फरवरी में इसे रोक दिया। लैटिन अमेरिका में, मेक्सिको और कोलंबिया के केंद्रीय बैंकों ने मार्च में 25 बीपीएस की मौद्रिक सख्ती करते हुए अपनी गति धीमी कर दी, जबकि चिली और पेरू ने क्रमशः दिसंबर 2022 और फरवरी 2023 से इस पर विराम लगाकर रखा है। यूरोप की उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में, हंगरी ने अक्तूबर 2022 में अपने वृद्धि-चक्र को रोक दिया। दूसरी ओर, तुर्की के केंद्रीय बैंक ने अक्तूबर और नवंबर 2022 में अपनी प्रमुख नीति दर में 150 बीपीएस और फरवरी 2023 में 50 बीपीएस की कटौती की, जबकि वहाँ मार्च 2023 में मुद्रास्फीति 50.5 प्रतिशत पर रहते हुए लक्ष्य से काफी ऊपर थी।

V.4 वैश्विक वित्तीय बाजार

वैश्विक वित्तीय बाजारों में 2022 की चौथी तिमाही और 2023 की पहली तिमाही में बड़े उतार-चढ़ाव देखे गए, जो मुद्रास्फीति की अविचल स्थिति के बारे में बदलती हुई धारणाओं, आर्थिक गतिविधियों की मजबूती और मौद्रिक नीति पथ से संबंधित अपेक्षाओं से प्रेरित थे। 10 मार्च के बाद से, अमेरिका में कुछ बैंकों की विफलताओं के बाद वित्तीय स्थिरता की चिंताओं ने वैश्विक वित्तीय बाजारों में बड़ी अस्थिरता पैदा की है: बॉण्ड प्रतिफल गिर गए हैं; इक्विटी बाजारों में तेज सुधार हुआ है; और आगे मौद्रिक सख्ती की प्रत्याशाएँ दर में ठहराव/कटौती में परिणत हो गई।

इक्विटी बाजारों में, यूएस एस एंड पी 500 ने मुद्रास्फीति में कुछ गिरावट और मजबूत आर्थिक आंकड़ों के मद्देनजर यूएस फेड की कम आक्रामक कार्रवाइयों की प्रत्याशा में चौथी तिमाही और जनवरी माह में सामान्य रूप से बढ़त बनाई। फरवरी में, मजबूत अमरीकी गैर-कृषि पेरॉल और मजबूत मुद्रास्फीति आंकड़े जारी होने के बाद, और अधिक सख्ती और दरों के लंबे समय तक ऊंची बने रहने की चिंताओं को देखते हुए, बाजार में सुधार हुआ। मार्च में बैंक की विफलताओं के बाद सुधार जारी रहा। हालांकि, समग्र रूप से यूएस एस एंड पी इंडेक्स में अक्तूबर 2022 और मार्च 2023 के बीच 14.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। शिकागो बोर्ड ऑप्शंस एक्सचेंज वोलैटिलिटी इंडेक्स (सीबीओएक्स वीआईएक्स) बैंकों की विफलताओं की प्रतिक्रिया में 2023 में 13 मार्च को अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। यूरोपीय शेयर बाजार ने मंदी की कम होती चिंताओं और प्राकृतिक गैस की कीमतों में तेज गिरावट से लाभान्वित होने के कारण, अमरीकी बाजारों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया।

चार्ट V.6: इक्विटी बाजार

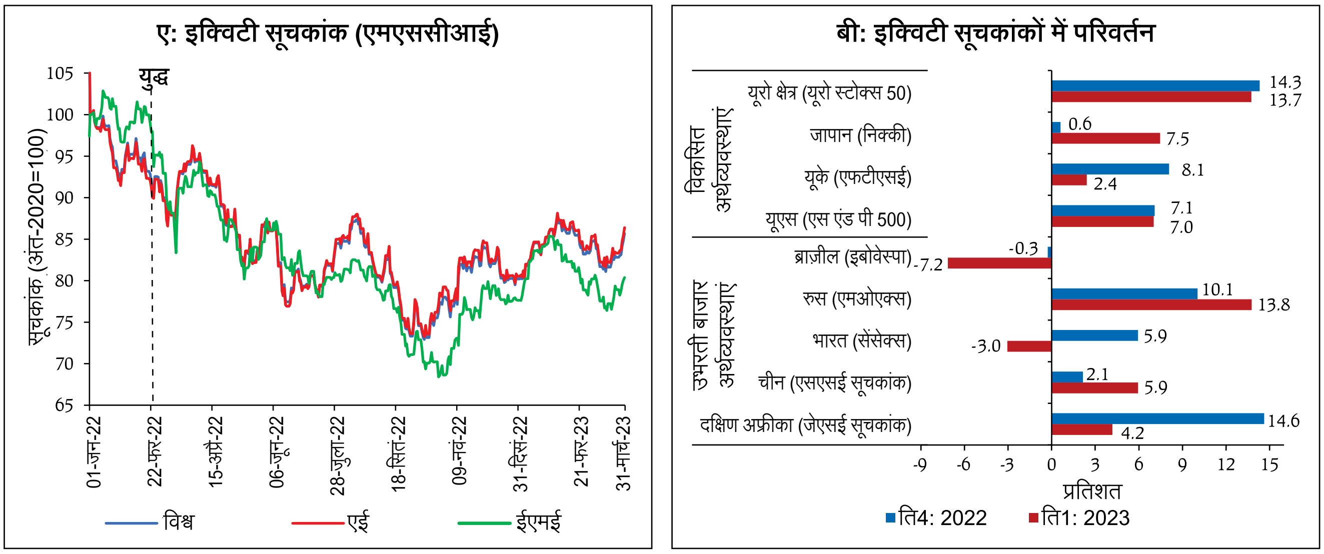

स्रोत: ब्लूमबर्ग; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

विकसित बाजारों के समान, ईएमई इक्विटी 2022 की चौथी तिमाही में लगभग 9 प्रतिशत बढ़ी। फेड की मौद्रिक नीति चक्र में बदलाव होने की प्रत्याशा के कारण 2023 की पहली तिमाही में, ईएमई इक्विटी बाजारों की तुलना में एई के इक्विटी बाजारों में तेजी से उछाल आया। पोर्टफोलियो बहिर्प्रवाह ने ईएमई की इक्विटी पर अधोगामी दबाव डाला (चार्ट V.6)। अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अमरीकी डॉलर की प्रमुख भूमिका को देखते हुए, अमरीकी मौद्रिक नीतिगत अप्रत्याशाओं का वैश्विक वित्तीय बाजारों पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है (बॉक्स V.1)।

बॉक्स V.1: अमरीकी मौद्रिक नीतिगत अप्रत्याशाएँ और वैश्विक वित्तीय बाजार

2022 में, यूएस फेडरल रिज़र्व ने 'लंबे समय तक उच्चतर' की भावी दिशा के साथ-साथ आक्रामक मौद्रिक सख्ती की, जिसने सभी क्षेत्रों और भौगोलिक क्षेत्रों में वित्तीय बाजारों को प्रभावित किया। अमरीकी मौद्रिक नीतिगत अप्रत्याशाओं को यूएस ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप दरों (ओआईएस) में बदलाव के द्वारा अनुमानित किया जा सकता है (लॉयड, 2018)। इस पृष्ठभूमि में, 3-महीने की ओआईएस दर में बदलाव से एक ब्याज दर अप्रत्याशा की पहचान की जाती है। एई और ईएमई दोनों के वैश्विक इक्विटी और बॉण्ड बाजारों पर इसका प्रभाव दैनिक डेटा का उपयोग करके तैयार किया गया है:

$$\Delta r_t = \alpha_0 + \alpha_1 surprise_t + \alpha_2 r_{t-1} + \alpha_3 \Delta vix_t + \alpha_4 \Delta sentiment_t + \varepsilon_t \quad \ldots(1)$$

जहां r_t इक्विटी या बॉण्ड इंडेक्स पर रिटर्न है (यूएस डॉलर के संदर्भ में); vix_t वैश्विक अस्थिरता को पकड़ने के लिए जेपी मॉर्गन वैश्विक एफएक्स अस्थिरता सूचकांक है; $sentiment_t$ वैश्विक रुख सूचकांक है; *surprise* 3-महीने के ओआईएस का इसके पिछले दिन के बंद होने से अंतर है। एमएससीआई वर्ल्ड, एई और ईएमई इक्विटी इंडेक्स क्रमशः संबंधित स्टॉक मार्केट के लिए इक्विटी रिटर्न की गणना के लिए उपयोग किए जाते हैं, जबकि एफटीएसई गवर्नमेंट और एफटीएसई इमर्जिंग मार्केट्स बॉण्ड इंडेक्स का उपयोग बॉण्ड पर रिटर्न की गणना के लिए किया जाता है।

अनुभवजन्य विश्लेषण, 2022 के दौरान अनुभव पर ध्यान केंद्रित करता है और इंगित करता है कि अस्थिरता और प्रचलित वैश्विक रुख को नियंत्रित करने के लिए एक अप्रत्याशित अमरीकी मौद्रिक सख्ती, वैश्विक इक्विटी के साथ-साथ बॉण्ड रिटर्न को कम करती है (सारणी V.1.1)। ईएमई के मामले में, उनके बॉण्ड बाजार अमरीकी मौद्रिक अप्रत्याशाओं के प्रति संवेदनशील हैं - अमेरिका के पक्ष में ब्याज दर में बढ़ते अंतर ईएमई ऋण आस्तियों को कम आकर्षक बना सकते हैं और पोर्टफोलियो प्रवाह को कम कर सकते हैं। इन परिस्थितियों में, असंभव त्रयी की बाधाओं और सुरक्षित निवेश स्थल की तलाश में चलायमान पूंजी प्रवाह के कारण मुद्रास्फीति प्रबंधन और जटिल हो जाता है (पात्रा, 2022)।

(जारी)

सारणी V.1.1: अमरीकी मौद्रिक नीतिगत अप्रत्याशाएँ और वैश्विक वित्तीय बाजार

चर	इक्विटी बाजार			बॉण्ड बाजार #	
	विश्व	एई	ईएमई	विश्व	ईएमई
अप्रत्याशा	-3.406*** (-3.75)	-3.936*** (-3.86)	-0.876 (-1.25)	-0.919** (-2.28)	-1.052*** (-2.85)
रिटर्न लैग 1	-0.148*** (-2.64)	-0.194*** (-3.55)	0.073 (1.42)	0.061 (1.00)	0.170* (1.83)
रिटर्न लैग 2	-0.151*** (-2.97)				
अस्थिरता सूचकांक में अंतर	-1.194*** (-4.23)	-1.282*** (-4.20)	-2.127*** (-6.76)	-0.084 (-0.63)	0.097 (0.77)
वैश्विक रुख सूचकांक में अंतर	8.720*** (-9.09)	8.355*** (8.65)	4.437*** (4.67)	0.541 (1.29)	0.343 (1.02)
स्थिरांक	-0.021 (-0.33)	-0.001 (-0.02)	-0.042 (-0.65)	-0.063 (-1.99)	0.007 (0.31)
समायोजित R^2	0.43	0.38	0.36	0.15	0.21
(एलएम टेस्ट (पी-मान)	0.49	0.10	0.74	0.88	0.09

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े टी-मानों (न्यूए-वेस्ट मानक त्रुटियों का उपयोग करके) को संदर्भित करते हैं।
***, **, * क्रमशः 1%, 5% और 10% पर महत्व के स्तर को दर्शाता है।
#: विक्षेपों (आउटलायर्स) को नियंत्रित करने के लिए प्रतिगमन में डमी चर शामिल हैं।
स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान।

संदर्भ:

लॉयड, एस.पी. (2018), “ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप मार्केट-बेस्ड मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेक्टेशंस”, बैंक ऑफ इंग्लैंड स्टाफ वर्किंग पेपर नंबर 709।

पात्रा, एम. डी. (2022), “डॉ. माइकल देवव्रत पात्रा का वक्तव्य”, मौद्रिक नीति समिति की बैठक के कार्यवृत्त, 28-30 सितंबर, 2022, भारतीय रिज़र्व बैंक।

चौथी तिमाही में, मुद्रास्फीति के दबाव में कमी और कम आक्रामक दर वृद्धि की प्रत्याशाओं के संकेत पाकर प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में सरकारी बॉण्ड प्रतिफल नवंबर में नरम हो गये। हालाँकि, बैंक ऑफ जापान द्वारा 10 साल के जापानी सरकारी बॉण्ड प्रतिफल में उतार-चढ़ाव के लिए अपनी सह्य-सीमा को ± 0.5 प्रतिशत अंक तक बढ़ा देने के साथ, दिसंबर 2022 में प्रतिफल बढ़ गये। 2023 की पहली तिमाही में, सभी देशों में मुद्रास्फीति में कमी के कारण जनवरी में प्रतिफल में नरमी आई।

चार्ट V.7: 10-वर्षीय सरकारी बॉण्ड प्रतिफल

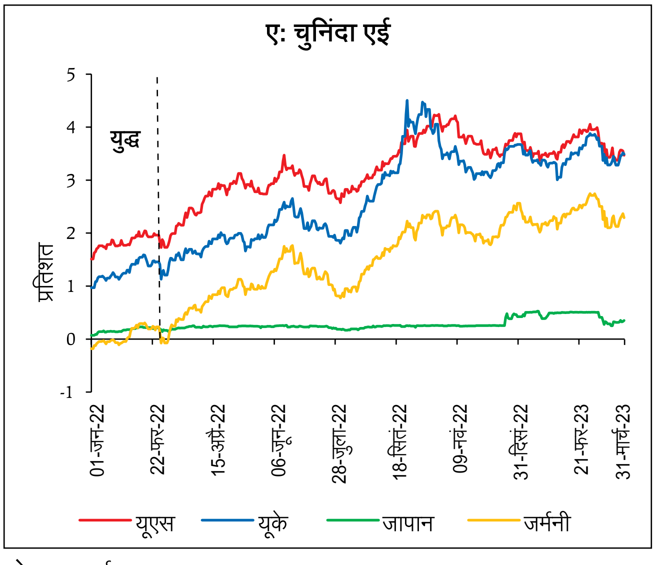

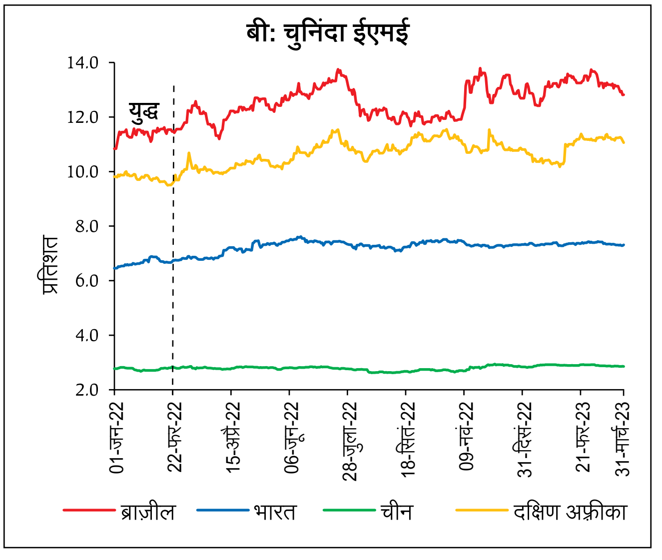

स्रोत: ब्लूमबर्ग।

चार्ट V.8: मुद्रा उतार-चढ़ाव और पूंजी प्रवाह

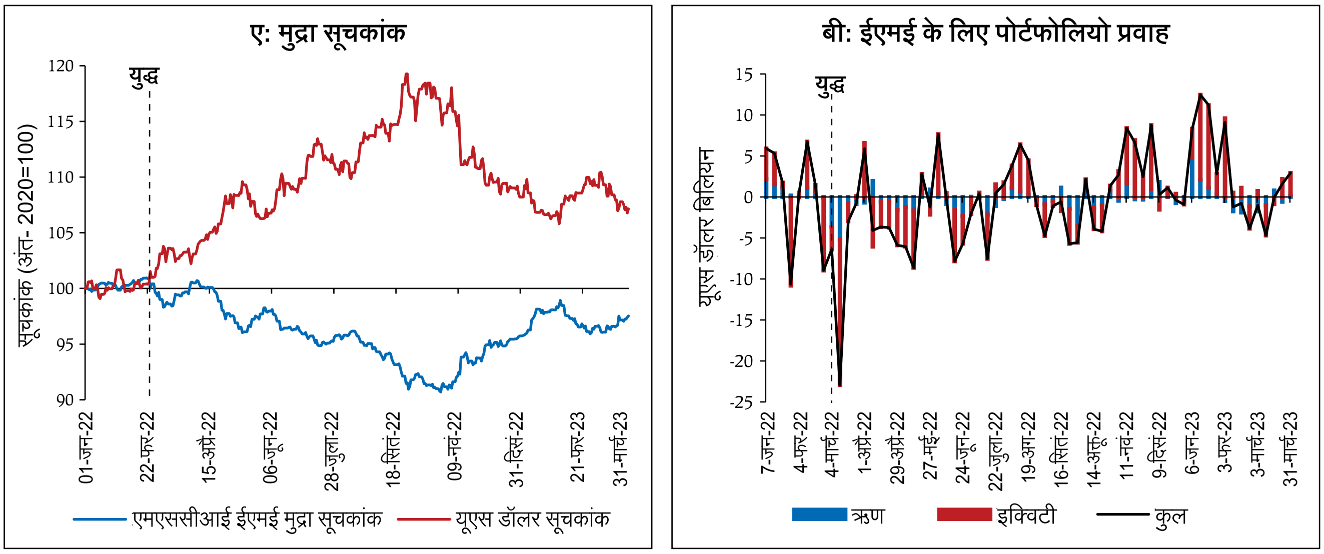

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थान।

हालांकि, स्थिर मुद्रास्फीति और मजबूत अमरीकी खुदरा बिक्री और गैर-कृषि पेरॉल लाभ दर्शाने वाले आंकड़ों के कारण फरवरी में प्रतिफल तेजी से ऊपर चढ़ा। मार्च में प्रतिफल में तेजी से गिरावट आई क्योंकि बैंकों की विफलताओं के कारण वित्तीय बाजार में आई उथल-पुथल से निवेशक घबरा गए और अपेक्षाकृत ज्यादा सुरक्षित आस्तियों की ओर बढ़ गए (चार्ट V.7ए)। मंदी की चिंताओं और मौद्रिक नीति चक्र में बदलाव की प्रत्याशाओं के कारण प्रतिफल वक्र चौथी तिमाही और पहली तिमाही में उलटा रहा। यूके और जर्मन 10-वर्षीय बॉण्ड प्रतिफल ने अमरीकी बाजारों का अनुसरण किया। दिसंबर में जापानी बॉण्ड प्रतिफल दायरे के भीतर रहे, जो बैंक ऑफ जापान की सह्य-सीमा में ऊर्ध्वमुखी समायोजन को रोकने वाली प्रतिफल वक्र नियंत्रण नीति को दर्शाता है। ईएमई में बॉण्ड प्रतिफल ने, घरेलू मौद्रिक सख्ती और वैश्विक संकेतों से प्रेरित होकर, सख्ती की ओर झुकाव के साथ, दो-तरफा उतार-चढ़ाव प्रदर्शित किया (चार्ट V.7बी)। मौद्रिक समायोजन के बावजूद चीनी बॉण्ड प्रतिफल मामूली रूप से मजबूत हुआ।

मुद्रा बाजारों की बात करें तो, अमरीकी डॉलर ने, सितंबर 2022 में दो दशक के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद- फेड द्वारा अपनी आक्रामक नीतिगत सख्ती से हटने की प्रत्याशा में- अक्तूबर में अपनी बढ़त को उलट दिया (चार्ट V.8ए)। हालांकि, तंग श्रम बाजार की स्थितियों और अपेक्षा से अधिक मजबूत मुद्रास्फीति के आंकड़ों ने बाजार को यह आकलन करने के लिए प्रेरित किया कि सख्ती का चक्र लंबे समय तक चल सकता है, और फरवरी में ग्रीनबैक को मजबूत कर सकता है। मार्च में अमरीकी डॉलर में गिरावट आई क्योंकि बैंकों की विफलताओं ने वित्तीय स्थिरता की चिंताएँ और ऐसी प्रत्याशाएँ उत्पन्न कर दीं कि फेड को अपने सख्ती चक्र को उलटने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। अमरीकी डॉलर का उतार-चढ़ाव ईएमई मुद्राओं में प्रतिबिंबित हुआ, जिसमें पूंजी के बहिर्वाह के कारण अस्थिरता और बढ़ गई थी (चार्ट V.8बी)। एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट करेंसी इंडेक्स 2022 की चौथी तिमाही में 4.3 प्रतिशत और 2023 की पहली तिमाही में 1.9 प्रतिशत बढ़ा।

V.5 निष्कर्ष

वैश्विक विकास परिदृश्य के प्रति जो जोखिम हैं उनका रुख और जोखिम की तरफ झुका दिखाई देता है। हाल के वित्तीय स्थिरता जोखिमों और वैश्विक प्रभाव-प्रसारों ने आर्थिक परिदृश्य के लिए उल्लेखनीय अनिश्चितता उत्पन्न कर दी है क्योंकि नीति-निर्माता एक ओर स्थिर मुद्रास्फीति और दूसरी ओर वित्तीय स्थिरता जोखिमों से जूझ रहे हैं। इन गतिविधियों से वैश्विक वित्तीय बाजारों में बड़ी अस्थिरता आ रही है और पूंजी प्रवाह, मुद्रा के उतार-चढ़ाव और बॉण्ड प्रतिफल में अस्थिरता के कारण उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं पर वृहद प्रतिकूल प्रभाव-प्रसार पैदा हो रहे हैं, जिससे उनकी विकास संभावनाओं के अधोगामी होने के प्रति जोखिम खड़े हो रहे हैं।

भाषण

विकसित भारत के लिए एक सहायक के रूप में वित्तीय क्षेत्र

*विकसित भारत के लिए एक सहायक के रूप में वित्तीय क्षेत्र**

एम. राजेश्वर राव

आप सभी को शुभ संध्या। त्रिशूर मैनेजमेंट एसोसिएशन के 31 वें वार्षिक प्रबंधन सम्मेलन में भाग लेने के लिए यहां आना वास्तव में खुशी की बात है।

जैसा कि सुकरात ने एक बार कहा था, "एकमात्र सच्चा ज्ञान यह जानने में है कि आप कुछ भी नहीं जानते हैं।" तीन साल पहले, हमें नहीं पता था कि हम अपने जीवनकाल की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक का सामना करेंगे - एक महामारी जो हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करेगी और हमें अज्ञात, अप्रत्याशित और अनदेखी अशांति के बीच से गुजरने के लिए मजबूर करेगी। महामारी की शुरुआत के तीन साल बाद, जब हम अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं, तो यह कोविड-19 के समय की चुनौतियों और प्रतिक्रियाओं को याद करने के साथ-साथ सीखे गए कुछ सबब का जायजा लेने का एक उपयुक्त समय हो सकता है।

सबसे पहले दिमाग में यह बात आती है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान देखी गई अनिश्चितता और उथल-पुथल इस वर्तमान पीढ़ी के लिए पहली बार हुई है। अनुभवों, चुनौतियों और प्रतिक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, मैं महामारी के बाद, वैश्विक और साथ ही, हमारे देश के आर्थिक सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए शुरू करता हूं और उसके बाद, संक्षेप में, वित्तीय दुनिया में महामारी द्वारा लाए गए परिवर्तनों और इस परिवर्तन का भारतीय विकास की कहानी से क्या मतलब है, इस पर अपने विचार संक्षेप में रखता हूं।

अर्थव्यवस्था की बहाली और पुनरुद्धार

कोविड से प्रेरित तनाव किसी भी अन्य तनाव जिसे दुनिया ने पहले देखा है, से अलग था। महामारी तेजी से फैली और उसने दुनिया के लगभग हर देश को प्रभावित किया। वित्तीय नियामकों के लिए, यह स्थिति एक पाठ्यक्रम से बाहर के विषय जैसी थी क्योंकि इस बार आर्थिक तनाव अंतर्निहित आर्थिक असंतुलन या वित्तीय बाजार की विफलताओं के कारण नहीं था, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के कारण था। उसने यह एक अनूठा झटका साबित किया, क्योंकि इसने अर्थव्यवस्था के आपूर्ति और मांग दोनों पक्षों को प्रभावित किया, जिससे उत्पादन और खपत दोनों प्रभावित हुए। इसका असर यह हुआ कि 2020 में वैश्विक जीडीपी में 3.5 प्रतिशत[1] की गिरावट आई । वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 5.8 प्रतिशत[2] की गिरावट आई जिससे यह देश के इतिहास में सबसे खराब आर्थिक संकुचन साबित हुआ। मंदी अत्यधिक समकालिक थी - यहां तक कि 1930-32[3] की महामंदी की पराकाष्ठा पर मंदी में घिरे लगभग 85 प्रतिशत देशों के अनुपात से भी ज्यादा, 90 प्रतिशत से अधिक अर्थव्यवस्थाओं में मंदी देखी गई।

दुनिया भर की सरकारों और केंद्रीय बैंकों ने व्यक्तियों, व्यवसायों और वित्तीय बाजारों का समर्थन करने के लिए पारंपरिक और अपरंपरागत दोनों तरह के अभूतपूर्व राजकोषीय और मौद्रिक नीति उपायों के साथ प्रतिक्रिया दी। इसमें बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन पैकेज, मात्रात्मक सहजता, और ऋण प्रवाह और आर्थिक गतिविधि को बनाए रखने के लिए अन्य उपाय शामिल थे। आईएमएफ के अनुमानों के अनुसार, 2021 के मध्य तक, कोविड के जवाब में वैश्विक आर्थिक प्रोत्साहन 16 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें अतिरिक्त सरकारी खर्च, राजस्व का नुकसान और तरलता उपाय[4] शामिल हैं, जो वैश्विक जीडीपी के लगभग 20 प्रतिशत के बराबर है।

कोविड-19 महामारी के प्रभाव से निपटने और आर्थिक विकास को पुनर्जीवित करने के लिए, भारत ने लगभग 27.1 लाख करोड़ रुपये – भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 13 प्रतिशत से अधिक[5] के विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज की घोषणा की ।

* भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर श्री एम. राजेश्वर राव द्वारा 22 मार्च, 2023 को त्रिशूर मैनेजमेंट एसोसिएशन के 31 वें वार्षिक प्रबंधन सम्मेलन दिया गया मुख्य भाषण - चंदन कुमार, प्रदीप कुमार और प्रमांशु राजपूत द्वारा प्रदान किए गए इनपुट को कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार किया जाता है।

[1] आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट, जनवरी 2021।

[2] सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकडे https://www.mospi.gov.in/data पर उपलब्ध हैं।

[3] अध्याय 1, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21।

[4] कोविड-19 महामारी के जवाब में देश के राजकोषीय उपायों का आईएमएफ राजकोषीय निगरानी डेटाबेस, अक्टूबर 2021।

[5] https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1693907

डब्ल्यूएचओ द्वारा कोविड को महामारी घोषित किए जाने के कुछ दिनों के भीतर रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए विभिन्न उपाय सरकार के कार्यकलापों के पूरक बने । रेपो दर को संचयी रूप से 115 बीपीएस (मार्च और मई 2020 के बीच) घटाया गया था और सीआरआर को 27 मार्च, 2020 को एक वर्ष के लिए 1 प्रतिशत अंक कम किया गया था, ताकि तत्काल चलनिधि की बाधाओं को कम किया जा सके। प्रणालीगत चलनिधि को और बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक रेपो संचालन (एलटीआरओ) और लक्षित दीर्घकालिक रेपो संचालन (टीएलटीआरओ) शुरू किए गए थे।

महामारी से राहत प्रदान करने के लिए नियामक उपायों के एक जांच-परखे सेट की भी घोषणा की गई। इन उपायों में छह महीने के लिए सावधि ऋणों पर अधिस्थगन, नकद ऋण/ओवरड्राफ्ट के रूप में स्वीकृत कार्यशील पूंजी सुविधाओं पर ब्याज आस्थगिति, कार्यशील पूंजी वित्तपोषण का सरलीकरण आदि शामिल थे।

सरकार और आरबीआई द्वारा किए गए उपायों ने महामारी के प्रतिकूल प्रभावों से अर्थव्यवस्था को सहारा देने में मदद की और अशांति के दौरान व्यवसायों और व्यक्तियों का समर्थन करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता का भी प्रदर्शन किया। अर्थव्यवस्था को चलनिधि सहायता प्रदान करने के लिए आरबीआई के उपायों ने वित्तीय बाजारों के सामने आनेवाली धन बाधाओं को कम करने में मदद की और उन्हें अपने परिचालन को जारी रखने और अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में सक्षम बनाया, जिससे आर्थिक गतिविधि का समर्थन हुआ। कमजोर वर्गों और अर्थव्यवस्था के सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों को राहत प्रदान करने के लिए सरकार की प्रेरणा ने यह सुनिश्चित किया कि उनकी तत्काल चिंताओं को दूर किया जाए। अगले वर्ष, यानी वित्त वर्ष 2022 में, जनवरी 2022 की ओमीक्रॉन लहर के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार आना शुरू हो गया। नतीजतन, वित्त वर्ष 2022 में उत्पादन वित्त वर्ष 2020[6] के अपने पूर्व-महामारी के स्तर को पार कर गया, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था ने प्रभावशाली सुधार दर्ज किया।

जहां भारत और दुनिया महामारी से उबरने की उम्मीद कर रहे थे, यूरोप में भू-राजनीतिक उथल-पुथल ने मौजूदा महामारी से संबंधित तनाव को बढ़ा दिया, विशेष रूप से वस्तुओं के बाजारों को बाधित किया। उथल-पुथल के कारण कीमतों में वृद्धि हुई तथा ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक, प्राकृतिक गैस और धातु की कीमतों में अस्थिरता आई, जिससे दुनिया भर में मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई। पण्य बाजार पर प्रभाव का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि मार्च 2022 तक कीमतों में साल-दर-साल वृद्धि प्राकृतिक गैस के लिए 400 प्रतिशत, कोयले के लिए 250 प्रतिशत, कच्चे तेल के लिए 76 प्रतिशत, खाद्य के लिए 30 प्रतिशत और उर्वरकों के लिए लगभग 120 प्रतिशत थी।[7] इन बढ़ी हुई कीमतों ने कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में कई दशकों की उच्च मुद्रास्फीति को जन्म दिया। यूरो क्षेत्र, जर्मनी और ब्रिटेन[8] में मुद्रास्फीति 10 प्रतिशत तक पहुंच गई। भारत में भी मुद्रास्फीति अप्रैल 2022 में 7.8 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो दिसंबर 2022 में घटकर 5.7 प्रतिशत हो गई। [9]

अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नेतृत्व में सभी अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय बैंकों ने उच्च मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए समन्वित नीतिगत दरों में वृद्धि की। मई 2022 के बाद से, अमेरिका ने नीतिगत दरों में 450 बीपीएस की वृद्धि की है, जबकि यूके और यूरोपीय संघ ने दरों में 300 बीपीएस की वृद्धि की है।

यूरोप में संघर्ष के कारण वित्त वर्ष 2023 में आर्थिक विकास और मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं में संशोधन की आवश्यकता थी। गिरावट के बावजूद, भारत के लिए वित्त वर्ष 2023 के लिए विकास अनुमान लगभग सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक है। आईएमएफ का अनुमान है कि भारत 2022 में शीर्ष दो तेजी से बढ़ती महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। लंबी वैश्विक चुनौतियों और सख्त मौद्रिक परिस्थितियों के बावजूद, भारत से अभी भी एक स्वस्थ विकास प्रदर्शित करने की उम्मीद है और यह भारत के अंतर्निहित आर्थिक लचीलेपन और अर्थव्यवस्था के विकास चालकों की पुनः प्राप्ति, नवीकरण और उन्हें फिर से सक्रिय करने की हमारी क्षमता का प्रमाण है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा 6 जनवरी, 2023 को जारी पहले अग्रिम अनुमान (एफएई) में 2022-23 के लिए भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि

[6] सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकडे https://www.mospi.gov.in/data पर उपलब्ध हैं।

[7] आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23।

[8] आईएमएफ, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23।

[9] मौद्रिक नीति समिति के कार्यवृत्त दिसं -22, फ़रवरी-23।

दर 7.0 प्रतिशत बताई गई है, जो निजी खपत और निवेश से प्रेरित है।

दिसंबर 2022 में बैंक ऋण वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) 16.8 प्रतिशत रही, जो एक साल पहले 8.4 प्रतिशत थी। दिसंबर 2022 में कुल जमा में 10.3 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई, जबकि एक साल पहले यह 9.6 प्रतिशत थी, जिसमें सावधि जमा में 13.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई।[10] सरकार ने व्यय मिश्रण को फिर से प्राथमिकता देकर केंद्रीय बजट 2023-24 में राजकोषीय समेकन के रास्ते पर चलना जारी रखा है। चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है और अगले वित्त वर्ष में यह घटकर 5.9 प्रतिशत होने की संभावना है। जनवरी 2023 में मासिक जीएसटी संग्रह 1.5 लाख करोड़ रुपये को पार करने के साथ, कर राजस्व में उछाल बना हुआ है।[11]

यह भारत को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनाता है और आज हमें 'अंधेरे क्षितिज पर उज्ज्वल स्थान' के रूप में जाना जाता है। अपनी बात के पहले भाग को समाप्त करने के लिए, मैं कहूंगा कि वास्तव में, पिछले तीन वर्षों में व्याप्त चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बीच, भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली ने उल्लेखनीय लचीलापन और सामर्थ्य दिखाया है।

नए क्षितिज, साझेदारी और प्राथमिकताएं

आगे बढ़ते हुए, मैं पिछले कुछ वर्षों के दौरान और विशेष रूप से कोविड अवधि के दौरान भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की परिवर्तनकारी यात्रा और कैसे यह भारतीय विकास की कहानी का समर्थन करने के लिए तैयार है, इस पर ध्यान केंद्रित करता हूं।

पिछले दशक में देश में बैंकिंग की महत्वपूर्ण पैठ देखी गई है। प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत अब तक 48.20 करोड़ लाभार्थी खाते खोले गए हैं और इन खातों में 1.89 लाख करोड़ रुपये की बकाया राशि है।[12] जून 2022 तक, 1.6 लाख से अधिक बैंक शाखाएं हैं, यानी प्रति 1 लाख आबादी पर लगभग 15 शाखाएं हैं। इसके अलावा, 217 लाख एटीएम[13] का नेटवर्क भी है, जिनमें से 47 प्रतिशत ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं। इसके अतिरिक्त, बैंकों द्वारा लगभग 32 लाख बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट (बीसी)[14] कार्यरत हैं जो अंतिम छोर तक पहुंच प्रदान करते हैं। 2021 तक, 78 प्रतिशत भारतीय वयस्कों (15 वर्ष या उससे अधिक आयु की आबादी) के पास बैंक खाते थे, जबकि 2014 में यह आंकड़ा 53 प्रतिशत था।[15] 25 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में 5 किलोमीटर के दायरे में हर गांव के लिए 15 बैंकिंग सेवाएं सुलभ बनाई गई हैं, जो 99.94 प्रतिशत गांवों को कवर करती हैं।[16]

इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम भी हुए हैं, जिन्हें कोविड के दौरान बढ़ावा मिला। **पहली महत्वपूर्ण गतिविधि वित्त में प्रौद्योगिकी का बढ़ता उपयोग है**। वित्त में प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण साधन रही है जिसने हमें अधिक समावेशी और कुशल वित्तीय पारितंत्र बनाने के लिए सशक्त बनाया है। बैंक पिछले कुछ समय से तकनीकी समाधानों का उपयोग करके अपनी सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच में नवाचार और वृद्धि कर रहे हैं। हालांकि, कोविड अवधि के दौरान इसमें तेजी आई जब गतिशीलता एक चुनौती बन गई और प्रौद्योगिकी हमारी सभी बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए बचाव में आई। परिस्थितियों की मांग ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अपनी व्यावसायिक प्रक्रियाओं पर पुनर्विचार करने और अपनी रणनीतियों की समीक्षा करने के लिए मजबूर किया। रिज़र्व बैंक ने वीडियो केवाईसी के उपयोग जैसे उचित दिशानिर्देश जारी करके बैंकों और वित्तीय संस्थानों को भी इस यात्रा में सुविधा प्रदान की। हालांकि, यह सब हमारे देश द्वारा इंडिया स्टैक के साथ जनधन - आधार - मोबाइल, तथाकथित जैम ट्रिनिटी, अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क और अन्य डिजिटल पहलों जैसे एक सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण में उठाए गए विशाल कदमों के माध्यम से संभव हुआ, इसने देश को डिजिटल वित्त युग में निर्णायक प्रवेश करने में सक्षम बनाया। दायरा, सार्वजनिक पहुंच और व्यापकता इंडिया स्टैक को अद्वितीय बनाते है, इसने एक अधिक समावेशी डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने में मदद की है।

मेरी नजर में, इस अवधि के दौरान दूसरी महत्वपूर्ण गतिविधि फिनटेक कंपनियों और बैंकों के बीच नई साझेदारी

[10] एससीबी के जमा और ऋण पर आरबीआई के त्रैमासिक आंकड़े: दिसंबर 2022।

[11] केंद्रीय बजट 2023-24।

[12] मार्च 2023 तक https://www.pmjdy.gov.in ।

[13] आरबीआई के आंकड़े https://www.rbi.org.in/Scripts/ATMView.aspx?atmid=136 पर उपलब्ध हैं।

[14] आरबीआई वार्षिक रिपोर्ट 2021-22।

[15] विश्व बैंक का ग्लोबल फिनडेक्स डेटाबेस।

[16] पूर्वोक्त।

का उद्भव थी। बैंकों को बेहतर उत्पाद प्रदान करने और अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए विभिन्न तरीकों से फिनटेक के साथ तकनीकी साझेदारी का लाभ उठाते हुए देखा जाता है। इस साझेदारी में, फिनटेक अपनी प्रौद्योगिकी विशेषज्ञता का योगदान कर सकते हैं, जबकि बैंक अपनी डोमेन विशेषज्ञता लाते हैं। चैटबॉट्स, मोबाइल ऐप और व्यक्तिगत डिजिटल समाधान जैसी तकनीकों का लाभ उठाकर, बैंक ग्राहकों को अधिक सुविधाजनक और सहज बैंकिंग अनुभव प्रदान कर सकते हैं। यह सहयोग बैंकों को अपनी डिजिटल क्षमताओं को बढ़ाने और तकनीक-प्रेमी ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करने की अनुमति देता है।

हम सभी ने महसूस किया है या अनुभव किया है कि महामारी के बाद की दुनिया में, डिजिटल ऋण तेजी से बढ़ा है, जिसमें भारत भी शामिल है, जिससे क्रेडिट के पैमाने और गति दोनों में वृद्धि हुई है। हालांकि, एक ही समय में इसने कई व्यावसायिक संचालन समस्याओं को भी जन्म दिया है। यह नियामक के रूप में एक नियामक दुविधा पैदा करता है क्योंकि तब नियामक को एक तरफ अभिनव व्यापार मॉडल द्वारा लाए गए लाभों और दूसरी तरफ उभरते व्यावसायिक आचरण और नियामक चिंताओं को तौलने में संतुलन रखने की आवश्यकता होती है। रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल ऋण पर सिद्धांत आधारित दिशानिर्देश जारी कर इस मुद्दे को हल करने का प्रयास किया गया है।

तीसरी महत्वपूर्ण गतिविधि समावेशिता के महत्व पर हमारा ध्यान केन्द्रित करना था। निराशाजनक समय ने हमें याद दिलाया कि उचित समय पर एक छोटी सी मदद भी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए दुनिया में बदलाव ला सकती है। इसलिए, रिज़र्व बैंक ने एक समावेशी वित्तीय प्रणाली के निर्माण की दिशा में अपने प्रयासों को तेज कर दिया है जहां वित्तीय सेवाओं तक पहुंच केवल एक मूल बैंक खाते तक सीमित नहीं है, बल्कि हर किसी के पास क्रेडिट के औपचारिक चैनलों तक पहुंच है और वे हर किसी को, हर जगह, हर समय डिजिटल भुगतान करने के लिए अपने बैंकिंग खाते का उपयोग करने में सक्षम हैं। दर्शकों को इस तथ्य के बारे में पता होना चाहिए कि आज भारत की भुगतान प्रणाली हमारी रियल टाइम फास्ट रिटेल पेमेंट सिस्टम, यूपीआई के साथ दुनिया में सर्वश्रेष्ठ में से एक है, जो मूल्य में प्रति माह लगभग 12 लाख करोड़ रुपये के लेनदेन और दैनिक मात्रा में लगभग 26 करोड़ लेनदेन करने में सक्षम है।

अगली चीज जो क्रेडिट बाजारों में क्रांति ला सकती है, वह क्रेडिट निर्णय है जो वित्तीय और साथ ही, वैकल्पिक डेटा की उपलब्धता के माध्यम से सूचित किए जाते हैं। डेटा विश्लेषिकी का लाभ उठाकर, वित्तीय संस्थान ग्राहक व्यवहार, बाजार के रुझान और उभरते जोखिमों में गहरी पहुँच प्राप्त करने में सक्षम होते हैं, जिससे उन्हें अधिक सतर्क क्रेडिट निर्णय लेने में सक्षम बनाया जाता है। डेटा-संचालित वित्त केवल जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने के बारे में नहीं है; यह नवाचार को चलाने, ग्राहकों के लिए मूल्य बनाने और सिस्टम के लाभ के लिए टिकाऊ, लचीला वित्तीय मॉडल बनाने के लिए उस जानकारी का उपयोग करने के बारे में है। डेटा के जिम्मेदार उपयोग को सक्षम करने के लिए, आरबीआई ने खाता एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पेश किया है जो ग्राहकों को अपने डेटा को नियंत्रित करने और विभिन्न वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के प्रावधान के लिए तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाताओं के साथ साझा करने की अनुमति प्रदान करने में सक्षम बनाता है। यह उम्मीद की जाती है कि एए फ्रेमवर्क वैकल्पिक उधार मॉडल जैसे नकदी प्रवाह-आधारित उधार और बाजार ऋण या जिसे हम लोकप्रिय रूप से पीयर-टू-पीयर लेंडिंग के रूप में जानते हैं, के विकास में तेजी लाएगा। इससे स्ट्रीट वेंडर्स सहित छोटे व्यवसायों जिनके पास पारंपरिक संपार्श्विक नहीं हो सकता है, को ऋण प्राप्त करने में मदद मिलेगी। जैसा कि प्रौद्योगिकी आगे बढ़ रही है, हम उम्मीद करते हैं कि उधार परिदृश्य को बदलने के लिए डेटा, स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ उठानेवाले अधिक अभिनव मॉडल उभरेंगे।

महामारी के बाद की चौथी गतिविधि हम नियामकों को वित्तीय स्थिरता को ध्यान में रखने की याद दिलाती है। आईएमएफ द्वारा 'द ग्रेट लॉकडाउन[17]' के रूप में वर्णित कोविड झटके ने सभी तनाव परीक्षण मॉडल और व्यापार निरंतरता योजनाओं को परीक्षण के दायरे में रखा। इसने हमें यह भी याद दिलाया कि वित्तीय प्रणाली बाहरी और आंतरिक किसी भी क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले झटकों के प्रति संवेदनशील है, और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना हमारे लिए अनिवार्य

[17] विश्व आर्थिक आउटलुक, अप्रैल 2020।

है। आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं के लिए, वित्तीय स्थिरता सिर्फ एक लक्ष्य नहीं है, यह एक आवश्यकता है - क्योंकि जब यह लड़खड़ाता है, तो लहर प्रभाव सबसे शक्तिशाली को भी अपने घुटनों पर ला सकता है। 2008 का वित्तीय संकट इस बात की याद दिलाता है कि वित्तीय स्थिरता सिर्फ एक आदर्श नहीं है, यह एक अच्छी तरह से काम करने वाली अर्थव्यवस्था के लिए एक शर्त है।

बैंक वित्तीय प्रणाली की रीढ़ हैं, और वे वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस कारण से, बैंकों को रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण विनियमों का अनुपालन करना और नुकसान को सहन करने के लिए पर्याप्त पूंजी बफर बनाए रखना आवश्यक है। वित्तीय स्थिरता का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व मजबूत शासन है। मजबूत शासन किसी भी संगठन की स्थिरता और समृद्धि की आधारशिला है, अखंडता की रक्षा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी निर्णय हितधारकों के सर्वोत्तम हित में लिए जाते हैं।

इसे स्वीकार करते हुए, रिज़र्व बैंक ने हमेशा अभिशासन पर अधिक महत्व दिया है और बैंकों में इसे मजबूत करने के लिए कई उपाय किए हैं। रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, अब बैंकों के लिए एक अलग और स्वतंत्र निदेशक मंडल होना चाहिए, जिसमें कुछ न्यूनतम योग्यता और अनुभव के साथ कार्यकारी और गैर-कार्यकारी निदेशकों का मिश्रण हो। निदेशक मंडल का निरीक्षण संतुलित जोखिम प्रबंधन, लेखा परीक्षा और अनुपालन कार्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए।

भविष्य की चुनौतियां और अवसर

हालांकि, हम सभी बैंकिंग सेवा प्रदान करने की अपनी खोज में एक लंबा सफर तय कर चुके हैं, लेकिन अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। शहरी और ग्रामीण भारत द्वारा वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता और उपयोग में भारी अंतर एक चुनौती है। यह हमें एक बड़ा अवसर देती है क्योंकि वित्तीय समावेशन का उद्देश्य केवल बचत और ऋण तक पहुंच प्रदान करना नहीं है, यह व्यक्तियों को उनकी वास्तविक क्षमता का एहसास कराने और एक संपन्न अर्थव्यवस्था में योगदान करने के लिए सशक्त बनाने से संबंधित है।

वित्तीय समावेशन को ऐसे उत्पादों और सेवाओं को विकसित करके फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है जो समाज के विभिन्न वर्गों के लिए उनकी आय के स्तर के आधार पर सबसे उपयुक्त हैं। इसमें अभिनव समाधान शामिल होंगे जो लोगों के लिए न केवल बुनियादी बल्कि विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाओं का उपयोग करना भी आसान बनाते हैं। इस दिशा में और आसान, पर्याप्त और अनुकूलित ऋण को सक्षम करने के लिए रिज़र्व बैंक ने विभेदित बैंकिंग लाइसेंस के लिए प्रावधान किए हैं। ये आला बैंक हैं जो व्यापक और विविध स्पेक्ट्रम में बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं के लिए विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने में अंतर को पाटने में मदद कर सकते हैं।

भारत के ऋण बाजार में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को ऋण की मांग और आपूर्ति के बीच लगातार अंतर रहा है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30 प्रतिशत, इसके विनिर्माण उत्पादन में 45 प्रतिशत और निर्यात में 48 प्रतिशत का योगदान देता है। इसे बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा अवसर के क्षेत्र के रूप में देखा जाना चाहिए।

ध्यान केन्द्रित करने योग्य एक और उभरता हुआ क्षेत्र कम-कार्बन अर्थव्यवस्था में अंतरण के लिए वित्त उपलब्ध कराना है। हम सभी अब उस वैश्विक चुनौती से अवगत हैं जो जलवायु परिवर्तन हमारे ग्रह के लिए पैदा कर रहा है और इसका प्रभाव दुनिया भर में गूंज रहा है। यदि हम समय पर कार्रवाई करने में विफल रहते हैं, तो परिणाम अपरिवर्तनीय होंगे। भारत सरकार पहले ही 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन एक बिलियन टन तक कम करने, 2030 तक कार्बन अर्थव्यवस्था की तीव्रता 45 प्रतिशत से ज्यादा कम करने तथा वर्ष 2070 तक 'निवल शून्य' उत्सर्जन की स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक केंद्रीय बैंक के रूप में, हमारे पास निरंतर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की भी जिम्मेदारी है जिसमें कम-कार्बन अर्थव्यवस्था में अंतरण शामिल है।

बैंक टिकाऊ और हरित परियोजनाओं के साथ-साथ हरित पहल को प्रोत्साहित करने वाले नए वित्तीय उत्पादों को विकसित करके कम-कार्बन वाली अर्थव्यवस्था में अंतरण के लिए वित्तपोषण में एक आवश्यक भूमिका निभा सकते हैं। हमारे कार्य न केवल ग्रह के भविष्य के लिए कार्यप्रणाली निर्धारित करेंगे, बल्कि यह भी निर्धारित करेंगे कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को किस तरह का वातावरण देते हैं।

एक विकसनशील देश में एक नियामक के लिए, प्रौद्योगिकी को अत्यंत तेजी से अपनाना, बाजार नवाचारों के साथ तालमेल रखना हमेशा एक चुनौती होती है। इस तरह के एक गतिशील वित्तीय क्षेत्र को विनियमित करने का वर्णन बहुत उपयुक्त रूप से "बस जब हमने सोचा कि हम सभी उत्तर जानते हैं, तो किसी ने सवालों को बदल दिया" के रूप में किया जा सकता है। लेकिन यह हमारा दृढ़ विश्वास है कि ग्राहकों को वित्तीय नवाचार के परिणाम का आनंद लेने के लिए, इसे टिकाऊ और एक मजबूत नियामक ढांचे के दायरे में होना चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए, हमने उत्तरदायी नवाचार के उद्देश्य से एक सूक्ष्म और परामर्शी दृष्टिकोण का पालन किया है, जबकि उद्योग को टिकाऊ व्यावसायिक प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित किया है।

समापन विचार

हमारे लिए इस तथ्य से अवगत होना महत्वपूर्ण है कि एक मजबूत और लचीली वित्तीय प्रणाली का आधार लोगों का उस पर भरोसा है। विश्वास तत्व न केवल व्यक्तिगत संस्थानों द्वारा बल्कि वित्तीय प्रणाली में कार्यरत संस्थाओं के सामूहिक कार्यों द्वारा भी बनाया जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि कंपनियां अपने कार्यों और अपने द्वारा नियुक्त सेवा प्रदाताओं के कार्यों के लिए जिम्मेदार होंगी और इसके लिए जवाबदेही प्रदर्शित करेंगी। वित्तीय क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं के लिए लागू नियमों का अनुपालन और ग्राहक-केंद्रितता सुनिश्चित करना दो गैर-परक्राम्य सिद्धांत हैं और उन्हें शीर्ष से प्रवाहित किया जाना चाहिए।

अंत में, मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि बैंकिंग क्षेत्र भारत की विकास गाथा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, और यह महत्वपूर्ण है कि बैंक अर्थव्यवस्था की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए बदलते समय के अनुसार नवाचार और अनुकूलन जारी रखें। जैसा कि भारत आगे बढ़ रहा है, बैंकिंग क्षेत्र, अब तक, देश की विकास कहानी में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बना रहना चाहिए। हमेशा की तरह, आरबीआई में हम यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे कि बैंकिंग क्षेत्र और अन्य हितधारक भारत के लिए एक मजबूत, अधिक समावेशी और स्थायी भविष्य बनाने में मदद कर सकें।

धन्यवाद।

आलेख

अर्थव्यवस्था की स्थिति

हालिया प्रतिगामी मुद्रास्फीति – भारतीय अनुभव

भारतीय राज्यों का पूंजी परिव्यय: इसकी भूमिका और निर्धारकों का एक तथ्यात्मक मूल्यांकन

औद्योगिक संबंध संहिता और श्रम उत्पादकता:
एक अंतर-देशीय अधि-विश्लेषण

भारत में रियल्टी क्षेत्र की गतिविधि का एक समग्र संकेतक

*अर्थव्यवस्था की स्थिति**

वैश्विक आर्थिक स्थितियां बढ़ी हुई अनिश्चितता से घिरी हुई हैं क्योंकि वित्तीय स्थितियां अस्थिर बनी हुई हैं और वित्तीय बाज़ार संवेदनशील स्थिति में हैं। भारत में, कुल मांग की स्थिति लचीली बनी हुई है, जो संपर्क-गहन सेवाओं में बहाली से समर्थित है। रबी की बेहतर फसल की उम्मीद, बुनियादी ढांचे पर राजकोषीय जोर, और चुनिंदा क्षेत्रों में कॉरपोरेट निवेश में पुनरुद्धार अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है। मौद्रिक नीति की कार्रवाइयों और आपूर्ति पक्ष के उपायों के चलते, हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति धीरे-धीरे अप्रैल 2022 के 7.8 प्रतिशत के अपने शिखर से घटकर मार्च 2023 में 5.7 प्रतिशत हो गई और 2023-24 की चौथी तिमाही में 5.2 प्रतिशत तक कम होने का अनुमान है।

परिचय

अप्रैल के मध्य में बहुपक्षीय संस्थानों - अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के बारे में गंभीर संदेश जारी किए। एक ने चेतावनी दी कि 2023 में वैश्विक विकास के निचले स्तर पर पहुंचने के साथ आगे की राह मुश्किल हो सकती है। दूसरे ने आगाह किया कि एक दशक का समय बर्बाद हो गया है क्योंकि उम्रदराज कार्यबल, कमजोर होते निवेश और उत्पादकता में कमी वैश्विक संभावित वृद्धि अर्थात "वह अधिकतम दर जिस पर अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति में वृद्धि के बिना बढ़ सकती है" - पर अपना असर डाल रही है।

इस बीच, कुछ विकसित अर्थव्यवस्थाओं (एई) में कुछ मध्यम आकार के बैंकों की अचानक विफलता और अत्यधिक बड़े बैंकों के जबरन समामेलन के बाद निवेशकों ने वैश्विक ब्याज दर में वृद्धि की उम्मीदों को कम कर दिया है। इन देशों में बैंकिंग क्षेत्र में विश्वास अभी तक पूरी तरह से बहाल नहीं हुआ है। वैश्विक वित्तीय प्रणाली की समुत्थानशीलता परीक्षा की घड़ी से गुजरी है। वित्तीय संस्थानों के बही-खातों में छिपे मूल्यांकन घाटे की आशंका के साथ धारणा कमजोर बनी हुई है। नीति निर्माताओं के समक्ष वित्त पोषण की कमी की समस्या है, जिनमें से कुछ ने आपातकालीन चलनिधि उपायों को लागू किया है जो अब तक हासिल मात्रात्मक सख्ती के कुछ हिस्से को उलट सकते हैं। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि केंद्रीय बैंकों और वित्तीय विनियामकों को मुद्रास्फीति को कम करने के बजाय विश्वास और वित्तीय स्थिरता को बहाल करने के लिए और अधिक प्रयास करना चाहिए जो उनका मूल अधिदेश है। तदनुसार, मौद्रिक नीति पथों का तीव्र पुनर्निर्धारण चल रहा है। नतीजतन, वित्तीय स्थितियां अस्थिर बनी हुई हैं और वित्तीय बाज़ार संवेदनशील स्थिति में हैं।

आईएमएफ के प्रमुख प्रकाशनों के संदेशों ने निकट की अनिश्चितता का अंदाज़ व्यक्त किया है। *फिस्कल मॉनिटर* रिपोर्ट में सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं पर बढ़ते ऋण जोखिम और राजकोषीय बफर में कमी को रेखांकित किया गया है। इस संदर्भ में, इसने पूर्वव्यापी और व्यवस्थित ऋण पुनर्गठन पर लेनदारों के बीच समन्वय के महत्व को रेखांकित किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुद्रास्फीति ने बढ़ते सार्वजनिक ऋण के बोझ को कुछ हद तक कम कर दिया है, इसके बावजूद मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने के लिए मौद्रिक नीति के साथ-साथ राजकोषीय नीति को सख्त किया जाना चाहिए। अन्य दो प्रमुख रिपोर्टों – दी वर्ल्ड इकॉनोमिक आउटलुक (डब्ल्यूईओ) और ग्लोबल फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट (जीएफएसआर) में भी मुद्रास्फीति के खिलाफ लड़ाई जारी रखने की सिफारिश की गई है। केवल प्रणालीगत वित्तीय दबाव की स्थिति में वैश्विक वित्तीय प्रणाली में विश्वास बनाए रखने के लिए प्राथमिकता बदलनी चाहिए, जिसमें संक्रमण को सीमित करने के लिए पर्याप्त चलनिधि हो। इस बीच, यह सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट साधनों के उपयोग की आवश्यकता है कि बैंकों का अभिशासन और जोखिम प्रबंधन जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप है। समाधान व्यवस्था और संकट प्रबंधन ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थों, स्थावार संपदा क्षेत्रों और वित्तीय क्षेत्र के कम/मामूली रूप से विनियमित क्षेत्रों में जोखिमों के निर्माण की निगरानी करना महत्वपूर्ण है। आईएमएफ ने विनिमय दर में उतार-चढ़ाव और संभावित पूंजी बहिर्वाह से उपजी उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) के लिए वित्तीय स्थिरता जोखिमों को

* इस आलेख को जी. वी. नथनएल, रजनी दहिया, कुणाल प्रियदर्शी, हर्षिता केशन, थंगजासन सोना, पंकज कुमार, हरेंद्र बेहरा, धन्या वी., रिग्ज़िन यांगड़ोल, प्रशांत कुमार, अनूप के सुरेश, ऋषभ कुमार, रोहन बंसल, कोवुरी आकाश यादव, हिमानी शेखर, प्रियंका सचदेवा, आशीष संतोष खोबरागड़े, सत्यम कुमार, अलीशा जॉर्ज, युवराज कश्यप, सुप्रियो मंडल, सुजीश कुमार, तुषार बरन दास, राजेंद्र नाना चव्हाण, रंजीत मोहन, विनीत कुमार श्रीवास्तव, समीर रंजन बेहरा, देब प्रसाद रथ और माइकल देवव्रत पात्र द्वारा तैयार किया गया है। इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

भी महत्वपूर्ण माना है, और इसके लिए विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप और पूंजी प्रवाह उपायों जैसे उपायों की वैधता को स्वीकार किया है।

लंबी अवधि के लिए, आईएमएफ ने हरित संक्रमण में तेजी लाकर विनाशकारी जलवायु परिवर्तन को रोकने की तात्कालिकता को रेखांकित किया है। इस उद्देश्य के लिए, ईएमडीई जलवायु वित्त के लिए पूंजी जुटाना आवश्यक है। उसके विचार में, जलवायु और औद्योगिक नीति और सब्सिडी के कारण विखंडन जोखिमों को कम करना जो दुनिया से अर्थव्यवस्थाओं को समाप्त करने का खतरा पैदा करते हैं, जैसे सामान्य वैश्विक सार्वजनिक विषयों पर सहयोग को मजबूत करना आवश्यक है। इस दूसरे मुद्दे के संदर्भ में, आईएमएफ का मानना है कि व्यापार प्रतिबंधों और अन्य भेदभावपूर्ण व्यवस्था को हटाया जाना चाहिए।

भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में बात करें तो बहुपक्षीय संस्थाओं ने 'धीमी खपत वृद्धि और चुनौतीपूर्ण बाहरी परिस्थितियों' (विश्व बैंक, 2023[1]) और पिछले वर्षों के जीडीपी डेटा के ऊपर की ओर के संशोधन (आईएमएफ 2023[2]) का हवाला देते हुए 2023-24 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि के अपने पहले के पूर्वानुमानों को कम कर दिया। भारत के संबंध में संवृद्धि की यह गिरावट वैश्विक विकास अनुमानों के साथ-साथ ईएमडीई के लिए भी कम किए जाने के अनुरूप है। फिर भी, भारत के दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने की उम्मीद है, जो वैश्विक वृद्धि का 15 प्रतिशत है - सबसे बड़े योगदान में दूसरे क्रम पर है, और अमेरिका और यूरोपीय संघ की तुलना में अधिक है। हालांकि यह बताना जल्दबाजी होगी, कि सबसे हालिया प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि बहुपक्षीय संस्थाओं - विशेष रूप से आईएमएफ- का पूर्वानुमान त्रुटिपूर्ण साबित हो सकता है और वास्तविक परिणाम उन्हें सकारात्मक रूप से आश्चर्यचकित कर सकते हैं।

भारत में कुल मांग की स्थिति अब तक लचीली बनी हुई है। शहरी उपभोग की मांग में जोरदार वृद्धि हुई है, संपर्क-गहन सेवाओं में बहाली ने एक मजबूत बढ़त प्रदान की है। ग्रामीण मांग संकेतकों में लगातार सुधार हो रहा है, जो *रबी* की मजबूत फसल की उम्मीद से ध्यान आकर्षित कर रहा है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण खड़ी फसलों को नुकसान कम होता दिख रहा है। जून में *अल नीनो* की स्थिति का स्थापित होना और यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा की गई भविष्यवाणी के अनुसार उसका एक मजबूत घटना में विकसित होना कृषि संभावनाओं के लिए एक नकारात्मक जोखिम है; हालांकि, हिंद महासागर द्विध्रुव (आईओडी), जो अरब सागर में पश्चिमी ध्रुव और इंडोनेशिया के दक्षिण में पूर्वी ध्रुव के बीच समुद्र की सतह के तापमान में अंतर है, वर्तमान में तटस्थ है और उसके सकारात्मक होने का अनुमान है। इस क्षेत्र में वर्षा परिवर्तनशीलता पर इसका प्रभाव दक्षिण-पश्चिम मानसून (एसडब्ल्यूएम) वृष्टि के लिए फायदेमंद होने की संभावना है।

मजबूत समग्र क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) के कारण भारत में निवेश गतिविधि उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही है - भारत में तुलनात्मक रूप से सबसे अधिक पीएमआई है - बुनियादी ढांचे के खर्च पर राजकोषीय जोर है, और कुछ प्रमुख क्षेत्रों में कॉरपोरेट निवेश में पुनरुद्धार हुआ है। बैंक ऋण सहित वाणिज्यिक क्षेत्र में संसाधनों का कुल प्रवाह मार्च 2023 तक 37 प्रतिशत बढ़ा है। 2022-23 में वस्तुओं के निर्यात में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और सेवा निर्यात तेजी से बढ़ रहा है। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा अनुमानित 2023-24 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.5 प्रतिशत के आसपास जोखिम समान रूप से संतुलित हैं। यहां तक कि अगर *अल नीनो* कृषि मूल्यों को प्रभावित करता भी है, तब भी भारत में वास्तविक जीडीपी वृद्धि आईएमएफ के डब्ल्यूईओ में अनुमानित 5.9 प्रतिशत से ऊपर होगी।

भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के दौर में भारतीय उद्योग जगत की निष्क्रिय भूमिका रही। पिछले दो वर्षों में संकुचन के बाद 2021-22 में मजबूत बदलाव के बाद, 2022-23 में कॉर्पोरेट राजस्व और मुनाफे में कमी आई, लेकिन वे कई चुनौतियों के बावजूद स्वस्थ बने रहे। इससे 2023-24 में कॉर्पोरेट पूंजीगत व्यय चक्र में बहुप्रतीक्षित पुनरुद्धार को गति मिल सकती है। सीमेंट, इस्पात, तेल और गैस, कपड़ा और डेटा केंद्रों जैसे

1 https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/04/04/indian-economy-continues-to-show-resilience-amid-global-uncertainties

2 अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक, अप्रैल 2023 https://www.imf.org/en/Publications/WEO

उद्योगों में तेजी के संकेत स्पष्ट हो रहे हैं। आपूर्ति शृंखला पुनर्गठन से भी मदद मिलेगी, विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल्स, सेमी-कंडक्टर और नवीकरणीय जैसे उद्योग में। कंपनियों का भाग्य मुद्रास्फीति में टिकाऊ कमी के इर्द-गिर्द टिका होगा, जिससे उपभोक्ता विवेकाधीन खर्च मजबूत होगा, जिससे आय बढ़ेगी और साथ-साथ ब्याज खर्च में कमी आएगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिंसों की कीमतों में नरमी आने से कच्चे माल की लागत में कमी आने की संभावना है। दूसरी ओर, 2022-23 की दूसरी छमाही से निर्यात के कमजोर होने से दोपहिया वाहनों, ऑटो एन्सीलरीज़, परिधान, रसायन, धातु और रत्न और आभूषण जैसे उद्योग प्रभावित हो सकते हैं। सेवा क्षेत्र, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी, व्यावसायिक सेवाओं की एक विस्तृत शृंखला, पर्यटन और वैश्विक क्षमता केंद्रों से बाहर निर्यात आकर्षक स्थान बने हुए हैं।

आरबीआई का उद्योग निगरानी समूह (आईएमजी) मौद्रिक नीति तैयार करने की सूचना देने के उद्देश्य से एक अर्ध-वार्षिक सर्वेक्षण करता है। एमपीसी की अप्रैल 2023 की बैठक से ठीक पहले सर्वेक्षण के नवीनतम दौर में विभिन्न उद्योग निकायों, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों और बैंकों से मिली प्रतिक्रिया से संकेत मिलता है कि प्रीमियम उत्पादों में बिक्री में वृद्धि के कारण कई श्रेणियों में कॉर्पोरेट बिक्री में दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की जा रही है, जिसमें उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं प्रमुख हैं। दूसरी ओर, उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं की मात्रा ग्रामीण बिक्री में गिरावट और पारंपरिक व्यापार के असंगठित खंड (किराना स्टोर) में गिरावट के साथ उच्च कीमतों से प्रतिकूल रूप से प्रभावित है, जिसमें गैर-खाद्य खपत की वस्तुएं प्रमुख हैं। दूसरी ओर, ई-कॉमर्स बाज़ार जो 2022 में अनुमानत: 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, 2023 में मजबूत विकास के लिए तैयार है।

सर्वेक्षण बताता है कि बुनियादी ढांचे से संबंधित क्षेत्रों में निवेश बढ़ सकता है। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना और नए युग के क्षेत्रों[3] में विकास की संभावनाएं निजी निवेश ला रही हैं। ऑटोमोबाइल क्षेत्र को छोड़कर, जिसमें दोपहिया और तिपहिया वाहनों में क्षमता उपयोग पिछड़ रहा है, प्रमुख पूंजी-गहन क्षेत्रों के साथ-साथ संपर्क गहन सेवा क्षेत्रों के लिए क्षमता उपयोग दशकीय औसत को पार कर गया है। आने वाले समय में 1 अप्रैल 2023 से बीएस 6 उत्सर्जन मानकों का दूसरा चरण और सुरक्षा विशेषताओं पर अतिरिक्त आदेश प्रारंभिक स्तरों की कारों पर दबाव जारी रखेंगे। लागत को तर्कसंगत बनाने के कारण सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र दृढ़ बना हुआ है। वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों से प्रभावित निर्यात उन्मुख क्षेत्रों को छोड़कर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र सुधार के रास्ते पर है, और 2023-24 में राजस्व पूर्व-महामारी के स्तर को पार करने की संभावना है। कमोडिटी की कीमतों में कमी आने से लाभ बढ़ सकता है और इस क्षेत्र के क्रेडिट प्रोफाइल में सुधार हो सकता है। आतिथ्य उद्योग में, समस्त होटल वर्गों में राजस्व में सुधार हुआ है, जो उद्योग में व्यापक पुनरुद्धार का संकेत देता है।

विभिन्न क्षेत्रों में ऋण अनुपात में सुधार हो रहा है और अपग्रेड डाउनग्रेड से अधिक हो रहा है। स्थावार संपदा की क्रेडिट रेटिंग में काफी सुधार हुआ है, जिसके बाद वित्त कंपनियों, बिजली, कपड़ा और इंजीनियरिंग का स्थान है। बढ़ते जांच स्तरों के साथ क्रेडिट वृद्धि लचीली बनी हुई है, हालांकि हाल ही में इसमें कुछ कमी आई है। क्रेडिट कार्ड और शिक्षा ऋण को छोड़कर, उपभोक्ता ऋण की सभी श्रेणियों में पिछले 90+ दिनों में चूक कम हो रही है।

इस पृष्ठभूमि के साथ इस आलेख के शेष भाग को चार खंडों में संरचित किया गया है। खंड II में वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी से विकसित हो रही गतिविधियों को शामिल किया गया है। घरेलू समष्टि आर्थिक स्थितियों का आकलन खंड III में किया गया है। खंड IV में भारत की वित्तीय स्थितियों का उल्लेख किया गया है, और अंतिम खंड में समापन टिप्पणी है।

II. वैश्विक स्थिति

वैश्विक आर्थिक स्थितियां एक बार फिर बढ़ी अनिश्चितता से घिरी हुई हैं। अप्रैल 2023 में जारी अपने वर्ल्ड इकॉनोमिक आउटलुक (डब्ल्यूईओ) में आईएमएफ ने 2023 में वैश्विक संवृद्धि दर घटकर 2.8 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है जो जनवरी 2023 के अनुमान से 10 आधार अंक नीचे है जबकि 2022 में यह

[3] हरित हाइड्रोजन; सेमीकंडक्टर; वियरेबल्स; और सौर मॉड्यूल।

सारणी 1: जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमान – चुनिंदा एई और ईएमई

(प्रतिशत)

पूर्वानुमान वर्ष पूर्वानुमान का माह	2023		2024	
	अप्रैल 2023	जनवरी 2023	अप्रैल 2023	जनवरी 2023
विश्व	2.8	2.9	3.0	3.1
विकसित अर्थव्यवस्था				
यूएस	1.6	1.4	1.1	1.0
यूके	-0.3	-0.6	1.0	0.9
यूरो क्षेत्र	0.8	0.7	1.4	1.6
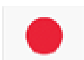 जापान	1.3	1.8	1.0	0.9
उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्था				
ब्राज़ील	0.9	1.2	1.5	1.5
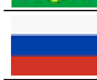 रूस	0.7	0.3	1.3	2.1
भारत	5.9	6.1	6.3	6.8
चीन	5.2	5.2	4.5	4.5
दक्षिण अफ्रीका	0.1	1.2	1.8	1.3

स्रोत : आईएमएफ़।

3.4 प्रतिशत था। तथापि 2024-28 के लिए 3.0 प्रतिशत का अनुमान है (सारणी 1)। वित्तीय क्षेत्र में हाल में हो रही उथल-पुथल, लगातार उच्च मुद्रास्फीति, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष और इसके स्पिलओवर और संक्रमण की नई लहरों सहित महामारी के लंबित प्रभाव वैश्विक संवृद्धि पर भारी पड़ रहे हैं। आईएमएफ ने वित्तीय क्षेत्र पर अत्यधिक दबाव के साथ एक वैकल्पिक परिदृश्य पर भी प्रकाश डाला है, जिससे 2023 में वैश्विक संवृद्धि 2.5 प्रतिशत तक गिर सकती है। मूलभूत परिदृश्य के तहत वैश्विक हेडलाइन मुद्रास्फीति 2022 के 8.7 प्रतिशत से घटकर 2023 में 7.0 प्रतिशत (जनवरी के पूर्वानुमान से 40 बीपीएस ऊपर संशोधन) होने की संभावना है, जबकि अंतर्निहित मुख्य मुद्रास्फीति लंबे समय तक उच्च रह सकती है।

चार्ट 1: वैश्विक जीडीपी वृद्धि का तात्कालिक पूर्वानुमान (समायोजित श्रृंखला, (ति-द-ति)

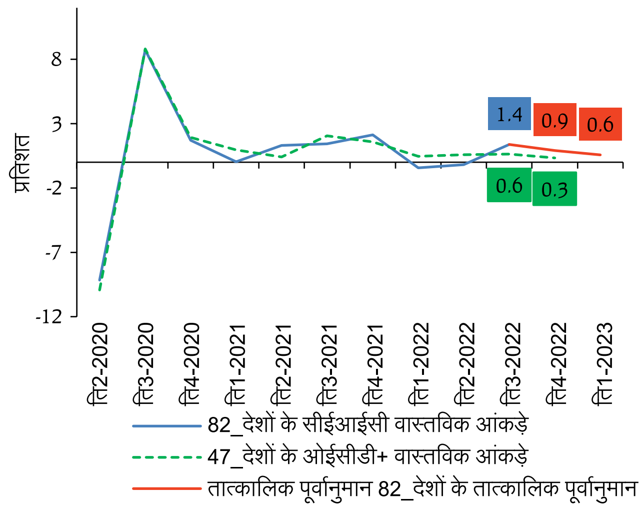

स्रोत : सीईआईसी; ओईसीडी; आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

हमारे मॉडल-आधारित तात्कालिक पूर्वानुमान के अनुसार 2023 की पहली तिमाही में 0.6 प्रतिशत की सकारात्मक वैश्विक संवृद्धि गति का अनुमान है (चार्ट 1)।

उच्च आवृत्ति संकेतकों में, वैश्विक समग्र क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) मार्च 2023 में बढ़कर 53.4 हो गया, जो पिछले महीने में 52.1 था, जो वैश्विक सेवा पीएमआई द्वारा

चार्ट 2 : वैश्विक पीएमआई

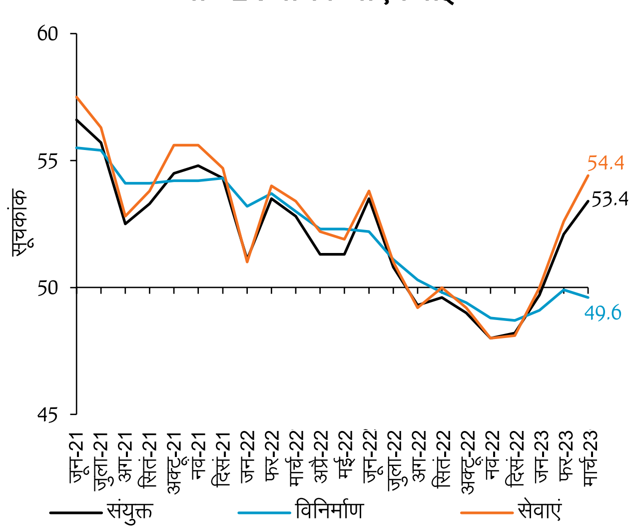

टिप्पणी: 50 का स्तर गतिविधि में कोई बदलाव नहीं होने और 50 से ऊपर की रीडिंग विस्तार और इसके विपरीत दर्शाते हैं।
स्रोत: आईएचएस मार्किट।

चार्ट 3: वैश्विक व्यापार और शिपिंग लागत

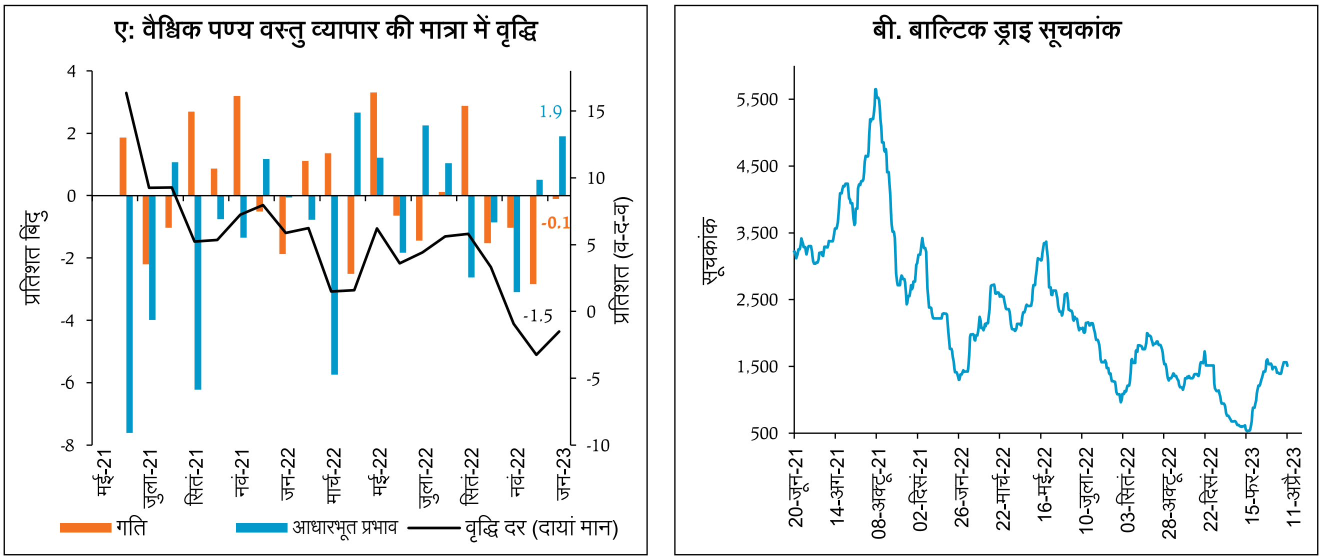

स्रोत: सीपीबी नीदरलैंड; और ब्लूमबर्ग।

संचालित था, जो फरवरी के 52.6 से बढ़कर मार्च में 54.4 हो गया। दूसरी ओर, उत्पादन और रोजगार की धीमी वृद्धि और नए ऑर्डर और खरीद के स्टॉक में गिरावट के कारण वैश्विक विनिर्माण पीएमआई मार्च 2023 में घटकर 49.6 रह गया, जो एक महीने पहले 49.9 था।

विश्व व्यापार की मात्रा में, अनुकूल आधार प्रभाव के बावजूद, नकारात्मक गति के कारण, जनवरी 2023 में लगातार तीसरे महीने 1.5 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की गिरावट आई (चार्ट 3ए)। बाल्टिक ड्राई सूचकांक, जो सूखी थोक वस्तुओं के शिपिंग शुल्क का एक माप है - हालांकि, फरवरी के मध्य से दोगुने से अधिक हो गया, जो केपसाइज और पैनामैक्स पोत खंडों के लिए उच्च दरों से प्रेरित है। मार्च 2023 में सूचकांक में 40 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है (चार्ट 3बी)। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीटीएडी) तात्कालिक पूर्वानुमान ने 2023 की पहली तिमाही के लिए वैश्विक व्यापार में तेजी का संकेत दिया है, जिसमें वस्तुओं में क्रमिक रूप से लगभग 1 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है, जबकि सेवा व्यापार में उसी आधार पर लगभग 3 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है (चार्ट 4)।

मार्च में, वैश्विक कमोडिटी की कीमतें पूर्व-यूक्रेन युद्ध (जनवरी 2022) के स्तर के करीब कम हो गईं क्योंकि काला सागर अनाज पहल[4] के नवीकरण के बाद अधिकांश कृषि वस्तुओं, विशेष रूप से अनाज की कीमतें कम हो गईं और आपूर्ति बाधाएं कम हो गईं (चार्ट 5ए)। कच्चे तेल की कीमतें मार्च में घटकर औसतन 78.5 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गईं, क्योंकि वैश्विक तेल की

चार्ट 4: वैश्विक व्यापार रुझान और परिदृश्य

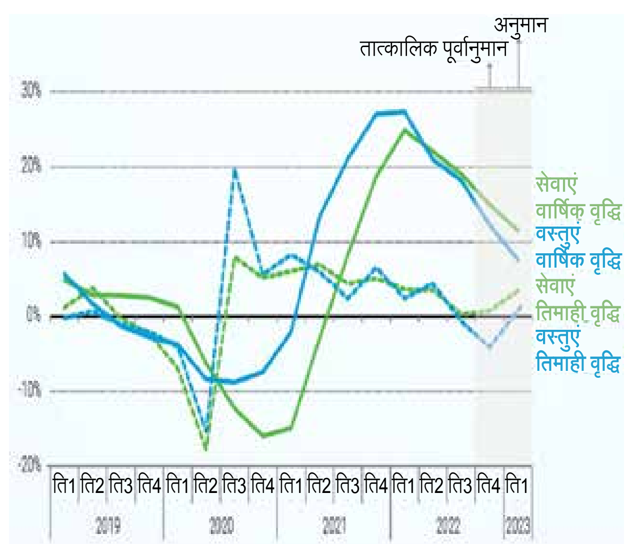

स्रोत: ग्लोबल ट्रेड अपडेट, मार्च 2023 (अंकटाड)।

4 यह पहल विशेष रूप से काला सागर में तीन प्रमुख यूक्रेनी बंदरगाहों से वाणिज्यिक खाद्य और उर्वरक (अमोनिया सहित) निर्यात के लिए अनुमति देती है - ओडेसा, चोरनोमोर्स्क और युजनी / पिवडेनी।

चार्ट 5: कमोडिटी और खाद्य कीमतें

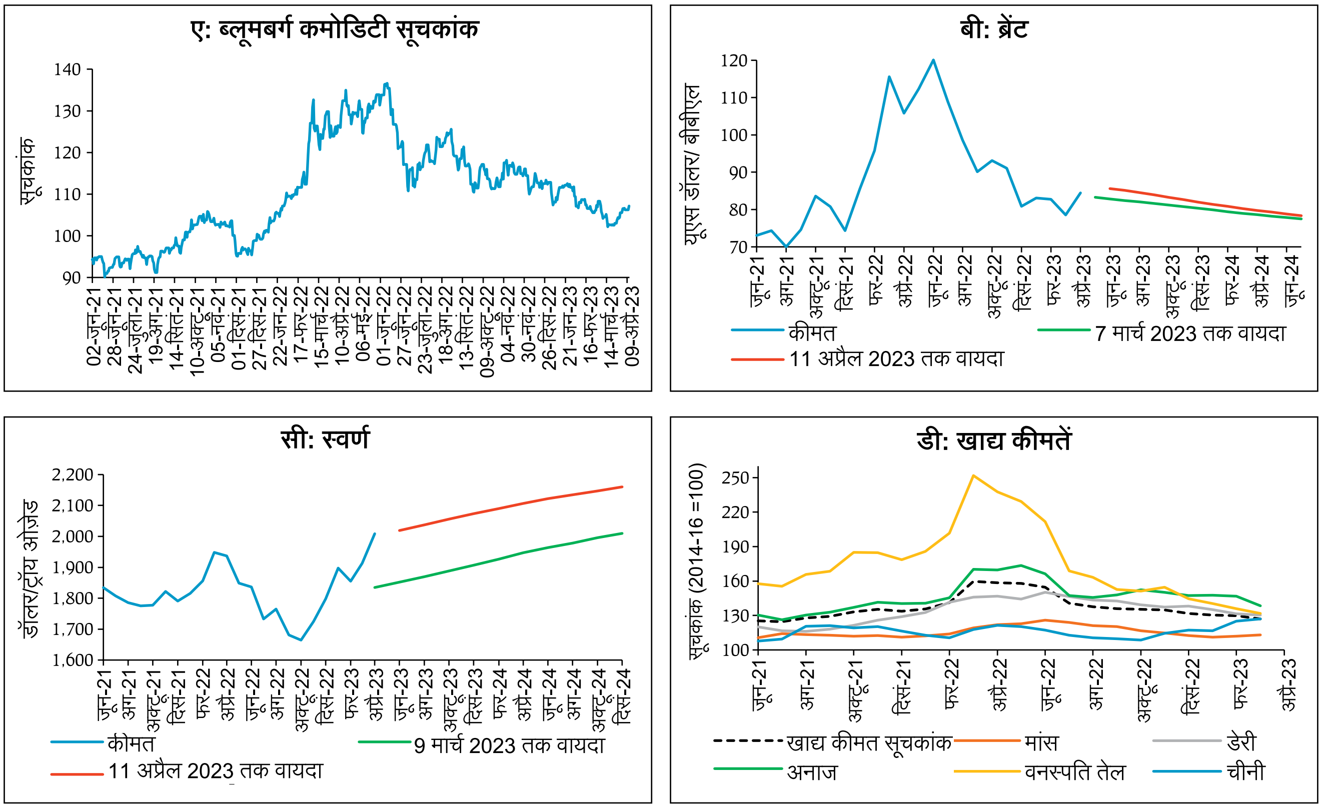

स्रोत: ब्लूमबर्ग; वर्ल्ड बैंक पिंक शीट; और एफएओ।

आपूर्ति, विशेष रूप से अमेरिका और कनाडा से, बढ़ गई, । पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) द्वारा आश्चर्यजनक ढंग से उत्पादन में कटौती की घोषणा के बाद अप्रैल की शुरुआत में कीमतें बढ़ीं [चार्ट 5 बी]। संयुक्त राज्य अमेरिका में बैंकों की विफलता के बीच सुरक्षित निवेश की मांग के कारण स्वर्ण की कीमतों में तेजी आई (चार्ट 5सी)। अनाज, वनस्पति तेल और डेयरी की कीमतों में गिरावट के कारण खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) खाद्य मूल्य सूचकांक[5] में मार्च 2023 में 2.1 प्रतिशत (माह दर माह) की गिरावट आई, जबकि चीनी और मांस में वृद्धि हुई (चार्ट 5डी)। सूचकांक एक साल पहले दर्ज किए गए अपने शिखर से लगातार गिरावट पर रहा है, जिससे मार्च 2023 में वर्ष-दर-वर्ष 20.5 प्रतिशत की गिरावट आई है।

ऊर्जा की कीमतों में नरमी और आपूर्ति शृंखला की बाधाओं में कमी आने के कारण अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति हाल की सर्वोच्च स्थिति से नीचे आ गई है; फिर भी मुख्य मुद्रास्फीति अडिग बनी हुई है। हाल की नरमी के बावजूद, अधिकांश एई और ईएमई में हेडलाइन मुद्रास्फीति लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है। अनुकूल आधार प्रभाव के कारण यू.एस. हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष) फरवरी में 6.0 प्रतिशत से उल्लेखनीय रूप से घटकर मार्च 2023 में 5.0 प्रतिशत हो गई जो मई 2021 के बाद से सबसे कम है। व्यक्तिगत उपभोग व्यय (पीसीई) सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति भी फरवरी में घटकर 5.0 प्रतिशत रह गई, जो इससे पिछले महीने 5.3 प्रतिशत थी (चार्ट 6 ए)। यूरो क्षेत्र में, मुद्रास्फीति मार्च 2023 में उल्लेखनीय रूप से घटकर 6.9 प्रतिशत हो गई, जो पिछले महीने में 8.5 प्रतिशत थी। यह गिरावट ऊर्जा उप-घटक में

5 उप-सूचकांकों में अनाज, वनस्पति तेल, डेयरी, मांस और चीनी मूल्य सूचकांक शामिल हैं।

चार्ट 6: मुद्रास्फीति

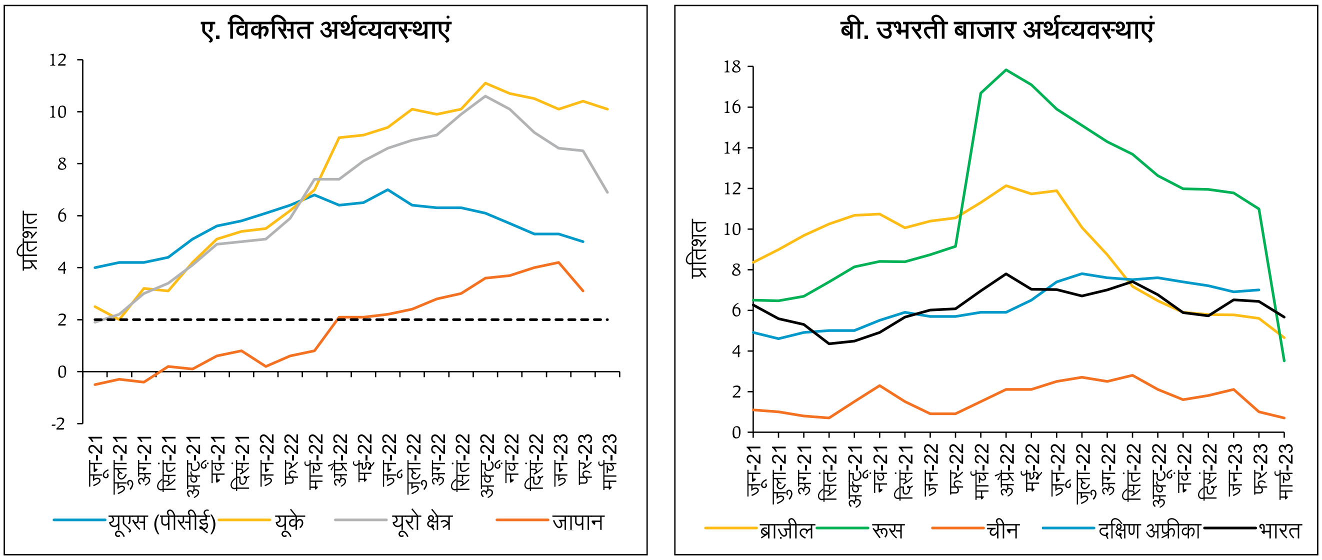

स्रोत: ब्लूमबर्ग; और ओईसीडी।

नकारात्मक गति से प्रेरित थी। हालांकि, ब्रिटेन में खाद्य और गैर-मादक पेय पदार्थों के मूल्यों में माह दर माह वृद्धि के चलते मुद्रास्फीति जनवरी के 10.1 प्रतिशत से फरवरी 2023 में बढ़कर 10.4 प्रतिशत हो गई। जापान की सीपीआई (सभी वस्तुएं कम ताजा खाद्य) मुद्रास्फीति फरवरी में घटकर 3.1 प्रतिशत हो गई, जो जनवरी 2023 में 4.2 प्रतिशत के 40 साल के उच्च स्तर पर थी। ईएमई में, मार्च 2023 में ब्राजील (4.7 प्रतिशत) और चीन (0.7 प्रतिशत) में मुद्रास्फीति में और कमी आई, जबकि फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका में इसमें मामूली वृद्धि हुई। रूस में आधार प्रभाव के कारण मार्च 2023 में यह तेज गिरावट के साथ 3.5 प्रतिशत हो गयी, (चार्ट 6 बी)।

वैश्विक वित्तीय बाजारों ने 10 मार्च 2023 से काफी अस्थिरता का प्रदर्शन किया क्योंकि अमेरिका में कुछ बैंकों के पतन के बाद वित्तीय स्थिरता की चिंताओं ने बाजारों को अस्थिर कर दिया और इक्विटी और बॉण्ड मूल्यांकन में तदनुसार तेजी से परिवर्तन हुआ। बाज़ार ने मार्च के अंत तक नुकसान की भरपाई की और अप्रैल में अब तक (17 अप्रैल तक) उच्च कारोबार जारी रखा क्योंकि संक्रमण की चिंताओं को दूर करने वाले नीतिगत कार्यों पर पुन: विश्वास निर्माण हुआ (चार्ट 7 ए)। रोज़गार और मुद्रास्फीति संबंधी नए आंकड़ों के यह संकेत देने पर कि मौद्रिक नीति का आगे का रुख दरों में उल्लेखनीय वृद्धि का है, यूएस दो वर्षीय जी-सेक प्रतिफल ने 07 मार्च 2023 को पांच प्रतिशत का आंकड़ा छू लिया जो पिछली बार 2007 में उच्च स्तर पर था। तथापि, मार्च में बैंकिंग क्षेत्र के दबाव ने मौद्रिक नीति चक्र में बदलाव की उम्मीद निर्माण की, जिससे प्रतिफल में नरमी आई (चार्ट 7बी)।

फेडरल रिज़र्व के आक्रामक नीतिगत सख्ती से पीछे हटने की धारणा बनने से मार्च में यूएस डॉलर में 2.3 प्रतिशत की गिरावट आई। उसी समय, ईएमई से संबंधित एमएससीआई मुद्रा सूचकांक ने पूंजी प्रवाह अस्थिर रहते हुए भी 1.6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ गति प्राप्त की (चार्ट 7 सी और 7 डी)। अस्थिरता सूचकांक (वीआईएक्स) मार्च 2023 की शुरुआत में अपने स्तरों के सापेक्ष अधिकार क्षेत्रों में काफी कम था (चार्ट 8 ए)। नतीजतन, मार्च के अंत तक प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय स्थिति भी आंशिक रूप से सुकर हो गई (चार्ट 8 बी)।

चार्ट 7: वैश्विक वित्तीय बाजार

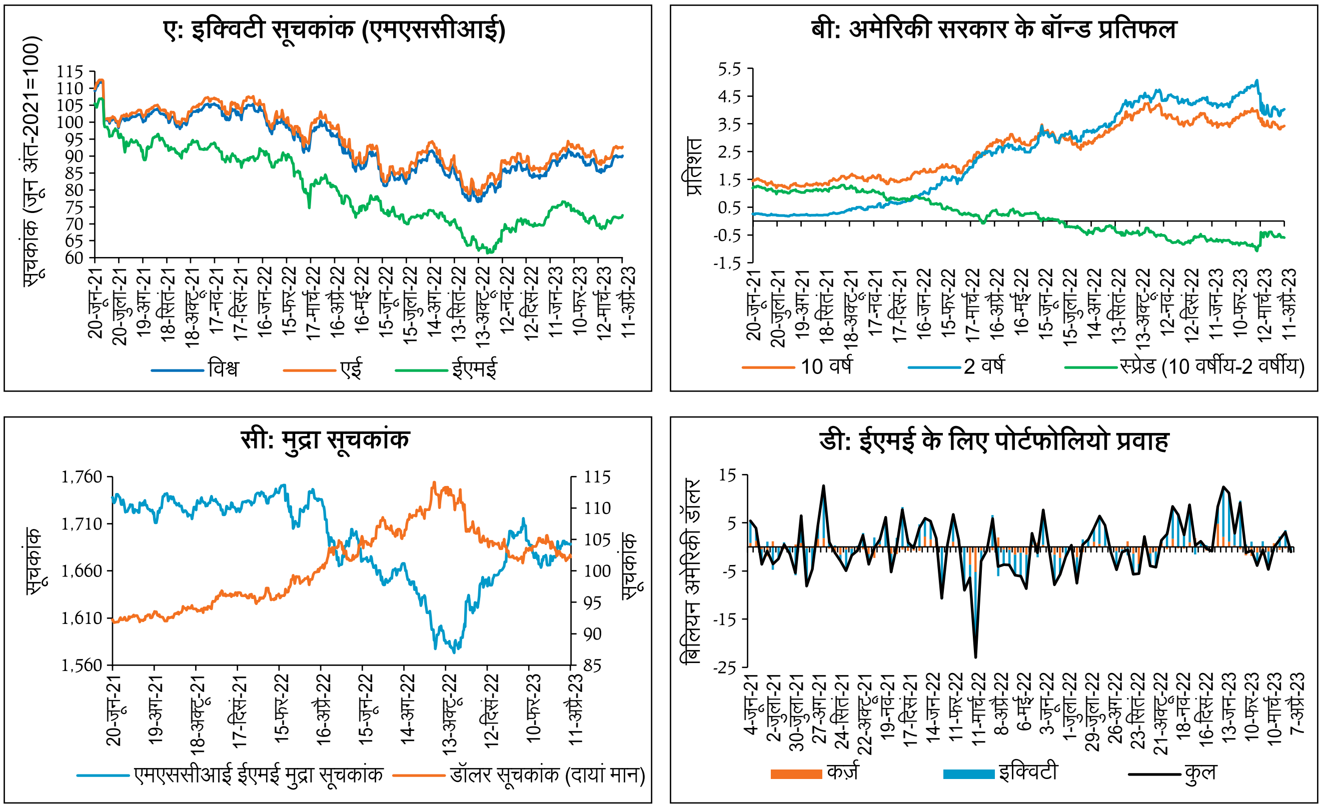

स्रोत: ब्लूमबर्ग; और आईआईएफ।

केंद्रीय बैंकों की प्रवृत्ति ठहराव या छोटी दर वृद्धि की ओर हुई है क्योंकि वित्तीय बाज़ार में अस्थिरता बढ़ने से आर्थिक दृष्टिकोण में अनिश्चितता और भी बढ़ गई है (चार्ट 9 ए)। मार्च 2023 में, यूएस फेडरल ओपन मार्केट कमिटी (एफओएमसी) ने फेडरल निधि दर

चार्ट 8: वैश्विक वित्तीय स्थितियां

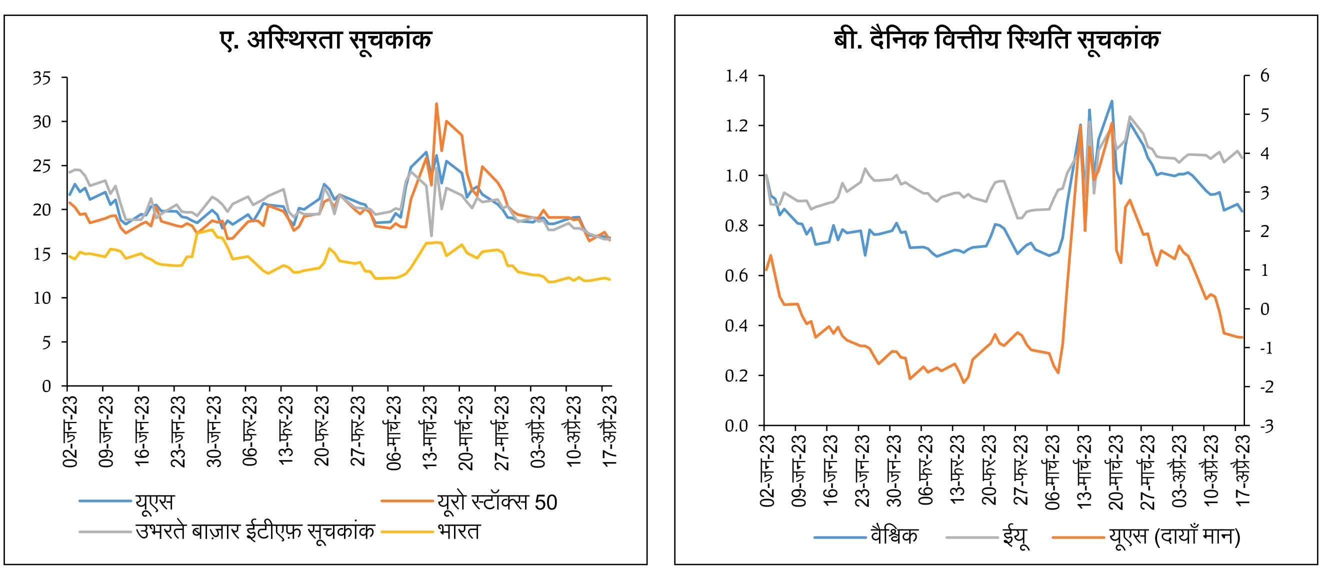

स्रोत: ब्लूमबर्ग।

चार्ट 9: मौद्रिक नीति कार्रवाई

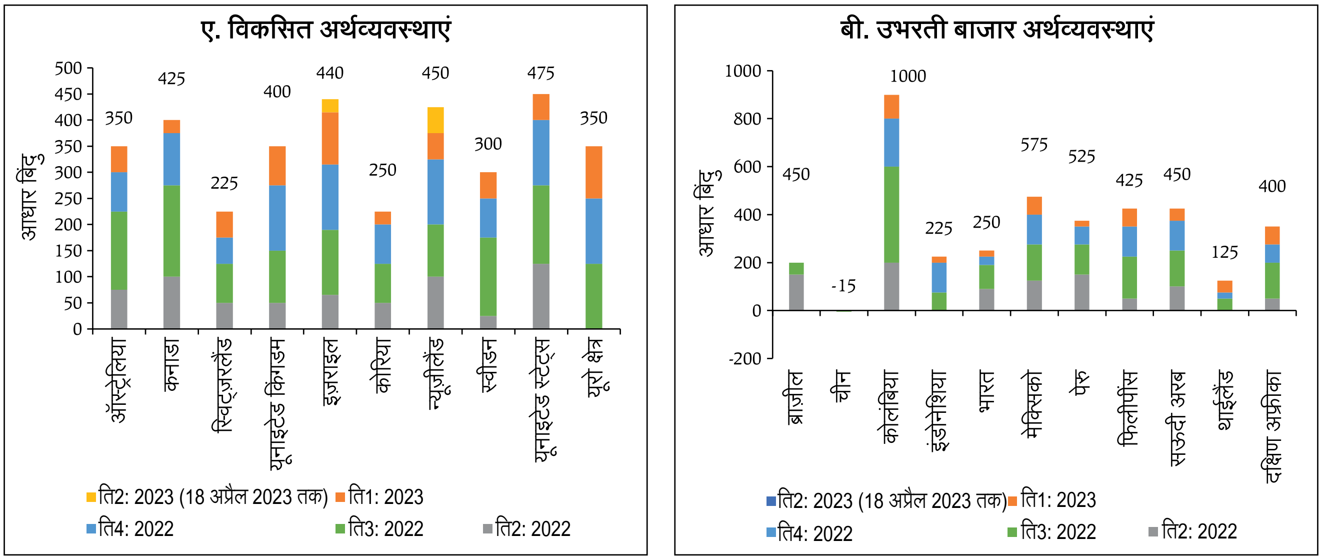

स्रोत : ब्लूमबर्ग।

के लिए अपनी लक्ष्य सीमा में 25 बीपीएस की वृद्धि की, और भविष्य में और भी सख्त नीति अपनाने का संकेत दिया। बैंकिंग क्षेत्र में उथल-पुथल के बाद, यूएस फेड ने मार्च में एक नई ऋण सुविधा - बैंक टर्म फंडिंग प्रोग्राम (बीटीएफपी) की घोषणा की जो बैंकों को अपने सभी जमाकर्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए चलनिधि प्रदान करने के लिए है। इसके अलावा, फेडरल रिज़र्व ने बैंक ऑफ कनाडा, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान, यूरोपीय सेंट्रल बैंक और स्विस नेशनल बैंक के साथ मिलकर 19 मार्च 2023 को स्थायी यूएस डॉलर चलनिधि स्वैप लाइन व्यवस्था के माध्यम से चलनिधि के प्रावधान को बढ़ाने के लिए समन्वित कार्रवाई की घोषणा की। स्विट्जरलैंड और नॉर्वे ने मार्च में अपनी प्रमुख दरों में क्रमशः 50 बीपीएस और 25 बीपीएस की वृद्धि की। रिज़र्व बैंक ऑफ न्यूज़ीलैंड और बैंक ऑफ इज़रायल ने अप्रैल की बैठक में अपनी नीतिगत दरों में क्रमश: 50 आधार अंक और 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की, जबकि ऑस्ट्रेलिया, कोरिया और सिंगापुर ने कोई परिवर्तन नहीं किया।

अधिकांश ईएमई केंद्रीय बैंकों ने भी अपेक्षाकृत कम आक्रामक मौद्रिक नीति कार्रवाई को अपनाया (चार्ट 9 बी)। मार्च 2023 में, मेक्सिको और फिलीपींस ने अपनी नीतिगत दरों में 25-25 बीपीएस की वृद्धि की, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने 50 बीपीएस की वृद्धि की। इंडोनेशिया, पेरू और रोमानिया ने फरवरी में अपनी प्रमुख दरों को अपरिवर्तित रखा, जबकि चिली ने अप्रैल की बैठक में अपनी नीतिगत दर को समान रखा। इसके विपरीत, चीन ने 27 मार्च 2023 से वित्तीय संस्थानों के लिए आवश्यक आरक्षित अनुपात (आरआरआर) को 25 बीपीएस से कम करते हुए अपने उदार रुख को जारी रखा।

III. घरेलू विकास

जैसा कि विभिन्न उच्च आवृत्ति संकेतकों से संकेत मिलता है अनिश्चित वैश्विक दृष्टिकोण के बीच भी भारतीय अर्थव्यवस्था समुत्थानशील रही। भारत के लिए हमारा आपूर्ति शृंखला दबाव सूचकांक (आईएसपीआई) जुलाई 2022 के बाद से अपने ऐतिहासिक औसत से नीचे के स्तर पर बना हुआ है (चार्ट 10)।

चार्ट 10: भारत के लिए आपूर्ति श्रृंखला दबाव का सूचकांक

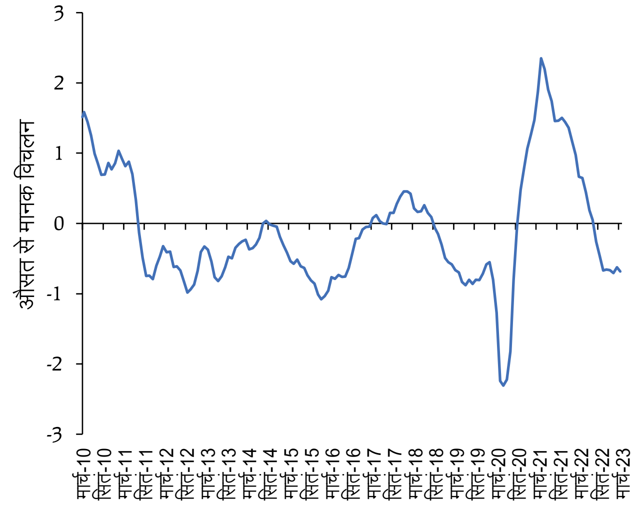

स्रोत: आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

आर्थिक गतिविधि सूचकांक (ईएआई), जो 27 उच्च आवृत्ति संकेतकों के एक समूह में होने वाले उताव-चढ़ाव पर नज़र रखता, ने संकेत दिया कि 2022-23 की चौथी तिमाही में हुई समग्र आर्थिक गतिविधि ने फरवरी में कुछ गति हासिल की होगी (चार्ट 11ए)। 2022-23 की चौथी तिमाही के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि का हमारा अनुमान (नाऊकास्ट्) 5.4 प्रतिशत है (चार्ट 11बी)।

कुल मांग

मांग की स्थिति के प्रमुख संकेतकों में, ई-वे बिल की मात्रा और टोल संग्रह में तेजी बनी रही, जो मार्च 2023 में नई ऊंचाई पर पहुंच गई (चार्ट 12 ए और 12 बी), जबकि मार्च 2023 में औसत बिजली उत्पादन में कमी आई, जिसमें बेमौसम बारिश के कारण तापमान में हुई गिरावट का भी आंशिक रूप से योगदान रहा (चार्ट 12 सी)।

मार्च 2023 में, ईंधन की दैनिक औसत खपत एक नए शिखर तक पहुंच गई (चार्ट 13 ए)। गैर-परिवहन और परिवहन वाहनों के पंजीकरण में वृद्धि के कारण वाहनों की खुदरा बिक्री, जो वाहन पंजीकरण से ज्ञात होती है, मार्च में चार महीने के उच्च स्तर पर दर्ज की गई(चार्ट 13 सी) ।

दोपहिया वाहनों की बिक्री सालाना आधार पर 7.7 प्रतिशत बढ़ी और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खंड में मार्च में अब तक की सबसे अधिक 1.4 लाख बिक्री दर्ज की गई। होली के त्योहार के

चार्ट 11: आर्थिक गतिविधि और जीडीपी का तात्कालिक पूर्वानुमान

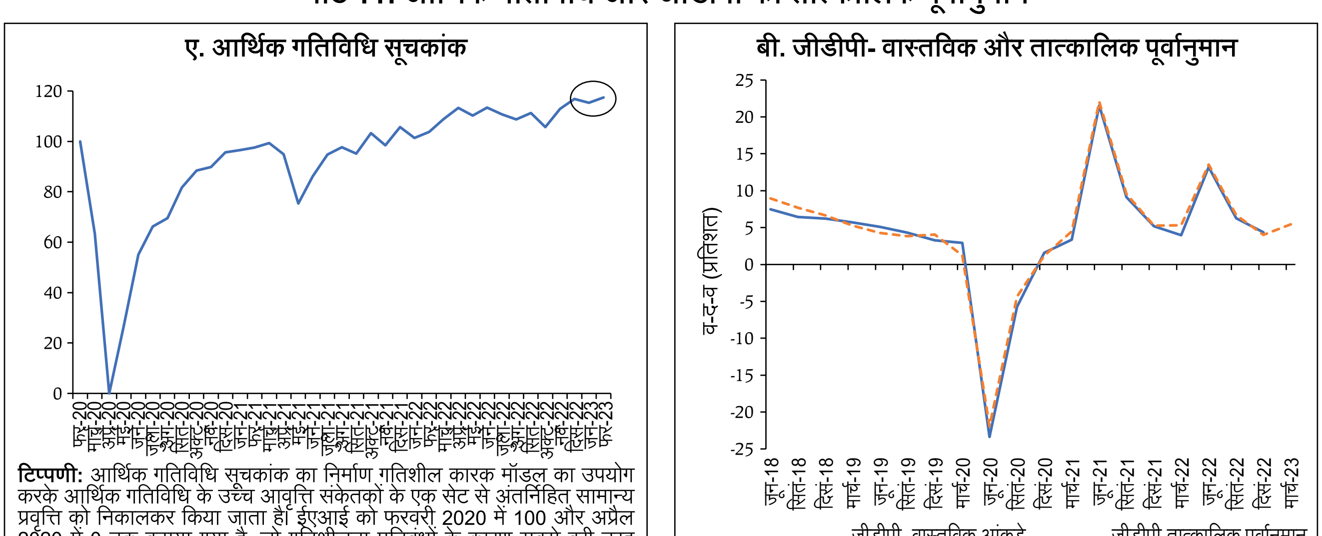

टिप्पणी: आर्थिक गतिविधि सूचकांक का निर्माण गतिशील कारक मॉडल का उपयोग करके आर्थिक गतिविधि के उच्च आवृत्ति संकेतकों के एक सेट से अंतर्निहित सामान्य प्रवृत्ति को निकालकर किया जाता है| ईएआई को फरवरी 2020 में 100 और अप्रैल 2020 में 0 तक बढ़ाया गया है, जो गतिशीलता प्रतिबंधों के कारण सबसे बुरी तरह प्रभावित महीना है|

स्रोत: आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

चार्ट 12: ई-वे बिल, टोल संग्रह और विद्युत आपूर्ति

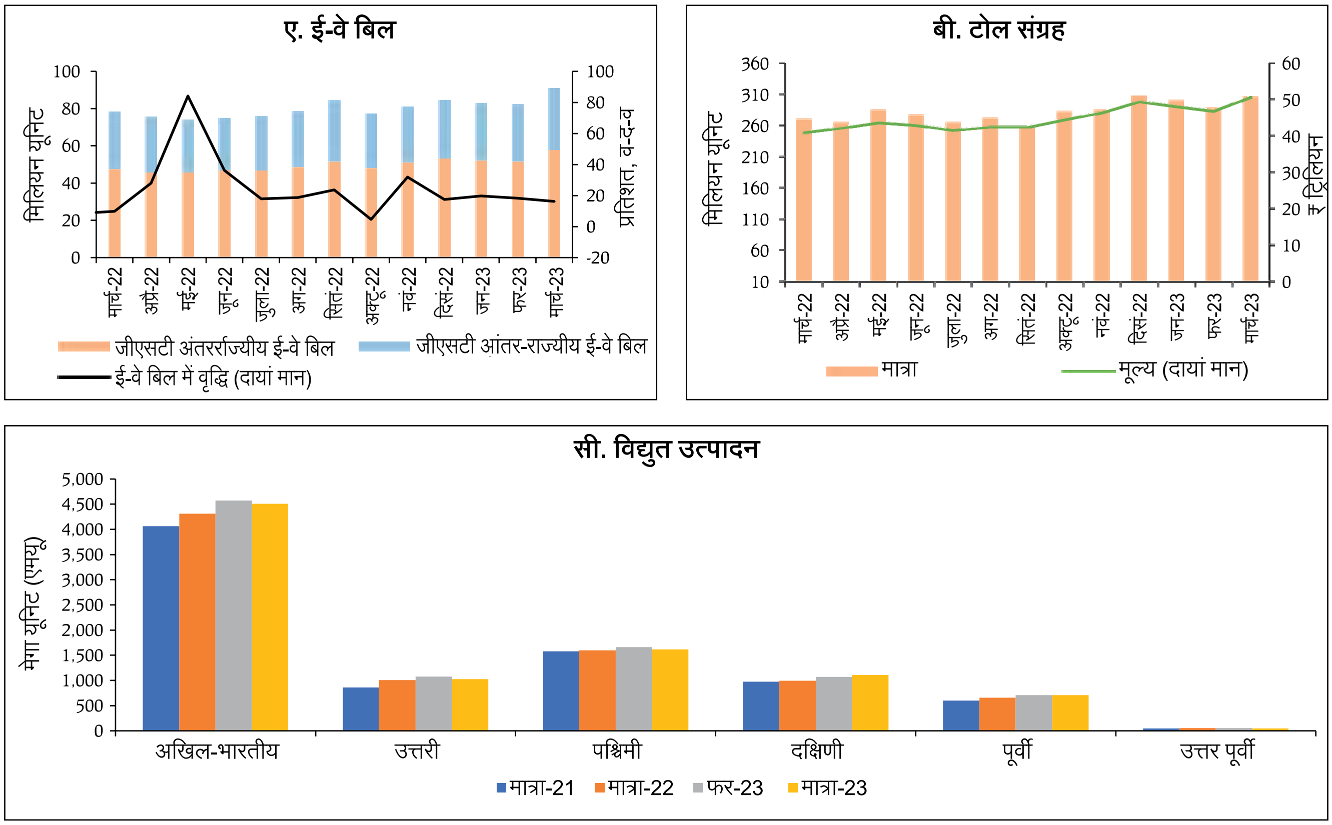

स्रोत: जीएसटीएन; आरबीआई; पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

दौरान अच्छी मांग के कारण मोटरसाइकिलों और तिपहिया वाहनों की बिक्री में भी तेजी आई। इसके बाद बीएस 6 चरण-2 (अप्रैल 2023 से लागू होने वाले)[6] से पहले खरीद में वृद्धि हुई। ट्रैक्टर की बिक्री में वृद्धि लगातार चौथे महीने दोहरे अंकों में रही, जिसमें फसल की बेहतर कीमतों का योगदान रहा (चार्ट 13 डी)।

पर्यटन क्षेत्र में, महामारी की शुरुआत के बाद पहली बार होटल अधिभोग दर 70 प्रतिशत को पार कर गई (चार्ट 14 ए)। एक वर्ष पहले की तुलना में फरवरी 2023 में औसत कमरे की दरों में भी तेजी से वृद्धि हुई, जिससे प्रति उपलब्ध कमरे राजस्व (आरईवीपीएआर) में वृद्धि हुई [चार्ट 14बी]।

मांग की स्थिति में सुधार से व्यापार क्षेत्र द्वारा क्षमता वृद्धि के प्रयास हुए जैसा कि उनके निवेश इरादों में परिलक्षित होता है (चार्ट 15)। बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत के तिमाही औसत में वृद्धि हुई।

रिज़र्व बैंक के उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीसीएस) में रिपोर्ट की गई आर्थिक स्थितियों के परिवारों के आकलन से पता चलता है कि 2021 के मध्य में अपने ऐतिहासिक निचले स्तर से उपभोक्ता विश्वास में निरंतर वृद्धि हुई है (चार्ट 16)। रिज़र्व बैंक के एंटरप्राइज़ सर्वेक्षणों की प्रमुख बातों को अनुबंध-1 में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के अनुसार, अखिल भारतीय बेरोजगारी दर मार्च 2023 में 7.8

6 https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/industry/auto-wholesales-in-march-pv-tractor-record-best-ever-2w-recovery-yet-to-happen/99206949

चार्ट 13: ऑटोमोबाइल क्षेत्र संकेतक

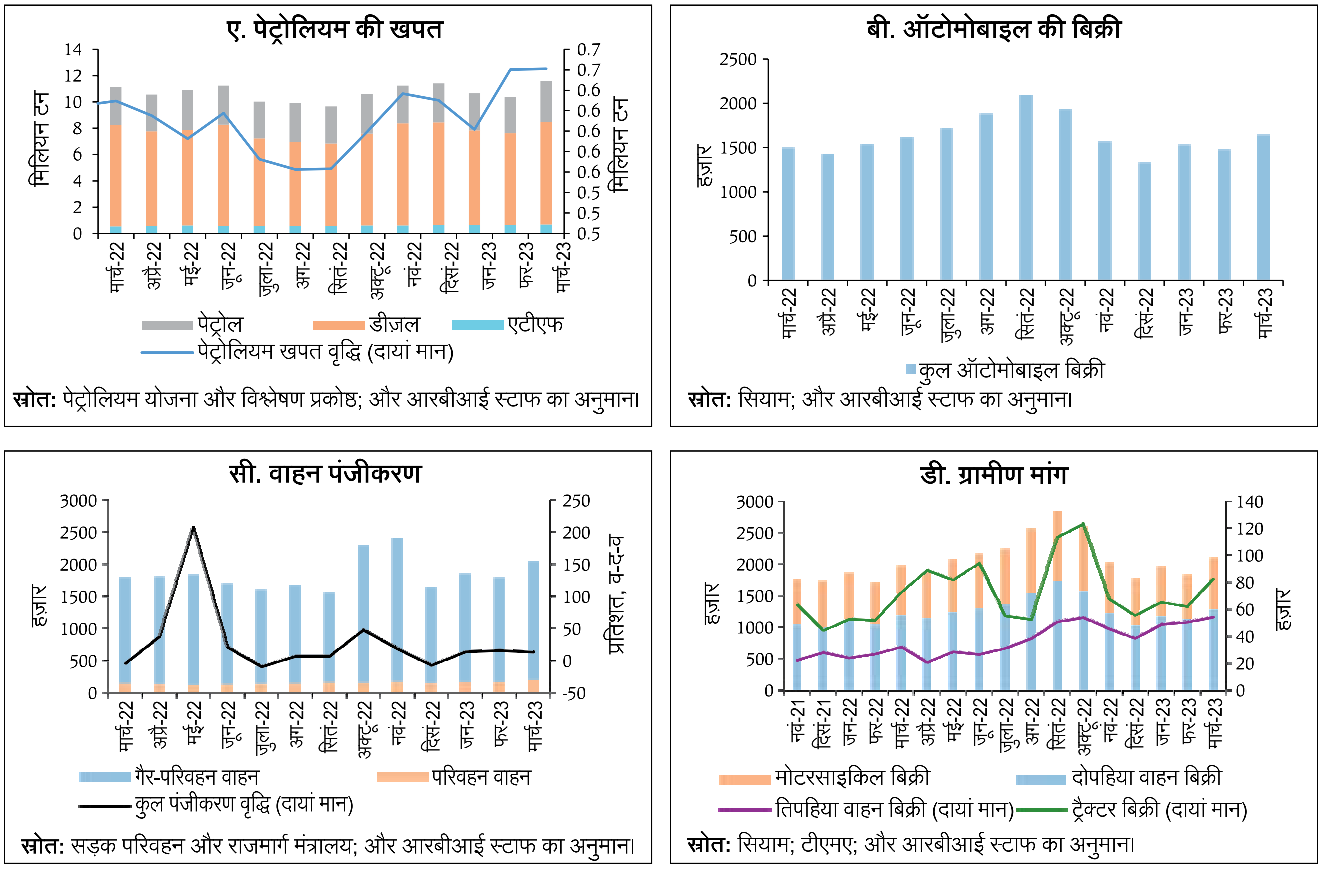

स्रोत: पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

स्रोत: सियाम; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

स्रोत: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

स्रोत: सियाम; टीएमए; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

प्रतिशत हो गई, जो एक महीने पहले 7.5 प्रतिशत थी (चार्ट 17ए)। रोजगार दर (ईआर) और श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) में गिरावट आई (चार्ट 17 बी)।

चार्ट 14: होटल क्षेत्र संकेतक

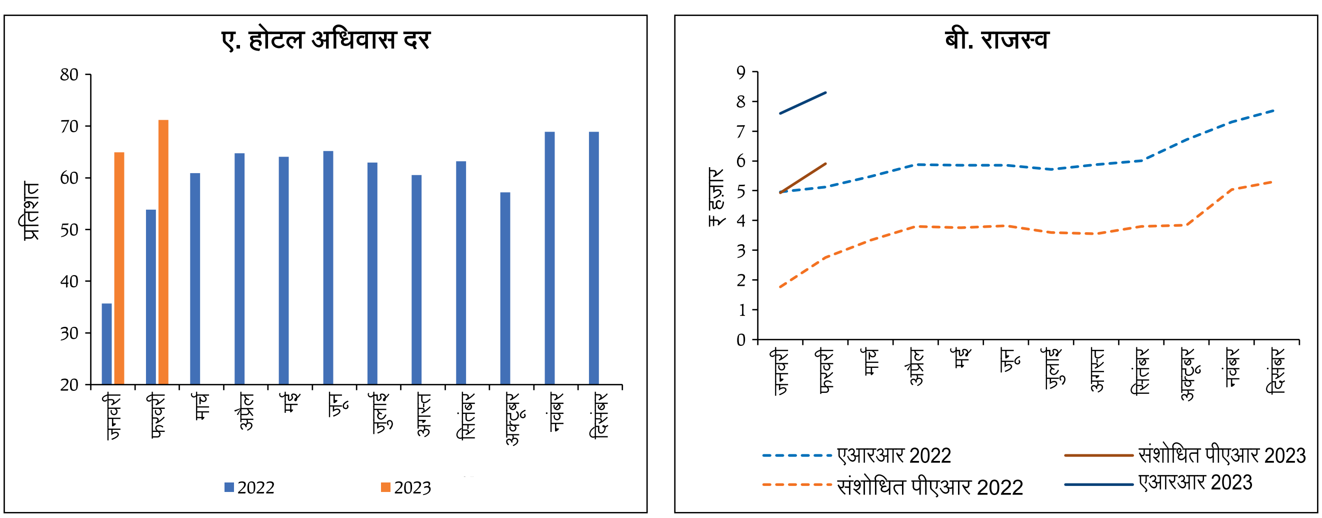

टिप्पणी: एआरआर: औसत कमरा (कमरे का राजस्व दिए गए / अधिवास वाले कमरों की संख्या से विभाजित); संशोधित पीएआर: प्रति उपलब्ध कमरे का राजस्व (कमरे का राजस्व किसी निश्चित अवधि में उपलब्ध कमरों की संख्या से विभाजित)।
स्रोत: एचवीएस एनारॉक; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

चार्ट 15: निजी गैर-वित्तीय क्षेत्र द्वारा निवेश के इरादे

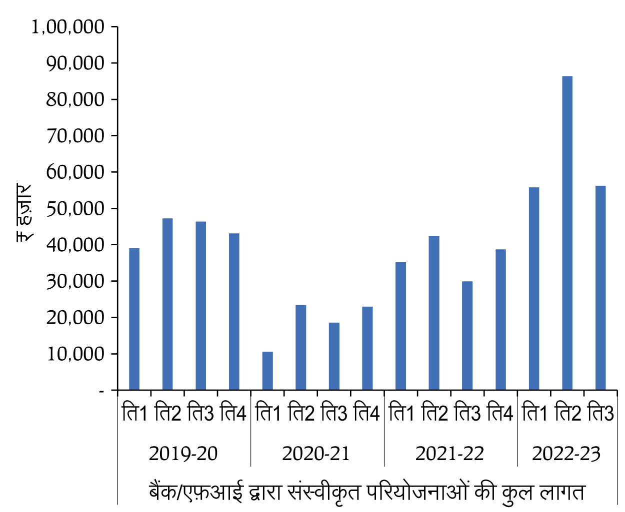

स्रोत: चुनिंदा बैंकों/वित्तीय संस्थानों से एकत्र किए गए परियोजना वित्त डेटा और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

चार्ट 16: उपभोक्ता विश्वसनीयता सूचकांक

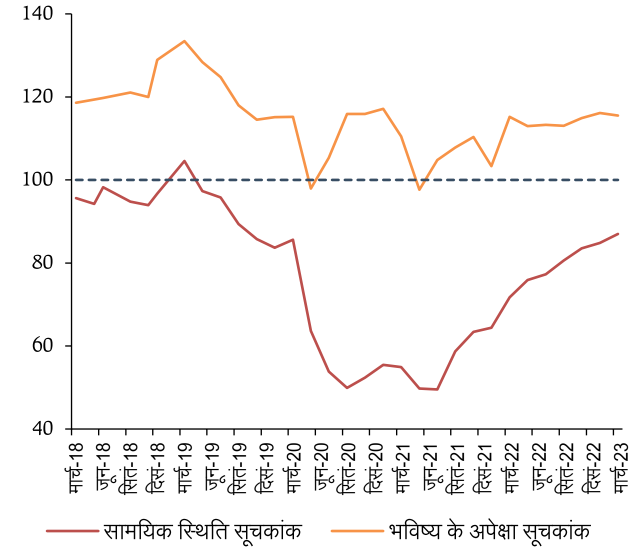

स्रोत : सीसीएस; आरबीआई।

विनिर्माण पीएमआई द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार संगठित विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार मार्च 2022 के बाद पहली बार मार्च 2023 में कमजोर हो गया (चार्ट 18)। सेवा क्षेत्र में रोजगार में हालांकि मार्च में मामूली वृद्धि दर्ज की गई।

रबी की बुवाई समाप्त होने के साथ ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत काम की मांग में मार्च माह-दर-माह (एम-ओ-एम) में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर नकारात्मक बनी हुई है, जो एक साल पहले की

चार्ट 17: श्रम बाजार की स्थिति

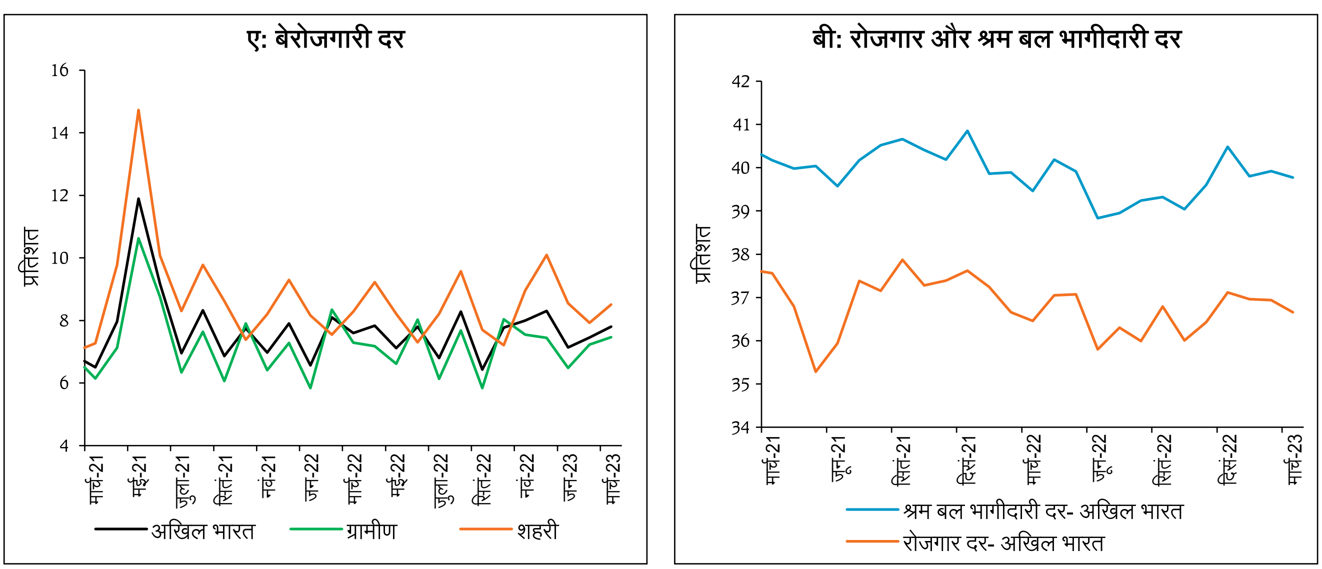

स्रोत: सीएमआईई।

चार्ट 18: पीएमआई रोजगार सूचकांक

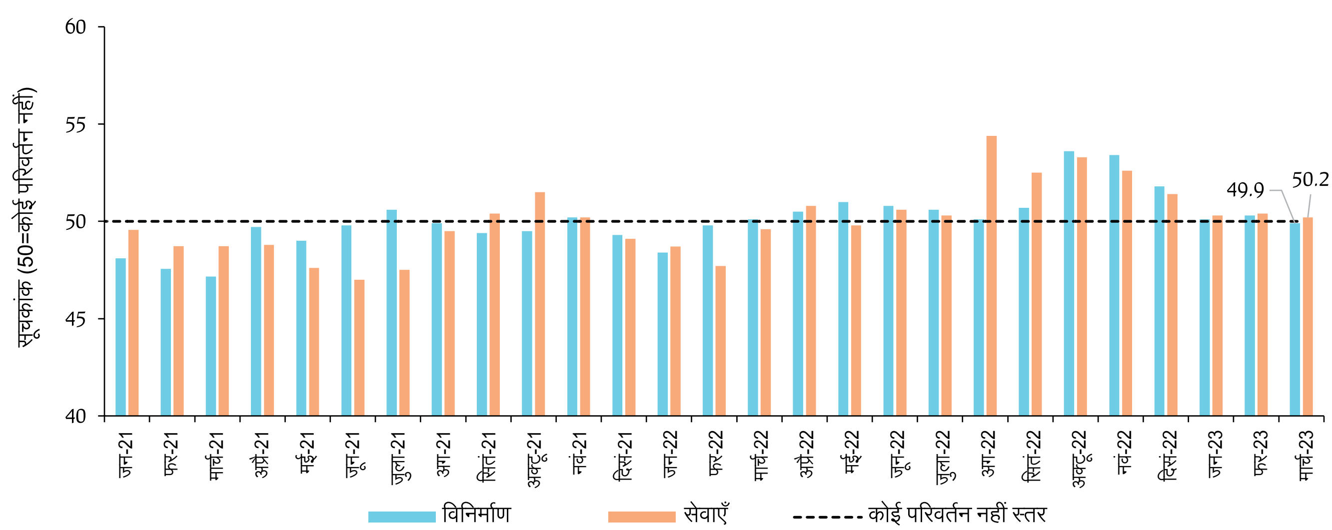

टिप्पणी: 50 से ऊपर का क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) विस्तार को दर्शाता है।
स्रोत: एस एंड पी ग्लोबल।

तुलना में ग्रामीण श्रम बाज़ार की स्थिति में सुधार को दर्शाती है (चार्ट 19ए)। ग्रामीण मजदूरों को उच्च मुद्रास्फीति की कठिनाइयों से बचाने के लिए, केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा के तहत दैनिक मजदूरी को 01 अप्रैल 2023 से 2 से 10 प्रतिशत (₹ 7 - ₹ 26 / दिन) तक संशोधित किया गया है (चार्ट 19बी)।

भारत के व्यापारिक[7] निर्यात में माह-दर-माह आधार पर 3.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो मार्च 2023 में 9 महीने के उच्च स्तर 38.4 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गया (चार्ट 20)। वार्षिक आधार पर प्रतिकूल आधार प्रभाव के कारण निर्यात में 13.9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। कुल मिलाकर, 2022-23 में

चार्ट 19: काम की मांग और मनरेगा में मजदूरी में संशोधन

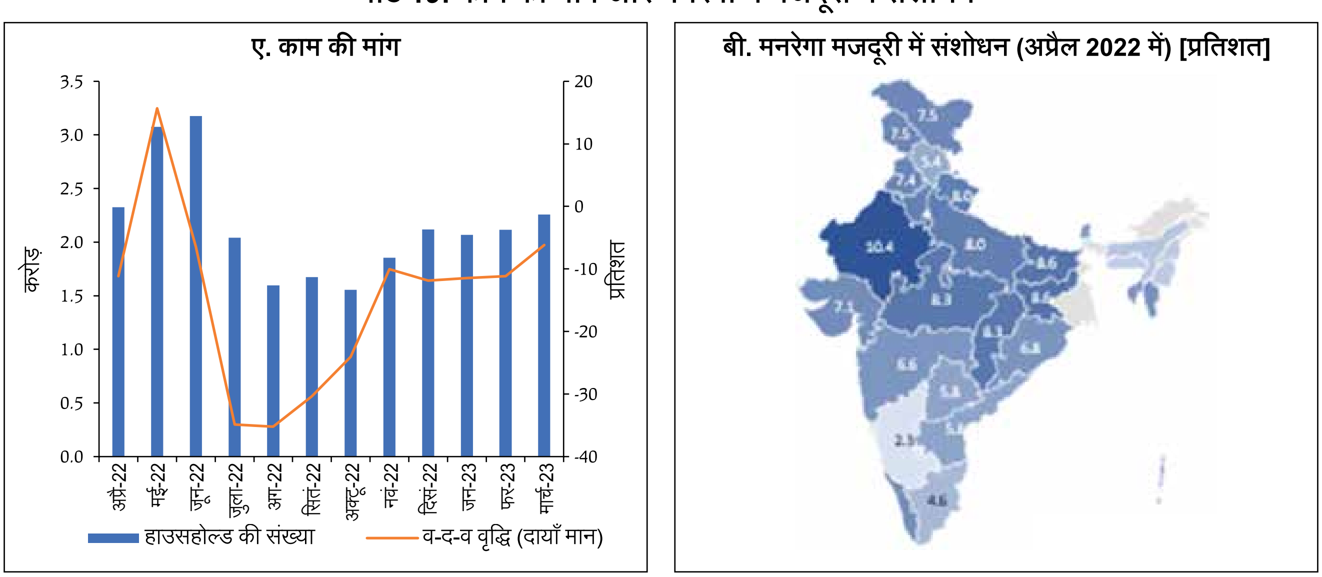

स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय।

7 वस्तु व्यापार का विश्लेषण वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा 13 अप्रैल 2023 की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार है।

चार्ट 20: पण्य वस्तु निर्यात

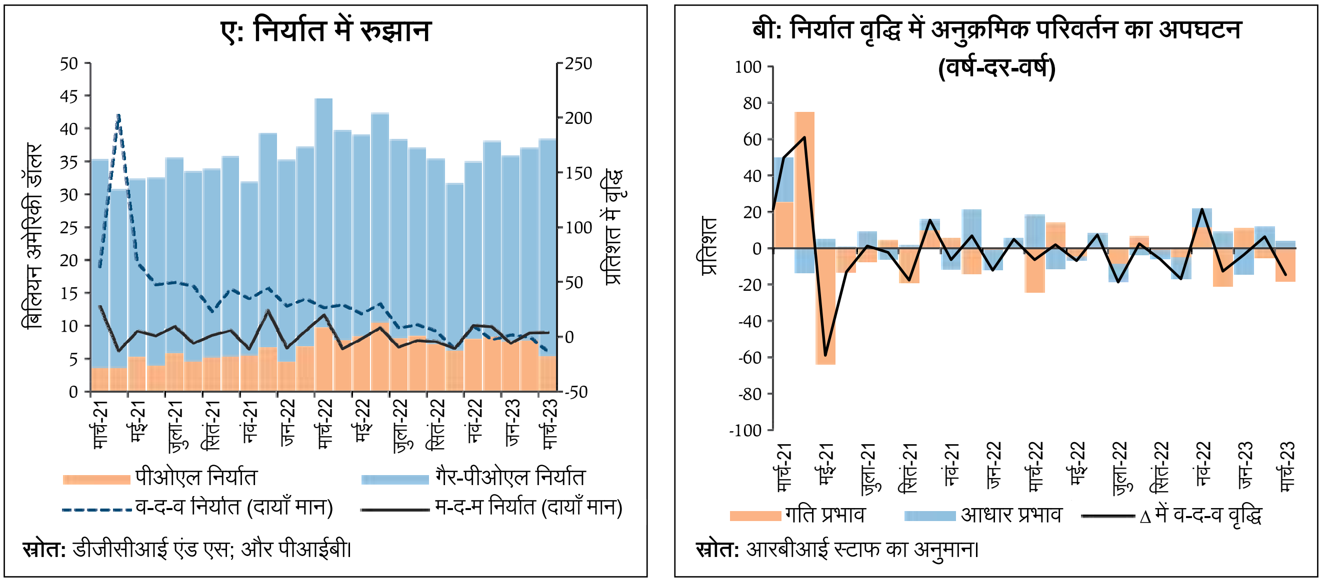

व्यापारिक निर्यात 447.5 बिलियन यूएस डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले वर्ष के स्तर से 6.0 प्रतिशत अधिक है।

30 प्रमुख जिंसों में से निर्यात बास्केट में 68.7 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाली 17 जिंसों में मार्च 2023 में सालाना आधार पर गिरावट दर्ज की गई। पेट्रोलियम उत्पादों, रत्न और आभूषण और इंजीनियरिंग वस्तुओं ने निर्यात में गिरावट लाई जबकि इलेक्ट्रॉनिक सामान, ऑयल मील (अलसी की खली) और चावल ने मार्च में निर्यात वृद्धि का समर्थन किया (चार्ट 21 ए)। मार्च में लगातार आठवें महीने गैर-तेल निर्यात में गिरावट दर्ज की गई। वार्षिक आधार पर, पेट्रोलियम उत्पाद 2022-23 में निर्यात वृद्धि के प्रमुख चालक थे। कुल निर्यात में उनकी हिस्सेदारी 2021-22 में 16.0 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर 21.1 प्रतिशत हो गई। गैर-तेल उत्पादों में, इलेक्ट्रॉनिक सामान, चावल और

चार्ट 21: निर्यात वृद्धि में सापेक्ष योगदान

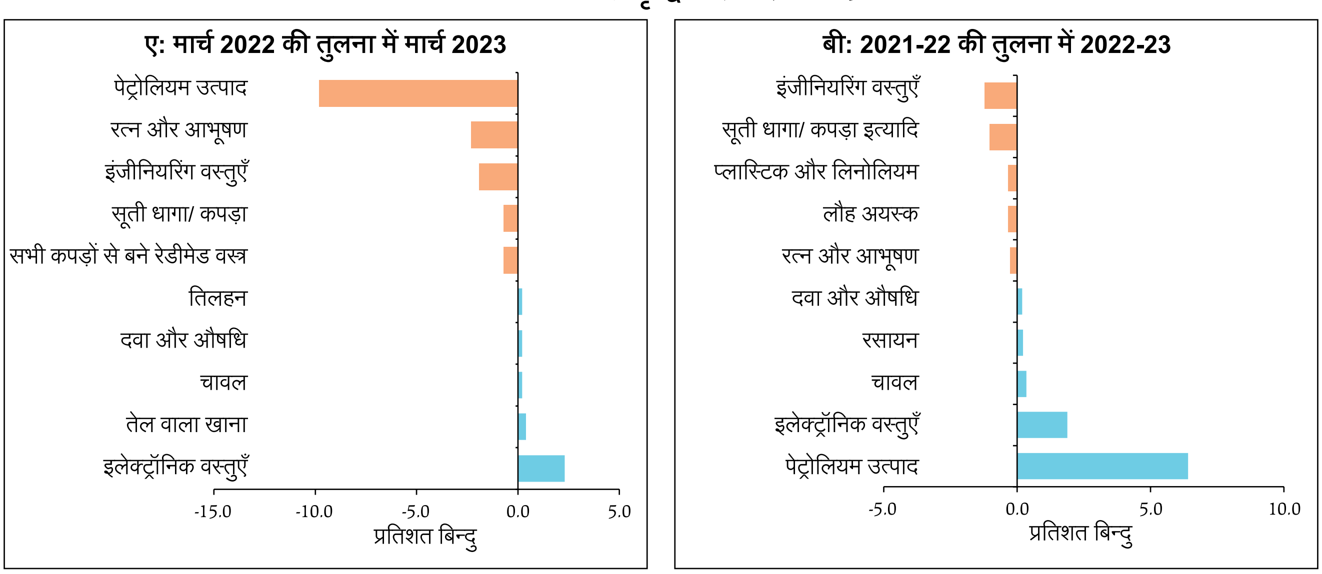

स्रोत: पीआईबी; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

रसायनों के कारण निर्यात में वृद्धि हुई, जबकि इंजीनियरिंग सामान, सूती धागा, कपड़े, प्लास्टिक और लिनोलियम का 2022-23 की निर्यात में नकारात्मक योगदान रहा (चार्ट 21 बी)।

भारत ने 2022-23 में रक्षा वस्तुओं का अब तक का सर्वोत्तम निर्यात दर्ज किया, जिसमें "आत्मनिर्भर भारत" जैसी नीतियों का लाभ उठाते हुए सात वर्षों की अवधि में निर्यात दस गुना बढ़ गया है (चार्ट 22)। खुली सामान्य निर्यात लाइसेंस नीति की शुरुआत, एंड-टू-एंड ऑनलाइन एक्सपोर्ट ऑथराइजेशन को सरल बनाना और रक्षा औद्योगिक गलियारों की स्थापना सहित हाल की पहल भारत के रक्षा निर्यात के लिए शुभ संकेत हैं।

हालिया नरमी के बावजूद, भारत के व्यापारिक निर्यात ने मार्च 2023 तक लागू पिछली विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के तत्वावधान में 2015-16 और 2022-23 के बीच 7.9 प्रतिशत की समस्त वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) दर्ज की (चार्ट 23)। सरकार ने 31 मार्च 2023 को एफटीपी 2023 की घोषणा की, जिसका उद्देश्य लेनदेन लागत को कम करना और प्रोसेस री-इंजीनियरिंग और स्वचालन के माध्यम से व्यापार करने में आसानी को प्रोत्साहित करना है। एफटीपी नीति निर्यात को सुविधाजनक बनाने वाली परखी गई योजनाओं पर आधारित होगी और व्यापार की उभरती आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी होगी।

चार्ट 22: भारत का रक्षा निर्यात

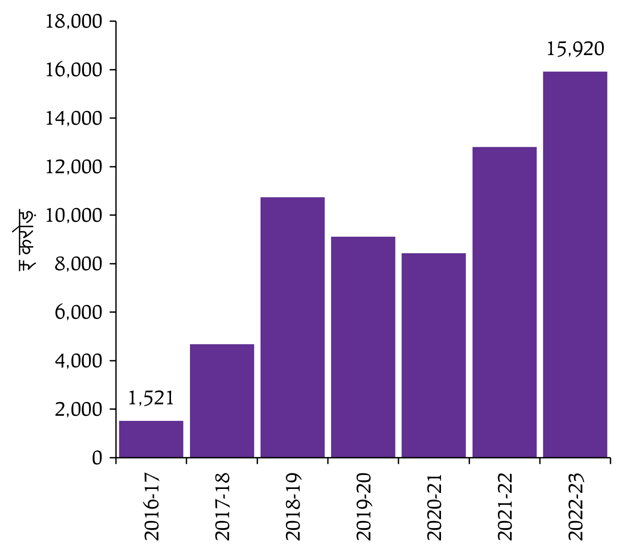

स्रोत : पीआईबी।

चार्ट 23: भारत का पण्य वस्तु निर्यात

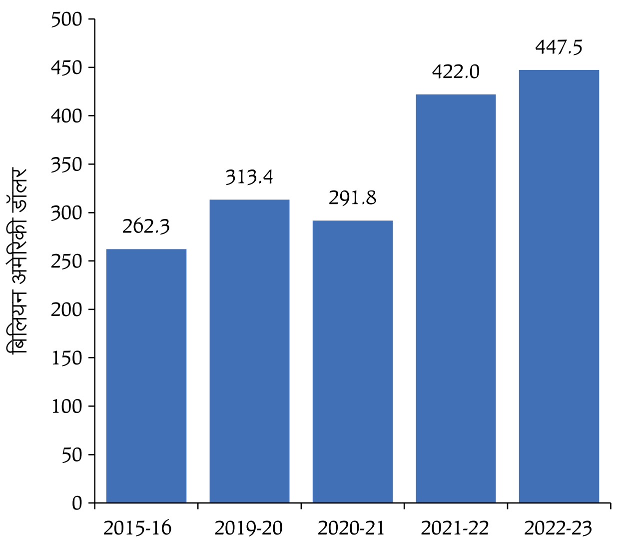

स्रोत: डीजीसीआईएस; और पीआईबी।

मार्च 2023 में 58.1 बिलियन यूएस डॉलर के व्यापारिक आयात में 9.1 प्रतिशत की सकारात्मक गति दर्ज की गई (चार्ट 24)। हालांकि, वर्ष-दर-वर्ष आधार पर बड़े आधार प्रभाव के कारण उनमें लगातार तीसरे महीने गिरावट दर्ज की गई।

अलग-अलग स्तर पर देखें तो आयात बास्केट में 65.5 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाली 14 प्रमुख वस्तुओं में गिरावट दर्ज की गई। पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक (पीओएल), इलेक्ट्रॉनिक सामान और कोयला मुख्य वस्तुएं थीं जिन्होंने समग्र आयात में गिरावट लाई, जबकि स्वर्ण, मशीनरी और धातु अयस्कों और अन्य खनिजों ने मार्च में सकारात्मक योगदान दिया (चार्ट 25 ए)। कुल मिलाकर, वस्तु आयात भी 2022-23 में 714.2 बिलियन यूएस डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो वर्ष-दर-वर्ष 16.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। पीओएल, कोयला और परिवहन उपकरणों के कारण वार्षिक आयात में वृद्धि हुई, जबकि स्वर्ण, औषधीय उत्पाद, और मोती, कीमती और अर्ध-कीमती पत्थरों के कारण वृद्धि में गिरावट आई (चार्ट 25 बी)।

चार्ट 24: पण्य वस्तु आयात

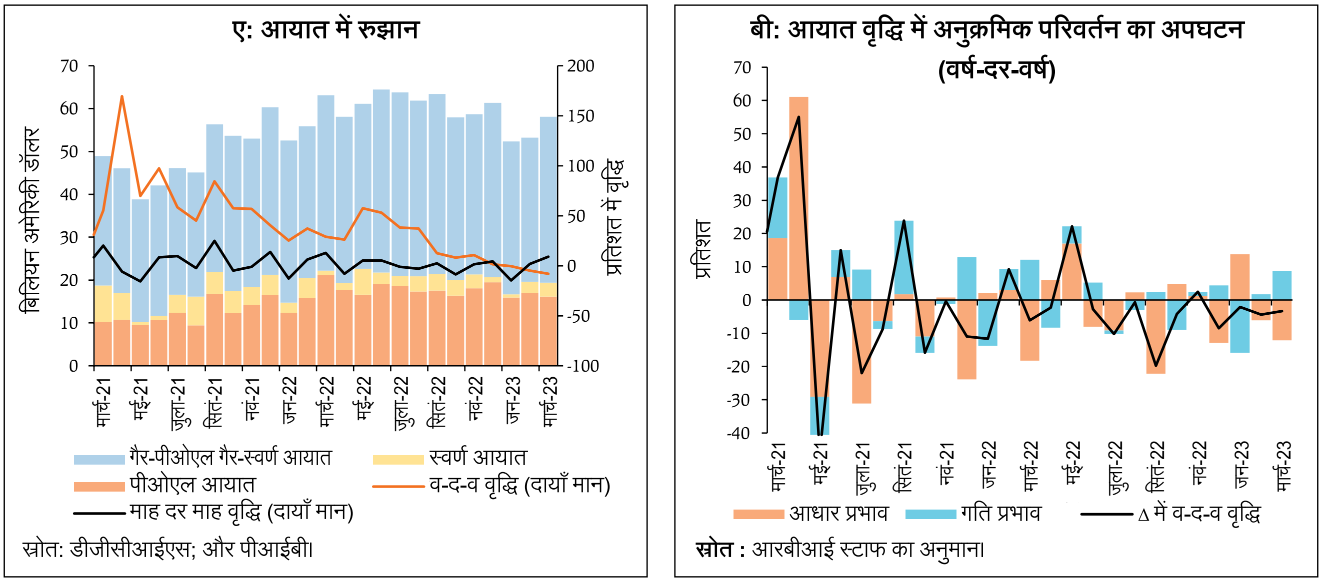

कृषि जिंसों में हाल के वर्षों में दालों पर आयात निर्भरता कम हुई है। दालों की कुल खपत में आयात का आयात निर्भरता अनुपात 2013-14 के 19.0 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में लगभग 8.0 प्रतिशत रह गया है। हाल के वर्षों में दालों के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है और 2022-23 में 27.8 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है, जिससे निर्यात को प्रोत्साहित करते हुए आयात निर्भरता को और कम करके भारत को दालों में आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी (चार्ट 26)।

चार्ट 25: आयात वृद्धि में सापेक्ष योगदान

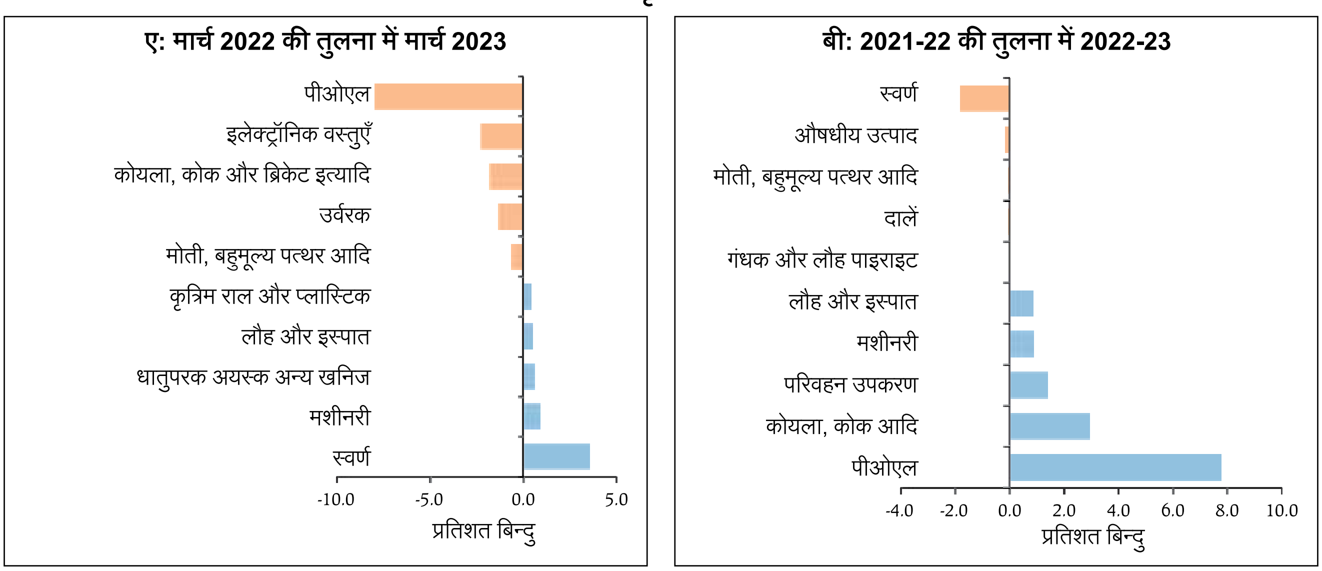

स्रोत: पीआईबी; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

चार्ट 26: दाल उत्पादन और व्यापार में रुझान

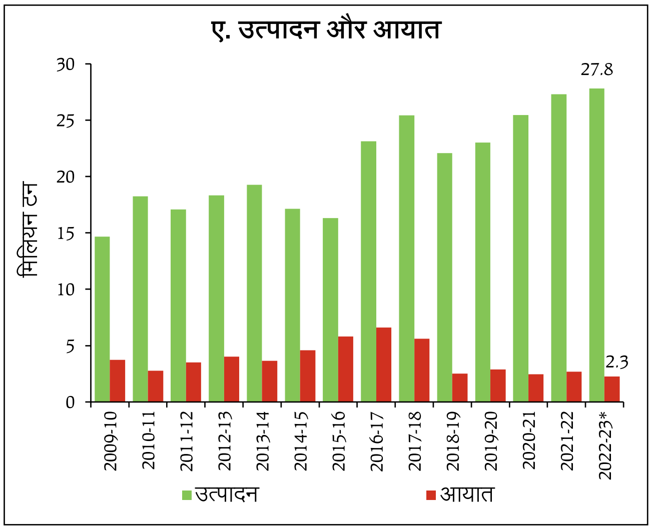

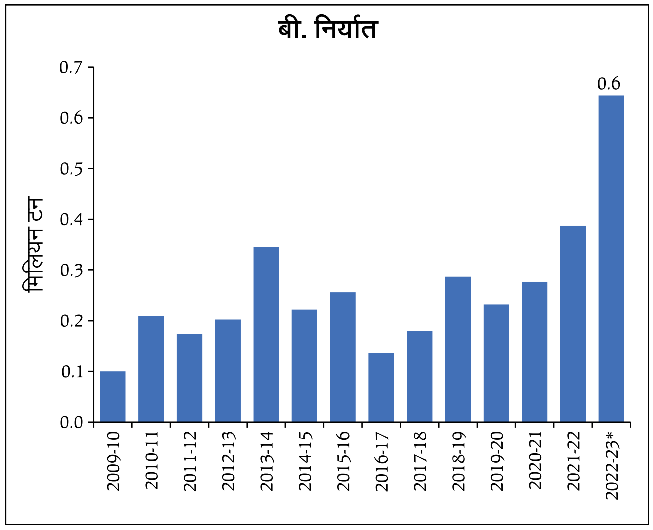

* उत्पादन के आंकड़े दूसरा अग्रिम अनुमान है, जबकि आयात और निर्यात के आंकड़े फरवरी 2022-23 तक हैं।
स्रोत: कृषि मंत्रालय; और डीजीसीआईएस।

निर्यात की तुलना में आयात में तेजी से क्रमिक वृद्धि के कारण, मार्च 2023 में पण्य व्यापार घाटा बढ़कर 19.7 बिलियन यूएस डॉलर हो गया। 2022-23 में, भारत का व्यापार घाटा बढ़कर 266.8 बिलियन यूएस डॉलर हो गया, जो पिछले वर्ष के स्तर का 1.4 गुना है। घाटे में वृद्धि मुख्य रूप से पेट्रोलियम उत्पादों के कारण हुई, जो एक साल पहले की तुलना में 22.0 प्रतिशत अधिक थी (चार्ट 27)।

वित्त वर्ष 2022-23 (अप्रैल-फरवरी 2022-23) के दौरान केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति मजबूत बनी रही, जिसमें आयकर, निगम कर और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) जैसे प्रमुख कर

चार्ट 27: व्यापार घाटे का अपघटन

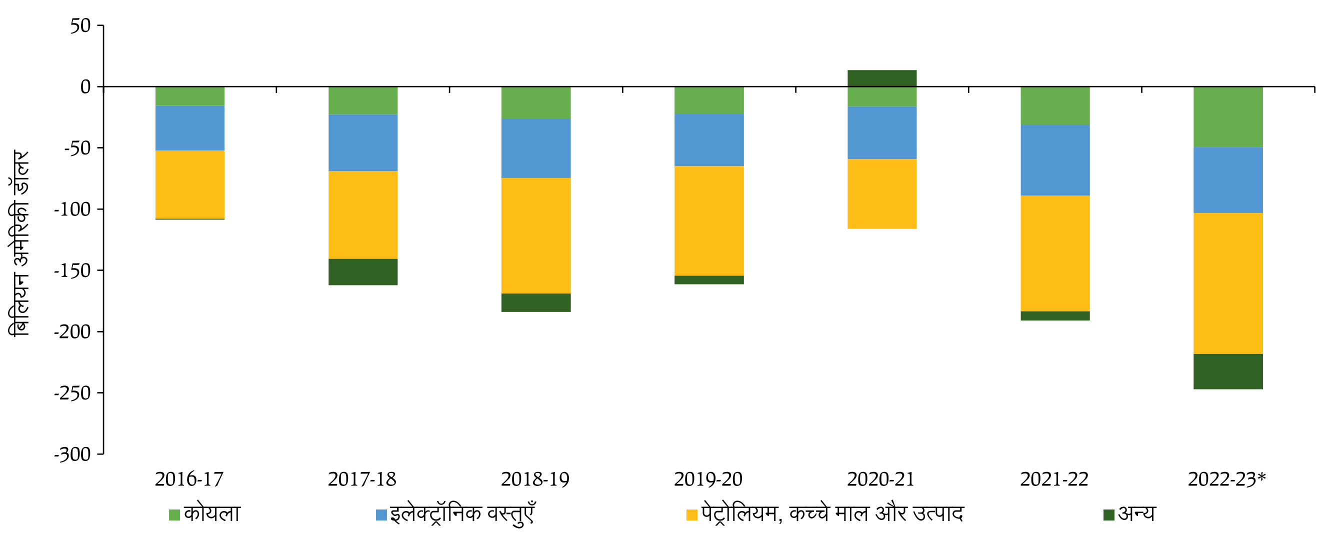

* नवीनतम महीने के आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण मार्च 2023 के लिए कोयले के निर्यात का मूल्य फरवरी 2023 के बराबर माना गया।
स्रोत: डीजीसीआईएस; और आरबीआई स्टाफ की गणना।

चार्ट 28: अप्रैल-फरवरी के दौरान व्यय वृद्धि और गुणवत्ता

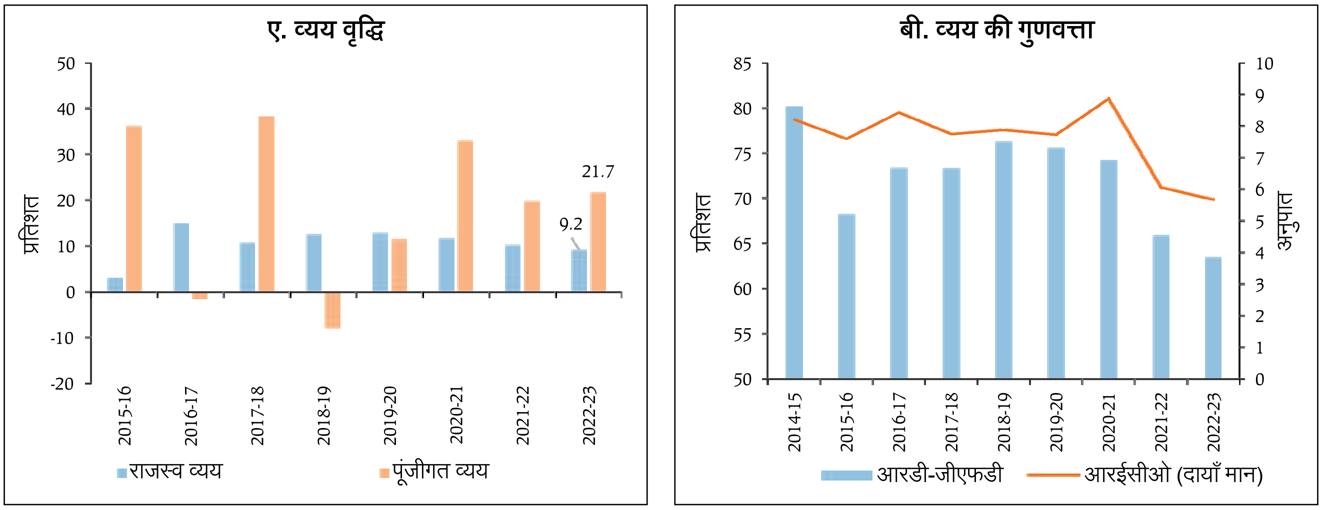

टिप्पणी: 1. आरडी-जीएफडी राजस्व घाटा है जो सकल राजकोषीय घाटे के प्रतिशत के रूप में व्यक्त होता है।
2. आरईसीओ राजस्व व्यय और पूंजीगत परिव्यय के अनुपात को संदर्भित करता है।
स्रोत: महालेखा नियंत्रक (सीजीए); केंद्रीय बजट दस्तावेज और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

शीर्षों के तहत कर संग्रह में तेजी के कारण मदद मिली। व्यय के मोर्चे पर, सब्सिडी पर खर्च में वृद्धि के बावजूद, पूंजीगत व्यय पर जोर देने से व्यय की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है। यह राजस्व व्यय में 9.2 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में पूंजीगत परिव्यय में 16.7 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि में परिलक्षित होता है। इसके परिणामस्वरूप राजस्व व्यय-पूंजी परिव्यय (आरईसीओ) अनुपात में कमी आई, जो व्यय की गुणवत्ता का संकेतक है (चार्ट 28ए और 28बी)।

नतीजतन, सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) काफी हद तक पिछले वर्ष की इसी अवधि (चार्ट 29) के समान रहा।

सरकार द्वारा 01 फरवरी 2023 को जारी संशोधित अनुमानों (आरई) के अनुसार 2022-23 के दौरान राजस्व और पूंजीगत व्यय में क्रमश: 8.1 प्रतिशत और 22.8 प्रतिशत की वृद्धि (वर्ष दर वर्ष) होने की उम्मीद है। बजटीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मार्च 2023 के दौरान राजस्व और पूंजीगत व्यय में क्रमश: 2.5 प्रतिशत और 28.2 प्रतिशत की वृद्धि की आवश्यकता होगी (चार्ट 30ए और 30बी)।

प्राप्तियों की बात करें तो, सकल कर राजस्व में 12.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। मई 2022 के दौरान पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती के कारण उत्पाद शुल्क से संग्रह में गिरावट दर्ज की गई। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों, दोनों ने वर्ष-दर-

चार्ट 29: अप्रैल-फरवरी के दौरान केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा

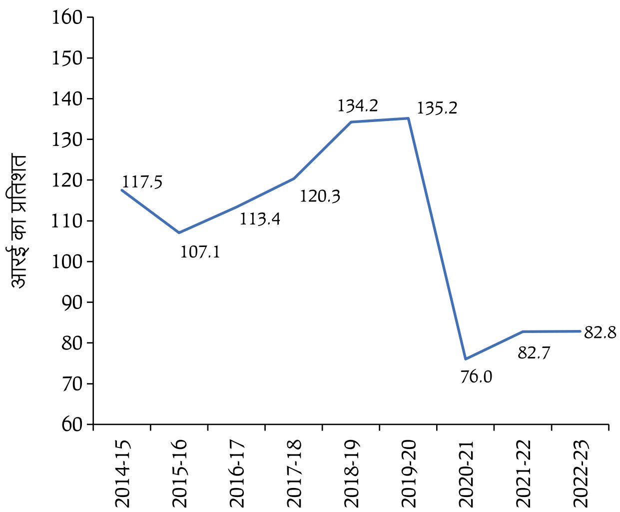

स्रोत: सीजीए; और केंद्रीय बजट दस्तावेज।

चार्ट 30: मार्च: 2022-23 के लिए अंतर्निहित व्यय वृद्धि

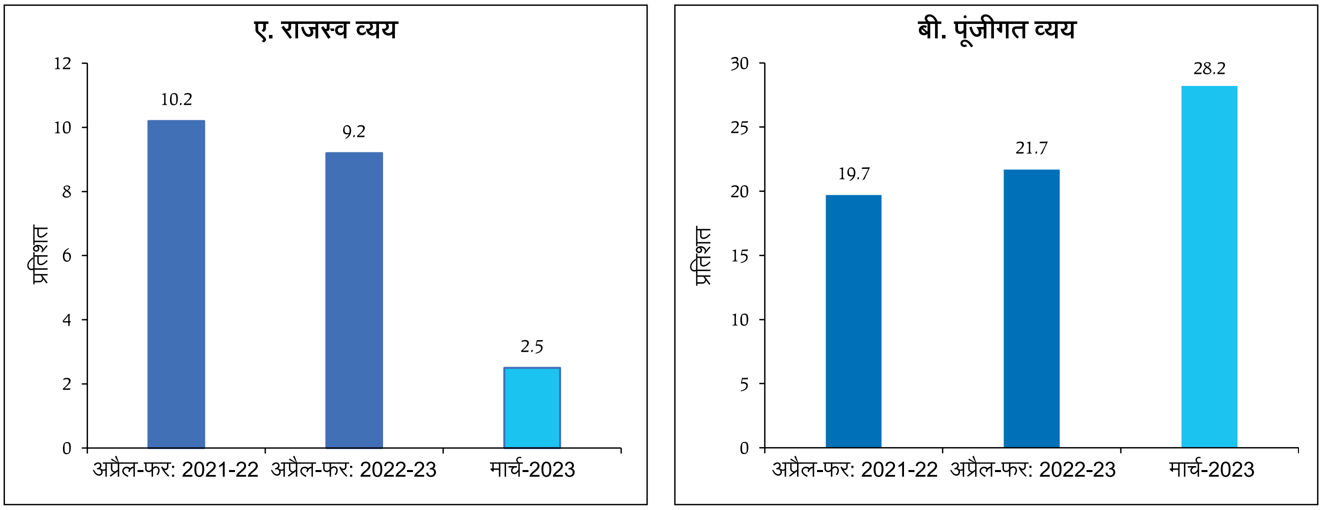

टिप्पणी: मार्च 2023 के लिए राजस्व और पूंजीगत व्यय वृद्धि सीजीए द्वारा जारी 2022-23 के संशोधित अनुमानों और फरवरी 2023 (यानी, अप्रैल-फरवरी 2022-23) तक के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर निहित वृद्धि दर है। हल्के नीले रंग की छाया पट्टियां निहित व्यय वृद्धि को दर्शाती हैं।
स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज 2023-24; सीजीए और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

वर्ष क्रमशः 15.9 प्रतिशत और 8.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की (चार्ट 31)।

अप्रैल-फरवरी 2022-23 के दौरान, गैर-कर राजस्व 2022-23 के लिए संशोधित अनुमान के 95.0 प्रतिशत तक पहुंच गया, जिसका मुख्य कारण केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) द्वारा उच्च लाभांश भुगतान था। दूसरी ओर, विनिवेश से प्राप्तियां 38,671 करोड़ रुपये रहीं, जो 2022-23 के संशोधित अनुमान का केवल 64.5 प्रतिशत थी। हालांकि, वर्ष-दर-वर्ष आधार पर विनिवेश प्राप्तियों में सुधार दर्ज किया गया, जिसमें मई 2022 में जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की सफल प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) की प्रमुख भूमिका रही।

मार्च 2023 में जीएसटी संग्रह (केंद्र और राज्य) में (वार्षिक आधार पर) 12.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से 1.6 लाख करोड़ रुपये के साथ यह दूसरा

चार्ट 31: अप्रैल-फरवरी के दौरान कर राजस्व

स्रोत: सीजीए; और केंद्रीय बजट दस्तावेज।

चार्ट 32: मासिक जीएसटी राजस्व

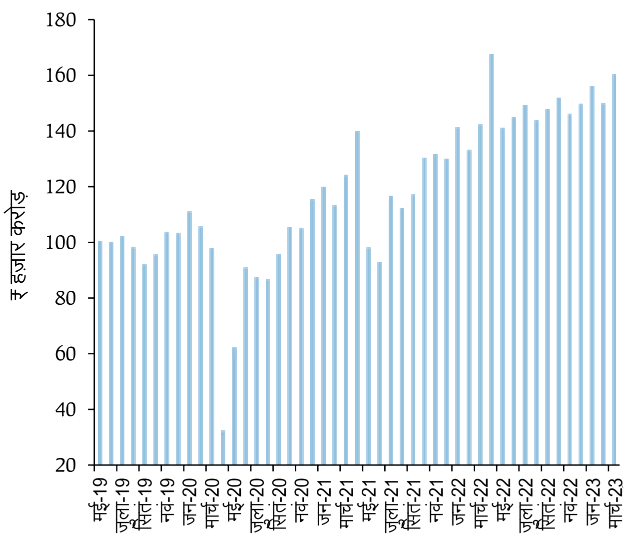

स्रोत: पीआईबी; और भारत सरकार (जीओआई)।

सबसे अधिक आंकड़ा है। वित्त वर्ष 2022-23 में सकल जीएसटी संग्रह 21.4 प्रतिशत बढ़ा है। यह 2022-23 के दौरान लगभग 1.51 लाख करोड़ रुपये के औसत सकल मासिक जीएसटी संग्रह को दर्शाता है, जबकि पिछले वर्ष यह 1.24 लाख करोड़ रुपये था।

कुल आपूर्ति

मार्च के उत्तरार्ध में बेमौसम बारिश 2015 के बाद से सबसे अधिक मात्रा में हुई (चार्ट 33 ए)। हालांकि इसने खड़ी रबी फसलों के लिए खतरा पैदा कर दिया, लेकिन इसने फरवरी 2023 से चल रही गर्म हवाओं को कम कर दिया, जिससे अनाज का सिकुड़ना कम हो गया, जैसा कि पिछले साल हुआ था। मार्च 2015 में इसी तरह की एक घटना के दौरान, गेहूं और सरसों के मामले में उत्पादन[8] में नुकसान मामूली था, लेकिन चने के लिए पर्याप्त था (चार्ट 33 बी)। हालांकि गेहूं के कुल उत्पादन को महत्वपूर्ण गिरावट का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन कीमतों में वृद्धि के साथ मंडी की आवक में लगभग 10 से 15 दिनों की देरी हुई (चार्ट 34 ए और 34 बी)।

खुले बाजार की बिक्री (ओएमएस) ने पूरे देश में गेहूं और आटे की कीमत को कम कर दिया। चल रही फसलों की पैदावार में नई उपज की अधिक खरीद से प्रक्रिया को और सहायता मिलने की उम्मीद है (चार्ट 34सी)[9]. 2023-24 के आगामी रबी विपणन सत्र के लिए गेहूं की सार्वजनिक खरीद का लक्ष्य 341.5 लाख टन निर्धारित किया गया है। 11 अप्रैल 2023 तक खरीद 16.7 लाख

चार्ट 33: मानसून पूर्व वर्षा (01 मार्च-30 मई) और रबी का उत्पादन

ए. मानसून पूर्व वर्षा के रुझान | **बी. अधिक वर्षा के बाद रबी उत्पादन अनुमानों में संशोधन (2015-16)**

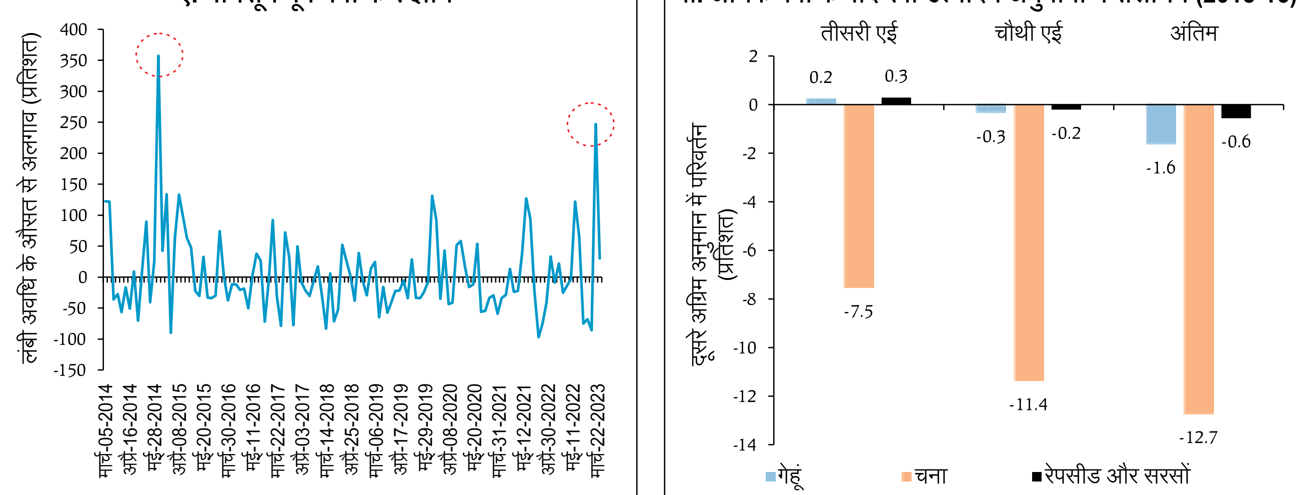

स्रोत: आईएमडी; और सीएमआईई। | **स्रोत:** कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय।

8 उत्पादन को हुए नुकसान की मात्रा का अनुमान बारिश से पहले जारी किए गए उत्पादन अनुमानों (फरवरी में दूसरे अग्रिम अनुमान (एई)) और बाद में जारी किए गए अनुमानों (तीसरे एई, चौथे एई और अंतिम अनुमान) के बीच अंतर से लगाया जा सकता है, जो नुकसान, यदि कोई हो, के लिए जिम्मेदार होगा।

9 https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1905607

चार्ट 34: गेहूं बाजार की आमद और कीमतों पर अत्यधिक बेमौसम मार्च की वर्षा का प्रभाव

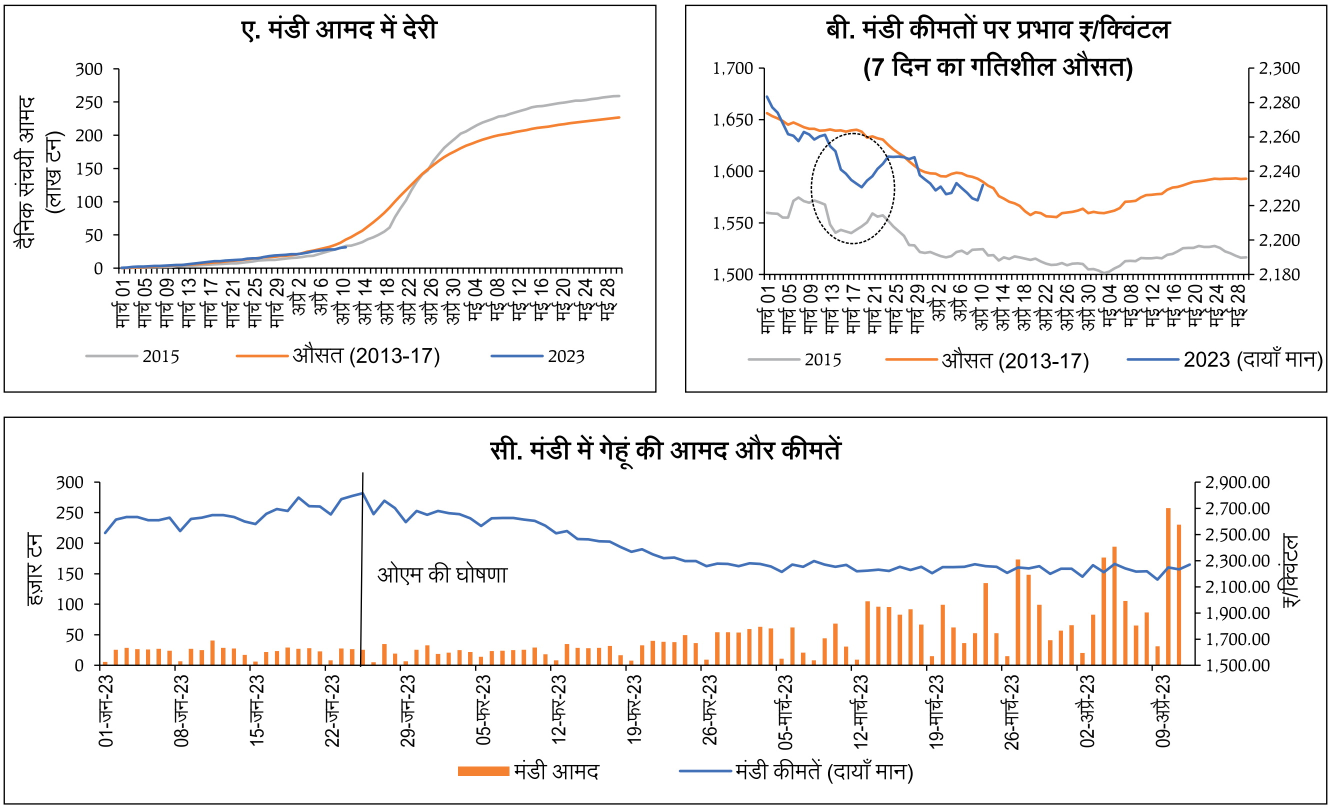

स्रोत: एगमार्कनेट, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय।

टन (पिछले वर्ष की इसी तारीख को 20.5 लाख टन की तुलना में) रहा, जिसमें अधिकांश खरीद (88.4 प्रतिशत) मध्य प्रदेश से हुई थी।

चावल के संबंध में, खरीफ विपणन सत्र (01 अक्टूबर 2022 - 11 अप्रैल, 2023) में संचयी खरीद 493.3 लाख टन रही, जो पिछले साल की तुलना में 2.4 प्रतिशत कम है। 01 अप्रैल 2023 तक सार्वजनिक स्टॉक चावल के लिए बफर मानदंड का 3.2 गुना और गेहूं के लिए 1.1 गुना था। 1.2-1.3 मिलियन टन पर चना स्टॉक भी उत्पादन के आघात के लिए एक बफर प्रदान करने के लिए पर्याप्त है।

2022-23 (दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार) के लिए तूर उत्पादन में वर्ष-दर-वर्ष अनुमानित 13.1 प्रतिशत की गिरावट के बाद, सरकार ने मुक्त आयात की अपनी नीति (जो पहले 31 मार्च 2023 तक थी) को एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया।[11] आयात के नियमित आगमन के बावजूद, अरहर की कीमतें पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक रही हैं (चार्ट 35)।[12] आयातकों, मिलमालिकों, गोदाम वालों और व्यापारियों जैसे लोगों द्वारा रखे गए अरहर के स्टॉक की निगरानी करने के लिए, सरकार ने एक समिति का गठन किया है जो राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करेगी।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के 11 अप्रैल 2023 को जारी दीर्घकालिक पूर्वानुमान के अनुसार, दक्षिण पश्चिम मानसून (एसडब्ल्यूएम) इस साल दीर्घकालिक औसत (एलपीए) के 96 प्रतिशत पर सामान्य रहने की संभावना है, जिसने खरीफ

[10] https://www.business-standard.com/economy/news/80-new-wheat-arriving-in-mandis-till-last-week-had-high-moisture-content-123040200682_1.html

[11] https://content.dgft.gov.in/Website/dgftprod/e364ae79-c8e4-42a1-9487-2b1c60a29a60/Noti%2052%20Eng.pdf

[12] https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1911140

चार्ट 35: तूर (अरहर) की कीमतें और आयात

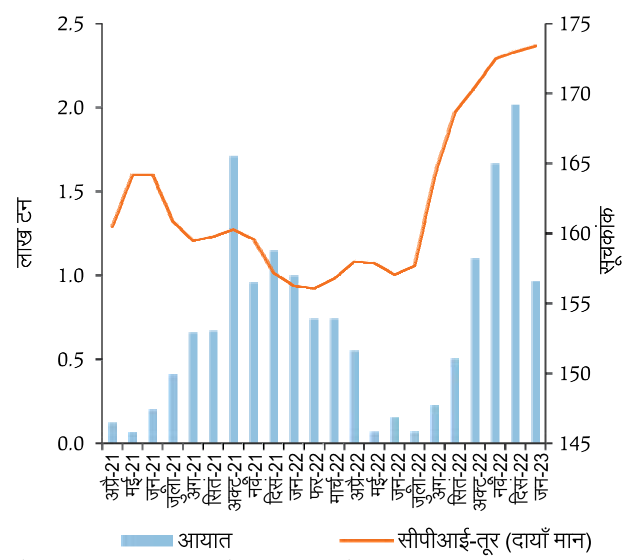

स्रोत: एपीईडीए एक्सचेंज; और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।

फसल की संभावनाओं को बढ़ावा दिया है। पूर्वानुमान में पूरे देश में बारिश के सामान्य या उससे अधिक रहने की 49 प्रतिशत संभावना जताई गई है। वर्तमान में, भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र में ला नीना की स्थिति तटस्थ हो गई है, लेकिन मौसम के दूसरे छमाही में अल नीनो की स्थिति बनने की संभावना है जो आमतौर पर कम एसडब्ल्यूएम बारिश से जुड़ी होती है। हालांकि, सकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रुवीय (आईओडी) स्थितियां अल नीनो के प्रभाव को कम कर सकती हैं।

औद्योगिक क्षेत्र में, मार्च 2023 में विनिर्माण के लिए हेडलाइन पीएमआई 56.4 था, जो उत्पादन और नए ऑर्डर में तेजी के कारण तीन महीनों में सबसे तेज दर से बढ़ा (चार्ट 36 ए)। नए व्यवसाय, भविष्य की गतिविधि और रोजगार में नरमी के कारण सेवा क्षेत्र में उत्पादन मार्च 2023 में 57.8 पर विस्तारक क्षेत्र में रहा, हालांकि एक महीने पहले 59.4 से कम था (चार्ट 36 बी)।

सेवा क्षेत्र में, रेलवे मालभाड़ा आय मार्च में काफी हद तक सपाट रही, क्योंकि कोयले और कंटेनर सेवाओं के मालभाड़े ने विस्तार दर्ज किया, जबकि सीमेंट और खाद्यान्न में संकुचन दर्ज किया गया (चार्ट 37)।

चार्ट 36: क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई)

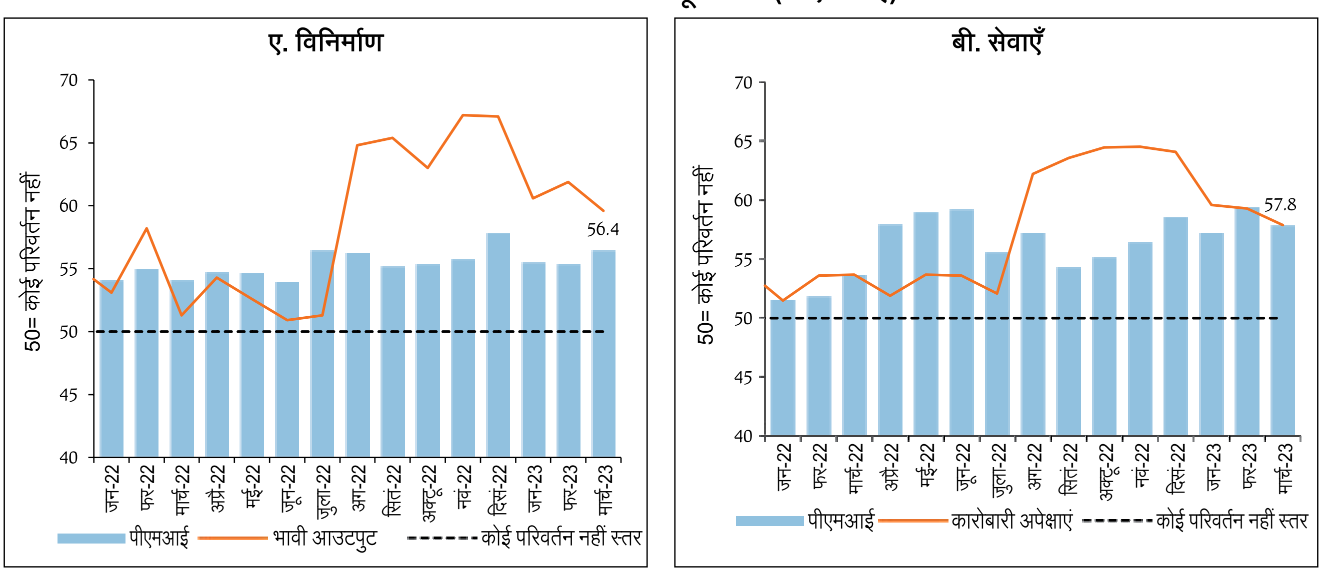

स्रोत: एस एंड पी ग्लोबल।

चार्ट 37: रेलवे मालभाड़ा राजस्व

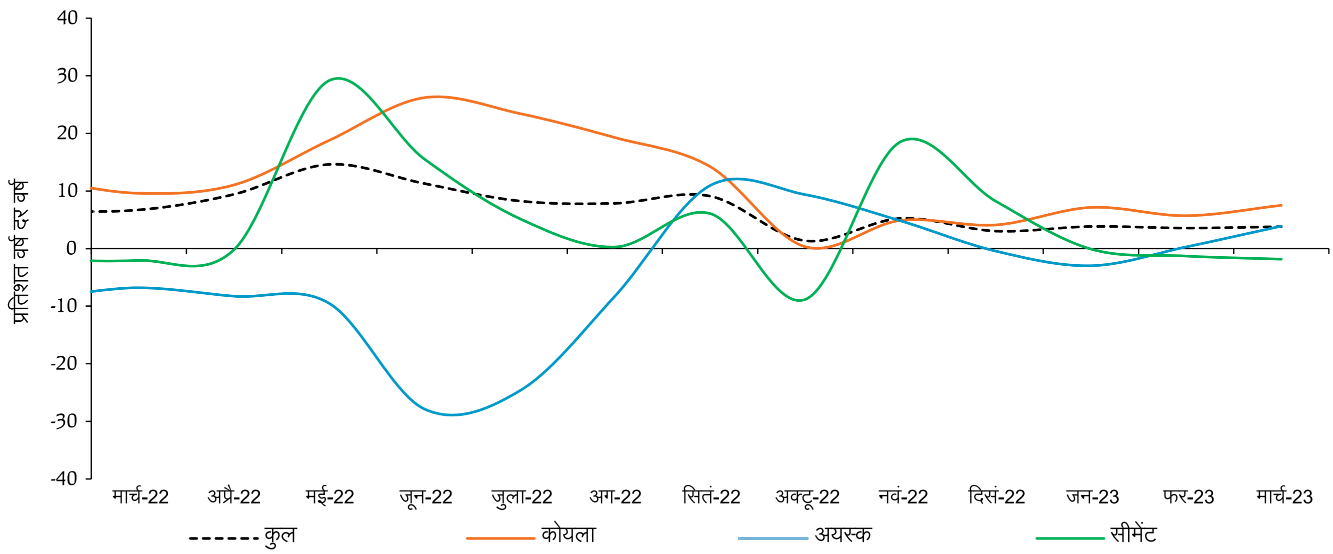

स्रोत: रेल दृष्टि।

निर्माण क्षेत्र में, गतिविधि मजबूत बनी रही, मार्च में इस्पात की खपत में वृद्धि बनी रही (चार्ट 38)। इस्पात की खपत में मार्च में दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की गई, जो आंशिक रूप से अनुकूल आधार प्रभावों से समर्थित है।

सेवा क्षेत्र में उच्च-आवृत्ति संकेतकों ने मार्च 2023 में माल के घरेलू परिवहन में तेजी के साथ आघात-सहनीयता का प्रदर्शन किया, जैसा कि रेलवे मालभाड़ा और ई-वे बिल की मात्रा में वृद्धि से परिलक्षित होता है (सारणी 2)।

क्षेत्रीय नीतिगत पहलों के संदर्भ में, कर्नाटक ने राज्य श्रम कानूनों में संशोधन किया है जो अब उद्योगों को स्थानीय विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए काम के घंटे बढ़ाने की अनुमति देता है। तमिलनाडु ने कृषि स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अपनी

चार्ट 38: इस्पात की खपत और सीमेंट उत्पादन

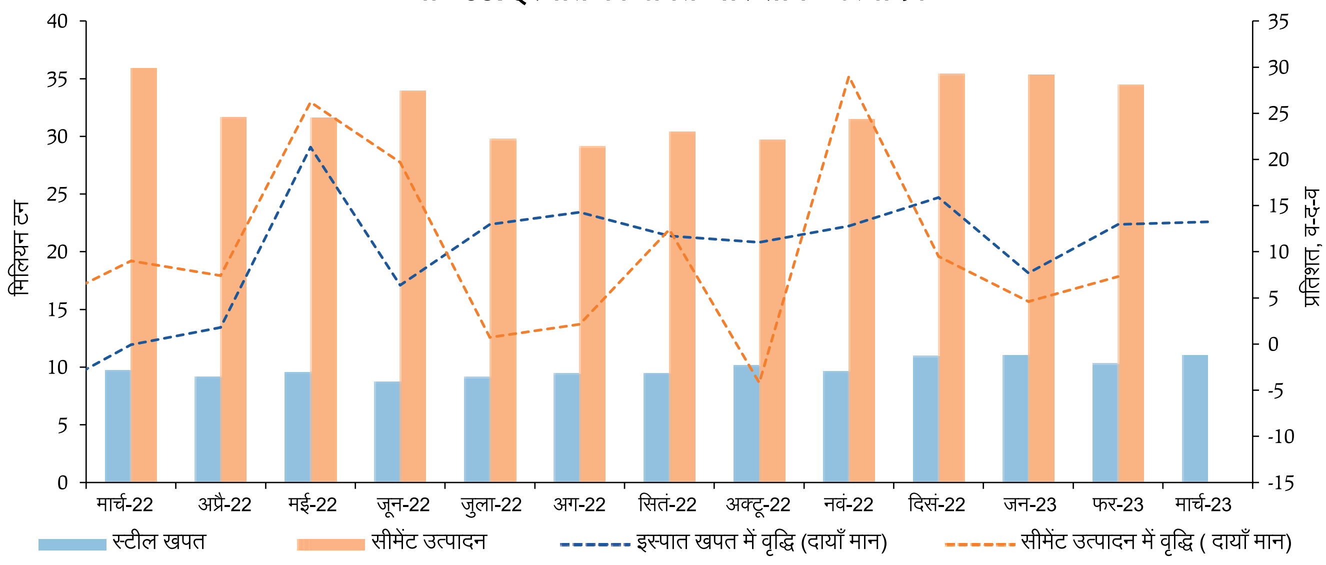

स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति; और आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।

सारणी 2: उच्च आवृत्ति संकेतक - सेवाएं

वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)

क्षेत्र	संकेतक	अक्टू-22	नवं-22	दिसं-22	जन-23	फर-23	मार्च-23
शहरी मांग	यात्री वाहनों की बिक्री	28.6	28.1	7.2	17.2	11.0	4.5
ग्रामीण मांग	दोपहिया वाहनों की बिक्री	2.3	17.7	3.9	5.0	7.6	7.7
	तिपहिया वाहनों की बिक्री	70.4	103.2	37.6	103.0	86.1	69.2
	ट्रैक्टर की बिक्री	6.8	6.5	25.6	24.4	20.0	13.7
व्यापार, होटल, परिवहन, संचार	वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री		11.5			7.1	
	रेलवे मालभाड़ा यातायात	1.4	5.2	3.1	3.8	3.6	3.8
	पोर्ट कार्गो यातायात	3.1	1.8	10.3	12.2	11.8	
	घरेलू हवाई कार्गो यातायात	-8.0	3.7	-3.6	2.4	8.1	
	अंतरराष्ट्रीय हवाई कार्गो यातायात	-18.7	-6.0	-7.4	-7.5	-1.7	
	घरेलू हवाई यात्री यातायात	30.4	12.6	14.6	96.8	57.4	
	अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्री यातायात	115.0	97.5	85.9	121.9	109.3	
	जीएसटी ई-वे बिल (कुल)	4.6	32.0	17.5	19.7	18.4	16.3
	जीएसटी ई-वे बिल (आंतर राज्यीय)	12.0	37.7	23.2	24.1	22.2	20.7
	जीएसटी ई-वे बिल (अंतर-राज्यीय)	-5.9	23.1	8.6	12.8	12.4	9.3
	पर्यटकों का आगमन	243.2	191.3	204.2	330.8	259.4	
निर्माण	इस्पात की खपत	11.0	12.8	15.9	7.7	13.0	13.2
	सीमेंट उत्पादन	-4.2	29.0	9.5	4.6	7.3	
पीएमआई सूचकांक #	सेवाएं	55.1	56.4	58.5	57.2	59.4	57.8

टिप्पणी: #: स्तरों में डेटा.

स्रोत: सीएमआईई; सीईआईसी डेटा; आईएचएस मार्किट; सियाम; भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण; और संयुक्त संयंत्र समिति।

जैविक खेती नीति 2023 जारी की। तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और पंजाब ने बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसलों के नुकसान के लिए किसानों को मुआवजा प्रदान करने के उपायों की घोषणा की है। राज्य के बजट के हिस्से के रूप में, तमिलनाडु ने लगभग एक करोड़ पात्र महिलाओं को लक्षित करते हुए मासिक प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण योजना (₹ 1,000) की घोषणा की है। असम ने स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की महिला सदस्यों के सभी बैंक खातों में ₹1,000 हस्तांतरित करने का भी प्रस्ताव दिया है ताकि उन्हें एक सक्रिय बैंक खाता बनाए रखने और एक व्यावसायिक प्रस्ताव तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

मुद्रास्फीति

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तनों द्वारा मापी गई मुद्रास्फीति, फरवरी में 6.4 प्रतिशत से घटकर मार्च 2023 में 5.7 प्रतिशत हो गई।[13] गिरावट प्रमुख समूहों अर्थात् खाद्य, ईंधन और कोर (भोजन और ईंधन को छोड़कर) में व्यापक थी [चार्ट 39 ए और 39 बी]। फरवरी और मार्च के बीच हेडलाइन मुद्रास्फीति में 78 बीपीएस की गिरावट एक बड़े अनुकूल आधार प्रभाव (96 बीपीएस) के कारण थी, जो माह के दौरान लगभग 23 बीपीएस की सकारात्मक मूल्य गति की तुलना से अधिक थी।

प्रमुख समूहों के भीतर, कीमतों में वृद्धि खाद्य और पेय पदार्थों में 23 बीपीएस और कोर समूह में 26 बीपीएस थी; जबकि ईंधन समूह कीमत सूचकांक अपरिवर्तित रहा।

वार्षिक मुद्रास्फीति के संदर्भ में, सीपीआई खाद्य मुद्रास्फीति 132 आधार अंक के अनुकूल आधार प्रभाव के कारण फरवरी में 6.3 प्रतिशत से घटकर मार्च में 5.1 प्रतिशत हो गई, जिसने 23 बीपीएस की सकारात्मक गति को प्रभावित किया। उप-समूहों के संदर्भ में, दूध, अनाज और चीनी के मामले में मुद्रास्फीति में तेजी से कमी आई, जो नकारात्मक गति से प्रेरित थी (चार्ट 40)।

[13] राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा 12 अप्रैल, 2023 को जारी अनंतिम आंकड़ों के अनुसार।

चार्ट 39: सीपीआई मुद्रास्फीति के रुझान और वाहक

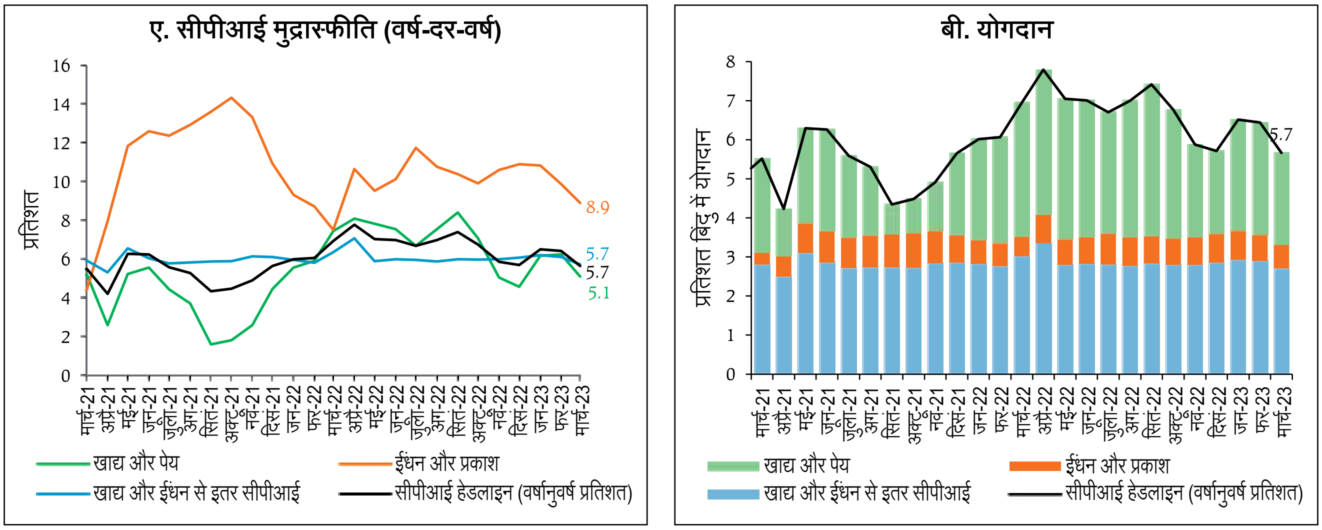

टिप्पणी: अप्रैल-मई 2021 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति की गणना अप्रैल-मई 2020 के लिए अभ्यारोपित सीपीआई सूचकांकों के आधार पर की गई थी।

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ); और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

मसाले, गैर-मादक पेय और तैयार भोजन में भी मुद्रास्फीति कम दर्ज की गई, जबकि खाद्य तेल, मांस और मछली में अपस्फीति दर्ज की गई। दालों, अंडों और फलों की मुद्रास्फीति बढ़ी जबकि सब्जियों में मार्च में कम अपस्फीति दर्ज की गई (चार्ट 41)।

चार्ट 40: उपसमूहों में वार्षिक मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष) और गति (म-द-म)

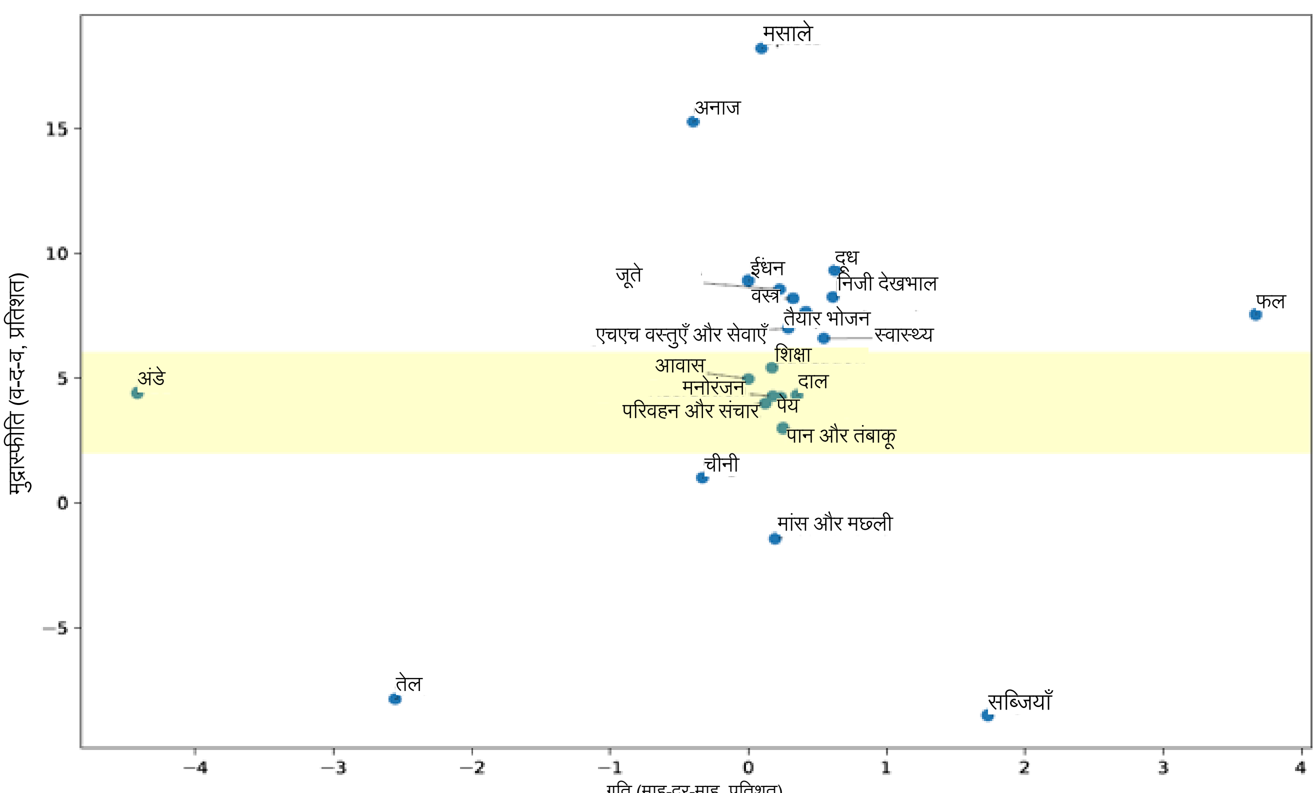

स्रोत: एनएसओ; आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

चार्ट 41: उपसमूहों में वार्षिक मुद्रास्फीति (फरवरी 2023 की तुलना में मार्च 2023)

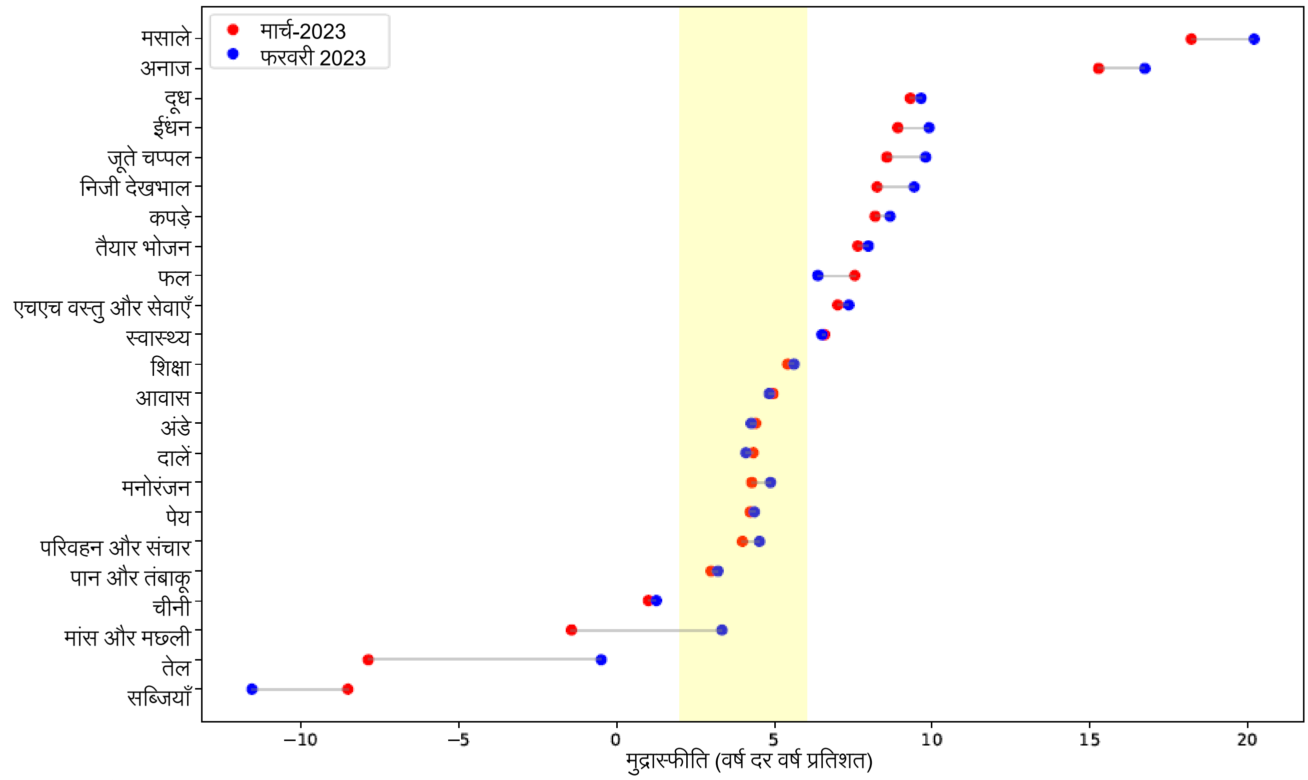

स्रोत: एनएसओ; आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

ईंधन और प्रकाश समूह में मुद्रास्फीति फरवरी के 9.9 प्रतिशत से घटकर मार्च में 8.9 प्रतिशत रह गई, जो मुख्य रूप से केरोसिन तेल (पीडीएस) और जलाऊ लकड़ी और चिप्स की कीमतों में बदलाव से प्रेरित थी। एलपीजी कीमत मुद्रास्फीति में वृद्धि दर्ज किए जाने के बावजूद विद्युत की कीमतों में स्थिरता बनी हुई है।

कोर मुद्रास्फीति फरवरी के 6.1 प्रतिशत से घटकर मार्च में 5.7 प्रतिशत पर आ गई। 9 उप-समूहों में से 7 (पान, तंबाकू और नशीले पदार्थ; आमोद प्रमोद; कपड़े और जूते; घरेलू सामान और सेवाएं; परिवहन और संचार; शिक्षा; और व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव) में मुद्रास्फीति में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, आवास और स्वास्थ्य उप-समूहों में वृद्धि दर्ज की गई।

क्षेत्रीय वितरण के संदर्भ में, ग्रामीण मुद्रास्फीति (5.5 प्रतिशत) मई 2022 के बाद पहली बार मार्च 2023 में शहरी मुद्रास्फीति (5.9 प्रतिशत) से कम थी, जिसमें ग्रामीण मुद्रास्फीति में गिरावट बड़े पैमाने पर सब्जियों और तेलों के कारण थी (चार्ट 42)। राज्यों में, त्रिपुरा ने 8 प्रतिशत से अधिक मुद्रास्फीति का अनुभव किया,

चार्ट 42: चुनिंदा मदों में मुद्रास्फीति (ग्रामीण बनाम शहरी)

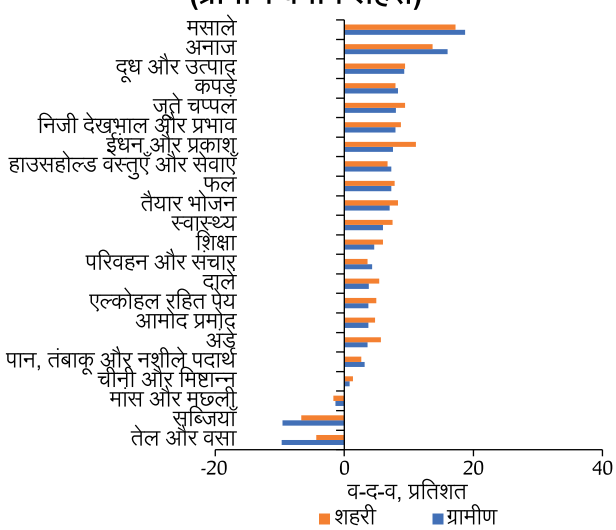

स्रोत: एनएसओ; आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

जबकि छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय ने 4 प्रतिशत से नीचे मुद्रास्फीति दर्ज की (चार्ट 43)।

उपभोक्ता मामलों के विभाग (डीसीए) के अप्रैल (1-12 अप्रैल) के लिए उच्च आवृत्ति खाद्य मूल्य डेटा मुख्य रूप से गेहूं और आटे की कीमतों में गिरावट के कारण अनाज की कीमतों में गिरावट की ओर इशारा करते हैं, । दालों की कीमतों में व्यापक आधार पर वृद्धि दर्ज की गई, जबकि मूंगफली तेल को छोड़कर खाद्य तेलों की कीमतों में गिरावट जारी रही। प्रमुख सब्जियों में, प्याज और आलू की कीमतों में नरमी आई, जबकि टमाटर की कीमतों में तेजी आई (चार्ट 44)।

चार प्रमुख महानगरों में पेट्रोल और डीजल की खुदरा बिक्री कीमतें अप्रैल में अब तक स्थिर रही हैं। जबकि मार्च में देखी गई वृद्धि के बाद अप्रैल में एलपीजी की कीमतों को अपरिवर्तित रखा गया था, अप्रैल में केरोसिन तेल की कीमतों में तेजी से गिरावट आई (सारणी 3)।

चार्ट 43: मुद्रास्फीति का स्थानिक वितरण मार्च 2023 (सीपीआई- संयुक्त, वर्ष-दर-वर्ष)

स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित इनपुट लागत मुद्रास्फीति मार्च 2023 में नरम बनी रही (चार्ट 45)। इनपुट

चार्ट 44: डीसीए आवश्यक वस्तु की कीमतें

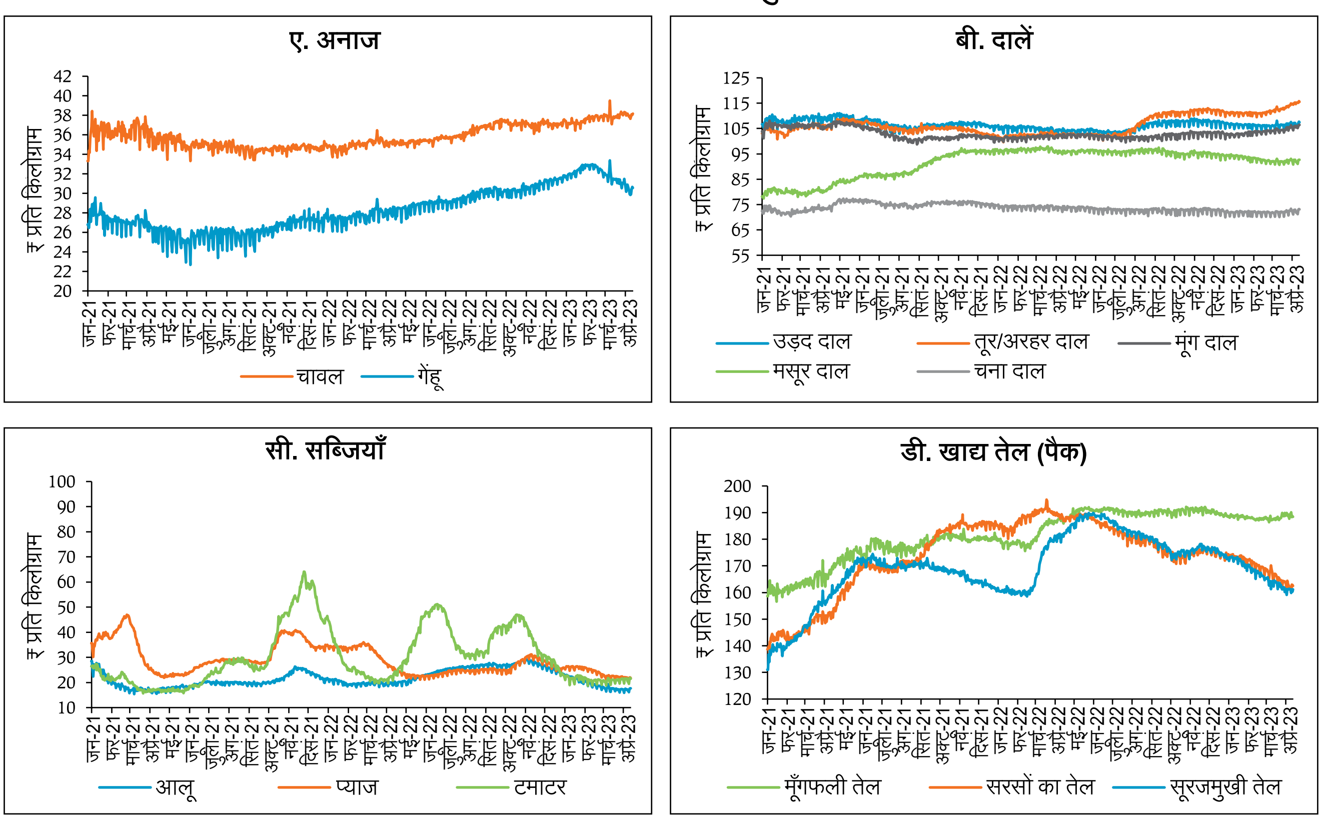

स्रोत: उपभोक्ता मामलों का विभाग, भारत सरकार; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

सारणी 3: पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें

मद	इकाई	घरेलू कीमतें			माह-दर-माह (प्रतिशत)	
		अप्रै-22	मार्च-23	अप्रै-23^	मार्च-23	अप्रै-23
पेट्रोल	₹/लीटर	112.61	102.92	102.92	0.0	0.0
डीज़ल	₹/लीटर	100.19	92.72	92.72	0.0	0.0
केरोसिन (छूट सहित)	₹/लीटर	56.99	54.21	49.20	-2.8	-9.2
एलपीजी (छूट रहित)	₹/सिलेंडर	960.13	1113.25	1113.25	4.7	0.0

टिप्पणी: केरोसिन तेल के अलावा, कीमतें चार प्रमुख महानगरों (दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई) में औसत इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) की कीमतों का प्रतिनिधित्व करती हैं। केरोसिन के लिए, कीमतें कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में सब्सिडी वाली कीमतों के औसत को दर्शाती हैं।
स्रोत: आईओसीएल; पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी); और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

चार्ट 45: इनपुट लागत

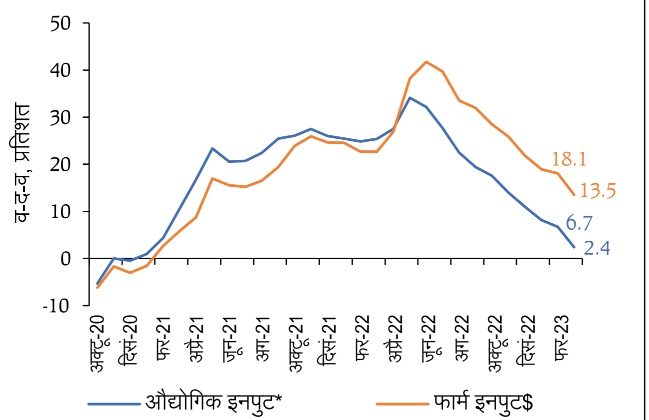

टिप्पणी: * प्राथमिक गैर-खाद्य वस्तुओं, खनिजों, कोयला, विमानन टरबाइन ईंधन, हाई स्पीड डीजल, नेफ्था, बिटुमेन, फर्नेस तेल, ल्यूब तेल, पेट्रोलियम कोक, विद्युत, सूती धागे और डब्ल्यूपीआई से पेपर और लुगदी शामिल हैं।
$ उच्च गति डीजल, चारा, विद्युत, उर्वरक, कीटनाशक और डब्ल्यूपीआई से कृषि और वानिकी मशीनरी शामिल हैं।
स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

लागत दबाव में गिरावट मुख्य रूप से एचएसडी (हाई स्पीड डीजल) और विद्युत की कीमतों में गिरावट के कारण थी।

मार्च 2023 के पीएमआई आंकड़ों के अनुसार, विनिर्माण और सेवाओं में बिक्री की कीमतों में वृद्धि हुई है; हालांकि, विस्तार की गति धीमी रही। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में इनपुट लागत ने एक महीने पहले की तुलना में मार्च में कम विस्तार दर्ज किया (चार्ट 46)।

चार्ट 46: पीएमआई इनपुट और आउटपुट कीमतें

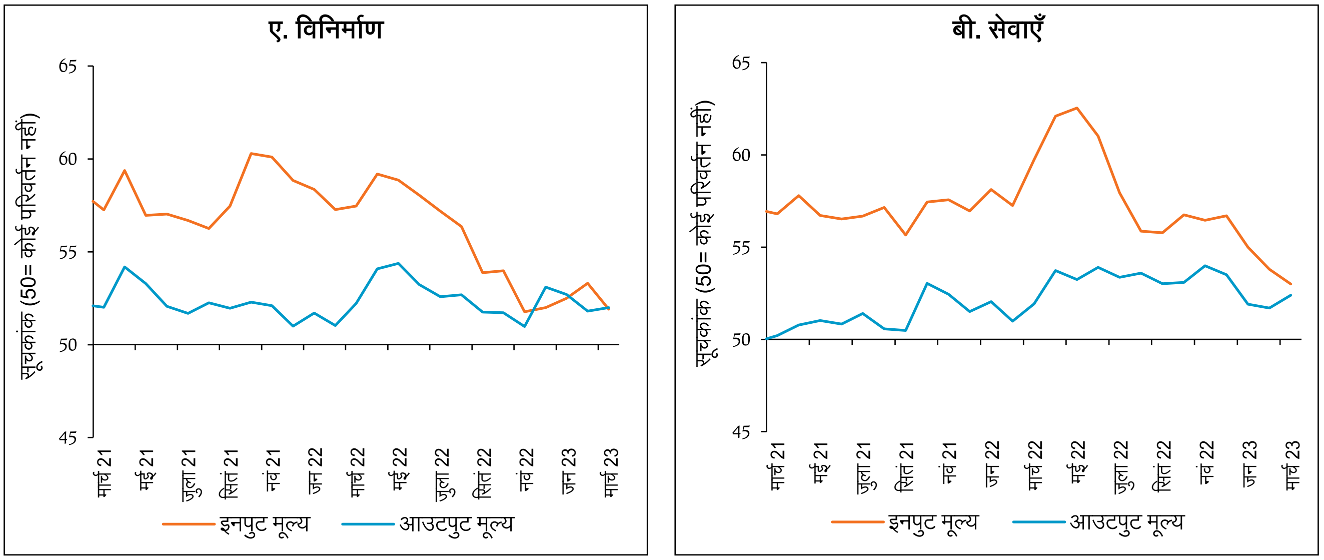

स्रोत: एस एंड पी ग्लोबल।

चार्ट 47: कच्चे माल और डब्ल्यूपीआई औद्योगिक कच्चे माल (आईआरएम) मुद्रास्फीति की लागत पर निवल प्रतिक्रियाएं

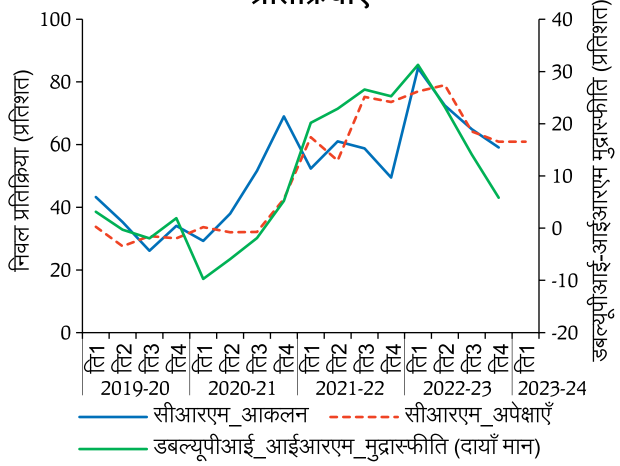

स्रोत: औद्योगिक आउटलुक सर्वेक्षण; आर्थिक सलाहकार का कार्यालय; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

चार्ट 48: बिक्री मूल्य और डब्ल्यूपीआई विनिर्मित उत्पाद (एमपी) मुद्रास्फीति पर निवल प्रतिक्रियाएं

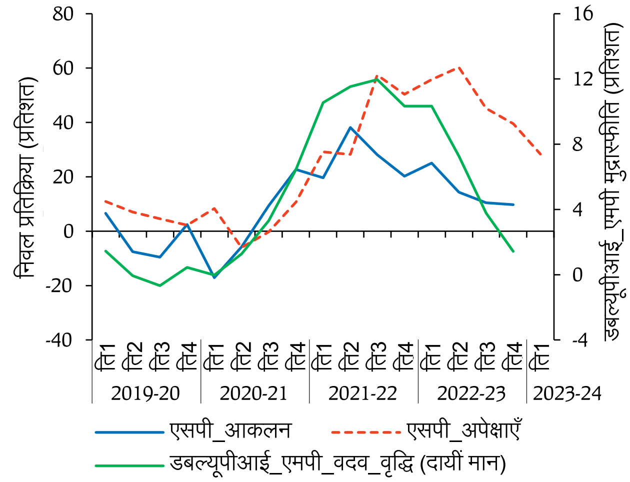

स्रोत: आईओएस, आर्थिक सलाहकार का कार्यालय और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

कच्चे माल की लागत (सीआरएम) के संबंध में विनिर्माताओं का आकलन और अपेक्षा, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक के तिमाही औद्योगिक परिदृश्य सर्वेक्षण (आईओएस) में निवल प्रतिक्रियाओं (एनआरएस)[15] में परिलक्षित होता है, औद्योगिक कच्चे माल[16] के थोक मूल्यों में उतार-चढ़ाव का बारीकी से पता लगाता है (चार्ट 47)। इसी प्रकार, आईओएस बिक्री मूल्यों (एसपी) पर एनआर डब्ल्यूपीआई विनिर्मित उत्पादों की मुद्रास्फीति (भारांक: 64.2 प्रतिशत) का काफी अच्छी तरह से पता करते हैं (चार्ट 48)। सर्वेक्षण के नवीनतम दौर के परिणाम इनपुट लागत में वृद्धि की गति में कमी और विनिर्माण क्षेत्र के लिए बिक्री मूल्य वृद्धि में सहवर्ती कमी का संकेत देते हैं।

सितंबर 2022 के बाद से हाउसहोल्ड की मुद्रास्फीति धारणा (चालू) में कमी के संकेत दिखाई दिए हैं; उन्होंने द्वि-मासिक सर्वेक्षण के मार्च 2023 दौर में 70 आधार अंकों (बीपीएस) की गिरावट दर्ज की (चार्ट 49)। इसके साथ ही, तीन महीने आगे और एक साल आगे मुद्रास्फीति की अपेक्षाएँ भी कम हो गईं।

चार्ट 49: हाउसहोल्ड की औसत मुद्रास्फीति अपेक्षाएं

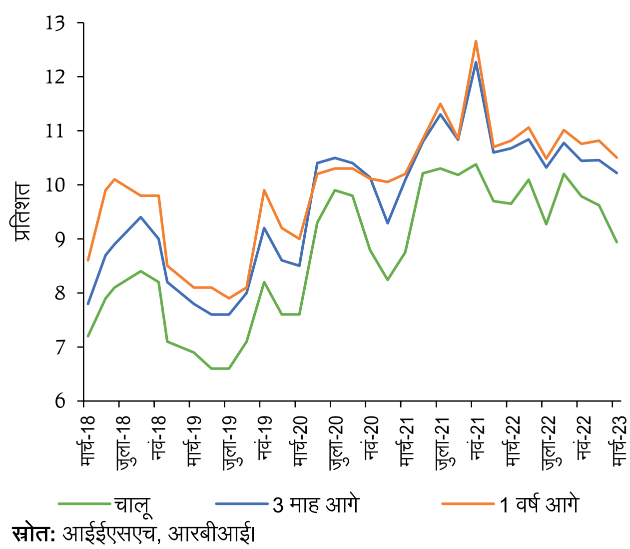

स्रोत: आईईएसएच, आरबीआई।

---

14 बनर्जी एन और मजूमदार, एस https://rbi.org.in/Scripts/BS_ViewBulletin.aspx?Id=20815

15 यदि आई, एन और डी किसी विशेष पैरामीटर पर प्रश्न के उत्तर के लिए क्रमशः वृद्धि प्रतिक्रिया के अनुपात के अनुरूप हैं, तो एनआर की गणना एनआर = 100 * (आई-डी) के रूप में की जाती है और कोई परिवर्तन (एनसी) या यथास्थिति को एनसी = 100 * एन के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

16 डब्ल्यूपीआई में विशिष्ट मदें शामिल हैं, जिनका कुल भारांक 18.1 प्रतिशत है।

IV. वित्तीय स्थितियां

मार्च 2023 की दूसरी छमाही के दौरान चलनिधि की स्थिति सख्त हो गई, लेकिन इसके बाद महीने के अंत में और अप्रैल की शुरुआत में सरकारी खर्च में वृद्धि के साथ सुधार हुआ। कुल मिलाकर, चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत औसत कुल अवशोषण 16 मार्च से 15 अप्रैल के दौरान ₹2.0 लाख करोड़ रहा, जो 16 फरवरी से 15 मार्च, 2023 के दौरान ₹1.5 लाख करोड़ से अधिक है। प्रणाली स्तर पर एसडीएफ के तहत वृहत स्तर पर निधियों के नियोजन के बावजूद, कई बैंकों ने सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) का सहारा लिया, जो 16 मार्च से 15 अप्रैल के दौरान औसतन ₹0.11 लाख करोड़ थी, जो बैंकिंग प्रणाली के भीतर चलनिधि के विषम वितरण को दर्शाता है। 16-26 मार्च की अवधि के दौरान निरंतर निवल अंतर्वेशन भी थे, जो औसतन लगभग ₹0.65 लाख करोड़ था (चार्ट 50)। चलनिधि के दबाव को कम करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने कई उपाय किए, जिसमें 24 मार्च 2023 को 5 दिन की परिमार्जित परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (वीआरआर) परिचालन शामिल था, जिसमें ₹55,885 करोड़ अंतर्वेशित किए गए। एकल प्राथमिक व्यापारी (एसपीडी) को स्थायी चलनिधि सुविधा (एसएलएफ) के तहत 31 मार्च 2023 को मौजूदा रेपो रेट पर ₹5,000 करोड़ रुपये की राशि भी उपलब्ध कराई गई, जिसमें इस सुविधा के तहत प्राप्त धन (₹3,900 करोड़) को 5 अप्रैल 2023 को या उससे पहले चुकाया जा सकता है

2022-23 के अंतिम सप्ताह (यानी 25-31 मार्च) में, सरकारी खर्च में ₹2.55 लाख करोड़ की वृद्धि हुई, जिससे प्रणाली चलनिधि में वृद्धि हुई। रिज़र्व बैंक के चलनिधि परिचालन से चलनिधि की स्थिति में सुधार के बावजूद, मुद्रा बाजार दरों में 31 मार्च को काफी वृद्धि हुई, जिसमें डब्ल्यूएसीआर 7.34 प्रतिशत तक मजबूत हो गया। इस सख्ती के लिए कई कारकों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है: (i) वित्तीय वर्ष खातों के बंद होने के कारण कुछ बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) से उच्च उधार मांग; (ii) 31 मार्च को बैंकों द्वारा अभिगम नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) रख-रखाव में भारी वृद्धि; (iii) 31 मार्च को आवासीय कर और गैर-कर भुगतानों के कारण बैंकिंग प्रणाली में व्यापक बहिर्वाह; (iv) कॉल बाज़ार मात्रा 29 मार्च के ₹12,540 करोड़ से घटकर 31 मार्च को ₹6,938 करोड़ रह गया क्योंकि प्रतिभागी साल के अंत में तुलन-पत्र को ध्यान में रखते हुए उधार देने के लिए अनिच्छुक हो गए; और (v) म्यूचुअल फंड – त्रिपक्षीय रेपो वाले भाग में पारंपरिक ऋणदाता - बड़े मोचन दबाव के मद्देनजर उधारकर्ताओं में बदल रहे हैं। औसत आधार पर, डब्ल्यूएसीआर, त्रिपक्षीय रेपो और बाज़ार रेपो दरें 16 मार्च से 15 अप्रैल 2023 के दौरान नीतिगत रेपो दर से क्रमशः 5 बीपीएस, 5 बीपीएस और 10 बीपीएस ऊपर रहीं (चार्ट 51 ए)।

चार्ट 50: चलनिधि परिचालन

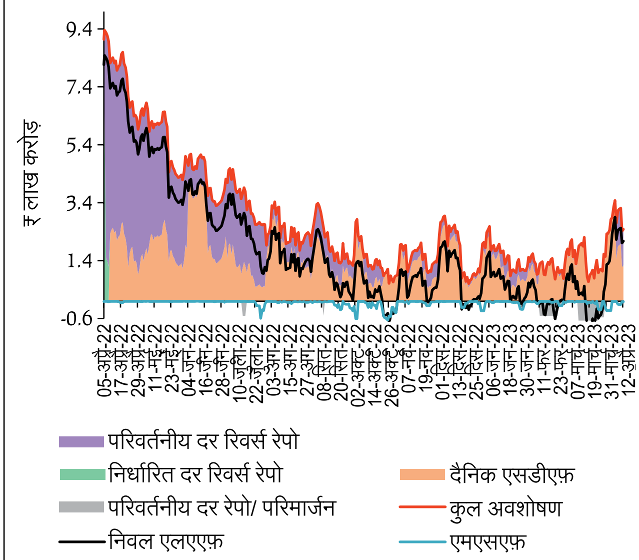

स्रोत : आरबीआई।

मीयादी मुद्रा भाग में, एमएसएफ दर से ऊपर कारोबार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए 3 महीने के खज़ाना बिल (टी-बिल), जमा प्रमाण पत्र (सीडी) और वाणिज्यिक पत्र (सीपी) पर प्रतिफल के साथ दरें ऊंची बनी रहीं, जो संचयी नीतिगत दर में वृद्धि, अनिश्चितता और घरेलू अधिशेष चलनिधि में तेज़ी से कमी को दर्शाती हैं (चार्ट 51 बी)।

प्राथमिक बाजार में सीडी जारी करने के जरिये निधि जुटाना 2022-23 के दौरान ₹6.7 लाख करोड़ रहा जो इससे पिछले वित्त वर्ष में ₹2.3 लाख करोड़ था। बैंकों को ऋण मांग में बढ़ोतरी में तेजी के कारण निधियों की अतिरिक्त मांग का सामना करना पड़ रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 (07 अप्रैल तक) के दौरान सीडी निर्गम ₹0.11 लाख करोड़ रहा जो 2022-23 की इसी अवधि में

चार्ट 51: नीतिगत कॉरिडोर और मुद्रा बाजार दरें

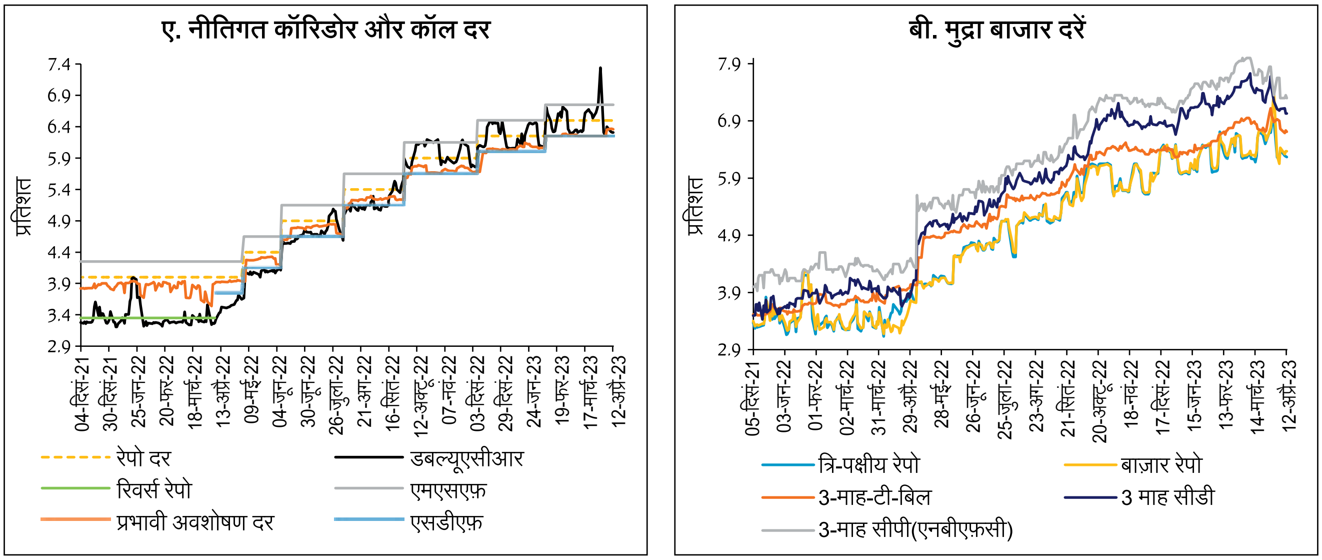

स्रोत: आरबीआई; ब्लूमबर्ग; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

₹0.22 लाख करोड़ था। कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा वित्तपोषण आवश्यकताओं के लिए बैंक ऋण का सहारा लेने के साथ, सीपी निर्गम 2021-22 में ₹20.2 लाख करोड़ से घटकर 2022-23 के दौरान ₹13.7 लाख करोड़ हो गया।

10 वर्षीय बेंचमार्क जी-सेक (7.26% जीएस 2033) पर प्रतिफल 15 मार्च के 7.34 प्रतिशत से घटकर 13 अप्रैल 2023 को 7.22 प्रतिशत हो गया (चार्ट 52ए)। अमेरिका में बैंकिंग संकट के मद्देनजर सुरक्षित आस्तियों की ओर पलायन के परिणामस्वरूप अमेरिकी खज़ाना प्रतिफल में कमी आई, जिसका घरेलू प्रतिफल पर भी असर पड़ा। फिर भी, 6 अप्रैल 2023 को मौद्रिक नीति वक्तव्य जारी होने से पहले घरेलू प्रतिफल काफी हद तक एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा था। एमपीसी के फैसले के बाद

चार्ट 52: जी-सेक बाजार में गतिविधियां

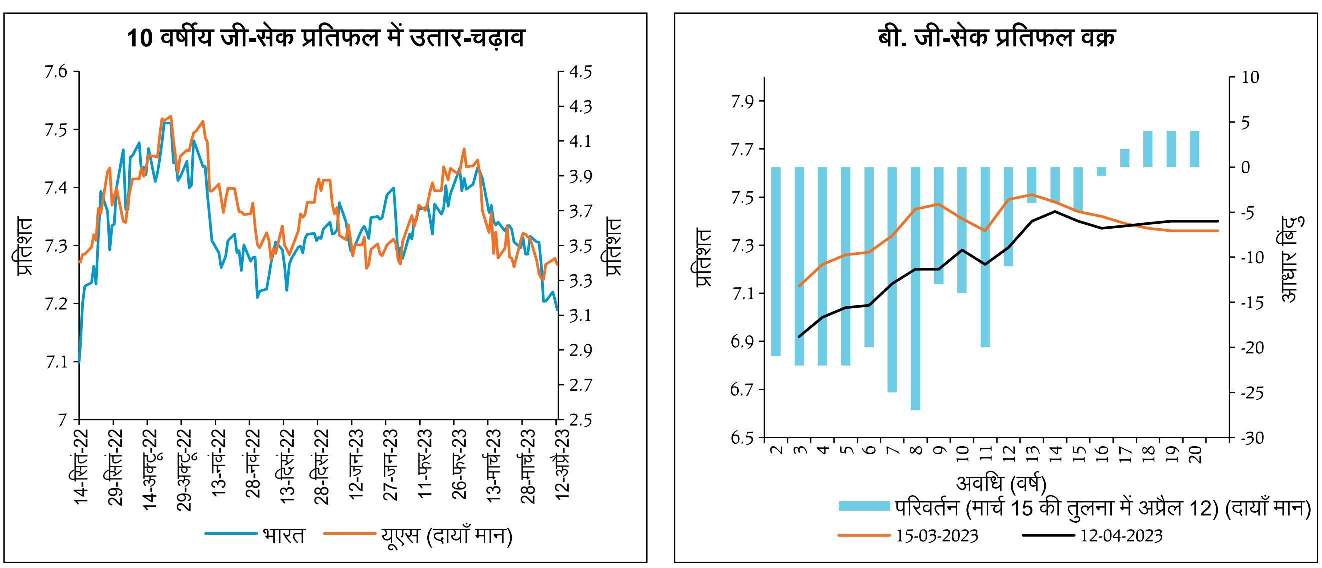

स्रोत: ब्लूमबर्ग; सीसीआईएल; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

10 वर्षीय जी-सेक पर प्रतिफल 7.28 प्रतिशत से घटकर 6 अप्रैल को 7.15 प्रतिशत के निचले स्तर पर आ गया। मौद्रिक नीति का निर्णय बाजार द्वारा काफी हद तक अप्रत्याशित प्रतीत होता है, जैसा कि सूचकांक स्वैप (ओआईएस) दरों से स्पष्ट है - मौद्रिक नीति की घोषणा के बाद 2 महीने की ओआईएस दर में 14 बीपीएस की गिरावट आई

29 मार्च 2023 को जारी 2023-24 की पहली छमाही के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों पर सरकारी उधार कैलेंडर में सकल उधार आवश्यकता ₹8.9 लाख करोड़ आंकी गई, जो वर्ष के लिए कुल बजटीय सकल उधार का 58 प्रतिशत है। टी-बिल कैलेंडर ने 2023-24 की पहली तिमाही के लिए ₹4.2 लाख करोड़ (₹1.4 लाख करोड़ का निवल निर्गम) जारी करने का प्रस्ताव किया है। वक्र में, प्रतिफल नीचे से बीच के अंत में कम हो गए, जबकि वे ऊंचे अंत में मजबूत हुए (चार्ट 52 बी)।

मार्च की दूसरी छमाही से 11 अप्रैल 2023 के दौरान कॉर्पोरेट बॉण्ड प्रतिफल में आम तौर पर कमी आई, जबकि अधिकांश जारीकर्ता श्रेणियों और अवधि के लिए स्प्रेड बढ़ गए। बॉण्ड बाजार में औसत जोखिम प्रीमियम (5-वर्षीय एएए से 5 वर्षीय जी-सेक घटाकर) 16 मार्च 2023 - 11 अप्रैल 2023 के दौरान तेजी से बढ़ा (सारणी 4)। कॉर्पोरेट बॉण्ड जारी करने के माध्यम से जुटाई गई निधि फरवरी 2023 के दौरान बढ़कर ₹0.75 लाख करोड़ हो गई, जो पिछले महीने में ₹0.68 लाख करोड़ थी।

आरक्षित मुद्रा (आरएम), सीआरआर में परिवर्तन के पहले दौर के प्रभाव को छोड़कर, 7 अप्रैल 2023 को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 7.5 प्रतिशत बढ़ी (1 वर्ष पहले 10.1 प्रतिशत)। आरएम की सबसे बड़ी घटक मुद्रा (सीआईसी) एक वर्ष पहले के 10.1 प्रतिशत से घटकर 7.6 प्रतिशत रह गई। सीआईसी में कमी ने रिज़र्व बैंक की विभिन्न पहलों के माध्यम से महामारी के बाद की अवधि में भारत में डिजिटल भुगतान में वृद्धि को ट्रैक किया, इसके अलावा महामारी के चरम के दौरान 'कैश के लिए डैश' व्यवहार में कमी आई।

सारणी 4: वित्तीय बाजार - दरें और स्प्रेड

लिखत	ब्याज दरें (प्रतिशत)			स्प्रेड (आधार बिंदु) (संबंधित जोखिम पर - मुक्त दर)		
	फर 16, 2023 – मार्च 15, 2023	मार्च 16, 2023 – अप्रै 11, 2023	भिन्नता (बीपीएस में)	फर 16, 2023 – मार्च 15, 2023	मार्च 16, 2023 – अप्रै 11, 2023	भिन्नता (बीपीएस में)
1	2	3	(4 = 3-2)	5	6	(7 = 6-5)
कॉर्पोरेट बॉन्ड						
(i) एएए (1-वर्ष)	8.06	8.00	-6	46	69	23
(ii) एएए (3-वर्ष)	8.03	8.02	-1	58	76	18
(iii) एएए (5-वर्ष)	7.95	8.01	6	43	71	28
(iv) एए (3 वर्ष)	8.75	8.70	-5	130	145	15
(v) बीबीबी-(3-वर्ष)	12.4	12.35	-5	495	510	15

टिप्पणी: पैदावार और स्प्रेड की गणना मासिक औसत के रूप में की जाती है।
स्रोत: एफ़आईएमएमडीए; और ब्लूमबर्ग।

2022-23 (24 मार्च 2023 तक) के दौरान, आरएम में विस्तार मुख्य रूप से निवल विदेशी आस्तियों (एनएफए) (लगभग

चार्ट 53: मौद्रिक और ऋण समुच्चय

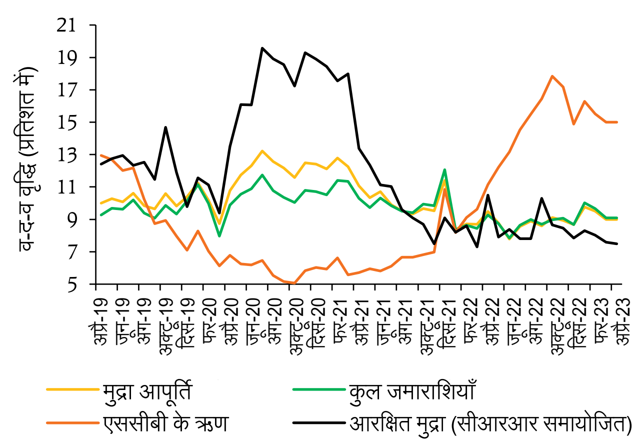

टिप्पणी: 1. डेटा मुद्रा आपूर्ति, कुल जमा और बैंक ऋण; के लिए हर महीने के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार और आरक्षित मुद्रा के लिए हर महीने के आखिरी शुक्रवार से संबंधित है।
2. आरक्षित मुद्रा के लिए नवीनतम डेटा 7 अप्रैल 2023 से और मुद्रा आपूर्ति के लिए 24 मार्च 2023 से संबंधित है।
स्रोत: आरबीआई।

चार्ट 54: रिज़र्व बैंक के एनडीए और एनएफए (साप्ताहिक परिवर्तन)

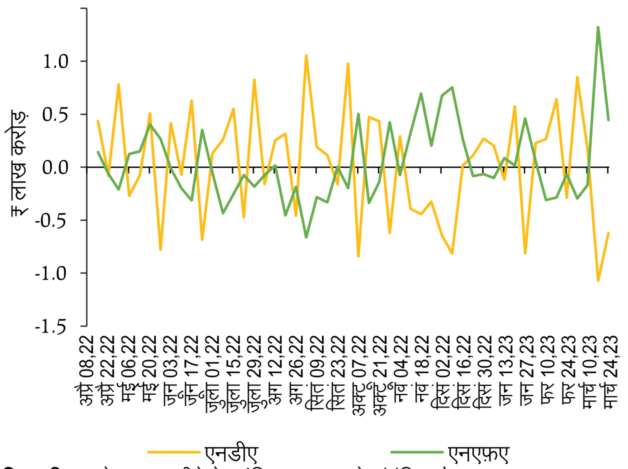

टिप्पणी: 1. डेटा हर महीने के अंतिम शुक्रवार से संबंधित है।
2. नवीनतम आंकड़े 24 मार्च 2023 से संबंधित हैं।
स्रोत: आरबीआई।

67 प्रतिशत योगदान), और निवल घरेलू आस्तियों (एनडीए) [लगभग 33 प्रतिशत योगदान] से प्रेरित था (चार्ट 54)।

मुद्रा आपूर्ति (एम3) में 24 मार्च 2023 (एक वर्ष पहले 8.7 प्रतिशत) तक 9.0 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई, जो मुख्य रूप से इसके सबसे बड़े घटक - बैंकों के साथ कुल जमा - से प्रेरित थी - जिसमें 9.1 प्रतिशत (एक वर्ष पहले 8.4 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के ऋण में 24 मार्च 2023 तक 15.0 प्रतिशत के दो अंकों में वृद्धि हुई, जो प्रतिकूल आधार प्रभावों और विशेष रूप से उद्योग के लिए ऋण उठाव की गति में कमी के कारण अक्टूबर 2022 में दर्ज 17.8 प्रतिशत के शिखर से कम है। नवंबर 2022 के बाद से औद्योगिक ऋण में गिरावट सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और बड़े उद्योगों के कारण थी, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर खंड से ऋण वृद्धि में गिरावट आई। खुदरा ऋण समग्र ऋण वृद्धि का प्रमुख चालक बना रहा, इसके बाद सेवा क्षेत्र का स्थान रहा। फरवरी में निजी ऋण में वृद्धि 20.4 फीसदी रही, जिसे आवास ऋण, वाहन ऋण और अन्य छोटे ऋण से बढ़ावा मिला। उपभोक्ता टिकाऊ और क्रेडिट कार्ड ऋणों का एक मजबूत गति से विस्तार हुआ, जो बढ़ती उपभोक्ता मांग को दर्शाता है (चार्ट 55 ए और 55 बी)। सेवा क्षेत्र में ऋण वृद्धि में बड़े पैमाने पर एनबीएफ़सी का योगदान था। बैंक ऋण वृद्धि सभी जनसंख्या समूहों (ग्रामीण, अर्ध-शहरी, शहरी और महानगरीय) में दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज करते हुए व्यापक आधार पर हुई। कार्यशील पूंजी ऋण की मांग बढ़ रही है।

07 अप्रैल 2023 तक, एससीबी का ऋण-जमा अनुपात 75.8 प्रतिशत (08 अप्रैल 2022 तक 71.5 प्रतिशत) था। वृद्धिशील ऋण-जमा (सी-डी) अनुपात, जो महामारी की शुरुआत

चार्ट 55: खुदरा ऋण वृद्धि गतिशीलता

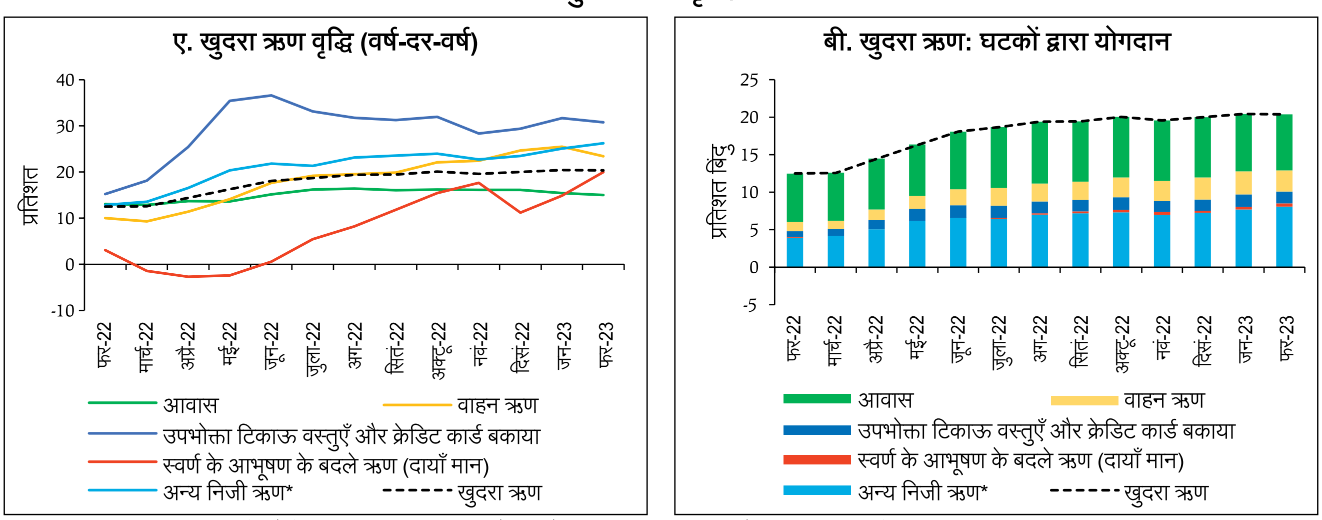

टिप्पणी: खुदरा ऋण विभिन्न उद्देश्यों के लिए एक ग्राहक / हाउसहोल्ड को दिए गए व्यक्तिक ऋण को संदर्भित करता है।
*अन्य व्यक्तिक ऋणों में शिक्षा, घरेलू खपत, चिकित्सा व्यय, यात्रा, विवाह और अन्य सामाजिक समारोह, ऋण के पुनर्भुगतान के लिए ऋण आदि के लिए ऋण शामिल हैं।
स्रोत: आरबीआई।

के आसपास 50 प्रतिशत से नीचे आ गया और 2021 के अंत तक कम रहा, नवंबर 2022 में बढ़कर 142.2 प्रतिशत हो गया और 07 अप्रैल 2023 को कम होकर 110.0 पर आ गया (चार्ट 56)।

एससीबी ने नीतिगत दरों में वृद्धि को प्रतिबिंबित करने के लिए अपनी बाह्य बेंचमार्क आधारित उधार दर (ईबीएलआर) को समायोजित किया। मई 2022 से मार्च 2023 के दौरान 1 वर्ष की निधि आधारित उधार दर की औसत सीमांत लागत(एमसीएलआर) में 140 बीपीएस की वृद्धि हुई। मई 2022-फरवरी 2023 के दौरान नए और बकाया रुपये के ऋणों पर भारित औसत उधार दरों (डब्ल्यूएएलआर) का प्रभाव अंतरण बढ़कर क्रमशः 173 बीपीएस और 95 बीपीएस हो गया (चार्ट 57)। जमा पक्ष पर, मई 2022-फरवरी 2023 के दौरान बकाया जमा पर भारित औसत घरेलू सावधि जमा दर (डब्ल्यूएडीटीडीआर) में 99 बीपीएस की वृद्धि हुई। बाह्य बेंचमार्क आधारित ऋण बकाया अस्थायी दर ऋणों पर हावी है, जो दिसंबर 2022 के अंत तक 48.3 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखते हैं।[17]

भारत सरकार ने 2022-23 की चौथी तिमाही की तुलना में 2023-24 की पहली तिमाही के लिए लघु बचत योजनाओं (एसएसआई) पर दरों में 10-70 बीपीएस की सीमा में संशोधन

चार्ट 56: बैंक ऋण वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) और वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात (26-पखवाड़े रोलिंग)

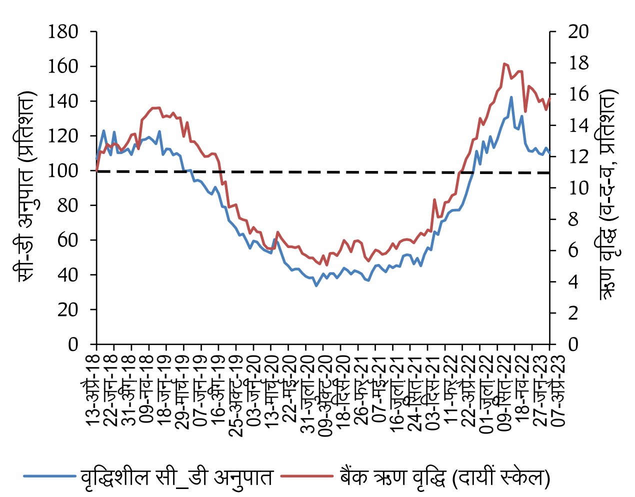

स्रोत : आरबीआई।

चार्ट 57: बैंकों की जमा राशि में संचरण और उधार दरें

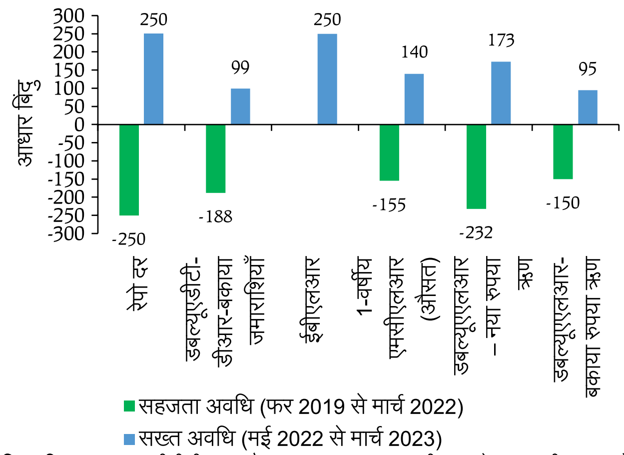

टिप्पणी: 1. डब्ल्यूएडीटीडीआर और डब्ल्यूएएलआर पर नवीनतम डेटा फरवरी 2023 से संबंधित है।
2. मार्च 2023 के अंत तक 31 घरेलू बैंकों ने अपने ईबीएलआर में 250 बीपीएस की वृद्धि की है।

स्रोत: आरबीआई।

किया है। लोक भविष्य निधि (पीपीएफ़) पर ब्याज दर अपरिवर्तित रही (चार्ट 58)। इन समायोजनों के साथ, अधिकांश लघु उद्योगों पर ब्याज दरें अब सूत्र-आधारित दरों के साथ निकटता से संरेखित हैं। पीपीएफ, डाकघर आवर्ती जमा खातों और सुकन्या समृद्धि खाता योजना पर ब्याज दरें हालांकि फॉर्मूला आधारित ब्याज दरों से 26 से 82 आधार अंक नीचे हैं।[18]

घरेलू शेयर बाजारों ने मार्च 2023 की दूसरी छमाही के दौरान अमेरिका और यूरोप में बैंकिंग उथल-पुथल से उभरने वाले झटकों को प्रतिबिंबित किया। हालांकि, महीने के अंत में बाजार में सुधार हुआ क्योंकि संक्रमण की आशंका कम हो गई। अप्रैल 2023 में यूरोक्षेत्र मुद्रास्फीति के उम्मीद से कम रहने से सकारात्मक वैश्विक संकेतों, मजबूत घरेलू विनिर्माण पीएमआई और वाहनों की बिक्री के उत्साहजनक आंकड़ों से बाजार धारणा को बल मिला। इसके अलावा, रिजर्व बैंक द्वारा दरों में वृद्धि चक्र में ठहराव ने सकारात्मक गति में योगदान दिया। इसके बाद 2022-23 की चौथी तिमाही के कमजोर परिणामों की घोषणा के बाद आईटी क्षेत्र के शेयरों में बिकवाली के बीच बाजार में गिरावट आई। कुल मिलाकर, बीएसई सेंसेक्स 15 मार्च 2023 के बाद से 3.8 प्रतिशत बढ़कर 18 अप्रैल 2023 को 59,727 पर बंद हुआ।

[17] मौद्रिक नीति रिपोर्ट- अप्रैल 2023, अध्याय IV

[18] मौद्रिक नीति रिपोर्ट- अप्रैल 2023, अध्याय IV

चार्ट 58: वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के लिए लघु बचत लिखतों पर दरों में परिवर्तन

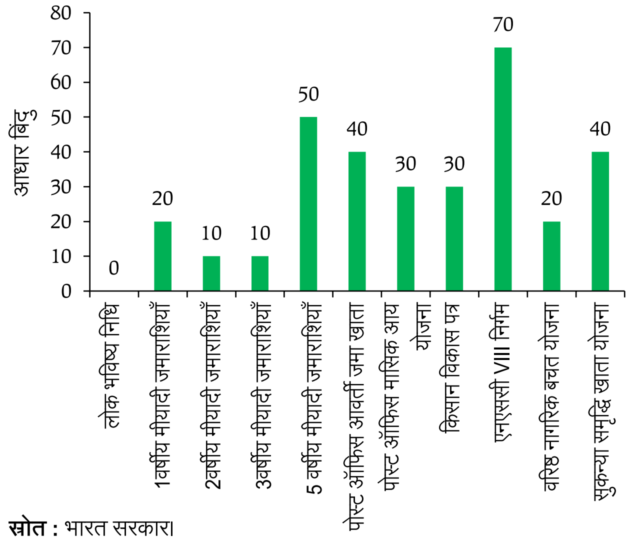

स्रोत : भारत सरकार।

चार्ट 59: 2023 में इक्विटी बाजारों का प्रदर्शन

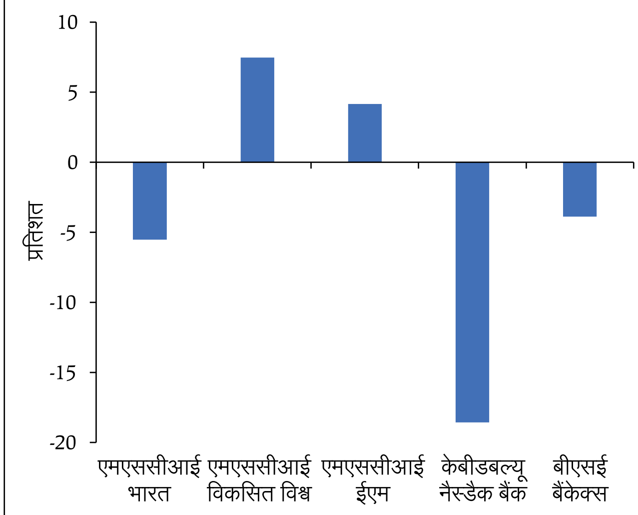

टिप्पणी: 11 अप्रैल 2023 तक का डेटा।
स्रोत: ब्लूमबर्ग।

2023 में, बैंकिंग क्षेत्र सूचकांक (बीएसई-बैंकेक्स) ने आघात-सहनीयता दिखाई, जो भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की मजबूती स्थिति को दर्शाता है (चार्ट 59)।

मार्च 2023 में विनियामकीय घटनाक्रमों के संदर्भ में, कर्ज़ म्यूचुअल फंडों को मिलने वाले कराधान अंतरपणन को हटा दिया गया,[19] जिससे विभिन्न निश्चित आय वाले निवेश विकल्पों के बीच कराधान में एकरूपता आ गई है। निवेशक मार्च के अंतिम सप्ताह में कर्ज़ म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए दौड़ पड़े, ताकि पूर्ववर्ती कर ढांचे के तहत तरजीही कराधान का लाभ उठाया जा सके, क्योंकि अप्रैल 2023 से नई कर व्यवस्था शुरू हो गई (चार्ट 60)।[20] इसके अलावा, दबाव के समय निवेश-ग्रेड कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों की खरीद के लिए बैकस्टॉप सुविधा के रूप में कॉर्पोरेट ऋण बाजार विकास निधि (सीडीएमडीएफ) की घोषणा ने कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार में विश्वास पैदा किया।

अप्रैल-फरवरी 2022-23 के दौरान सकल आवक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 14.5 प्रतिशत की कमी आई (चार्ट 61)। इस अवधि के दौरान 63 प्रतिशत से अधिक एफडीआई इक्विटी प्रवाह सिंगापुर, मॉरीशस और अमेरिका से होने की सूचना मिली थी। निवल एफडीआई एक वर्ष पूर्व के 355 बिलियन अमरीकी डालर से घटकर 277 बिलियन अमरीकी डालर रह गया, जिसका मुख्य कारण सकल प्रत्यक्ष

चार्ट 60: निरंतर स्वरूप के ऋण-आधारित निधियों में निवल प्रवाह

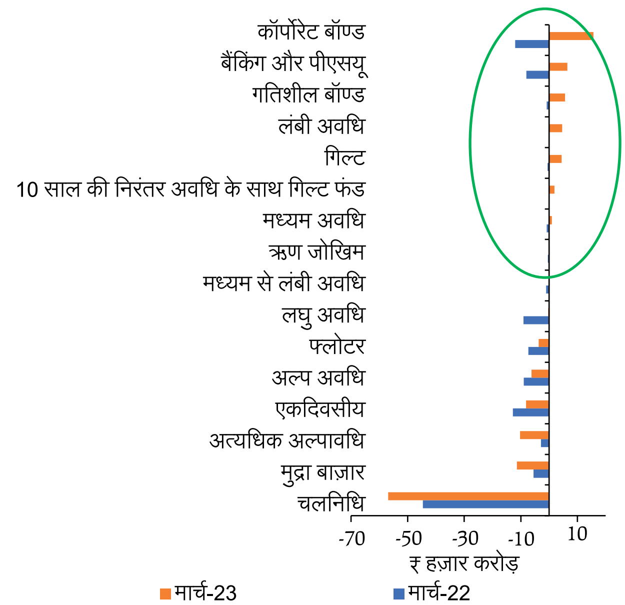

स्रोत : एएमएफ़आई।

[19] https://egazette.nic.in/WriteReadData/2023/244830.pdf

[20] https://www.livemint.com/news/india/investors-pour-31-179cr-into-debt-mfs-ahead-of-tax-change-11681236818180.html

चार्ट 61: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

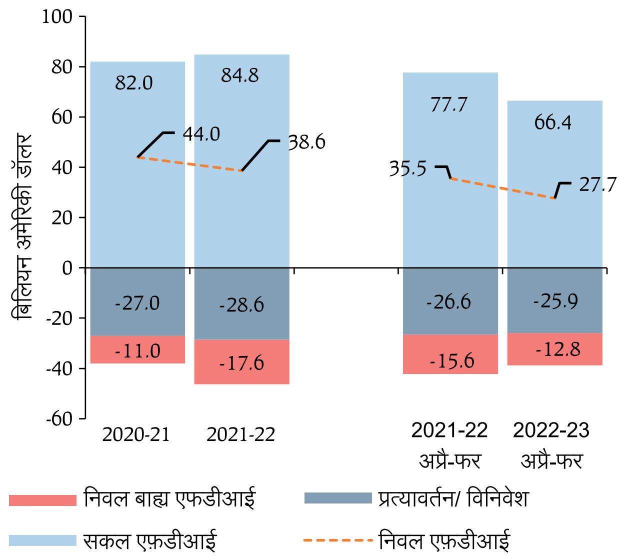

स्रोत : आरबीआई।

विदेशी निवेश अंतर्वाह में कमी और प्रत्यावर्तन में वृद्धि है। एफडीआई इक्विटी प्रवाह विनिर्माण की ओर झुका रहा, इसके बाद वित्तीय सेवाओं और कंप्यूटर सेवाओं का स्थान रहा। अप्रैल-फरवरी 2023 के दौरान कुल निवेश में इनकी हिस्सेदारी करीब आधी रही।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) मार्च 2023 के दौरान घरेलू वित्तीय बाजारों में निवल खरीदार बन गए, मुख्य रूप से इक्विटी वाले भाग में (1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर) में (चार्ट 62), जबकि ऋण खंड ने बहिर्वाह दर्ज किया। 2022-23 में, एफपीआई ने 5.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की निकासी की; हालांकि, जुलाई 2022 के बाद से, एफपीआई ने 9.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल प्रवाह दर्ज किया है, जो बड़े पैमाने पर इक्विटी बाजार में है। मार्च 2023 की दूसरी छमाही में पूंजीगत वस्तु क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र और तेज़ी से गतिशील उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र इक्विटी एफपीआई के प्रमुख प्राप्तकर्ता थे। अप्रैल 2023 (17 तारीख तक) में, एफपीआई प्रवाह 0.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक सकारात्मक थे।

जनवरी-फरवरी 2023 में 2.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) संवितरण में 2022 के पहले दो महीनों की तुलना में 70 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है। हालांकि, मूल भुगतान थोड़ा कम होने के साथ, निवल ईसीबी जनवरी-फरवरी 2023 के दौरान सकारात्मक थे, जबकि 2022-23 की तीसरी तिमाही में बड़े निवल बहिर्वाह थे (चार्ट 63)। अनिवासी जमाओं में निवल अभिवृद्धि अप्रैल-फरवरी 2022-23 में बढ़कर 6.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई, जो एक साल पहले 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी।

चार्ट 62: निवल पोर्टफोलियो निवेश

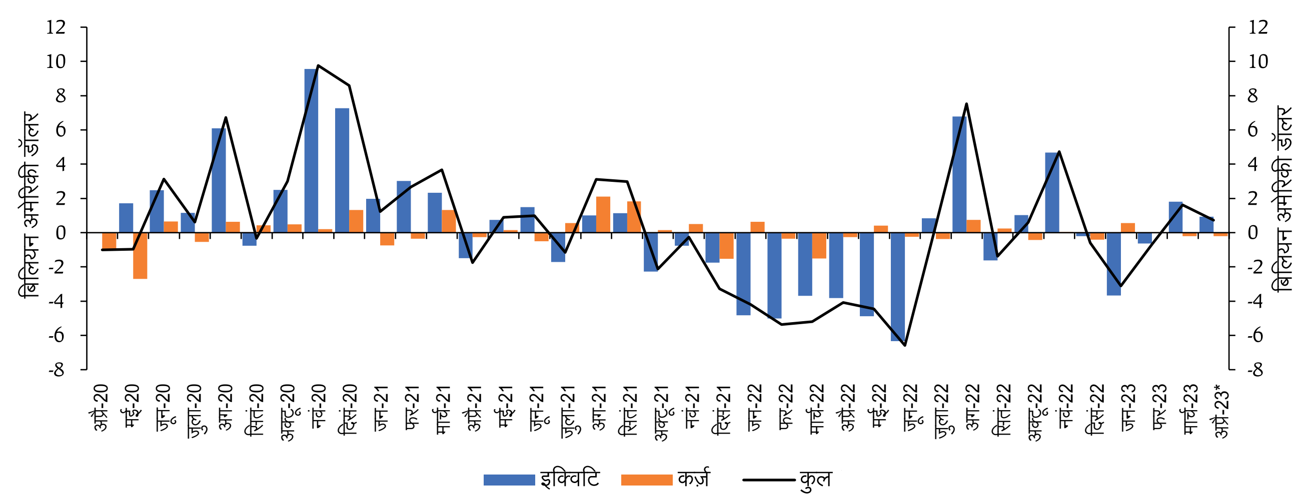

टिप्पणी: 1. *: 17 अप्रैल 2023 तक।

2. ऋण में स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर) और हाइब्रिड लिखतों के तहत निवेश शामिल हैं।

स्रोत: नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)।

चार्ट 63: ईसीबी - पंजीकरण, अंतर्वाह और बहिर्वाह

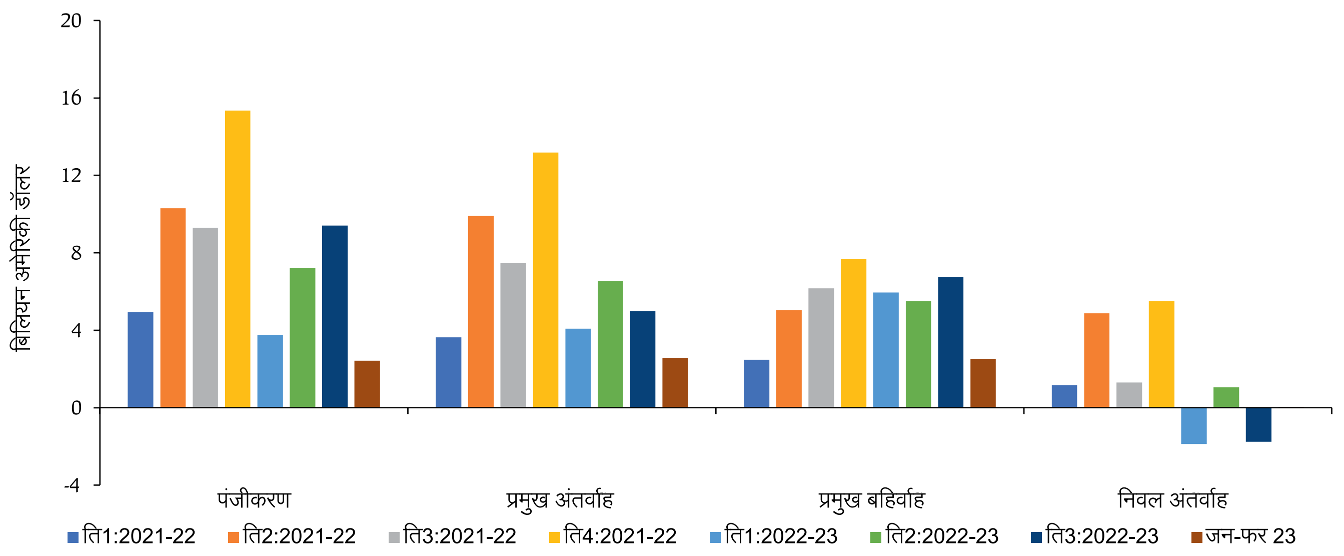

स्रोत : आरबीआई।

बाह्य क्षेत्र की संवेदनशीलता के प्रमुख संकेतक जैसे जीडीपी अनुपात में विदेशी ऋण, आरक्षित अनुपात में अल्पकालिक ऋण (अवशिष्ट परिपक्वता), ऋण सेवा अनुपात और सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में निवल अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति (आईआईपी) ने 2022-23 की तीसरी तिमाही में सुधार दर्ज किया जो बाह्य क्षेत्र की आघात सहनीयता को दर्शाता है (चार्ट 64)। जीडीपी अनुपात के मुकाबले भारत का विदेशी ऋण दिसंबर 2022 के अंत में सितंबर 2022 के अंत के समान स्तर 19.1 प्रतिशत पर था।

चार्ट 64: बाह्य सुभेद्यता संकेतक

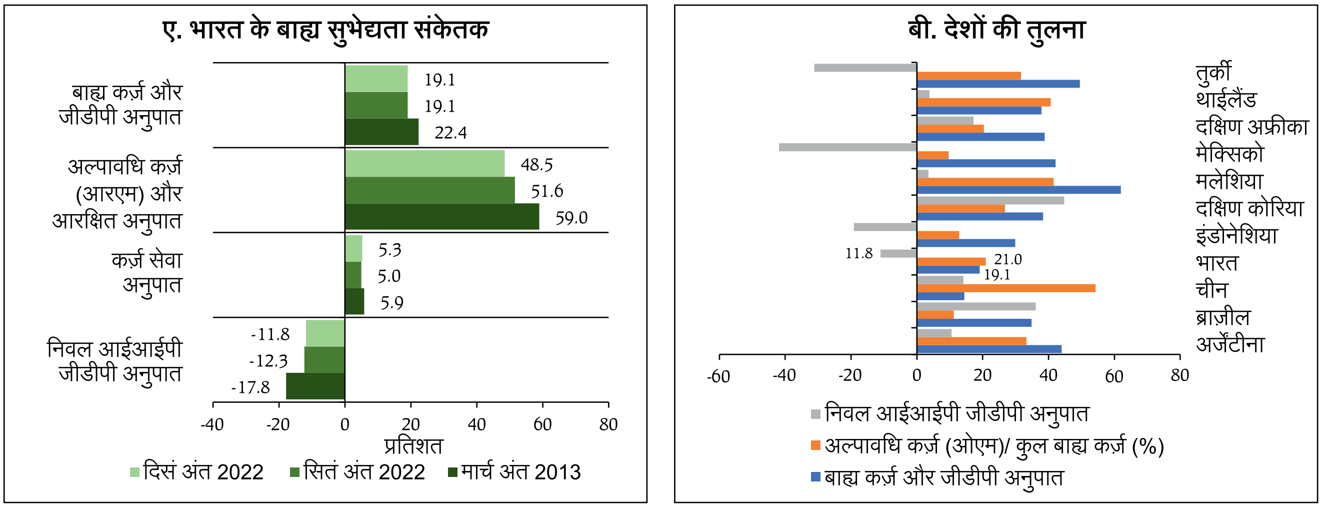

आरएम: अवशिष्ट परिपक्वता; आईआईपी: अंतरराष्ट्रीय निवेश की स्थिति; ओम: मूल परिपक्वता।
नोट: डेटा अल्पावधि ऋण (ओएम)/ कुल बाह्य ऋण (%) जो सितंबर 2022 तक है को छोड़कर डेटा दिसंबर 2022 के अंत तक है।
स्रोत: सीईआईसी; आरबीआई; वित्त मंत्रालय; और संबंधित सेंट्रल बैंक की वेबसाइटें।

चार्ट 65: भारत का विदेशी मुद्रा भंडार

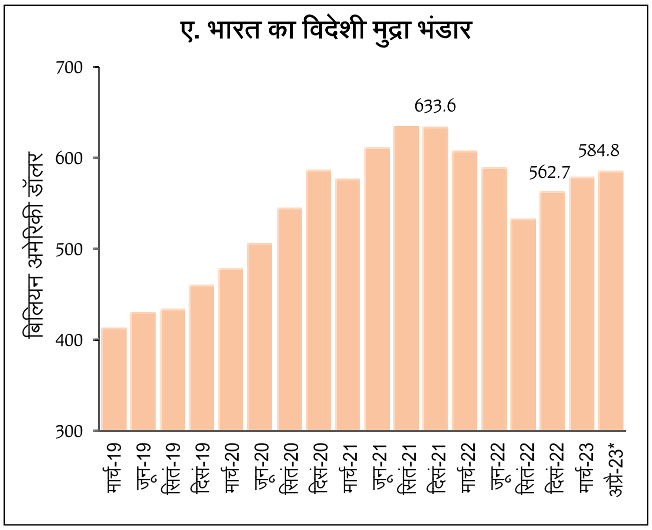

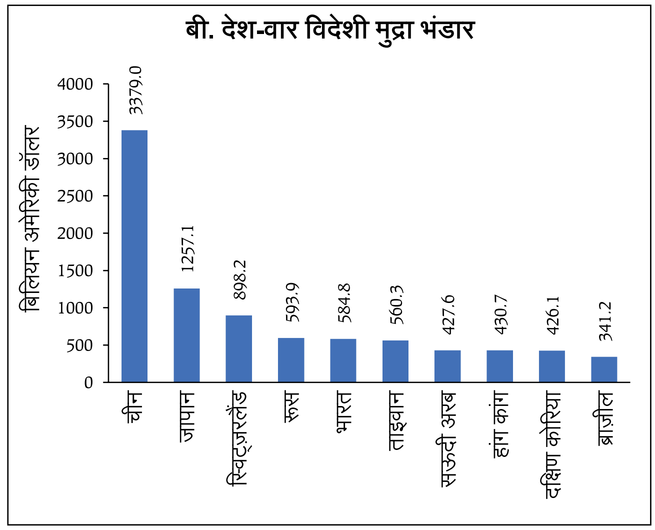

टिप्पणी : भारत के लिए डेटा 07 अप्रैल 2023 तक है। स्विट्ज़रलैंड और सऊदी अरब (फरवरी) को छोड़कर अन्य देशों के आंकड़े मार्च 2023 के अंत तक के हैं।
स्रोत: आरबीआई; और संबंधित सेंट्रल बैंक की वेबसाइटें।

21 अक्टूबर, 2022 से विदेशी मुद्रा भंडार में 60.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई और 07 अप्रैल 2023 को यह 584.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 2022-23 के लिए अनुमानित आयात के 9.9 महीनों को कवर करने के लिए पर्याप्त है (चार्ट 65)।

भारतीय रुपया (आईएनआर) मार्च 2023 में अमेरिकी डॉलर की तुलना में 0.4 प्रतिशत (एम-ओ-एम) मजबूत हुआ और सबसे कम अस्थिर प्रमुख मुद्राओं में से एक बन गया (चार्ट 66)।

चार्ट 66: अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये और प्रमुख मुद्राओं का उतार-चढ़ाव (मार्च 2023, एम-ओ-एम)

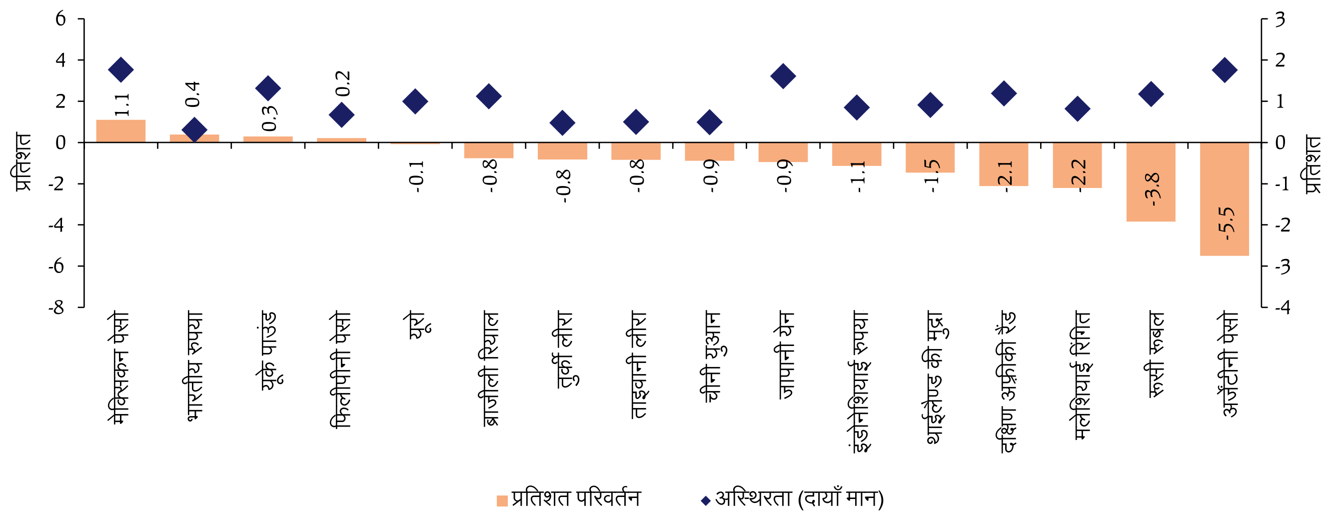

स्रोत: एफबीआईएल; आईएमएफ; थॉमसन रॉयटर्स; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

चार्ट 67: 40-मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में उतार-चढ़ाव

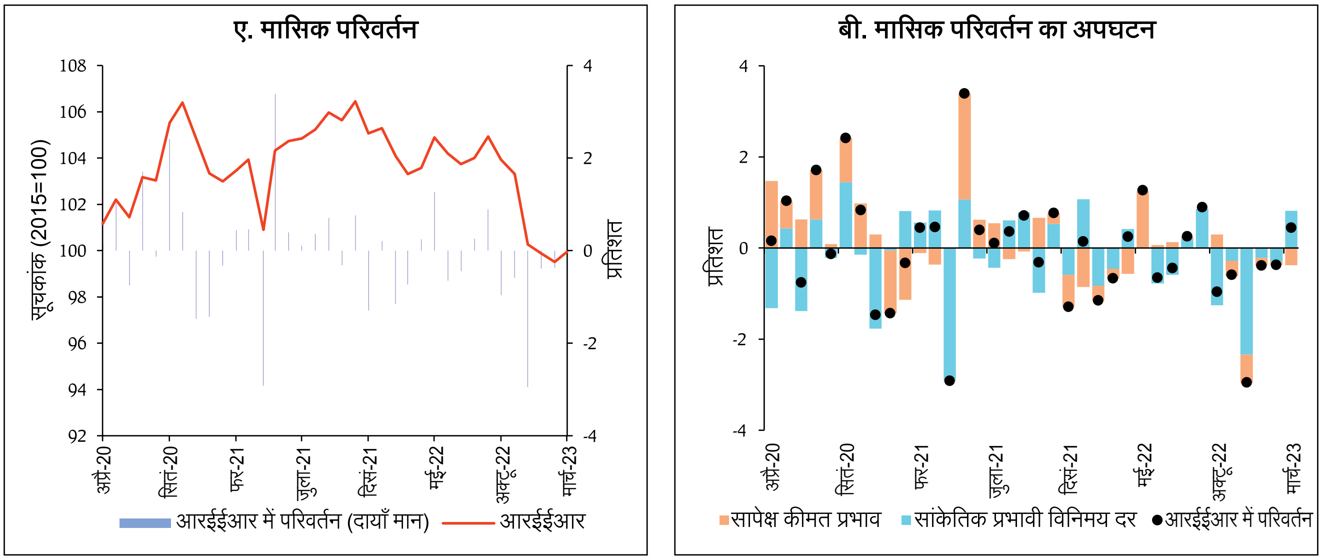

स्रोत: आरबीआई।

मार्च 2023 में 40-मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) सूचकांक के संदर्भ में रुपये में 0.4 प्रतिशत (एम-ओ-एम) की वृद्धि हुई (चार्ट 67)।

भुगतान प्रणाली

एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई), भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) और राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच) के माध्यम से खुदरा लेनदेन के नेतृत्व में मार्च 2023 में चैनलों में डिजिटल भुगतान में वृद्धि हुई (सारणी 5)। 6 अप्रैल 2023 के विकासात्मक और नियामक नीतियों पर अपने वक्तव्य में रिज़र्व बैंक ने जमा खातों के अलावा, यूपीआई का उपयोग करके बैंकों में पूर्व-स्वीकृत ऋण लाइनों से हस्तांतरण को सक्षम करके यूपीआई के दायरे का विस्तार करने का प्रस्ताव किया। यह उपाय बैंक ऋण द्वारा वित्तपोषित भुगतान की सुविधा प्रदान करेगा। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने प्रीपेड भुगतान इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआई) वॉलेट को ₹2,000 से अधिक के पीपीआई व्यापारी लेनदेन के लिए इंटरचेंज शुल्क के साथ इंटरऑपरेबल यूपीआई पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा बनने की अनुमति दी है ताकि यूपीआई की इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ावा दिया जा सके और पारिस्थितिकी तंत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जा सके।[21]

सारणी 5: चुनिंदा भुगतान प्रणालियों में वृद्धि

(व-द-व प्रतिशत में)

भुगतान प्रणाली संकेतक	लेनदेन की मात्रा				लेनदेन का मूल्य			
	फर-22	फर-23	मार्च-22	मार्च-23	फर-22	फर-23	मार्च-22	मार्च-23
आरटीजीएस	14.3	11.2	13.7	7.8	14.1	16.7	11.4	11.5
एनईएफ़टी	28.8	28.7	23.9	26.8	15.1	12.1	14.6	7.4
यूपीआई	97.5	66.4	97.9	60.0	94.5	49.5	90.3	46.3
आईएमपीएस	32.0	6.4	35.5	1.0	39.7	21.9	41.3	18.2
एनएसीएच	28.0	70.9	7.5	29.8	30.2	36.6	-6.3	35.1
एनईटीसी	53.3	18.4	39.9	13.3	42.0	29.0	32.7	23.7
बीबीपीएस	121.2	54.1	102.4	56.5	136.2	63.4	120.7	61.6

स्रोत: आरबीआई।

[21] एनपीसीआई प्रेस विज्ञप्ति, मार्च 2023

बैंक ने संयुक्त अरब अमीरात के सेंट्रल बैंक (सीबीयूएई) के साथ फिनटेक और संबंधित देशों की डिजिटल मुद्राओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उभरती हुई तकनीकी और साइबर सुरक्षा से संबंधित अनुसंधान और क्षमता निर्माण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, भुवनेश्वर, ओडिशा में रिज़र्व बैंक के ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर और एंटरप्राइज कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए आधारशिला रखी गई।

तत्काल भुगतान (आरटीपी) [22] वाले भाग में, भारत ने 2022 में सबसे अधिक[23] लेनदेन दर्ज किए (दुनिया भर में सभी वास्तविक समय लेनदेन का 46 प्रतिशत हिस्सा है), इसके बाद ब्राजील, चीन और थाईलैंड हैं। यूपीआई की मजबूत ब्रांड पहचान, उच्च व्यापारी स्वीकृति और नीतिगत समर्थन इस विकास के प्रमुख वाहक हैं।डिजिटलीकरण में तेजी से प्रगति से नकद लेनदेन में गिरावट आ रही है – बिक्री केंद्र (पीओएस) पर नकद उपयोग 2022 में पीओएस लेनदेन मूल्य के 27 प्रतिशत तक गिर गया, जो 2019 में 71 प्रतिशत से भी नीचे था।

बीबीपीएस के माध्यम से डिजिटल ऋण चुकौती (मात्रा और मूल्य) पिछले महीने में दोगुनी (वर्ष-दर-वर्ष) हो गई, जो ऋण व्यवसाय के तेजी से डिजिटलीकरण का संकेत है। भारत में ई-कॉमर्स का कुल लेनदेन मूल्य 2026 में 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर दर्ज होने की उम्मीद है, जो 2022 में 83 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। 2026 तक अनुमानित 16 प्रतिशत सीएजीआर के साथ, भारत वैश्विक ई-कॉमर्स विकास (9 प्रतिशत) को पीछे छोड़ देगा। [25]

[22] आरटीपी भुगतान अनुरोध की शुरुआत के बाद तत्काल निपटान को संदर्भित करता है। यूपीआई और तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) भारत में इस तरह के भुगतान की श्रेणी में आते हैं।

[23] भारत में तत्काल लेनदेन 76.8 प्रतिशत बढ़कर 2022 में 89.5 बिलियन की कुल लेनदेन मात्रा दर्ज करने के लिए बढ़ गया।

[24] एसीआई वर्ल्डवाइड एंड ग्लोबल डेटा (2023), यह तत्काल 2023 के लिए प्राइम टाइम है।

[25] फिडेलिटी नेशनल इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इंक (2023), द ग्लोबल पेमेंट्स रिपोर्ट।

V. निष्कर्ष

आरबीआई की एमपीसी ने 6-8 अप्रैल, 2023 के दौरान बैठक की और समष्टिआर्थिक और वित्तीय दृष्टिकोण की समीक्षा की। यह देखते हुए कि 2023-24 के लिए मुद्रास्फीति के प्रक्षेपवक्र की घरेलू और वैश्विक दोनों जोखिमों से अधिक और कम होने की संभावना है, रिपोर्ट में 2023-24 के लिए मुद्रास्फीति 5.2 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है, जो 2022-23 में 6.7 प्रतिशत से कम है, लेकिन फिर भी ऊंचा है। तदनुसार, समिति ने मूल्य दबावों के सामान्यीकरण पर लगाम लगाने और मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं को रोकने के लिए लक्ष्य के साथ मुद्रास्फीति को संरेखित करने पर दृढ़ता से ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया ताकि घरेलू आर्थिक गतिविधि में आघातसहनीयता बनाए रखा जा सके। उस बैठक में नीतिगत दर को अपरिवर्तित रखते हुए और समायोजन को जारी रखते हुए, एमपीसी ने 'आवश्यकता की स्थिति में कार्रवाई करने के लिए तैयार रखा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संवृद्धि का समर्थन करते हुए मुद्रास्फीति उत्तरोत्तर लक्ष्य के अनुरूप हो।

(i) 2021-22 की दूसरी छमाही में परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो नीलामी के माध्यम से चलनिधि को संरेखित करने से शुरुआत करना, (ii) अप्रैल 2022 में 3.35 प्रतिशत की निर्धारित दर रिवर्स रेपो दर से 40 आधार अंक अधिक दर पर स्थायी जमा सुविधा की शुरुआत और (iii) 2022-23 के दौरान 250 आधार अंकों की नीति रेपो दर में संचयी वृद्धि, भारित औसत कॉल मनी दर, मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य, 2022-23 के दौरान प्रभावी 320 आधार अंक बढ़ाया गया था। आपूर्ति पक्ष के उपायों की मदद से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति अप्रैल 2022 के 7.8 प्रतिशत के अपने उच्चतम स्तर से धीरे-धीरे घटकर मार्च 2023 में 5.7 प्रतिशत पर आ गई है और जनवरी-मार्च 2024 में चार तिमाहियों में इसके और कम होकर 5.2 प्रतिशत पर आने का अनुमान है। मौद्रिक नीति काम कर रही है। पर्याप्त अवस्फीति हासिल कर ली गई है, लेकिन मुद्रास्फीति को 4 प्रतिशत के लक्ष्य के आसपास या उसके करीब लाने का रास्ता बहुत लंबा है।

इस बिंदु पर, 6.5 प्रतिशत पर नीतिगत दर का स्तर चार तिमाहियों आगे मुद्रास्फीति के स्तर का 1.25 गुना है (एमपीसी

द्वारा अनुमानित 2023-24 की चौथी तिमाही में 5.2 प्रतिशत)। यह टेलर सिद्धांत की पुष्टि करता है जो मौद्रिक नीति का एक केंद्रीय सिद्धांत बन गया है। इसमें कहा गया है कि मुद्रास्फीति बढ़ने पर नाममात्र ब्याज दर को बिंदु-दर-बिंदु से अधिक बढ़ाया जाना चाहिए। टेलर सिद्धांत को संतुष्ट करना मुद्रास्फीति को स्थिर करने के लिए आवश्यक और पर्याप्त दोनों है। टेलर सिद्धांत प्रसिद्ध टेलर नियम (टेलर, 1993)[26] में अंतर्निहित है। भारत में मौद्रिक नीति ने अब तक जो प्रगति की है, वह अब तक उठाए गए कदमों के प्रभाव का आकलन करने और वास्तविक मुद्रास्फीति के अनुमानित मार्ग से भटकने की स्थिति में उचित प्रतिक्रिया की कार्यनीति बनाने के लिए पर्याप्त गुंजाइश प्रदान करती है। सहवर्ती रूप से, हमें अंतर्निहित आर्थिक गतिविधि पर प्रभावों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है क्योंकि पिछले मौद्रिक नीति कार्य मौद्रिक नीति के कार्यान्वयन से जुड़े जाने माने अंतराल के माध्यम से अपना काम करते हैं। गवर्नर श्री शक्तिकांत दास के शब्दों में, "हमारा काम अभी समाप्त नहीं हुआ है और मुद्रास्फीति के खिलाफ युद्ध तब तक जारी रखना होगा जब तक कि हम टिकाऊ गिरावट के साथ मुद्रास्फीति को लक्ष्य के करीब नहीं देखते। हम उचित और समय पर कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। हमें विश्वास है कि हम मध्यम अवधि में मुद्रास्फीति को लक्ष्य दर तक लाने के लिए सही रास्ते पर हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के इस मिशन के प्रति दृढ़ और प्रतिबद्ध रहने के साथ, हमारा दृढ़ विश्वास है कि वास्तविक परिणाम अंततः अर्थव्यवस्था की स्थिति में हमारे द्वारा प्रदान किए गए दृष्टिकोण के सूक्ष्म मूल्यांकन को प्रतिबिंबित करेंगे। समय के साथ, स्थायी मूल्य और वित्तीय स्थिरता अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूत करेगी और संवृद्धि को बढ़ावा देगी। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक जो दोहरे जनादेश के साथ निवेश कर रहे हैं, वे अपने रास्ते में एक कांटे पर हैं। आरबीआई ने कार्यों और गति दोनों को संतुलित और सही करने के लिए मुश्किल राह अपनाई है।

[26] टेलर नियम के अनुसार, नीतिगत ब्याज दर मुद्रास्फीति दर के साथ-साथ मुद्रास्फीति अंतर (मुद्रास्फीति से कम लक्षित मुद्रास्फीति दर) के योग के साथ आउटपुट अंतर (जीडीपी और संभावित जीडीपी के बीच प्रतिशत अंतर) के 0.5 गुना योग संतुलन वास्तविक ब्याज दर के बराबर होती है। लक्ष्य मुद्रास्फीति दर और संतुलन वास्तविक ब्याज दर दोनों 2.0 के बराबर निर्धारित होने के साथ, नियम नीति दर = 1.0 + 1.5 * मुद्रास्फीति + 0.5 * आउटपुट अंतर को सरल बनाती है।

अनुबंध 1: आरबीआई के उद्यम सर्वेक्षण के प्रमुख बिंदु

वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही के दौरान किए गए रिज़र्व बैंक के तिमाही उद्यम सर्वेक्षण[27] के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:

- मांग की स्थिति में निरंतर सुधार को लेकर कंपनियां आशावादी बनी हुई हैं।
- क्षमता उपयोग (सीयू) और मौसमी रूप से समायोजित सीयू 2022-23 की तीसरी तिमाही में दीर्घकालिक औसत सीयू से मामूली रूप से अधिक है और उछाल जारी रहने की संभावना है (चार्ट ए 1 और ए 2)।
- कुल मिलाकर सेवाओं और बुनियादी ढांचा फर्मों के लिए व्यावसायिक भावनाएं मजबूत बनी हुई हैं; निर्माताओं को आगे सामान्यीकरण की उम्मीद है, जैसा कि उत्पादन, ऑर्डर बुक, क्षमता उपयोग और विदेशी व्यापार पर उच्च आशावाद से नीचे आने से परिलक्षित होता है (चार्ट ए 3 और ए 4)।

चार्ट ए1: विनिर्माण क्षेत्र में क्षमता का उपयोग

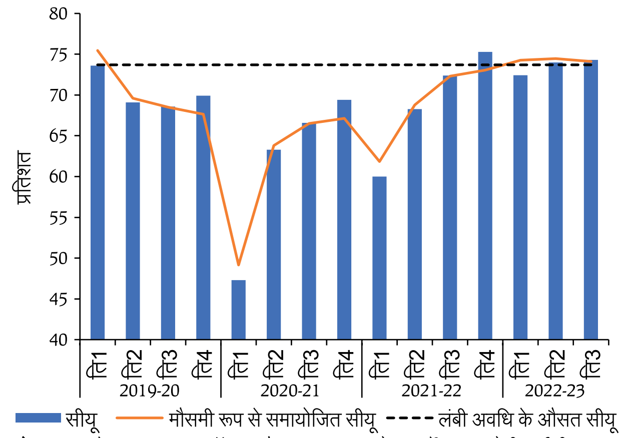

स्रोत: क्रयादेश पुस्तक, स्टॉक और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण (ओबीआईसीयूएस) आरबीआई।

चार्ट ए2: निर्माताओं की भावनाएँ क्षमता इस्तेमाल

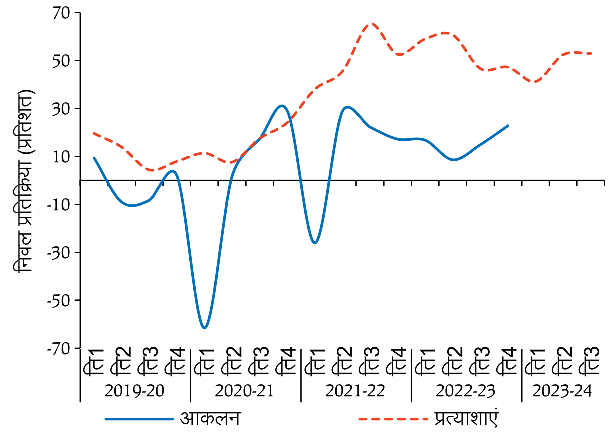

स्रोत: औद्योगिक आउटलुक सर्वेक्षण (आईओएस), आरबीआई।

चार्ट ए3: उत्पादन/कारोबार पर भावनाएँ

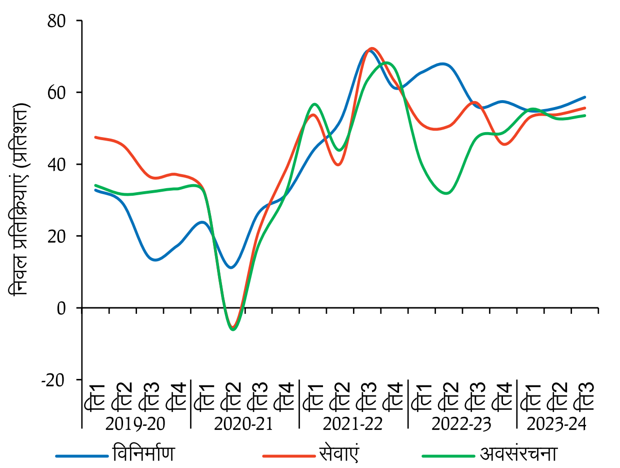

स्रोत: आईओएस; और सेवा और अवसंरचना आउटलुक सर्वेक्षण (एसआईओएस), आरबीआई।

चार्ट ए4: समग्र व्यवसाय पर भावनाएँ परिस्थिति

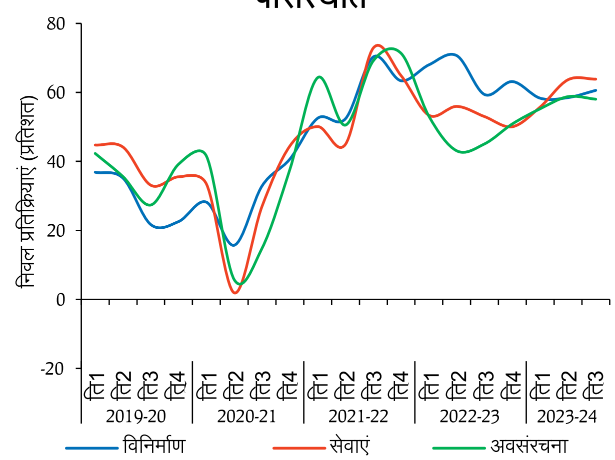

स्रोत: आईओएस और एसआईओएस, आरबीआई।

(जारी)

[27] https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=55480

अनुबंध 1: आरबीआई के उद्यम सर्वेक्षण के प्रमुख बिंदु *(जारी)*

चार्ट ए5: रोजगार की स्थिति पर नज़रिया

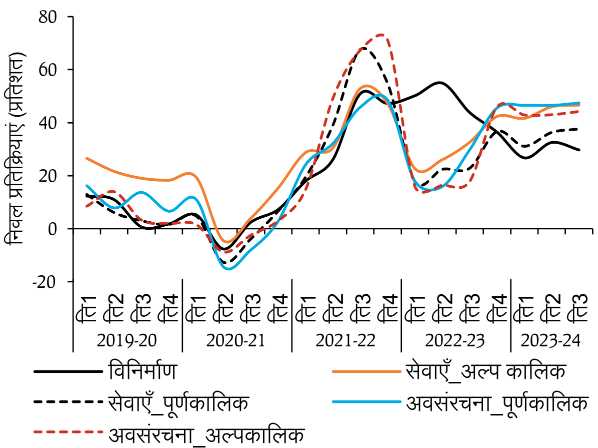

स्रोत: आईओएस और एसआईओएस, आरबीआई।

चार्ट ए6: इनपुट लागत पर नज़रिया

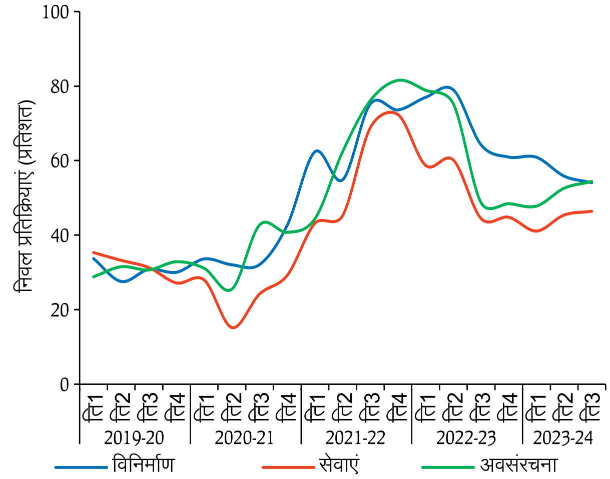

स्रोत: आईओएस और एसआईओएस, आरबीआई।

चार्ट ए7: विक्रय मूल्य पर नज़रिया

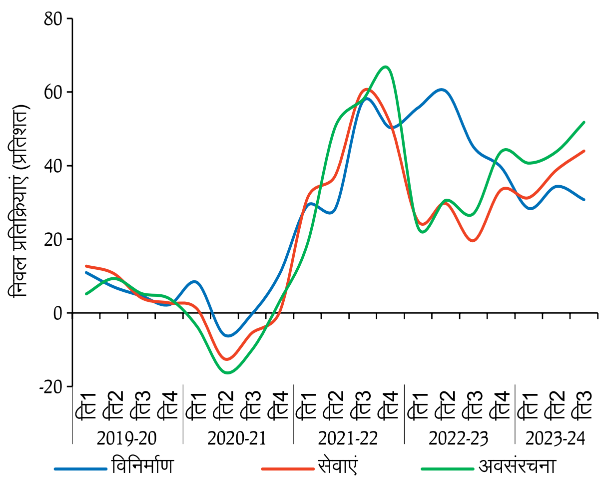

स्रोत: आईओएस और एसआईओएस, आरबीआई।

चार्ट ए8: ऋण की मांग पर वरिष्ठ ऋण अधिकारियों की अपेक्षाएँ

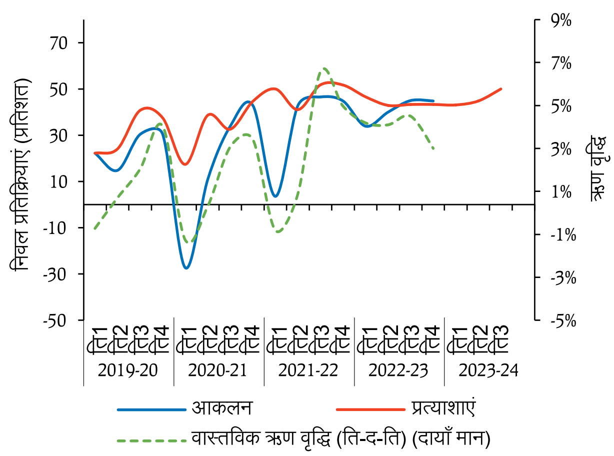

स्रोत: बैंक ऋण सर्वेक्षण (बीएलएस), आरबीआई।

टिप्पणी: 'निवल प्रतिक्रिया' आशावाद की रिपोर्ट करने वाले उत्तरदाताओं के प्रतिशत और निराशावाद की रिपोर्ट करने वालों के बीच का अंतर है। यह -100 और 100 के बीच होता है; शून्य से अधिक कोई भी मान विस्तार/आशावाद को दर्शाता है और शून्य से कम मान संकुचन/ निराशावाद को दर्शाता है।

- सेवाओं और अवसंरचना क्षेत्रों में रोजगार परिदृश्य में क्रमिक रूप से सुधार होने की उम्मीद है (चार्ट ए 5)।
- कच्चे माल की लागत में वृद्धि की गति में अपेक्षित कमी के साथ इनपुट लागत दबाव अपेक्षाकृत हल्का हो सकता है (चार्ट ए 6 और ए 7)।
- वरिष्ठ ऋण अधिकारियों को 2023-24 की पहली तीन तिमाहियोंके दौरान बैंक ऋण की मजबूत मांग की उम्मीद है (चार्ट ए 8)।

*हालिया प्रतिगामी मुद्रास्फीति – भारतीय अनुभव**

*द्वारा - माइकल देवब्रत पात्र, जॉयस जॉन और आशीष थॉमस जॉर्ज^*

जड़ता, स्थिरता, सामान्यीकरण, प्रसरण और चक्रीय संवेदनशीलता जैसे गुणों की पड़ताल करते हुए, यह आलेख बताता है कि 2020-22 के दौरान आपूर्ति आघात ने भारतीय अर्थव्यवस्था को उच्च मुद्रास्फीति दौर में स्थानांतरित कर दिया था। वर्ष 2022-23 की दूसरी छमाही के बाद से, इस बात की संभावना बढ़ रही है कि जड़ता और प्रवृत्ति में गिरावट के साथ उच्च मुद्रास्फीति का दौर खत्म हो रहा है, भले ही यह मांग-कारकों के प्रति बढ़ती संवेदनशीलता प्रदर्शित कर रही है। मौद्रिक नीति का कार्य अर्थव्यवस्था को कम मुद्रास्फीति की दौर में प्रवेश करने में मदद करना और मांग को बढ़ाने के लिए मुद्रास्फीति की बढ़ती संवेदनशीलता से निपटने के लिए तत्पर रहना है।

भारत में, 2010 की शुरुआत में मुद्रास्फीति दोहरे अंकों से कम हुई थी और 2016 से 2019 की अवधि में लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (एफआईटी) ढांचे के तहत निर्धारित 4 प्रतिशत के विधायी अनिवार्यता लक्ष्य के अनुरूप हो गई। कोविड-19 महामारी की शुरुआत के कारण लॉकडाउन, शहर से गाँव की ओर बड़े पैमाने पर पलायन और गंभीर आपूर्ति व्यवधान सामने आए। ज्यों ही महामारी की लहरें कम हुई, फरवरी 2022 के बाद से यूक्रेन में युद्ध ने दुनिया भर में केंद्रीय बैंकों पर मुद्रास्फीति के दबावों को बढ़ा दिया जो कि विभिन्न आपूर्ति के आघातों के कारण था (आपूर्ति शृंखला में व्यवधान; जहाज की कमी; बंदरगाह और पोत-परिवहन अव्यवस्था; भोजन, ऊर्जा, उर्वरक और धातु की आपूर्ति में युद्धजनित कमी; प्रतिबंध और वित्तीय विभाजन) जब शुरुआत में महामारी के बाद मांग में वृद्धि के कारण जोर पकड़ रही थी। तेजी से मुद्रास्फीति वैश्विक हो गई, जिससे केंद्रीय बैंकों को कई दशकों के सबसे आक्रामक और समकालिक मौद्रिक नीति कार्रवाई करनी पड़ी। भारत में, मुद्रास्फीति ऊपरी सहन-स्तर से ऊपर रही, जिससे नवंबर 2022 तक सांविधिक जवाबदेही प्रक्रियाएं शुरू हो गई।

यह आलेख मुद्रास्फीति आँकड़ों की पड़ताल करता है कि भारत इन मुद्रास्फीतिक अवधि-परिवर्तन से क्यों प्रभावित हुआ - 2020 और 2022 का उच्च मुद्रास्फीति अनुभव, उसके बाद संक्रमण के संकेत। यह खंड II में सांख्यिकीय रूप से उनकी पहचान करने के बाद भारत में उन अवधियों की विशेषताओं का विश्लेषण करने के लिए संक्रमण (बोरियो, और अन्य, 2023) पर ध्यान केंद्रित करने के साथ मुद्रास्फीति के द्विआवधिक दृष्टिकोण पर प्रभावशाली कार्य का अनुसरण करता है। हम मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं की स्थिति की जांच करने के लिए प्रवृत्ति मुद्रास्फीति के व्यवहार, इसकी दृढ़ता और प्रसंभाव्य अस्थिरता की जांच करते हैं। मुद्रास्फीति के दबावों में इन काल परिवर्तनों से जुड़ी बाह्यताओं, उनकी सामान्यीकरण प्रवृत्तियों और सापेक्ष मूल्य गतिशीलता को मुद्रास्फीति की व्यापक प्रकृति को खंड III में विश्लेषित किया गया है। खंड IV मूल और शीर्षक के बीच प्रसरण गुणों पर दोबारा गौर करती है ताकि मुद्रास्फीति के दबावों के स्थायित्व की पड़ताल की जा सके। खंड V मुद्रास्फीति की वृद्धि में मांग कारकों की भूमिका का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न कालों में मुद्रास्फीति की चक्रीय संवेदनशीलता की पड़ताल करता है। खंड VI कुछ नीतिगत विचारों के साथ निष्कर्ष प्रस्तुत करता है।

II. भारत के मुद्रास्फीति के इतिहास में परिवर्तन का दौर

मार्कोव स्विचिंग मॉडल (हैमिल्टन, 1989) साहित्य में सबसे लोकप्रिय अरेखीय काल-क्रम अवधि परिवर्तन मॉडल में से एक है। यह मॉडल कई संरचनाओं की जांच करता है जो विभिन्न व्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति व्यवहार को चित्रित कर सकते हैं, इन संरचनाओं के बीच परिवर्तित होने वाले जटिल गतिशील पैटर्न को चित्रित कर सकते हैं।

जनवरी 2012 से मार्च 2023 तक भारत में वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति दरों पर लागू मार्कोव स्विचिंग मॉडल से पता चलता है कि 2014 में भारत में एफआईटी की वास्तविक शुरूआत के साथ, मुद्रास्फीति उच्चता के दौर में आ गई जिसमें यह 2012-14 के दौरान 8 प्रतिशत से अधिक औसत से, न्यूनता के दौर में 4.4 प्रतिशत के औसत पर आ गई। 2020 की शुरुआत में कोविड-19

^ लेखक भारतीय रिज़र्व बैंक से हैं। इस आलेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

चार्ट 1: मुद्रास्फीति: दो दौर के दृष्टिकोण

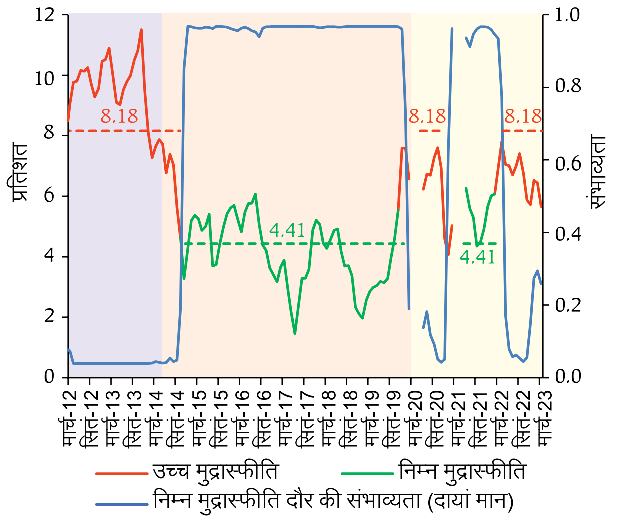

टिप्पणी: 2011-13 2014-19 2020-23

स्रोत: लेखकों के अनुमान.

चार्ट 2: समय-समय पर बदलती मुद्रास्फीति की निरंतरता

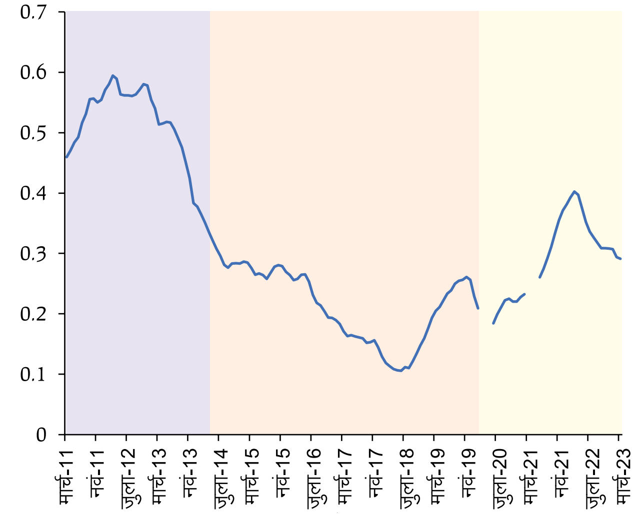

टिप्पणी: 2011-13 2014-19 2020-23

स्रोत: लेखकों के अनुमान.

महामारी के फैलने के कारण, मुद्रास्फीति अल्प अवधि के लिए उच्च स्तर पर वापस आ गई। जैसे-जैसे महामारी कम होती गई, मुद्रास्फीति 2021 की शुरुआत में निम्न स्तर पर वापस आ गई और 2022 की शुरुआत में यूक्रेन युद्ध तक वहीं बनी रही, जिसके कारण 2022-23 की पहली छमाही के दौरान यह उच्च स्तर पर वापस आ गई। 2022-23 की दूसरी छमाही के बाद से इस बात की संभावना बढ़ रही है कि मुद्रास्फीति उच्च स्तर से दूर जाए (चार्ट 1)।

इस विषय पर मौलिक कार्य (स्टॉक और वॉटसन, 2007 और कॉगली, और अन्य, 2010) के अनुरूप, हम मुद्रास्फीति को दो घटकों - प्रवृत्ति और चक्र में विघटित करते हैं। प्रवृत्ति घटक में परिवर्तन अत्यधिक लगातार होते हैं, जबकि चक्रीय घटक के आघात अस्थायी होते हैं। समीकरण (1) और (2) का अनुमान प्रसंभाव्य अस्थिरता (टीवीपी-एसवी) के साथ समय-भिन्न पैरामीटर प्रतिगमन के रूप में लगाया जाता है, जिसमें मुद्रास्फीति को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) की मौसमी रूप से समायोजित माह-दर-माह की वार्षिक दर से मापा जाता है।

मुद्रास्फीति: $\pi_t = \underbrace{\rho_t}_{\text{intrinsic}} * \pi_{t-1} + \underbrace{(1-\rho_t)}_{\text{expectation-based}} * \pi_t^T + \underbrace{\varepsilon_t^{\pi}}_{\text{error-term}}$ ...(1)

मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति: $\pi_t^T = \pi_{t-1}^T + \varepsilon_t^{\pi^T}$ ...(2)

$\varepsilon_t^{\pi} \sim N(0, \sigma_t^{\pi})$ और $\varepsilon_t^{\pi} \sim N(0, \sigma_t^{\pi^T})$, $(\sigma_t^{\pi})^2$ और $(\sigma_t^{\pi^T})^2$ के लॉग स्वतंत्र यादृच्छिक चर के रूप में विकसित होते हैं। नाकाजिमा (2011) के कोड का उपयोग करके बायेसियन मार्कोव चेन मोंटे कार्लो (एमसीएमसी) विधि का उपयोग करके समय के अलग-अलग मापदंडों का अनुमान लगाया जाता है।

हम देखते हैं कि "आंतरिक" तत्व, जो अपने स्वयं के अतीत या मूल्य-निर्धारण जड़ता के कारण मुद्रास्फीति की दृढ़ता का प्रतिनिधित्व करता है, 2011-13 के दौरान उच्च था। 2014 से इसमें गिरावट आई और 2016 से 2019 तक कम रही। 2020 की शुरुआत में कोविड-19 आघात के बाद, मुद्रास्फीति की स्थिरता अप्रैल 2022 में चरम पर पहुंचने तक बढ़ने लगी। हाल ही में, आंतरिक मुद्रास्फीति की स्थिरता में गिरावट देखी जा रही है (चार्ट 2)।

समीकरण (1) और (2) का उपयोग भारत में मुद्रास्फीति की अज्ञात प्रवृत्ति को फ़िल्टर करने के लिए भी किया जा सकता है। भारत में प्रवृत्ति मुद्रास्फीति 2011-13 के दौरान चरम स्थिति से नीचे आ गई और 2016-19 के दौरान लक्ष्य के आसपास तक सीमित रही। महामारी की शुरुआत के बाद, यानी 2020 की शुरुआत से इसमें वृद्धि होनी शुरू हुई, लेकिन यह पाया गया कि यह बहुत धीरे-धीरे लक्ष्य पर लौट रही है (चार्ट 3)।

प्रवृत्ति और चक्रीय घटकों में परिवर्तनशीलता को विघटित करना दोनों घटकों में, कोविड-19 के बाद की अवधि में एक

चार्ट 3: समय-समय पर बदलती मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति

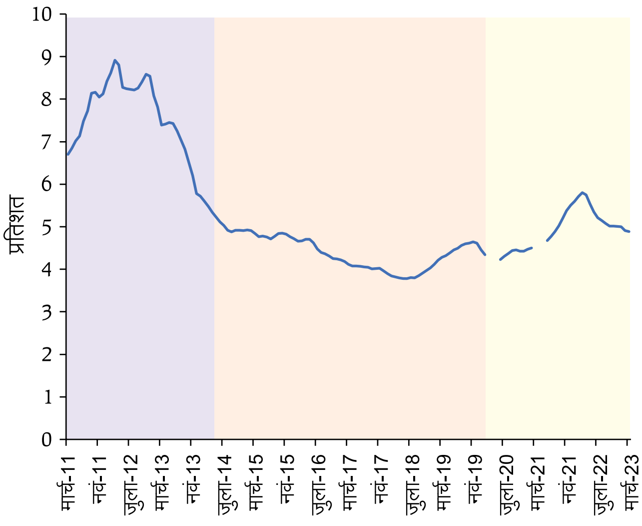

टिप्पणी: 2011-13 2014-19 2020-23
स्रोत: लेखकों के अनुमान.

उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। कुल मिलाकर, सभी व्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति परिवर्तनशीलता मुख्य रूप से इसके चक्रीय घटक द्वारा संचालित होती है, जो आपूर्ति आघात की भूमिका को दर्शाता है। मुद्रास्फीति के प्रवृत्ति घटक की परिवर्तनशीलता, 2011-13 के दौरान अपने उच्चतम स्तर से कम हो गई है और 2019 तक मामूली बनी हुई है, यह दर्शाता है कि मुद्रास्फीति की उम्मीदें स्थिर हो रही हैं। हालाँकि, कोविड-19 के झटके के बाद, आपूर्ति के

चार्ट 4 : समय-समय पर बदलती मुद्रास्फीति की अस्थिरता

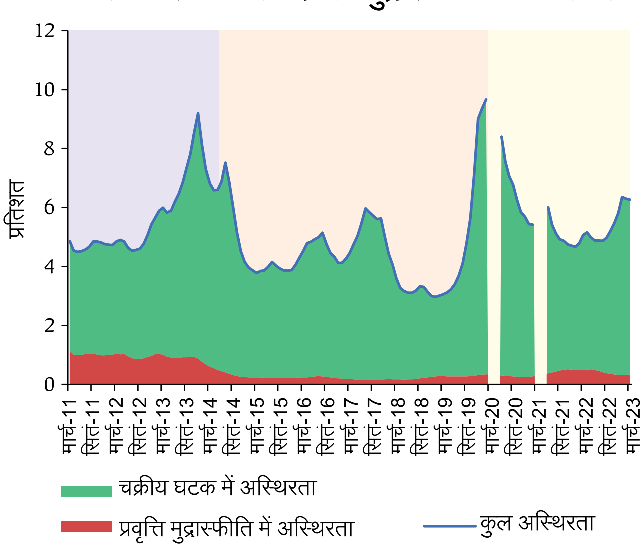

टिप्पणी: 2011-13 2014-19 2020-23
स्रोत: लेखकों के अनुमान.

कारण मुद्रास्फीति के चक्रीय घटक में अस्थिरता ने भी मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति की परिवर्तनशीलता में वृद्धि का संकेत दिया, जो मुद्रास्फीति प्रत्याशा में कमी का संकेत देता है (चार्ट 4)।

III. सापेक्ष मूल्य गतिशीलता और मुद्रास्फीति प्रभाव-प्रसार

क्या मुद्रास्फीति की प्रक्रिया सापेक्ष कीमतों से प्रेरित है या इसे सामान्यीकृत किया गया है? स्पिलओवर के बिना, वस्तु-विशिष्ट मूल्य वृद्धि सामान्यीकृत होने के बजाय समय के साथ समाप्त हो जाएगी। यहां तक कि जब कमोडिटी की कीमतें अस्थिरता प्रदर्शित करती हैं, तब भी एक-दूसरे से स्वतंत्र विशिष्ट परिवर्तन व्यापक-आधारित होने के बजाय सापेक्ष मूल्य परिवर्तनों में परिलक्षित होंगे।

हम उप समूह स्तर के माह-दर-माह वार्षिक मुद्रास्फीति (बोरियो, और अन्य, 2023) के वेक्टर ऑटो रिग्रेशन (वीएआर) से अनुमानित किसी दिए गए क्षितिज (जैसे 12 महीने) पर सामान्यीकृत पूर्वानुमान त्रुटि विचरण अपघटन (जीएफिवीडी) का उपयोग करके सीपीआई के विभिन्न घटक उप-समूहों में मूल्य परिवर्तनों के स्पिलओवर को मापते हैं। जीएफईवीडी मैट्रिक्स के ऑफ-डायगोनल तत्व प्रत्येक उप-समूह की मुद्रास्फीति में भिन्नता के शेयरों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे अन्य उप-समूहों में मुद्रास्फीति द्वारा समझाया गया है। कुल स्पिलओवर का माप जीएफवीडी मैट्रिक्स के ऑफ-डायगोनल तत्वों के भारित समुच्चय द्वारा बनाया जा सकता है। यह प्रत्येक उप-समूह से संबंधित मुद्रास्फीति में भिन्नता की मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे अपने स्वयं के झटके से नहीं समझाया जाता है, बल्कि इसके बजाय वीएआर (बोरियो, और अन्य 2023) की अंतराल संरचना के माध्यम से काम करने वाले अन्य उप-समूह मुद्रास्फीति से झटके के संचरण द्वारा समझाया जाता है। इसे ऊष्मा मानचित्र (चार्ट 5) में दर्शाया गया है। लाल रंग के गहरे रंग क्षैतिज अक्ष पर उप-समूहों से ऊर्ध्वाधर अक्ष पर उप-समूहों तक अधिक फैलाव का संकेत देते हैं। चार्ट 5 में मैट्रिक्स के विकर्ण तत्व स्वयं के झटके का प्रतिनिधित्व करते हैं और उप-समूहों में प्रभाव-प्रसार में योगदान नहीं करते हैं। दूसरे सब-सैंपल (2014-19) में जीएफईवीडी मैट्रिक्स के सभी ऑफ-डायगोनल तत्वों का भारित योग 45 प्रतिशत है, जो पहले उप-नमूना (2011-13, 60

चार्ट 5: सीपीआई उप-समूहों में मुद्रास्फीति का फैलाव*

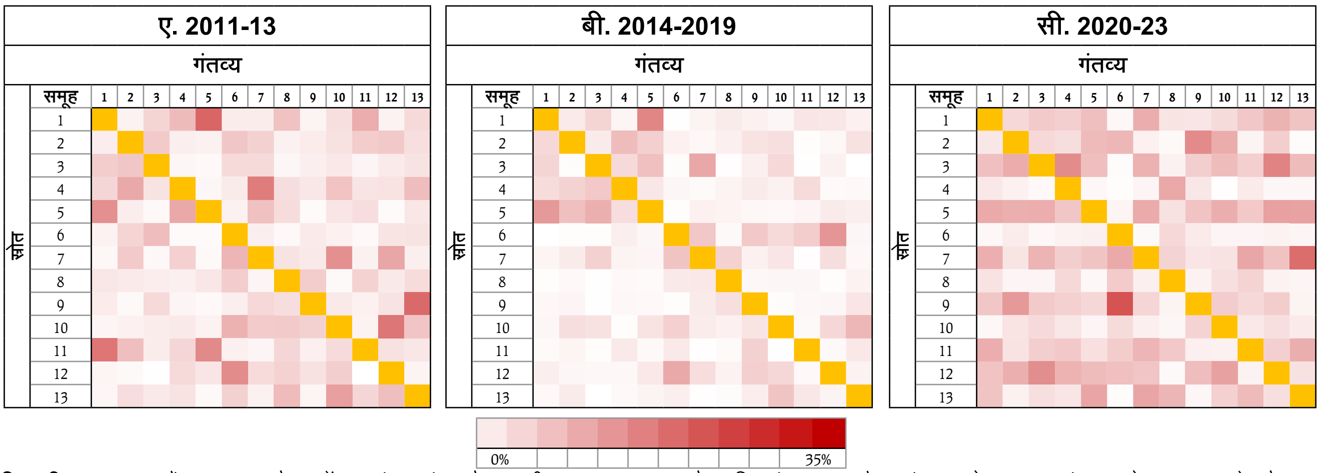

टिप्पणी : *उप समूह हैं 1) अनाज और दालें, 2) अंडा, मांस और मछली, 3) दूध, 4) फल और सब्जियां, 5) अन्य गैर-प्रसंस्कृत भोजन, 6) प्रसंस्कृत भोजन, 7) कपड़े और जूते, 8) आवास, 9) ईंधन और प्रकाश, 10) स्वास्थ्य, 11) परिवहन और संचार, 12) शिक्षा, 13) अन्य विविध।
लाल शेडिंग 12 महीने के कालावधि में उप-समूह मुद्रास्फीति के बदलाव का हिस्सा दर्शाती है, जिसे अन्य उप-समूहों में मुद्रास्फीति आघात के माध्यम से समझाया गया है।
स्रोत: लेखकों के अनुमान।

प्रतिशत) की तुलना में काफी कम है। 2020 के बाद, छाया के गहरा होने से प्रभाव-प्रसार में वृद्धि हुई है - इस अवधि के दौरान औसत भारित प्रभाव-प्रसार 74 प्रतिशत था।

मुद्रास्फीति प्रभाव-प्रसार को मापने का एक और तरीका 12 महीने की मुद्रास्फीति के क्रॉस-सेक्शनल भिन्नता को दो घटकों के कारण हिस्से में विघटित करना है: ए) उप-समूहों में मुद्रास्फीति का कुल भारित भिन्नता और बी) उनके बीच कुल सहप्रसरण, बाद वाला उप-समूहों में मुद्रास्फीति के फैलाव का एक संकेतक होना (बोरियो, और अन्य, 2023)।

यह अपघटन उप-समूहों के बीच मुद्रास्फीति में कम सहप्रसरण और इसलिए उनके सह-आंदोलन और एंकरिंग की कम डिग्री के कारण 2016-19 के दौरान मुद्रास्फीति में समग्र भिन्नता में गिरावट को दर्शाता है। मुद्रास्फीति में कुल भिन्नता, उप-समूहों में इसका भिन्नता और सहप्रसरण 2020 के बाद बढ़ गया है, जो मुद्रास्फीति के सामान्यीकरण की ओर इशारा करता है। खुशी की बात है कि सहप्रसरण में गिरावट के कारण अक्टूबर 2022 से मुद्रास्फीति में कुल भिन्नता में गिरावट देखी गई है, हालांकि, व्यक्तिगत उप-समूह उच्च मुद्रास्फीति अस्थिरता प्रदर्शित कर रहे हैं, जो विशिष्ट और एक-दूसरे से स्वतंत्र हैं (चार्ट 6)। हाल के महीनों में, इसलिए, मुद्रास्फीति का सामान्यीकरण कमजोर हो रहा है और यह स्थानीयकृत मूल्य गतिविधियां हैं जो मुद्रास्फीति को बढ़ा रही हैं।

चार्ट 6: मुद्रास्फीति का प्रसरण सहप्रसरण अपघटन (वर्ष-दर-वर्ष)

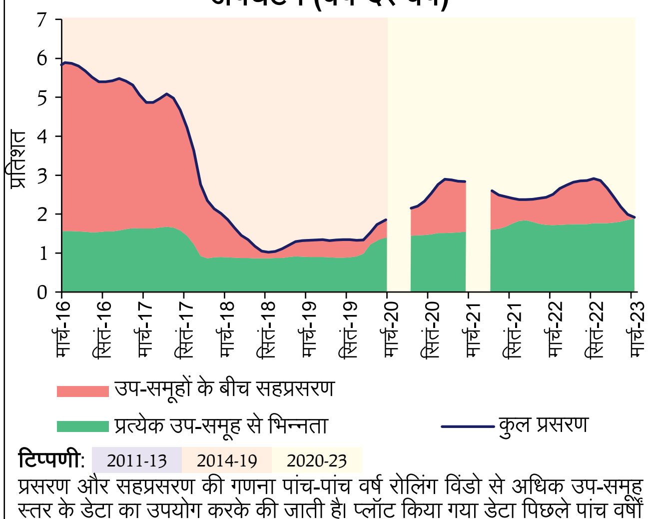

टिप्पणी: 2011-13 2014-19 2020-23
प्रसरण और सहप्रसरण की गणना पांच-पांच वर्ष रोलिंग विंडो से अधिक उप-समूह स्तर के डेटा का उपयोग करके की जाती है। प्लॉट किया गया डेटा पिछले पांच वर्षों के अनुरूप भिन्नताओं और सहप्रसरणों का प्रतिनिधित्व करता है।
स्रोत: लेखकों के अनुमान।

IV. हेडलाइन-मूल प्रसरण

अंतर्निहित या मूल मुद्रास्फीति दर हेडलाइन मुद्रास्फीति में क्षणिक उतार-चढ़ाव को फ़िल्टर करती है और मुद्रास्फीति का एक स्थिर अंतर्निहित माप प्रदान करती है जो क्षेत्रीय झटकों के प्रभाव से मुक्त होती है। चूँकि भोजन और ईंधन के अलावा सीपीआई उप-समूहों में मूल्य परिवर्तन से भी अस्थिरता उभर सकती है, मूल मुद्रास्फीति के "बहिस्थ-बहिष्करण" तरीके लोकप्रिय हो गए हैं (बॉल, और अन्य, 2023)। सबसे सरल प्रविधि भारित औसत मुद्रास्फीति है जिसमें सीपीआई मद-स्तरीय मुद्रास्फीति दरों के वितरण का 50 प्रतिशत प्रत्येक तरफ से कम कर दिया जाता है और मूल मुद्रास्फीति को मध्य में मुद्रास्फीति दर से मापा जाता है।

मूल मुद्रास्फीति के दो अलग-अलग प्रकार के भारित माध्य माप बनाए गए हैं। प्रत्येक माह के लिए पिछले 12 महीनों की औसत मुद्रास्फीति की गणना की जाती है। यह प्रत्येक सीपीआई आइटम की मुद्रास्फीति दर की गणना महीने t-12 से महीने t तक और भारित माध्यिका लेकर की जाती है। भारित औसत मुद्रास्फीति को एक रैंकिंग ऑपरेटर के तहत सभी सीपीआई वस्तुओं पर विचार करके समय t पर परिभाषित किया जा सकता है, जो आइटम-विशिष्ट मुद्रास्फीति दरों को सबसे छोटे से सबसे बड़े तक रैंक करता है और उनके संबंधित भार को संचयित करता है। भारित औसत मुद्रास्फीति दर को सीपीआई-आइटम के लिए समय t पर मुद्रास्फीति दर के रूप में चुना जाता है, जिस पर रैंक किए गए भार का योग 50वें प्रतिशत (बॉल और मजूमदार, 2019) से ऊपर होता है। भारित माध्यिका मुख्य मुद्रास्फीति का एक पक्षपाती अनुमानक बन सकता है कि समय के साथ इसका औसत हेडलाइन मुद्रास्फीति से कम है। एक पक्षपातपूर्ण समायोजित माप को आइटम-स्तरीय मुद्रास्फीति के उस प्रतिशत पर मुद्रास्फीति दर के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसके मूल्य और हेडलाइन मुद्रास्फीति (बॉल, और अन्य, 2023) के बीच सबसे छोटा औसत अंतर है। पूर्वाग्रह समायोजन नमूना अवधि पर निर्भर है। यहां, हमने जनवरी 2015 से मार्च 2023 की अवधि के लिए नमूने में पूर्वाग्रह को समायोजित किया है ताकि उस अवधि के दौरान हेडलाइन और मुख्य मुद्रास्फीति का औसत लगभग समान हो।

भारित औसत मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष) दृढ़ता दर्शाती है (चार्ट 7ए)। पूर्वाग्रह समायोजन मुख्य मुद्रास्फीति को और ऊपर बढ़ाता है (चार्ट 7बी)।

वर्ष-दर-वर्ष माप के विपरीत, 2022-23 की पहली तिमाही में यूक्रेन युद्ध से संबंधित मुद्रास्फीति वृद्धि के बाद से माह-दर-माह

चार्ट 7: भारित औसत मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष)

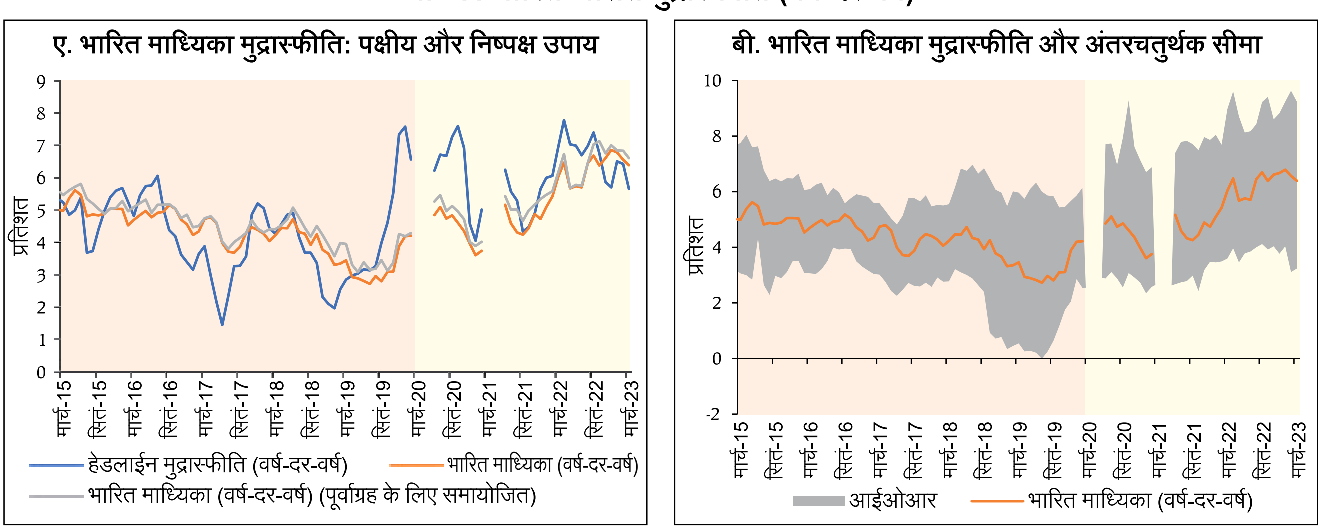

टिप्पणी: 2011-13 2014-19 2020-23
2014 से पहले आइटम-स्तरीय सीपीआई की अनुपलब्धता इस विश्लेषण को 2015 के बाद तक सीमित कर देती है। आईक्यूआर: इंटरक्वेर्टाइल रेंज।
स्रोत: लेखकों के अनुमान.

चार्ट 8 : भारित औसत मुद्रास्फीति (माह-दर-माह)

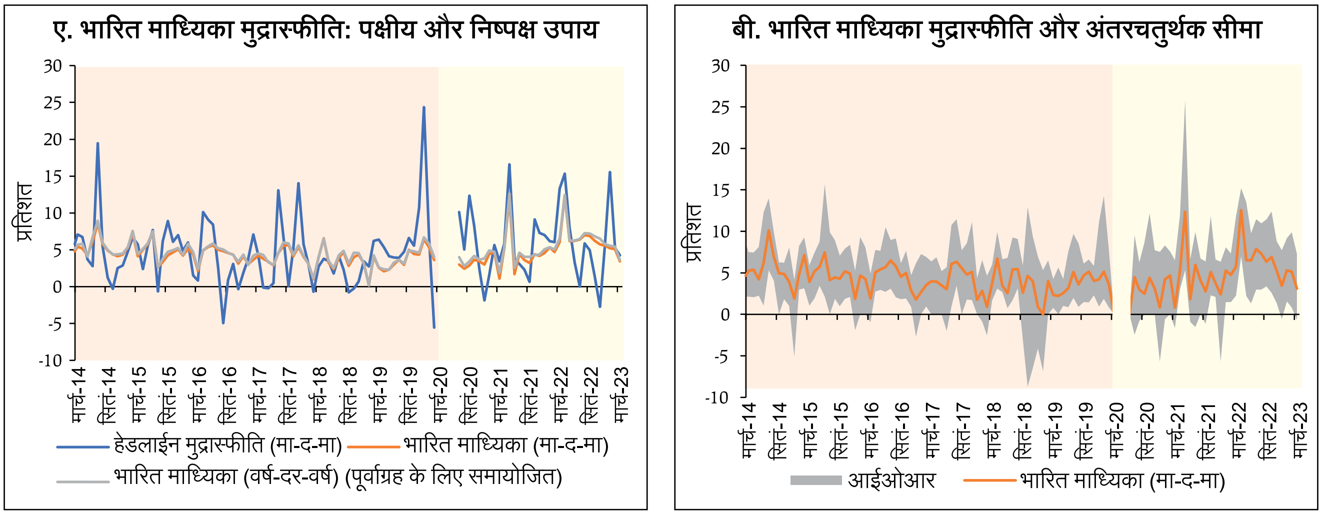

टिप्पणी: 2011-13 2014-19 2020-23

2014 से पहले आइटम-स्तरीय सीपीआई की अनुपलब्धता इस विश्लेषण को 2014 के बाद तक सीमित कर देती है। आईक्यूआर : इंटरक्वेर्टाइल रेंज।

स्रोत: लेखकों के अनुमान.

भारित माध्यिका में गिरावट देखी गई है, जो दर्शाता है कि किसी भी प्रतिकूल झटके के अभाव में आगे चलकर वर्ष-दर-वर्ष भारित माध्यिका मुद्रास्फीति में और गिरावट आ सकती है (चार्ट 8ए, बी)।

यह जांचने का एक तरीका है कि क्या आइटम-स्तरीय मूल्य परिवर्तनों का अंतर्निहित मुद्रास्फीति के लिए महत्वपूर्ण परिणाम होने की संभावना है, यह जांच करना है कि क्या हेडलाइन मुद्रास्फीति मूल में परिवर्तित होती है या इसके विपरीत। जब हेडलाइन मूल (मुद्रास्फीति) में परिवर्तित हो जाती है तो अस्थिर मूल्य परिवर्तन समाप्त हो जाते हैं, इसके विपरीत, जब मूल (मुद्रास्फीति) हेडलाइन में परिवर्तित हो जाती है, तो वे मूल्य परिवर्तन संभावित रूप से शक्तिशाली दूसरे दौर के प्रभावों का संकेत देते हैं (सेकेट्टी और मोसेनर, 2008; बोरियो, और अन्य, 2023)।

इस प्रस्ताव की जांच करने के लिए, हम निम्नलिखित दो प्रतिगमन समीकरणों का अनुमान लगाते हैं जो समय के साथ मापदंडों को बदलने की अनुमति देते हैं:

$$\Delta^{12}P^{H}_{t+12} - \Delta^{12}P^{H}_{t} = \alpha^{0}_{t} + \alpha^{1}_{t}(\Delta^{12}P^{H}_{t} - \Delta^{12}P^{C}_{t}) + \varepsilon^{H}_{t+12} \quad ...(3)$$

$$\Delta^{12}P^{C}_{t+12} - \Delta^{12}P^{C}_{t} = \beta^{0}_{t} + \beta^{1}_{t}(\Delta^{12}P^{C}_{t} - \Delta^{12}P^{H}_{t}) + \varepsilon^{C}_{t+12} \quad ...(4)$$

जहाँ $\Delta^{12}P^{H}_{t+12}$ और $\Delta^{12}P^{C}_{t+12}$ 12 माह का हेडलाइन और मूल मुद्रास्फीति (भारित माध्यिका का उपयोग कर मापी जाती है) दर्शाते हैं - जो क्रमशः माह t -12 और t के बीच है। α^{1}_{t} और β^{1}_{t} उस डिग्री को मापता है जिसमें हेडलाइन मुद्रास्फीति से मूल मुद्रास्फीति की ओर और उसके विपरीत विचलन क्रमशः 12 महीनों की अवधि में प्रसारित होता है।

अलग-अलग समय के अनुमान से पता चलता है कि ऋणात्मक और महत्वपूर्ण है, जबकि पूरे नमूना अवधि (अप्रैल 2016 से मार्च 2023) के दौरान नगण्य है (चार्ट 9)। इन निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि हेडलाइन मुद्रास्फीति मूल में परिवर्तित होती है, अन्यथा नहीं। इसके अलावा, गौण हिस्से से उत्पन्न होने वाले क्षणिक आघातों से 12 महीने की अवधि से अधिक मूल मुद्रास्फीति के प्रभावित नहीं होने की उम्मीद है।

चार्ट 9 : परिवर्तनशील समय प्रसरण गुणांक

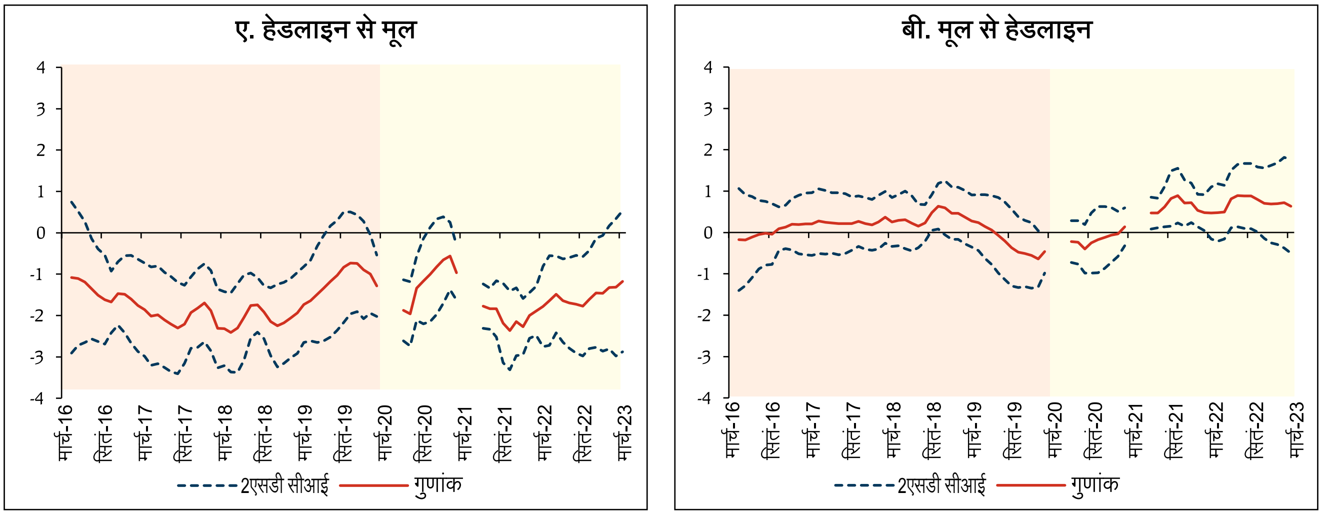

टिप्पणी: 2011-13 2014-19 2020-23
2014 से पहले आइटम-स्तरीय सीपीआई की अनुपलब्धता इस विश्लेषण को 2015 के बाद तक सीमित कर देती है। 2एसडी सीआई: दो मानक विचलन विश्वसनीय अंतराल।
स्रोत: लेखकों का अनुमान.

उप-समूह स्तर की मुद्रास्फीति और आउटपुट अंतर (पात्र, और अन्य, 2021) द्वारा अनुमानित कुल मांग के माप के बीच सहसंबंधों के आधार पर ऐतिहासिक रूप से निर्धारित भार का उपयोग कर, चक्रीय रूप से संवेदनशील मुद्रास्फीति का अनुमान लगाया जा सकता है (स्टॉक और वाटसन, 2020; पात्र और अन्य 2022)। इस बारे में विभिन्न स्पष्टीकरण हो सकते हैं कि आर्थिक गतिविधि के प्रति मुद्रास्फीति की संवेदनशीलता एक उप-समूह से दूसरे उप-समूह में भिन्न क्यों हो सकती है। सबसे पहले, किसी वस्तु या सेवा की कीमत की चक्रीय संवेदनशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि यह अंतरराष्ट्रीय या घरेलू बाजार स्थितियों द्वारा निर्धारित है या नहीं। उदाहरण के लिए, लगभग 85 प्रतिशत जीवाश्म ईंधन की मांग आयात के माध्यम से पूरी होने के कारण, भारत आमतौर पर वैश्विक बाजारों में निर्धारित कीमतों को स्वीकार करता है। इसलिए घरेलू मांग और परिवहन लागत के बीच संबंध कच्चे तेल की आयात कीमतों से प्रभावित होगा। दूसरी ओर, घरेलू सामान और सेवाओं, शिक्षा और आवास जैसी सीपीआई श्रेणियों की कीमतें स्थानीय बाजार स्थितियों पर आधारित होती हैं और घरेलू चक्रीय उतार-चढ़ाव के अधीन होती हैं। सामान्य तौर पर, मूल्य-निर्धारण व्यवहार बाजार संरचना, वेतन-निर्धारण प्रक्रिया और अन्य संरचनात्मक कारकों के आधार पर उप-समूहों में भिन्न होता है। दूसरा, माप के मुद्दे भी मुद्रास्फीति के प्रति संवेदनशीलता में अंतर में योगदान करते हैं। तदनुसार, भारत के लिए चक्रीय रूप से संवेदनशील मुद्रास्फीति (सीआईएसआई) की गणना यह पहचानने के लिए की जाती है कि सीपीआई के कौन से हिस्से आर्थिक चक्र (मांग) से प्रभावित होते हैं। प्रत्येक भाग से जुड़ा भार, उप-समूह स्तर से संबंधित अनुमानित समय-समय पर अलग-अलग फिलिप्स वक्रों से निकाला जाता है (पात्र, और अन्य, 2022)।

नतीजे बताते हैं कि चक्रीय रूप से संवेदनशील मुद्रास्फीति (सीआईएसआई) ने 2014 से पहले की उच्च मुद्रास्फीति व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 2014 में भारत में एफआईटी को वास्तविक रूप से अपनाने के बाद से, सीआईएसआई के योगदान में गिरावट आई है। महामारी की अवधि के दौरान (2020 की पहली तिमाही से), सीआईएसआई चक्रीय मुद्रास्फीति की तुलना में लगातार कम रही, जो मांग में गिरावट का संकेत देती है (पात्र और अन्य, 2022)। इस प्रकार, यह आपूर्ति बाधाओं और लॉकडाउन से प्रेरित अचक्रीय कारक थे जिन्होंने इसके बजाय हेडलाइन मुद्रास्फीति को बढ़ाया। 2022-23 की दूसरी छमाही से सीआईएसआई का योगदान बढ़ रहा है (चार्ट 10) और चक्रीय मुद्रास्फीति और सीआईएसआई के बीच का अंतर ऋणात्मक हो गया है, जो मौद्रिक नीति कार्रवाई की औचित्य का संकेत है (पात्र और अन्य, 2022)।

चार्ट 10: चक्रीय रूप से संवेदनशील मुद्रास्फीति

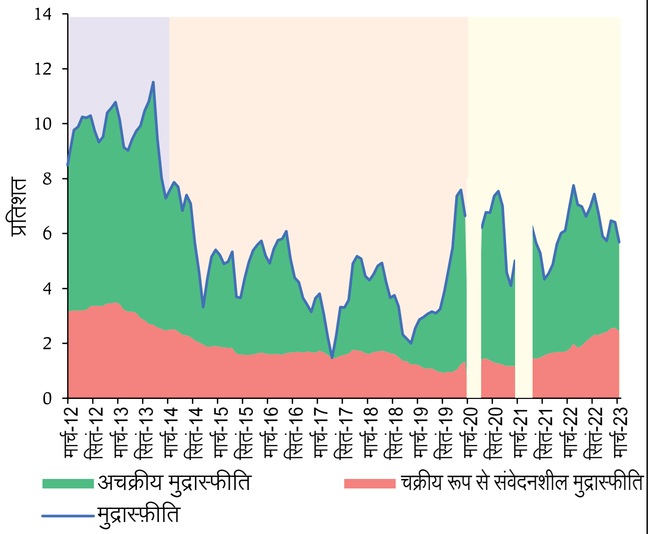

टिप्पणी: 2011-13 2014-19 2020-23
स्रोत: लेखकों के अनुमान.

2020-21 की दूसरी छमाही से 2022-23 की पहली छमाही तक मुद्रास्फीति को उच्च स्तर पर पहुंचाने में वैश्विक कारकों ने बड़ी भूमिका निभाई; इसके विपरीत, 2014 से पहले की उच्च मुद्रास्फीति दौर में घरेलू कारक प्रमुख थे। 2022-23 की दूसरी छमाही से, आयातित मुद्रास्फीति का योगदान धीरे-धीरे कम हो रहा था और घरेलू कारक बड़ी भूमिका निभा रहे थे, जो चक्रीय रूप से बढ़ती संवेदनशील मुद्रास्फीति की भूमिका को दर्शाता है।[1]

VI. निष्कर्ष

पिछले एक दशक में, भारत में मुद्रास्फीति उच्च पूर्व-एफआईटी व्यवस्था से निम्न एफआईटी व्यवस्था में बदल गई है और अभूतपूर्व और अतिव्यापी झटकों के कारण वापस आ गई है। 2022-23 की दूसरी छमाही के बाद से, निम्न मुद्रास्फीतिक काल में संक्रमण के संकेत मिल रहे हैं। हमारे निष्कर्षों को दो भागों में संक्षेपित किया जा सकता है।

सबसे पहले, यह 2020-22 के दौरान आपूर्ति के आघातों का सिलसिला था जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को उच्च मुद्रास्फीति दौर में स्थानांतरित कर दिया। आघात के बाद भी चक्रीय रूप से संवेदनशील मुद्रास्फीति का हमारा माप अचक्रीय मुद्रास्फीति की तुलना में लगातार कम रहा, जो नए दौर में संक्रमण के दौरान मांग की कमी का संकेत देता है। संक्रमण काल में, मुद्रास्फीति ने दृढ़ता प्रदर्शित की और इसकी प्रवृत्ति में वृद्धि हुई। इसके साथ ही, प्रवृत्ति और चक्रीय दोनों घटकों की अस्थिरता बढ़ गई। कुल मिलाकर, ये नतीजे 2016-19 के दौरान हुई मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं के टूटने की ओर इशारा करते हैं। दूरदर्शिता की स्पष्ट दृष्टि से पता चलेगा कि विश्वसनीयता बहाल करने और अपेक्षाओं को फिर से मजबूत करने के लिए मौद्रिक नीति कार्रवाई की आवश्यकता थी, जो मार्च 2022 और मार्च 2023 के बीच भारत में मौद्रिक नीति के परिचालन लक्ष्य, भारित औसत कॉल मनी दर में 3.2 प्रतिशत अंक की प्रभावी वृद्धि को उचित ठहराती है। पहले उद्धृत वैश्विक मुद्रास्फीति के द्वि-आवधिक दृष्टिकोण पर प्रभावशाली कार्य उच्च मुद्रास्फीति शासन में संक्रमण का जोखिम बढ़ने पर मौद्रिक नीति के अग्रसक्रिय होने के महत्व पर प्रकाश डालता है, हालांकि यह इस जोखिम का आकलन करने की चुनौती को स्वीकार करता है। वास्तविक समय (बोरियो, और अन्य, 2023)। प्रतिक्रिया में देरी करने से संवृद्धि के नुकसान की संभावना के कारण अनिवार्य रूप से अधिक सशक्त कार्रवाई की आवश्यकता होगी।

2020-22 के आपूर्ति झटकों ने हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति के कुल अंतर के साथ-साथ इसके उप-समूहों में मुद्रास्फीति के बीच सहप्रसरण को बढ़ा दिया। यह इस बात का प्रमाण है कि उच्च मुद्रास्फीति शासन में, मूल्य दबावों का एक सामान्यीकरण हुआ है - वे कई उप-समूहों में प्रसारित हो गए हैं, जो सामान्य रूप से देखी जाने वाली उच्च मुद्रास्फीति के अधिक सह-बदलाव का अनुभव कर रहे हैं। यह मुद्रास्फीति के दबावों को कम करने और उनके व्यापक आधार को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति कार्रवाई की एक स्पष्ट मांग है। पुन:, 2022-23 तक रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति कार्रवाइयां और रुख औचित्यपूर्ण हैं।

दूसरा, हमारे निष्कर्ष आगे के लिए क्या सुझाव देते हैं? व्यवस्था परिवर्तन की कवायद के संदर्भ में, 2022-23 की दूसरी

[1] आयातित मुद्रास्फीति के योगदान की गणना, जनवरी 2012 से मार्च 2023 की अवधि के लिए समय भिन्न पैरामीटर (टीवीपी) प्रतिगमन का उपयोग कर, उप-समूह स्तर पर अनुमानित पास-थ्रू गुणांक के आधार पर सीपीआई भार को फिर से समायोजित करके की गई थी।

छमाही से इस बात की संभावना बढ़ रही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था उच्च मुद्रास्फीति दौर से दूर जा रही है। प्रतिकूल विशिष्ट आघातों के अभाव में, निराशाजनक अवस्फीति के शुरुआती संकेतों के केंद्रीय प्रवृत्ति में मजबूत होने के लिए स्थितियाँ सही हैं। इसके अलावा, मुद्रास्फीति की दृढ़ता और प्रवृत्ति में गिरावट आ रही है, भले ही धीरे-धीरे। यह दर्शाता है कि मुद्रास्फीति प्रत्याशाएँ धीरे-धीरे फिर से मजबूत हो रही हैं क्योंकि नीतिगत कार्रवाइयां और रुख गति पकड़ रहे हैं और मांग पर नियंत्रण का प्रभाव दिखना शुरू हो गया है। मौद्रिक नीति के लिए, अनुशंसा होगी: प्रतीक्षा करें और देखें, साथ ही मुद्रास्फीति को कम मुद्रास्फीति दौर की आसन्न शुरुआत की ओर निर्देशित करें। 2022-23 की दूसरी छमाही के बाद से, व्यक्तिगत उप-समूह उच्च अस्थिरता प्रदर्शित कर रहे हैं - छिटपुट आपूर्ति झटके काम कर रहे हैं - लेकिन, महत्वपूर्ण बात यह है कि सहप्रसरण में गिरावट आ रही है। इससे पता चलता है कि मुद्रास्फीति के दबावों का सामान्यीकरण या व्यापक आधार कम हो रहा है और तेज स्थानीय मूल्य बदलाव हेडलाइन मुद्रास्फीति को प्रभावित कर रहे हैं। इसके लिए विशिष्ट वस्तुओं और सेवाओं की मांग और आपूर्ति को संरेखित करने के लिए सुधारात्मक उपायों की आवश्यकता है, जो मौद्रिक नीति के दायरे से बाहर हैं, लेकिन संभावित मूल्य दबावों को गहरा होने से रोकने के लिए निरंतर आधार पर किए जा रहे हैं।

अतिरिक्त साक्ष्य कि भारत में मुद्रास्फीति का दबाव कम हो रहा है, मूल मुद्रास्फीति की माह-दर-माह गति में गिरावट में पाया गया है, जो इस कथन कि हेडलाइन मुद्रास्फीति अंततः मूल मुद्रास्फीति में परिवर्तित हो जाएगी के बनिस्पत कम मुद्रास्फीति दौर का तार्किक समर्थन करता है। हमारे निष्कर्षों में एक असंगत टिप्पणी यह है कि हमारी चक्रीय रूप से संवेदनशील मुद्रास्फीति मापक बढ़ रहा है। इससे पता चलता है कि मांग में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इसलिए, मौद्रिक नीति सतर्कता में कोई कमी नहीं आने दी जा सकती है। चालू अवस्फीति बाधित न हो यह सुनिश्चित करने हेतु अग्रसक्रिय तत्परता, हमारी नीतिगत अनुशंसा है।

संदर्भ :

Ball, L. M., & Mazumder, S. (2019). The nonpuzzling behavior of median inflation (No. w25512). National Bureau of Economic Research.

Ball, L. M., Carvalho, C., Evans, C., & Ricci, L. A. (2023). Weighted median inflation around the world: A measure of core inflation. *IMF Working Papers*, *2023* (044).

Borio, C., Lombardi, M., Yetman, J., & Zakrajšek, E. (2023). The two-regime view of inflation. *BIS Papers.*

Cecchetti, S. G., & Moessner, R. (2008). Commodity prices and inflation dynamics. *BIS Quarterly Review*, 55-66.

Cogley, T., Primiceri, G. E., & Sargent, T. J. (2010). Inflation-gap persistence in the US. *American Economic Journal: Macroeconomics*, *2*(1), 43-69.

Hamilton, J. D. (1989). A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle. *Econometrica: Journal of the econometric society*, 357-384.

Nakajima, J. (2011). Time-varying parameter VAR model with stochastic volatility: An overview of methodology and empirical applications.

Patra, M. D., Behera, H., & John, J. (2021). Is the Phillips Curve in India dead, inert and stirring to life or alive and well? RBI Bulletin November.

Patra, M. D., George, A. T., Nadhanael, G. V., & John, J. (2022). Anatomy of inflation's ascent in India. RBI Bulletin December.

Stock, J. H., & Watson, M. W. (2007). Why has US inflation become harder to forecast?. *Journal of Money, Credit and banking*, *39*, 3-33.

Stock, J. H., & Watson, M. W. (2020). Slack and cyclically sensitive inflation. *Journal of Money, Credit and Banking*, *52*(S2), 393-428.

*भारतीय राज्यों का पूंजी परिव्यय: इसकी भूमिका और निर्धारकों का एक तथ्यात्मक मूल्यांकन**

डॉ. देब प्रसाद रथ, विचित्रानंद सेठ, समीर रंजन बेहरा और अनूप के. सुरेश, द्वारा

यह अध्ययन राज्यों के पूंजीगत परिव्यय और सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के बीच संबंधों की पड़ताल करता है, साथ ही उन कारकों की पहचान भी करता है जो राज्यों के पूंजीगत परिव्यय निर्णयों को प्रभावित करते हैं। 15 भारतीय राज्यों के लिए पैनल ढांचे के एप्लिकेशन से पूंजीगत परिव्यय और जीएसडीपी के बीच धनात्मक और महत्वपूर्ण संबंध का पता चलता है। पिछला पूंजीगत परिव्यय वर्तमान पूंजीगत परिव्यय निर्णयों का पूर्वसूचक बन जाता है और उच्च ऋण स्तर सार्वजनिक निवेश में बाधा बनता है। राज्य, ऋणात्मक और धनात्मक आउटपुट अंतर वातावरण, दोनों के तहत पूंजीगत परिव्यय के संदर्भ में एक प्रति-चक्रीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। राज्य, राजकोषीय जिम्मेदारी का पालन करने के अलावा, उच्च ऋण स्तर के बारे में सतर्क रहते हुए पूंजीगत परिव्यय को प्राथमिकता दे सकते हैं।

भूमिका

जैसे-जैसे दुनिया कोविड-19 महामारी से उबर रही है, इस बात पर आम सहमति बढ़ रही है कि सरकारों के पूंजीगत व्यय आर्थिक सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं (बेरावी और अन्य, 2020, गैस्पर और अन्य, 2020; ओईसीडी, 2021)। अवसंरचना परियोजनाओं, नवीकरणीय ऊर्जा और प्रौद्योगिकी में निवेश करने से नौकरियां पैदा हो सकती हैं, साथ ही संवृद्धि और स्थिरता को बढ़ावा मिल सकता है।

पूंजीगत व्यय एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसका उपयोग सरकारें उच्च और स्थिर आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देने के लिए करती हैं, विशेष रूप से उन अर्थव्यवस्थाओं में जो बुनियादी ढांचे की बाधाओं का सामना करती हैं (इस्माइल और महीदीन, 2015; वावेरू और मोसे, 2021)। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है और उच्च और सतत संवृद्धि को बनाए रखने के लिए बुनियादी ढांचे में अधिक निवेश की आवश्यकता होगी। एक हालिया अनुमान के अनुसार अगर भारत को अपनी तेजी से बढ़ती शहरी आबादी की जरूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा करना है तो अगले 15 वर्षों में शहरी बुनियादी ढांचे में 840 बिलियन अमेरिकी डॉलर की निवेश की आवश्यकता होगी (विश्व बैंक, 2022)। इसे स्वीकार करते हुए, भारत में केंद्र और राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय पर निरंतर जोर दिया गया है, खासकर महामारी की शुरुआत के बाद से। उदाहरण के लिए, केंद्र द्वारा पूंजीगत व्यय को 2022-23 (आरई) में सकल घरेलू उत्पाद के 2.7 प्रतिशत से बढ़ाकर 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत करने का बजट रखा गया है। हालाँकि, भारत जैसे संघीय ढांचे में, केंद्र सरकार के साथ-साथ उप-राष्ट्रीय सरकारों के पूंजीगत व्यय निर्णय, आर्थिक संवृद्धि को चलाने के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सामाजिक बुनियादी ढाँचा में निवेश के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा, उप-राष्ट्रीय सरकारों द्वारा किया जाने वाला पूंजीगत व्यय सामान्य सरकार द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय का लगभग दो-तिहाई होता है, जबकि उनका स्वयं का राजस्व केवल एक-तिहाई होता है। हाल ही में, राज्य सरकारों ने पूंजीगत व्यय के प्रति अपने आबंटन में वृद्धि की है, 2021-22 में पूंजीगत परिव्यय बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 2.7 प्रतिशत हो गया है (2000 के दशक में औसतन 2.0 प्रतिशत से) और इसे 2022-23 में 2.9 प्रतिशत के सार्वकालिक उच्च स्तर तक बढ़ाया गया है। इस संदर्भ में, यह आलेख राज्यों के पूंजीगत परिव्यय के चालकों का आकलन प्रदान करता है, क्योंकि इस मुद्दे पर साक्ष्यपरक साहित्य की कमी है।

स्थापित तथ्यों का एक सेट प्रदान करने के अलावा, यह अध्ययन, सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) पर पूंजीगत परिव्यय के प्रभाव का आकलन करने के लिए विभिन्न आंकड़े [1] विश्लेषणात्मक तरीकों का उपयोग करता है, जैसे- पैनल सह-एकीकरण, पूर्णतः संशोधित साधारण न्यूनतम वर्ग (एफएमओएलएस) और गतिशील साधारण न्यूनतम वर्ग (डीओएलएस)। इसके बाद, यह अध्ययन, पूंजीगत व्यय पर

* लेखकगण आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग से हैं। लेखकगण, बहुमूल्य इनपुट और सुझावों के लिए, डॉ. जी.वी. नथनएल के आभारी हैं। इस आलेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और जरूरी नहीं कि वे भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हों।

[1] राज्यों के पूंजी परिव्यय और उनके जीएसडीपी के बीच संबंधों की जांच के लिए, हमने 2000-01 से 2019-20 तक 20 वर्षों तक व्याप्त 15 प्रमुख भारतीय राज्यों के एक पैनल आंकड़ा-समूह का उपयोग किया है। अध्ययन जानबूझकर 2022-23 तक विस्तारित नहीं किया गया है, क्योंकि यह असामान्य कारकों से प्रभावित हो सकता है जो परिणामों को विकृत कर सकता है। दूसरी ओर, राज्यों के पूंजी परिव्यय को निर्धारित करने वाले कारकों की जांच के लिए, हमने विश्लेषण की अवधि 2011-12 से 2019-20 तक सीमित कर दी है।

राज्यों के निर्णयों को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान करने हेतु जेनरलाइज्ड मेथड ऑफ मोमेंट्स की द्वि-आयामी प्रणाली (जीएमएम) को नियोजित करता है, जिसमें जीएसडीपी अनुपात के लिए पूंजीगत परिव्यय को आश्रित चर के रूप में उपयोग किया गया किया गया है और चुनावी वर्षों एवं प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को स्वतंत्र चर के रूप में पकड़ने के लिए एक वर्ष के विलंबित ऋण-जीएसडीपी अनुपात, आउटपुट अंतर और डमी चर जैसे कारकों का उपयोग किया गया है। इसके बाद, यह अध्ययन, पूंजीगत व्यय पर राज्यों के निर्णयों को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान करने हेतु जेनरलाइज्ड मेथड ऑफ मोमेंट्स की द्वि-आयामी प्रणाली (जीएमएम) को नियोजित करता है, जिसमें जीएसडीपी अनुपात के लिए पूंजीगत परिव्यय को आश्रित चर के रूप में उपयोग किया गया किया गया है और चुनावी वर्षों एवं प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को स्वतंत्र चर के रूप में कैप्चर करने के लिए एक वर्ष के विलंबित ऋण-जीएसडीपी अनुपात, आउटपुट अंतर और डमी चर जैसे कारकों का उपयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त, यह अध्ययन, ऋण स्तर और आउटपुट अंतर के प्रति राज्यों की असममित कार्रवाईयों की पड़ताल करता है।

शेष आलेख पाँच खंडों में विभाजित है। खंड II इस क्षेत्र में पिछले शोध अध्ययनों का एक साहित्यिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है। खंड III में स्थापित तथ्यों का उल्लेख है जो शोध प्रश्न में आवश्यक अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। खंड IV अध्ययन में नियोजित आंकड़े और कार्यप्रणाली पर चर्चा करता है जबकि तार्किक परिणाम खंड V में प्रस्तुत किए गए हैं। अंत में, खंड VI हमारे विश्लेषण के निष्कर्षों के आधार पर नीतिगत निहितार्थ और अनुशंसाओं को रेखांकित करता है।

II. साहित्य की समीक्षा

सरकार के पूंजीगत व्यय और आर्थिक संवृद्धि के बीच संबंध ने बहस की एक शृंखला को जन्म दिया है (वावेरू और मोसे, 2021)। सरकार द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय में नए कार्यबल को अवशोषित करने, निजी निवेश में तेजी लाने और अर्थव्यवस्था को गरीबी के दुष्चक्र से मुक्त करने की क्षमता है (लीसीवाल, 2021; टेकले, 2016; विक्टोरिया, 2015)। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मानव पूंजी पर सरकारों का पूंजीगत व्यय आर्थिक संवृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव डालता है (कुलिसन, 1993; पौडेल, 2023)। इसके विपरीत, यह भी तर्क दिया जाता है कि आर्थिक संवृद्धि पर पूंजीगत व्यय का प्रभाव, ह्रासमान प्रभाव (क्राउडिंग आउट) प्रभाव के कारण नकारात्मक होता है (कोरमन और ब्रैटिमासरीन, 2007; ग्रेगोरीउ और घोष, 2009)।

सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय के निर्धारकों के मामले में, बजट की कमी और ऋण के स्तर को, पूंजीगत व्यय संबंधी सरकार के निर्णयों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक माने गए हैं (टौबेउ और वाम्पा, 2021; इडेनयी और अन्य, 2016; लोरा और ओलिवेरा, 2007)। इसी तरह, चुनाव और प्राकृतिक आपदाएँ पूंजीगत व्यय के लिए उनके उपलब्ध बजट को प्रभावित कर सकती हैं (रासमुसेन, 2004; रिज़कियाती और सेतियावान, 2022)।

भारत में, पूंजीगत व्यय का गुणक प्रभाव इसके राजस्व समकक्ष की तुलना में 7.6 पर बहुत अधिक पाया जाता है (जैन और कुमार, 2013)। इसके अलावा, राजस्व व्यय गुणक के विपरीत, जिसका अल्पकालिक प्रभाव होता है, पूंजीगत व्यय गुणक गतिशील होता है, जिसका प्रभाव कई वर्षों तक रहता है। दिलचस्प बात यह है कि पूंजीगत व्यय आर्थिक सुस्ती की अवधि के दौरान विशेष रूप से प्रभावी पाया जाता है (आरबीआई, 2022)।

कुल मिलाकर, ऐसे कई अध्ययन हैं जो सरकार के पूंजी निवेश और आर्थिक संवृद्धि के बीच संबंध की पड़ताल करते हैं; हालाँकि, ऐसे उप-राष्ट्रीय स्तरीय अध्ययनों की कमी प्रतीत होती है। इसलिए, यह पेपर पूंजीगत परिव्यय और भारतीय राज्यों के जीएसडीपी के बीच संबंधों पर मौजूदा साहित्य में योगदान करने का प्रयास करता है और नीति के लिए निहितार्थों की प्राप्ति में सहायता करेगा। ये निष्कर्ष, भारतीय राज्यों को बेहतर निर्णय लेने और इस मध्यम से दीर्घकालिक आर्थिक संवृद्धि की संभावनाओं में सुधार लाने में सहायक होंगे।

III. स्थापित तथ्य

परंपरा के अनुसार, राज्य सरकारों द्वारा किए गए व्यय को दो अलग-अलग समूहों में वर्गीकृत किया जाता है: राजस्व और पूंजी। पहले में वेतन, मजदूरी, पेंशन और आपूर्ति जैसे परिचालन खर्च शामिल होते हैं जबकि दूसरे में बुनियादी ढांचे और अन्य दीर्घकालिक आस्तियों में निवेश शामिल होता है। पूंजीगत व्यय को पूंजीगत परिव्यय के साथ-साथ ऋण और अग्रिम, जो राज्यों द्वारा विभिन्न संस्थाओं को प्रदान किया जाता है, में भी विभाजित किया जाता है। हम शैलीगत तथ्यों का एक सेट प्रस्तुत करते हैं जो भारत में प्रमुख 15 राज्यों के पूंजीगत परिव्यय की प्रकृति को दर्शाते हैं।

पहला, 2000 के शुरुआती वर्षों के विपरीत, राज्यों की उधारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पूंजीगत परिव्यय के लिए लिया गया है, जहां उनका उपयोग राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए किया गया था जैसा कि राजस्व घाटे और सकल राजकोषीय घाटे (आरडी-जीएफडी) के अनुपात के रुझान से स्पष्ट है (चार्ट 1)। इसी तरह का पैटर्न राजस्व व्यय-पूंजीगत परिव्यय (आरईसीओ) अनुपात के लिए भी दिखाई देता है - व्यय की गुणवत्ता का एक और संकेतक। हालाँकि यह अनुपात 2017-18 से बढ़ा है, लेकिन यह 2000 के दशक की पहली छमाही के दौरान अपनी प्रवृत्ति से अपेक्षाकृत कम है। पूंजीगत परिव्यय के लिए राज्यों द्वारा उधार का उपयोग काफी हद तक इस सिद्धांत का पालन करता है कि राजस्व घाटे को राजस्व संग्रह के माध्यम से वित्त पोषित किया जाना चाहिए, और उधार को उत्पादक संपत्ति बनाने पर खर्च किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में संपत्ति से निकलने वाली प्राप्तियों का उपयोग ऋण चुकाने के लिए किया जा सके।

दूसरा, वित्त वर्ष 2014-15 से राज्यों का कुल खर्च बढ़ रहा है. व्यय में इस बढ़ती प्रवृत्ति को उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) योजना, कृषि ऋण माफी और अन्य विकास-संबंधी खर्चों जैसे कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

चार्ट 1 : मुद्रास्फीति: आरडी-जीएफडी और आरईसीओ अनुपात

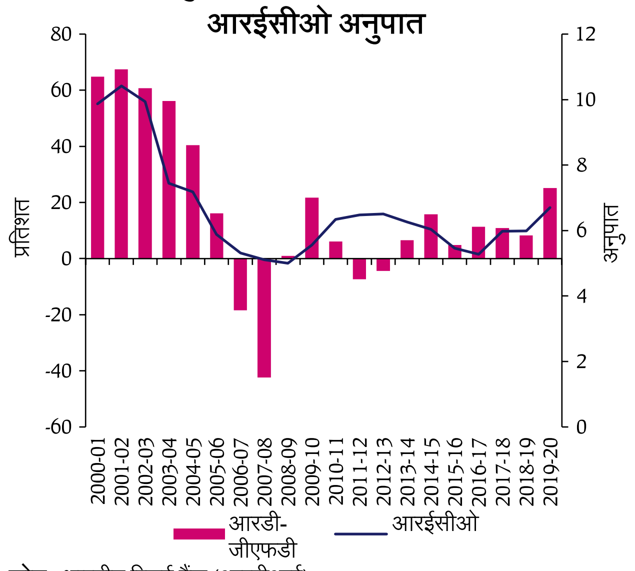

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई)

चार्ट 2 : राज्यों द्वारा व्यय का आकार

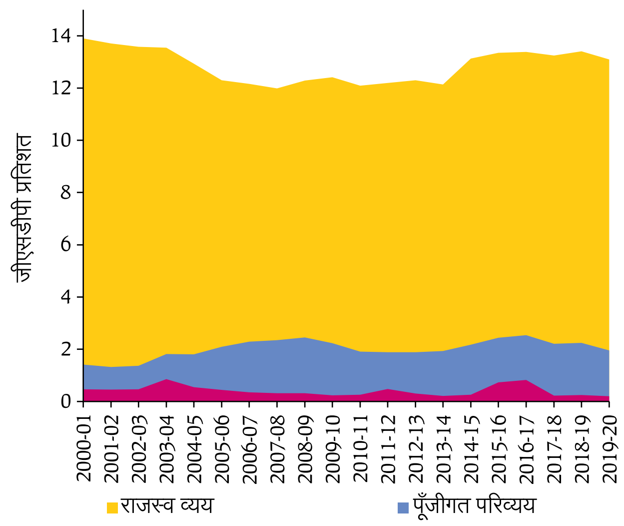

स्रोत : आरबीआई।

हालाँकि, पूंजीगत परिव्यय की वृद्धि अपेक्षाकृत धीमी रही है (चार्ट 2)।

तीसरा, जीएसडीपी में उच्च वृद्धि के कारण जीएसडीपी की तुलना पूंजी परिव्यय अनुपात धीरे-धीरे 2002-03 में 1.3 प्रतिशत से बढ़कर पूर्व-वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) वर्ष में 2.5 प्रतिशत हो गया जिसके कारण जीएसडीपी (चार्ट 3) में उच्च वृद्धि हुई। जीएफसी के प्रभाव के कारण मंदी के साथ, राज्यों की जीएफडी राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान (एफआरएल) सीमा से ऊपर बढ़ गई, जिससे 2010-11 तक उनका पूंजीगत परिव्यय कम हो गया। 2013-14 के बाद, हालांकि, यह अनुपात 2016-17 तक बढ़कर 2.5 प्रतिशत हो गया, तथापि इसके बाद ऊपर बताए गए कारक सहित व्यय में वृद्धि और माल और सेवा कर (जीएसटी) की 1 जुलाई 2017 से कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व अनिश्चितता के कारण इसे कायम नहीं रखा जा सका।

चौथा, राज्य सरकारें विभिन्न सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों को पूंजीगत परिव्यय में प्राथमिकता देती हैं और उन्हें आबंटित करती हैं। कुल पूंजीगत परिव्यय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा परिवहन, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और ऊर्जा क्षेत्रों की ओर लगाया जाता है, जबकि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मानव विकास से

चार्ट 3 : पूंजी परिव्यय – जीएसडीपी अनुपात

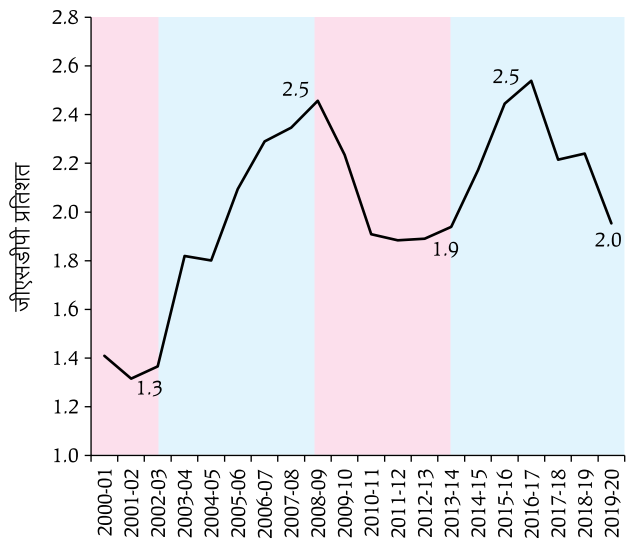

स्रोत : आरबीआई।

चार्ट : 4 राज्यों का पूंजी परिव्यय संयोजन

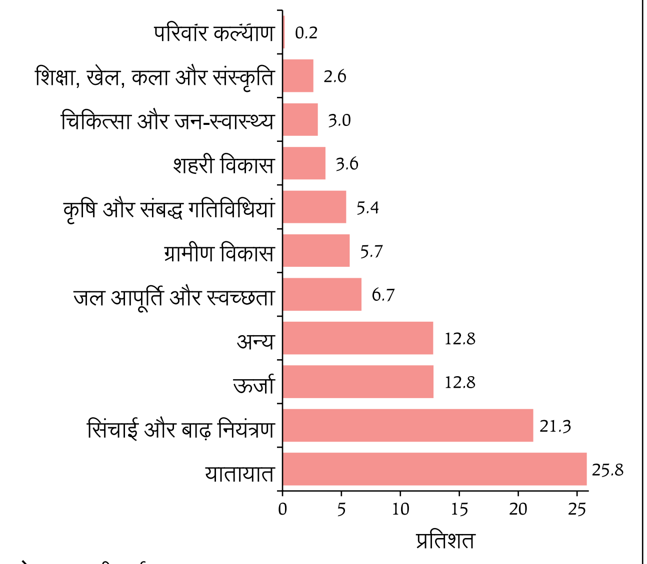

स्रोत : आरबीआई।

संबंधित क्षेत्रों को तुलनात्मक रूप से छोटा हिस्सा मिलता है (चार्ट 4)। शिक्षा और स्वास्थ्य को छोड़कर, यह आबंटन पैटर्न आर्थिक संवृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश पर सरकार के जोर के अनुरूप है।

पांचवां, परिशोधित अनुमान, (आरई) बजट अनुमान (बीई) और वास्तविक, दोनों से अधिक हो जाता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण विचलन राजस्व प्राप्तियों, मुख्य रूप से कर राजस्व (आरबीआई, 2023) से उत्पन्न होता है। प्रतिक्रिया के रूप में, अधिकांश राज्य पूंजीगत परिव्यय के प्रति अपने आवंटन को आरई में और आगे जाकर वास्तविक में और भी कम कर देते हैं। अंत में, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, पूंजीगत परिव्यय पर निर्णय लेते समय राज्य ऋण स्तर और आर्थिक स्थितियों के दबाव में होते हैं। चार्ट 5 दर्शाता है कि पूंजीगत परिव्यय ऋण स्तरों के साथ विपरीत रूप से सहसंबद्ध है, परंतु जीएसडीपी वृद्धि के साथ यह धनात्मक रूप से सहसंबद्ध है।

चार्ट : 5 पूंजी परिव्यय,कर्ज़ और वास्तविक संवृद्धि – सभी राज्य

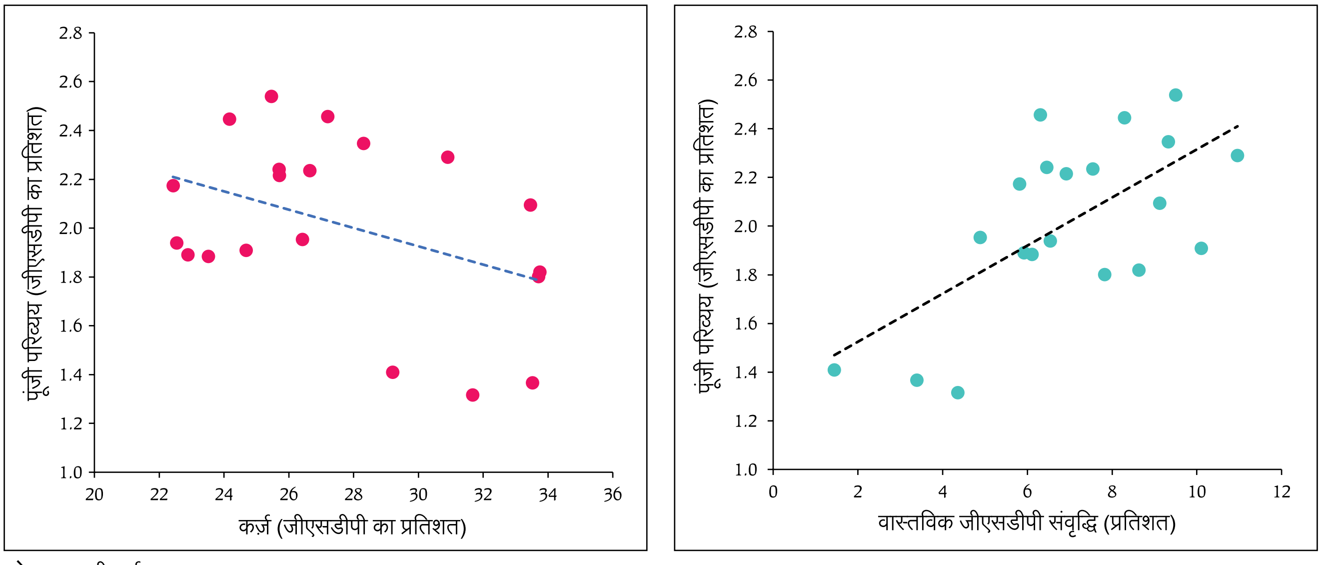

स्रोत : आरबीआई।

ऊपर प्रस्तुत स्थापित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हमने औपचारिक रूप से उप-राष्ट्रीय स्तर पर पूंजीगत परिव्यय और आर्थिक संवृद्धि के बीच संबंधों की पड़ताल की है और साथ ही राज्यों के पूंजीगत परिव्यय को निर्धारित करने में विभिन्न कारकों की भूमिका की पहचान की है।

IV. आंकड़े और प्रविधि

यह अध्ययन 15 भारतीय राज्यों पर केंद्रित है।[2] तथ्यात्मक विश्लेषण के पहले चरण के रूप में, 2000-01 से 2019-20 तक पूंजीगत परिव्यय और जीएसडीपी के बीच संबंधों की जांच की गयी है। हम अपने तथ्यात्मक दृष्टिकोण के रूप में पेड्रोनी और काओ के अवशेष पैनल सह-एकीकरण प्रविधियों[3], एफएमओएलएस, डीओएलएस का उपयोग करते हैं। पूंजीगत परिव्यय और जीएसडीपी से संबंधित आंकड़े क्रमशः भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) से प्राप्त किया गया था। स्थिरता परीक्षणों ने पुष्टि की कि लॉग फॉर्म में चर गैर-स्थिर हैं, जो I(1) में दिए हैं। एक बार जब पूंजीगत परिव्यय और राज्यों के जीएसडीपी के बीच सह-एकीकरण स्थापित हो जाता है, तो दीर्घकालिक गुणांक का अनुमान लगाया जाता है।

राज्यों के पूंजीगत परिव्यय के निर्धारकों की जांच करने के लिए, एक पैनल सेटिंग में द्वि-आयामी प्रणाली जीएमएम को अपनाया जाता है। ये विधियाँ लेखांकन की अंतर्जातता, व्यक्तिगत-विशिष्ट प्रभावों और संभावित पूर्वग्रहों की अनुमति देती हैं, जो सुसंगत और विश्वसनीय अनुमान प्रदान करते हैं। यहां हम 2011-12 से 2019-20 की अवधि के लिए राज्यों के समान समूह के लिए पूंजीगत परिव्यय पर आंकड़े का उपयोग करते हैं।

हम ऋण-जीएसडीपी अनुपात को पूंजीगत परिव्यय-जीएसडीपी, आउटपुट अंतर[4], प्राकृतिक आपदा डमी और चुनाव डमी पर रिग्रेस किया जाता है। अधिक गहराई तक जाने का प्रयास करने के लिए, ऋण और आउटपुट अंतर को उच्च और निम्न ऋण स्तरों की अवधि के लिए अलग-अलग डमी चर शामिल करके और उन्हें ऋण स्तरों के साथ इंटरैक्ट करके एक असममित ट्रीटमेंट अपनाया गया है[5]। इसी प्रकार डमी का उपयोग धनात्मक और ऋणात्मक आउटपुट अंतर के लिए भी किया जाता है और आउटपुट अंतर चर के साथ इंटरैक्ट किया गया।

V. तथ्यात्मक निष्कर्ष

क्या पूंजीगत परिव्यय और जीएसडीपी एक साथ एकीकृत हैं?

पेड्रोनी अवशेष सह-एकीकरण परीक्षण पूंजीगत परिव्यय और जीएसडीपी (सारणी1) के बीच सह-एकीकरण के मजबूत प्रमाण का संकेत देता है। संवर्धित डिकी फुलर (एडीएफ) परीक्षण पर आधारित काओ अवशेष सह-एकीकरण परीक्षण ने भी सह-एकीकरण की उपस्थिति का समर्थन किया। इसके अलावा, एक

सारणी 1 : अनुमान परिणाम: पेड्रोनी और काओ अवशेष सह-एकीकरण परीक्षण

पेड्रोनी अवशेष सह-एकीकरण परीक्षण				
वैकल्पिक परिकल्पना: सामान्य एआर गुणांक				
	आँकड़ा	**संभाव्यता**	**भारित आँकड़े**	**संभाव्यता**
पैनल वी - सांख्यिकी	3.879	0.0001	3.406422	0.0003
पैनल आरएचओ - स्टैटिस्टिक्स	-7.250	0.0000	-6.6964	0.0000
पैनल पीपी - सांख्यिकी	-6.482	0.0000	-5.979	0.0000
पैनल एडीएफ - सांख्यिकी	-6.721	0.0000	-6.33	0.0000
वैकल्पिक परिकल्पना : व्यक्तिगत एआर गुणांक				
	आँकड़ा	**संभाव्यता**		
समूह आरएचओ - सांख्यिकी	-3.0781	0.0010		
समूह पीपी - सांख्यिकी;	-4.5413	0.0000		
समूह एडीएफ - सांख्यिकी	-5.159	0.0000		
काओ अवशेष सह-एकीकरण परीक्षण				
सांख्यिकी			**टी-आंकड़े**	**संभाव्यता**
एडीएफ			-7.861936	0.0000

नोट : सामान्य एआर गुणांक 'आयाम के भीतर' से संबंधित हैं जबकि व्यक्तिगत एआर गुणांक 'आयाम के बीच' से संबंधित हैं।
स्रोत : लेखकों के अनुमान।

[2] आंध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित), बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

[3] पेड्रोनी परीक्षण अवशेषों में अंतर-अनुभागीय स्वतंत्रता मानता है, जबकि काओ परीक्षण अवशेषों में एक सामान्य कारक मॉडलिंग करके अंतर-अनुभागीय निर्भरता की अनुमति देता है। इसके अलावा, पेड्रोनी परीक्षण अंतर-अनुभाग में अवरोधन और प्रवृत्ति गुणांक में विविधता की अनुमति देता है, जबकि काओ परीक्षण अंतर-अनुभाग में सह-एकीकरण संबंध की एकरूपता मानता है।

[4] एचपी फ़िल्टर का उपयोग करके आउटपुट अंतर का अनुमान लगाया जाता है।

[5] ये डमी वैरिएबल उन अवधियों के लिए 1 का मान लेते हैं जब वास्तविक ऋण स्तर शीर्ष या निचले चतुर्थक (25 प्रतिशत) में होते हैं। 25 प्रतिशत पर ऋण-जीएसडीपी अनुपात की सीमा सभी राज्यों के 2015-16 से 2019-20 के अनुपात के औसत के आधार पर चुनी गई है। हालाँकि, यह अनुपात ऋण के इष्टतम स्तर या ऋण के धारणीय स्तर का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

सारणी 2 : अनुमान परिणाम : पैनल एफएमओएलएस और डीओएलएस।

चर	गुणांक	मानक त्रुटि	टी-आंकड़े	संभाव्यता
एफएमओएलएस	0.84	0.02	47.91	0.00
डीओएलएस	0.82	0.02	45.99	0.00

स्रोत : लेखकों के अनुमान।

पैनल वेक्टर त्रुटि सुधार मॉडल (वीईसीएम) को नियोजित करने से यह सुनिश्चित हुआ कि त्रुटि सुधार टर्म[6] नकारात्मक है और सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है।[7]

सारणी 2 राज्यों के पूंजी परिव्यय और जीएसडीपी के बीच संबंधों की जांच करते हुए दो-पैनल प्रतिगमन मॉडल, एफएमओएलएस और डीओएलएस के परिणाम प्रस्तुत करती है और गुणांक 0.84 और 0.82 पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिसका अर्थ यह है कि राज्यों के पूंजीगत परिव्यय में एक प्रतिशत की वृद्धि जीएसडीपी में 0.82-0.84 प्रतिशत की वृद्धि के साथ जुड़ी हुई है।

पूंजीगत परिव्यय के लिए राज्यों के निर्णय को कौन से कारक प्रभावित करते हैं?

इसके बाद, हम एक पैनल ढांचे के भीतर द्वि-आयामी प्रणाली जीएमएम का उपयोग करके राज्यों के पूंजीगत परिव्यय के निर्धारकों की ओर मुड़ते हैं। जैसा कि पहले बताया गया है, ऋण, आर्थिक स्थिति, प्राकृतिक आपदाएं और चुनाव जैसे विभिन्न कारक, पूंजीगत परिव्यय के राज्य के निर्णय को प्रभावित करते हैं और हमारे चर इन आयामों को पकड़ते हैं।

(क) आधारभूत परिणाम

सारणी 3 में कॉलम (I) में आधारभूत विशिष्टताएं दी गई हैं, जबकि कॉलम (II) और (III) में क्रमशः चुनावी वर्ष डमी और प्राकृतिक आपदाएं डमी शामिल हैं। अध्ययन में उपयोग किए गए उपकरणों (यानी, ऋण-जीएसडीपी अनुपात का अंतराल) की

सारणी 3 : अनुमान परिणाम: द्वि-आयामी जीएमएम।

निर्भर चर: पूंजी परिव्यय से जीएसडीपी अनुपात

चर	(I)	(II)	(III)
जीएसडीपी अनुपात$_{t-1}$ की तुलना में पूंजी परिव्यय	0.77***	0.98***	0.97***
	(0.15)	(0.12)	(0.12)
जीएसडीपी अनुपात$_{t-1}$ की तुलना में कर्ज़	-0.01	-0.06*	-0.07**
	(0.03)	(0.03)	(0.03)
आउटपुट अंतर (वास्तविक अवधि)	-0.08	-0.10***	-0.08***
	(0.05)	(0.03)	(0.02)
इलेक्शन डमी		0.15	0.29
		(0.19)	(0.17)
प्राकृतिक आपदाएं			-0.52
			(0.44)
अवरोधन	0.68	1.60*	1.80**
	(0.56)	(0.88)	(0.77)
टिप्पणियाँ	135	105	105
एआर (2)	0.91	0.50	0.73
हानसेन	0.78	0.90	0.94

टीप्पणी: 1. मानक त्रुटियां कोष्ठक में दी गई हैं।

2. तारांकन पी-मान महत्व स्तरों (*** पी<0.01, ** पी<0.05, * पी<0.1) को इंगित करते हैं।

स्रोत : लेखकों के अनुमान।

वैधता का मूल्यांकन हैनसेन और सारगन परीक्षणों का उपयोग करके किया जाता है। दोनों परीक्षण तीनों समीकरणों में शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने में विफल रहे, यह दर्शाता है कि मॉडल सही ढंग से निर्दिष्ट है, और उपयोग किए गए उपकरण वैध हैं।

जीएसडीपी की तुलना में पूंजीगत परिव्यय के विलंबित मूल्य के गुणांक का तीनों विशिष्टताओं पर सकारात्मक और महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जो बताता है कि पूंजीगत परिव्यय के पिछले मूल्य चालू वर्ष के निर्णय को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा, उच्च ऋण स्तर राज्य की पूंजी परिव्यय में निवेश करने की क्षमता में बाधा डालता है। चूँकि समीकरणों में ऋण-से-जीएसडीपी अनुपात का गुणांक ऋणात्मक है, यह इंगित करता है कि अधिक ऋण वाले राज्यों द्वारा पूंजी परिव्यय में अपने निवेश को बढ़ाने की संभावना कम है। आउटपुट अंतर का पूंजी परिव्यय पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है, जैसा कि कॉलम (II) और (III) में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण ऋणात्मक गुणांक द्वारा दिखाया गया है। आउटपुट अंतर में वृद्धि से पूंजी परिव्यय में गिरावट आती है। चुनाव और प्राकृतिक आपदाओं के लिए दोनों डमी चर महत्वहीन हैं, जिसका अर्थ है कि वे राज्यों के पूंजीगत परिव्यय निर्णयों को खास प्रभावित नहीं करते हैं।

[6] त्रुटि सुधार टर्म चरों के बीच अल्पकालिक गतिशीलता का प्रतिनिधित्व करता है, यह दर्शाता है कि चर कितनी जल्दी दीर्घकालिक संतुलन संबंध से विचलन को समायोजित करते हैं। यदि त्रुटि सुधार अवधि का गुणांक ऋणात्मक और सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है, तो यह इंगित करता है कि दीर्घकालिक संतुलन से विचलन को अल्पावधि में ठीक किया जाता है, जिसका अर्थ है कि यदि पूंजी परिव्यय अपने दीर्घकालिक संतुलन स्तर से विचलित होता है, तो यह अल्पावधि में उस स्तर पर समायोजित हो जाएगा।

[7] पैनल वीईसीएम के परिणाम पेपर में प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। हालाँकि, उन्हें अनुरोध पर उपलब्ध कराया जाएगा।

ऋण स्तरों (अर्थात, 25 प्रतिशत से कम और 25 प्रतिशत से अधिक ऋण) के प्रति राज्यों की असममित प्रतिक्रिया और आर्थिक स्थितियाँ (अर्थात, धनात्मक और ऋणात्मक आउटपुट अंतर), जानने के लिए आधार स्तर समीकरण में (सारणी 3 के कॉलम III और सारणी 4 के कॉलम I में दर्शाया गया है) सारणी 4 में कॉलम II से V में दर्शाए गए स्वरूप के अनुसार परिशोधन किया गया है। समग्र ऋण चर को 25 प्रतिशत से कम (डीएल25) और 25 प्रतिशत से अधिक (डीएम25) के ऋण की इंटरैक्टिंग डमी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, जिनका उपयोग डमी परिवर्तनीय ट्रैप से बचने के लिए वैकल्पिक रूप से किया जाता है। अंत में, आउटपुट अंतराल के लिए वैकल्पिक विनिर्देश, यानी, धनात्मक (पीओजी) और ऋणात्मक (एनओजी) भी सिस्टम में शामिल किए गए हैं। अन्य सभी चर सभी विशिष्टताओं में अपरिवर्तित रखे गए हैं।

दिलचस्प बात यह है कि यह निष्कर्ष कि ऋण स्तर बढ़ने पर राज्य सार्वजनिक निवेश कम कर देते हैं, ऋण के सभी स्तरों के लिए सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है। डीएल25 का महत्वहीन गुणांक इंगित करता है कि पूंजीगत परिव्यय आवंटित करने का राज्य सरकार का निर्णय 25 प्रतिशत से कम ऋण स्तर से प्रभावित नहीं होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि जब ऋण का स्तर कम होता है, तो राज्य सरकार के पास सार्वजनिक निवेश पर खर्च करने के लिए अधिक वित्तीय लचीलापन होता है। दूसरी ओर, डीएम25 का ऋणात्मक और सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण गुणांक बताता है कि जब ऋण का स्तर 25 प्रतिशत से अधिक हो जाता है, तो राज्य सरकार सार्वजनिक निवेश का आबंटन कम कर देती है। कर्ज का स्तर ऊंचा होने पर राज्य सरकार को वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे सार्वजनिक निवेश पर खर्च करने की उसकी क्षमता सीमित हो जाती है। उच्च ऋण स्तर से उधार लेने की लागत भी बढ़ जाती है, जिससे सार्वजनिक निवेश के लिए धन की उपलब्धता कम हो जाती है।

सारणी 4 : अनुमान परिणाम : द्विभाषी जीएमएम

निर्भर चर : जीएसडीपी की तुलना में पूंजी परिव्यय अनुपात

चर	(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)
जीएसडीपी अनुपात$_{t-1}$ की तुलना में पूंजी परिव्यय	0.97*** (0.12)	0.97*** (0.13)	0.99*** (0.14)	0.99*** (0.10)	0.90*** (0.11)
जीएसडीपी अनुपात$_{t-1}$ की तुलना में कर्ज़	-0.07** (0.03)			-0.06* (0.04)	-0.05* (0.03)
आउटपुट अंतर (वास्तविक अवधि)	-0.08*** (0.02)	-0.11*** (0.03)	-0.10*** (0.02)		
इलेक्शन डमी	0.29 (0.17)	0.27 (0.22)	0.28 (0.20)	-0.17 (0.54)	0.37 (0.35)
प्राकृतिक आपदाएं	-0.52 (0.44)	-0.54 (0.56)	-0.72 (0.55)	-0.03 (0.53)	-0.29 (0.40)
डीएल 25 (ऋण<25 प्रतिशत)		0.03 (0.02)			
डीएम 25 (ऋण>25 प्रतिशत)			-0.02* (0.01)		
पीओजी (धनात्मक आउटपुट अंतर)				-0.16*** (0.04)	
एनओजी (ऋणात्मक आउटपुट अंतर)					-0.20*** (0.05)
स्थिरांक	1.80** (0.77)	-0.25 (0.38)	0.36 (0.33)	2.04* (1.08)	1.41 (0.85)
टिप्पणियाँ	105	105	105	105	105
एआर (2)	0.73	0.62	0.74	0.61	0.40
हानसेन	0.94	0.84	0.89	0.86	0.84

नोट: 1. मानक त्रुटियां कोष्ठक में दी गई हैं।

2. तारांकन पी-मान महत्व स्तरों (*** पी<0.01, ** पी<0.05, * पी<0.1) को इंगित करते हैं।

स्रोत : लेखकों के अनुमान।

आउटपुट अंतर (ओजी) के लिए गुणांक ऋणात्मक और महत्वपूर्ण है, आउटपुट अंतर के धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मामलों में - परिणाम सावधानीपूर्वक व्याख्या की माँग करता है। धनात्मक आउटपुट अंतराल अवधि के दौरान, यह तर्कसंगत हो सकता है कि राज्य राजकोषीय सुदृढ़ता के पथ पर प्रतिबद्ध हों, यानी जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात को एफआरएल सीमा के भीतर रखें। ऋणात्मक आउटपुट अंतराल अवधि के दौरान, सरकारें प्रति-चक्रीय राजकोषीय नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था को सहायता प्रदान करती हैं। इसका एक हिस्सा उच्च पूंजीगत व्यय के रूप में भी हो सकता है। यह नीति हाल के वर्षों में देखने को मिली है जब सरकारों ने कोविड-19 महामारी के बाद समुत्थान अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय में वृद्धि की है।

संक्षेप में, अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि पूंजीगत परिव्यय के पिछले मूल्य, जीएसडीपी की तुलना में ऋण अनुपात और आउटपुट अंतर से व्युत्पन्न आर्थिक स्थितियां राज्यों के पूंजीगत परिव्यय निर्णयों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। इन निष्कर्षों का नीति निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण अर्थ है, अर्थात्, राज्यों द्वारा सचेत राजकोषीय प्रबंधन और योजना की आवश्यकता जताने वाले ऋण के उच्च स्तर से पूंजी परिव्यय में निवेश बाधित हो सकता है।

VI. निष्कर्ष

अध्ययन के तथ्यात्मक निष्कर्षों से राज्यों के पूंजी परिव्यय और जीएसडीपी के बीच एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक संबंध का पता चला - पूंजी परिव्यय में एक प्रतिशत की वृद्धि से जीएसडीपी में 0.82-0.84 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके अलावा, निष्कर्षों से यह भी पता चला है कि पूंजी परिव्यय के पिछले मूल्य चालू वर्ष के निर्णय को प्रभावित करते हैं, जबकि ऋण का उच्च स्तर राज्यों द्वारा सार्वजनिक निवेश में निवेश करने की क्षमता में बाधा डालता है। इसके अतिरिक्त, कर्ज का स्तर ऊंचा होने पर राज्य सरकारें सार्वजनिक निवेश का आबंटन कम कर देती हैं। राज्य पूंजी परिव्यय के आवंटन में प्रति-चक्रीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। अध्ययन के निष्कर्ष पूंजी परिव्यय पर राज्य सरकारों के निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत निहितार्थ दर्शाते हैं। जबकि जीएसडीपी के साथ उनके धनात्मक जुड़ाव के कारण पूंजी परिव्यय को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है, ऋण स्तर ऊंचे होने पर सार्वजनिक निवेश के लिए विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने की भी आवश्यकता है। इस प्रकार, विश्लेषण समग्र ऋण स्तर को कम और धारणीय बनाए रखने के लक्ष्य के साथ उच्च पूंजी परिव्यय की आवश्यकता को संतुलित करने की आवश्यकता को सामने लाता है।

संदर्भ

Berawi, M., Miraj, P and Sari, M (2020). Accelerating Infrastructure Development in Post-Pandemic Era. *CSID Journal of Infrastructure Development.* Vol. 3(114).

Cullison, W. E. (1993). Public Investment and Economic Growth. *Federal Reserve Bank Of Richmond Economic Quarterly*, 15.

Gaspar, V., Mauro, P., Pattillo, C and Espinoza, R (2020). Public Investment for the Recovery. *IMF Blog.* October.

Gregoriou, A and Ghosh, S. (2009). The Impact of Government Expenditure on Growth: Empirical Evidence from Heterogeneous Panel. *Bulletin of Economic Research.* Vol. 61(1). pp.95-102. February.

Idenyi, O.S., Ogonaa, I.C., and Ifeyinwa, A.C (2016). Public Debt and Public Expenditure in Nigeria: A Causality Analysis. *Research Journal of Finance and Accounting.*Vol. 7(10).

Ismail, N and Mahyideen, J. (2015). The Impact of Infrastructure on Trade and Economic Growth in Selected Economies in Asia. *ADBI Working Paper Series.* No.553. December.

Jain, R. and Kumar, P. (2013). Size of Government Expenditure Multipliers in India: A Structural VAR Analysis. *RBI Working Paper Series.* No.7. September.

Korman, J and Bratimasrene, T. (2007). The Relationship between Government Expenditure and Economic Growth in Thailand. *Journal of Economic Education.* Vol.14. pp. 234-246.

Leasiwal, T. (2021). Impact of Government Capital Expenditure on Poverty Levels in Maluku. *Jurnal Cita Ekonomika*, Vol.15(1). pp.43–49.

Lora, E and Olivera, M. (2007). Public Debt and Social Expenditure: Friends or Foes?. *Emerging Markets Review.* Elsevier, Vol. 8(4). pp. 299-310. December.

Organisation for Economic Cooperation and Development (2021). COVID-19 Transport Brief: Analysis, Facts and Figures for Transport's Response to Corona Virus. March.

Paudel, R. (2023). Capital Expenditure and Economic Growth: A Disaggregated Analysis for Nepal. *Cogent Economics and Finance.* Vol. 11(1). March.

Rasmussen, T. (2004). Macroeconomic Implications of Natural Disasters in the Caribbean. *IMF Working Paper.* December.

Reserve Bank of India (2022). Report on Currency and Finance. April.

Reserve Bank of India (2023). State Finances: A Study of Budgets of 2022-23. January.

Rizqiyati, C and Setiawan, D. (2022). Do Regional Heads Utilize Capital Expenditures, Grants, and Social Assistance in the Context of Elections? *Economies.* Vol.10(220). September.

Teklay, B. (2016). Impact of Government Capital Expenditure on Growth of Private Sector Investment: The Case of Ethiopia. *Developing Country Studies.* Vol. 6(4). pp.49-61.

Toubeau, S and Vampa, D (2021). Adjusting to Austerity: The Public Spending Responses of Regional Governments to the Budget Constraint in Spain and Italy. *Journal of Public Policy*, Cambridge University Press. Vol. 41(3). pp. 462-488. September.

Victoria, J (2015). Human Capital Investment and Economic Growth in Nigeria. *African Research Review.* 9(1). S/No. 36. January.

Waweru, D and Mose, N. (2021). Government Capital Expenditure and Economic Growth: An Empirical Investigation. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting.* Vol.21(8). pp.29-36. June

World Bank (2022). Financing India's Urban Infrastructure Needs: Constraints to Commercial Financing and Prospects for Policy Action. November.

*औद्योगिक संबंध संहिता और श्रम उत्पादकता: एक अंतर-देशीय अधि-विश्लेषण**

श्रुति जोशी और राखी पी. बालचंद्रन^ द्वारा

भारत ने हाल ही में 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को चार श्रम संहिताओं में संहिताबद्ध किया है, जो वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाजी परिस्थितियों से संबंधित संहिताएं हैं। औद्योगिक संबंधों पर संहिता में निश्चित अवधि के रोजगार (एफटीई) की भी शुरुआत की गई है। यह अध्ययन मेटा-रिग्रेशन विश्लेषण का उपयोग करके एफटीई-प्रभाव से संबंधित अंतरराष्ट्रीय साक्ष्य को संश्लेषित करता है। विभिन्न देशों के संदर्भों में किए गए 19 अध्ययनों के आधार पर, हमने पाया कि एफटीई का औसतन श्रम उत्पादकता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

भारत में श्रम कानूनों को विभिन्न राष्ट्रीय समितियों और आयोगों की सिफारिशों के आधार पर आकार दिया गया है, जिनमें पहला राष्ट्रीय श्रम आयोग (1969), राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग (1991), दूसरा राष्ट्रीय श्रम आयोग (2002), और असंगठित क्षेत्र में उद्यम के लिए आयोग (2009) शामिल हैं। इन समितियों ने सामाजिक सुरक्षा, वेतन, बीमा और औद्योगिक संबंधों पर सुधारों की सिफारिश की। इनमें से कई बदलाव खंडश: जोड़े गए हैं, जिससे श्रम कानून जटिल हो गए हैं। हाल ही में, भारत ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को चार श्रम संहिताओं में संहिताबद्ध किया है, जैसे वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाजी परिस्थितियों पर संहिता।

औद्योगिक संबंधों पर संहिता का उद्देश्य ट्रेड यूनियनों और औद्योगिक विवादों के निपटारे से संबंधित कानूनों को समेकित करना है। इस संहिता में तीन पूर्ववर्ती केंद्रीय श्रम कानूनों को शामिल किया गया: ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926; औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946, और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947। इस संहिता के प्रावधानों में विवादों का समय पर निपटान, निश्चित अवधि के श्रमिकों को काम पर रखने का लचीलापन और हड़ताल और लॉकडाउन के कारण काम में अचानक व्यवधान को सीमित करना शामिल है। इसने श्रम विवादों के समाधान के लिए संरचनात्मक प्रक्रिया को नया रूप दिया और भारत में एफटीई की शुरुआत की, जिससे श्रम प्रबंधन को अधिक लचीला बनाया जा सके। एफटीई को, कारोबारी चक्रों के अनुसार श्रम लचीलेपन को बढ़ाने के लिए एक तंत्र के रूप में देखा जाता है, जिससे समग्र आर्थिक दक्षता बढ़ सकती है, हालांकि उपलब्ध साक्ष्य श्रम उत्पादकता पर एफटीई के मिश्रित प्रभाव का संकेत देते हैं।

श्रम प्रबंधन में कंपनियों के लचीलेपन को बढ़ाने के लिए एफटीई यूरोपीय देशों में लोकप्रिय हैं। एफटीई कर्मचारी स्थायी कर्मचारियों की तरह समान वेतन, भत्ते और लाभ के हकदार हैं[1] और बिचौलियों से बचकर सीधे फर्मों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं[2]। हालाँकि, एफटीई कर्मचारी अपने संविदा का नवीकरण न होने के कारण किसी भी समाप्ति नोटिस या विच्छेद वेतन और किसी भी छंटनी लाभ के हकदार नहीं हैं। यह बिना किसी अतिरिक्त अतिरेक लागत के श्रम प्रबंधन में लचीलापन प्रदान करता है। एक ओर, इस तरह का लचीलापन कंपनियों को मांग में मौसमी उतार-चढ़ाव को पूरा करने में सक्षम बनाता है, लेकिन प्रकृति में अस्थायी होने के कारण, यह श्रमिकों को हतोत्साहित करता है। नियोजकों को इन कर्मचारियों को नौकरी पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, जिससे उनकी उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है (अरुलमपालम और बूथ 1998; बूथ और अन्य 2002; फोरेज और अन्य 2012; विडाल और ट्रिग्स 2009)। वैकल्पिक रूप से, एफटीई फर्मों द्वारा उत्पादक श्रमिकों की पहचान करने के लिए एक स्क्रीनिंग तंत्र के रूप में भी कार्य कर सकता है और इससे श्रम उत्पादकता में समग्र सुधार होगा (वांग और वीस 1988; गेरफिन और अन्य। 2005; गश 2008)। इन अध्ययनों से हम भारत में श्रम उत्पादकता पर एफटीई के प्रभाव के बारे में कैसे निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इस उद्देश्य की पूर्ति के

^ यह आलेख आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग की श्रुति जोशी और राखी पी. बालचंद्रन द्वारा तैयार किया गया है। आलेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

1 https://egazette.nic.in/WriteReadData/2020/222118.pdf

2 https://indianexpress.com/article/opinion/columns/labour-laws-india-apple-plant-wistron-violence-7117353/

लिए, हमने एफटीई की शुरुआत करने वाले औद्योगिक संबंध संहिता के कार्यान्वयन से श्रम उत्पादकता के मोर्चे पर भारत क्या उम्मीद कर सकता है, इस पर विचार करने के लिए 19 अध्ययनों का एक अधि-विश्लेषण किया है।

इस पृष्ठभूमि के साथ, शेष आलेख निम्नानुसार व्यवस्थित हैं : खंड II विकास, रोजगार और उत्पादकता पर एफटीई के प्रभाव का विश्लेषण करने वाले साहित्य का एक सिंहावलोकन प्रदान करता है। खंड III मेटा डेटा के निर्माण की व्याख्या करता है। खंड IV मेटा-रिग्रेशन मॉडल की व्याख्या करता है, खंड V परिणाम दर्शाता है और VI निष्कर्ष प्रस्तुत करता है।

II. साहित्य की समीक्षा

श्रम नियमों और आर्थिक संकेतकों के बीच संबंधों का विश्लेषण करने वाला साहित्य ज्यादातर रोजगार संरक्षण कानून को आर्थिक संवृद्धि, उत्पादकता और रोजगार से जोड़ता है। साहित्य में इस बात के प्रमाण हैं कि लचीले श्रम कानून औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाते हैं (होम्स 1988; बेस्ली और बर्गेस 2004; सान्याल और मेनन 2005; अहसान और पेज 2009)। दूसरी ओर, कठिन श्रम नियम, अर्थव्यवस्थाओं की संवृद्धि संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं (कैबलेरो और अन्य 2004; मिको और पेजज 2006)। 53 अध्ययनों पर एक मेटा रिग्रेशन से पता चलता है कि केवल 28 प्रतिशत अध्ययन आईएमएफ की आम सहमति से सहमत हैं कि श्रम बाजार अविनियमन से रोजगार बढ़ता है और बेरोजगारी कम होती है (ब्रांकासियो 2020)। इसके अलावा, लेखक और अन्य (2007) पाते हैं कि अनिवार्य रोज़गार सुरक्षा, पूंजी गहनता और फर्म की उत्पादकता को कम कर देती है।

न्यूनतम मजदूरी और अनिवार्य विच्छेद वेतन सहित श्रम बाजार नियम, श्रम की मांग को कम करके बेरोजगारी पर प्रभाव डालते हैं (लेज़ियर 1990; करी और फ़ॉलिक 1996; एबाउड क्रामरज़ और मार्गोलिज़ 1999; ब्लैंचर्ड और वोल्फ़र्स 2000; हेकमैन और पेज 2003; कुग्लर 2004; बोएटेरो और अन्य 2004)। न्यूनतम मजदूरी मजदूरी पर एक न्यूनतम स्तर बनाती है और नियोजकों की स्वतंत्र रूप से मजदूरी तय करने की क्षमता को बाधित करती है, जिससे रोजगार सृजन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हालाँकि, 16 अध्ययनों से 236 अनुमानित न्यूनतम वेतन लचीलापन और 710 आंशिक सहसंबंध गुणांक पर एक मेटा रिग्रेशन ने, यूके में न्यूनतम मजदूरी के प्रतिकूल रोजगार प्रभाव की जांच में पाया गया कि न्यूनतम मजदूरी का कोई प्रतिकूल रोजगार प्रभाव नहीं है (लियोनार्ड और अन्य 2020)।

कई अध्ययन उत्पादकता पर एफटीई के प्रभाव की जांच करते हैं (सांचेज़ और अन्य 2000; ओर्टेगा और अन्य 2010; ल्यूसीडी 2010)। मानव पूंजी सिद्धांत का तर्क है कि नियोजक अपनी छोटी अवधि के कारण फर्म-विशिष्ट मानव पूंजी और अस्थायी कर्मचारियों पर प्रशिक्षण में निवेश करने के लिए अनिच्छुक हैं, जिससे एफटीई और मानव पूंजी में निवेश के बीच एक समझौता होता है (अरुलमपलम और बूथ 1998; बूथ और अन्या 2002) ; फोरेज और अन्य. 2012)। दूसरा, निश्चित अवधि के श्रमिकों द्वारा मुख्य श्रमिकों के प्रतिस्थापन से मूल और निश्चित अवधि के श्रमिकों (विडाल और ट्रिग्स 2009) दोनों की प्रेरणा कम हो जाती है। तीसरा, एफटीई का उच्च स्तर गतिविधि में क्षेत्रीय बदलाव को प्रोत्साहित कर सकता है, क्योंकि आमतौर पर कम उत्पादक क्षेत्र अस्थायी रोजगार से सबसे अधिक लाभान्वित होते हैं (ओईसीडी 2005)। दूसरी ओर, अपूर्ण बाज़ारों और असममित जानकारी की उपस्थिति में, एफटीई कंपनियों को नए श्रमिकों की स्क्रीनिंग करने में सक्षम बनाता है, जिससे श्रमिकों को प्रयास करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। जो कंपनियाँ अधिकांश उत्पादक श्रमिकों को स्थायी संविदा प्रदान करती हैं, वे अपनी समग्र उत्पादकता में सुधार कर सकती हैं (वांग और वीस 1988; गेरफिन और अन्या 2005; गश 2008)। कुल कारक उत्पादकता पर अस्थायी अनुबंधों के प्रभाव को साहित्य में नकारात्मक बताया गया है (डोलाडो और अन्य 2008; एडेसी 2011; होस्पिडो और अन्य 2015)।

भारतीय संदर्भ में अध्ययन, सामान्य तौर पर, औद्योगिक रोजगार और उत्पादन के साथ श्रम कानूनों में लचीलेपन के बीच एक सकारात्मक संबंध की ओर इशारा करते हैं। उदाहरण के लिए, कठोर कानूनों वाले राज्यों में, उत्पादन, रोजगार और उत्पादकता में मंदी थी (बेस्ले और बर्गेस 2004); उदारीकरण नीतियों की प्रतिक्रिया में लचीले श्रम कानूनों वाले राज्यों में स्थित उद्योग अधिक तेजी से बढ़े (अघियोन और अन्य 2003); लचीले श्रम कानूनों वाले राज्यों में औद्योगिक रोजगार श्रम बाजार में आघात

के प्रति अधिक संवेदनशील था (शर्मा और अन्य 2011); श्रम विवादों की बढ़ी हुई लागत ने पंजीकृत विनिर्माण में उत्पादन और रोजगार को कम कर दिया (अहसन और पेजज 2008)।

III. आंकड़े

यह अध्ययन श्रम उत्पादकता पर एफटीई के अनुमानित प्रभाव पर केंद्रित है। मेटा के लिए आलेख की खोज अप्रैल-जून, 2022 के दौरान हुई। हमने मुख्य रूप से चार खोज इंजनों का उपयोग किया- गूगल स्कॉलर, ईसीओएनएलाआईटी, साइंस डायरेक्ट और जेसटीओआर। इन खोज इंजनों के अलावा, हमने खोज के पहले दौर से पहचाने गए अध्ययनों में उल्लिखित संदर्भ सूची का भी उल्लेख किया। खोज के लिए कीवर्ड में 'निश्चित अवधि रोजगार' 'अस्थायी रोजगार', 'श्रम संविदा', 'निश्चित अवधि संविदा', 'अस्थायी संविदा', 'उत्पादकता' और 'श्रम उत्पादकता' के विभिन्न संयोजन शामिल थे। उपर्युक्त खोज के आधार पर, हम 65 अध्ययनों की पहचान करने में सक्षम थे। मेटा में जोड़ने के लिए, एक अध्ययन में उत्पादकता पर एफटीई के प्रभाव का तथ्यात्मक अनुमान शामिल होना चाहिए। दो सैद्धांतिक अध्ययन जिनमें तथ्यात्मक अनुमान शामिल नहीं थे, उन्हें मेटा में शामिल नहीं किया गया था। इसके अलावा, 39 अध्ययनों ने उत्पादकता पर एफटीई के प्रभाव का अध्ययन नहीं किया, और इसलिए, उन्हें अधि-विश्लेषण से हटा दिया गया। ये अध्ययन एफटीई के बजाय उत्पादकता पर रोजगार संरक्षण कानून के प्रभाव को देख रहे थे। अंत में, दो अध्ययन विशुद्ध रूप से वर्णनात्मक थे। इस प्रक्रिया के कारण पहचाने गए 65 अध्ययनों में से 43 अध्ययन समाप्त हो गए। इसके अलावा, हमने कुल कारक उत्पादकता पर तीन अध्ययनों को भी बाहर रखा है। परिणामस्वरूप, हमने मेटा-विश्लेषण के लिए 311 गुणांक वाले 19 प्रासंगिक अध्ययनों का चयन किया।

सभी शामिल अध्ययनों में, एफटीई से संबंधित चर, कुल श्रमिकों की तुलना में अस्थायी/निश्चित अवधि के श्रमिकों का अनुपात था। आश्रित चर को मापने के लिए सैद्धांतिक विनिर्देश के दो रूप मौजूद हैं: आंशिक माप और कुल कारक उत्पादकता (टीएफपी)। हम उत्पादकता के आंशिक माप पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सम्मिलित अध्ययनों में उपयोग किए गए श्रम उत्पादकता के विभिन्न आंशिक उपाय प्रति श्रमिक उत्पादन, प्रति श्रमिक बिक्री और प्रति श्रमिक राजस्व हैं। इसके अलावा, दो अध्ययनों में उत्पादकता के माप के रूप में मजदूरी और उत्पादन के स्तर का उपयोग किया गया है। हमारे विश्लेषण में, हम प्रति कर्मचारी उत्पादकता माप को एक और अन्यथा शून्य के रूप में कोडित करते हैं।

श्रम उत्पादकता और एफटीई के बीच कारण संबंध स्थापित करने में, हम अंतर्जातता का सामना करते हैं, क्योंकि श्रम उत्पादकता के आघात फर्म द्वारा उपयोग किए जाने वाले निश्चित अवधि के श्रमिकों की हिस्सेदारी को भी प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, उत्पादकता को आघात लगने से अस्थायी श्रमिकों का उपयोग बढ़ सकता है। इसलिए, श्रम उत्पादकता पर एफटीई का प्रभाव पक्षपातपूर्ण होने की संभावना है। हमारे पास कोडित अध्ययन हैं जिन्होंने अंतर्जातता को एक और अन्यथा शून्य के रूप में नियंत्रित किया है।

अध्ययन में उपयोग किए गए डेटा का प्रकार भी अध्ययन के परिणामों में भिन्नता प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, क्रॉस सेक्शन पर पैनल डेटा का उपयोग करने का लाभ यह है कि यह समय-अपरिवर्तनीय परिवर्तनों को नियंत्रित करने में सक्षम बनाता है। इस प्रकार, उनके क्रॉस-सेक्शन समकक्षों की तुलना में पैनल डेटा अध्ययनों से परिणाम अपेक्षाकृत अधिक मजबूत हैं। हमारे पास कोडित अध्ययन हैं जो पैनल डेटा को एक के रूप में उपयोग करते हैं और अन्यथा शून्य का उपयोग करते हैं।

हम सर्वेक्षण के प्रकार को भी नियंत्रित करते हैं: सरकारी सर्वेक्षण को एक के रूप में कोडित करना और अन्यथा शून्य। सरकारी सर्वेक्षणों में आमतौर पर व्यापक कवरेज, संरचित प्रश्नावली के साथ-साथ अधिक पेशेवर डेटा संग्रहण प्रक्रिया होती है, जो व्यक्तिगत लेखकों द्वारा किए गए सर्वेक्षणों की तुलना में इसे अधिक विश्वसनीय और निष्पक्ष बनाती है। इसके अलावा, नियत वर्ष प्रभाव किसी भी समय परिवर्तन को कैप्चर करते हैं जो विश्लेषण की अवधि के दौरान हो सकता है। यदि अध्ययन किसी एक देश पर आधारित है तो देश डमी का मान एक होता है और अन्यथा शून्य। अंत में, यदि यह यूरोपीय क्षेत्र है तो क्षेत्र कंट्रोल एक मान लेता है और अन्यथा शून्य।

अन्य अध्ययन विशिष्ट विशेषताओं में फर्म के विशिष्ट प्रभाव जैसे कि फर्म की आयु, फर्म का आकार, निवेश, ट्रेड यूनियन घनत्व और आर्थिक गतिविधि का क्षेत्र शामिल हैं। फर्म की उम्र और आकार श्रम उत्पादकता पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं क्योंकि इन फर्मों के पास आवश्यक निवेश के साथ-साथ अनुभव भी होता है जो उन्हें श्रम उत्पादकता में सुधार को सक्षम बनाता है। हम कामगार की विशिष्टताओं को भी शामिल करते हैं जिसमें शिक्षा, कार्य का प्रकार और लिंग शामिल हैं। श्रम उत्पादकता, व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले कार्य की प्रकृति पर भी निर्भर करती है; ब्लू कॉलर सेवाओं में लगे श्रमिकों की उत्पादकता सफेद कॉलर नौकरियों में शामिल लोगों की तुलना में कम होगी।

स्वामित्व संरचना जैसे अन्य चरों के लिए भी अध्ययन नियंत्रित किया जाता है। कुछ अध्ययनों में, महिलाओं की उत्पादकता के माप के रूप में बच्चों की संख्या का उपयोग किया गया है। नवाचार और अनुसंधान एवं विकास का श्रम उत्पादकता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसका कारण कई अध्ययन हैं। इसके अलावा, विलय और अधिग्रहण का उपयोग फर्म संगठन के संकेतक के रूप में किया जाता है और कार्य-प्रदर्शन से जुड़ा वेतन श्रमिकों को अधिक प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करने का एक तरीका है। हालाँकि, इन विशेषताओं को शामिल करने वाले अध्ययनों की संख्या इतनी अधिक नहीं है कि उन्हें अधि-विश्लेषण में मॉडरेटर चर के रूप में शामिल किया जा सके।

IV. वर्णनात्मक आँकड़े

हमारे डेटासेट में 1987 से 2015 तक की अवधि को शामिल करने वाले 311 प्रेक्षण हैं जो 7 देशों[3] और यूरोपीय संघ से लिए गए हैं। सबसे अधिक इटली (35 प्रतिशत) और कोलम्बिया (24 प्रतिशत) से लिए गए हैं। सभी अध्ययन सीधे तौर पर श्रम उत्पादकता पर अस्थायी नौकरियों के अनुमानित प्रभाव की रिपोर्ट देते हैं। भारतीय संदर्भ में कुछ अध्ययन हैं, हालाँकि, हम इन अध्ययनों को अपने विश्लेषण में शामिल नहीं कर सके क्योंकि वे श्रम उत्पादकता पर एफटीई के प्रभाव का सटीक विश्लेषण नहीं कर रहे थे।[4]

रिपोर्ट किए गए गुणांक का वितरण चित्र 1 में दिखाया गया है। रिपोर्ट किए गए गुणांक की सीमा (-) 0.84 से 1.12 तक है। रिपोर्ट किए गए गुणांकों में से 60 प्रतिशत प्रेक्षण शून्य से कम हैं। यह श्रम उत्पादकता पर एफटीई के प्रतिकूल प्रभाव को इंगित करता है जबकि शेष 40 प्रतिशत प्रेक्षण शून्य से अधिक हैं जो उत्पादकता पर एफटीई के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाते हैं। रिपोर्ट किया गया कोई भी गुणांक शून्य नहीं है जिसका अर्थ है कि शामिल अध्ययनों में उत्पादकता पर एफटीई का कुछ प्रभाव पाया गया है। जैसा कि चित्र 1 से देखा जा सकता है, हमारा रिपोर्ट किया गया गुणांक पूरे नमूने के लिए दोहरा मॉडल है, जो स्पष्ट रूप से यूरोपीय क्षेत्र के अनुमानों के लिए एक मोड और गैर-यूरोपीय क्षेत्र के अनुमानों के लिए दूसरा मोड दर्शाता है। यूरोपीय क्षेत्र का औसत प्रभाव आकार (-) 0.102 है जबकि गैर-यूरोपीय क्षेत्रों के लिए 0.83 है। (चित्र 1 और सारणी 4)।

मेटा नमूने में, 73 प्रतिशत अध्ययन यूरोपीय क्षेत्र से हैं और उनमें से 80 प्रतिशत एकल देश के अध्ययन हैं। उनमें से सत्तर प्रतिशत सहकर्मी-समीक्षित पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं। अधिकांश अध्ययनों में सरकारी सर्वेक्षणों (85 प्रतिशत) के डेटा का विश्लेषण किया गया है और पैनल डेटा (60 प्रतिशत) का उपयोग किया गया है। 44 प्रतिशत अध्ययनों ने अंतर्जातता को शामिल किया है, इस प्रकार, एफटीई और श्रम उत्पादकता के

चित्र 1 : अध्ययन-वार श्रम उत्पादकता से संबंधित एफटीई के गुणांक का विभाजन

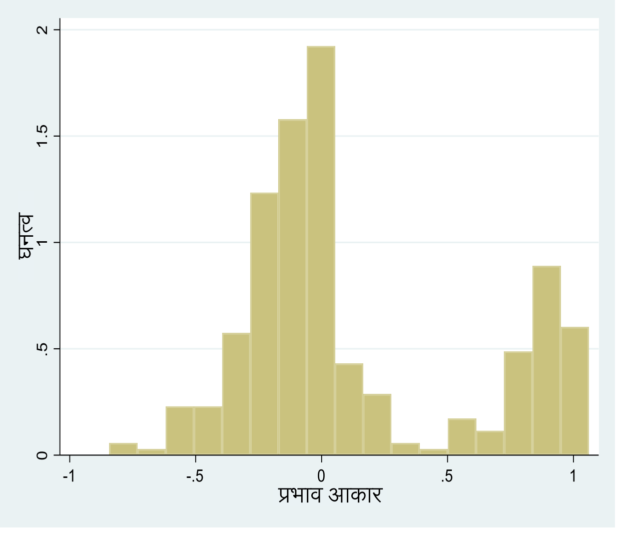

[3] शामिल किए गए अध्ययन निम्नलिखित देशों से संबंधित हैं: जर्मनी, इटली, स्पेन, दक्षिण कोरिया, बेल्जियम, कोलंबिया और ब्रिटेन।

[4] भारतीय संदर्भ में अध्ययन के निष्कर्षों का सारांश साहित्य समीक्षा में प्रदान किया गया है।

सारणी 4 : वर्णनात्मक सांख्यिकी

चर	कोड	पूर्ण नमूना	यूरोपीय नमूना	गैर-यूरोपीय नमूना
उत्पादकता अनुमानों की कुल संख्या (निर्भर चर)		311	229	82
औसत अनुमान		-0.13	-0.12	0.83
सापेक्ष माप		1.9	2.4	0
प्रति श्रमिक माप		96	95	100
प्रतिशत में मॉडरेटर चर				
आंकड़े	पैनल=1; 0 अन्यथा	60	81	1.2
सर्वेक्षण	सरकार द्वारा सर्वेक्षण=1; 0 अन्यथा	85	81	100
अनुमान	अंतर्जातता के लिए कंट्रोल = 1; 0 अन्यथा	44	27	95
फर्म की आयु	फर्म आयु के लिए कंट्रोल =1; 0 अन्यथा	14	20	0
फर्म का आकार	फर्म आकार के लिए कंट्रोल =1; 0 अन्यथा	25	34	0
ट्रेड यूनियन घनत्व	ट्रेड यूनियन घनत्व के लिए कंट्रोल =1; 0 अन्यथा	20	27	0
निवेश	निवेश के लिए कंट्रोल =1; 0 अन्यथा	19	27	0
आर्थिक गतिविधि का क्षेत्र	आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के लिए कंट्रोल =1; 0 अन्यथा	48	66	0
शिक्षा	कंट्रोल्ड शिक्षा=1; 0 अन्यथा	18	23	0
प्रशिक्षण	प्रशिक्षण के लिए कंट्रोल =1; 0 अन्यथा	27	36	0
ब्लू कॉलर	ब्लू कॉलर वर्कर के लिए कंट्रोल =1; 0 अन्यथा	19	27	0
जेंडर	जेंडर के लिए कंट्रोल =1; 0 अन्यथा	14	20	0
नियत वर्ष प्रभाव	नियत वर्ष प्रभाव के लिए कंट्रोल =1; 0 अन्यथा	30	41	0
देश	एकल देश=1; 0 अन्यथा	80	72	100
क्षेत्र	यूरोपीय=1; 0 अन्यथा	73	100	0
प्रकाशित	प्रकाशित=1; 0 अन्यथा	70	58	100

बीच संबंधों पर खासा परिणाम प्राप्त होते हैं। वे अध्ययन जो अन्य अध्ययन की विशिष्टताओं, जैसे फर्म की आयु (14 प्रतिशत), फर्म का आकार (25 प्रतिशत), ट्रेड यूनियन घनत्व (20 प्रतिशत), निवेश (19 प्रतिशत), शिक्षा (18 प्रतिशत), को प्रशिक्षण (27 प्रतिशत), ब्लू कॉलर श्रमिक (19 प्रतिशत), जेंडर (14 प्रतिशत) को शामिल करते हैं, मेटा-सैंपल (सारणी 4) में अपेक्षाकृत कम हैं।

V. मॉडल

अधि-विश्लेषण निष्कर्षों को एकीकृत करने के उद्देश्य से व्यक्तिगत अध्ययनों के सांख्यिकीय विश्लेषण को संदर्भित करता है। यह शोधकर्ताओं को संपूर्ण तथ्यात्मक साहित्य का तात्पर्य गहराई से समझाने में मदद करता है। मेटा-रिग्रेशन संभावित प्रकाशन पूर्वाग्रह को नियंत्रित करने के लिए एक प्रभावी उपकरण है जो तब होता है जब शोधकर्ता सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण निष्कर्षों की रिपोर्ट करते हैं (कार्ड और क्रुएगर, 1995)।

प्रकाशन पूर्वाग्रह को शामिल करने के लिए, प्रत्येक अध्ययन को एक प्रभाव आकार, अर्थात, एफटीई से संबंधित गुणांक और संबंधित मानक त्रुटियों की रिपोर्ट करनी चाहिए। चूंकि टी-सांख्यिकी की गणना संबंधित मानक त्रुटि के साथ गुणांक को विभाजित करके की जाती है, जब मानक त्रुटि अधिक होती है, तो शोधकर्ता सांख्यिकीय महत्व स्थापित करने के लिए एक बड़े गुणांक की खोज कर सकता है। इससे गुणांक और मानक त्रुटि के बीच सकारात्मक संबंध बनेगा। यह संबंध प्रकाशन पूर्वाग्रह को नियंत्रित करने के लिए एक मानक एफएटी-पीईटी (फ़नल-असममिति परीक्षण-सटीक प्रभाव परीक्षण) विनिर्देश में तैयार किया गया है (स्टेनली और डौकुलियागोस, 2012)। एफटीई पर मानक त्रुटि और गुणांक के बीच संबंध को दर्शाने वाले एफएटी-पीईटी मॉडल को निम्नानुसार दर्शाया जा सकता है:

$$EffectSize_i = B_0 + B_1 SE_i + \varepsilon_i \qquad ...(1)$$

समीकरण 1 में, B1SEi प्रकाशन पूर्वाग्रह का औसत अनुमान है। एफएटी परीक्षण प्रकाशन पूर्वाग्रह की पहचान करने का पारंपरिक तरीका है, H0: B1= 0. संभावित प्रकाशन पूर्वाग्रह को नियंत्रित करने के बाद, पैरामीटर B0 उत्पादकता का निष्पक्ष अनुमान बन जाता है। H0: B0 = 0 का परीक्षण यह पहचानने के लिए एक वैध तरीका प्रदान करता है कि प्रकाशन पूर्वाग्रह को नियंत्रित करने के बाद कोई वास्तविक तथ्यात्मक प्रभाव है या नहीं। इसे अग्रगमन प्रभाव परीक्षण भी कहा जाता है। इसके अलावा, स्टेनली और डौकुलियागोस (2014) का सुझाव है कि यदि समीकरण (1) में B0 महत्वपूर्ण है, तो मानक त्रुटि (पीईईएसई) अनुमानक के साथ परिशुद्धता-प्रभाव अनुमान का उपयोग करके वास्तविक प्रभाव का बेहतर अनुमान लगाया जाएगा जो एसई वर्ग पर निर्भर करता है। तथ्यात्मक विनिर्देश (1) में, हम मॉडरेटर चर के लिए अतिरिक्त नियंत्रण करते हैं। चूँकि प्रत्येक अनुमान की मानक त्रुटियाँ ज्ञात हैं, समीकरण 1 का अनुमान भारित न्यूनतम वर्ग (डब्ल्यूएलएस) का उपयोग करके लगाया जा सकता है।

उत्पादकता अनुमान स्वतंत्र नहीं हैं क्योंकि अध्ययन एक ही डेटा से एक से अधिक अनुमान की रिपोर्ट करते हैं। इस प्रकार, हम मानक त्रुटियों (नेल्सन 2014; पेन और हू 2018) के बीच सहसंबंध को नियंत्रित करने के लिए क्लस्टर मानक त्रुटि का उपयोग करते हैं। हालाँकि, हमारे पास केवल 19 अध्ययन हैं, इसलिए 19 क्लस्टर, जिससे क्लस्टर एसई में छोटे नमूना पूर्वाग्रह पैदा होते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए, हम रैखिक प्रतिगमन के लिए छोटे-नमूना सुधारों के साथ क्लस्टर-मजबूत विचरण अनुमानकों का उपयोग करते हैं (टाइज़लर और अन्य 2017)।

सारणी 5 : पूर्ण नमूने के लिए एफएटी-पीईटी और पीईईएसई

	एफएटी-पीईटी	पीईईएसई	एफएटी-पीईटी ड्ब्ल्यूएलएस – सुधार	पीईईएसई ड्ब्ल्यूएलएस – सुधार
	प्रभाव का आकार	प्रभाव का आकार	प्रभाव का आकार	प्रभाव का आकार
एस.ई.	0.121 (0.32)		0.085 (0.19)	
एस.ई. स्क्वायर		-0.722 (-0.58)		-0.722 (-0.53)
अचर	0.0852 (0.54)	0.0905 (0.55)	0.087 (0.501)	0.0905 (0.51)
एन	304	304	304	304

टी- आँकड़े कोष्ठक में हैं।
* पी < 0.05, ** पी < 0.01, ***पी < 0.001

VI. परिणाम

सारणी 5 मॉडरेटर चर जोड़े बिना पूरे नमूने के लिए एफएटी - पीईटी और पीईईएसई परिणाम देती है। हमने पाया कि एफएटी परीक्षण कोई प्रकाशन पूर्वाग्रह नहीं दर्शाता है क्योंकि एसई का गुणांक सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। हमने पाया कि उत्पादकता पर एफटीई के निष्पक्ष प्रभाव का हमारा अनुमान भी सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, जो दर्शाता है कि उत्पादकता पर एफटीई का कोई तथ्यपरक प्रभाव नहीं है। क्लस्टर मानक त्रुटि के लघु नमूना पूर्वाग्रह को ठीक करने के बाद भी हमारे परिणाम वही रहते हैं। सारणी 6 से पता चलता है कि यूरोपीय नमूने के लिए हालांकि कोई प्रकाशन पूर्वाग्रह नहीं है, एफटीई का श्रम उत्पादकता पर थोड़ा महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

सारणी 7 में, हम अन्य मॉडरेटर चर जोड़ते हैं। श्रम उत्पादकता रोजगार संविदा की प्रकृति के अलावा कई चर से प्रभावित होती है। इसलिए, किसी भी गलत विशिष्टता पूर्वाग्रह से बचने के लिए मॉडरेटर चर को समीकरण (1) में जोड़ा जाता है। मॉडरेटर चर जोड़ने के बाद, सारणी 7 से पता चलता है कि श्रम उत्पादकता पर एफटीई का औसत प्रभाव 0.81 है, जो पूर्ण नमूने में 0.1 प्रतिशत के स्तर पर महत्वपूर्ण है। यूरोपीय नमूने में, श्रम उत्पादकता पर एफटीई का औसत प्रभाव 0.85 के गुणांक के साथ मामूली रूप से महत्वपूर्ण है। क्लस्टर्ड एसई के छोटे नमूना पूर्वाग्रह को सही करने के बाद, हमें इस प्रभाव में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं मिला। उदाहरण के लिए, पूर्ण नमूने के लिए गुणांक मामूली रूप से बढ़कर 1.03 हो जाता है, जबकि यूरोपीय नमूने के

सारणी 6 : यूरोपीय नमूने के लिए एफएटी-पीईटी और पीईईएसई

	एफएटी-पीईटी	पीईईएसई	एफएटी-पीईटी ड्ब्ल्यूएलएस – सुधार	पीईईएसई ड्ब्ल्यूएलएस – सुधार
	प्रभाव का आकार	प्रभाव का आकार	प्रभाव का आकार	प्रभाव का आकार
एस.ई.	-0.0647 (-0.17)		-0.072 (-0.14)	
एस.ई. स्क्वायर		0.411 (0.63)		0.411 (0.52)
अचर	-0.0838 (-2.11)	-0.0868* (-2.21)	-0.0838* (-1.97)	-0.0868* (-2.08)
एन	226	226	226	226

टी- आँकड़े कोष्ठक में हैं।
* पी < 0.05, ** पी < 0.01, ***पी < 0.001

सारणी 7 : परिणाम

	पूर्ण नमूना	यूरोपीय नमूना	पूर्ण नमूना ड्ब्ल्यूएलएस – सुधार	यूरोपीय नमूना ड्ब्ल्यूएलएस – सुधार
	प्रभाव का आकार	प्रभाव का आकार	प्रभाव का आकार	प्रभाव का आकार
एसई	-1.095** (-3.11)	-1.210** (-3.00)	-1.009** (-3.15)	-1.099** (-2.89)
डेटा का प्रकार	-0.571*** (-4.36)	-0.611*** (-4.11)	-0.571*** (-3.53)	-0.602*** (-3.43)
सर्वेक्षण	– –	-0.326* (-2.51)		
अनुमान	-0.0263 (-1.33)	-0.0212 (-1.06)	-0.025 (-1.25)	-0.02 (-0.99)
श्रम उत्पादकता (सापेक्ष माप)	-0.0426 (-0.25)	-0.0564 (-0.35)	-0.113 (-0.49)	-0.112 (-0.22)
प्रति श्रमिक श्रम उत्पादकता का माप	0.00922 (0.93)	0.00802 (0.84)	0.007 (0.7)	0.007 (0.7)
अन्य फर्मों की तुलना में श्रम उत्पादकता	-0.00652 (-0.08)	-0.0170 (-0.21)		
प्रकाशित अध्ययन	0.0465 (1.07)	0.0489 (1.23)	-0.024 (-0.3)	-0.021 (0.80)
फर्म का आकार	-0.0981 (-2.06)	-0.108* (-2.28)	-0.096 (-1.37)	-0.103 (-1.47)
फर्म की आयु	– –	– –	0.263* (1.45)	0.292* (1.98)
ट्रेड यूनियन घनत्व	-0.0127 (-0.77)	-0.00875 (-0.48)	-0.082 (-0.911)	-0.0084 (-0.91)
सेक्टर डमी	-0.0333* (-2.44)	-0.0342* (-2.75)	0.01 (0.2)	0.006 (0.12)
निवेश	0.121 (1.54)	0.119 (1.66)	0.158 (1.21)	0.154 (1.28)
प्रशिक्षण	-0.580*** (-4.80)	-0.611*** (-4.63)	-0.575** (-3.05)	-0.601** (-3.17)
शिक्षा	0.229** (2.93)	0.247** (3.04)	0.206 (2.2)	0.220 (2.4)
ब्लू कॉलर	0.110 (1.49)	0.108 (1.59)	0.053 (0.58)	0.053 (0.58)
जेंडर	0.293* (2.51)	– –		
देश	0.0273 (1.15)	0.0327 (1.31)	-0.08 (1.6)	-0.076 (1.52)
क्षेत्र	-0.329* (-2.14)	– –	-0.302** (-1.68)	
वर्ष	0.0141 (0.39)	0.00951 (0.27)	0.0141 (0.29)	0.00951 (0.20)
अचर	0.811*** (14.30)	0.859* (2.60)	1.027*** (5.00)	0.695* (2.07)
एन	304	226	304	226

टी- आँकड़े कोष्ठक में हैं।
* पी < 0.05, ** पी < 0.01, ***पी < 0.001

लिए यह मामूली रूप से गिरकर 0.7 हो जाता है। इस प्रकार, उन देशों के तथ्यात्मक साक्ष्यों के अधि-विश्लेषण से पता चलता है कि सभी अध्ययन विशिष्टताओं को शामिल करने के बाद, औसत श्रम उत्पादकता पर एफटीई का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह इस परिकल्पना का समर्थन करता है कि, असममित जानकारी की उपस्थिति में, एफटीई नियोजकों को उत्पादक श्रमिकों की पहचान करने में मदद करता है और यह श्रमिकों को अधिक प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करता है ताकि वे फर्म में स्थायी कर्मचारी बन

सकें (वांग और वीस 1988; गेरफिन और अन्य 2005; गश 2008)।

क्लस्टर्ड एसई के छोटे नमूना पूर्वाग्रह को सही करने के बाद, हम पाते हैं कि पूर्ण नमूने में, अन्य अध्ययन विशिष्टताएं, जैसे प्रशिक्षण और डेटा के प्रकार को नियंत्रित करना, और जिस क्षेत्र में अध्ययन आयोजित किया जाता है, वह भी श्रम उत्पादकता पर एफटीई प्रभाव के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। श्रम उत्पादकता पर एफटीई का औसत प्रभाव काफी कम हो जाता है जब अध्ययन को उनके संबंधित अनुमानों में प्रशिक्षण के लिए स्वतंत्र रूप से नियंत्रित किया जाता है। यह अध्ययनों में परिवर्तनीय 'प्रशिक्षण' द्वारा बनाए गए संभावित सकारात्मक छोड़े गए परिवर्तनीय पूर्वाग्रह के कारण हो सकता है, जो इसे स्वतंत्र रूप से नियंत्रित नहीं करता है, इस प्रकार, श्रम उत्पादकता पर एफटीई के औसत प्रभाव को बढ़ाता है। कुछ मामलों में, एफटीई पर कर्मचारी प्रशिक्षु के रूप में शामिल होते हैं या कुछ मामलों में कंपनियां एफटीई को अपने भविष्य के उत्पादक कर्मचारियों को प्रशिक्षित/स्क्रीन करने के लिए एक तंत्र के रूप में मानती हैं (वांग और वीस 1988; गेरफिन और अन्य 2005; गश 2008)। हमने पाया कि पैनल डेटा को नियोजित करने वाले अध्ययनों ने क्रॉस सेक्शन डेटा को नियोजित करने वाले अध्ययनों की तुलना में श्रम उत्पादकता पर एफटीई के काफी कम प्रभाव की सूचना दी है। यह क्रॉस सेक्शन डेटा की तुलना में पैनल डेटा में उच्च सूचना सामग्री के कारण हो सकता है। क्षेत्र, एफटीई और श्रम उत्पादकता के बीच संबंध को प्रभावित करता है क्योंकि देश अपने बाजार नियमों और संस्थानों के संदर्भ में भिन्न हो सकते हैं और इस प्रकार, ये संबंध प्रभावित हो सकते हैं।

निष्कर्ष

इस अध्ययन में, हमने अंतरराष्ट्रीय अनुभव के आधार पर श्रम उत्पादकता पर एफटीई के प्रभाव को समझने के लिए एक मेटा-रिग्रेशन विश्लेषण का उपयोग किया। एक ओर, एफटीई श्रम उत्पादकता को खराब कर सकता है क्योंकि यह फर्मों को निश्चित अवधि के श्रमिकों पर निवेश करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है; दूसरी ओर, एफटीई को स्थायी संविदा में बदलने की प्रत्याशा में, कर्मचारी अधिक प्रयास कर सकते हैं जिससे उनकी उत्पादकता में सुधार होगा। हम, इस संबंध के निष्पक्ष औसत अनुमान पर पहुंचने के लिए श्रम उत्पादकता और एफटीई के बीच संबंधों पर मौजूदा तथ्यात्मक साहित्य को संश्लेषित करते हैं।

हमारे नतीजे बताते हैं कि एफटीई का श्रम उत्पादकता पर सकारात्मक और महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। हमारे अधि-विश्लेषण से पता चला कि प्रकाशन पूर्वाग्रह को नियंत्रित करते हुए, प्रभाव का आकार पूरे नमूने के लिए 1.03 और यूरोपीय नमूने के लिए 0.7 था। श्रम उत्पादकता पर एफटीई का सकारात्मक प्रभाव इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि एफटीई उत्पादक कर्मचारियों की पहचान करने के लिए एक स्क्रीनिंग तंत्र के रूप में कार्य कर सकता है। इसके अलावा, यदि इन संविदाओं को स्थायी संविदाओं में बदल दिया जाता है, तो श्रमिकों को और अधिक प्रयास करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है (वांग और वीस 1988; गेरफिन और अन्य 2005; गश 2008)। परिणामों के आधार पर, औद्योगिक संबंध संहिता के तहत एफटीई की शुरूआत से भारत में श्रम उत्पादकता में सुधार की उम्मीद की जा सकती है, जो वर्तमान में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कम है। हालाँकि, प्रभाव का सटीक गुरुत्व भारतीय श्रम बाजार की विशिष्टताओं पर निर्भर करेगा। डेटा की अनुपलब्धता के कारण भारत पर केंद्रित अध्ययन फिलहाल संभव नहीं है। इसलिए, इस पेपर के परिणाम इस कमी को भरने के लिए अंतरराष्ट्रीय अनुभव के आधार पर एक व्यापक दिशा प्रदान करते हैं।

संदर्भ :

Abowd, J. M., Kramarz, F., & Margolis, D. N. (1999). Minimum wages and employment in France and the United States.

Addessi, W. (2011). Labor contracts and productivity dynamics. In XXVI National Conference of Labour Economics, Milan, September (pp. 15-16).

Aghion, P., Burgess, R., Redding, S., & Zilibotti, F. (2003). *The unequal effects of liberalization: theory and evidence from India.* LSE mimeo. London, UK: LSE.

Ahsan, A., & Pagés, C. (2009). Are all labor regulations equal? Evidence from Indian manufacturing. Journal of Comparative Economics, 37(1), 62-75.

Arulampalam, W., & Booth, A. L. (1998). Training and labour market flexibility: is there a trade-off?. British Journal of Industrial Relations, 36(4), 521-536.

Baek, J., & Park, W. (2018). Firms' adjustments to employment protection legislation: Evidence from South Korea. ILR Review, 71(3), 733-759.

Besley, T., & Burgess, R. (2004). Can labor regulation hinder economic performance? Evidence from India. *The Quarterly journal of economics*, *119*(1), 91-134.

Blanchard, O., & Wolfers, J. (2000). The role of shocks and institutions in the rise of European unemployment: the aggregate evidence. The Economic Journal, 110(462), C1-C33.

Booth, A. L., Francesconi, M., & Frank, J. (2002). Temporary jobs: stepping stones or dead ends?. *The economic journal*, *112*(480), F189-F213.

Botero, J. C., Djankov, S., Porta, R. L., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. (2004). The regulation of labor. The Quarterly Journal of Economics, 119(4), 1339-1382.

Brancaccio, E., De Cristofaro, F., & Giammetti, R. (2020). A meta-analysis on labour market deregulations and employment performance: no consensus around the IMF-OECD consensus. Review of Political Economy, 32(1), 1-21.

Caballero, R. J., Cowan, K., Engel, E., & Micco, A. (2004). Effective labor regulation and microeconomic flexibility.

Cappellari, L., Dell'Aringa, C., & Leonardi, M. (2012). Temporary employment, job flows and productivity: A tale of two reforms. The Economic Journal, 122(562), F188-F215.

Card, D., & Krueger, A. B. (1995). Time-series minimum-wage studies: a meta-analysis. The American Economic Review, 85(2), 238-243.

Castellani, F., Lotti, G., & Obando, N. (2020). Fixed or open-ended? Labor contract and productivity in the Colombian manufacturing sector. Journal of Applied Economics, 23(1), 199-223.

Currie, J., & Fallick, B. (1993). The minimum wage and the employment of youth: evidence from the NLSY.

de Linde Leonard, M., & Stanley, T. D. (2020). The wages of mothers' labor: A meta-regression analysis. *Journal of Marriage and Family*, *82*(5), 1534-1552.

De Linde Leonard, Megan, T. D. Stanley, and Hristos Doucouliagos. "Does the UK minimum wage reduce employment? A meta-regression analysis." British Journal of Industrial Relations 52.3 (2014): 499-520.

Dolado, J. J., Ortigueira, S., & Stucchi, R. (2012). Does dual employment protection affect TFP? Evidence from Spanish manufacturing firms.

Gash, V. (2008). Bridge or trap? Temporary workers' transitions to unemployment and to the standard employment contract. European Sociological Review, 24(5), 651-668.

Gerfin, M., Lechner, M., & Steiger, H. (2005). Does subsidised temporary employment get the unemployed back to work? Aneconometric analysis of two different schemes. Labour economics, 12(6), 807-835.

Heckman, J. J., & Pages, C. (2003). Law and employment: Lessons from Latin America and the Caribbean.

Holmes, T. J. (1998). The effect of state policies on the location of manufacturing: Evidence from state borders. Journal of political Economy, 106(4), 667-705.

Hospido, L., & Moreno-Galbis, E. (2015). The Spanish productivity puzzle in the great recession.

Hospido, L., & Moreno-Galbis, E. (2015). The Spanish productivity puzzle in the great recession.

Kugler, A. D. (2004). The effect of job security regulations on labor market flexibility. Evidence from the Colombian Labor Market Reform. In Law and

Employment: Lessons from Latin America and the caribbean (pp. 183-228). University of Chicago Press.

Kugler, A., & Kugler, M. (2009). Labor market effects of payroll taxes in developing countries: Evidence from Colombia. *Economic development and cultural change*, *57*(2), 335-358.

Lazear, E. P. (1990). Job security provisions and employment. The Quarterly Journal of Economics, 105(3), 699-726.

Lucidi, F. (2010, September). Labour market flexibility and productivity growth: new evidence from firm-level data. In XXIII National Conference of Labour Economics, Brescia (pp. 11-12).

Micco, A., & Pagés, C. (2006, May). The economic effects of employment protection laws. In *IZA/ The World Bank Conference on employment and development* (pp. 25-27).

OECD (2005) OECD economic surveys: Spain 2005. OECD, Paris

Ortega, B., & Marchante, A. J. (2010). Temporary contracts and labour productivity in Spain: a sectoral analysis. Journal of Productivity analysis, 34(3), 199-212.

Sanyal, P., & Menon, N. (2005). Labor disputes and the economics of firm geography: A study of domestic investment in India. Economic Development and Cultural Change, 53(4), 825-854.

Taymaz, E. (2002, November). Are small firms really less productive? An analysis of productivity differentials and firm dynamics. In International Workshop on" The Post-entry Performance of Firms: Technology, Growth and Survival", University of Bologna.

Vidal, M., & Tigges, L. M. (2009). Temporary employment and strategic staffing in the manufacturing sector. Industrial Relations: A Journal of Economy and Society, 48(1), 55-72.

Wang, R., & Weiss, A. (1998). Probation, layoffs, and wage-tenure profiles: A sorting explanation. Labour Economics, 5(3), 359-383.

भारत में रियल्टी क्षेत्र की गतिविधि का एक समग्र संकेतक

दीपक आर चौधरी, आकांक्षा हांडा, प्रियंका उप्रेती और सौरभ घोष ^

रियल्टी क्षेत्र भारत में रोजगार सृजन, भौतिक रूप में बचत, देश के जीवीए में योगदान और यहां तक कि प्रारंभिक चेतावनी संकेतक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि, कम आवृत्ति वाले पारंपरिक डेटा और डेटा रिलीज में अंतराल नीति-निर्माण में इसके सक्रिय उपयोग को मुश्किल बनाते हैं। हमारा उद्देश्य विभिन्न प्रकार के उच्च आवृत्ति संकेतकों और एक गतिशील कारक मॉडल का उपयोग करते हुए एक रियल्टी क्षेत्र गतिविधि संकेतक का निर्माण करके इस चुनौती को पाटना है। इस संकेतक को देखते हुए, हम आर्थिक गतिविधि पर रियल्टी क्षेत्र के विकास के प्रभाव, व्यापार चक्रों में इसके पहले और दूसरे दौर के प्रभावों को निर्धारित करते हैं।

परिचय

रियल्टी क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह क्षेत्र कृषि क्षेत्र के बाद, कुशल और अकुशल श्रमिकों (अनौपचारिक श्रमिकों का 84 प्रतिशत हिस्सा) दोनों के लिए दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करता है। इसके अलावा, रियल्टी क्षेत्र देश के कई हिस्सों (जीओआई, 2021) से आप्रवासी श्रमिकों के एक बड़े हिस्से के लिए रोजगार के अवसर पैदा करता है। रियल्टी क्षेत्र प्रवाह विरुद्ध (अपस्ट्रीम) तथा प्रवाह अभिमुख (डाउनस्ट्रीम) उद्योगों से भी जुड़ा हुआ है, जिससे उन पर दूसरे दौर का सकारात्मक स्पिलओवर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा, रियल्टी क्षेत्र[1] भौतिक रूप में बचत के लिए एक आवश्यक अवसर प्रदान करता है। भारत में औसत परिवार अचल संपत्ति में अपनी कुल संपत्ति का 77 प्रतिशत हिस्सा रखता है जिसमें आवासीय उद्देश्यों के लिए निर्माण, कृषि और गैर-कृषि गतिविधियों, मनोरंजन सुविधाओं, ग्रामीण और शहरी भूमि आदि शामिल हैं। (रामादुरई, 2017)। भारतीय परिवारों द्वारा रियल एस्टेट होल्डिंग्स का उच्च स्तर सामान्य खपत आवश्यकताओं के अलावा अचल संपत्ति निवेश की उनकी आवश्यकता का संकेत दे सकता है।

इसी तरह की उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) के उपलब्ध साहित्य से पता चलता है कि निर्माण गतिविधियों का आर्थिक विकास के साथ सकारात्मक संबंध है, हालांकि, यह एक समकालीन, अग्रणी या विलंबित संबद्धता हो सकती है। उदाहरण के लिए, बर्क और बिसेन (2017) ने निर्माण क्षेत्र में निवेश और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि के बीच संबंधों की जांच की और पाया कि पहला आर्थिक विकास की ओर अग्रेसर है। अहमद एट अल (2019) ने चीनी अर्थव्यवस्था के लिए निर्माण क्षेत्र और शहरीकरण, ऊर्जा खपत, आर्थिक विकास और कार्बन उत्सर्जन के पारस्परिक संबन्धों की जांच की और पाया कि निर्माण क्षेत्र शहरीकरण की ओर अग्रेसर है, जो आर्थिक विकास का एक प्रमुख संचालक है। हंग एट अल (2019) ने हांगकांग के लिए एक बहु-क्षेत्रीय इनपुट-आउटपुट सारणी का उपयोग करके अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन के साथ निर्माण क्षेत्र के संबंधों का विश्लेषण किया और इसी तरह के परिणाम पाए।

भारतीय संदर्भ में, आर्थिक विकास के साथ निर्माण गतिविधियों के संबंधों की जांच करनेवाला सीमित साहित्य मौजूद है। तिवारी (2011) ने निर्माण गतिविधि और आर्थिक विकास के बीच संबंधों का अध्ययन किया और आर्थिक विकास और निर्माण गतिविधियों के बीच द्विदिशात्मक कार्य-कारण के अस्तित्व को पाया। कुमार और चौधरी (2014) ने जीडीपी पर आवास निवेश के प्रभाव की अनुभवजन्य जांच की और आवास, जीडीपी और रोजगार के बीच एक मजबूत सकारात्मक सहसंबंध पाया। उत्पादन कार्य आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए, मलिक और महालिक (2010) ने आर्थिक विकास पर निर्माण का सकारात्मक प्रभाव पाया।

चूंकि रियल्टी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा और इसके प्रतिक्रियात्मक प्रभाव भारत में अनौपचारिक क्षेत्रों से संबंधित हैं, इसलिए इस क्षेत्र में डेटा उपलब्धता के मुद्दे पूर्व-निर्धारित नीति अनुसंधान के लिए काफी चुनौती पेश करते हैं। हम पारंपरिक और अपरंपरागत डेटा स्रोतों दोनों का उपयोग करके इस अंतर का पता लगाना चाहते हैं। इस क्रम में, हम उपलब्ध उच्च आवृत्ति

^ लेखक आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (डीईपीआर), भारतीय रिजर्व बैंक से हैं। इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और जरूरी नहीं कि वे बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व करें।

[1] अध्ययन में, अचल संपत्ति, आवास और निर्माण का परस्पर उपयोग किया जा रहा है।

संकेतकों के प्रारंभिक मूल्यांकन के साथ शुरू करते हैं, जो भारत में रियल एस्टेट क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं। दूसरा, हम इन शृंखलाओं में अंतर्निहित एक अव्यक्त सामान्य कारक खोजने का प्रयास करते हैं जो रियल्टी क्षेत्र के विकास का प्रतिनिधित्व करते हैं और आवास (डीएफएच) के लिए एक गतिशील कारक का निर्माण करते हैं, जिसका उपयोग नीति अनुसंधान के लिए किया जा सकता है। अंत में, हम नीति-अनुसंधान में डीएफएच की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने के लिए डीएफएच, निर्माण सकल मूल्य वर्धित (जीवीए), और निर्माण के जीवीए नेट का उपयोग करके अनुभवजन्य परीक्षण करते हैं।

शेष अध्ययन निम्नानुसार आयोजित किया गया है: खंड II पारंपरिक और अपरंपरागत उच्च आवृत्ति डेटा की मदद से रियल्टी क्षेत्र में गहरा अध्ययन करता है। खंड III डेटा मात्रा में कमी, नाउकास्टिंग और अन्य अनुभवजन्य निष्कर्षों की व्याख्या करता है। खंड IV अध्ययन का निष्कर्ष निकालता है और नीतिगत निहितार्थों पर चर्चा करता है।

II. डेटा और कार्यप्रणाली

भारत एक सेवा संचालित अर्थव्यवस्था है, जिसमें सेवा क्षेत्र का कुल जीवीए में 60 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है। कुल जीवीए में लगभग 8 प्रतिशत का योगदान करने वाले निर्माण क्षेत्र में सबसे अधिक 50.3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, क्योंकि 2020-21 की पहली तिमाही में मुख्य रूप से लॉकडाउन और महामारी अवधि (एमओएसपीआई, 2020) के दौरान उपभोक्ता की निष्क्रियता के कारण बिक्री और नए लॉन्च में गिरावट आई। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के उपभोक्ता पिरामिड डेटाबेस से संकेत मिलता है कि निर्माण क्षेत्र के लिए बेरोजगारी के आंकड़े लॉकडाउन के दौरान विभिन्न उद्योगों में सबसे अधिक थे। सेवाओं के एक अन्य घटक यानी वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाओं में 2019-20 की समान अवधि की तुलना में 2020-21 की पहली और दूसरी तिमाही में गिरावट देखी गई।

हालांकि, पारंपरिक डेटासेट के साथ दो समस्याएं हैं: (ए) यह त्रैमासिक आवृत्ति का है, और (बी) समग्र आर्थिक आंकड़ों पर रियल्टी क्षेत्र में प्रतिकूल आघात या मंदी के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव को मापना मुश्किल है, विशेष रूप से मांग पक्ष की तुलना में आपूर्ति पक्ष पर प्रभाव की पहचान करने के लिए। इसलिए, हमने उपलब्ध उच्च आवृत्ति संकेतकों की एक शृंखला पर विचार किया जो भारत में रियल्टी क्षेत्र से संबंधित हैं। इनमें आवास की कीमतें, क्रेडिट और रियल एस्टेट कंपनियों के मुनाफे जैसे चर शामिल हैं जो ज्यादातर सीईआईसी से प्राप्त होते हैं।

उपलब्ध कॉर्पोरेट कार्यनिष्पादन डेटा (सीएमआईई प्रोवेस डेटासेट से) और शेयर बाजार सूचकांक (ब्लूमबर्ग डेटा) मिश्रित प्रमाण दर्शाते हैं। जहां पूर्व में गिरावट के संकेत दिख रहे हैं, वहीं रियल्टी शेयर सूचकांक कोविड-19 से पूर्व स्तर को पार कर गए हैं, जो इस क्षेत्र के लिए भविष्य के वादों का संकेत देते हैं। इसके अलावा, हमने सीमेंट और स्टील उत्पादन (सीईआईसी डेटाबेस) जैसे उच्च आवृत्ति चर शामिल किए, जो अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम आपूर्ति शृंखला लिंकेज के माध्यम से निर्माण क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं। चूंकि आईआईपी कोर[2] में स्टील और सीमेंट का संयुक्त भारांश केवल 23 प्रतिशत है और अन्य उद्योग यानी बिजली, कोयला और कच्चा तेल भी शामिल हैं जिनका रियल्टी क्षेत्र पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, इसलिए आईआईपी कोर का उपयोग एक अलग चर के रूप में किया जाता है। इसके अलावा, चूंकि इनमें से कई थोक इनपुट हैं और आमतौर पर रेलवे द्वारा परिवहन किए जाते हैं, इसलिए हमने अपने विश्लेषण में रेलवे माल ढुलाई के विभिन्न घटकों को भी शामिल किया है। ऐसा करने में, हमने महसूस किया कि प्रति किमी कुल माल ढुलाई और माल ढुलाई (टन) के काफी अलग-अलग चक्र हैं (अनुबंध चार्ट 1.बी)। इसलिए, हमने अपने विश्लेषण के लिए दोनों को बनाए रखना पसंद किया।

अंत में, इन्फोटेक क्रांति और शेयर बाजार की गतिविधियों को देखते हुए, हम अपने विश्लेषण में कुछ अपरंपरागत चर का उपयोग करते हैं। इनमें रियल्टी इंडेक्स (व्यापक बाजार उतार-चढ़ाव लिए समायोजित) और रियल्टी क्षेत्र से संबंधित गूगल सर्च प्रवृत्ति शामिल हैं। चार्ट 1 समग्र अचल संपत्ति खोज प्रवृत्ति संकेतक में प्रवृत्तियों को दर्शाता है जिसकी गणना वाणिज्यिक संपत्ति (अचल संपत्ति, वाणिज्यिक संपत्ति, आवासीय संपत्ति, 99 एकड़, मैजिकब्रिक्स, नो ब्रोकर) से संबंधित कुछ कीवर्ड की खोज

[2] आईआईपी कोर आठ प्रमुख उद्योगों अर्थात् बिजली, इस्पात, रिफाइनरी उत्पाद, कच्चा तेल, कोयला, सीमेंट, प्राकृतिक गैस और उर्वरकों के उत्पादन का एक सूचकांक है।

चार्ट 1: समग्र खोज प्रवृत्ति संकेतक (सूचकांक मान: 0-100)

स्रोत : गूगल की कार्यप्रणाली और लेखकों की गणना।

प्रवृत्ति के भारित औसत को लेकर की जाती है, भार प्रत्येक कीवर्ड की खोज प्रवृत्ति के विचरण का व्युत्क्रम है। यह खोज प्रवृत्ति उस समयावधि के दौरान खोजों की कुल संख्या के सापेक्ष किसी विशेष कीवर्ड वाली खोजों की कुल संख्या के अनुपात को इंगित करती है, जिसे बाद में 0-100 के बीच सामान्य किया जाता है।

हालांकि ये चर अल्पावधि में अलग-अलग उतार-चढ़ाव का संकेत देते हैं, हमारे विश्लेषण से संकेत मिलता है कि एक छिपा हुआ सामान्य कारक हो सकता है जो लंबे समय में सभी रियल्टी क्षेत्र से संबंधित चर को चलाता है। निम्नलिखित अनुभवजन्य खंड में, हम चर की एक चुनिंदा सूची के आधार पर इस सामान्य कारक को समझने की मंशा रखते हैं।

III. अनुभवजन्य निष्कर्ष

हम चर के उपरोक्त सेट का विश्लेषण करते हैं जो व्यापार चक्रों के विभिन्न चरणों में रियल्टी क्षेत्र से संबंधित हैं। यहां, हमने वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के बाद अर्थात् 2009 के बाद की अवधि पर ध्यान केंद्रित किया है। अध्ययन की अवधि मार्च 2009 से दिसंबर 2020 तक है। हमने निर्माण क्षेत्र जीवीए और समग्र जीडीपी के साथ उपर्युक्त चर के सहसंबंध का मूल्यांकन किया और गतिशील सहसंबंधों की गणना की।

III.1. जीडीपी विकास चक्र और चुनिंदा आवास चर की वृद्धि दर की डेटिंग

भादुरी एट अल. (2020) के बाद, हम जीडीपी विकास के पहले और चौथे चतुर्थक, यानी, सबसे कम 25 प्रतिशत और उच्चतम 25 प्रतिशत विकास दर का उपयोग करके पिछले दो दशकों में जीडीपी विकास चक्र की पहचान करते हैं। इसके अलावा, हम जीडीपी चक्र में महत्वपूर्ण बिंदुओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए कुछ सेंसर नियम लागू करते हैं। हम निर्माण से संबंधित चर, अर्थात् स्टील, सीमेंट और रेलवे माल ढुलाई में एक सामान्य प्रवृत्ति / सह-उतार-चढ़ाव का निरीक्षण करते हैं। अन्य चर, अर्थात् आवास की कीमतें, स्टॉक सूचकांक (समायोजित रियल्टी इंडेक्स) और आवास ऋण ज्यादातर प्रो-साइक्लिकल (अनुबंध चार्ट 1.ए) प्रतीत होते हैं। गूगल सर्च प्रवृत्ति सूचकांक ने भी व्यापार चक्र के चरणों से विचलन दिखाया है जो मंदी के चरणों के दौरान वास्तविक क्षेत्र से संबंधित शब्दों की अधिक खोज तीव्रता को दर्शाता है।

इसके बाद, हम अपने तिमाही-दर-तिमाही (क्यू-ओ-क्यू) निर्माण-जीवीए की मौसमी रूप से समायोजित वार्षिक वृद्धि का सहसंबंध विश्लेषण करते हैं, क्योंकि यह अचल संपत्ति क्षेत्र में उत्पादन के लिए एक अधिक प्रातिनिधिक संकेतक है (सारणी 1)। यह अभ्यास ति2:2009 से ति4:2020 की अवधि के लिए

आयोजित किया जाता है, जिसमें निर्माण जीवीए के विभिन्न लीड और अंतराल पर 46 अवलोकन होते हैं। चर का निर्माण जीवीए के साथ समकालीन ('सी'), लीडिंग ('एल +') या लैगिंग ('एल-') संबंध है। सारणी 1 से यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि इस्पात, सीमेंट उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) कोर, सेंसेक्स-समायोजित रियल्टी इंडेक्स और रेल माल ढुलाई निर्माण जीवीए के साथ उच्च समकालीन सहसंबंध प्रदर्शित करते हैं। आवास की कीमतें पिछले निर्माण जीवीए के साथ काफी सहसंबद्ध पाई गई हैं।

इन दो अभ्यासों से, पांच चर निर्माण जीवीए के साथ एक उच्च समकालीन संबंध पाए जाते हैं और एक चर के निर्माण जीवीए[3] के साथ कमजोर संबंध पाया जाता है। ये चर इस्पात, सीमेंट उत्पादन, आईआईपी कोर, रेल-माल ढुलाई, रेल-माल ढुलाई (टन) प्रति किलोमीटर, समायोजित रियल्टी इंडेक्स और आवास की कीमतें हैं, जिन्हें गतिशील कारक मॉडल (अनुबंध चार्ट 1.ए और 1.बी) में सामान्य कारक निकालने के लिए लिया गया था।

III.2 रियल्टी क्षेत्र के लिए गतिशील कारक

हम रियल्टी क्षेत्र से संबंधित प्रासंगिक चर का चयन करने के बाद रियल्टी क्षेत्र में आम प्रवृत्ति निकालने के लिए डेटा संकोचन तकनीक का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। हम प्रत्येक चर, अर्थात् इस्पात और सीमेंट उत्पादन, आईआईपी कोर, रेल-माल ढुलाई (प्रति कि.मी टन भी), समायोजित रियल्टी इंडेक्स, गूगल सर्च प्रवृत्ति सूचकांक और आवास कीमतों को उनके स्तरों के साथ लेते हुये, सेंसेक्स एक्स -12 का उपयोग करके उन्हें डी-सीजनलाइज्ड किया जाता है, जिसे बाद में मानकीकरण के लिए जेड-स्कोर में बदल दिया जाता है। चूंकि हम कई उच्च आवृत्ति संकेतकों से एक आम सहमति अंतर्निहित प्रवृत्ति को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए अलग-अलग होने से जानकारी का नुकसान हो सकता है। यह साहित्य के अनुरूप है (भादुरी एट

सारणी 1: निर्माण जीवीए के साथ चयनित चर का सहसंबंध

चर	निर्माण जीवीए (-टी) (लैगिंग संबंध)	निर्माण जीवीए (समकालीन संबंध)	निर्माण जीवीए (+टी) (अग्रणी संबंध)	टिप्पणियां
आवास ऋण	0.1336	-0.1094	-0.1127	कोई महत्वपूर्ण सहसंबंध नहीं
आवास ऋण (कोविड अवधि को छोड़कर)	-0.0086	-0.0676	0.1533	कोई महत्वपूर्ण सहसंबंध नहीं
आवास की कीमते	0.1433	-0.0078	-0.0907	कोई महत्वपूर्ण सहसंबंध नहीं
सेंसेक्स	-0.0723	0.2278	-0.0272	कोई महत्वपूर्ण सहसंबंध नहीं
आवास की किमाते	0.3462**	0.2344	-0.0579	एल- (कोविड अवधि को छोड़कर)
इस्पात उत्पादन	-0.3772**	0.9454**	-0.5187**	सी
सीमेंट उत्पादन	-0.3726**	0.9429**	-0.5016**	सी
आईआईपी कोर	-0.3343**	0.921**	-0.6141**	सी
गूगल खोज प्रवृत्ति सूचकांक	-0.2706	0.5524**	-0.3128**	सी
रियल्टी इंडेक्स	-0.0963	0.3373**	-0.2591	सी
रेल माल भाड़ा	-0.399**	0.9406**	-0.4636**	सी
रेल सीमेंट	-0.1506	-0.3677**	0.7448**	सी
समायोजित रियल्टी	-0.0918	0.3395**	-0.3655**	एल+/सी

नोट: प्रतीक *, **, *** उन मामलों को दर्शाते हैं जहां हम क्रमशः 10%, 5%, 1% महत्व स्तरों पर शून्य को अस्वीकार करते हैं। टिप्पणियों की संख्या: 46
स्रोत: लेखकों की गणना।

[3] कोविड-पूर्व अवधि के लिए निर्माण जीवीए के साथ चयनित चर का सहसंबंध अनुबंध सारणी 1.ए में सूचित किया गया है।

अल। सात चुने हुए चर का उपयोग करके एक गतिशील कारक मॉडल (डीएफएम) का अनुमान लगाकर प्रवृत्ति को प्राप्त किया जाता है। प्रक्रिया स्टॉक एंड वाटसन (1989) के अनुरूप है, जो एक "अनदेखे एकल सूचकांक" x_t. को निर्दिष्ट करता है। अवलोकन समीकरण ($y_t=Zx_t+\alpha+v_t$) में y_t होता है जो एक समय t पर आर्थिक संकेतकों का n×1 मैट्रिक्स है। राज्य विनिर्देश ($x_t=Bx_{t-1}+w_t$), y_t में सामान्य अंतर्निहित प्रवृत्ति को एकल-सूचकांक गतिशील कारक में निकालता है। इस विनिर्देश में, Z कारक लोडिंग (अनुबंध चार्ट 1.C) का प्रतिनिधित्व करता है और "α" एक ऑफसेट कारक को संदर्भित करता है।

अपेक्षित माध्य पद्धति[4] का उपयोग करके गतिशील कारक का अनुमान लगाने के बाद, हम सत्यापित करते हैं कि क्या डीएफएच सूचकांक एक वैकल्पिक डेटा स्रोत, यानी, प्रॉपटाइगर जो विभिन्न शहरों में बेची गई आवास इकाइयों की संख्या की रिपोर्ट करता है, के साथ भारत में आवास विकास का पता लगा सकता है । ऐसा प्रतीत होता है कि डीएफएच कुछ नीतिगत हस्तक्षेप चरणों जैसे सभी के लिए आवास, विमुद्रीकरण, रेरा (रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण) की शुरूआत आदि को छोड़कर आवास बाजार में देखे गए व्यापक रुझानों को पकड़ने में सक्षम है (चार्ट 2)। शहर-वार डेटा के सीमित अवलोकनों के कारण, हम कोई गहन अनुभवजन्य अनुमान नहीं लगा सके; हालांकि, बेची गई संबंधित शहर इकाइयों और 0.56 से 0.80 सकारात्मक (2017-18 के बाद) की सीमा में डीएफएच का सहसंबंध यह दर्शाता है कि डीएफएच सूचकांक आवास क्षेत्र की गतिविधियों को सटीक रूप से पकड़ रहा है।

इसके बाद, हम आर्थिक गतिविधियों और डीएफएच के संकेतकों के बीच एक ग्रेंजर कॉजलिटी टेस्ट करते हैं। कॉजलिटी के परिणाम इंगित करते हैं कि आवास क्षेत्र से आर्थिक गतिविधि के लिए एकतरफा कॉजेशन के सबूत हैं। संक्षिप्त रुप से, हम अनुलग्नक (सारणी 1.बी) में कॉजलिटी परिणामों की रिपोर्ट करते हैं और सीधे व्यापार चक्र विश्लेषण की ओर मुड़ते हैं, ताकि हम कुछ नीतिगत निष्कर्ष निकाल सकें। इसके लिए, हम एक ही व्यवसाय चक्र डेटिंग का उपयोग करते हैं और एक अपसाइकिल

[4] ईएम एल्गोरिथ्म एक पुनरावृत्ति प्रक्रिया का उपयोग करके अधिकतम संभावना अनुमान पाता है, जो मापदंडों के प्रारंभिक सेट θ1 से शुरू होता है, यह अव्यक्त चर के मूल्य की गणना करता है जो सशर्त θ1 पर है और फिर लॉग संभावना कार्य की गणना करता है। अगली पुनरावृत्ति के लिए, θ2 मान "argmax E{L(X/θ1 का उपयोग करके की गई गणना है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि लॉग संभावना में परिवर्तन पूर्व निर्धारित सहिष्णुता सीमा (संदर्भ. MARSS पैकेज R prog) से कम न हो।

चार्ट 2: डीएफएच सूचकांक बनाम शहरों में बेची गई आवास इकाइयाँ

(व-द-व प्रतिशत परिवर्तन)

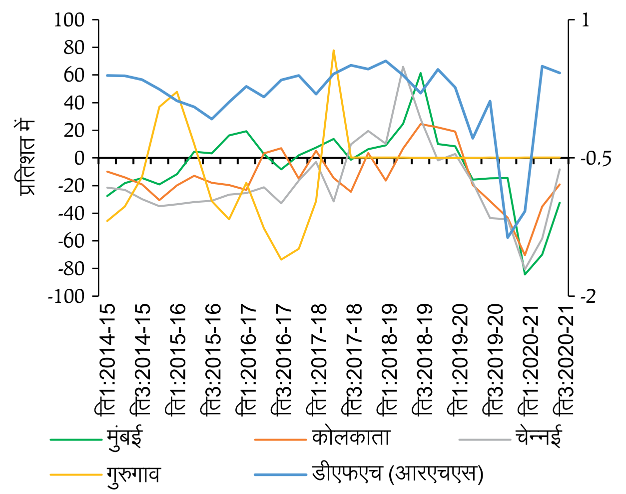

स्रोत: प्रोप्रराइटर और लेखकों की गणना।

डमी बनाते हैं। फिर हम अपने आश्रित चर के रूप में जीवीए, गैर-कृषि जीवीए, गैर-कृषि-गैर-निर्माण जीवीए में से प्रत्येक का उपयोग करके डीएफएच और अपसाइकिल डमी के अंतराल को पीछे छोड़ देते हैं। प्रतिगमन समीकरणों को समकालीन डीएफएच, टैग किए गए डीएफएच और अपसाइकिल इंटरैक्शन टर्म द्वारा संवर्धित आर्थिक गतिविधियों (जीवीए, और समायोजित जीवीए) के ओटोरिग्रेसिव समीकरण के रूप में संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है। समीकरण निम्नानुसार दिया गया है:

$$y_t = c + \beta * y_{t-1} + \sum_{i=0}^{n} \gamma_i * DFH_{t-i} + \sum_{j=0}^{n} \delta_j * DFH_{t-j} * upcycle_{dummy} + \epsilon_t$$

डीएफएच गुणांक एक सकारात्मक संकेत दर्शाते हैं, जब उनमें से प्रत्येक का एक आश्रित चर के रूप में उपयोग किया जाता है, तो वे जीवीए और गैर-कृषि-जीवीए के लिए पारंपरिक स्तरों पर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा, जब इस प्रतिगमन में अपसाइकिल अवधि के लिए एक इंटरैक्टिव डमी का उपयोग किया गया था, तो एक अंतराल के बाद इंटरैक्टिव डमी का गुणांक सकारात्मक और महत्वपूर्ण हो गया। सकारात्मक और महत्वपूर्ण मूल्य सभी निर्भर चर में सुसंगत थे, जो अपसाइकिल अवधि के दौरान रियल्टी क्षेत्र के विकास की उछाल को इंगित करता है (सारणी 2)।

सारणी 2: प्रतिगमन परिणाम

चर	जीवीए		जीवीए माइनस एग्री		जीवीए माइनस एग्री एंड कंस्ट्रक्शन	
	1	2	3	4	5	6
	गुणांक					
सी	1.52	1.53	1.83	1.95	1.84	1.94
आश्रित चर अंतराल	0.73***	0.77***	0.71***	0.73***	0.71***	0.76***
डीएफएच	0.24*	0.18	0.26*	0.17	0.28	
डीएफएच (-1)		-0.98		-1.10		-1.15
डीएफएच (-1) *अपसाइकल		1.02*		1.18*		1.22*
आर-एसक्यू	0.63	0.6	0.59	0.65	0.61	0.63
एफ-स्टैट	1 प्रतिशत के स्तर पर महत्वपूर्ण					
एन	39					

नोट: सभी चर वाई-ओ-वाई विकास के संदर्भ में हैं। प्रतीक *, **, *** उन मामलों को दर्शाते हैं जहां हम क्रमशः 10%, 5%, 1% महत्व स्तरों पर शून्य को अस्वीकार करते हैं। 2010 और 2020 के दौरान छंटनी किए गए त्रैमासिक नमूने के आधार पर।
स्रोत: लेखकों की गणना।

निर्माण जीवीए शृंखला में शामिल है; इसलिए, उपरोक्त परिणाम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रभावों का संकेत दे सकते हैं। अप्रत्यक्ष प्रभाव की पहचान करने के लिए, हम गैर-कृषि जीवीए (एनएएनसी-जीवीए) से निर्माण को बाहर करते हैं और उसी का निर्भर चर[5] के रूप में उपयोग करते हैं। सकारात्मक और महत्वपूर्ण गुणांक एनएएनसी-जीवीए निर्माण के अप्रत्यक्ष प्रभाव को पकड़ते हैं, जो सकारात्मक और महत्वपूर्ण है। यह रियल्टी क्षेत्र के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम लिंकेज के कारण हो सकता है, जो न केवल सीमेंट और स्टील जैसे पूंजी-गहन क्षेत्रों से जुड़ता है, बल्कि कई सहायक उद्योगों से भी जुड़ता है जो आमतौर पर श्रम-गहन होते हैं।

III.3 गतिशील कारक आवास की मजबूती

सारणी 1 के आधार पर, हमने उच्च समकालीन संबंध वाले छह चर (प्रति किमी रेलवे माल ढुलाई टन सहित) पाए, जबकि एक का जीवीए-निर्माण के साथ कम संबंध है। हालांकि सीपीआई आवास की कीमतों ने संकेत दिया कि आवास की कीमतों की शृंखला एक लैग संबंध है, हमारा मानना है कि आवास की कीमतों की शृंखला एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर है और आवास बाजार के बारे में जानकारी प्रदान करती है। हालांकि, तकनीकी दृष्टिकोण से, आवास की कीमतों पर अलग से विचार किया जा सकता है। इसलिए, हमने घर की कीमत को हटाने के बाद डीएफएच की गणना की और पाया कि हमारा डीएफएच_आवास कीमत हमारे डीएफएच के अनुरूप है।

इसी तरह, ओवरलैप की संभावना के बावजूद, हमने रेलवे माल ढुलाई और रेलवे माल ढुलाई टन प्रति किमी दोनों पर विचार किया, क्योंकि हमने पाया कि उनके चक्रीय पैटर्न अलग-अलग हैं

चार्ट 3(ए): अपवाद-आधारित गतिशील आवास कारक महामारी से पहले

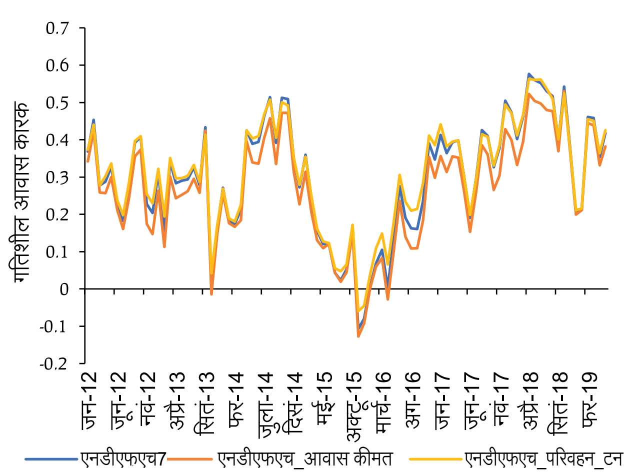

चार्ट 3(बी): अपवाद-आधारित गतिशील आवास कारक महामारी की अवधि

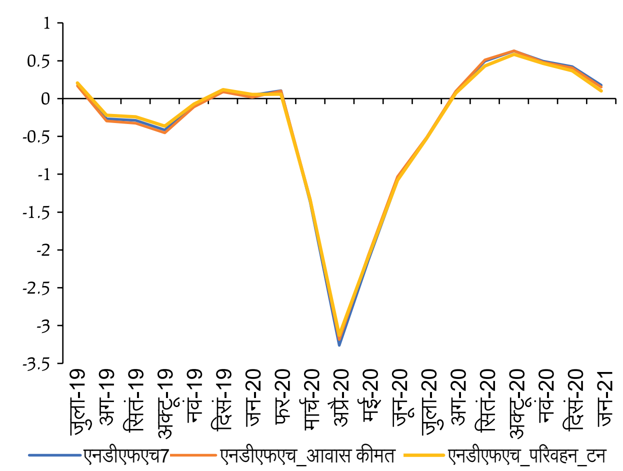

स्रोत: लेखकों की गणना।

[5] ईएम एल्गोरिथ्म एक पुनरावृत्ति प्रक्रिया का उपयोग करके अधिकतम संभावना अनुमान पाता है, जो मापदंडों के प्रारंभिक सेट θ1 से शुरू होता है, यह अव्यक्त चर स्थिति के मूल्य की गणना करता है ।

(एनडीएफएच 7)। हालांकि, हमने प्रति किलोमीटर रेलवे माल ढुलाई टन को छोड़कर डीएफएच की गणना की। डीएफएच_माल भाड़ा_टन चार्ट 3 में रिपोर्ट किया गया है। यह इंगित करता है, कुछ समयावधियों को छोड़कर, डीएफएच भारतीय रियल्टी क्षेत्र में व्यापक रुझानों पर नज़र रखते हुए एक साथ आगे बढ़ रहे हैं।

IV. निष्कर्ष

विकास और रोजगार सृजन के लिए रियल्टी क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए, हम समष्टि आर्थिक निगरानी में इसकी भूमिका का मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं। नीति विश्लेषण के लिए इसकी खोज करते समय, हमने पाया कि कम डेटा आवृत्ति (त्रैमासिक) और डेटा उपलब्धता में लंबे अंतराल ने सक्रिय नीति निर्माण में इस क्षेत्र के प्रयोग को कुछ हद तक बाधित किया है। इस लेख में, हम तेजी से सूचना उपलब्धता और नीति विश्लेषण की सुविधा के लिए इस अंतर को पाटने का प्रयास करते हैं।

इस संबंध में, हम विभिन्न पारंपरिक मासिक संकेतकों जैसे आवास की कीमतें, रियल्टी क्षेत्र की बैलेंस शीट, इस्पात और सीमेंट उत्पादन की जांच करते है। हम अपरंपरागत संकेतकों जैसे कि निफ्टी रियल्टी इंडेक्स व्यापक बाजार उतार-चढ़ाव के लिए समायोजित और रियल एस्टेट क्षेत्र से संबंधित गूगल खोज प्रवृत्ति संकेतक को भी देखते हैं। फिर हम इन चरों से एक सामान्य कारक प्राप्त करने के लिए एक गतिशील कारक आवास (डीएफएच) का अनुमान लगाते हैं जो मासिक आवृत्ति पर रियल्टी क्षेत्र में व्यापक प्रवृत्ति को पकड़ लेगा।

इसके बाद, हम मान्य करते हैं कि यह वास्तव में निर्माण / रियल्टी क्षेत्र को ट्रैक करता है, और इसलिए इसका उपयोग नीति विश्लेषण के लिए किया जा सकता है। हमारे अनुभवजन्य निष्कर्ष जीवीए और गैर-कृषि-गैर-निर्माण-जीवीए पर डीएफएच के सकारात्मक और महत्वपूर्ण प्रभाव का संकेत देते हैं, जो आर्थिक गतिविधियों पर रियल्टी क्षेत्र के प्रत्यक्ष और दूसरे दौर के प्रभावों का संकेत देते हैं।

हमारा मानना है कि इस पेपर के निष्कर्षों का उपयोग नीति विश्लेषण में सुधार के लिए विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। शुरुआत में, समय पर जानकारी, मान्यता अंतराल को कम करके कुशल नीति निर्माण की सुविधा प्रदान करती है। इस क्रम में, गतिशील कारक-आधारित 'डीएफएच' एक मासिक उच्च आवृत्ति चर द्वारा छोड़े गए शून्य को भरने की संभावना है जो अंतर्निहित स्थिति तक पहुंचने में सक्षम है और यहां तक कि निर्माण जीवीए को बनाने में भी सहायता करता है। इसके अलावा, जीवीए में निर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को देखते हुए, पहले और दूसरे दौर के प्रभावों के बारे में हमारे निष्कर्ष बताते हैं कि रियल्टी क्षेत्र महामारी के बाद के विकास पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

संदर्भ

अहमद, एम., झाओ, जेड.वाई., एण्ड ली, एच. (2019)। चीन में निर्माण क्षेत्र, शहरीकरण, ऊर्जा खपत, आर्थिक विकास और सीओ2 उत्सर्जन के बीच शैलीबद्ध अनुभवजन्य बातचीत का खुलासा। कुल पर्यावरण का विज्ञान, 657, 1085-1098।

बर्क, एन, और बिकेन, एस. (2017)। उभरते देशों में निर्माण क्षेत्र और जीडीपी वृद्धि के बीच कार्य-कारण: तुर्की का मामला। भूमध्यसागरीय अध्ययन पर 10 वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में (पीपी. 10-13)।

भादुरी, एस., घोष, एस., एण्ड कुमार, पी. (2020). डायनामिक फैक्टर मॉडल का उपयोग करके भारतीय जीडीपी विकास की नाउकास्टिंग। आरबीआई वर्किंग पेपर्स नंबर 3।

भारत सरकार (जीओआई)। (2013). आर्थिक सर्वेक्षण।

---. (2021). आर्थिक सर्वेक्षण।

हंग, सी.सी., ह्सू, एस.सी., प्रैट, एस., चेन, पी.सी., ली, सी.जे., एण्ड चान, ए.पी. (2019)। बहुक्षेत्रीय इनपुट-आउटपुट विश्लेषण का उपयोग करके एक खुली अर्थव्यवस्था में निर्माण गतिविधियों के लिंकेज और रिसाव की मात्रा निर्धारित करना। जर्नल ऑफ मैनेजमेंट इन इंजीनियरिंग, 35 (1), 04018054।

कुमार, ए., और चौधरी, एन. (2014)। भारतीय अर्थव्यवस्था पर आवास निवेश का प्रभाव। भाषा, शिक्षा और सामाजिक विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल।

मल्लिक, एच., और महालिक, एम.के. (2010)। अर्थव्यवस्था का

निर्माण: भारत के विकास में निर्माण क्षेत्र की भूमिका। जर्नल ऑफ रियल एस्टेट फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, 40 (3), 368-384।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई)। 2020। 2020-21 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के लिए सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान।

रामादुरई, टी (2017)। घरेलू वित्त समिति की रिपोर्ट। तकनीकी रिपोर्ट, भारतीय रिजर्व बैंक।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)। 2020। भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट।

स्टॉक, जे, और वाटसन, एम (1989)। संयोग और प्रमुख आर्थिक संकेतकों के नए सूचकांक। मैक्रोइकॉनॉमिक्स वार्षिक, राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान ब्यूरो, 4, 351-409।

तिवारी, ए. के. (2011)। निर्माण प्रवाह और आर्थिक विकास के बीच एक सामयिक विश्लेषण: भारत से साक्ष्य। जर्नल ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एंड इकोनॉमी, 12 (2), 27-42।

अनुलग्नक

चार्ट 1.ए: निर्माण जीवीए वृद्धि के साथ चर और उनकी सह-घट-बढ़
(व-द-व प्रतिशत)

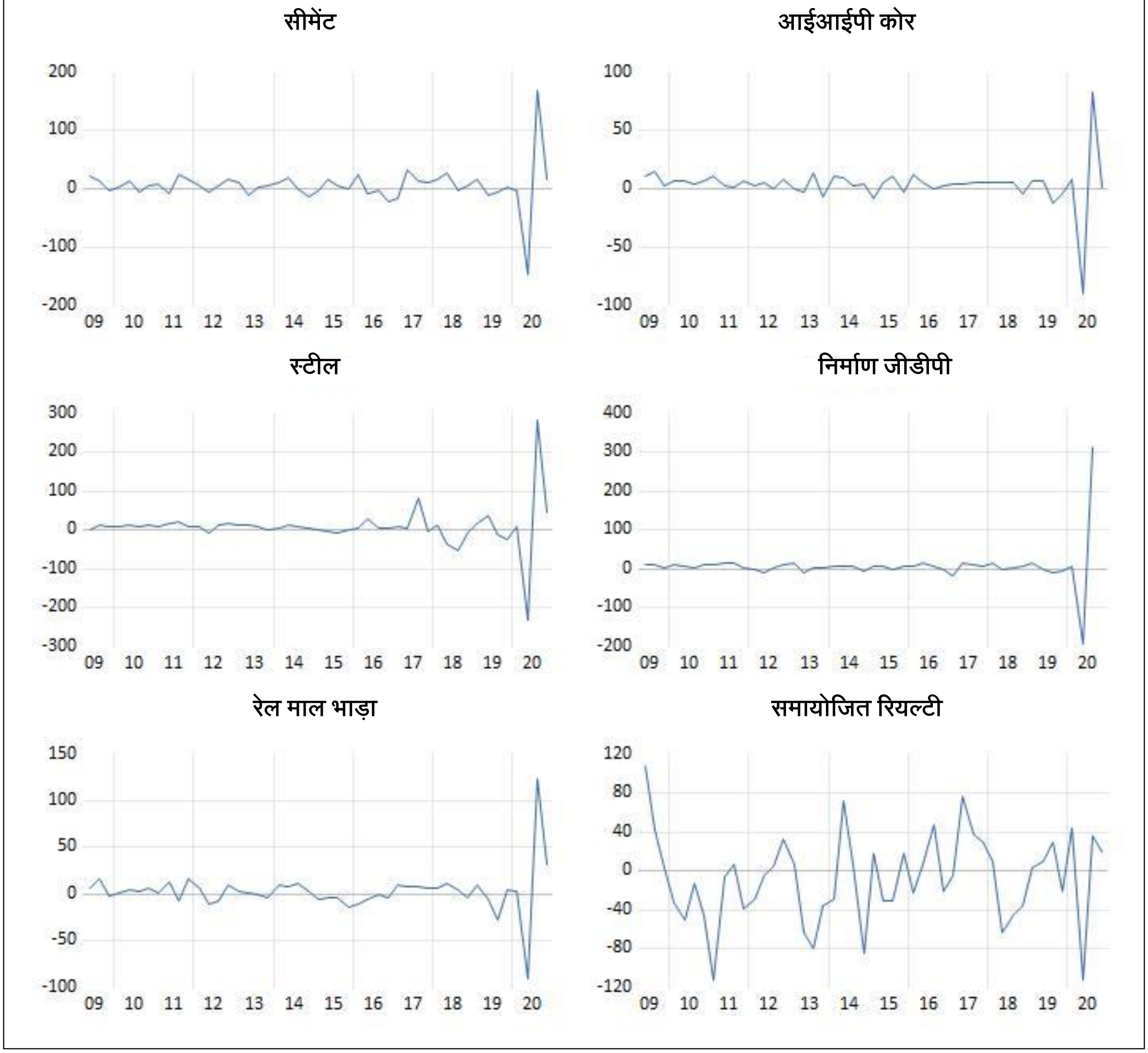

स्रोत: सीबीआईईई; डीबीआईईई और लेखकों की गणना।

चार्ट 1.बी: रेल माल ढुलाई और प्रति किलोमीटर माल ढुलाई (टन)

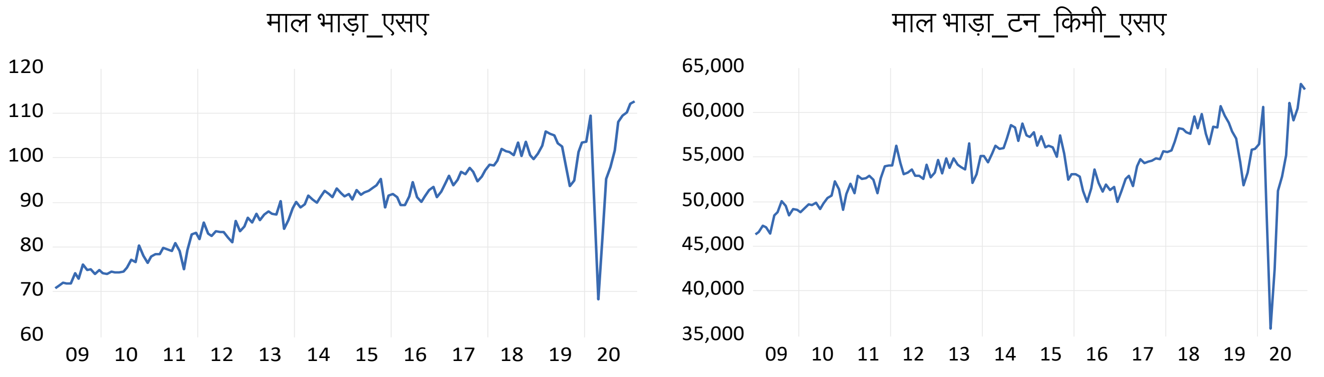

स्रोत: सीईआईसी और लेखकों की गणना।

सारणी 1.ए: निर्माण जीवीए (पूर्व कोविड अवधि) के साथ चयनित चर का सहसंबंध

चर	निर्माण जीवीए (-टी) (लैगिंग संबंध)	निर्माण जीवीए (समकालीन संबंध)	निर्माण जीवीए (+टी) (अग्रणी संबंध)	टिप्पणियां
आवास ऋण	-0.0086	-0.0676	0.1533	कोई महत्वपूर्ण सहसंबंध नहीं
इस्पात उत्पादन	0.3392**	0.3422**	-0.085	सी और एल-
सीमेंट उत्पादन	0.0681	0.5443**	0.1715	सी
आईआईपी कोर	0.1817	0.2773	0.1491	कोई महत्वपूर्ण सहसंबंध नहीं
आवास की कीमतें	0.3462**	0.2344	-0.0579	एल-
रेल माल भाड़ा	0.2015	0.28**	0.1184	सी
रेल-सीमेंट	-0.0101	-0.1704	0.1567	कोई महत्वपूर्ण सहसंबंध नहीं
रियल्टी इंडेक्स	-0.098	0.2662	0.0644	कोई महत्वपूर्ण सहसंबंध नहीं
सेंसेक्स	-0.0392	0.11	0.096	कोई महत्वपूर्ण सहसंबंध नहीं
समायोजित रियल्टी	-0.117	0.3153**	0.025	सी
गुगल खोज प्रवृत्ति सूचकांक	-0.1939	-0.2101	-0.022	कोई महत्वपूर्ण सहसंबंध नहीं

नोट: प्रतीक *, **, *** उन मामलों को दर्शाते हैं जहां हम क्रमशः 10%, 5%, 1% महत्व स्तरों पर शून्य को अस्वीकृत करते हैं।
स्रोत: लेखकों की गणना।

चार्ट 1.सी: डीएफ-आवास के लिए फैक्टर लोडिंग

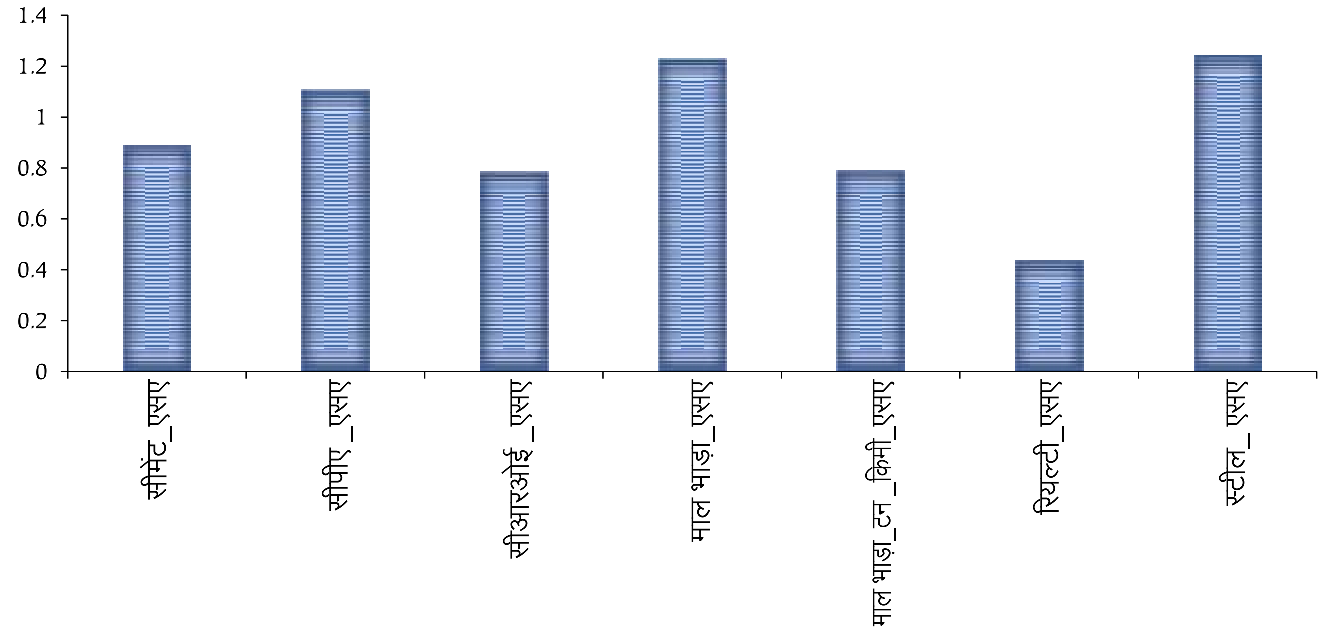

स्रोत: लेखकों के आकलन।

सारणी 1.B ग्रेंजर कॉजलिटी टेस्ट

शून्य प्राक्कल्पना:	**अवलोकन**	**एफ-सांख्यि-की क**	**संभावना**
जीडीपी डीएफएच का ग्रेंजर कॉज़ नहीं है	34	0.49	0.74
डीएफएच जीडीपी का ग्रेंजर कॉज़ नहीं है		1.70	0.17
गैर_कृषि_जीडीपी डीएफएच का ग्रेंजर कॉज़ नहीं है	34	0.33	0.85
डीएफएच गैर_कृषि_जीडीपी का ग्रेंजर कॉज़ नहीं है		2.72	0.05
गैर_कृषि_जीडीपी_निर्माण डीएफएच का ग्रेंजर कॉज़ नहीं है	34	0.41	0.79
डीएफएच गैर_कृषि_जीडीपी_निर्माण का ग्रेंजर कॉज़ नहीं है		2.05	0.10

स्रोत: लेखकों की गणना।

वर्तमान सांख्यिकी

चुनिंदा आर्थिक संकेतक

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुद्रा और बैंकिंग

मूल्य और उत्पादन

सरकारी लेखा और खज़ाना बिल

वित्तीय बाजार

बाह्य क्षेत्र

भुगतान और निपटान प्रणालियाँ

अवसरिक श्रृंखला

विषय-वस्तु

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
1	चुनिंदा आर्थिक संकेतक	197
	भारतीय रिज़र्व बैंक	
2	भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां	198
3	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन	199
4	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमेरिकी डॉलर का क्रय/विक्रय	200
4ए	भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार) परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	201
5	भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं	201
	मुद्रा और बैंकिंग	
6	मुद्रा स्टॉक मात्रा	202
7	मुद्रा स्टॉक (एम$_3$) के स्रोत	203
8	मौद्रिक सर्वेक्षण	204
9	कुल चलनिधि राशियां	204
10	भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण	205
11	आरक्षित मुद्रा - घटक और स्रोत	205
12	वाणिज्यिक बैंक सर्वेक्षण	206
13	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश	206
14	भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	207
15	प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का अभिनियोजन	208
16	सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार विनियोजन	209
17	भारतीय रिज़र्व बैंक में खाते रखने वाले राज्य सहकारी बैंक	210
	कीमत और उत्पादन	
18	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधारः 2012=100)	211
19	अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	211
20	मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य	211
21	थोक मूल्य सूचकांक	212
22	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधारः 2011-12=100)	216
	सरकारी खाते और खज़ाना बिल	
23	केन्द्र सरकार के खाते - एक नज़र में	216
24	खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप	217
25	खज़ाना बिलों की नीलामी	217
	वित्तीय बाजार	
26	दैनिक मांग मुद्रा दरें	218
27	जमाराशि प्रमाण-पत्र	219
28	वाणिज्यिक पत्र	219
29	चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर	219
30	गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम	220

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
	बाह्य क्षेत्र	
31	विदेशी व्यापार	221
32	विदेशी मुद्रा भंडार	221
33	अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां	221
34	विदेशी निवेश अंतर्वाह	222
35	निवासी भारतीयों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत जावक विप्रेषण	222
36	भारतीय रुपये का सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) सूचकांक	223
37	बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)- पंजीकरण	224
38	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	225
39	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (₹ करोड़)	226
40	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	227
41	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (₹ करोड़)	228
42	भारत की अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति	229
	भुगतान और निपटान प्रणालियाँ	
43	भुगतान प्रणाली संकेतक	230
	अवसरिक श्रृंखला	
44	लघु बचत	232
45	केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप	233
46	केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण	234
47	विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता	235
48	राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश	236
49	राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियां	237
50 (ए)	हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह- लिखत-वार	238
50 (बी)	हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक- चुनिंदा संकेतक	241

टिप्पणियां : .. = उपलब्ध नहीं।
– = शून्य/नगण्य
प्रा/अ= प्रारंभिक/अनंतिम आंसं = आंशिक रूप से संशोधित

सं. 1 : चुनिंदा आर्थिक संकेतक

मद	2021-22	2021-22		2022-23	
		ति2	ति3	ति2	ति3
	1	2	3	4	5
1 वास्तविक क्षेत्र (% परिवर्तन)					
1.1 आधार मूल्यों पर जीवीए	8.8	9.3	4.7	5.5	4.6
1.1.1 कृषि	3.5	4.8	2.3	2.4	3.7
1.1.2 उद्योग	10.5	7.3	2.2	-2.3	0.3
1.1.3 सेवाएं	9.6	11.0	6.5	9.0	6.5
1.1ए अंतिम खपत व्यय	10.5	13.9	10.2	7.0	1.7
1.1बी सकल नियत पूंजी निर्माण	14.6	12.4	1.2	9.7	8.3

	2021-22	2022		2023	
		जन.	फर.	जन.	फर.
	1	2	3	4	5
1.2 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक	11.4	2.0	1.2	5.5	5.6
2 मुद्रा और बैंकिंग (% परिवर्तन)					
2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक					
2.1.1 जमाराशियां	8.9	8.3	8.6	10.5	10.1
2.1.2 ऋण#	9.6	8.2	9.1	16.3	15.5
2.1.2.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	9.7	8.3	9.2	16.7	15.9
2.1.3 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश#	6.0	3.3	4.7	13.4	14.3
2.2 मुद्रा स्टॉक मात्रा					
2.2.1 आरक्षित मुद्रा (एम0)	13.0	13.5	13.9	10.8	10.5
2.2.2 स्थूल मुद्रा (एम3)	8.8	8.4	8.7	9.8	9.5
3 अनुपात (%)					
3.1 आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.00	4.00	4.00	4.50	4.50
3.2 सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
3.3 नकदी-जमा अनुपात	4.7	4.8	4.6	5.2	5.0
3.4 ऋण-जमा अनुपात	72.2	71.5	71.8	75.3	75.3
3.5 वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात#	77.2	67.6	72.1	115.3	111.6
3.6 निवेश-जमा अनुपात	28.7	28.6	28.8	29.3	29.9
3.7 वृद्धिशील निवेश-जमा अनुपात	19.7	12.8	18.8	37.1	43.6
4 ब्याज दरें (%)					
4.1 नीति रिपो दर	4.00	4.00	4.00	6.25	6.50
4.2 स्थायी रिवर्स रिपो दर	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
4.3 स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ़) दर*	-	-	-	6.00	6.25
4.4 सीमांत स्थायी सुविधा दर	4.25	4.25	4.25	6.50	6.75
4.5 बैंक दर	4.25	4.25	4.25	6.50	6.75
4.6 आधार दर	7.25/8.80	7.25/8.80	7.25/8.80	8.65/9.40	8.65/9.40
4.7 एमसीएलआर (एक दिन के लिए)	6.45/7.00	6.45/7.00	6.45/7.00	7.30/8.40	7.50/8.40
4.8 मीयादी जमा दर>1 वर्ष	5.00/5.60	5.00/5.60	5.00/5.60	6.00/7.25	6.00/7.25
4.9 बचत जमा दर	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00
4.10 मांग मुद्रा दर (भारित औसत)	3.34	3.72	3.30	6.44	6.62
4.11 91-दिवसीय खज़ाना बिल (प्राथमिक) आय	3.84	3.71	3.70	6.47	6.82
4.12 182-दिवसीय खज़ाना बिल (प्राथमिक) आय	4.27	4.18	4.19	6.87	7.18
4.13 364-दिवसीय खज़ाना बिल (प्राथमिक) आय	4.58	4.51	4.52	6.90	7.26
4.14 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर आय (एफबीआईएल)	6.86	6.69	6.78	7.35	7.43
5 संदर्भ दर और फारवर्ड प्रीमियम					
5.1 भा.रु.-अमेरिकी डॉलर हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	76.18	74.95	75.28	81.54	82.74
5.2 भा.रु.-यूरो हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	84.01	83.60	84.38	88.66	87.70
5.3 अमेरिकी डॉलर का वायदा प्रीमिआ 1-माह (%)	5.67	3.84	4.30	1.77	2.10
3-माह (%)	4.46	4.88	4.41	2.55	2.56
6-माह (%)	4.10	4.66	4.20	2.44	2.30
6 मुद्रास्फीति (%)					
6.1 अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	5.51	6.0	6.1	6.5	6.4
6.2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	5.13	5.8	5.0	6.2	6.2
6.3 थोक मूल्य सूचकांक	12.97	13.7	13.4	4.7	3.9
6.3.1 प्राथमिक वस्तुएं	10.25	15.6	13.9	3.9	3.3
6.3.2 ईंधन और पावर	32.50	34.4	30.8	15.2	14.8
6.3.3 विनिर्मित उत्पाद	11.10	9.5	10.2	3.0	1.9
7 विदेशी व्यापार (% परिवर्तन)					
7.1 आयात	55.43	25.1	37.2	-0.5	-4.8
7.2 निर्यात	44.62	27.9	34.5	1.6	-0.4

टिप्पणी : फाइनेंसियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लि. (एफबीआईएल) भारतीय रिज़र्व बैंक के 31 मार्च 2018 के परिपत्र एफएमआरडी.डीआईआरडी.7/14.03.025/ 2017-18 के अनुसार जी सेक बेंचमार्क का प्रकाशन शुरू किया है। एफबीआईएल ने 10 जुलाई 2018 से संदर्भ दरों का प्रसार शुरू किया है।

*: 8 अप्रैल 2022 दिनांकित प्रेस अधिसूचना सं.2022-2023/41के अनुसार।

#: 3 दिसंबर 2021 से 18 नवंबर 2022 तक सभी पखवाड़ों के लिए बैंक ऋण वृद्धि और संबंधित अनुपात को चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा पिछली रिपोर्टिंग त्रुटियों के लिए समायोजित किया जाता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक

सं. 2 : भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(₹ करोड़)

मद	अंतिम शुक्रवार/शुक्रवार की स्थिति						
	2022-23	2022	2023				
		मार्च	फर. 24	मार्च 3	मार्च 10	मार्च 17	मार्च 24
	1	2	3	4	5	6	7
1 निर्गम विभाग							
1.1 देयताएं							
1.1.1 संचलन में नोट	3350412	3107637	3301605	3315748	3343547	3342288	3350412
1.1.2 बैंकिंग विभाग में रखे गए नोट	13	15	11	15	13	13	13
1.1/1.2 कुल देयताएं (जारी किए गए कुल नोट) या आस्तियां	**3350425**	**3107652**	**3301616**	**3315764**	**3343560**	**3342301**	**3350425**
1.2 आस्तियां							
1.2.1 सोना और बुलियन	142136	128208	130104	129616	129377	137425	142136
1.2.2 विदेशी प्रतिभूतियां	3207988	2978927	3171023	3185699	3213804	3204537	3207988
1.2.3 रुपया सिक्का	300	518	489	448	379	338	300
1.2.4 भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां	–	–	–	–	–	–	–
2 बैंकिंग विभाग							
2.1 देयताएं							
2.1.1 जमाराशियां	1340653	1794574	1320222	1314256	1330340	1365084	1340653
2.1.1.1 केंद्र सरकार	100	101	101	101	100	100	100
2.1.1.2 बाजार स्थिरीकरण योजना							
2.1.1.3 राज्य सरकारें	43	42	43	42	43	42	43
2.1.1.4 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	809907	683437	797986	837782	810703	835042	809907
2.1.1.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	7332	7123	7320	7552	7326	7436	7332
2.1.1.6 गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	4615	4121	4419	4596	4489	4545	4615
2.1.1.7 अन्य बैंक	45939	37589	45092	45664	45678	45898	45939
2.1.1.8 अन्य	379890	988819	357329	317829	365247	381863	379890
2.1.1.9 भारत के बाहर वित्तीय संस्थान	92826	73343	107934	100690	96755	90157	92826
2.1.2 अन्य देयताएं	1627193	1359254	1509502	1454931	1463131	1573416	1627193
2.1/2.2 कुल देयताएं या आस्तियां	**2967845**	**3153828**	**2829724**	**2769188**	**2793471**	**2938500**	**2967845**
2.2 आस्तियां							
2.2.1 नोट और सिक्के	13	15	11	15	13	13	13
2.2.2 विदेश में रखे शेष	1023426	1243853	960958	917722	873203	993346	1023426
2.2.3 ऋण और अग्रिम							
2.2.3.1 केन्द्र सरकार	–	–	–	–	–	–	–
2.2.3.2 राज्य सरकारें	7625	670	9515	14077	736	8189	7625
2.2.3.3 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	165085	94299	109026	94174	177196	179260	165085
2.2.3.4 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	–	–	–	–	–	–	–
2.2.3.5 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	–	–	–	–	–	–	–
2.2.3.6 नाबार्ड	–	24927	–	–	–	–	–
2.2.3.7 एक्जिम बैंक	–	–	–	–	–	–	–
2.2.3.8 अन्य	18368	8077	10466	12378	16693	18869	18368
2.2.3.9 भारत के बाहर की वित्तीय संस्थाएं	93236	72741	107037	99704	96112	90740	93236
2.2.4 खरीदे और भुनाए गए बिल							
2.2.4.1 आंतरिक	–	–	–	–	–	–	–
2.2.4.2 सरकारी खज़ाना बिल	–	–	–	–	–	–	–
2.2.5 निवेश	1407585	1491042	1399711	1399050	1397795	1403534	1407585
2.2.6 अन्य आस्तियां	252508	218203	233001	232068	231723	244551	252508
2.2.6.1 स्वर्ण	232981	201354	215380	214980	214584	226626	232981

*: डेटा अनंतिम है।

शुक्रवार, 31 मार्च, 2023 के आंकड़े बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में मई 2023 में आरबीआई की बैलेंस शीट के हिस्से के रूप में प्रकाशित किए जाएंगे।

सं. 3 : भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन

(₹ करोड़)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा						स्थायी चलनिधि सुविधाएं	ओएमओ (एकमुश्त)		निवल अंतर्वेशन (+)/ अवशोषण (-) (1+3+5+7+9-2-4-6-8)
	रिपो	रिवर्स रिपो	परिवर्तन-शील रिपो दर	परिवर्तन-शील रिवर्स रिपो दर	एमएसएफ	एसडीएफ		विक्रय	क्रय	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
फर. 1, 2023	-	-	-	-	2083	84118	-506	-	-	-82541
फर. 2, 2023	-	-	-	-	2124	117318	-2545	-	-	-117739
फर. 3, 2023	-	-	-	-	684	101061	-272	-	-	-100649
फर. 4, 2023	-	-	-	-	1902	21996	-	-	-	-20094
फर. 5, 2023	-	-	-	-	23	5777	-	-	-	-5754
फर. 6, 2023	-	-	-	-	784	103392	-	-	-	-102608
फर. 7, 2023	-	-	-	-	4102	94084	-	-	-	-89982
फर. 8, 2023	-	-	-	-	8038	57577	-	-	-	-49539
फर. 9, 2023	-	-	-	-	8706	59043	456	-	-	-49881
फर. 10, 2023	-	-	50000	-	888	129379	320	-	-	-78171
फर. 11, 2023	-	-	-	-	159	3668	-	-	-	-3509
फर. 12, 2023	-	-	-	-	11	3355	-	-	-	-3344
फर. 13, 2023	-	-	-	-	720	92422	-309	-	-	-92011
फर. 14, 2023	-	-	-	-	1996	90336	-	-	-	-88340
फर. 15, 2023	-	-	-	-	702	122837	-	-	-	-122135
फर. 16, 2023	-	-	-	-	713	134132	-	-	-	-133419
फर. 17, 2023	-	-	-	-	967	126267	-	-	-	-125300
फर. 18, 2023	-	-	-	-	2685	18360	-	-	-	-15675
फर. 19, 2023	-	-	-	-	47	2696	-	-	-	-2649
फर. 20, 2023	-	-	-	-	3650	108858	500	-	-	-104708
फर. 21, 2023	-	-	-	-	983	76053	511	-	-	-74559
फर. 22, 2023	-	-	-	-	817	98744	-	-	-	-97927
फर. 23, 2023	-	-	-	-	741	117490	-500	-	-	-117249
फर. 24, 2023	-	-	-	12752	15233	84681	477	-	-	-81723
फर. 25, 2023	-	-	-	-	578	7052	-	-	-	-6474
फर. 26, 2023	-	-	-	-	9	2841	-	-	-	-2832
फर. 27, 2023	-	-	-	-	1874	65660	7500	-	-	-56286
फर. 28, 2023	-	-	-	-	3755	113466	-	-	-	-109711

एसडीएफ़: स्थायी जमा सुविधा, एमएसएफ़: सीमांत स्थायी सुविधा।

सं. 4: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमेरिकी डॉलर का क्रय/ विक्रय

i) तटवर्ती/अपतटीय ओटीसी सेगमेन्ट में परिचालन

मद	2021-22	2022	2023	
		फर.	जन.	फर.
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमेरिकी डॉलर) (1.1-1.2)	17312	771	-384	254
1.1 क्रय (+)	113991	5946	12902	4381
1.2 विक्रय (-)	96679	5175	13286	4127
2 संविदा दर पर ₹ के बराबर (₹ करोड़)	134629	6459	-3869	1134
3 संचयी (मार्च के अंत से) (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	17312	37413	-26520	-26266
(₹ करोड़)	134629	287639	-224276	-223142
4 माह के अंत में बकाया निवल वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	65791	49106	21729	20470

ii) मुद्रा वायदा खंड में परिचालन

मद	2021-22	2022	2023	
		फर.	जन.	फर.
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमेरिकी डॉलर) (1.1-1.2)	0	0	0	0
1.1 क्रय (+)	2370	0	150	0
1.2 विक्रय (-)	2370	0	150	0
2 माह के अंत में बकाया निवल मुद्रा वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	0	0	0	0

सं. 4ए भारतीय रिज़र्व बैंक के बकाया वायदे का परिपक्वता विश्लेषण (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार) (मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	28 फरवरी 2023 की स्थिति		
	दीर्घ (+)	अल्प (-)	निवल (1-2)
	1	2	3
1. 1 माह तक	750	1400	-650
2. 1 माह से अधिक और 3 माह तक	4368	500	3868
3. 3 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	13363	1246	12117
4. 1 वर्ष से अधिक	5135	0	5135
कुल (1+2+3+4)	**23616**	**3146**	**20470**

सं. 5: भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं

(₹ करोड़)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार की स्थिति							
	2022-23	2022				2023		
		मार्च 25	अक्टू. 21	नवं. 18	दिसं. 30	जन. 27	फर. 24	मार्च 24
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 सीमांत स्थायी सुविधा	28388	11	51134	3250	33224	27370	15233	28388
2 अनुसूचित बैंकों के लिए निर्यात ऋण पुर्नवित्त	-							
2.1 सीमा	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 बकाया	-	-	-	-	-	-	-	-
3 प्राथमिक व्यापारियों के लिए चलनिधि सुविधा	-							
3.1 सीमा	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900
3.2 बकाया	2442	0	1022	1801	2376	1675	2107	2442
4. अन्य	-							
4.1 सीमा	76000	76000	76000	76000	76000	76000	76000	76000
4.2 बकाया	15900	32401	20249	10850	15400	7500	8350	15900
5 कुल बकाया (1+2.2+3.2+4.2)	46730	32412	72405	15901	51000	36545	25690	46730

टिप्पणी: 1. अन्य अर्थात एक्जिम बैंक के लिए विशेष पुनर्वित्त सुविधा 22 मई, 2020 से फिर से शुरु की गई है।

2. 17 अप्रैल, 2020 से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (4एच) के तहत अन्य अर्थात नाबार्ड/सिडबी/एनएचबी के लिए पुनर्वित्त सुविधा।

मुद्रा और बैंकिंग

सं. 6: मुद्रा भंडार उपाय

(₹ करोड़)

मद	मार्च 31 /माह के नियत अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की बकाया स्थिति				
	2021-22	2022	2023		
		फर. 25	जन. 27	फर. 10	फर. 24
	1	2	3	4	5
1 जनता के पास मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 - 1.4)	3035689	2980565	3169720	3207073	3231824
1.1 संचलन में नोट	3105703	3052620	3261863	3294591	3301475
1.2 रुपये सिक्के का संचलन	27270	27139	29048	29048	29264
1.3 छोटे सिक्कों का संचलन	743	743	743	743	743
1.4 बैंकों के पास नकदी	98028	99937	122062	117443	99788
2 जनता की जमाराशियां	2271436	2157809	2360613	2294719	2356710
2.1 बैंकों के पास मांग जमाराशियां	2212992	2103056	2296792	2230889	2292581
2.2 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशियां	58444	54752	63821	63830	64129
3 एम$_1$ (1 + 2)	**5307125**	**5138374**	**5530333**	**5501792**	**5588534**
4 डाकघर बचत बैंक जमाराशियां	188433	182889	199087	199087	199087
5 एम$_2$ (3 + 4)	**5495558**	**5321263**	**5729420**	**5700879**	**5787621**
6 बैंकों के पास मीयादी जमाराशियां	15186605	15045154	16364701	16486210	16513885
7 एम$_3$ (3 + 6)	**20493729**	**20183528**	**21895034**	**21988001**	**22102418**
8 कुल डाकघर जमाराशियां	1012241	990274	1105137	1105137	1105137
9 एम$_4$ (7 + 8)	**21505970**	**21173802**	**23000171**	**23093138**	**23207555**

सं. 7: मुद्रा भंडार (एम$_3$) का स्रोत

(₹ करोड़)

स्रोत	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2021-22	2022	2023		
		फर. 25	जन. 27	फर. 10	फर. 24
	1	2	3	4	5
1 सरकार को निवल बैंक ऋण	**6477629**	**6232004**	**6657365**	**6784535**	**6854246**
1.1 आरबीआई का सरकार को निवल ऋण (1.1.1-1.1.2)	1450596	1267912	1162729	1216727	1216525
1.1.1 सरकार पर दावे	1490991	1498132	1419355	1403887	1407652
1.1.1.1 केन्द्र सरकार	1489324	1497945	1402610	1401485	1398137
1.1.1.2 राज्य सरकारें	1667	186	16745	2401	9515
1.1.2 आरबीआई के पास सरकार की जमाराशियां	40394	230220	256626	187160	191127
1.1.2.1 केन्द्र सरकार	40352	230177	256584	187117	191085
1.1.2.2 राज्य सरकारें	42	43	42	43	43
1.2 सरकार को अन्य बैंक ऋण	5027033	4964092	5494636	5567808	5637721
2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	**12616520**	**12350302**	**14072457**	**14155164**	**14188368**
2.1 आरबीआई का वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	16571	1853	11223	11850	12529
2.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को अन्य बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	12599950	12348448	14061234	14143314	14175838
2.2.1 वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बैंक ऋण	11891314	11643717	13337536	13418060	13450269
2.2.2 सहकारी बैंकों द्वारा बैंक ऋण	690201	686893	706416	707947	708230
2.2.3 वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश	18435	17838	17281	17306	17340
3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1 + 3.2)	**4854063**	**4881815**	**4792608**	**4767235**	**4731899**
3.1 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1.1-3.1.2)	4442479	4582959	4537015	4511642	4476306
3.1.1 सकल विदेशी आस्तियां	4442720	4583200	4537274	4511904	4476568
3.1.2 विदेशी देयताएं	241	241	259	262	262
3.2 अन्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	411583	298856	255593	255593	255593
4 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	**28013**	**27882**	**29791**	**29791**	**30007**
5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	**3482496**	**3308475**	**3657186**	**3748723**	**3702101**
5.1 आरबीआई की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	1308500	1324383	1531460	1535228	1496402
5.2 अन्य बैंकों की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं (अवशिष्ट)	2173996	1984092	2125727	2213495	2205699
एम$_3$ (1+2+3+4-5)	**20493729**	**20183528**	**21895034**	**21988001**	**22102418**

सं. 8: मौद्रिक सर्वेक्षण

(₹ करोड़)

मद	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2021-22	2022	2023		
		फर. 25	जन. 27	फर. 10	फर. 24
	1	2	3	4	5
मौद्रिक समुच्चय					
एन एम1 (1.1 + 1.2.1+1.3)	5307125	5138374	5530143	5501792	5588318
एन एम2 (एन एम1 + 1.2.2.1)	12081049	11848309	12824268	12848837	12947497
एन एम3 (एन एम2 + 1.2.2.2 + 1.4 = 2.1 + 2.2 + 2.3 - 2.4- 2.5)	20634885	20326080	22199079	22291759	22408995
1 घटक					
1.1 जनता के पास मुद्रा	3035689	2980565	3169530	3207073	3231607
1.2. निवासियों की कुल जमाराशियां	17266157	17014024	18505959	18557658	18646314
1.2.1 मांग जमाराशियां	2212992	2103056	2296792	2230889	2292581
1.2.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां	15053166	14910967	16209167	16326769	16353733
1.2.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियां	6773925	6709935	7294125	7347046	7359180
1.2.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र (सीडी)	176718	128422	282706	270840	282944
1.2.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां	8279241	8201032	8915042	8979723	8994553
1.3 आरबीआई के पास 'अन्य' जमाराशियां	58444	54752	63821	63830	64129
1.4 वित्तीय संस्थाओं से मांग /सावधि निधीयन	274594	276739	459769	463199	466945
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	20080599	19568663	21861698	22027909	22163277
2.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	6477629	6232004	6657365	6784535	6854246
2.1.1.1 सरकार को निवल आरबीआई ऋण	1450596	1267912	1162729	1216727	1216525
2.1.1.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा सरकार को ऋण	5027033	4964092	5494636	5567808	5637721
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	13602969	13336659	15204333	15243374	15309031
2.1.2.1 वाणिज्यिक क्षेत्र को आरबीआई ऋण	39581	26706	11223	11850	12529
2.1.2.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	13563389	13309953	15193109	15231524	15296502
2.1.2.2.1 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियां)	952181	952673	1111042	1067645	1097846
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	28013	27882	29600	29791	29791
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	4705191	4763870	4628291	4605238	4607135
2.3.1 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	4442479	4582959	4537015	4511642	4476306
2.3.2 बैंकिंग प्रणाली की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	262711	180910	91276	93596	130829
2.4 पूंजी खाता	3021858	3053964	3503011	3510957	3487014
2.5 अन्य मदें (निवल)	1157060	980370	817499	860222	904194

सं. 9: चलनिधि समुच्चय

(₹ करोड़)

समुच्चय	2021-22	2022		2023	
		फर.	दिसं.	जन.	फर.
	1	2	3	4	5
1 एन एम$_3$	**20630753**	**20326080**	**22199079**	**22199079**	**22408995**
2 डाकघर जमाराशियां	596588	585275	594633	651847	651847
3 एल$_1$ (1 + 2)	**21227341**	**20911355**	**22793712**	**22850926**	**23060842**
4 वित्तीय संस्थाओं की देयताएं	49578	44627	65601	70232	49679
4.1 सावधि मुद्रा उधार	1824	2082	963	1133	1229
4.2 जमा प्रमाण-पत्र	39170	34185	56570	61870	41920
4.3 सावधि जमाराशियां	8584	8360	8069	7229	6530
5 एल$_2$ (3 + 4)	**21276919**	**20955982**	**22859314**	**22921158**	**23110522**
6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास जनता की जमाराशियां	70564	..	78061	..	..
7 एल$_3$ (5 + 6)	**21347483**	..	**22937375**	..	..

टिप्पणी : 1. संभव है कि पूर्णांकन के कारण कॉलम के आंकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।

सं. 10: भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण

(₹ करोड़)

मद	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2021-22	2022	2023		
		फर. 25	जन. 27	फर. 10	फर. 24
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 संचलन में मुद्रा	3133716	3080502	3291592	3324515	3331396
1.2 आरबीआई के पास बैंकरों की जमाराशियां	876726	712237	870956	862238	854816
1.2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	823632	664473	813573	805398	797986
1.3 आरबीआई के पास 'अन्य' जमाराशियां	58444	54752	63821	63830	64129
आरक्षित मुद्रा (1.1+1.2+1.3=2.1+2.2+2.3-2.4-2.5)	4068887	3847491	4226369	4250583	4250341
2 स्रोत					
2.1 आरबीआई के देशी ऋण	906895	561032	1191213	1244378	1240647
2.1.1 सरकार को निवल आरबीआई ऋण	1450596	1267912	1162729	1216727	1216525
2.1.1.1 केन्द्र सरकार को निवल आरबीआई ऋण (2.1.1.1.1+2.1.1.1.2+2.1.1.1.3+2.1.1.1.4-2.1.1.1.5)	1448972	1267768	1146027	1214368	1207052
2.1.1.1.1 केन्द्र सरकार को ऋण और अग्रिम	–	–	–	–	–
2.1.1.1.2 खज़ाना बिलों में निवेश	–	–	–	–	–
2.1.1.1.3 दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	1488816	1497537	1402174	1401124	1397648
2.1.1.1.3.1 केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	1488816	1497537	1402174	1401124	1397648
2.1.1.1.4 रुपया सिक्के	508	409	436	361	489
2.1.1.1.5 केन्द्र सरकार की जमाराशियां	40352	230177	256584	187117	191085
2.1.1.2 राज्य सरकारों को निवल आरबीआई ऋण	1624	144	16702	2359	9472
2.1.2 बैंकों पर आरबीआई के दावे	-583282	-733586	17261	15801	11593
2.1.2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ऋण और अग्रिम	-560272	-708733	17261	15801	11593
2.1.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को आरबीआई के ऋण	39581	26706	11223	11850	12529
2.1.3.1 प्राथमिक व्यापारियों को ऋण और अग्रिम	–	–	1675	1428	2107
2.1.3.2 नाबार्ड को ऋण और अग्रिम	23010	24853	–	–	–
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	28013	27882	29600	29791	29791
2.3 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	4442479	4582959	4537015	4511642	4476306
2.3.1 सोना	322213	319800	358942	353627	345484
2.3.2 विदेशी मुद्रा आस्तियां	4120283	4263177	4178090	4158033	4130840
2.4 पूंजी खाता	1254092	1290045	1566409	1571862	1547974
2.5 अन्य मदें (निवल)	54408	34338	-34950	-36634	-51572

सं. 11: आरक्षित मुद्रा - घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	2021-22	मार्च 31 /माह के अंतिम शुक्रवारों/शुक्रवारों की स्थिति के अनुसार बकाया					
		2022	2023				
		फर. 25	जन. 27	फर. 3	फर. 10	फर. 17	फर. 24
	1	2	3	4	5	6	7
आरक्षित मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 = 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 - 2.6)	4068887	3847491	4226559	4255037	4250583	4285987	4250557
1 घटक							
1.1 संचलन में मुद्रा	3133716	3080502	3291782	3297737	3324515	3330335	3331612
1.2 आरबीआई के पास बैंकरों की जमाराशियां	876726	712237	870956	892435	862238	888699	854816
1.3 आरबीआई के पास 'अन्य' जमाराशियां	58444	54752	63821	64865	63830	66954	64129
2 स्रोत							
2.1 सरकार को निवल रिज़र्व बैंक ऋण	1450596	1267912	1162729	1286371	1216727	1248754	1216525
2.2 बैंकों को रिज़र्व बैंक ऋण	-560272	-708733	17261	-41124	15801	18493	11593
2.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को रिज़र्व बैंक ऋण	16571	1853	11223	11074	11850	11541	12529
2.4 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	4442479	4582959	4537015	4542673	4511642	4482971	4476306
2.5 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	28013	27882	29791	29791	29791	29791	30007
2.6 आरबीआई की निवल गैर मौद्रिक देयताएं	1308500	1324383	1531460	1573747	1535228	1505561	1496402

सं. 12: वाणिज्यिक बैंक सर्वेक्षण

(₹ करोड़)

मद	माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवारों/ माह के रिपोर्टिंग शुक्रवारों की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2022-23	2022	2023		
		फर. 25	जन. 27	फर. 10	फर. 24
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 निवासियों की कुल जमाराशियां	17882783	16083342	17563894	17614084	17701702
1.1.1 मांग जमाराशियां	2180402	1963976	2156747	2091305	2150731
1.1.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां	15702381	14119366	15407147	15522779	15550972
1.1.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियां	7066072	6353715	6933216	6985251	6997937
1.1.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र (सीडी)	304088	128422	282706	270840	282944
1.1.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां	8636310	7765651	8473931	8537528	8553034
1.2 वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधीयन	445329	276739	459769	463199	466945
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	20197172	17266754	19655333	19765532	19899791
2.1.1 सरकार को ऋण	5414322	4669023	5193768	5267113	5336711
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	14782850	12597731	14461566	14498419	14563080
2.1.2.1 बैंक ऋण	13675228	11643717	13337536	13418060	13450269
2.1.2.1.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	13655322	11575493	13287371	13373764	13414992
2.1.2.2 प्राथमिक व्यापारियों को निवल ऋण	19491	9095	21097	20828	23081
2.1.2.3 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	826	1209	853	848	847
2.1.2.4 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में)	1087305	943710	1102079	1058683	1088883
2.2 वाणिज्यिक बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (2.2.1-2.2.2-2.2.3)	114930	180910	91276	93596	130829
2.2.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	353850	384970	318413	317345	357705
2.2.2 अनिवासी विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तनीय मीयादी जमाराशियां	160923	134187	155534	159441	160152
2.2.3 समुद्रपार विदेशी मुद्रा उधार	77997	69873	71602	64308	66724
2.3 निवल बैंक रिज़र्व (2.3.1+2.3.2-2.3.3)	833002	1461464	906743	895413	874539
2.3.1 आरबीआई के पास शेष	809907	664473	813573	805398	797986
2.3.2 उपलब्ध नकदी	90263	88258	110431	105816	88146
2.3.3 आरबीआई से ऋण और अग्रिम	67168	-708733	17261	15801	11593
2.4 पूंजी खाता	1916966	1739748	1912431	1914924	1914869
2.5 अन्य मदें (निवल) (2.1+2.2+2.3-2.4-1.1-1.2)	900026	809300	717259	762333	821643
2.5.1 अन्य मांग और मीयादी देयताएं (2.2.3 का निवल)	710215	568393	660098	710034	696225
2.5.2 निवल अंतर-बैंक देयताएं (प्राथमिक व्यापारियों से इतर)	44693	28229	32462	55719	44850

सं. 13: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश

(₹ करोड़)

मद	25 मार्च 2022 की स्थिति	2022	2023		
		फर. 25	जन. 27	फर. 10	फर. 24
	1	2	3	4	5
1 एसएलआर प्रतिभूतियां	4728948	4670231	5194621	5267961	5337558
2 अन्य सरकारी प्रतिभूतियां (गैर-एसएलआर)	-	-	181956	182553	182650
3 वाणिज्यिक पत्र	55315	49155	52392	55078	56361
4 निम्नलिखित द्वारा जारी शेयर					
4.1 सरकारी उद्यम	7642	8384	10047	10096	9829
4.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	73814	73319	70612	70608	70826
4.3 अन्य	5152	5014	5071	4788	4757
5 निम्नलिखित द्वारा जारी बांड / डिबेंचर					
5.1 सरकारी उद्यम	117860	117941	90212	90183	90873
5.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	326188	336955	326385	299306	325678
5.3 अन्य	148753	142778	97973	100869	101399
6 निम्नलिखित द्वारा जारी लिखत					
6.1 म्यूचुअल फंड	34404	43286	58938	55954	56553
6.2 वित्तीय संस्थाएं	174090	166879	191608	189248	189957

टिप्पणी : कॉलम संख्या (1), (2) और (3) के डेटा अंतिम हैं, और कॉलम (4) एवं (5) के डेटा अनंतिम हैं।
'-' डेटा उपलब्ध नहीं हैं।

सं. 14: भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

(₹ करोड़)

मद	अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार (मार्च के संबंध में) /अंतिम शुक्रवार की स्थिति							
	सभी अनुसूचित बैंक				सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक			
	2021-22	2022	2023		2021-22	2022	2023	
		फर.	जन.	फर.		फर.	जन.	फर.
	1	2	3	4	5	6	7	8
सूचना देने वाले बैंकों की संख्या	212	212	212	212	136	136	137	137
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं	**262674**	**255874**	**329409**	**348005**	**258649**	**251956**	**326191**	**344778**
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	194143	185500	210725	219565	190570	182114	208480	217311
1.2 बैंकों से उधार राशि	38369	44491	63049	68709	38317	44343	62698	68361
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	30162	25883	55635	59731	29762	25499	55013	59106
2 अन्य के प्रति देयताएं	**17832517**	**17569489**	**19353582**	**19537234**	**17380755**	**17132534**	**18910898**	**19091748**
2.1 कुल जमाराशियां	16899634	16638218	18145363	18290154	16465313	16217529	17719428	17861854
2.1.1 मांग	2117513	2006907	2201162	2197093	2072747	1963976	2156747	2150731
2.1.2 मीयादी	14782121	14631311	15944201	16093061	14392567	14253553	15562681	15711123
2.2 उधार	278985	281772	464367	471760	274594	276739	459769	466945
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	653898	649500	743851	775320	640848	638266	731701	762949
3 रिज़र्व बैंक से उधार	**94299**	**96123**	**121622**	**109026**	**94299**	**96123**	**121622**	**109026**
3.1 मीयादी बिल / वचन पत्रों की जमानत पर	–	–	–	–	–	–	–	–
3.2 अन्य	94299	96123	121622	109026	94299	96123	121622	109026
4 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेष	788725	771413	945680	906590	769363	752731	924004	886132
4.1 उपलब्ध नकदी	88732	90640	112768	90492	85926	88258	110431	88146
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष	699993	680772	832912	816098	683437	664473	813573	797986
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां	**315282**	**296277**	**376259**	**388234**	**243637**	**232823**	**314826**	**323009**
5.1 अन्य बैंकों के पास शेष	199434	196853	227365	234118	164240	161886	190072	195668
5.1.1 चालू खाते में	19733	23926	24940	29876	16691	21250	21710	27045
5.1.2 अन्य खातों में	179701	172927	202425	204241	147549	140636	168362	168623
5.2 मांग और अल्पसूचना पर मुद्रा	36905	27515	40131	39207	6982	6053	21711	20448
5.3 बैंकों को अग्रिम	39340	36348	43544	44408	35802	32138	40586	39919
5.4 अन्य आस्तियां	39603	35561	65218	70501	36613	32746	62457	66974
6 निवेश	**4874070**	**4810498**	**5340544**	**5483663**	**4728948**	**4670231**	**5194621**	**5337558**
6.1 सरकारी प्रतिभूतियां	4867102	4803361	5333965	5477026	4728179	4669023	5193768	5336711
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	6968	7136	6579	6637	769	1209	853	847
7 बैंक ऋण	**12259048**	**12003700**	**13734998**	**13852956**	**11891314**	**11643717**	**13337536**	**13450269**
7ए खाद्यान्न ऋण	90827	104041	95913	80994	55011	68224	50165	35276
7.1 ऋण नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	12016486	11774926	13500963	13611233	11651337	11417404	13106520	13212088
7.2 देशी बिल - खरीदे गए	36070	34151	34384	37032	36055	34138	34366	37020
7.3 देशी बिल- भुनाए गए	155796	146599	153963	159300	154212	145123	151575	156351
7.4 विदेशी बिल - खरीदे गए	19537	19676	17315	17307	19157	19269	17142	17161
7.5 विदेशी बिल - भुनाए गए	31160	28348	28373	28085	30554	27783	27933	27649

टिप्पणी : कॉलम (4) एवं (8) के डेटा अनंतिम हैं।

सं. 15: प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का अभिनियोजन

(₹ करोड़)

क्षेत्र	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 25, 2022	2022	2023		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
		फर. 25	जन. 27	फर. 24	2022-23	2023
	1	2	3	4	%	%
I. बैंक ऋण (II+III)	**11891314**	**11643717**	**13341662**	**13450706**	**13.1**	**15.5**
II. खाद्यान्न ऋण	**55011**	**68224**	**50165**	**35276**	**-35.9**	**-48.3**
III. गैर-खाद्यान्न ऋण	**11836304**	**11575493**	**13291496**	**13415430**	**13.3**	**15.9**
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां	**1461719**	**1440634**	**1638079**	**1655938**	**13.3**	**14.9**
2. उद्योग	**3156067**	**3076840**	**3288720**	**3291205**	**4.3**	**7.0**
2.1 सूक्ष्म और लघु	532792	518873	578976	587494	10.3	13.2
2.2 मझौले	213996	206949	235162	234858	9.7	13.5
2.3 बड़े	2409279	2351018	2474582	2468853	2.5	5.0
3. सेवाएं	**3011975**	**2920284**	**3477752**	**3523813**	**17.0**	**20.7**
3.1 परिवहन परिचालक	155352	148976	166550	168735	8.6	13.3
3.2 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	20899	20317	21071	20621	-1.3	1.5
3.3 पर्यटन, होटल और रेस्तरां	64378	64304	64909	65234	1.3	1.4
3.4 शिपिंग	8436	7303	7259	6881	-18.4	-5.8
3.5 नौवहन	23979	23890	27824	27819	16.0	16.4
3.6 पेशेवर सेवाएं	116742	113845	127711	131443	12.6	15.5
3.7 व्यापार	696301	683736	777832	798032	14.6	16.7
3.7.1 थोक व्यापार	351213	344335	381139	389231	10.8	13.0
3.7.2 खुदरा व्यापार	345088	339401	396692	408801	18.5	20.4
3.8 वाणिज्यिक स्थावर संपदा	291168	288326	313440	312809	7.4	8.5
3.9 गैर -बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी)[1] जिसमें से	1022399	988882	1287906	1309521	28.1	32.4
3.9.1 आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी)	282048	273442	309755	307870	9.2	12.6
3.9.2 सरकारी वित्तीय संस्थाएं (पीएफआई)	137084	129407	181803	178651	30.3	38.1
3.10 अन्य सेवाएं [2]	612320	580704	683251	682720	11.5	17.6
4 वैयक्तिक ऋण	**3386982**	**3333416**	**3958874**	**4013299**	**18.5**	**20.4**
4.1 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	27628	26552	36910	37011	34.0	39.4
4.2 आवास	1684424	1661241	1888144	1910531	13.4	15.0
4.3 मीयादी जमाराशि पर अग्रिम	83379	79349	109749	113457	36.1	43.0
4.4 शेयरों और बांडों पर व्यक्तियों को अग्रिम	6261	6195	6858	6937	10.8	12.0
4.5 क्रेडिट कार्ड बकाया	148416	144646	186783	186856	25.9	29.2
4.6 शिक्षा	82723	82887	95226	96164	16.2	16.0
4.7 वाहन ऋण	402689	401800	496662	495922	23.2	23.4
4.8 सोने के आभूषण पर ऋण	73960	73193	85928	87822	18.7	20.0
4.9 अन्य वैयक्तिक ऋण	877503	857554	1052614	1078599	22.9	25.8
5. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र *(मेमो)*						
(i) कृषि और संबद्ध गतिविधियां[3]	1484923	1448989	1656599	1686333	13.6	16.4
(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यम[4]	1377848	1381186	1534099	1561345	13.3	13.0
(iii) मध्यम उद्यम [5]	351900	347595	393252	390714	11.0	12.4
(iv) आवास	616814	606141	614829	619039	0.4	2.1
(v) शिक्षा ऋण	58118	58553	59250	59362	2.1	1.4
(vi) नवीकरणीय ऊर्जा	3842	2750	4617	4642	20.8	68.8
(vii) सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर	2483	2545	2499	2449	-1.4	-3.8
(viii) निर्यात ऋण	24177	23965	14390	14396	-40.5	-39.9
(ix) अन्य	37159	40414	48680	50056	34.7	23.9
(x) नेट पीएसएलसी- एसएफ /एमएफ सहित कमजोर वर्ग	1180928	1142535	1365708	1428627	21.0	25.0

टिप्पणी 1: डेटा अनंतिम हैं। बैंक ऋण, खाद्य ऋण और गैर-खाद्य ऋण डेटा धारा -42 रिटर्न पर आधारित हैं जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को शामिल किया गया है, जबकि क्षेत्रीय गैर-खाद्य ऋण डेटा क्षेत्र-वार और उद्योग-वार बैंक क्रेडिट (एसआईबीसी) रिटर्न पर आधारित हैं, जिसमें उन चुनिंदा बैंकों को शामिल किया जाता है जो एससीबी द्वारा प्रदान किए गए कुल गैर-खाद्य ऋण के 93 प्रतिशत के लिए उत्तरदायी होते हैं।

टिप्पणी 2: जनवरी 2019 से, क्षेत्रीय क्रेडिट डेटा संशोधित प्रारूप पर आधारित हैं, जिसके कारण पहले प्रकाशित किए गए कुछ मौजूदा घटकों के मूल्य और विकास दर परिवर्तनों से गुजरे हैं। टिप्पणी 3: दिसंबर 2021 से चुनिंदा एससीबी द्वारा पिछली रिपोर्टिंग त्रुटियों के लिए क्रेडिट डेटा समायोजित किया जाता है।

1. एनबीएफसी में एचएफसी, पीएफआई, माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस (एमएफआई), गोल्ड लोन में लगी एनबीएफसी और अन्य शामिल हैं।
2. अन्य सेवाओं" में म्यूचुअल फंड (एमएफ), एनबीएफसी और एमएफ के अलावा बैंकिंग और वित्त और अन्य सेवाएं शामिल हैं जिन्हें सेवाओं के तहत कहीं और इंगित नहीं किया गया है।
3. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत कृषि और संबद्ध कार्यकलापों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रमाण-पत्र (पीएसएलसी) भी शामिल हैं।
4. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत "सूक्ष्म और लघु उद्यमों" में उद्योग और सेवा क्षेत्रों में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण शामिल है और इसमें पीएसएलसी भी शामिल हैं।
5. प्राथमिकता क्षेत्र के तहत "मध्यम उद्यमों" में उद्योग और सेवा क्षेत्रों में मध्यम उद्यमों को ऋण शामिल है।

सं. 16: सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार अभिनियोजन

(₹ करोड़)

उद्योग	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 25, 2022	2022	2023		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
		फर. 25	जन. 27	फर. 24	2022-23	2023
	1	2	3	4	%	%
2 उद्योग (2.1 से 2.19)	3156067	3076840	3288720	3291205	4.3	7.0
2.1 खनन और उत्खनन (कोयला सहित)	49135	47287	56354	57348	16.7	21.3
2.2 खाद्य प्रसंस्करण	173246	168020	173768	177739	2.6	5.8
2.2.1 चीनी	26307	23874	18911	21171	–19.5	–11.3
2.2.2 खाद्य तेल और वनस्पति	18246	17450	18941	19005	4.2	8.9
2.2.3 चाय	5728	5481	5080	5005	–12.6	–8.7
2.2.4 अन्य	122965	121215	130836	132558	7.8	9.4
2.3 पेय पदार्थ और तंबाकू	18176	17854	20612	22098	21.6	23.8
2.4 वस्त्र	224026	221765	219820	222372	–0.7	0.3
2.4.1 सूती वस्त्र	90384	90887	86588	88073	–2.6	–3.1
2.4.2 जूट से बने वस्त्र	3509	3359	3848	4046	15.3	20.5
2.4.3 मानव-निर्मित वस्त्र	38371	37331	39630	39624	3.3	6.1
2.4.4 अन्य वस्त्र	91761	90189	89753	90628	–1.2	0.5
2.5 चमड़ा और चमड़े से बने उत्पाद	11573	11309	11494	11480	–0.8	1.5
2.6 लकड़ी और लकड़ी से बने उत्पाद	16294	16004	18790	19204	17.9	20.0
2.7 काग़ज़ और काग़ज़ से बने उत्पाद	40565	40341	42674	42608	5.0	5.6
2.8 पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और आण्विक इंधन	107333	97804	150285	146052	36.1	49.3
2.9 रसायन और रासायनिक उत्पाद	196363	185011	215056	213080	8.5	15.2
2.9.1 उवर्रक	33160	28814	35009	33656	1.5	16.8
2.9.2 औषधि और दवाइयां	61093	58527	66403	66686	9.2	13.9
2.9.3 पेट्रो केमिकल्स	19622	19357	20878	20467	4.3	5.7
2.9.4 अन्य	82486	78313	92767	92271	11.9	17.8
2.10 रबड़, प्लास्टिक और उनके उत्पाद	72013	70442	77560	77492	7.6	10.0
2.11 कांच और कांच के सामान	5952	5763	7763	7934	33.3	37.7
2.12 सीमेन्ट और सीमेन्ट से बने उत्पाद	47910	47884	52846	54884	14.6	14.6
2.13 मूल धातु और धातु उत्पाद	288531	281539	336682	336959	16.8	19.7
2.13.1 लोहा और स्टील	187584	185513	229716	228316	21.7	23.1
2.13.2 अन्य धातु और धातु से बने उत्पाद	100946	96025	106966	108643	7.6	13.1
2.14 सभी अभियांत्रिकी	167966	162456	170022	173395	3.2	6.7
2.14.1 इलेक्ट्रानिक्स	38179	37209	40644	41136	7.7	10.6
2.14.2 अन्य	129787	125247	129378	132260	1.9	5.6
2.15 वाहन, वाहन के पुर्जे और परिवहन उपस्कर	89896	87377	96844	97942	9.0	12.1
2.16 रत्न और आभूषण	80512	77890	75160	75547	–6.2	–3.0
2.17 निर्माण	117724	117235	116511	120428	2.3	2.7
2.18 इन्फ्रास्ट्रक्चर	1195027	1172319	1185454	1178969	–1.3	0.6
2.18.1 पॉवर	611410	600259	605986	604072	–1.2	0.6
2.18.2 दूरसंचार	130318	126059	110506	111184	–14.7	–11.8
2.18.3 सड़क	270395	262119	284739	280012	3.6	6.8
2.18.4 हवाई अड्डा	6646	6638	9217	9181	38.1	38.3
2.18.5 बंदरगाह	8886	8803	7860	8209	–7.6	–6.7
2.18.6 रेलवे	10512	13954	10851	10936	4.0	–21.6
2.18.7 अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर	156860	154486	156294	155376	–0.9	0.6
2.19 अन्य उद्योग	253823	248539	261025	255674	0.7	2.9

टिप्पणी : जनवरी 2019 से, क्षेत्रीय ऋण डेटा संशोधित प्रारूप पर आधारित हैं, जिसके कारण पहले प्रकाशित कुछ मौजूदा घटकों के मान और विकास दर में कुछ बदलाव हुए हैं।

सं. 17: भारतीय रिज़र्व बैंक में राज्य सहकारी बैंकों के खाते

(₹ करोड़)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार (मार्च के संबंध में)/अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की स्थिति								
	2021-22	2022						2023	
		जन. 28	नवं. 18	नवं. 25	दिसं. 02	दिसं. 16	दिसं. 30	जन. 13	जन. 27
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
सूचना देने वाले बैंकों की संख्या	32	33	33	33	33	33	33	33	33
1 कुल जमाराशियां (2.1.1.2+2.2.1.2)	**126746.8**	**127431.3**	**126894.1**	**127382.3**	**127292.9**	**128339.4**	**130835.1**	**132887.9**	**133539.0**
2 मांग और मीयादी देयताएं									
2.1 मांग देयताएं	**23533.1**	**24041.4**	**25577.6**	**24931.7**	**25574.4**	**26161.0**	**28819.3**	**27185.8**	**26514.9**
2.1.1 जमाराशियां									
2.1.1.1 अंतर-बैंक	4281.2	5534.4	5568.0	5197.9	5822.7	5522.9	5201.5	6029.5	5760.8
2.1.1.2 अन्य	14,413.7	13490.3	14228.8	14221.3	14281.6	14807.4	15609.5	15866.7	15381.7
2.1.2 बैंकों से उधार	0.0	0.0	404.9	624.7	544.7	624.7	50.0	0.0	0.0
2.1.3 अन्य मांग देयताएं	4838.2	5016.7	5376.0	4887.9	4925.4	5206.1	7958.3	5289.6	5372.4
2.2 मीयादी देयताएं	**181808.1**	**178141.3**	**171549.2**	**172191.9**	**171447.3**	**172012.1**	**174159.8**	**175067.2**	**176298.1**
2.2.1 जमाराशियां									
2.2.1.1 अंतर-बैंक	66572.3	61099.8	54040.1	54088.1	54278.4	54295.2	55395.7	55338.6	55159.9
2.2.1.2 अन्य	112333.1	113941.1	112665.3	113161.0	113011.3	113532.1	115225.6	117021.2	118157.3
2.2.2 बैंकों से उधार	899.9	876.9	2433.3	2519.3	1715.3	1734.4	1074.3	1764.1	2032.1
2.2.3 अन्य मीयादी देयताएं	2002.7	2223.6	2410.4	2423.5	2442.3	2450.5	2464.2	943.3	948.7
3 रिज़र्व बैंक से उधार	0.0	0.0	35.0	35.0	35.0	35.0	0.0	0.0	0.0
4 अधिसूचित बैंक/राज्य सरकार से उधार	58868.2	64328.2	73458.8	73686.9	74853.3	74975.2	79539.1	131532.1	78164.1
4.1 मांग	12625.5	12684.0	15528.3	15498.3	15914.2	15783.7	17875.0	17952.8	17966.9
4.2 मीयादी	46242.7	51644.2	57930.5	58188.6	58939.1	59191.5	61664.2	113579.2	60197.2
5 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेष	**8371.5**	**9868.9**	**10229.6**	**10166.0**	**10547.0**	**10820.3**	**11342.1**	**11647.2**	**11360.2**
5.1 उपलब्ध नकदी	602.2	705.8	867.6	777.6	846.0	856.4	893.9	1224.4	732.3
5.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष	7769.3	9163.0	9362.0	9388.3	9701.0	9963.9	10448.2	10422.8	10627.9
6 चालू खाते में अन्य बैंकों के पास शेष	**894.4**	**1275.4**	**1560.4**	**1557.2**	**1561.1**	**1555.0**	**1676.2**	**1641.3**	**1850.1**
7 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	**66350.1**	**71991.8**	**73166.1**	**72325.9**	**72326.1**	**72684.3**	**72306.1**	**72808.5**	**72775.3**
8 मांग और अल्प सूचना पर मुद्रा	**25325.3**	**25584.6**	**17899.7**	**18018.5**	**17284.9**	**17449.4**	**23466.4**	**20920.3**	**21666.8**
9 बैंक ऋण (10.1+11)	**117228.4**	**110029.1**	**120186.2**	**120652.2**	**120965.0**	**121585.0**	**121588.2**	**122782.6**	**123897.1**
10 अग्रिम									
10.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	**117209.2**	**110008.5**	**120147.3**	**120612.7**	**120925.5**	**121543.5**	**121546.4**	**122742.4**	**123866.2**
10.2 बैंकों से प्राप्य राशि	87632.4	103697.0	117456.0	117682.0	117687.7	118828.7	122854.5	124378.1	125739.6
11 खरीदे और भुनाए गए बिल	19.2	20.6	38.8	39.5	39.5	41.5	41.7	40.3	30.9

कीमत और उत्पादन

सं. 18: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2012=100)

समूह/उप समूह	2021-22			ग्रामीण			शहरी			मिश्रित		
	ग्रामीण	शहरी	मिश्रित	फर. '22	जन.'23	फर.'23(अ)	फर.'22	जन.'23	फर.'23(अ)	फर.'22	जन.'23	फर.'23(अ)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 खाद्य और पेय पदार्थ	**162.8**	**168.7**	**165.0**	**163.9**	**175.0**	**174.7**	**170.2**	**179.5**	**179.8**	**166.2**	**176.7**	**176.6**
1.1 अनाज और उत्पाद	146.4	150.4	147.6	148.8	174.0	175.3	152.5	173.3	174.8	150.0	173.8	175.1
1.2 मांस और मछली	200.4	206.5	202.6	198.1	208.3	205.0	205.2	215.2	211.7	200.6	210.7	207.4
1.3 अंडा	173.3	176.0	174.4	175.5	192.9	182.6	176.4	197.0	184.6	175.8	194.5	183.4
1.4 दूध और उत्पाद	158.3	159.0	158.6	160.7	174.3	175.8	160.6	175.2	176.9	160.7	174.6	176.2
1.5 तेल और वसा	192.2	172.4	184.9	192.6	192.6	188.9	171.5	178.0	175.6	184.9	187.2	184.0
1.6 फल	155.3	163.5	159.2	151.4	156.3	161.2	156.4	160.5	166.1	153.7	158.3	163.5
1.7 सब्जी	156.1	192.8	168.5	155.2	142.9	138.7	198.0	175.3	172.1	169.7	153.9	150.0
1.8 दाल और उत्पाद	164.1	164.4	164.2	163.9	170.7	170.1	163.2	171.2	171.1	163.7	170.9	170.4
1.9 चीनी और उत्पाद	117.4	119.1	118.0	118.1	120.3	119.5	120.6	122.7	122.2	118.9	121.1	120.4
1.10 मसाले	171.2	167.5	170.0	175.4	210.5	211.9	172.2	204.3	204.8	174.3	208.4	209.5
1.11 गैर-नशीले पेय पदार्थ	167.8	154.7	162.3	170.5	176.9	177.3	156.7	163.7	164.3	164.7	171.4	171.9
1.12 तैयार भोजन, नाश्ता, मिठाई	173.0	175.8	174.3	176.3	188.5	189.2	180.0	194.3	195.7	178.0	191.2	192.2
2 पान, तंबाकू और मादक पदार्थ	**190.3**	**196.5**	**191.9**	**191.5**	**196.9**	**197.8**	**196.5**	**201.6**	**202.2**	**192.8**	**198.2**	**199.0**
3 कपड़ा और जूते	**168.2**	**158.4**	**164.3**	**173.7**	**188.6**	**189.2**	**163.4**	**176.6**	**177.4**	**169.6**	**183.8**	**184.5**
3.1 कपड़ा	168.8	160.9	165.7	174.1	189.0	189.6	165.7	178.7	179.4	170.8	184.9	185.6
3.2 जूते	164.5	144.7	156.3	171.0	186.3	186.9	150.4	165.3	166.2	162.4	177.6	178.3
4 आवास	--	**163.0**	**163.0**	--	--	--	**165.5**	**172.1**	**173.5**	**165.5**	**172.1**	**173.5**
5 ईंधन और लाइट	**164.0**	**159.8**	**162.4**	**167.4**	**183.2**	**183.0**	**163.0**	**180.1**	**180.7**	**165.7**	**182.0**	**182.1**
6 विविध	**164.1**	**156.1**	**160.2**	**167.3**	**176.5**	**177.3**	**159.4**	**168.9**	**169.5**	**163.5**	**172.8**	**173.5**
6.1 घरेलू सामान और सेवा	161.8	153.5	157.9	165.7	177.2	178.0	157.4	168.0	168.8	161.8	172.9	173.7
6.2 स्वास्थ्य	172.0	163.3	168.6	175.3	184.7	185.6	167.2	178.5	179.9	172.2	182.3	183.4
6.3 परिवहन और संचार	157.9	150.0	153.7	161.2	168.2	168.7	153.1	159.5	159.6	156.9	163.6	163.9
6.4 मनोरंजन	162.7	154.8	158.2	165.5	171.8	172.3	159.5	167.8	168.1	162.1	169.5	169.9
6.5 शिक्षा	168.4	160.1	163.5	170.3	177.8	178.2	162.0	171.8	172.2	165.4	174.3	174.7
6.6 व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव	161.3	160.8	161.1	164.5	178.4	179.7	164.2	178.8	180.1	164.4	178.6	179.9
सामान्य सूचकांक (सभी समूह)	**164.5**	**163.1**	**163.8**	**166.7**	**177.8**	**177.9**	**165.5**	**174.9**	**175.6**	**166.1**	**176.5**	**176.8**

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

अ: अनंतिम

सं. 19: अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

मद	आधार वर्ष	योजक कारक	2021-22	2022	2023	
				फर.	जन.	फर.
	1	2	3	4	5	6
1 औद्योगिक कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	2016	2.88	123.6	125	132.8	132.7
2 कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	5.89	1075	1095	1170	1171
3 ग्रामीण श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	–	1084	1106	1181	1182

स्रोत: श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 20: मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य

मद	2021-22	2022	2023	
		फर.	जन.	फर.
	1	2	3	4
1 मानक स्वर्ण (₹ प्रति 10 ग्राम)	47999	49254	56246	56646
2 चांदी (₹ प्रति किलोग्राम)	65426	63175	68305	66402

स्रोत: मुंबई में सोने और चांदी के मूल्य के लिए भारत बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लि., मुंबई।

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक

(आधारः 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2021-22	2022		2023	
			फर.	दिसं.	जन. (अ)	फर. (अ)
	1	2	3	4	5	6
1 सभी पण्य वस्तुएँ	**100.000**	**139.4**	**145.3**	**150.5**	**150.6**	**150.9**
1.1 प्राथमिक वस्तुएं	**22.618**	**160.7**	**167.5**	**172.9**	**174.0**	**173.0**
1.1.1 खाद्य वस्तुएं	**15.256**	**167.3**	**170.4**	**174.9**	**176.1**	**176.9**
1.1.1.1 खाद्यान्न (अनाज+ दाल)	3.462	163.5	165.9	184.4	187.0	185.4
1.1.1.2 फल और सब्जियाँ	3.475	187.6	192.1	173.1	171.2	172.8
1.1.1.3 दूध	4.440	156.9	157.8	169.9	171.5	174.1
1.1.1.4 अंडा, मांस और मछली	2.402	164.0	167.3	167.0	169.3	169.8
1.1.1.5 मसाले	0.529	159.8	170.3	191.5	195.7	191.6
1.1.1.6 अन्य खाद्य वस्तुएं	0.948	168.3	173.8	181.3	181.9	183.4
1.1.2 खाद्येतर वस्तुएं	**4.119**	**158.1**	**170.2**	**171.2**	**173.4**	**170.4**
1.1.2.1 फाइबर	0.839	158.4	190.4	188.6	185.3	183.3
1.1.2.2 तिलहन	1.115	214.4	215.4	199.7	201.9	199.5
1.1.2.3 अन्य खाद्येतर वस्तुएं	1.960	119.9	123.3	135.4	136.6	135.0
1.1.2.4 पुष्पोत्पादन	0.204	217.0	290.2	288.6	321.8	297.7
1.1.3 खनिज	**0.833**	**197.2**	**225.0**	**203.9**	**203.9**	**201.1**
1.1.3.1 धात्विक खनिज	0.648	193.3	226.9	190.2	190.2	185.9
1.1.3.2 अन्य खनिज	0.185	211.0	218.6	252.0	251.8	254.5
1.1.4 पेट्रोलियम और नैसर्गिक गैस	**2.410**	**110.3**	**125.1**	**152.4**	**151.4**	**143.2**
1.2 ईंधन और पेट्रोलियम	**13.152**	**124.6**	**138.3**	**158.0**	**155.8**	**158.8**
1.2.1 कोल	**2.138**	**129.0**	**130.9**	**134.3**	**134.3**	**135.3**
1.2.1.1 कुकिंग कोल	0.647	143.0	143.4	143.4	143.4	143.4
1.2.1.2 नॉन-कुकिंग कोल	1.401	119.8	119.8	119.8	119.8	119.8
1.2.1.3 लिग्नाइट	0.090	170.5	212.6	294.3	294.3	317.9
1.2.2 खनिज तेल	**7.950**	**126.2**	**142.9**	**164.4**	**160.9**	**165.5**
1.2.3 बिजली	**3.064**	**117.4**	**131.8**	**157.7**	**157.7**	**157.7**
1.3 विनिर्मित उत्पाद	**64.231**	**135.0**	**138.9**	**141.1**	**141.3**	**141.6**
1.3.1 खाद्य उत्पादों का विनिर्माण	**9.122**	**157.9**	**160.5**	**163.6**	**163.1**	**162.0**
1.3.1.1 मांस का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.134	142.8	141.0	144.6	142.7	142.2
1.3.1.2 मछली, क्रस्टेशियस, मोलस्क और उनके उत्पादों का प्रसंस्करण एवं परिरक्षण	0.204	144.1	147.3	146.6	146.8	140.0
1.3.1.3 फल और सब्जियों का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.138	122.3	122.5	127.5	126.9	126.1
1.3.1.4 सब्जियां और पशु तेल एवं वसा	2.643	187.2	190.1	168.7	166.7	163.5
1.3.1.5 डेयरी उत्पाद	1.165	149.4	151.9	170.7	171.9	173.3
1.3.1.6 अनाज मिल के उत्पाद	2.010	145.6	147.6	168.3	169.6	169.1
1.3.1.7 स्टार्च और स्टार्च के उत्पाद	0.110	133.3	146.7	158.5	159.2	158.2
1.3.1.8 बेकरी उत्पाद	0.215	146.2	150.8	166.6	165.7	166.2
1.3.1.9 चीनी,गुड़ और शहद	1.163	122.9	124.8	127.9	127.2	127.3
1.3.1.10 कोक, चॉकलेट और चीनी कन्फेक्शनरी	0.175	130.5	133.8	138.8	137.9	138.0
1.3.1.11 मैक्रोनी, नूडल्स, कूसकूस और उसके जैसे मैदे से बने उत्पाद	0.026	136.7	144.3	148.7	154.6	153.7
1.3.1.12 चाय और कॉफी उत्पाद	0.371	171.1	165.8	172.8	167.3	167.0
1.3.1.13 प्रसंस्कृत मसाले और नमक	0.163	157.5	163.7	181.6	181.8	178.8
1.3.1.14 प्रसंस्कृत तैयार खाद्य पदार्थ	0.024	137.0	138.6	140.8	141.5	141.8
1.3.1.15 स्वास्थ्य पूरक	0.225	153.5	164.2	181.8	181.0	181.1
1.3.1.16 पशु के लिए तैयार खाद्य	0.356	200.9	204.1	209.1	208.9	208.2
1.3.2 पेय पदार्थों का विनिर्माण	**0.909**	**126.8**	**127.6**	**129.1**	**130.0**	**130.3**
1.3.2.1 शराब और स्पिरीट	0.408	123.6	124.9	131.2	131.5	132.0
1.3.2.2 माल्ट लिकर और माल्ट	0.225	130.5	132.7	133.8	134.9	134.4
1.3.2.3 शीतल पेय,मिनरल वॉटर और बोतलबन्द पानी के अन्य उत्पाद	0.275	128.6	127.3	122.3	123.7	124.4
1.3.3 विनिर्मित तंबाकू उत्पाद	**0.514**	**160.2**	**159.8**	**166.1**	**166.4**	**166.2**
1.3.3.1 तंबाकू के उत्पाद	0.514	160.2	159.8	166.1	166.4	166.2

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक *(जारी)*

(आधारः 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2021-22	2022		2023	
			फर.	दिसं.	जन. (अ)	फर. (अ)
1.3.4 वस्त्र विनिर्माण	**4.881**	**135.2**	**142.4**	**137.6**	**137.2**	**137.4**
1.3.4.1 धागों की कताई और वस्त्र तैयार करना	2.582	128.2	137.9	124.3	123.7	124.1
1.3.4.2 बुनाई और तैयार वस्त्र	1.509	146.8	151.8	158.4	158.9	159.2
1.3.4.3 बुने हुए और क्रॉचिडेट फेब्रिक्स	0.193	125.5	130.0	126.2	124.1	124.0
1.3.4.4 कपड़ों को छोड़कर निर्मित वस्त्र सामग्री	0.299	138.7	142.3	153.1	152.7	153.0
1.3.4.5 डोरियाँ, रस्सी, सुतली और नेटिंग	0.098	168.5	165.7	151.7	149.3	147.4
1.3.4.6 अन्य वस्त्र	0.201	126.2	130.9	131.9	131.8	129.0
1.3.5 विनिर्मित तैयार वस्त्र	**0.814**	**143.1**	**144.7**	**149.6**	**149.5**	**149.7**
1.3.5.1 फर से बने वस्त्रों को छोड़कर बुने हुए तैयार वस्त्र	0.593	142.0	143.5	148.6	147.9	148.4
1.3.5.2 बुने हुए क्रॉस्चिटेड वस्त्र	0.221	145.8	147.8	152.1	153.9	153.2
1.3.6 चमड़ा और उससे बने हुए उत्पाद का विनिर्माण	**0.535**	**119.2**	**121.3**	**121.5**	**122.0**	**121.3**
1.3.6.1 चमड़े की टैनिंग और ड्रेसिंग; ड्रेसिंग और फर की रंगायी	0.142	103.4	107.2	103.4	104.7	102.1
1.3.6.2 सामान, हैंडबैग, काठी और दोहन	0.075	141.5	144.4	141.0	140.3	140.1
1.3.6.3 जूते-चप्पल	0.318	121.0	122.1	125.0	125.4	125.5
1.3.7 लकड़ी के विनिर्माण और लकड़ी और कॉर्क के उत्पाद	**0.772**	**141.0**	**142.9**	**143.1**	**143.3**	**143.1**
1.3.7.1 आरा मिलिंग और लकड़ी के उत्पाद	0.124	128.8	132.6	139.3	139.2	137.7
1.3.7.2 विनियर शीट,प्लायवुड का विनिर्माण,लॅमिन बोर्ड,पार्टिकल बोर्डऔर अन्य पॅनल और बोर्ड	0.493	141.9	143.5	141.2	141.3	141.4
1.3.7.3 बिल्डरों की बढ़ईगीरी	0.036	193.9	195.2	205.6	204.5	203.2
1.3.7.4 लकड़ी के डिब्बे	0.119	134.1	135.9	136.2	137.6	137.7
1.3.8 कागज़ और कागज़ के उत्पाद का विनिर्माण	**1.113**	**137.5**	**143.3**	**148.4**	**147.9**	**148.0**
1.3.8.1 लुगदी, कागज़ और कागज़ बोर्ड	0.493	141.4	146.2	156.8	156.3	157.5
1.3.8.2 लहरदार कागज़ और पेपर बोर्ड और कागज़ के पात्र और पेपर बोर्ड	0.314	137.8	142.5	145.2	145.2	143.9
1.3.8.3 कागज़ की अन्य सामग्री और पेपर बोर्ड	0.306	131.0	139.3	138.3	136.9	136.9
1.3.9 मुद्रण और रिकार्डेड मीडिया का पुनरुत्पादन	**0.676**	**157.8**	**160.5**	**177.7**	**177.8**	**177.1**
1.3.9.1 मुद्रण	0.676	157.8	160.5	177.7	177.8	177.1
1.3.10 रसायन और रासायनिक उत्पाद का विनिर्माण	**6.465**	**133.5**	**139.2**	**144.0**	**143.2**	**143.0**
1.3.10.1 मूल रसायन	1.433	143.8	153.2	155.4	152.6	151.8
1.3.10.2 उर्वरक और नाइट्रोजन यौगिक	1.485	129.6	133.8	147.3	146.2	145.8
1.3.10.3 प्लास्टिक और सिथेंटिक रबड़ प्राथमिक रूप में	1.001	140.3	143.9	136.4	138.6	140.7
1.3.10.4 कीटनाशक और अन्य एग्रोकेमिकल उत्पाद	0.454	132.1	139.7	143.8	142.0	141.6
1.3.10.5 पेन्ट, वार्निश और समान कोटिंग, मुद्रण स्याही और मैस्टिक्स	0.491	130.4	137.3	145.9	146.2	145.6
1.3.10.6 साबुन और डिटर्जेंट,सफाई और चमकाने की सामग्री, इत्र और शौचालय सफाई की सामग्री	0.612	128.1	128.0	142.3	141.8	141.2
1.3.10.7 अन्य रासायनिक उत्पाद	0.692	130.3	137.6	141.1	140.1	138.7
1.3.10.8 मानव निर्मित फाइबर	0.296	106.6	111.1	105.6	105.6	105.9
1.3.11 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद का विनिर्माण	**1.993**	**135.9**	**137.9**	**141.8**	**141.8**	**142.7**
1.3.11.1 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद	1.993	135.9	137.9	141.8	141.8	142.7
1.3.12 रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद का विनिर्माण	**2.299**	**124.8**	**127.3**	**128.1**	**128.3**	**128.7**
1.3.12.1 रबड़ टायर और ट्यूब,रबड़ टायर की रीट्रीडिंग और पुनर्निर्माण	0.609	104.3	106.4	113.3	113.3	114.3
1.3.12.2 रबड़ के अन्य उत्पाद	0.272	101.9	105.1	105.7	105.8	106.3
1.3.12.3 प्लास्टिक उत्पाद	1.418	138.0	140.6	138.8	139.1	139.2
1.3.13 अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण	**3.202**	**123.7**	**126.7**	**134.8**	**134.6**	**135.3**
1.3.13.1 कांच और कांच उत्पाद	0.295	139.1	144.7	164.1	164.8	164.2
1.3.13.2 आग रोधक उत्पाद	0.223	115.6	119.9	118.9	118.6	118.7
1.3.13.3 मिट्टी से बनी भवन निर्माण सामग्री	0.121	119.3	133.6	137.5	132.9	130.0
1.3.13.4 चीनी मिट्टी के बर्तन और चीनी मिट्टी	0.222	112.9	116.1	118.5	118.7	119.2
1.3.13.5 सीमेन्ट,चूना और प्लास्टर	1.645	126.4	128.4	137.6	137.6	138.9

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक *(जारी)*

(आधारः 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2021-22	2022		2023	
			फर.	दिसं.	जन. (अ)	फर. (अ)
1.3.13.6 कंक्रीट,सीमेन्ट और प्लास्टर से बनी वस्तुएं	0.292	129.2	130.6	135.1	134.5	135.6
1.3.13.7 पत्थरों को काटना,आकार देना और संवारना	0.234	122.2	120.5	126.9	126.8	126.4
1.3.13.8 अन्य अधात्विक खनिज उत्पाद	0.169	90.6	98.3	106.6	107.4	108.6
1.3.14 मूल धातुओं का विनिर्माण	**9.646**	**140.1**	**147.1**	**143.2**	**145.0**	**146.8**
1.3.14.1 स्टील तैयार करने में प्रयुक्त सामग्री	1.411	150.8	162.4	150.4	150.8	153.8
1.3.14.2 धात्विक लौह	0.653	147.7	154.9	157.6	160.8	162.2
1.3.14.3 नरम इस्पात-अर्ध निर्मित इस्पात	1.274	119.1	122.9	122.0	124.4	124.7
1.3.14.4 नरम इस्पात- लंबे उत्पाद	1.081	137.4	144.8	145.5	147.8	148.2
1.3.14.5 नरम इस्पात- चपटे उत्पाद	1.144	157.5	160.3	143.8	143.5	150.1
1.3.14.6 स्टेनलेस स्टील के अतिरिक्त एलॉय स्टील-आकार	0.067	133.7	143.6	141.3	143.6	144.8
1.3.14.7 स्टेनलेस स्टील अर्ध निर्मित	0.924	141.7	147.7	142.5	147.8	146.9
1.3.14.8 पाइप और ट्यूब	0.205	155.9	167.1	171.9	174.3	175.2
1.3.14.9 कीमती धातु सहित अलौह धातु	1.693	139.7	149.4	143.2	145.4	147.8
1.3.14.10 कास्टिंग	0.925	118.9	122.7	133.3	133.7	133.7
1.3.14.11 स्टील से गढ़ी वस्तुएं	0.271	159.0	165.8	175.7	174.3	175.4
1.3.15 मशीनरी और उपकरणों को छोड़कर गढ़े हुए धातु उत्पादों का विनिर्माण	**3.155**	**130.5**	**133.5**	**138.0**	**137.7**	**139.1**
1.3.15.1 इमारती धातु उत्पाद	1.031	123.9	125.3	132.4	131.4	132.0
1.3.15.2 धातु से बने टैंक,जलाशय और डिब्बे	0.660	156.2	159.8	156.3	155.6	159.6
1.3.15.3 वाष्प चालित जनरेटर, सेंट्रल हीटिंग हॉट वाटर बॉयलरर्स को छोड़कर	0.145	96.1	93.5	101.2	103.8	103.9
1.3.15.4 धातु की फोर्जिंग, दबाना, स्टैपिंग और रोल फॉर्मिंग, पाउडर धातुकर्म	0.383	117.5	126.2	135.6	135.6	138.5
1.3.15.5 कटलरी, हस्त चालित उपकरण और सामान्य हार्डवेयर	0.208	108.2	109.4	113.3	110.8	110.6
1.3.15.6 अन्य गढ़े हुए धातु उत्पाद	0.728	136.5	140.1	144.8	145.9	146.0
1.3.16 कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण	**2.009**	**113.7**	**116.4**	**116.7**	**117.6**	**117.0**
1.3.16.1 इलेक्ट्रॉनिक पुरजे	0.402	106.0	111.5	113.7	115.5	115.7
1.3.16.2 कंप्यूटर और संबंधित उपकरण	0.336	134.7	134.7	135.0	135.0	135.1
1.3.16.3 संचार उपकरण	0.310	121.7	128.6	130.7	130.7	130.5
1.3.16.4 उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स	0.641	102.1	102.3	100.2	101.8	99.7
1.3.16.5 मापने, जांचने, नेविगेशन और नियंत्रण उपकरण	0.181	108.4	112.2	112.5	112.9	113.0
1.3.16.6 हाथ घडी और दीवार घडी	0.076	145.6	148.4	151.3	151.5	151.9
1.3.16.7 विभासन, विद्युत चिकित्सकीय एवं विद्युत उपचारात्मक उपकरण	0.055	106.1	107.4	108.0	108.0	109.1
1.3.16.8 ऑप्टिकल उपकरण और फोटोग्राफिक उपकरण	0.008	98.3	99.7	101.8	100.4	100.3
1.3.17 इलेक्ट्रिकल उपकरण का विनिर्माण	**2.930**	**122.3**	**124.8**	**129.5**	**130.0**	**129.6**
1.3.17.1 विद्युत मोटर्स, जनरेटर, ट्रांसफार्मर और बिजली वितरण और नियंत्रण संबंधी उपकरण	1.298	119.7	121.2	128.1	129.2	126.8
1.3.17.2 बैटरी और एक्युम्युलेटर	0.236	121.8	125.1	131.7	131.5	131.6
1.3.17.3 डेटा संचरण या छवियों के सजीव प्रसारण के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल	0.133	103.1	106.4	119.1	119.3	119.7
1.3.17.4 अन्य इलेक्ट्रानिक और बिज़ली के वायर और केबल	0.428	140.7	146.5	144.1	145.5	148.5
1.3.17.5 वायरिंग संबंधी चीजें और बिजली के प्रकाश और सजावट के उपकरण	0.263	114.5	115.4	117.7	116.7	116.9
1.3.17.6 घरेलू उपकरण	0.366	128.4	131.3	133.7	133.7	134.0
1.3.17.7 अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण	0.206	113.2	113.9	119.7	119.1	120.4
1.3.18 मशीनरी और उपकरणों का विनिर्माण	**4.789**	**120.0**	**122.0**	**126.3**	**126.8**	**127.3**
1.3.18.1 इंजन और टर्बाइन,एयरक्राफ्ट, वाहन और दुपहिया वाहनों के इंजन को छोड़कर	0.638	119.2	121.4	125.9	126.3	127.6
1.3.18.2 तरल बिजली उपकरण	0.162	122.1	124.9	129.2	129.9	130.1
1.3.18.3 अन्य पंप, कंप्रेसर, नल और वाल्व	0.552	115.1	115.2	117.6	117.5	117.5
1.3.18.4 बेयरिंग, गियर्स, गेयरिंग और ड्राइविंग उपकरण	0.340	118.1	119.9	125.1	125.0	125.9
1.3.18.5 ओवन, फर्नेस और फर्नेस बर्नर	0.008	74.2	76.9	81.3	82.3	82.2
1.3.18.6 माल उठाने एवं चढ़ाने –उतारने वाले उपकरण	0.285	120.0	124.1	126.9	127.0	127.6

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (समाप्त)

(आधारः 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2021-22	2022		2023	
			फर.	दिसं.	जन. (अ)	फर. (अ)
1.3.18.7 कार्यालय मशीनरी और उपकरण	0.006	130.2	130.2	130.2	130.2	130.2
1.3.18.8 सामान्य प्रयोजन के अन्य उपकरण	0.437	133.4	135.5	138.6	144.2	144.5
1.3.18.9 कृषि और वानिकी मशीनरी	0.833	128.4	132.1	138.7	138.2	139.4
1.3.18.10 धातु निर्माण करनेवाली मशीनरी और मशीन टूल्स	0.224	114.2	116.5	121.1	121.2	121.2
1.3.18.11 खनन, उत्खनन और निर्माण के लिए मशीनरी	0.371	78.2	79.4	85.5	85.5	86.2
1.3.18.12 खाद्य, पेय और तंबाकू प्रसंस्करण के लिए मशीनरी	0.228	130.1	131.2	125.3	124.7	124.6
1.3.18.13 कपड़ा,परिधान और चमड़े के उत्पादन से जुड़ी मशीनरी	0.192	125.3	125.9	132.4	131.0	130.9
1.3.18.14 अन्य विशेष प्रयोजनों के लिए मशीनरी	0.468	134.7	136.1	142.2	142.8	142.6
1.3.18.15 नवीकरणीय विद्युत उत्पादन उपकरण	0.046	66.6	67.2	69.7	69.4	69.7
1.3.19 मोटर वाहन, ट्रेलरों और अर्ध-ट्रेलरों का विनिर्माण	**4.969**	**122.7**	**125.6**	**128.0**	**127.7**	**127.6**
1.3.19.1 मोटर वाहन	2.600	122.6	125.9	126.0	126.6	126.4
1.3.19.2 मोटर वाहन पुरजे और सहायक उपकरण	2.368	122.7	125.2	130.1	128.8	128.8
1.3.20 अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण	**1.648**	**131.7**	**133.7**	**138.2**	**138.4**	**139.4**
1.3.20.1 जहाजों और तैरने वाली –वस्तुओं का निर्माण	0.117	158.9	158.9	163.6	163.6	163.6
1.3.20.2 रेलवे इंजन और रोलिंग स्टाक	0.110	104.4	103.7	104.3	104.3	106.5
1.3.20.3 मोटर साइकल	1.302	131.0	133.6	138.6	139.0	140.0
1.3.20.4 साइकल और अवैध गाडी	0.117	137.2	137.9	139.2	138.8	138.5
1.3.20.5 अन्य परिवहन उपकरण	0.002	135.9	139.5	158.2	157.2	155.8
1.3.21 फर्नीचर का विनिर्माण	**0.727**	**150.1**	**154.7**	**157.7**	**157.9**	**158.3**
1.3.21.1 फर्नीचर	0.727	150.1	154.7	157.7	157.9	158.3
1.3.22 अन्य विनिर्माण	**1.064**	**137.9**	**140.5**	**153.1**	**151.1**	**153.7**
1.3.22.1 आभूषण और संबंधित सामग्री	0.996	136.0	138.9	152.3	150.2	153.1
1.3.22.2 संगीत उपकरण	0.001	192.3	185.1	182.7	185.6	185.6
1.3.22.3 खेल के सामान	0.012	140.4	144.3	151.9	151.7	151.1
1.3.22.4 खेल और खिलौने	0.005	150.9	152.4	159.3	158.7	158.5
1.3.22.5 चिकित्सा और दंत चिकित्सा उपकरण और सामग्री	0.049	171.8	169.6	168.0	167.2	166.7
2 खाद्य सूचकांक	**24.378**	**163.8**	**166.7**	**170.7**	**171.2**	**171.3**

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 22: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधारः 2011-12=100)

उद्योग	भारांक	2020-21	2021-22	अप्रैल-जनवरी		जनवरी	
				2021-22	2022-23	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7
सामान्य सूचकांक	100.00	118.1	131.6	129.9	136.9	139.3	146.5
1 क्षेत्रवार वर्गीकरण							
1.1 खनन	14.37	101.0	113.3	109.2	115.5	124.9	135.9
1.2 विनिर्माण	77.63	117.2	131.0	129.6	135.8	139.2	144.3
1.3 बिजली	7.99	157.6	170.1	169.0	186.1	165.6	186.6
2 उपयोग आधारित वर्गीकरण							
2.1 मूल वस्तुएं	34.05	118.1	129.5	127.0	137.1	136.5	149.6
2.2 पूंजीगत माल	8.22	75.9	88.7	85.9	97.6	94.9	105.3
2.3 मध्यवर्ती माल	17.22	124.7	143.9	142.7	148.5	153.5	153.6
2.4 इंफ्रास्ट्रक्चर/निर्माण वस्तुएं	12.34	124.7	148.2	145.7	157.1	158.9	171.7
2.5 उपभोक्ता टिकाऊ माल	12.84	101.2	113.8	112.3	114.8	118.5	109.6
2.6 उपभोक्ता गैर-टिकाऊ माल	15.33	142.1	146.7	147.3	146.7	154.4	164.0

स्रोत : राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

सरकारी लेखा और खज़ाना बिल

सं. 23ः केन्द्र सरकार का लेखा - एक नज़र में

(₹ करोड़)

मद	वित्तीय वर्ष	अप्रैल-जनवरी			
	2022-23 (बजट आकलन)	2022-23 (वास्तविक)	2021-22 (वास्तविक)	बजट आकलन के लिए प्रतिशत	
				2022-23	2021-22
	1	2	3	4	5
1 राजस्व प्राप्तियां	**2348413**	**1980828**	**1791017**	**84.3**	**86.2**
1.1 कर राजस्व (निवल)	2086662	1732193	1480886	83.0	83.9
1.2 करेतर राजस्व	261751	248635	310131	95.0	98.8
2 गैर-कर्ज पूंजीगत प्राप्तियां	**83500**	**58900**	**36263**	**70.5**	**36.3**
2.1 ऋण की वसूली	23500	20229	22749	86.1	103.5
2.2 अन्य प्राप्तियां	60000	38671	13514	64.5	17.3
3 कुल प्राप्तियां (उधारियों को छोड़कर) (1+2)	**2431913**	**2039728**	**1827280**	**83.9**	**83.9**
जिसमें से:	3458959	2903363	2658694	83.9	83.9
4 राजस्व व्यय					
4.1 ब्याज भुगतान	940651	798957	671951	84.9	82.6
5 पूंजी व्यय	728274	590227	485181	81.0	80.5
6 कुल व्यय (4+5)	**4187232**	**3493590**	**3143875**	**83.4**	**83.4**
7 राजस्व घाटा (4-1)	**1110546**	**922535**	**867677**	**83.1**	**79.7**
8 राजकोषीय घाटा (6-3)	**1755319**	**1453862**	**1316595**	**82.8**	**82.7**
9 सकल प्राथमिक घाटा (8-4.1)	**814668**	**654905**	**644644**	**80.4**	**82.9**

स्रोत : महालेखानियंत्रक (सीजीए), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और केंद्रीय बजट 2023-24।

सं. 24: खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप

(₹ करोड़)

मद	2021-22	2022	2023					
		फर. 25	जन. 20	जन. 27	फर. 3	फर. 10	फर. 17	फर. 24
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 91-दिवसीय								
1.1 बैंक	5310	4923	12822	11152	11150	14486	14214	16434
1.2 प्राथमिक व्यापारी	16705	15781	16909	18178	19252	20701	20144	22121
1.3 राज्य सरकारें	31320	58638	44463	44263	39063	38923	29723	27121
1.4 अन्य	72109	80823	108660	105059	101022	94045	92044	87550
2 182-दिवसीय								
2.1 बैंक	70130	58219	68470	68345	69316	69399	70142	69416
2.2 प्राथमिक व्यापारी	63669	49488	49675	56129	57433	58893	63489	63459
2.3 राज्य सरकारें	15763	8826	12568	12568	11268	11268	9268	7568
2.4 अन्य	69259	49752	76449	75749	78102	81938	84150	88604
3 364-दिवसीय								
3.1 बैंक	112386	116951	103244	103202	101899	106964	102122	96616
3.2 प्राथमिक व्यापारी	160461	125294	176369	179052	167652	167949	166299	158712
3.3 राज्य सरकारें	22836	20551	46607	45637	45725	46030	46233	46233
3.4 अन्य	118392	117697	135272	131829	142858	138149	143374	151423
4 14-दिवसीय मध्यवर्ती								
4.1 बैंक								
4.2 प्राथमिक व्यापारी								
4.3 राज्य सरकारें	289362	367557	147808	161017	132353	219868	216844	239122
4.4 अन्य	659	976	1045	1211	1337	718	1123	1678
कुल खज़ाना बिल (14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल को छोड़कर)#	758339	706943	851509	851164	844740	848746	841202	835256

14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल बिक्री योग्य नहीं है, ये बिल 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिलों जैसे नहीं है। यह बिल स्वरूप के अनुसार मध्यवर्ती हैं क्योंकि राज्य सरकारों के दैनिक न्यूनतम नकदी शेष में कमी को पूरा करने के लिए परिसमाप्त किए जाते हैं।

टिप्पणी: प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) में पीडी कारोबार करने वाले बैंक शामिल हैं।

सं. 25: खज़ाना बिलों की नीलामी

(राशि ₹ करोड़ में)

नीलामी की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियाँ			स्वीकृत बोलियां			कुल निर्गम (6+7)	कट-ऑफ मूल्य	कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिफल (प्रतिशत)
		संख्या	कुल अंकित मूल्य		संख्या	कुल अंकित मूल्य				
			प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी		प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91-दिवसीय खज़ाना बिल										
2022-23										
जन. 25	7000	68	17705	49	38	6951	49	7000	98.41	6.4731
फर. 1	7000	50	14425	2528	30	6972	2528	9500	98.39	6.5588
फर. 8	7000	95	19061	1030	50	6970	1030	8000	98.36	6.6699
फर. 15	7000	85	27804	4033	18	6967	4033	11000	98.35	6.7292
फर. 22	7000	67	20559	1435	14	6963	1435	8398	98.33	6.8154
182-दिवसीय खज़ाना बिल										
2022-23										
जन. 25	12000	135	21704	44	101	11956	44	12000	96.69	6.8693
फर. 1	12000	111	23735	244	76	11956	244	12200	96.66	6.9298
फर. 8	12000	107	27697	69	74	11931	69	12000	96.62	7.0157
फर. 15	12000	118	24330	21	86	11979	21	12000	96.57	7.1232
फर. 22	12000	162	32924	2069	46	11931	2069	14000	96.54	7.1800
364-दिवसीय खज़ाना बिल										
2022-23										
जन. 25	10000	180	34542	144	19	9986	144	10130	93.56	6.9048
फर. 1	10000	101	25363	93	57	9994	93	10087	93.49	6.9775
फर. 8	10000	152	23278	327	83	9978	327	10306	93.42	7.0628
फर. 15	10000	185	25900	219	79	9983	219	10202	93.34	7.1594
फर. 22	10000	152	24991	23	60	9977	23	10000	93.25	7.2563

वित्तीय बाजार

सं. 26: दैनिक मांग मुद्रा दरें

(वार्षिक प्रतिशत)

स्थिति के अनुसार		दरों का दायरा	भारित औसत दरें
		उधार लेना/उधार देना	उधार लेना/उधार देना
		1	2
फरवरी	1, 2023	4.55-6.35	6.26
फरवरी	2, 2023	4.60-6.15	6.09
फरवरी	3, 2023	4.75-6.17	6.10
फरवरी	4, 2023	5.15-6.00	5.70
फरवरी	6, 2023	4.75-6.15	6.08
फरवरी	7, 2023	4.70-6.17	6.11
फरवरी	8, 2023	4.55-6.80	6.39
फरवरी	9, 2023	4.55-6.80	6.71
फरवरी	10, 2023	4.55-6.70	6.61
फरवरी	13, 2023	4.55-6.60	6.48
फरवरी	14, 2023	4.55-6.45	6.38
फरवरी	15, 2023	4.55-6.60	6.32
फरवरी	16, 2023	4.55-6.35	6.32
फरवरी	17, 2023	4.55-6.45	6.32
फरवरी	20, 2023	4.60-6.80	6.61
फरवरी	21, 2023	4.85-6.70	6.58
फरवरी	22, 2023	4.85-6.70	6.63
फरवरी	23, 2023	4.60-6.60	6.55
फरवरी	24, 2023	4.50-6.80	6.71
फरवरी	27, 2023	4.60-6.85	6.67
फरवरी	28, 2023	4.60-6.75	6.65
मार्च	1, 2023	4.60-6.40	6.36
मार्च	2, 2023	4.60-6.80	6.34
मार्च	3, 2023	4.90-6.35	6.30
मार्च	4, 2023	5.20-6.25	5.72
मार्च	6, 2023	4.00-6.40	6.30
मार्च	8, 2023	5.30-6.50	6.35
मार्च	9, 2023	4.80-6.47	6.35
मार्च	10, 2023	4.80-6.40	6.31
मार्च	13, 2023	4.85-6.65	6.34
मार्च	14, 2023	4.85-6.65	6.32
मार्च	15, 2023	4.85-6.42	6.34

टिप्पणी: नोटिस मुद्रा सहित।

सं. 27: जमा प्रमाण-पत्र

मद	2022	2023			
	फर. 25	जन. 13	जन. 27	फर. 10	फर. 24
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (₹ करोड़)	127618.40	292289.01	279788.46	269679.45	280336.78
1.1 पखवाड़े के दौरान जारी (₹ करोड़)	19096.55	28381.24	17509.69	19835.23	32563.25
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	3.86-5.62	6.74-7.85	6.82-7.30	7.07-7.35	7.09-8.04

सं. 28: वाणिज्यिक पत्र

मद	2022	2023			
	फर. 28	जन. 15	जन. 31	फर. 15	फर. 28
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (₹ करोड़)	364645.30	381154.85	363889.15	368908.25	364530.10
1.1 पखवाड़े के दौरान रिपोर्ट किए गए (₹ करोड़)	44435.25	45026.90	51481.60	43347.15	58975.35
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	3.64-11.51	6.37-12.75	6.56-13.10	6.70-16.31	6.77-12.51

सं. 29: चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक कारोबार

(₹ करोड़)

मद	2021-22	2022	2023					
		फर. 25	जन. 20	जन. 27	फर. 3	फर. 10	फर. 27	फर. 24
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 मांग मुद्रा	14515	16146	22692	24030	24142	22365	27945	29916
2 नोटिस मुद्रा	2122	383	5976	244	4730	197	332	278
3 मीयादी मुद्रा	515	334	800	317	858	298	720	482
4 त्रिपक्षीय रिपो	618526	823707	750771	636660	769293	634268	753913	760332
5 बाजार रिपो	383844	492832	532332	450512	628200	565484	633578	618929
6 कार्पोरेट बांड में रिपो	4373	358	3205	8260	6981	2269	2892	1064
7 फोरेक्स (यूएस मिलियन डॉलर)	67793	87562	87392	97941	97033	80089	84899	80089
8 भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	51300	39524	70669	60310	88138	79199	74271	62050
9 राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	5570	3982	3684	6547	3518	5869	3721	6700
10 खज़ाना बिल								
10.1 91-दिवसीय	4690	2800	4784	1535	3401	4366	3279	2664
10.2 182-दिवसीय	3440	3479	3075	2134	3192	3614	3193	4854
10.3 364-दिवसीय	3530	1353	2712	1422	1425	3131	2929	1905
10.4 नकदी प्रबंधन बिल								
11 कुल सरकारी प्रतिभूतियां (8+9+10)	68530	51137	84923	71947	99673	96179	87393	78173
11.1 भारतीय रिज़र्व बैंक	–	615	781	674	84	84	537	46

सं. 30: गैर-सरकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम

(राशि ₹ करोड़ में)

प्रतिभूति और निर्गम का प्रकार	2021-22		2021-22 (अप्रै-फर.)		2022-23 (अप्रै-फर.)*		फर. 2022		फर. 2023*	
	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 इक्विटी शेयर	**164**	**138894**	**148**	**137840**	**200**	**42201**	**13**	**6944**	**17**	**570**
1ए प्रीमियम	154	136893	139	135911	184	39583	12	6894	16	435
1.1 पब्लिक	121	112567	111	112393	141	37520	9	6831	7	85
1.1.1 प्रीमियम	119	111314	109	111171	138	36236	8	6800	7	64
1.2 राइट्स	43	26327	37	25448	59	4681	4	113	10	485
1.2.1 प्रीमियम	35	25580	30	24739	46	3347	4	94	9	371
2 अधिमान शेयर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.1 पब्लिक	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.2 राइट्स	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3 बॉण्ड और डिबेंचर	**28**	**11589**	**27**	**11412**	**31**	**8735**	**1**	**104**	**–**	**–**
3.1 परिवर्तनीय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.1.1 पब्लिक	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.1.2 राइट्स	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.2 अपरिवर्तनीय	28	11589	27	11412	31	8735	1	104	–	–
3.1.1 पब्लिक	28	11589	27	11412	31	8735	1	104	–	–
3.1.2 राइट्स	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4 कुल (1+2+3)	**192**	**150484**	**175**	**149252**	**231**	**50936**	**14**	**7048**	**17**	**570**
4.1 पब्लिक	149	124157	138	123804	172	46255	10	6936	7	85
4.2 राइट्स	43	26327	37	25448	59	4681	4	113	10	485

टिप्पणी: 1. अप्रैल 2020 से इक्विटी निर्गमों का मासिक डेटा उनकी लिस्टिंग की तारीख के आधार पर संकलित किया गया है।

2. संख्याओं के पूर्णांकन के कारण कालम के आंकडे कुल में नहीं जुड़ सकते।

स्रोत : भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)।

* : आंकड़े अनंतिम हैं।

बाह्य क्षेत्र

सं. 31: विदेशी व्यापार

मद	इकाई	2021-22	2022				2023	
			फर.	अक्टू.	नवं.	दिसं.	जन.	फर.
		1	2	3	4	5	6	7
1 निर्यात	करोड़ ₹	3147021	278666	260213	285450	313935	293044	305620
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	422004	37154	31602	34892	38069	35781	36996
1.1 तेल	करोड़ ₹	503850	51734	51863	66154	68779	63017	64688
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	67472	6898	6299	8086	8341	7694	7831
1.2 तेल से इतर	करोड़ ₹	2643171	226932	208350	219296	245155	230028	240932
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	354533	30256	25304	26805	29729	28087	29166
2 आयात	करोड़ ₹	4572775	419255	476879	480132	505653	428448	439799
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	613052	55898	57916	58688	61318	52314	53239
2.1 तेल	करोड़ ₹	1207803	118171	134561	147698	160344	130697	140061
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	161810	15755	16342	18054	19444	15958	16955
2.2 तेल से इतर	करोड़ ₹	3364972	301084	342318	332433	345309	297750	299738
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	451242	40143	41574	40635	41874	36356	36284
3 व्यापार शेष	करोड़ ₹	-1425753	-140589	-216666	-194682	-191719	-135404	-134179
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	-191048	-18744	-26314	-23797	-23249	-16533	-16243
3.1 तेल	करोड़ ₹	-703953	-66437	-82698	-81545	-91565	-67681	-75373
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	-94339	-8858	-10043	-9968	-11104	-8264	-9124
3.2 तेल से इतर	करोड़ ₹	-721800	-74152	-133968	-113137	-100154	-67723	-58807
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	-96709	-9886	-16270	-13829	-12145	-8269	-7119

स्रोत: डीजीसीआई एण्ड एस तथा वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय।

सं. 32: विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां

मद	इकाई	2022	2023					
		अप्रै. 1	फर. 24	मार्च 3	मार्च 10	मार्च 17	मार्च 24	मार्च 31
		1	2	3	4	5	6	7
1 कुल आरक्षित निधियां	**करोड ₹**	**4592504**	**4641716**	**4610849**	**4594592**	**4727502**	**4773649**	**4754265**
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	**606475**	**560942**	**562400**	**560003**	**572801**	**578778**	**578449**
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	करोड ₹	4087017	4103554	4075251	4060163	4170825	4204245	4189132
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	539727	495906	497087	494863	505348	509728	509691
1.2 स्वर्ण	करोड ₹	323596	345484	344595	343961	364051	375117	371500
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	42734	41751	42033	41923	44109	45480	45200
	मात्रा (मैट्रिक टन)	760.42	790.16	791.1	791.1	792.82	794.63	794.63
1.3 एसडीआर	एसडीआरएस मिलियन	13657	13667	13667	13667	13667	13667	13667
	करोड ₹	142960	150492	148993	148673	150366	151923	151164
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	18879	18187	18174	18121	18219	18419	18392
1.4 आईएमएफ में आरक्षित भाग की स्थिति	करोड ₹	38931	42186	42010	41795	42261	42364	42468
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	5136	5098	5107	5096	5125	5151	5165

* अंतर यदि कोई हो, तो पूर्णांकन की वजह से हैं।

सं. 33: अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

योजना	बकाया				प्रवाह	
	2021-22	2022	2023		2021-22	2022-23
		फर.	जन.	फर.	अप्रै.-फर.	अप्रै.-फर.
	1	2	3	4	5	6
1 एनआरआई जमाराशियां	**139022**	**139572**	**136821**	**135540**	**2350**	**6402**
1.1 एफसीएनआर (बी)	16918	17293	18207	18402	-3180	1484
1.2 एनआर (ई) आरए	100801	101116	95490	94135	2462	1426
1.3 एनआरओ	21303	21163	23125	23003	3069	3491

सं. 34: विदेशी निवेश अंतर्वाह

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	2021-22	2021-22	2022-23	2022	2023	
		अप्रै-फर.	अप्रै-फर.	फर.	जन.	फर.
	1	2	3	4	5	6
1.1 निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1-1.1.2)	**38587**	**35535**	**27668**	**4657**	**4133**	**1857**
1.1.1 भारत में प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1.1-1. 1.1.2)	**56231**	**51085**	**40505**	**5169**	**4868**	**2975**
1.1.1.1 सकल अंतर्वाह/सकल निवेश	**84835**	**77681**	**66436**	**7178**	**6177**	**4787**
1.1.1.1.1 इक्विटी	59684	55008	44960	4700	4138	2932
1.1.1.1.1.1 सरकारी (एसआईए/एफआईपीबी)	1698	1638	683	18	29	1
1.1.1.1.1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक	42932	38706	35196	3366	3434	2113
1.1.1.1.1.3 शेयरों की अधिप्राप्ति	14143	13836	7774	1234	592	736
1.1.1.1.1.4 अनिगमित निकायों की ईक्विटी पूंजी	910	828	1308	82	82	82
1.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	19347	17604	17611	1743	1743	1743
1.1.1.1.3 अन्य पूंजी	5805	5069	3865	736	296	112
1.1.1.2 प्रत्यावर्तन /विनिवेश	**28605**	**26596**	**25931**	**2009**	**1309**	**1812**
1.1.1.2.1 इक्विटी	27189	25463	23842	1726	1244	1758
1.1.1.2.2 अन्य पूंजी	1416	1132	2089	284	64	53
1.1.2 भारत द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.2.1+1.1.2.2+ 1.1.2.3-1.1.2.4)	**17644**	**15551**	**12837**	**512**	**735**	**1118**
1.1.2.1 इक्विटी पूंजी	10061	9007	7991	267	571	770
1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	3379	3097	3801	282	282	282
1.1.2.3 अन्य पूंजी	7604	6475	4263	335	142	374
1.1.2.4 प्रत्यावर्तन /विनिवेश	3400	3028	3217	372	259	308
1.2 निवल संविभागीय निवेश (1.2.1+1.2.2+1.2.3-1.2.4)	**-16777**	**-11784**	**-6952**	**-5788**	**-3038**	**-426**
1.2.1 जीडीआर/एडीआर	–	–	–	–	–	–
1.2.2 एफआईआई	-14071	-9387	-7024	-5480	-3103	-681
1.2.3 अपतटीय निधियां और अन्य	–	–	–	–	–	–
1.2.4 भारत द्वारा संविभागीय निवेश	2706	2398	-72	309	-65	-254
1 विदेशी निवेश अंतर्वाह	**21809**	**23750**	**20716**	**-1131**	**1095**	**1431**

सं. 35: वैयक्तिक निवासियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत जावक विप्रेषण

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	2021-22	2022		2023	
		फर.	दिसं.	जन.	फर.
	1	2	3	4	5
1 एलआरएस के अंतर्गत जावक विप्रेषण	**19610.77**	**1823.35**	**2068.26**	**2728.17**	**2101.38**
1.1 जमाराशियां	830.05	54.20	60.49	73.14	61.16
1.2 अचल संपत्ति की खरीद	112.90	8.07	13.26	14.98	16.10
1.3 इक्विटी / कर्ज में निवेश	746.57	60.39	119.58	160.05	132.15
1.4 उपहार	2336.29	201.36	202.76	223.22	245.31
1.5 दान	16.55	3.28	0.87	0.66	0.80
1.6 यात्रा	6909.04	980.45	1137.93	1493.17	1070.71
1.7 निकट संबंधियों का रखरखाव	3302.37	282.61	274.79	342.47	323.43
1.8 चिकित्सा उपचार	37.79	3.69	4.36	6.27	3.93
1.9 विदेश में शिक्षा	5165.33	216.07	237.65	395.87	229.34
1.10 अन्य	153.88	13.23	16.59	18.34	18.45

सं. 36: भारतीय रुपये का सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (नीर) और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (रीर) सूचकांक

	2021-22	2022-23	2022	2023	
			मार्च	फरवरी	मार्च
मद	1	2	3	4	5
40- मुद्रा समूह (आधार: 2015-16=100)					
1 व्यापार आधारित भारांक					
1.1 नीर	93.13	91.27	92.74	88.82	89.55
1.2 रीर	104.64	102.68	103.32	99.51	99.95
2 निर्यात आधारित भारांक					
2.1 नीर	93.55	93.03	93.71	90.76	91.42
2.2 रीर	103.46	100.94	102.20	97.79	98.01
6- मुद्रा समूह (व्यापार-भारित)					
1 आधार : 2015-16=100					
1.1 नीर	87.03	85.98	86.42	82.83	83.38
1.2 रीर	102.27	102.02	100.92	98.29	98.94
2 आधार : 2020-21 =100					
2.1 नीर	98.39	97.20	97.70	93.64	94.27
2.2 रीर	100.42	100.18	99.10	96.52	97.16

सं. 37: बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) - पंजीकरण

(अमेरिकी मिलियन डॉलर)

मद	2021-22	2022	2023	
		फर.	जन.	फर.
	1	2	3	4
1 स्वचालित मार्ग				
1.1 संख्या	1086	71	74	69
1.2 राशि	28851	805	777	644
2 अनुमोदन मार्ग				
2.1 संख्या	18	2	1	0
2.2 राशि	11035	1523	1000	0
3 कुल (1+2)				
3.1 संख्या	1104	73	75	69
3.2 राशि	39886	2328	1777	644
4 भारित औसत परिपक्वता (वर्षों में)	8.00	6.30	7.90	5.20
5 ब्याज दर (प्रतिशत)				
5.1 6 महीने के लाइबोर पर भारित औसत मार्जिन या अस्थिर दर के ऋणों के लिए संदर्भ दर	1.71	1.40	2.16	1.53
5.2 सावधि दर के ऋणों के लिए ब्याज दर की सीमा	0.00-10.50	0.00-12.00	0.00-11.30	0.01-10.50
उधारकर्ता श्रेणियाँ				
I. कॉर्पोरेट विनिर्माण	12244	491	291	160
II. कॉर्पोरेट -बुनियादी संरचना	17023	1324	192	156
ए) परिवहन	1597	1308	0	37
बी) ऊर्जा	8215	7	2	111
सी) पानी और सफ़ाई व्यवस्था	10	0	0	0
डी) संचार	1258	0	0	1
ई) सामाजिक और वाणिज्यिक बुनियादी संरचना	0	0	0	0
एफ) अन्वेषण खनन और रिफाइनरी	4691	0	150	0
जी) अन्य उप -क्षेत्र	1252	9	40	7
III. कॉर्पोरेट सेवा क्षेत्र	1570	129	236	66
IV. अन्य संस्थाएं	609	0	1000	0
ए) एसईज़ेड में इकाई	9	0	0	0
बी) सिडबी	0	0	0	0
सी) एक्ज़िम बैंक	600	0	1000	0
V. बैंक	100	0	0	0
VI. वित्तीय संस्थान (एनबीएफसी के अलावा)	4	0	0	0
VII. एनबीएफसी	7995	372	35	216
ए) एनबीएफसी -आईएफसी/एएफसी	5621	273	0	0
बी) एनबीएफसी -एमएफआई	93	0	35	0
सी) एनबीफसी - अन्य (एनजीओ)	2282	99	0	216
VIII. गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ)	0	0	0	0
IX. सूक्ष्म वित्त संस्था (एमएफआई)	0	0	0	0
X. अन्य	341	12	23	46

सं. 38: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	अक्टू-दिसं. 2021			अक्टू-दिसं. 2022 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	**427124**	**426659**	**465**	**404167**	**393098**	**11069**
1 चालू खाता (1.1+1.2)	**205567**	**227734**	**-22167**	**227491**	**245734**	**-18243**
1.1 पण्य	**108927**	**168677**	**-59750**	**105609**	**178328**	**-72720**
1.2 अप्रत्यक्ष मदें (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	**96640**	**59057**	**37583**	**121883**	**67406**	**54477**
1.2.1 सेवाएं	67016	39207	27809	83422	44702	38719
1.2.1.1 यात्रा	2599	4335	-1735	8123	6910	1213
1.2.1.2 परिवहन	8948	10037	-1089	8758	9409	-651
1.2.1.3 बीमा	844	644	200	783	797	-13
1.2.1.4 जीएनआईई	223	264	-41	185	282	-97
1.2.1.5 विविध	54402	23927	30475	65572	27304	38268
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	31740	3384	28356	37599	4058	33541
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	15312	13722	1590	21198	15125	6073
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	1354	1535	-181	1949	1292	657
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	801	276	524	842	329	514
1.2.2 अंतरण	23528	2216	21312	30867	2400	28467
1.2.2.1 आधिकारिक	132	267	-135	58	232	-174
1.2.2.2 निजी	23396	1949	21447	30809	2168	28641
1.2.3 आय	6096	17634	-11538	7594	20304	-12710
1.2.3.1 निवेश आय	4449	16839	-12391	5878	19437	-13559
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	1647	794	853	1716	867	850
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	**221424**	**198925**	**22500**	**176675**	**146497**	**30178**
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	**147690**	**148973**	**-1283**	**95253**	**88553**	**6700**
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	19608	15050	4559	17002	14913	2089
2.1.1.1 भारत में	19032	10192	8840	16107	8796	7311
2.1.1.1.1 इक्विटी	12259	9936	2324	10246	7932	2315
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	5072		5072	5067		5067
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	1701	257	1444	794	865	-71
2.1.1.2 विदेश में	576	4857	-4281	895	6117	-5222
2.1.1.2.1 इक्विटी	576	2573	-1997	895	3563	-2668
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	845	-845	0	1079	-1079
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	1439	-1439	0	1475	-1475
2.1.2 संविभाग निवेश	128082	133924	-5842	78251	73641	4611
2.1.2.1 भारत में	127509	132213	-4704	77433	72916	4517
2.1.2.1.1 एफआईआई	127509	132213	-4704	77433	72916	4517
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	115423	119516	-4093	71477	65940	5537
2.1.2.1.1.2 ऋण	12086	12697	-611	5956	6976	-1020
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0		0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	573	1711	-1138	818	724	93
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	**29433**	**19410**	**10023**	**25903**	**24110**	**1793**
2.2.1 बाह्य सहायता	2692	1399	1293	3088	1584	1504
2.2.1.1 भारत द्वारा	13	16	-3	8	22	-14
2.2.1.2 भारत को	2680	1383	1297	3080	1562	1518
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	6111	6365	-254	4629	7089	-2460
2.2.2.1 भारत द्वारा	352	241	111	439	316	123
2.2.2.2 भारत को	5759	6124	-365	4190	6773	-2583
2.2.3 भारत को अल्पावधि	20629	11645	8984	18186	15437	2749
2.2.3.1 खरीदार और आपूर्तिकर्ता का ऋण >180 दिन	12003	11645	357	17744	15437	2307
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	8626	0	8626	442	0	442
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	**25913**	**17707**	**8206**	**36230**	**21795**	**14435**
2.3.1 वाणिज्यिक बैंक	25913	17501	8412	36230	21649	14580
2.3.1.1 आस्तियां	11213	6154	5058	18145	6135	12009
2.3.1.2 देयताएं	14700	11346	3353	18085	15514	2571
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियां	12141	10809	1332	16928	14359	2569
2.3.2 अन्य	0	206	-206	0	145	-145
2.4 रुपया कर्ज सेवाएं	0	0	0	0	1	-1
2.5 अन्य पूंजी	18389	12835	5554	19289	12038	7251
3 भूल-चूक	**132**	0	**132**	0	**866**	**-866**
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	0	**465**	**-465**	0	**11069**	**-11069**
4.1 आईएमएफ	0	0	0	0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां (वृद्धि -/ कमी +)		465	-465	0	11069	-11069

टिप्पणी: प्रा: प्रारंभिक

सं. 39: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(₹ करोड़)

मद	अक्टू-दिसं. 2021			अक्टू-दिसं. 2022 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	**3200360**	**3196873**	**3487**	**3322449**	**3231457**	**90992**
1 चालू खाता (1.1+1.2)	**1540277**	**1706367**	**-166090**	**1870090**	**2020055**	**-149965**
1.1 पण्य	**816171**	**1263865**	**-447694**	**868155**	**1465946**	**-597791**
1.2 अप्रत्यक्ष मदें (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	**724106**	**442502**	**281604**	**1001935**	**554109**	**447826**
1.2.1 सेवाएं	502141	293771	208370	685767	367473	318293
1.2.1.1 यात्रा	19476	32478	-13002	66776	56807	9970
1.2.1.2 परिवहन	67048	75208	-8160	71994	77348	-5354
1.2.1.3 बीमा	6327	4826	1501	6438	6548	-110
1.2.1.4 जीएनआईई	1668	1976	-309	1520	2317	-797
1.2.1.5 विविध	407623	179283	228340	539038	224454	314584
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	237819	25352	212467	309080	33356	275723
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	114730	102817	11913	174257	124338	49919
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	10149	11503	-1354	16021	10624	5397
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	6000	2071	3929	6924	2701	4223
1.2.2 अंतरण	176292	16607	159685	253741	19726	234014
1.2.2.1 आधिकारिक	991	2002	-1011	478	1907	-1429
1.2.2.2 निजी	175301	14605	160696	253262	17819	235443
1.2.3 आय	45673	132125	-86452	62427	166910	-104482
1.2.3.1 निवेश आय	33333	126174	-92841	48318	159784	-111466
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	12340	5951	6389	14109	7126	6984
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	**1659091**	**1490505**	**168586**	**1452359**	**1204279**	**248080**
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	**1106614**	**1116227**	**-9613**	**783028**	**727953**	**55075**
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	146921	112764	34157	139765	122591	17174
2.1.1.1 भारत में	142606	76370	66235	132411	72310	60101
2.1.1.1.1 इक्विटी	91856	74446	17411	84230	65203	19027
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	38004	0	38004	41657	0	41657
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	12745	1925	10821	6524	7107	-583
2.1.1.2 विदेश में	4315	36393	-32078	7353	50281	-42928
2.1.1.2.1 इक्विटी	4315	19279	-14964	7353	29287	-21934
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	6329	-6329	0	8871	-8871
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	10786	-10786	0	12123	-12123
2.1.2 संविभाग निवेश	959694	1003463	-43770	643263	605362	37901
2.1.2.1 भारत में	955401	990645	-35244	636539	599406	37133
2.1.2.1.1 एफआईआई	955401	990645	-35244	636539	599406	37133
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	864845	895510	-30665	587580	542060	45520
2.1.2.1.1.2 ऋण	90555	95135	-4580	48959	57346	-8387
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	4293	12818	-8525	6723	5955	768
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	**220533**	**145432**	**75101**	**212938**	**198199**	**14739**
2.2.1 बाह्य सहायता	20174	10483	9690	25384	13021	12363
2.2.1.1 भारत द्वारा	95	120	-26	63	180	-117
2.2.1.2 भारत को	20079	10363	9716	25321	12841	12480
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	45789	47692	-1902	38055	58276	-20221
2.2.2.1 भारत द्वारा	2638	1806	833	3608	2599	1010
2.2.2.2 भारत को	43151	45886	-2735	34447	55677	-21231
2.2.3 भारत को अल्पावधि	154570	87257	67313	149499	126902	22597
2.2.3.1 खरीदार और आपूर्तिकर्ता का ऋण >180 दिन	89934	87257	2677	145866	126902	18964
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	64636	0	64636	3633	0	3633
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	**194158**	**132675**	**61483**	**297825**	**179162**	**118663**
2.3.1 वाणिज्यिक बैंक	194158	131130	63028	297825	177967	119858
2.3.1.1 आस्तियां	84016	46113	37902	149160	50436	98724
2.3.1.2 देयताएं	110142	85016	25126	148665	127531	21135
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियां	90969	80991	9978	139159	118040	21119
2.3.2 अन्य	0	1546	-1546	0	1195	-1195
2.4 रुपया कर्ज सेवाएं	0	0	0	0	4	-4
2.5 अन्य पूंजी	137786	96171	41615	158568	98961	59607
3 भूल-चूक	**992**	0	**992**	0	**7123**	**-7123**
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	0	**3487**	**-3487**	0	**90992**	**-90992**
4.1 आईएमएफ	0	0	0	0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि -/ कमी +)	0	3487	-3487	0	90992	-90992

टिप्पणी: प्रा: प्रारंभिक

सं. 40: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	अक्टू-दिसं. 2021			अक्टू-दिसं. 2022 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
1 चालू खाता (1.अ+1आ+1.इ)	**205556**	**227712**	**-22156**	**227486**	**245714**	**-18227**
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1अ.ख.)	**175944**	**207884**	**-31940**	**189030**	**223030**	**-34000**
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1अ.क.3)	**108927**	**168677**	**-59750**	**105609**	**178328**	**-72720**
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	108811	154622	-45811	105247	170206	-64959
1.अ.क.2 वाणिज्यिक के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	116	0	116	362	0	362
1.अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण		14055	-14055		8123	-8123
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	**67016**	**39207**	**27809**	**83422**	**44702**	**38719**
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	129	17	112	553	108	446
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	68	394	-326	55	255	-200
1.अ.ख.3 परिवहन	8948	10037	-1089	8758	9409	-651
1.अ.ख.4 यात्रा	2599	4335	-1735	8123	6910	1213
1.अ.ख.5 निर्माण	750	592	158	1129	573	556
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	844	644	200	783	797	-13
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	1354	1535	-181	1949	1292	657
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	238	2363	-2125	318	3435	-3116
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	32638	3813	28825	38538	4590	33947
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	15312	13722	1590	21198	15125	6073
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	834	1205	-371	997	1155	-158
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं	223	264	-41	185	282	-97
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं है	3079	286	2793	835	770	65
1.आ. प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	**6096**	**17634**	**-11538**	**7594**	**20304**	**-12710**
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	1647	794	853	1716	867	850
1.आ.2 निवेश आय	3067	16552	-13485	3746	18994	-15249
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	1750	11634	-9884	1784	11461	-9677
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	88	1941	-1853	69	2853	-2784
1.आ.2.3 अन्य निवेश	82	2975	-2892	146	4579	-4433
1.आ.2.4 रिज़र्व आस्तियां	1147	2	1144	1746	101	1645
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	1382	287	1094	2132	443	1689
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	**23516**	**2194**	**21322**	**30862**	**2379**	**28483**
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तेतर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	23396	1949	21447	30809	2168	28641
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	22443	1359	21084	29973	1548	28425
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	953	590	363	836	619	216
1.इ.2 सामान्य सरकार	121	245	-125	53	212	-158
2. पूँजी खाता (2.1+2.2)	**227**	**430**	**-202**	**127**	**188**	**-62**
2.1 अनुत्पादित वित्तेतर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	94	166	-71	23	37	-14
2.2 पूँजी अंतरण	133	264	-131	104	151	-47
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	**221209**	**198982**	**22226**	**176553**	**157398**	**19155**
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)	**19608**	**15050**	**4559**	**17002**	**14913**	**2089**
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	19032	10192	8840	16107	8796	7311
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	17331	9936	7396	15314	7932	7382
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	12259	9936	2324	10246	7932	2315
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	5072		5072	5067		5067
3.1.अ.2 ऋण लिखत	1701	257	1444	794	865	-71
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	1701	257	1444	794	865	-71
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	576	4857	-4281	895	6117	-5222
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	576	3418	-2842	895	4642	-3747
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	576	2573	-1997	895	3563	-2668
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश		845	-845		1079	-1079
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	1439	-1439	0	1475	-1475
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक		1439	-1439		1475	-1475
3.2 संविभाग निवेश	**128082**	**133924**	**-5842**	**78251**	**73641**	**4611**
3.2अ भारत में संविभाग निवेश	127509	132213	-4704	77433	72916	4517
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	115423	119516	-4093	71477	65940	5537
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	12086	12697	-611	5956	6976	-1020
3.2आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	573	1711	-1138	818	724	93
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (आरक्षित निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	**4851**	**6752**	**-1902**	**5509**	**5955**	**-446**
3.4 अन्य निवेश	**68668**	**42792**	**25876**	**75792**	**51821**	**23971**
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	12141	11015	1125	16928	14505	2424
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी डेट मूवमेंट; एनआरजी)	0	206	-206	0	145	-145
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेने वाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	12141	10809	1332	16928	14359	2569
3.4.2.3 सामान्य सरकार			0			0
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र			0			0
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूँजी)	22575	14456	8120	27018	15963	11055
3.4.3अ भारत को ऋण	22211	14199	8012	26572	15625	10947
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	365	257	108	447	338	109
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	70	89	-19	30	38	-8
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	20629	11645	8984	18186	15437	2749
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	13253	5586	7667	13628	5878	7751
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार			0			0
3.5 आरक्षित आस्तियां	0	**465**	**-465**	0	**11069**	**-11069**
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण			0			0
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए			0			0
3.5.3 आईएमएफ में रिज़र्व निधियों की स्थिति एन.ए			0			0
3.5.4 अन्य रिज़र्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	465	-465	0	11069	-11069
4. कुल आस्तियां / देयताएं	**221209**	**198982**	**22226**	**176553**	**157398**	**19155**
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	138824	141421	-2597	94043	85231	8811
4.2 ऋण लिखत	69132	51510	17622	68882	55220	13662
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	13253	6051	7202	13628	16947	-3318
5. निवल भूल-चूक	**132**		**132**		**866**	**-866**

टिप्पणी: प्रा: प्रारंभिक

सं. 41: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(₹ करोड़)

मद	अक्टू-दिसं. 2021			अक्टू-दिसं. 2022 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
1 चालू खाता (1.अ+1आ+1.इ)	**1540189**	**1706202**	**-166013**	**1870049**	**2019887**	**-149838**
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1अ.ख.)	**1318312**	**1557635**	**-239324**	**1553922**	**1833419**	**-279497**
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1अ.क.3)	**816171**	**1263865**	**-447694**	**868155**	**1465946**	**-597791**
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	815302	1158554	-343253	865182	1399175	-533992
1.अ.क.2 वाणिज्यिक के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	869	0	869	2973	0	2973
1.अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण	0	105311	-105311	0	66771	-66771
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	**502141**	**293771**	**208370**	**685767**	**367473**	**318293**
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	967	127	839	4547	885	3663
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	506	2950	-2444	451	2097	-1646
1.अ.ख.3 परिवहन	67048	75208	-8160	71994	77348	-5354
1.अ.ख.4 यात्रा	19476	32478	-13002	66776	56807	9970
1.अ.ख.5 निर्माण	5621	4437	1183	9284	4710	4575
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	6327	4826	1501	6438	6548	-110
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	10149	11503	-1354	16021	10624	5397
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	1784	17709	-15926	2616	28234	-25618
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	244549	28566	215983	316797	37734	279063
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	114730	102817	11913	174257	124338	49919
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	6250	9030	-2780	8199	9498	-1299
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं	1668	1976	-309	1520	2317	-797
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं है	23068	2142	20925	6865	6334	531
1.आ. प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	**45673**	**132125**	**-86452**	**62427**	**166910**	**-104482**
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	12340	5951	6389	14109	7126	6984
1.आ.2 निवेश आय	22980	124021	-101040	30791	156142	-125352
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	13111	87172	-74062	14664	94217	-79553
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	661	14541	-13881	569	23452	-22883
1.आ.2.3 अन्य निवेश	617	22289	-21672	1203	37645	-36442
1.आ.2.4 रिज़र्व आस्तियां	8592	18	8574	14355	829	13527
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	10353	2153	8199	17527	3641	13886
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	**176205**	**16442**	**159763**	**253700**	**19559**	**234141**
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तेतर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	175301	14605	160696	253262	17819	235443
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	168163	10186	157977	246394	12727	233667
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	7138	4419	2719	6868	5092	1776
1.इ.2 सामान्य सरकार	903	1837	-933	438	1740	-1302
2. पूँजी खाता (2.1+2.2)	**1704**	**3220**	**-1516**	**1043**	**1549**	**-506**
2.1 अनुत्पादित वित्तेतर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	707	1241	-535	190	307	-117
2.2 पूँजी अंतरण	998	1979	-981	852	1242	-390
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	**1657474**	**1490938**	**166537**	**1451356**	**1293890**	**157467**
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)	**146921**	**112764**	**34157**	**139765**	**122591**	**17174**
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	142606	76370	66235	132411	72310	60101
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	129860	74446	55415	125887	65203	60684
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	91856	74446	17411	84230	65203	19027
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	38004	0	38004	41657	0	41657
3.1.अ.2 ऋण लिखत	12745	1925	10821	6524	7107	-583
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	12745	1925	10821	6524	7107	-583
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	4315	36393	-32078	7353	50281	-42928
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	4315	25608	-21293	7353	38158	-30805
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	4315	19279	-14964	7353	29287	-21934
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	0	6329	-6329	0	8871	-8871
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	10786	-10786	0	12123	-12123
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	0	10786	-10786	0	12123	-12123
3.2 संविभाग निवेश	**959694**	**1003463**	**-43770**	**643263**	**605362**	**37901**
3.2अ भारत में संविभाग निवेश	955401	990645	-35244	636539	599406	37133
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	864845	895510	-30665	587580	542060	45520
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	90555	95135	-4580	48959	57346	-8387
3.2आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	4293	12818	-8525	6723	5955	768
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिज़र्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	**36345**	**50593**	**-14248**	**45283**	**48951**	**-3668**
3.4 अन्य निवेश	**514515**	**320631**	**193885**	**623046**	**425994**	**197052**
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	90969	82537	8432	139159	119235	19924
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी डेट मूवमेंट; एनआरजी)	0	1546	-1546	0	1195	-1195
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेने वाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	90969	80991	9978	139159	118040	21119
3.4.2.3 सामान्य सरकार	0	0	0	0	0	0
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र	0	0	0	0	0	0
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूँजी)	169152	108314	60838	222105	131224	90881
3.4.3अ भारत को ऋण	166419	106388	60031	218433	128445	89988
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	2733	1926	807	3671	2779	893
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	522	668	-146	250	315	-65
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	154570	87257	67313	149499	126902	22597
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	99302	41855	57447	112033	48318	63715
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार	0	0	0	0	0	0
3.5 आरक्षित आस्तियां	**0**	**3487**	**-3487**	**0**	**90992**	**-90992**
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण	0	0	0	0	0	0
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए	0	0	0	0	0	0
3.5.3 आईएमएफ में रिज़र्व निधियों की स्थिति एन.ए	0	0	0	0	0	0
3.5.4 अन्य रिज़र्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	3487	-3487	0	90992	-90992
4. कुल आस्तियां / देयताएं	**1657474**	**1490938**	**166537**	**1451356**	**1293890**	**157467**
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	1040181	1059643	-19462	773077	700643	72434
4.2 ऋण लिखत	517992	385953	132039	566247	453937	112310
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	99302	45342	53960	112033	139310	-27277
5. निवल भूल-चूक	**992**	**0**	**992**	**0**	**7123**	**-7123**

टिप्पणी: प्रा: प्रारंभिक

सं. 42: अंतरराष्ट्रीय निवेश की स्थिति

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	वित्तीय वर्ष/समाप्त तिमाही की स्थिति							
	2021-22		2021		2022			
			दिसं.		सितं.		दिसं.	
	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 विदेश में/ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	211573	521632	208096	514112	217335	510150	222557	510719
1.1 इक्विटी पूंजी*	132765	493987	130904	487895	136255	481972	140002	482118
1.2 अन्य पूंजी	78807	27645	77192	26217	81080	28178	82554	28601
2 पोर्टफोलियो निवेश	10642	270484	9716	284708	10983	245793	10890	245679
2.1 इक्विटी	1110	156381	6113	172794	6312	137013	8624	140469
2.2 कर्ज	9533	114103	3603	111914	4671	108779	2266	105209
3. अन्य निवेश	90974	486635	76447	481692	85917	477453	79570	493790
3.1 व्यापार ऋण	18561	118147	12849	113439	24675	123520	26125	126252
3.2 ऋण	10474	195290	8856	194917	8084	188463	8628	194842
3.3 मुद्रा और जमाराशि	42081	140994	34796	143502	33528	135621	27093	136132
3.4 अन्य आस्तियां/ देयताएं	19858	32203	19946	29833	19630	29850	17723	36564
4 आरक्षित निधियां	607309		633614		532664		562721	
5 कुल आस्ति/ देयताएं	920498	1278751	927873	1280511	846899	1233395	875737	1250187
6 निवल आईआईपी (आस्ति-देयताएं)	-358253		-352638		-386496		-374451	

टिप्पणी: * इक्विटी पूंजी में निवेश निधि का हिस्सा और पुनर्निवेशित अर्जन शामिल है।

भुगतान और निपटान प्रणाली

सं. 43: भुगतान प्रणाली संकेतक

भाग I - भुगतान प्रणाली संकेतक – भुगतान तथा निपटान प्रणाली सांख्यिकी

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	वि. व 2021-22	2022	2023		वि.व 2021-22	2022	2023	
		फर.	जन.	फर.		फर.	जन.	फर.
	1	2	3	4	5	6	7	8
ए. निपटान प्रणाली								
वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)								
1 सीसीआईएल प्रचलित प्रणाली (1.1 से 1.3)	33.01	2.92	3.66	3.51	206873112	17994586	21571346	22281370
1.1 सरकारी प्रतिभूति समाशोधन (1.1.1 से 1.1.3)	12.22	1.10	1.17	1.27	142072939	12914111	14383734	14888685
1.1.1 आउटराईट	6.22	0.58	0.60	0.68	8793301	721038	785714	895740
1.1.2 रेपो	3.08	0.25	0.35	0.38	51015712	4221392	5556922	6436404
1.1.3 त्रि-पक्षीय रिपो	2.92	0.27	0.21	0.21	82263926	7971681	8041098	7556541
1.2 विदेशी मुद्रा समाशोधन	19.91	1.73	2.40	2.11	59775826	4540145	6553596	6602897
1.3 रुपये के डेरिवेटिव @	0.88	0.10	0.10	0.13	5024347	540330	634016	789788
बी. भुगतान प्रणाली								
I वित्तीय बाजार आधार-संरचना (एफएमआई)	–	–	–	–	–	–	–	–
1 ऋण अंतरण - आरटीजीएस (1.1 से 1.2)	2078.39	180.29	204.18	200.50	128657516	10324618	12546467	12053579
1.1 ग्राहक लेनदेन	2063.73	179.15	202.99	199.35	113319292	9277356	11028450	10566198
1.2 इंटरबैंक लेनदेन	14.66	1.13	1.19	1.14	15338225	1047262	1518016	1487381
II खुदरा								
2 ऋण अंतरण - खुदरा (2.1 से 2.6)	577934.74	55305.52	92396.07	88613.03	42728006	3806484	4738328	4650034
2.1 एईपीएस (निधि अंतरण) @	9.76	0.51	0.32	0.31	575	28	23	22
2.2 एपीबीएस $	12573.33	651.67	1112.35	2584.03	133345	13152	19956	35514
2.3 आईएमपीएस	46625.25	4209.31	4745.08	4478.13	4171037	384404	477491	468647
2.4 एनएसीएच जमा $	18757.82	1536.56	1354.13	1527.38	1281685	104998	131620	134032
2.5 एनईएफटी	40407.29	3632.58	4798.31	4675.61	28725463	2477059	2810180	2775972
2.6 यूपीआई @	459561.30	45274.89	80385.88	75347.57	8415900	826843	1299059	1235847
2.6.1 जिसमें से यूएसएसडी@	11.99	0.68	1.79	1.51	177	10	19	17
3 डेबिट ट्रांसफर और डायरेक्ट डेबिट (3.1 से 3.3)	12189.49	1089.30	1360.36	1360.85	1034444	90746	115658	115315
3.1 भीम आधार पे @	227.73	15.23	13.01	11.50	6113	506	468	454
3.2 एनएसीएच नामे $	10754.74	948.20	1202.79	1210.19	1026641	90056	114953	114630
3.3 एनईटीसी (बैंक खाते से जुड़ा) @	1207.02	125.87	144.56	139.16	1689	184	236	231
4 कार्ड भुगतान (4.1 से 4.2)	61782.93	4840.47	5103.61	4588.51	1701851	143111	183460	168378
4.1 क्रेडिट कार्ड (4.1.1 से 4.1.2)	22398.82	1884.24	2593.52	2323.20	971638	86041	127682	118684
4.1.1 पीओएस आधारित $	11124.59	963.40	1409.19	1255.88	380643	32500	48934	44611
4.1.2 अन्य $	11274.23	920.84	1184.33	1067.32	590994	53541	78748	74073
4.2 डेबिट कार्ड (4.2.1 से 4.2.1)	39384.11	2956.23	2510.09	2265.31	730213	57070	55778	49693
4.2.1 पीओएस आधारित $	22967.10	1845.45	1742.51	1581.95	451550	36376	37520	33432
4.2.2 अन्य $	16417.00	1110.78	767.59	683.36	278663	20694	18258	16261
5 प्रीपेड भुगतान लिखत (5.1 से 5.2)	65782.75	5551.16	6129.40	6050.89	279416	22923	22193	22399
5.1 वालेट	53013.86	4386.09	4873.96	4929.04	220183	17259	17899	18356
5.2 कार्ड (5.2.1 से 5.2.2)	12768.89	1165.07	1255.44	1121.85	59233	5664	4294	4043
5.2.1 पीओएस आधारित $	1116.16	126.61	64.59	63.07	19546	3360	774	792
5.2.2 अन्य $	11652.73	1038.46	1190.86	1058.78	39687	2304	3520	3251
6 पेपर-आधारित लिखत (6.1 से 6.2)	6999.12	581.98	573.17	538.79	6650333	615321	570639	554113
6.1 सीटीएस (एनपीसीआई प्रबंधित)	6999.12	581.98	573.17	538.79	6650333	615321	570639	554113
6.2 अन्य	0.00	–	–	–	–	–	–	–
कुल - खुदरा भुगतान (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	724689.03	67368.43	105562.61	101152.07	52394049	4678585	5630279	5510239
कुल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	726767.42	67548.71	105766.79	101352.56	181051565	15003203	18176745	17563818
कुल डिजिटल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	719768.30	66966.73	105193.62	100813.78	174401233	14387882	17606106	17009704

भाग II - भुगतान के प्रकार तथा चैनल

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	वि. व. 2021-22	2022	2023		वि. व. 2021-22	2022	2023	
		फर.	जन.	फर.		फर.	जन.	फर.
	1	2	3	4	5	6	7	8
ए. अन्य भुगतान चैनल								
1 मोबाइल भुगतान (मोबाइल ऐप आधारित) (1.1 से 1.2)	506842.31	48292.44	86642.24	82667.18	14961371	1391254	2105417	2068090
1.1 इंट्रा-बैंक $	40805.69	3626.98	4884.25	5107.77	2726363	246931	345334	353815
1.2 इंटर-बैंक $	466036.62	44665.47	81757.99	77559.40	12235007	1144324	1760083	1714274
2 इंटरनेट भुगतान (नेटबैंकिंग / इंटरनेट ब्राउज़र आधारित) @ (2.1 से 2.2)	40825.85	3274.19	3544.67	3319.04	83255958	6792274	7327328	7380904
2.1 इंट्रा-बैंक @	9576.46	780.51	889.79	834.55	52139336	4169926	4089462	4172937
2.2 इंटर-बैंक @	31249.39	2493.68	2654.88	2484.49	31116622	2622349	3237866	3207966
बी. एटीएम								
3 एटीएम से नकद निकासी (3.1 से 3.3)	65240.43	5296.66	5749.82	5471.86	3111946	256463	272135	263673
3.1 क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना $	62.37	5.29	8.13	7.39	3130	264	385	358
3.2 डेबिट कार्ड का उपयोग करना $	64851.61	5263.17	5708.93	5433.00	3097739	255218	270588	262090
3.3 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना $	326.45	28.20	32.76	31.47	11076	981	1161	1225
4 पीओएस पर नकद निकासी $ (4.1 से 4.2)	91.17	2.19	2.44	2.18	728	20	25	22
4.1 डेबिट कार्ड का उपयोग करना $	79.42	2.15	2.43	2.17	557	20	25	22
4.2 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना $	11.75	0.04	0.02	0.01	171	0	0	0
5 माइक्रो एटीएम में नकद निकासी @	11126.04	928.46	963.46	918.44	299776	24975	26203	25483
5.1 एईपीएस @	11126.04	928.46	963.46	918.44	299776	24975	26203	25483

भाग III - भुगतान अवसंरचना (लाख)

प्रणाली	मार्च 2022 तक	2022	2023	
		फर.	जन.	फर.
	1	2	3	4
भुगतान प्रणाली अवसंरचना				
1 कार्ड की संख्या (1.1 से 1.2)	9912.93	10067.74	10280.33	10374.87
1.1 क्रेडिट कार्ड	736.27	717.08	824.52	833.66
1.2 डेबिट कार्ड	9176.66	9350.66	9455.81	9541.22
2 पीपीआई की संख्या @ (2.1 से 2.2)	15553.69	15652.06	16029.29	16109.65
2.1 वालेट @	12787.93	12942.28	13244.34	13335.10
2.2 कार्ड @	2765.76	2709.78	2784.95	2774.55
3 एटीएम की संख्या (3.1 से 3.2)	2.52	2.47	2.58	2.57
3.1 बैंक के स्वामित्व वाले एटीएम $	2.20	2.16	2.21	2.21
3.2 व्हाइट लेबल एटीएम $	0.31	0.31	0.37	0.36
4 माइक्रो एटीएम की संख्या @	9.16	8.51	14.75	15.59
5 पीओएस टर्मिनलों की संख्या	60.70	58.34	76.57	77.58
6 भारत क्यूआर @	49.72	48.27	50.57	52.22
7 यूपीआई क्यूआर *	1727.34	1600.19	2442.34	2500.89

@: नवंबर 2019 से नया समावेश
#: दिसंबर 2021 से शामिल सहकारी बैंकों, एलएबी और आरआरबी द्वारा रिपोर्ट किए गए डेटा।
$: नवंबर 2019 से अलग से शुरू किया गया समावेश - अभी तक अन्य मदों का हिस्सा रहा होगा।
* सितंबर 2020 से नया समावेश; केवल स्थिर यूपीआई क्यूआर कोड शामिल है।

टिप्पणियां: 1. डेटा अनंतिम है।
2. 31 जनवरी 2020 से ईसीएस (डेबिट और क्रेडिट) एनएसीएच के साथ मिला दिया गया है।
3. कार्ड पेमेंट्स (डेबिट / क्रेडिट कार्ड्स) और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई) के लिए नवंबर 2019 के डेटा की पहले के महीनों / अवधि के साथ तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि डेटा के परिभाषाओं में संशोधन के साथ अधिक ग्रैन्युलर डेटा प्रकाशित किया जा रहा है।
4. केवल घरेलू वित्तीय लेनदेन पर विचार किया गया है। नए प्रारूप में ई-कॉमर्स लेनदेन लिया जाता है; फास्ट टैग लेनदेन; डिजिटल बिल भुगतान और एटीएम आदि के माध्यम से कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर आदि। इसके अलावा, असफल लेनदेन, चार्जबैक, रिवर्सल, एक्सपायर्ड कार्ड / वॉलेट को शामिल नहीं किया गया है।

अवसरिक शृंखला

सं. 44: अल्प बचत

(₹ करोड़)

योजना		2021-22	2021	2022		
			मार्च	जन.	फर.	मार्च
		1	2	3	4	5
1. लघु बचत	**प्राप्तियां**	**203175**	**34767**	**14893**	**13932**	**35956**
	बकाया	**1463777**	**1259585**	**1412766**	**1426737**	**1463777**
1.1 कुल जमाराशियां	**प्राप्तियां**	**144749**	**20375**	**10676**	**9753**	**21967**
	बकाया	**1012241**	**867494**	**980523**	**990274**	**1012241**
1.1.1 डाक घर बचत बैंक जमाराशियां	प्राप्तियां	41329	11150	3018	3568	13930
	बकाया	247216	205888	229719	233287	247216
1.1.2 एमजीएनआरईजी	प्राप्तियां					
	बकाया					
1.1.3 राष्ट्रीय बचत योजना, 1987	प्राप्तियां	-1524	382	-15	-20	-1271
	बकाया	1894	3419	3185	3165	1894
1.1.4 राष्ट्रीय बचत योजना, 1992	प्राप्तियां	-352	135	-1	-777	451
	बकाया	-177	175	149	-628	-177
1.1.5 मासिक आय योजना	प्राप्तियां	14441	1102	1146	933	994
	बकाया	235820	221379	233892	234825	235820
1.1.6 वरिष्ठ नागरिक योजना, 2004	प्राप्तियां	22281	2301	1615	1490	2094
	बकाया	119333	97051	115749	117239	119333
1.1.7 डाक घर मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	43725	3960	3438	3217	3592
	बकाया	251282	207557	244474	247690	251282
1.1.7.1 1 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	118282	108205	116819	117578	118282
1.1.7.2 2 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	8008	7473	7967	7996	8008
1.1.7.3 3 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	6918	7227	6964	6944	6918
1.1.7.4 5 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	118074	84652	112724	115172	118074
1.1.8 डाक घर आवर्ती जमाराशियां	प्राप्तियां	24840	1346	1475	1338	2171
	बकाया	156869	132029	153359	154697	156869
1.1.9 डाक घर सावधि मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	7	-1	0	4	4
	बकाया	-19	-25	-25	-22	-19
1.1.10 अन्य जमाराशियां	प्राप्तियां	2	0	0	0	2
	बकाया	23	21	21	21	23
1.2 बचत प्रमाणपत्र	**प्राप्तियां**	**45307**	**4334**	**3691**	**3583**	**3768**
	बकाया	**333189**	**286863**	**324713**	**328337**	**333189**
1.2.1 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VIII निर्गम	प्राप्तियां	19696	2332	1626	1585	1320
	बकाया	155043	135348	152139	153724	155043
1.2.2 इंदिरा विकास पत्र	प्राप्तियां	-16	2	0	0	-16
	बकाया	143	159	158	158	143
1.2.3 किसान विकास पत्र	प्राप्तियां	-1115	-582	-193	940	-184
	बकाया	-7891	-6776	-8648	-7708	-7891
1.2.4 किसान विकास पत्र-2014	प्राप्तियां	26619	2520	2258	1019	2564
	बकाया	174560	147942	170978	171996	174560
1.2.5 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VI निर्गम	प्राप्तियां	92	33	0	23	69
	बकाया	-22	-114	-114	-90	-22
1.2.6 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VII निर्गम	प्राप्तियां	31	29	0	16	15
	बकाया	-44	-74	-74	-58	-44
1.2.7 अन्य प्रमाणपत्र	बकाया	11400	10378	10274	10315	11400
1.3 लोक भविष्य निधि	**प्राप्तियां**	**13119**	**10058**	**526**	**596**	**10221**
	बकाया	**118347**	**105228**	**107530**	**108126**	**118347**

टिप्पणी : अप्रैल 2017 से प्राप्तियों का डाटा निवल प्राप्तियाँ हैं। अर्थात सकल प्राप्तियाँ माइनस सकल भुगतान |

स्रोत : महालेखाकार, पोस्ट और टेलीग्राफ।

सं. 45: केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप

(प्रतिशत)

केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां					
श्रेणी	2021	2022			
	दिसं.	मार्च	जून	सितं.	दिसं.
	1	2	3	4	5
(क) कुल (₹ करोड़ में)	8439811	8529036	8784931	9098788	9373372
1. वाणिज्यिक बैंक	35.40	35.93	36.16	36.44	36.13
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	0.27	0.29	0.33	0.38	0.44
3. बीमाकृत कंपनियां	25.74	25.89	26.34	25.94	26.14
4. म्यूच्युअल फंड	3.08	2.91	2.32	2.58	2.87
5. सहकारी बैंक	1.82	1.81	1.84	1.80	1.70
6. वित्तीय संस्थाएं	1.69	0.94	1.09	0.98	1.07
7. कॉरपोरेट	1.37	1.47	1.52	1.58	1.57
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	1.66	1.56	1.43	1.38	1.31
9. भविष्य निधियां	4.33	4.60	4.77	4.66	4.67
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	16.92	16.62	16.06	15.28	14.73
11. अन्य	7.73	7.97	8.18	8.98	9.37
11.1 राज्य सरकार	1.69	1.82	1.84	1.83	1.88

राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां					
श्रेणी	2021	2022			
	दिसं.	मार्च	जून	सितं.	दिसं.
	1	2	3	4	5
(ख) कुल (₹ करोड़ में)	4257578	4410250	4472011	4589128	4712902
1. वाणिज्यिक बैंक	34.41	34.39	34.22	34.37	34.34
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	0.40	0.38	0.41	0.36	0.44
3. बीमाकृत कंपनियां	28.85	28.42	28.39	27.71	27.42
4. म्यूच्युअल फंड	1.91	1.82	1.89	2.08	2.02
5. सहकारी बैंक	4.07	4.04	4.06	3.89	3.80
6. वित्तीय संस्थाएं	1.73	1.72	1.73	1.71	1.77
7. कॉरपोरेट	1.70	1.82	1.98	1.85	1.94
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
9. भविष्य निधियां	20.66	20.79	20.52	20.18	20.31
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	0.83	0.80	0.79	0.79	0.75
11. अन्य	5.40	5.81	5.99	7.05	7.19
11.1 राज्य सरकार	0.19	0.20	0.21	0.21	0.24

खज़ाना बिल					
श्रेणी	2021	2022			
	दिसं.	मार्च	जून	सितं.	दिसं.
	1	2	3	4	5
(ग) कुल (₹ करोड़ में)	692869	757198	1022053	920205	839931
1. वाणिज्यिक बैंक	47.01	49.04	51.37	50.91	49.15
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	1.53	4.20	2.49	2.12	2.17
3. बीमाकृत कंपनियां	6.29	6.58	5.34	5.46	5.81
4. म्यूच्युअल फंड	13.72	14.01	14.86	11.98	14.23
5. सहकारी बैंक	1.49	1.79	1.34	1.48	1.27
6. वित्तीय संस्थाएं	2.36	3.53	3.73	4.17	4.52
7. कॉरपोरेट	3.13	3.47	4.27	3.86	3.59
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	0.72	0.49	0.40	0.53	0.50
9. भविष्य निधियां	0.85	0.21	1.70	3.21	1.37
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. अन्य	22.89	16.69	14.50	16.27	17.39
11.1 राज्य सरकार	18.92	11.54	10.99	12.27	13.38

सं. 46: केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण

(₹ करोड़)

मद	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (सं.अ.)	2022-23 (ब.अ.)
	1	2	3	4	5	6
1. कुल वितरण	**4515946**	**5040747**	**5410887**	**6353359**	**7453320**	**8008684**
1.1 गतिविधियां	2635110	2882758	3074492	3823423	4489442	4761567
1.1.1 राजस्व	2029044	2224367	2446605	3150221	3444624	3536719
1.1.2 पूंजी	519356	596774	588233	550358	963856	1144725
1.1.3 ऋण	86710	61617	39654	122844	80962	80123
1.2 गैर गतिविधियां	1812455	2078276	2253027	2442941	2864084	3140466
1.2.1 राजस्व	1741432	1965907	2109629	2271637	2653832	2928102
1.2.1.1 ब्याज भुगतान	814757	894520	955801	1060602	1244104	1408929
1.2.2 पूंजी	69370	111029	141457	169155	178038	209892
1.2.3 ऋण	1654	1340	1941	2148	32214	2472
1.3 अन्य	68381	79713	83368	86995	99794	106652
2. कुल प्राप्तियां	**4528422**	**5023352**	**5734166**	**6397162**	**7193029**	**7944834**
2.1 राजस्व प्राप्तियां	3376416	3797731	3851563	3688030	4894050	5497245
2.1.1 कर प्राप्तियां	2978134	3278947	3231582	3193390	4026487	4551271
2.1.1.1 पण्य और सेवाओं पर कर	1853859	2030050	2012578	2076013	2608666	2904479
2.1.1.2 आय और संपत्ति पर कर	1121189	1246083	1216203	1114805	1414088	1642678
2.1.1.3 संघशासित क्षेत्र (बिना विधान मंडल के) के कर	3086	2814	2800	2572	3732	4115
2.1.2 गैर-कर प्राप्तियां	398282	518783	619981	494640	867564	945974
2.1.2.1 ब्याज प्राप्तियां	34224	36273	31137	33448	40481	46552
2.2 गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां	142433	140287	110094	64994	117937	90824
2.2.1 ऋण और अग्रिम की वसूली	42213	44667	59515	16951	33188	19835
2.2.2 विनिवेश से प्राप्त राशि	100219	95621	50578	48044	84748	70989
3. सकल वित्तीय घाटा [1-(2.1+2.2)]	**997097**	**1102729**	**1449230**	**2600335**	**2441333**	**2420614**
3 क वित्तपोषण के स्रोत : संस्था-वार						
3क.1 घरेलू वित्तपोषण	989167	1097210	1440548	2530155	2421587	2401363
3क.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	144792	387091	571872	890012	627255	-----
3क.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि. बैंक का ऋण	-144847	325987	190241	107493	350911	-----
3क.1.2 सरकार को गैर-बैंक ऋण	844375	710119	868676	1640143	1794332	2401363
3क.2 बाह्य वित्तपोषण	7931	5519	8682	70180	19746	19251
3ख. वित्तपोषण के स्रोत : लिखत-वार						
3ख.1 घरेलू वित्तपोषण	989167	1097210	1440548	2530155	2421587	2401363
3ख.1.1 बाज़ार उधार (निवल)	794856	795845	971378	1696012	1377060	1808401
3ख.1.2 लघु बचत (निवल)	71222	88961	209232	458801	565522	398870
3ख.1.3 राज्य भविष्य निधियां (निवल)	42351	51004	38280	41273	45133	44731
3ख.1.4 आरक्षित निधियां	18423	-18298	10411	4545	-1675	5824
3ख.1.5 जमाराशियां और अग्रिम	25138	66289	-14227	25682	32945	34029
3ख.1.6 नकद शेष	-12476	17395	-323279	-43802	260291	63850
3ख.1.7 अन्य	49653	96014	548753	347643	142310	45659
3ख.2 बाह्य वित्तपोषण	7931	5519	8682	70180	19746	19251
4. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल वितरण	*26.4*	*26.7*	*27.0*	*32.1*	*31.5*	*31.0*
5. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल प्राप्तियां	*26.5*	*26.6*	*28.6*	*32.3*	*30.4*	*30.8*
6. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर राजस्व प्राप्तियां	*19.8*	*20.1*	*19.2*	*18.6*	*20.7*	*21.3*
7. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कर प्राप्तियां	*17.4*	*17.3*	*16.1*	*16.1*	*17.0*	*17.6*
8. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर सकल वित्तीय घाटा	*5.8*	*5.8*	*7.2*	*13.1*	*10.3*	*9.4*

…: उपलब्ध नहीं। सं.अ.: संशोधित अनुमान, ब.अ.: बज़ट अनुमान

स्रोत : केन्द्रीय और राज्य सरकारों का बजट दस्तावेज।

सं.47: विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता

(₹ करोड़)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	फरवरी 2023 के दौरान					
		विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ)		अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)		ओवरड्राफ्ट (ओडी)	
		प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या
	1	2	3	4	5	6	7
1	आंध्र प्रदेश	442.41	27	1718.11	27	1337.41	13
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
3	असम	915.78	7	-	-	-	-
4	बिहार	-	-	-	-	-	-
5	छत्तीसगढ़	74.85	6	-	-	-	-
6	गोवा	-	-	-	-	-	-
7	गुजरात	-	-	-	-	-	-
8	हरियाणा	422.02	5	-	-	-	-
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
10	जम्मू और कश्मीर यूटी	-	-	839.21	26	178.17	9
11	झारखंड	-	-	-	-	-	-
12	कर्नाटक	-	-	-	-	-	-
13	केरल	72.86	7	1055.70	7	-	-
14	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-
15	महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-
16	मणिपुर	-	-	159.34	21	37.44	3
17	मेघालय	110.72	9	209.00	8	78.73	8
18	मिज़ोरम	-	-	57.45	8	14.38	1
19	नगालैंड	-	-	-	-	-	-
20	उड़ीसा	-	-	-	-	-	-
21	पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-
22	पंजाब	1548.57	27	-	-	-	-
23	राजस्थान	4901.00	24	311.03	4	-	-
24	तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-
25	तेलंगाना	651.36	28	1418.16	25	736.51	11
26	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-
27	उत्तर प्रदेश	-	-	-	-	-	-
28	उत्तराखंड	239.81	9	447.37	9	525.78	2
29	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-

टिप्पणियां: 1. राज्य सरकारों द्वारा एसडीएफ का लाभ समेकित ऋण-शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) और नीलामी खजाना बिल (एटीबी) शेष और सरकारी प्रतिभूतियों में अन्य निवेशों के संपार्श्विक पर लिया जाता है।

2. डब्ल्यूएमए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को अस्थायी नकदी बेमेल को पूरा करने के लिए अग्रिम है।

3. ओडी राज्य सरकारों को उनकी डब्ल्यूएमए सीमा से परे अग्रिम दिया जाता है।

4. प्राप्त किया गया औसत: कुल सहायता (एसडीएफ/ डब्ल्यूएमए/ ओडी) को दिनों की संख्या से विभाजन करने पर प्राप्त मान है जिसके लिए महीने के दौरान सहायता बढ़ाई गई थी।

5. - : शून्य।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक ।

सं. 48: राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश

(₹ करोड़)

क्र.सं.	राज्य /संघ शासित प्रदेश	फरवरी 2023 के अंत तक			
		समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	निलामी खज़ाना बिल (एटीबी)
	1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	10037	989	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	2222	4	0	1800
3	असम	4932	75	0	0
4	बिहार	8102	-	0	0
5	छत्तीसगढ़	6187	-	0	4008
6	गोवा	825	397	1	0
7	गुजरात	9749	580	0	0
8	हरियाणा	1476	1471	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	0	0
10	जम्मू और कश्मीर यूटी	-	-	0	0
11	झारखंड	1050	-	0	0
12	कर्नाटक	13106	312	0	24269
13	केरल	2591	-	0	0
14	मध्य प्रदेश	-	1108	0	0
15	महाराष्ट्र	57891	1218	0	13000
16	मणिपुर	60	122	0	0
17	मेघालय	946	66	8	0
18	मिज़ोरम	369	66	0	0
19	नगालैंड	1544	40	0	0
20	उड़ीसा	15763	1772	102	25848
21	पुदुचेरी	459	-	0	1100
22	पंजाब	6392	0	0	0
23	राजस्थान	-	-	129	7900
24	तमिलनाडु	8096	-	18	2373
25	तेलंगाना	6854	1501	0	0
26	त्रिपुरा	840	16	0	625
27	उत्तराखंड	4257	174	0	0
28	उत्तर प्रदेश	4748	-	116	0
29	पश्चिम बंगाल	11082	806	239	0
	कुल	**179579**	**10716**	**612**	**80922**

टिप्पणियां: 1. सीएसएफ और जीआरएफ कुछ राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी गई आरक्षित निधियां हैं।

2. एटीबी में प्राथमिक बाजार में राज्य सरकारों द्वारा निवेश किए गए 91 दिनों, 182 दिनों और 364 दिनों के ट्रेजरी बिल शामिल हैं।

3. - : लागू नहीं (योजना का सदस्य नहीं)।

सं. 49: राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियां

(₹ करोड़)

क्र. सं.	राज्य	2020-21		2021-22		2022-23						2022-23 में अब तक कुल राशि उठाई गई है	
						दिसंबर		जनवरी		फरवरी			
		सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल	निवल
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	आंध्र प्रदेश	50896	40498	46443	36103	-	-437	3000	1834	3557	1807	51860	41362
2	अरुणाचल प्रदेश	767	767	563	530	559	559	-	-	-	-	559	489
3	असम	15030	14230	12753	10753	800	800	800	800	2400	2400	16100	15800
4	बिहार	27285	24685	28489	24334	6000	5000	-	-1300	6000	5500	31000	25122
5	छत्तीसगढ़	13000	10500	4000	913	-	-	-	-2000	-	-	-	-2000
6	गोवा	3354	3054	2000	1450	300	300	300	150	-	-	1350	700
7	गुजरात	44780	33280	31054	13554	2000	1000	2500	1000	5000	4000	33500	18800
8	हरियाणा	30000	25550	30500	20683	1500	950	2500	1360	6000	4660	36500	24440
9	हिमाचल प्रदेश	6000	3755	4000	1875	1000	1000	1500	1500	1300	1011	10800	8951
10	जम्मू और कश्मीर यूटी	9328	6020	8562	5373	1495	895	700	200	500	500	6745	5006
11	झारखंड	9400	8900	5000	3191	2000	1500	-	-	1000	-	4000	1500
12	कर्नाटक	69000	61900	59000	49000	16000	13500	4000	4000	-	-1000	36000	27000
13	केरल	28566	23066	27000	18120	1500	650	4103	1603	2000	1000	23039	10053
14	मध्य प्रदेश	45573	38773	22000	13900	-	-	-	-2000	13000	11000	25000	18500
15	महाराष्ट्र	69000	50022	68750	40790	-	-1563	5000	4063	-	-3375	50000	24440
16	मणिपुर	1302	1044	1476	1326	122	122	150	150	200	200	1222	947
17	मेघालय	1777	1587	1608	1298	440	440	-	-80	-	-	1753	1423
18	मिज़ोरम	944	677	747	447	150	150	100	100	100	100	1190	1075
19	नगालैंड	1721	1366	1727	1222	300	300	193	193	248	248	1763	1313
20	उड़ीसा	3000	500	0	-6473	-	-	-	-500	-	-1500	-	-6500
21	पुदुचेरी	1390	790	1374	841	300	200	-	-302	500	500	1200	698
22	पंजाब	32995	23467	25814	12428	2245	1745	500	-	4200	3700	36600	26246
23	राजस्थान	57359	44273	51149	38243	1251	751	1500	500	4000	3826	34751	23495
24	सिक्किम	1292	1292	1511	1471	-	-	-	-	437	437	1314	1244
25	तमिलनाडु	87977	76796	87000	72500	6000	4850	10000	8000	9000	6600	68000	48603
26	तेलंगाना	43784	38782	45716	39256	2500	2187	3500	2666	3500	2250	35000	27498
27	त्रिपुरा	1916	1631	300	0	-	-100	-	-	-	-	-	-315
28	उत्तरप्रदेश	75500	59185	62500	42355	-	-78	7000	7000	12500	12500	33500	21713
29	उत्तराखंड	6200	5208	3200	1800	-	-650	500	500	750	-350	1750	-
30	पश्चिम बंगाल	59680	50180	67390	45199	7000	5000	4000	3200	1000	500	42000	24200
	कुल	798816	651777	701626	492483	53462	39071	51846	32637	77192	56514	586496	391803

- : शून्य

टिप्पणी : 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य संवैधानिक रूप से मौजूद नहीं है और उस राज्य की देनदारियाँ जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश की देनदारियों के रूप में बनी हुई हैं।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

सं. 50 (ए): हाउसहोल्ड की वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह- लिखत-वार

(राशि करोड़ में)

मद	2019-20				
	ति1	ति2	ति3	ति4	वार्षिक
निवल वित्तीय आस्तियां(I-II)	**238613.6**	**476724.8**	**386450.4**	**530769.8**	**1632558.5**
जीडीपी का प्रतिशत	*4.8*	*9.8*	*7.5*	*10.3*	*8.1*
I. वित्तीय आस्तियां	**398076.7**	**567753.2**	**517351.0**	**924069.3**	**2407250.2**
जीडीपी का प्रतिशत	*8.1*	*11.7*	*10.1*	*18.0*	*12.0*
जिसमें:					
1. कुल जमाराशियां (ए+बी)	12239.0	296625.6	124015.7	451698.3	884578.5
(ए) बैंक जमाराशि	-10550.9	278124.4	116211.9	444044.6	827830.0
i. वाणिज्यिक बैंक	-13293.8	269475.4	66666.7	446006.7	768855.0
ii. सहकारी बैंक	2742.9	8649.0	49545.2	-1962.1	58975.0
(बी) गैर-बैंक जमाराशियां	22789.9	18501.2	7803.7	7653.7	56748.5
2. जीवन बीमा निधियाँ	117873.1	108209.1	110373.8	37714.2	374170.2
3. भविष्य और पेंशन निधि (पीपीएफ़ सहित)	104681.1	98426.3	103356.1	193739.0	500202.5
4. मुद्रा	61244.1	-26104.8	86832.6	160690.2	282662.1
5. निवेश	43936.8	43018.8	22655.1	-11953.8	97656.9
जिसमें:					
(ए) म्यूचुअल फंड	23303.5	38382.2	19191.1	-19191.1	61685.7
(बी) इक्विटी	18648.2	2172.4	936.2	4981.0	26737.8
6. अल्प बचत (पीपीएफ़ छोड़ कर)	57038.5	46514.1	69053.6	91117.2	263723.4
II. वित्तीय देयताएँ	**159463.1**	**91028.5**	**130900.6**	**393299.5**	**774691.7**
जीडीपी का प्रतिशत	*3.2*	*1.9*	*2.6*	*7.7*	*3.9*
से ऋण (उधार)					
1. वित्तीय निगम (ए+बी)	159429.6	90994.9	130867.1	393266.0	774557.6
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	140261.4	58074.4	114905.9	196581.1	509822.8
जिसमें :					
वाणिज्यिक बैंक	135754.1	57135.0	87377.4	202214.2	482480.6
(बी) अन्य वित्तीय संस्थान	19168.2	32920.5	15961.2	196684.8	264734.8
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	-519.7	22976.7	29930.7	198264.3	250652.0
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	17033.0	8093.1	-15710.4	-3093.1	6322.6
iii. बीमा कंपनियाँ	2655.0	1850.8	1740.9	1513.6	7760.2
2. गैर-वित्तीय कार्पोरेशन (निजी कॉर्पोरेट व्यापार)	33.8	33.8	33.8	33.8	135.1
3. सामान्य सरकार	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-1.0

सं. 50 (ए): हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह- लिखत-वार *(जारी..)*

(राशि करोड़ में)

मद	2020-21				
	ति1	ति2	ति3	ति4	वार्षिक
निवल वित्तीय आस्तियां(I-II)	**600422.5**	**573643.2**	**481433.5**	**719844.5**	**2375343.7**
जीडीपी का प्रतिशत	*15.5*	*12.1*	*8.8*	*12.5*	*12.0*
I. वित्तीय आस्तियां	**805869.5**	**612224.3**	**651241.3**	**1092617.4**	**3161952.5**
जीडीपी का प्रतिशत	*20.8*	*13.0*	*12.0*	*19.0*	*16.0*
जिसमें:					
1. कुल जमाराशियां (ए+बी)	297412.4	278631.7	158172.2	525550.7	1259767.1
(ए) बैंक जमाराशि	281191.3	264565.3	147096.0	527056.7	1219909.2
i. वाणिज्यिक बैंक	279010.5	262033.7	143558.6	471730.9	1156333.7
ii. सहकारी बैंक	2180.8	2531.6	3537.3	55325.8	63575.6
(बी) गैर-बैंक जमाराशियां	16221.1	14066.4	11076.3	-1506.0	39857.9
2. जीवन बीमा निधियाँ	123291.4	142365.7	156438.6	141120.0	563215.8
3. भविष्य और पेंशन निधि (पीपीएफ़ सहित)	119666.9	110916.6	108512.2	207604.5	546700.1
4. मुद्रा	202432.7	21286.9	91456.0	66800.5	381976.1
5. निवेश	6249.8	-12956.4	67659.3	63624.0	124576.7
जिसमें:					
(ए) म्यूचुअल फंड	-16021.0	-28837.7	57675.4	51267.0	64083.8
(बी) इक्विटी	18599.4	8291.5	5307.1	6333.3	38531.2
6. अल्प बचत (पीपीएफ़ छोड़ कर)	55760.7	70924.2	67947.4	86862.2	281494.6
II. वित्तीय देयताएँ	**205447.0**	**38581.1**	**169807.8**	**372772.9**	**786608.8**
जीडीपी का प्रतिशत	*5.3*	*0.8*	*3.1*	*6.5*	*4.0*
से ऋण (उधार)					
1. वित्तीय निगम (ए+बी)	205490.3	38624.3	169851.0	372816.9	786782.5
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	211058.8	13213.0	139622.0	284732.6	648626.4
जिसमें :					
वाणिज्यिक बैंक	211259.3	13213.8	140514.3	242476.0	607463.5
(बी) अन्य वित्तीय संस्थान	-5568.6	25411.3	30229.0	88084.4	138156.1
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	-15450.4	21627.1	15921.2	61326.1	83424.0
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	10516.6	2875.1	13048.5	25336.1	51776.2
iii. बीमा कंपनियाँ	-634.8	909.2	1259.3	1422.2	2955.9
2. गैर-वित्तीय कार्पोरेशन (निजी कॉर्पोरेट व्यापार)	33.8	33.8	33.8	33.0	134.4
3. सामान्य सरकार	-77.0	-77.0	-77.0	-77.0	-308.0

सं. 50(ए): हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह- लिखत-वार *(समाप्त)*

(राशि करोड़ में)

मद	2021-22				
	ति1	ति2	ति3	ति4	वार्षिक
निवल वित्तीय आस्तियां(I-II)	**519781.2**	**358325.2**	**453302.7**	**636259.8**	**1967668.9**
जीडीपी का प्रतिशत	*10.1*	*6.4*	*7.2*	*9.6*	*8.3*
I. वित्तीय आस्तियां	**382780.7**	**547346.2**	**834009.6**	**796341.7**	**2560478.2**
जीडीपी का प्रतिशत	*7.5*	*9.7*	*13.2*	*12.0*	*10.8*
जिसमें:					
1. कुल जमाराशियां (ए+बी)	-84377.1	202652.1	425821.4	151374.9	695471.4
(ए) बैंक जमाराशि	-106507.3	197301.2	422819.5	140297.2	653910.7
i. वाणिज्यिक बैंक	-108037.7	195617.4	418642.9	145510.5	651733.1
ii. सहकारी बैंक	1530.4	1683.8	4176.7	-5213.3	2177.6
(बी) गैर-बैंक जमाराशियां	22130.2	5350.9	3001.9	11077.7	41560.7
2. जीवन बीमा निधियाँ	114617.8	127356.0	103154.9	95681.7	440810.4
3. भविष्य और पेंशन निधि (पीपीएफ़ सहित)	126469.7	108777.0	91543.9	254877.2	581667.9
4. मुद्रा	128660.2	-68631.2	62793.3	146845.0	269667.4
5. निवेश	24929.6	82305.4	69760.9	50980.8	227976.7
जिसमें:					
(ए) म्यूचुअल फंड	14573.0	63151.3	37912.2	44963.7	160600.1
(बी) इक्विटी	4502.5	13218.5	27808.2	3084.1	48613.3
6. अल्प बचत (पीपीएफ़ छोड़ कर)	71423.1	93829.6	79877.9	95524.7	340655.3
II. वित्तीय देयताएँ	**-137000.5**	**189021.0**	**380706.9**	**160081.8**	**592809.2**
जीडीपी का प्रतिशत	*-2.7*	*3.4*	*6.0*	*2.4*	*2.5*
से ऋण (उधार)					
1. वित्तीय निगम (ए+बी)	-137021.8	188999.7	380685.6	160060.6	592724.1
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	-113662.5	134166.1	320160.2	153323.3	493987.0
जिसमें :					
वाणिज्यिक बैंक	-108061.2	135728.8	317452.5	152364.2	497484.4
(बी) अन्य वित्तीय संस्थान	-23359.3	54833.7	60525.5	6737.3	98737.1
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	-31118.4	28880.1	29479.8	-31016.3	-3774.8
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	7132.0	24403.8	29494.8	37436.2	98466.8
iii. बीमा कंपनियाँ	627.1	1549.8	1550.9	317.4	4045.2
2. गैर-वित्तीय कार्पोरेशन (निजी कॉर्पोरेट व्यापार)	33.8	33.8	33.8	33.8	135.1
3. सामान्य सरकार	-12.5	-12.5	-12.5	-12.5	-50.0

टिप्पणियां: 1. हाउसहोल्ड की निवल वित्तीय बचत निवल वित्तीय आस्तियों के प्रवाह को संदर्भित करती है, जो हाउसहोल्ड द्वारा धारित वित्तीय आस्तियों में परिवर्तन को घटाकर उनकी वित्तीय देयताओं में परिवर्तन को दर्शाती है।
2. छोटी बचत और पीपीएफ में संशोधन मुख्य रूप से लेखा महानियंत्रक, भारत सरकार के मासिक डेटा से प्राप्त तिमाही आंकड़ों के कारण होता है।
3. 2021-22 के लिए बैंक जमा में संशोधन का श्रेय बीएसआर-2 के अनुसार कुल जमा में हाउसहोल्ड की कम हिस्सेदारी को दिया जाता है।
4. जीडीपी के अनुपात के रूप में डेटा की गणना 31 मई 2022 को जारी राष्ट्रीय आय 2021-22 के अनंतिम अनुमानों के आधार पर की गई है।
5. पूर्णांकन के कारण कॉलम में दिए गए आंकड़े कुल योग के बराबर नहीं हो सकते हैं।

सं. 50(बी): हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक- चुनिंदा संकेतक

(राशि करोड़ में)

मद	जून-2019	सितं-2019	दिसं-2019	मार्च-2020
वित्तीय आस्तियां (ए+बी+सी+डी)	**16315506.3**	**16632816.5**	**17010694.5**	**17180616.2**
जीडीपी का प्रतिशत	*84.7*	*85.4*	*86.2*	*85.6*
(ए) बैंक जमाराशियाँ (i+ii)	8858293.4	9136417.9	9252629.8	9696674.3
i. वाणिज्यिक बैंक	8131543.2	8401018.6	8467685.3	8913692.0
ii. सहकारी बैंक	726750.2	735399.2	784944.4	782982.3
(बी) जीवन बीमा निधि	3883609.7	3930727.6	4049902.5	3884771.5
(सी) मुद्रा	2010842.9	1984738.1	2071570.7	2232261.0
(डी) म्यूचुअल फंड	1404631.5	1412654.1	1468727.6	1197092.9
वित्तीय देयताएँ (ए+बी)	**6370092.6**	**6461087.5**	**6591954.6**	**6985220.6**
जीडीपी का प्रतिशत	*33.1*	*33.2*	*33.4*	*34.8*
से ऋण (उधार)				
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	5148115.0	5206189.4	5321095.3	5517676.4
जिसमें:				
i. वाणिज्यिक बैंक	4668496.4	4725631.3	4813008.7	5015222.9
ii. सहकारी बैंक	478956.2	479656.9	506946.6	501074.8
(बी) अन्य वित्तीय संस्थाएँ	1221977.5	1254898.1	1270859.3	1467544.1
जिसमें:				
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	451922.3	474899.0	504829.7	703094.0
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	673312.1	681405.2	665694.8	662601.7

50(बी): हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक- चुनिंदा संकेतक *(जारी.)*

(राशि करोड़ में)

मद	जून-2020	सितं-2020	दिसं-2020	मार्च-2021
वित्तीय आस्तियां (एए+बी+सी+डी)	**18039169.4**	**18606364.4**	**19333484.1**	**20168953.3**
जीडीपी का प्रतिशत	*94.9*	*98.6*	*100.8*	*101.9*
(ए) बैंक जमाराशियाँ (i+ii)	9977865.6	10242430.9	10389526.9	10916583.6
i. वाणिज्यिक बैंक	9192702.5	9454736.2	9598294.8	10070025.7
ii. सहकारी बैंक	785163.1	787694.7	791232.1	846557.9
(बी) जीवन बीमा निधि	4102000.7	4274424.9	4551882.0	4718718.2
(सी) मुद्रा	2434693.7	2455980.6	2547436.6	2614237.0
(डी) म्यूचुअल फंड	1343752.0	1443784.4	1648999.0	1730461.0
वित्तीय देयताएँ (एए+बी)	**7190710.8**	**7229335.1**	**7399186.1**	**7772003.0**
जीडीपी का प्रतिशत	*37.8*	*38.3*	*38.6*	*39.3*
से ऋण (उधार)				
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	5728735.3	5741948.3	5881570.2	6166302.8
जिसमें:				
i. वाणिज्यिक बैंक	5226482.2	5239696.0	5380210.4	5622686.4
ii. सहकारी बैंक	500870.2	500865.3	499968.8	542221.2
(बी) अन्य वित्तीय संस्थाएँ	1461975.5	1487386.9	1517615.9	1605700.3
जिसमें:				
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	687643.6	709270.7	725191.9	786518.0
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	673118.3	675993.4	689041.8	714377.9

50(बी): हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक- चुनिंदा संकेतक *(समाप्त)*

(राशि करोड़ में)

मद	जून-2021	सितं-2021	दिसं-2021	मार्च-2022
वित्तीय आस्तियां (ए+बी+सी+डी)	**20508115.7**	**21057343.4**	**21673261.7**	**22104312.7**
जीडीपी का प्रतिशत	*97.4*	*95.9*	*95.0*	*93.4*
(ए) बैंक जमाराशियाँ (i+ii)	10810076.3	11007377.6	11430197.1	11570494.3
i. वाणिज्यिक बैंक	9961988.0	10157605.4	10576248.3	10721758.8
ii. सहकारी बैंक	848088.3	849772.1	853948.8	848735.5
(बी) जीवन बीमा निधि	4894238.5	5105262.1	5175997.5	5287980.3
(सी) मुद्रा	2742897.3	2674266.1	2737059.4	2883904.4
(डी) म्यूचुअल फंड	1855000.1	2064363.5	2126112.0	2152140.5
वित्तीय देयताएँ (ए+बी)	**7634981.2**	**7823980.9**	**8204666.6**	**8364727.1**
जीडीपी का प्रतिशत	*36.3*	*35.6*	*36.0*	*35.3*
से ऋण (उधार)				
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	6052640.2	6186806.3	6506966.5	6660289.7
जिसमें:				
i. वाणिज्यिक बैंक	5514625.2	5650354.1	5967806.6	6120170.8
ii. सहकारी बैंक	536604.9	535027.3	537720.1	538664.3
(बी) अन्य वित्तीय संस्थाएँ	1582341.0	1637174.6	1697700.1	1704437.4
जिसमें:				
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	755399.6	784279.7	813759.5	782743.2
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	721510.0	745913.7	775408.5	812844.7

टिप्पणी: 1. डेटा को केवल चुनिंदा वित्तीय लिखतों के लिए संकलित किया गया है(बैंकिंग क्षेत्र, एनबीएफ़सी और एचएफ़सी से ऋण) जिसके लिए डेटा उपलब्ध है।
2. जीडीपी अनुपात के रूप में डेटा की गणना 31 मई 2022 को जारी राष्ट्रीय आय 2021-22 के दूसरे अग्रिम अनुमान पर आधारित है।
3. पूर्णांकन के कारण कॉलम में दिये गए आंकड़े कुल योग के बराबर नहीं हो सकते हैं।

वर्तमान सांख्यिकी की व्याख्यात्मक टिप्पणियां

सारणी सं. 1

1.2 और 6: वार्षिक आंकड़े महीनों के औसत हैं।

3.5 और 3.7: वित्त वर्ष में अब तक वृद्धि के अनुपात से संबंधित है।

4.1 से 4.4, 4.8, 4.9 और 5 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार से संबंधित है।

4.5, 4.6 और 4.7 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार को पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित है।

4.10 से 4.12 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम निलामी दिन से संबंधित है।

4.13 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम दिन से संबंधित है।

7.1 और 7.2: विदेशी व्यापार यूएस डॉलर से संबंधित है।

सारणी सं. 2

2.1.2 : चुकता पूंजी, आरक्षित निधि और दीर्घावधि परिचालनगत निधि शामिल है।

2.2.2 : नकदी, सावधि जमाराशियों और अल्पावधि प्रतिभूतियों/बांडों सहित जैसे - आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी।

सारणी सं. 4

http://nsdp.rbi.org.in के 'रिज़र्व टैम्पलेट' के अंतर्गत परिपक्वतावार बकाया फॉर्वर्ड संविदा की स्थिति दर्शायी गयी है।

सारणी सं. 5

अन्य अर्थात एक्सिम बैंक को विशेष पुनर्वित्त सुविधा 31 मार्च 2013 से बंद है।

सारणी सं. 6

अनुसूचित बैंकों के लिए, मार्च की समाप्ति के आंकडे सूचना देने के लिए नियत अंतिम शुक्रवार से संबंधित हैं।

2.2 : आईएमएफ खाता सं.1 की शेष राशि, आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि, पेंशन निधि, उपदान और अधिवर्षिता निधि शामिल नहीं हैं।

सारणी सं. 7 और 11

सारणी 7 में 3.1 और सारणी 11 में 2.4: आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांड शामिल हैं।

सारणी सं. 8

एनएम$_2$ और एनएम$_3$ में एफसीएनआर (बी) जमाराशियां शामिल नहीं हैं।

2.4: चुकता पूंजी और आरक्षित राशि शामिल हैं।

2.5 : बैंकिंग प्रणाली की अन्य मांग और मीयादी देयताएं शामिल हैं।

सारणी सं. 9

वित्तीय संस्थाओं में एक्जिम बैंक, सिडबी, नाबार्ड और एनएचबी शामिल हैं।

एल$_1$ और एल$_2$ मासिक आधार पर और एल$_3$ तिमाही आधार पर संकलित किए जाते हैं।

जहां आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, वहां अंतिम उपलब्ध आंकड़े पुनः दिए गए हैं।

सारणी सं. 13

कालम सं. (1) (2) और (3) में दर्शाये गए आंकड़े अंतिम और कालम सं. (4) और (5) में दर्शाए गए आंकड़े अनंतिम हैं।

सारणी सं. 14

कालम सं. (4) और (8) में दर्शाए गए आंकड़े अनंतिम हैं।

सारणी सं. 17

2.1.1: राज्य सहकारी बैंकों में सहकारी सोसाइटियों द्वारा अनुरक्षित आरक्षित निधि शामिल नहीं है।

2.1.2 : आरबीआई, एसबीआई, आईडीबीआई, नाबार्ड, अधिसूचित बैंकों और राज्य सरकारों से लिए गए ऋण शामिल नहीं है।

4. : आईडीबीआई और नाबार्ड से लिए गए ऋण शामिल हैं।

सारणी सं. 24

प्राथमिक व्यापारियों में, प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करने वाले बैंक शामिल हैं।

सारणी सं. 30

प्राइवेट प्लेसमेंट और बिक्री के प्रस्ताव शामिल नहीं हैं।

1: बोनस शेयर शामिल नहीं हैं।

2: संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयर और इक्वी - अधिमान शेयर शामिल हैं।

सारणी सं. 32

आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांडों में निवेश तथा सार्क स्वैप व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त विदेशी मुद्रा और भारत सरकार द्वारा रिज़र्व बैंक को अंतरित एसडीआर शामिल नहीं हैं। अमेरिकी डॉलर में दिखाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में रिज़र्व में रखी गैर यूएस मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन और ऑस्ट्रेलिया डॉलर) के मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास को शामिल किया गया है। विदेशी मुद्रा धारिता को रूपी-अमेरिकी डॉलर आरबीआई धारिता दरों में परिवर्तित किया गया है।

सारणी सं. 34

1.1.1.1.2 और 1.1.1.1.1.4 : अनुमान

1.1.1.2 : नवीनतम माह के लिए अनुमान

'अन्य पूंजी' एफडीआई उद्यम की मूल और अनुषंगी संस्थाओं/शाखाओं के बीच के ऋण सबंधी लेनदेन से संबंधित है।

हो सकता है कि सूचना देने में हुए समय-अंतराल के कारण ये आँकड़े भुगतान-संतुलन के आंकड़ो से मेल न खाएं।

सारणी सं. 35

1.10 : जर्नलों के लिए अभिदान, विदेश में किए गए निवेशों का अनुरक्षण, छात्र ऋण चुकौती और क्रेडिट कार्ड भुगतान जैसी मदें शामिल हैं।

सारणी सं. 36

सूचकांकों में वृद्धि रुपये की मूल्यवृद्धि या मूल्यह्रास का संकेतक है। 6-मुद्राओंवाले सूचकांक के लिए, आधार वर्ष 2020-21 अस्थिर है जिसे प्रत्येक वर्ष अद्यतन किया जाता है। रीर के आंकड़े उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) पर आधारित है। नीर/रीर सूचकांकों के संकलन के लिए उपयोग की जाने वाली कार्यप्रणाली का ब्यौरा आरबीआई बुलेटिन के दिसंबर 2005, अप्रैल 2014 और जनवरी 2021 के अंक में उपलब्ध हैं।

सारणी सं. 37

ईसीबी/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों (एफसीसीबी) के लिए आवेदनों पर आधारित जिन्हें उस अवधि के दौरान ऋण पंजीकरण संख्या दी गई है।

सारणी सं. 38, 39, 40 और 41

इन सारणियों के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणियां आरबीआई बुलेटिन 2012 के दिसंबर अंक में उपलब्ध हैं।

सारणी सं. 43

भाग I- ए. भुगतान प्रणाली

1.1.3: प्रतिभूति खंड के अंतर्गत त्रिपक्षीय रेपो का परिचालन 05 नवंबर, 2018 से किया गया है।

भाग I-बी भुगतान प्रणाली

4.1.2: अन्य 'में ई-कॉमर्स लेनदेन और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

4.2.2: अन्य 'में ई-कॉमर्स लेनदेन, कार्ड से कार्ड अंतरण और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

5: दिसंबर 2010 से उपलब्ध है।

5.1: माल और सेवाओं की खरीद और वॉलेट के माध्यम से निधि अंतरण शामिल है।

5.2.2: ऑनलाइन लेनदेन और अन्य लेनदेन के लिए पीपीआई कार्ड का उपयोग शामिल है।

6.1: तीन ग्रिडों से संबंधित - मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नई।

6.2: अन्य 'में गैर-एमआईसीआर लेनदेन शामिल है जो 21 बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन केंद्र से संबंधित है।

भाग II- ए अन्य भुगतान चैनल

1: मोबाइल भुगतान -
- इसमें बैंकों के मोबाइल ऐप और यूपीआई ऐप के जरिए किए गए लेनदेन शामिल हैं।
- जुलाई 2017 के डेटा में केवल व्यक्तिगत भुगतान और मोबाइल के माध्यम से पहल किए गए, संसाधित और अधिकृत किए गए कॉर्पोरेट भुगतान शामिल हैं। अन्य कॉर्पोरेट भुगतान जो मोबाइल के माध्यम से शुरू नहीं किए गए है, संसाधित और अधिकृत नहीं हैं, को शामिल नहीं किया गया है।

2: इंटरनेट भुगतान --नेटबैंकिंग 'के माध्यम से केवल ई-कॉमर्स लेनदेन और बैंक की इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट से किया गया वित्तीय लेनदेन शामिल है।

भाग II-बी एटीएम

3.3 और 4.2: केवल बैंक द्वारा जारी पीपीआई से किए गए लेनदेन से संबंधित है।

भाग III. भुगतान प्रणाली अवसंरचना

3: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स (डब्ल्यूएलएओ) के एटीएम शामिल हैं। डब्ल्यूएलएओ को अप्रैल 2014 से शामिल किया गया हैं।

सारणी सं. 45

(-): शून्य/ नगण्य को दर्शाता है।

जून 2016 से टेबल फार्मेट संशोधित किया है, जिसमें केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों सहित राज्य सरकारों की स्वामित्ववाली प्रतिभूतियाँ और खज़ाना बिलों सहित शामिल है।

राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में उज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (यूडीएवाई) के अंतर्गत जारी विशेष बान्ड शामिल हैं।

वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत बैंक के प्राथमिक डीलरों को शामिल किया गया है। तथापि, कुल बकाया प्रतिभूतियों में इसका हिस्सा बहुत कम है।

"अन्य" श्रेणी में राज्य सरकारों, पेंशन निधियां न्यास, संस्थाएं, हिंदू अविभक्त परिवार / वैयक्तिक आदि. शामिल है।

सारणी सं. 46

जीडीपी डेटा 2011-12 के आधार पर आधारित है। 2022-23 के लिए जीडीपी केंद्रीय बजट 2022-23 से है।
डेटा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है।
1 और 2: आंकड़े केंद्र सरकार (एनएसएसएफ की पुन:चुकौती सहित) और राज्य सरकार के निवल चुकौती से संबंधित है।
1.3: राज्य द्वारा स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को दिये गये मुआवजे और कार्य से संबंधित है।
2: यह डेटा केंद्र और राज्य सरकारों को दिये गये उधार प्राप्तियों सहित केंद्र और राज्य सरकारों के नकदी शेष में हुए घटबढ़ से संबंधित निवल को दर्शाते है।
3ए.1.1: आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक के अभिलेख के अनुसार है।
3बी.1.1: दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से उधारियां शामिल हैं।
3बी.1.2: राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) की ओर से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विशेष प्रतिभूतियों में किये गये निवल निवेश को दर्शाते हैं।
यह डेटा नए डेटा की उपलब्धता के साथ घटकों में समायोजन के कारण पिछले प्रकाशनों से भिन्न हो सकता है।
3बी.1.6: केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को दिये गये अर्थोपाय अग्रिमों सहित।
3बी.1.7: ख़ज़ाना बिल, वित्तीय संस्थानों से ऋण, बीमा और पेंशन निधि, प्रेषण, नकदी शेष निवेश खाता सहित।

सारणी सं. 47

राज्य सरकारों द्वारा समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) और निलामी खज़ाना बिल (एटीबी) के शेषों तथा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए अन्य निवेशों को संपाश्विक के तौर पर रखते हुए विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) प्राप्त की जाती है।
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को उनके अल्प कालिक नकदी असंतुलन से निपटने के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) दिया जाता है।
राज्य सरकारों को उनकी अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा से अधिक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आग्रिम के तौर पर ओवरड्राफ्ट दिया जाता है।
प्राप्त कुल सहायता (एसडीएफ/डब्ल्यूएमए/ओडी) को उन दिनों की संख्या से भाग देने पर, जिनके लिए माह के दौरान सहायता प्राप्त हुई, औसत राशि प्राप्त होती है।
-: नगण्य

सारणी सं. 48

समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) वे आरक्षित निधियाँ हैं जो कुछ राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी जाती हैं।
नीलामी खज़ाना बिलों (एटीबी) में राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिक बाज़ारो में निवेश किए गए 91 दिवसीय, 182 दिवसीय तथा 364 दिनों की खज़ाना बिल शामिल हैं।
--: लागू नहीं (इस योजना का सदस्य नहीं है)।

वर्तमान सांख्यिकी संबंधी अवधारणाएं एवं कार्यप्रणालियां भारतीय रिज़र्व बैंक मासिक बुलेटिन के वर्तमान सांख्यिकी संबंधी व्यापक मार्गदर्शिका (**https://rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=17618**) में उपलब्ध हैं।

'वर्तमान सांख्यिकी' का टाइम सीरिज डेटा https://dbie.rbi.org.in पर उपलब्ध है।
विस्तृत टिप्पणियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संबंधित प्रेस विज्ञप्तियों और बैंक के अन्य प्रकाशनों जैसे **भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी पुस्तिका** में उपलब्ध हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के प्रकाशन

प्रकाशन का नाम	मूल्य	
	भारत में	विदेश में
1. भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन 2023	₹350 एक प्रति ₹250 एक प्रति (रियायती दर*) ₹4,000 (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) ₹3,000 (एक वर्ष रियायती दर*)	15 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति 150 अमेरिकी डॉलर (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
2. भारतीय राज्यों से संबंधित सांख्यिकी पुस्तिका 2021-22	₹550 (सामान्य) ₹600 (डाक प्रभार सहित)	24 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
3. भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी पुस्तिका 2021-22	₹600 (सामान्य) ₹650 (डाक प्रभार सहित) ₹450 (रियायती) ₹500 (रियायती डाक प्रभार सहित)	50 अमेरिकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
4. राज्य वित्त: 2022-23 के बजटों का अध्ययन	₹600 एक प्रति (कांउटर पर) ₹650 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	24 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
5. मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट 2021-22	₹575 एक प्रति (कांउटर पर) ₹625 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	22 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
6. रिपोर्ट ऑफ दि कमिटी ऑन फुलर कैपिटल अकांउट कन्वर्टिबिलिटी (तारापोर समिति की रिपोर्ट II)	₹140 एक प्रति (कांउटर पर) ₹170 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	25 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
7. बैंकिंग शब्दावली (2012)	₹80 एक प्रति (कांउटर पर) ₹120 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
8 अनुवाद के विविध आयाम (हिंदी)	₹165 एक प्रति (कांउटर पर) ₹205 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
9. बैंक में राजभाषा नीति का कार्यान्वयनः दशा और दिशा (हिंदी)	₹150 एक प्रति (कांउटर पर) ₹200 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
10. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 43, सं. 1, 2022	₹200 एक प्रति (कांउटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
11. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 42, सं. 2, 2021	₹200 एक प्रति (कांउटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
12. पर्सपेक्टिव्स ऑन सेंट्रल बैंकिंग गवर्नर्स; स्पीक (1935-2010) प्लैटिनम जुबिली	₹1400 एक प्रति (कांउटर पर)	50 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
13. नगरपालिका वित्त संबंधी रिपोर्ट	₹300 एक प्रति (कांउटर पर) ₹350 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	16 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)

टिप्पणियां:

1. उपर्युक्त प्रकाशनों में से कई प्रकाशन आरबीआई की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध हैं।
2. टाइम सीरीज़ डेटा भारतीय अर्थव्यवस्था के डेटाबेस में उपलब्ध हैं (http://dbie.rbi.org.in)।
3. भारतीय रिज़र्व बैंक का इतिहास 1935-1997 (4 खंड), वित्तीय संकट के संदर्भ में केन्द्रीय बैंकिंग की चुनौतियां और भारत की क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था: वृद्धि और वित्त भारत के प्रमुख पुस्तक भंडारों में उपलब्ध हैं।

* भारत में छात्रों, अध्यापकों / व्याख्याताओं, अकादमिक और शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को रियायत दी जाएगी बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

सामान्य अनुदेशः

1. सभी संचार निम्न को संबोधित किए जाने चाहिए:
   निदेशक, रिपोर्ट और ज्ञान प्रसार विभाग,
   आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (डीआरकेडी, डीईपीआर),
   भारतीय रिज़र्व बैंक, अमर भवन, तल मंजिल,
   सर पी. एम. रोड, फोर्ट, पोस्ट बॉक्स सं. 1036. मुंबई- 400 001
   टेलीफोन: 022-2260 3000 विस्तार: 4002, ईमेल: spsdepr@rbi.org.in
2. बिक्री के लिए प्रकाशन प्रातः 10:30 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक (सोमवार से शुक्रवार) उपलब्ध हैं।
3. प्रकाशनों को कैश-ऑन डिलीवरी के आधार पर नहीं भेजा जाएगा।
4. एक बार बेचे गए प्रकाशनों को वापस नहीं लिया जाएगा।
5. प्रकाशन के पिछले अंक आम तौर पर उपलब्ध नहीं होते हैं।
6. जहां कहीं भी रियायती मूल्य का संकेत नहीं दिया गया है, भारत में छात्रों, शिक्षकों, शैक्षिक/ अकादमिक संस्थानों, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं के लिए 25 प्रतिशत की छूट उपलब्ध है, बशर्ते पात्रता का प्रमाण प्रस्तुत किया जाए।
7. सदस्यता शुल्क मुख्यतः एनईएफटी द्वारा किया जाना चाहिए और भुगतानकर्ता के नाम, सदस्यता संख्या (यदि कोई हो), खाता संख्या, तारीख और राशि सहित लेनदेन विवरण spsdepr@rbi.org.in पर ईमेल किया जाना चाहिए या डाक द्वारा भेजा जाना चाहिए।

   ए. एनईएफटी हस्तांतरण के लिए निम्नलिखित विवरण अपेक्षित है:

लाभार्थी का नाम	आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, आरबीआई
बैंक का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक
शाखा और पता	फोर्ट, मुंबई
बैंक शाखा का आईएफएससी	RBIS0MBPA04
खाता प्रकार	चालू खाता
खाता संख्या	41-8024129-19

   बी. गैर-डिजिटल मोड के माध्यम से सदस्यता के मामले में, कृपया मुंबई में देय डिमांड ड्राफ्ट/ चेक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई के नाम पर भेजें।

8. ‘प्रकाशन प्राप्त न होने’ संबंधी शिकायतें दो माह की अवधि के अंदर भेजी जाएं।